# OUEDATE SUP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

Students can retain library books only for two KOTA (Raj )

KOTA (Raj ) an retain library b	ooks only for two
	SIGNATURE
DUE DTATE	Sidil
	KOTA (Raj ) can retain library b st  DUE DYATE

# भारतीय धर्यशास्त्र की समस्याएँ भाग (१)

# लेखक की अन्य रचनायें

A Textbook of Modern Economics
Problems in Indian Economics
इन्डस्ट्रियल माञ्चम्स आव इविडया (संगदित)
इविडया विरुट्ड इर वार इकानमी
आधुनिक अर्थशास्त्र (सर्-लेखक : श्री आर० एन० भागव)

# भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ

भाग १

पी. सी. जैन, एम. ए., एम. एस सी. (अर्थशास्त्र) लन्दन, अर्थशास्त्र विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

१६४६

चैतन्य पब्लिशिंग हाउस ५-ए, यूनीवर्षिटी रोड, इलाहानीद सर्वाधिकार सुरक्षित

द्वितीय संस्करण १९५५ जितीय संस्करण १९५७ चतुर्थं संस्करण १९५६

प्रथम संस्करण १९५३

# विषय-सूची

भारताय

શ્રુષ્યાય	-
१. भारतीय ग्रथंशास्त्र का ग्रथं	8
२. प्राकृतिक साधन	6
३. जन संख्या	₹=
<ul><li>सामाजिक ग्रीर धार्मिक व्यवस्थाएँ</li></ul>	२६
कृषि तथा सहकारिता	
५. क्वांप उत्पादन श्रीर नीति	\$4.
र्द. जमीन्दारी उन्मूलन	પ્રશ
र्थ. भूमि को चकमन्दी	ሂ⊏
<ul><li>मृमि इरण</li></ul>	६६
E. विंचाई	७१
<ol> <li>बहुउदेशीय योजनाएँ श्रीर बाढ़ नियत्रण कार्यकम</li> </ol>	66
११. सामुदायिक विकास ये।जनाएँ	<b>E</b> E41
१२. सहकारो भ्रान्दोलन	88
<b>१३.</b> सहकारी विकय	१०६
१४. सहकारी कृषि	११६
१५. सहकारी अधिकीपण्	188
१६. भूमि बन्धक वैंक	191
रे७. माग्य वित्त व्यवस्था	3,50
<b>१</b> ⊏. कृषि नियोजन	१५१
ध् उद्योग तथा मजदूर	
√É. बड़े पैमाने के उद्योग	341
र्ज. छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योग	131
२१. श्रीदोगिक उत्पादन श्रीर नियोजन	208
२२. सरकार की ऋौद्योगिक नीति	295

# (=)

श्रध्याय		â
₹₹.	मैनेजिय एजेन्सी प्रणाली	221
74.	द्योद्योगिक विच निगम (कार्पोरेशन)	789
24	विदेशी पूँजी	रप्
२६.	उद्योगों का स्थान निर्धारण	२६१
20	युक्तिकरण	205
२⊏	बेरोजगारी की समस्या	२दर
₹€.	. श्रीद्योगिक गृह्-निर्माण	784
Ş٠.	श्रमिक की कार्यच्या	70€
₹₹.	न्त्रीचोगिक सम्बन्ध	935
ई२,	्रद्रेड यूनियन	\$9\$
	यीवर्ष्यान	
₹₹.	•	222
١¥,	सङ्क यातायात	₹Y5
<b>३</b> ५.	जल यातायात	<b>4</b> 88
<b>₹</b> Ę,	इवाई यातायात	₹७१
₹७,	यातायात का परस्पर सम्बन्ध श्रीर नियन्त्रोन	
	नियोजन	
₹<.	प्रथम पंचवर्षीय योजना	
38.		
٧٠.		¥53
	•	• • • •

#### श्रध्याय १

# भारतीय अर्थशास का अर्थ

े अर्थवाल की अर्थवन की बुविधा के लिए दो मागों में बाँटा गया है जिनमें से एक भाग 'खेंद्रानिक अर्थग्राक' (Theory of economics) और दूसरा माग क्यवहारिक अर्थग्राक' (Applied economics) कहा जाता है । वैद्यानिक अर्थग्राक भें हम कुछ ऐसे आधारमूत विद्यानों का अर्थयम करते हैं जो आवश्यक आरोत में हम कुछ ऐसे आधारमूत विद्यानों के अर्थवराम करते हैं जो आवश्यक लाओं (wants) को पूर्ति के ध्ववरा में मानुष्ण के ध्ववरा को विवेचना करते हैं वि के कि उद्देश दिवे हों और उत्वर्धन पूर्ति के सावन अर्थाम हो ति अर्थाम में इन आधारमूत विद्यानों को हम उत्पादन, उपभोग विनिम्म अर्थी। द्वारण के अन्यवर्धन करते हैं। बीमात उपभोगिता के हाल का निवम, उत्पादन के तियम, लगान का विद्यानत और रोजनार तथा व्यवसाय चक्क के विद्यान अर्थग्राक के इन आधारमूत विद्यानों के ही उदाहरण है। इस वैद्यानिक अर्थश्यक्त का अर्थश्यक किय तथा से दि रोतिहारिक होस्कों से कर ककते हैं या विश्वतेष्णात्मक हिस्स दे रोतिहारिक होस्कों से कर ककते हैं या विश्वतेष्णात्मक हिस्स तथा के विचारपात का इतिहास वैद्यान के बाता के विद्यान किया जाय तो इसका कर्म 'अर्थग्राक की विचारपात (Analytical Economics) जेवा हो जाता है किसे संकेष में केवल अर्थग्राक भी कहते हैं।

व्यवहारिक छथेगाल वैकानिक छथेगाल से बिल्कुल भिन्न है। इवने उन समस्यात्रों का अध्ययन किया जाता है जो मानवीय आयश्यक्ताओं की पृति के प्रयस्तों के बीच पेदा हो जाती है, जैमे कृषि और उद्योग की समस्यायें, उत्पादन, आपात और निर्मात, बैंक और मुद्रा व्यवस्था, आर्थिक नियोजन, आहि। सिहानिक अर्थराह्म की भौति, व्यवहारिक अर्थशास्त्र का अध्ययन हम पेतिहासिक हिस्कोय से मी कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र 'आर्थिक इतिहास', (Economic History) का रूप धारण कर खेता है। यदि विश्लेषण की हाँच्ट से अराययन किया जाय तो यह 'वर्तमान आर्थिक समस्याओं के अध्ययन' का रूप से सेता है।

धिद्यान्तिक प्रयोशास्त्र की उत्पन्ति वास्तव में मनुष्य के व्यवदार के कुछ आशारमूत विद्यान्ती ज्ञीर जनता की द्यापिक स्थिति के आधार पर होती है। उदा-दरण के लिये, प्राचीन अर्थशास्त्र के विद्यान्ती पर इंगर्लैंड की १८ वीं शताब्दी की परिस्थितियों का बहुत प्रमाव पड़ा। इसके बाद जनता की व्यधिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप आर्थिक खिदानों में मी संशोधन परिवर्तन होते गये। जैसे हो नयी परिस्थितियों उत्पन्न हुई उनकी ब्याख्या करने के लिये या तो पहले के आर्थिक खिदान्तों का जिस्सा गया या नये खिदान्तों का जन्म हुआ। इस बर्दमान की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर के लिये या तो पहले के आर्थिक खिदान्तों का जन्म हुआ। इस बर्दमान की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर के लिये या आर्थिक इतिहास लिखने के लिए आर्थिया कर से स्थापन के लिए अर्थिया के सिद्धान्तों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार यह स्वय्ट है कि सिद्धान्तिक और व्यवहारिक अर्थियाल में सरस्य धनिष्ट सम्बन्ध है।

भारतीय अर्थशास्त्र—मारतीय अर्थशास्त्र व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक अक है । हक अन्वर्यत वर्तमान समय की विभिन्न आर्थिक समस्याओं ना अर्थ्यत किया नाता है, जैसे, वक्कर्यो, भूमिन्नस्य, मैनेकिय प्रवेन्नी प्रणाली, हसाहि और साथ ही उनकी उत्तरिक कारयों का भी विवेचन किया जाता है। इस अर्थ में मारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ्ययन विश्लेषशास्त्र को नाता है। इस अर्थ में मारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ्ययन विश्लेषशास्त्र को नाता है। इसमें मह प्रवत्त किया जाता है कि वर्तमान आर्थिक पंशिक्षत्रियों ना सही सही चित्र प्रस्ता काय, विश्लेष पटनाइयों के कारयों को सम्भावना यो, वह चयो नहीं हुई। वर्तमान समय की समस्याओं को अर्थ्यस्त्र करने और इसम की समस्याओं को अर्थ्यस्त्र करने और इसम की समस्याओं को अर्थ्यस्त्र करने और इसकी भावी प्रवृत्तियों का पता लगाने में हम शैक्षतिक अर्थशास्त्र की सहयाया सेते हैं। यह अर्थशास्त्र के एक्सर्वा भावी प्रवृत्तियों का पता लगाने में हम शैक्षतिक अर्थशास्त्र की स्वरायन वहते कुछ इमारे सेत्रात्र का अर्थ्यस्त्र करने होरे इस विम्य परिलामों पर पहुंचते हैं वह मो अत्रस्य कि अर्थशास्त्र के स्वर्थ कर अर्थशास्त्र का अर्थ्यस्त्र कर अर्थशास्त्र का अर्थ्यस्त्र कर अर्थशास्त्र के स्वर्थ कर करने प्रति हम परिलामों पर पहुंचते हैं वह मो अर्थ कर अर्थशास्त्र के स्वर्थ कर इस्तर है। कि स्वर्थ कर अर्थशास्त्र के स्वराय के स्वर्थ पर स्वर्थ है स्वर्थ कर अर्थ का अर्थ्यस्त्र वह स्वर्थ के स्वर्थ पर स्वर्थ है भारत में विभिन्न आर्थिक समस्याओं के

होतिहारिक विकास का अध्ययन 'भारत का आर्थिक हतिहासे कहा जाता है। आराति वाहा है। आराति है। आराति आराति है। आराति आर्थिक हतिहासे कहा जाता है। आराति आर्थिक हतिहासे कहा जाता है। आराति आर्थिक हितासे कही जाता है। आराति आर्थिक हतिहासे अर्थिक आर्थिक हतिहासे अर्थिक आर्थिक हतिहासे अर्थिक आर्थिक हतिहासे अर्थिक हतिहासे अर्थिक हतिहासे अराति हतिहासे अराति हतिहासे अराति हतिहासे आरावि हतिहासे हति

अपरेशाल को एक में मिला हैं तो वर्तमान आर्थिक एमस्याएँ, जिन पर पाठक को अपरिक हितहार के विस्तृत विवेचन में स्वान देना आवश्यक है, सारत के आर्थिक हितहार के विस्तृत विवेचन में हुत हो जातो है। इसिलये इस पुस्तक में यह प्रयत्न किया गया है कि लाती है। इसिलये इस पुस्तक में यह प्रयत्न किया गया है कि मारतीय अपरेशाल की समस्याएँ आर्थिक हतिहाल के विस्तृत वर्णन में लोन आर्थिक जाई। जहाँ आवश्यक प्रतीत हुआ है वहाँ तुलतालक अध्ययन के लिये आर्थिक हितहाल का कुल चिरतृत वर्णन किया गया है। परन्त जिशेष जोर मारत की हतिहाल का कुल चिरतृत वर्णन किया गया है। परन्त जिशेष जोर मारत की हतिहाल का कुल चिरतृत वर्णन किया गया है।

अन्य परिभाषार्थे—पूर्व लिखित परिमाया के अनुसार भारतीय अर्थशास्त्र भारत की वर्तमान आपिक समस्वाओं का अध्ययन है। परम्तु भारतीय अर्थशास्त्र की हमके अतिरिक्त तीन और परिमाषार्थे हो गयी हैं:—

(१) भारत की आर्थिक विचारभाग के विकास के अध्ययन को भारतीय अर्थशाल कहा गया है। प्राचीन भारत में वैद्धानिक अर्थशाल के सरक्ष्य में बहुत अर्थशाल कहा गया है। प्राचीन भारत में वैद्धानिक अर्थशाल के सरक्ष्य में बहुत कुछ लिखा गया था। भारतीय आर्थिक विचारभार। पित्रचनी आर्थिक विचारभार। कुछ लिखा गया था। भारतीय अर्थिक विचारभार। कुछ ने में अर्थशाल के रिव्हानती के चेत्र में मानत ने अवस्य कुछ ने गदानिक हुग है। वर्षि लाव तो भारतीय आर्थिक विचारभार। पूर्वतया प्राचीन भारत की देन है। वर्षि लाव तो भारतीय आर्थिक विचारभार। पूर्वतया प्राचीन भारत की देन है। वर्षि यह मान भी लिया लाय कि भारतीय आर्थिक तिचारभार। आर्थिक विचारक अर्थशाल का अर्थशाल के साथ विकास कर एकी है तब भी हम उसे मारतीय अर्थशाल का एक माम नहीं दे छकते हैं क्योंक भारतीय अर्थशाल व्यवहारिक अर्थशाल का एक प्राची के कि कि आर्थिक विचारभार। का हितहास, चाहे वह भारतीय हो या पूरी-पीय, विद्यानिक अर्थशाल के अर्थाल कहा कि आर्थिक विचारभार। का हितहास, चाहे वह भारतीय हो या पूरी-पीय, विद्यानिक अर्थशाल के अर्थाल है।

(२) वह कहा गया है कि भारत को सामाजिक और सामिक नियति एक निरोप प्रकार की है, उसकी गठन और उसमें निहित विचारवारा अन्य देशों से निरोप प्रकार की है, उसकी गठन और उसमें निहित विचारवारा अन्य देशों से निरोप प्रकार के मिल है दर्शकिये मारतीय परिस्पितियों के अनुकूल होने देशकुल हो नये प्रकार के आर्थिक विद्वारों का सुकत करना चाहिए और उसे 'भारतीय अर्थशाक' करना आर्थिक विद्वारों के मारत की रियति विद्यार्थों से नितान्त भिन्न है, प्रतिवर्शावता (Competition) से कहीं अधिक प्रमावशाकी यहाँ के रीति-विद्यार्थ और राज्य के नियम है, वाय हो किसी अभक्तिते की अपेदा समाज से समामा अधिक प्रभाव रखता है। यहाँ न पूँ जी समझीते की अपेदा समाज से समामा अधिक प्रभाव रखता है। यहाँ न पूँ जी गाविशांल है और न अम और न इनमें इतना उत्पाह (enterprising) और गाविशांल है और न अस और न इनमें इतना उत्पाह (enterprising) और अदि हो है कि गतियोंल वर्षे। माजदूरी और लाम भी निश्चत है; जनसख्या असि हो है कि गतियोंल वर्षे।

श्रपने नियम के श्रनसार बहती जाती है परन्त बीमारियों और श्रकाल से उसमें कमी भी होती रहती है, उत्पादन की मात्रा प्राय: स्थिर है, यदि एक वर्ष फछल श्चन्छी हो गयी हो यह अगले वर्ष के छानिश्चित मीसम से होने वाली हानि की पति का साधन बन जाती है। इसके आधार पर न्यायाधीश रानाडे इस परिसाम पर पहुँचे कि शाधनिक शर्यशास्त्र के सिद्धानतों में जिन वातों को निश्चित शाधार मान लिया गया है वह भारत में लागू ही नहीं होती बल्कि वह बास्तव में गलत दिशा की ब्योर से जाती हैं। इससे कल लोग इस परिकास पर पहेंचे कि भारत की आर्थिक स्थित को समझने के लिये नये आर्थिक सिद्धानती की आवश्यकता है। बास्तव में स्थित ऐसी नहीं है। कोई भी खार्थिक सिटास्त, चाहे वह पश्चिमी देशों में विकतित हुआ हो या पर्वी देशों में, न्यापक रूप में खारे विश्व पर लाग होता है। खार्थिक सिद्धान्त मनव्य के स्वभाव पर खाधारित होता है और मन्द्रप का स्वभाव सर्वेत्र समाज होता है। यदि ग्रार्थिक सिटाउन का असित जिल्लाग किया गया है तो बह सर्वत्र लाग होगा । परन्त यह शानमा परेगा कि छार्थिक चिद्यान्त स्थिर चिद्यान्त नहीं होता छोर न वह अपरिवर्तनशील ही होता है। यदि श्राधिक स्थिति मे परिवर्तन हळा तो आर्थिक सिद्धान्त मे भी परिवर्तन होगा । इंगलैंड में प्राचीन सैद्धानिक वर्षशास्त्र का जो विकास हवा वट इंगलैंड की उस समय की द्यार्थिक रिवनियों वर द्याधारित था । वह यह भाव्य नीति (Laissez faire) और स्वतंत्र व्यापार (Free trade) के विद्यान्तों पर आधारित था। परन्त बाद में जब विशेष रूप से यरोपीय देशों में यह पता चला कि स्वतंत्र ब्यापार आर्थिक परिस्थिति के प्रतिकृत्त है तो फ्रीड्रिक लिस्ट तथा अन्य आर्थ-शास्त्रियों की श्राक्षोचना के श्राधार पर स्थलत क्यापार के विद्यान्त में श्रावश्यक संग्रोधन किया गया श्रीर कम विकसित देशों के सरहरण के लिये तटकरी (Tariffs) तथा ग्रन्य उपायो का महत्व स्वीकार किया ग्रामा । शोवियत सघ की परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ समाजवाद और शार्थिक नियोजन के सिद्धान्तों में भी परि-वर्तन होता गया। इधर कुछ वर्षों से पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी पशिया के श्रार्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए चेत्रों की ऋार्यिक समस्याओं के कारण आयिक विदान्तों में परिवर्तन-परिवर्द्धन हो रहा है। भारत में आध्यात्मिक विचारधारा से प्रभावित 'आवरयकता' का एक विल्कल नया सिद्धान्त विकसित हो रहा है जिसे 'आवश्य-कता रहित होने का विदान्त' (Theory of wantlessness) कहा जाता है। यह पश्चिम के ग्रावर्यकता क विदान्तों से निवान्त भिन्न है। यह वभव है कि विभिन्न देशों को बदलती परिस्थितियों से प्रभावित हाकर, जिनमें भारत भी समितित है, भविष्य में अर्थशास्त्र के सिदान्तों में और भी संशोधन हो । परन्त

जातिवाद, संपुक्त परिवार को प्रथा, अम और पूंजी में यतियीलता का अमान, इत्यादि इस बात को सिंद नहीं करते कि इस देश के लिये नये प्रकार के आर्थिक सिंदान्तों की आपश्यकता है। माँग और पूर्ति का सिंदान्ते वितना भारत में लागू होता है उतना ही अन्य देशों में भी लागू होता है। इसलिये हमारी भारत की भिन्न परिस्पतियों के कारण नये प्रकार के आर्थिक सिंदान्तों और नियम करें को माँग उनित नहीं है, साथ है इन वियोग सिंदान्तों और नियमों को को देवल अगत में लगा होते है।

(१) यह भी कहा गया है कि वांद उपमोग, उत्पादन, बिलिमय श्रीर वितरण के श्रापिक विश्वान्तों का विवेचन मारतीय उदाहरणों के साथ किया गया हो तो उसे भारतीय श्राप्तीक करा जाना चाहिये। किसी भी विश्वान्त की त्याह कर से समक्ताने के लिये निश्वान्त ही कुछ उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है परन्त इससे ही यह भारतीय श्राप्तीक्षण नहीं हो जाता। यदि कोई पाट्य पुरतक श्रीज वियाधियों के लिये लिखे नाय तो यह स्थाभाविक ही है कि उसमें श्रीजी या रंगलैंड के उदा- रंग्य दिये जावेंगे। इसी प्रकार विद् कोई पाट्य पुस्तक भारतीय विश्वाधियों के लिखे जाय तो उसमें भारत के उदाहरण श्रिय जावेंगे। परन्त इतने से ही नहीं जी श्रयंशाक्षण, था 'मारतीय श्राप्तीक्षण नहीं वन जाते। इन परिस्थितियों में वह श्रिकी श्रयंशाक्षण, था 'मारतीय श्राप्तीक्षण नहीं वन जाते। इन परिस्थितियों में वह श्रिकी श्रयंशाक्षण, था 'मारतीय श्राप्तीक्षण निर्मा किसी भी रेश के उदाहरण हैये गये हैं।

इ छत्ते त्यष्ट है कि भारतीय क्रायंश्वाक भारत की वर्तमान क्राधिक छमस्याकों का ठीक वैद्या हो अध्ययन है जैद्या अन्य देशों में किया जाता है। यत्तेमान आर्थिक छमस्याकों का अध्ययन करने के लिये अन्य देशों की मौति ही भारत में मी इम देश की छमस्याओं पर उन आर्थिक छिद्यान्तों को लागू करते हैं जो वर्षण बरर रिवह हो जुडे हें या उन्हें सभी स्त्रीकार करते हैं। इछलिये अर्थाताल के आर्थिक छिद्यानों को भारत की आर्थिक स्थिति वर लागू कर इम जिन परियामों पर पहुँचने हें तथा जिन प्रवृचियां का यता लगाते हैं उनको 'भारतीय अर्थगाला' करते हैं तथा किन प्रवृचियां का यता लगाते हैं उनको 'भारतीय अर्थगाला' करते हैं तो यह निवास्त नगायवंगत है।

भारतीय वार्यशास्य के वार्ययन की वार्यप्रकार

(१) यदि इन अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सही सही समझना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इस भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करें। इसके अध्य-यन से हम यह जान सकते हैं कि इस प्रश्नति कर रहे हैं या नहीं, यदि कर रहे हैं तो किस सीमा तक और यदि प्रगति नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण वया है है

## प्रस्तीय सर्वेशास्त्र की सप्रस्थातें (२) भारतीय द्वार्थशास्त्र के अध्ययन से हम अपने देश की अन्य देशों के साथ

तलना कर सकते हैं और इस प्रकार की तलना से यह जान सकते हैं कि हम किस प्रकार तथा किस दिशा में सक्रिय होकर अपनी कमियों को दर कर सकते हैं और द्याधिक उर्जात के खमीए स्तर को मास कर सकते हैं। (३) भारतीय खर्यशास्त्र का

श्रास्ययन करके ही हम भविष्य के लिये अपनी नीति निर्धारित कर सकते हैं। प्रश्न-वर्षीय योजना तैयार करने में और योजनाओं को प्रमुखता देने में योजना जायोग

को भारतीय धर्मशास्त्र के खय्ययन पर ही अपने निर्मायों को आधारित करना पका। भारत के आर्थिक विकास में जो बटियाँ रह गयी है तथा आयोग ने

आर्थिक प्रगति की वाखित गति से उन्हें दूर कर देने के सुकाव भारतीय श्रथंशास्त्र के भारत्यान के आधार पर ही दिये हैं।

#### ष्ट्रधाय २

## प्राकृतिक साधन

#### भौगोलिक स्थिति

किसी देश के निवासियों की आर्थिक स्पितितथा उनके व्यवसायों पर उस देश की भीगोलिक स्पिति, भूमि की उपजाल शक्ति, वर्षां, जलवायु और उसकी बनस्पति तथा उनके बन्य एयम् पालन् प्युओं का विशेष अभाव पहता है। इस-लिये भारत की भीगोलिक स्थिति का अथ्ययन करना आवश्यक है।

भौतिक विशेषताएँ—मारवीय संव का ज्ञेषका १२६६६५० वर्ग मीत है । उत्तर से दिविण तक इस देश की लम्बाई २००० मील और पूर्व से पिक्षम तक १७०० मील और पूर्व से पिक्षम तक १७०० मील और पूर्व से पिक्षम तक १७०० मील है। इसकी भीतिक सीमा ६२०० मील है। कर्क रेखा इसकी भीवो-बीच से दी भागों में बाँटवरी है। उत्तरी भाग सीतोच्या कटिवरूप में छीर दिविणों उच्या कटिवर्ग में सिद्ध है। अम्बु अर्थ काइमोर सामा कटिवरूप में छीर दिविणों उच्या कटिवर्ग में रिच्छ है। अम्बु अर्थ काइमोर सामा कटिवरूप में छीर्मित काँग दावर सहित भारत संघ में राज्यों के दुन-संक्षठन के पूर्व २८ राज्य थे। १ मयम्बर १६५६ में राज्यों का पुनर्यंगटन होने के पक्षात् अब भारत संघ में १४ राज्य यथा आँख मदेश, सहाय, ममई, मैसर, उक्रीय, प्रवास्त्र , ज्ञास्त्र , प्रवास्त्र , प्रवास्त्र , व्या कट्मीय म्हास्त्र, क्रास्त्र, क्रास्त्र, क्रास्त्र, सामा कट्मीय, प्रवास्त्र के दिक्की, (स्मोचल प्रदेश, मसीपुर, मिपुरा, अंक्षमन-निकोगर हीय स्वस्त्र और वेक्सिवर, मिनिकाय, प्रसिन्दियों हीय समूद नागक ६ प्रदेश हैं।

भारत उत्तर में हिमालय, उत्तर-धिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व में पर्वत-श्रीपार्यो, दिक्षण में बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर और पिश्रम में अरब सागर द्वारा पिरा हुआ है। भारत को चार विभिन्न भीगोलिक भागो में बाँटा जा खकता है (१) हिमालय, (२) गज्ञा का मैदान, (३) दिक्षणी पढार, (४) तटवर्ती मदेरा। हिमालय की श्रीपार्थ १५०० शील की लक्षाई में और १५० भील ते लगा कर २५० भील तक की चौड़ाई में फैली हुई है। हिमालय उत्तर की भर्मीली वाय ते तथा उत्तरीय विदेशियों के खाकम्य से मारत की बदा से रज्ञा करता आया है। इंचके कारण उत्तरीय थीगा के मार्गो से ज्यापार में भी बावा पहुंची है। मार्ग-स्त को रोक कर मारत के उत्तरीय थाग की बचुर वर्ष का साथन हिमालय ही सहा है। मारत को खनेको निर्यों का उद्गम हवी मारा से हुआ है। यहाँ बहु- मूल्य यन पाये जाते हैं जिनका पूर्ण प्रयोग होना अभी वाकी है। इसका ऋि कांस माग काश्मीर और जम्मू की झाटियों तथा पूर्वीय चाय के चेत्रों को छोड़कर खेती के जायोग्य है।

गङ्गा का मैदान पूर्व से पश्चिम की खोर लगमग १५०० मोल लग्मा और उत्तर से दक्षिण की छोर १५० से लगाकर २५० मील तक जोड़ा है। यहाँ अनेकी नर्दियाँ अपनी प्रशुपक नांद्यों के लाथ बहती हैं। यहाँ की भूमि बहुत उपकाक है और इसीलिए यहाँ की कमसंख्या का प्रमान भी स्वसं अधिक है। देश के महुत बहु-बहु नगर इसी आग में स्थित है।

पठारी माग जो विध्याचल पर्वत शेखी के दक्षिण में स्थित है, दो भागों में साँटा जा सकता है। (ख) मध्य मारसीय पठार खोर (ब) दक्षिणी पठार।

पठारी भाग गङ्गा के बैदान के विषयीत झालेश पदी शियारों से मरा हुआ है। इनकी केंचाई १५०० से ४४०० फीट तक है। इस भाग के दोनों आर पूर्वीय और पश्चिमीय पाट की पर्वत केंयियों हैं। एठार स्वयं पयरीला और केंचा-नीचा है। इसका विस्तार पूरे दिख्य की पहांक्यों तक है जो कही-कही पर ४००० फीट केंची हैं जैसे नील पाठी और कार्डमास की पहांक्यों। इस पठार से होकर ममेदा और सामी निदयाँ वहती हैं जो खरब सामर में गिरती हैं और महानदी, इच्या तथा कार्वरी को थंगाल की लाबी में गिरती हैं। बनते की इस पदेश में कमी है पर जीनज पदार्थ पर्यात सामा में मिलते हैं। उन्नती तट कट दुए नहीं हैं। इसलिये स्थामांक्क प्रवर्गात समाम में मिलते हैं। उन्नती तट कट दुए नहीं हैं। इसलिये स्थामांक्क प्रवर्गात केंचल विज्ञापद्धा, कोचीन और कालीकट हैं। पूर्वी और पश्चिमी तटों की भूमि उपजांक है। वहाँ पर्यात वर्षा होती है तथा चाक्क चाम छीर कहवा मैदा होता है।

जात वार्य करित कर्या करित की जलवायु मानसूनी तथा उच्च मदेशीय है। यहाँ की लीन प्रमुख ऋतुर्वे निभन है: (१) मार्च के झारम्भ से जल के झन्त कक मार्ग की ऋतु, (२) जून के झंत के किस्मद के झंत तक वर्षा मुद्र और (१) अन्य के झारम्भ से जल के झन्त कक मार्ग की ऋतु, (२) जून के झंत के किस्मद के झंत तक वर्षा मुद्र आप्रेल और मर्द के मर्दा में मंद्र की किर में मर्द की किर में मर्द की में में मर्द की में मर्द की स्था के किर में मर्द की में मर्द की मर्द के मर्द के मर्द में मर्द की है। अप्रकार मर्द के किर में मर्द की मर्द के मर्द में मानसूनी हमार्थ चलने लगती है। अप्रकार के साथ मर्द मानसूत हमार्थ चलने लगती है और विजली की चमक के साथ मर्द् का साथ मर्द होत है। अप्रकार वर्षा विच्यी-मर्द्य मंत्र मानसून हमार्थ मर्द होती है। अप्रकार वर्षा विच्यी-मर्द्य मंत्र मानसून हमार्थ मर्द होती है। अप्रकार वर्षा विच्यी-मर्द्य मानसून हम्बन के कारण होती है। अपराम्य मंत्र हम्बन की की साथ मर्द हमार्थों मानसून हम्बन की की साथ मर्द हमार्थों मानसून हम्बन की कारण होती है। अप्रकार वर्षा विच्यी-मर्द्य मानसून हमार्थों मानसून हम्बन की कारण होती है। स्वावकाल में

योजनायें तीन या चार पंचवर्षीय योजनाओं के श्रन्त तक पूर्ण हो जायेंगी तब विद्युत शक्ति लगभग ७० लाख किलोबाट बढ़ जायगी। हमारे देश में समस्या केवल श्रांपिक विद्युत शक्ति के उत्पादन की ही नहीं है वस्त् यह भी है कि विद्युत शक्ति पत्यों साम मात्रा में इतने सक्ते मृत्य पर लोगों को शप्त हो सके कि किलान, क्रींवरी वाले श्रीर श्रुत्य सामारण कारीगर उसका श्रांपानी से प्रयोग कर सकें।

## धनस्पति श्रीर जानवर

विशाल चेनफल, विभिन्न मौगोलिक रियतियों, विभिन्न जलवायु इत्यादि के कारण मारत में वे सब प्रकार के वन, फलों के बाग, और खेती की उपन जो प्रायः उच्या, शांत और वमशोतोष्य जलवायु बाले मूं-बेनों में वाये जाते हैं प्राप्त हैं। देश में वालत् तथा यन्य पश् भी अनेक प्रकार के भिलते हैं।

वस—भारत में बनों का चेत्रकल लगमग १४ करोड़ ७७ लाल एकड़ है, जिसमें से ४ करोड़ ३५ लाल एकड़ जंगल दिख्यों भाग में, ३ करोड़ ३५ लाल एकड़ जंगल दिख्यों भाग में, ३ करोड़ ३५ लाल एकड़ मत्यम भाग में, ३ करोड़ ६८ लाल एक मत्यम भाग में, ३ करोड़ ६८ लाल एक एकड़ उद्यो-पित्वमं भागों में दिवत हैं। दितीय महायुद के समय और अमेक राव्यों में नमींदारी उन्मृतन के पूर्व बहुत वहीं विद्या में उन्च कार आप होते हैं। तमने देखन बहुत काम दो गया है। तमने देखन और हमारतों लकड़ी तो मत होती है, इवके अतिरिक्त (१) वे अविवेशिक उपयोग के लिए वाँड, वार्य एडिंग इंग्रेट एसाई व अम्प यार्स, लाल, गोद हत्यादि मी अम्दान करते हैं, (२) वे मूमि-प्राप्त (Soll cossion) रोहते हैं, मूमि की उत्येश को सुरस्वित रखते हैं, और (३) प्रश्ली के लिए चरागाइ भी प्रहान करते हैं।

वन राष्ट्रीय खाय के अत्यन्त महत्वपूर्ण शावन है। उनसे उद्योगों के लिए अनेक कच्चे माल प्राप्त होते हैं। मारत के बनों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याएँ यह है हिं; (१) वनों के जीनफल में बृखि की जाय, (१) देश में जितने प्रकार के इस पाए जाते हैं उनका संरक्षण किया जाय और (१) यथासंभय नहें जाति के इस भी उनाने प्रारम्भ हों। गाउत सकार ने उन मीति के सम्बन्धित नहें राहित के स्वस्ताव में भारतीय बनों की सुरन्ना और उनके विकास की आवश्यकता पर प्यान दिया। उन प्रस्ताव में यह तथ्य रखा गया कि देश की सुद्ध भूमि का एक-तिहाई भाग वनों के रूप में रहे। हिमालय-प्रदेश, दिख्य और अन्य पर्वतीय देशों पर बनों के अध्यस्तत कुल भूमि का च-% रहेगा, जन कि समतल चेत्रों में कुल भूमि २०% पर जंगल उमाए जायेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनों की विकास सम्बन्धी मीति के बान्तर्गत यह ब्यवस्था रखी गई थी कि (अ) यह के समय में जो भाग बिल्कल उजह गए थे. उनका नवकरण (renovation) हो. (व) जहाँ अधिक मात्रा में भूमि-सारण हन्ना था. वहाँ जगल लगाए आयें. (स) वनों में श्रावारामन के साधनों का विकास किया जाय, (द) ईंधन के श्रामान की दर करने के लिए गाँवों में छाधिक बाग लगाए जायें. और (य) कई प्रकार की ऐसी लकड़ी, जो खब तक हमारती लकबी के रूप में काम में नहीं छा रही थी. उसे ठीक दंग से जिसाने श्रीर समाला लगाकर सजबत बनाने के बाद श्राधिकाधिक प्रयोग में लाया जाय। राज्य सरकारों की बन-सम्बन्धी नीति न तो मई १९५२ के धन-नीति से सम्बन्धित प्रस्ताय के बिल्कल अनुकल है और न बनों को बेन्द्रीय समिति (Central Board of Forests) के अनुस्य है। इस यन फेन्द्रीय समिति की बैठक जुन १९५३ को देहराइन में हुई थी जिसने कई प्रस्तान पास किए श्रीर जिसका उद्देश्य यह था कि राज्य सरकार आरत-सरकार की सन-बीति की कियात्मक रूप दें। १९५० में भारत-सरकार ने 'बन-सहीत्सव आन्दोलन' प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य यह है कि मारत से जंगलों का अभाव दूर किया जाय। किया, जिसका उद्देश्य यह है कि मारत से जंगलों का अभाव दूर किया जाय। किंद्र अभाग्यवश इस कार्य-क्रम के अंतर्गत लगाए गए अधिकांश वृक्ष पानी न मिलने श्रीर लापरबाडी के कारण सख गए । श्रधिक बन्त सगयाना श्रीर जब तक वे काफी बड़े न हो जाय इनकी देख माल करते रहना तो द्यावश्यक है ही, किंत उसके साय-साथ यह भी श्राहराक है कि ईंधन श्रापया श्रान्य किसी उपयोग के लिए खंदे वस न करवाए नार्य। सळ्ली-डद्योग— "भारत के लम्बे शमुद्र-बट पर ऋषंख्य मुहाने, नमकीन

खबें इच्च न करवाप नार्व ।

मळ्ती-डवान - "मारत के लम्मे शमुद्ध-वर पर अर्थस्य मुहाने, नमकीन
पानी वाशो में सीरे स्थिर नलाशय है, जिनसे काफी मळ्लियाँ प्राप्त होती हैं।

नमकीन पानी धांका चैन लगभग १० करोड़ ६० लाल एक्ड है, जिसमें चिल्का
भील मी शामिल है। यह चिल्हा मील २,४६,००० एकड़ के विस्तार में फैली
हुई है और इच्छे मतिवर्य ३,००० रन मळ्ली प्राप्त होती हैं। मळ्ली-उयोग से
भारत की राष्ट्रीय-प्राप में प्रांतवर्य १० करोड क्यमे आते हैं। मळ्ली-उयोग से
भारत की राष्ट्रीय-प्राप में प्रांतवर्य १० करोड क्यमे आते हैं। यह मळ्ली-उयोग से
भारत की राष्ट्रीय-प्राप में प्रांतवर्य १० करोड क्यमे आते हैं। महत्वी विकल्का
सुख्यतः हो प्रकार का है: (१) देश के अरद का मळ्ली उयोग (inland
fisheries), (२) छम्डी मळ्ली-उयोग (marine fisheries)। मळ्ली वकड़ने
के खाँकड़े मारत में विश्वतत रूप से प्राप्त नहीं हैं। भारत में प्रतिवर्य समुश्री मळ्ली
हार्यों का उत्पादत सम्माग २०० लाल मन है और वाने पानी को मळ्लीवर्यों को
भितानर सारत में प्रवियं ए०० लाल मन छी कुल पूर्वि होती है, जिसमें से ७०%
मुहाने और एस्ट्रद को मळ्लियाँ और रोप २०% ताने पानी की मळ्लीवर्यां होती हैं।

इसका अर्थ यह है कि प्रतिवर्ष पति क्यांत को ३४ पीड महाली मिलती है, जो निश्चित रूप से अपवास है। उत्तरप्रदेश कोर पंजाब की अपेनाहत द्रायनकोर को जान, पश्चिमी बंगाल और बन्धई में प्रति ब्यांक महाली का उपयोग अधिक है। गर अनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवणीय योजना के आरम्भ में महाले में प्रति व्यांक महाले आरम्भ में महाले से कुल उत्स्वि क्यमम १० लाल मीट्रिक टन थी जिसका २०% परंतु उपयोग के नियं पी ओर बाकी छनुती महाले अपवा बेचने के लिये देश के अंदर के प्राप्त महालियों थीं। प्रथम योजना के कलस्वरूप ऐसा अनुमान किया जाता है कि महालियों भी उत्पत्ति १०% वर्ष जायगी। १९५५—५६ में महालियों की उत्पत्ति ११ लाल लाल मिट्रिक टन से कुछ अधिक थी। दृष्टी पंचवर्षीय योजना में महालियों का उत्पत्ति हम लाम मीट्रिक टन हो लायगा। अर्थात् १४ लाल मीट्रिक टन हो लायगा। इस्पी पंचवर्षीय वोजना में प्रति का जायगा। वर्षीमान सम्प्र में प्रति व्यक्ति महालियों का वार्षिक उपमोग प्रयोग कि सहित प्रतिवर्णी का वार्षिक उपमोग यहाया जाय।

सप्तरी महालियों के उत्पादन को बहाने के लिए यखली पकड़ने में वैशानिक संगी के प्रयाग करने को आवश्यकता है, बवों कि सभी तक एक सीमित स्त्र में ही महालियों का विकार किया जाता है। वहीं तक देश के अंदर महली पकड़ने का स्वक्ष्म की ता किया जाता है। वहीं तक देश के अंदर महली पकड़ने का स्वक्ष्म के हात की आवश्यकता है कि महालियों वा पोपण करने और उनके किया करने को लिया। "भारत के वर्तमान जलाशयों में प्रमुख रूप से तालान और फीलें आती है। कार्य (Carp) महालियों बहुया मारतीय सप्तरों में पांपत होती है। वृद्धि वह में हुये पानी में अंदे नहीं देती, हंगीलिये उन्हें मतिवयं पेशित करने की आवश्यकता होती है। यदि वैधे हुए पानी में कार्य महाली में अंदिम अवश्रीवायता (artificial spawning) को पिफिल किया जाता है वा उन्हें भविष्य में साने महाले के कृतिम अवश्रीवायता (artificial spawning) को पिफिल किया जाता है या उनके किया जाता है या नमक में विकार के सीम नहीं रहा जाती है या नमक में वात को सीम की है। से सीम महाले की है। से सीम महिला जो लाने के सीम नहीं रहा जाती है उनकी आदर का लेते हैं। से पेशी महिला जो लाने के सीम नहीं रहा जाती है उनकी आदर का लेते हैं। से पेशी महिला जो लाने के सीम नहीं रहा जाती है उनकी आदर का लेते हैं। से पेशी महिला जो लाने के सीम नहीं रहा जाती है उनकी आदर का लेते हैं। से पेशी महिला जो लाने के सीम नहीं महा होती है, इसके आदिक साहोंने (Sardines), राक्ष लिया तेल (shark liver oil) जैशे अनेक महसूल्य वस्तर्य भी भार होती है।

कृषि स्त्यादम्---भारतवर्षं में उच्छ कृष्टिक्य, अर्थं उच्छ कृष्टिक्य और समशीतोब्ध कृष्टिक्य में उत्पन्न होने वालो (विविष्ट प्रकार की फुछलें उगाई जाती हैं। इन फुछतों में खायाज और व्यवसायिक दोनों ही प्रकार की फुछलें सिम्मलित हैं, किन्दु मुख्य रूप से खायाज ही अधिक उगाए बाते हैं। उक्क कथन इसी वात से सम्ब्र हो जाता है कि खेती की बाने वालीकुल भूमि के 🛶% भाग पर खाद्यात्र का ही उत्पादन किया बाता है ।

है ६ ५ की गणना के अनुसार इस देश का मौगोलिक स्वेत्रक लगमन द करोड़ २५ लाख एकड़ है, किन्न इसमें से केनल ६२ करोड़ ३५ लाख एकड़ भूमि ही गाँव के पुराने खेखी (record) में दर्ज मिलती है। इस स्वेत्रकल में से लगमना २६ करोड़ ८५ लाख एकड़ शूमि पर खेती की बाती है। यह इस इस चेत्रकल में उन स्वेत्रों के भी अनुसामित खाँकड़े जोड़ से बहाँ से कोई सुचना मात नहीं होती तो खेती की जाने याली कुल भूमि लगमस ३४ करोड़ एकड़ हो

<sup>1.</sup> जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ हैं वहाँ खरीफ फसल जून में, नहीं तो फिर बरसात हुट हो जाने पर जुलाई में कोई जाती है और जादे में कादी जाती है। रची फसल बरसात समाप्त हो जाने पर अव्यवस्त्र-नवन्य में बोदे आती है और फरेल महें में कादी जाती है। मजा जनवरी-फरवरी में बोता जाता है और फरान्ते जाहें में परकर के कारजान में पिराई होने के समयतक तैयार हो जाता। यह पिराई नवन्यस-दिसम्बर से प्रारंग होता है। क्यार्थ गांवा रची फरान समाप्त हो जाने पर बोया जाता है, फिर मी हुसे लगीक दी फरानों के धन्तर्यंग इस्तिए शामिल किया जाता है कि इसका क्टाई संरोफ की फरानों के साथ डी होती है।

जायगी। १६५६-५७ में कुल खज की उपन ५७३ लाल टन हुई थी, जिसमें से चानल की उपन २८२ लाल टन, मेहूँ ६१ लाल टन, बनार और बानार १०२ लाल टन थी। इसके खितिक ११४ लाल टन दालें, पना खादि की उत्तिन हुई थी। इस मकार १६५६-५७ में कुल खन्न तर दालें, पना खादि की उत्तिन हुई थी। इस मकार १६५६-५७ में कुल खन्न लोल टन दालें, पना खादि की उत्तिन हुई थी। इस मकार मारत की जनता की लिलाने के लिये पर्याप्त नहीं या खोर इसलिय विदेश के खन्म पर निर्मर रहना पहा। पर उत्तित व्यवस्था से लाखान्म के सम्बंध में देश के खात्म निर्मर रहे पन की सम्भावना है। छन्न के खतिरिक खेती से खनेक प्रकार के कच्चे माल की मी उपन होती हैं। इस्थ-५७ में जनने की उपन ६५ लाल टन, जूट को ४२.५ लाल गाँठ, लई ४७.५ लाल गाँठ और तिलहन ६० लाल टन, जूट को ४२.५ लाल गाँठ, कई ४७.५ लाल गाँठ और तिलहन ६० लाल टन हुई थी। देश में जितना इन कच्चे मालों का उत्पादन होता है वह हमारी झायरयकता के हिएकोण से कम है। इसलिये इस कमी को पूरा करने के लिये काफो समय तक हमें खायात पर निर्मर रहना पड़ेगा।

सैसार के पश्चमों की संख्या (क्स के पश्चमों को छोड़कर) का के है। १६५१ की पशु-गणुना के अनुसार भारत में कुल २६ करोड़ २२ लाख ५० हजार पश है जिनमें में १५ करोड़ ५० लाख गाय-नैल, ४ करोड़ ३३ई साख मैंस-मैंसे, ३ करोड़ ६० लाल मेरें, ४ करोड़ ७० लाल वकरे-बकरियाँ, ४५ लाल से कुछ कम सुधा, १५ लाख घोड़े, १२ लाख ५० हजार गये, ६,२९,००० ऊँट और ६०,००० लबर हैं। इसके अतिरिक्त ६ करोड़ ७१ लाख ३० इबार मुनै-मुनियाँ और ६२ लाल ६० इनार बतलें हैं। किन्तु भारत के पशुश्रो की नस्त बहुत लराव है। यहाँ एक गाय श्रीवत से प्रतिवर्ष ४१३ वींड द्रध देती है, जब कि दूसरे देशों की गाएँ प्रतिवर्ष २००० से ७००० पींड तक दब देती हैं। भारत में कुछ प्रबद्धी नस्त के मी पशु हैं, जैसे गुजरात की काँकरेज और धीराष्ट्र की गिरि गाएँ दूव देने और अब्छे बछड़े उत्पन्न करने के लिए संसार की सर्वोत्तम नस्लों में गिनी नाती है। किन्तु बेकार व निकम्मे पशुश्रों की संख्या अपेजाकृत बहुत अधिक है जो किसानों के लिए तिनक मी सहायक शिद्ध नहीं होते हैं और उनके लिए भार-स्वरूप बनकर रहते हैं। भारत में विविध प्रकार के जंगली जीव श्रीर पद्मी भी पाये जाते हैं, किन्दु अमान्यवश "हमारे यहाँ के शेर, गेंडा, चीता आदि प्रमुख जंगली नीनों की नस्त समाप्त हो रही है। मारतीय जीवों को सरस्य देने, उनकी नस्त को सुरिवृत रखने और उन्हें प्राकृतिक व मानवीय वातावरण में छन्तुलित रखने के लिए भारत-मरकार ने अप्रैल, १९५२ में जंगली जीवों के लिए एक

कन्द्रीय बार्ब की स्थापना कींग । पांचयों व संरक्ष्य के लिए एक राष्ट्रीय समिति (National Committee for Bird Protection) भी बनाई गई है । यह खाखा की जाती है कि इन सस्याओं से मारतीय पांचयों और जंगली जीवों का संरक्ष्य और विकास होगा।

### खनिज-पदार्थ

किसी देश के खोदोगिक विकास के लिए उनकी लिनन सम्पत्त का दिशेष महत्व होता है। खनिल सम्पत्त को निम्मलिखित वर्गों में बाँटा गया है:—(१) अभात लिनन (non-metallic minerals), (२) धात लिनन (metallic minerals) और (३) हैंबन (fuels)। अधात लिनन के झन्तर्गत अप्रमृत्तिका, शीसीमेनाइट, मेगनेसाइट, बालू, जूना और नमक खादि खाते हैं। धातु लिनन के झम्तर्गात सोना, चाँदी, सत्ता, राँगा, टिन, तिका, खादि खाते हैं और ईंधनों के सम्पत्तीत कोमला तथा येटीलियम खाते हैं।

भारत में कोवले, कच्चे लोहे, मैंगनीज, बीक्वाहट और झबरक जैसे खर्मिज पदायों की बहुतायत है, रिक्त केटरीज (refractories), एबेलिब (abrasives), चूना और जिम्म भी पर्याप्त भावा में उपलब्ध हैं और झबरक, टिटा-नियम और कच्चा थोरियम भी काफी बाने मात्रा में पाया जाता है। परन्त दुर्मीन्य स ताँबा, टिन, छीना, जस्ता, गिलट, कोबाल्ट, गयक और पेट्रोज जैसे महस्वपूर्ण खनिजों की बहुत कमी है और हनके झमाब की पूरा करने के लिए हमें अधिकतर झायात पर निभीर करना वहता है।

"लानों की इिंग्ट से उपसे ऋषिक मह्त्वशाली भाग छोटा नागपुर का पठार है, जिसे मीडकाना भी कहते हैं, क्लिस मेहत्य विहार, दिख्य पश्चिमी संगाल उत्तरी उड़ीवा आने हैं। कोमला, लोटा, अवस्क और तिवा आदि अधि- कांच इसी भाग ने मान होते हैं। कोमला स्थिपकर क्रिया, रामीगंज के छोती ने निकाला जाता है पर बमुखंगार (Ligmit) के रूप में दिख्यी पूर्वी हैदराबाद, दिख्यी मन्य प्रदेश और दिख्यी पूर्वी मत्या के समुद्री तट पर भी पामा जाता है। लोटा मैस्स में आप अवस्क उत्तरी मत्य परिवा जाता है। लोटा मैस्स में भीन बाहट (Imenite and Monazite) जो उद्ध-कालीन महत्ता एक ती मीनेवाहट (Imenite and Monazite) जो उद्ध-कालीन महत्ता एक ती वालु में याथी जाती है। मैसनेवाहट महास की व्यक्ति महत्ता कि दर्शन अपने वालु में याथी जाती है। मैसनेवाहट महास की व्यक्ति महत्ता कि दर्शन स्वाप पर भीर लंदा। मैस्स के कोलार के में पाया जाता है। बीनवाहट स्विध्य स्वाप से सीर लंदा। मैस्स के कोलार के में पाया जाता है। बीनवाहट स्विध्य महत्ता के बालू में नामी में कोलार के में पाया जाता है। बीनवाहट स्विध्य स्वाप से सारी के बनाने में कोलार के में पाया जाता है। बीनवाहट स्विध्य स्वाप को स्वप्त में भी पर्यात मान स्वाप अपने अपने पर्यात में मान से से स्वाप्त में में से स्वप्त में से स्वप्त में में पर्यात में मान से से स्वप्त में में प्रयोग मान स्वप्त में स्वप्त में प्रयोग स्वप्त में प्रयोग स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में प्रयोग स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में प्रयोग स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त से स्वप्त से स्वप्त में स्वप्त से स्वप्त से स्वप्त से स्वप्त से से स्वप्त से से से स्वप्त से से स्वप्त से से से से से स्वप्त से से से स्वप्त से से स्वप्त से से से से से स्वप्त से से से से स

मात्रा में यहाँ पाये जाते हैं। संबाद मर की अवरक की उत्त्वित का ६०% मारत में उत्त्व्य होता है। मैंबनीय, हरूमैनाइट, भोनेवाहट, लोहा आदि छंशार मर में वनते अधिक मारत में ही मिलते हैं। मारत की धातुओं की पूर्वरूप से काम में नहीं लाखा गया है। देश में पेट्रेलियम की कमी है केवल आलाम में ही इनके कुमें हैं। इन कुशों से प्राप्त उत्त्वित बहुत ही नमस्य है। इसी प्रकार अन्य धातुओं को जैसे राँगा, गण्यक, बांदी, करता, दिन, पारा आदि की उत्त्वित देश की आयरपकता से बहत कर है।

#### अध्याय ३

#### जन संख्या

किसी देश के आर्थिक विकास का वहाँ की जनसंख्या से पनिष्ट सम्बन्ध होता है। मनुष्यों की सख्या, उनका स्वास्त्य, अवस्या की और पुष्य की संख्या का अनुपान, अनम और मुख्य दर और वेश में मास लॉनज पदार्थों के सम्बन्ध में उनके उच्चोग ख्रादि सब उनकी स्वित आर्थिक निश्चित करते हैं। यह एक वसे विचार का ति कि भारतवर्थ जो कि स्वयंत्र का सबसे अवस्था का ना हिरा है समसे गरीव मी है। हस्तिये यहाँ की समस्या जन संख्या के वृद्धि की दर में कमी और प्राकृतिक साधनी के उपयोग में बुधि करने की है।

भारत की जनसंख्या १८६१ में २३५६ करोड़ थी; १६२१ में धहुकर १४'८६ करोड़ हुई जो १६३१ में १७'५५ करोड़ हों. १६५१ ते १९'५५ करोड़ हों. १६५१ ते १९'५५ करोड़ हों. १६५१ ते को जनसंख्या की वृद्धि में छकाल और बीमार्पियों द्वारा कमी होती रही और छक की उपक बढ़ती हुई वजसंख्या के खिल पूरी पक्ती रही। परन्त १६२१ के परचात जनसंख्या में छक की उपक की उपक की जाता तीनतर गति है बुद्धि हुई है विश्वका स्वामार्थिक परिवास यह हुआ कि देश को छक्ता तीनतर गति है बुद्धि है विश्वका स्वामार्थिक परिवास यह हुआ कि देश को छक्ता की किया हिया है विश्वका स्वामार्थक परिवास वह हुआ कि देश को छक्ता की किया है विश्वका स्वामार्थक परिवास के किया के किया विश्वका करना प्रकार के स्वामार्थक करती है, क्योंक (१) इनके पहिले जनसंख्या म्यूनाधिक घटती हुई सी पी परन्त हुस वर्ष के बाद से निरन्दर बदवी रही है, और (२) इन वर्ष के पहिले तक सूमि का प्रयोग भी जनसंख्या की वृद्धि के खनुकूल ही बद्धा रहा पर इन्हें यद से इस को क्यों मी

पृद्धि की दर—१९५१ वक के विखले १० वर्षों से भारत की जनस्वरा जगमम ४९१४ करोड़ के बढ़ वर्ष है जो १९३% की वृद्धि कही जा सकती है अथवा जिसे १३% प्रतिवर्ष की वृद्धि कह चकते हैं। यह वृद्धि विभिन्न भागों में विभिन्न गाँव है हुई है। पंजाब, अथवमान और नीकोबार टापुओं में ०५ प्रतिशत कीर द"६ प्रतिशत कमशः क्यों हुई है। अन्य राज्यों ने से दिल्ली (६२ १%), कुर्म (३० ५%), निपुरा (११.६%), मैसर (२१ २%), निवंकुर कोचीन (२१ १%) और बम्बई

<sup>ै</sup> इस सख्या में जम्मू कारबीर और आसाम के आदिवासियों की संरया समिवनित नहीं है।

२०'८%) में सबसे ऋषिक बृद्धि हुई; हिमांचल प्रदेश (२'७%), पेप्स (२'६%), विनन्य प्रदेश (६%), उड़ीसा (६'२%), भोपाल (७'२%), मप्प प्रदेश (७'६%) और बिहार (६'६%) में बृद्धि को गति क्षयेबाकुत कम रही।

कम्म दर में कमी विवाह की ख़बरणा बहुति, ख़ात्म खंशम श्रीर गर्म निरोध के कृतिम उपायों के ख़तुवार खम्मव हो ककती है। परन्तु जल्दी तावयथ ख़बरथा का मात करने तथा ख़ार्षिक ख़प्या ख़न्म कारखों से विवाह की ख़बरथा बढ़ाना सम्मव नहीं है। देर में विवाह करने की माया पढ़े लिखे लोगों में बढ़ रही है हरने पर भी उन लोगों में ख़मी भी विवाह की ख़बरथा कम हो है। शात्म-चेपम बहुत हो कित है। उसने लिये माया हममें ख़ारमत्व की कमी है ज़िवके कारख उसकी सफ़ताता में सम्बेद है। गर्म निरोधक कृत्रिम उपकरखों का मयोग निम्म कारखों में विशेष प्रचलित नहीं हो सका है: (१) उनके लिव्ह धार्मिक मायना, (२) उनका ख़िक्स स्हर, (३) जनता में उनके प्रयोग करने के देगी के प्रति खनमिलता, (४) हम सम्बेद प्रचणन में प्रपास करने के देगी के प्रति खनमिलता, (४) हम सम्बेद प्रचणन में परासर्थ और शिक्षा देने वाले ख़रगालों की कमी। यदि क्षिम उपायों का प्रयोग प्रचलित करना है तो हम कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करना आप करना ख़राना खाने हम हम दूर करने के उपाय करना स्वार्णन ख़ाना प्रयोग प्रचलित करना है तो हम कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करना स्वार्णन ख़ानाइयक क्षेता।

हार स्टोन का नुराहित काल प्रखाली ("Safe Period method") का प्रभाग भी स्पता और क्षाई की हिन्द से उपयुक्त होते हुने भी अधिक लांकप्रिय नहीं हो पाया है क्यों कि अधिकांश जनता इस प्रखाली का सकलतापूर्वक उपयोग करना नहीं जानती। यह दुर्भीव्य की बात है कि जन साधारण (बहुत से उच्च शिक्षा प्राक्ष सीता को साम्मांवात करते हुये) परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा उसके उपायों से ज्ञानाभाव हैं। वे सब बात मान्य के मरोसे छोड़ देते हैं। इसके कारण परिवार नियोजन का कार्य अपने देश में एक किटन समस्या के कर में उपरिवार परिवार नियोजन का कार्य अपने देश में एक किटन समस्या के कर में उपरिवार विशेचन कार्य के म्रांत जनता में समिय पंचवर्षीय योजना के छान्यांच परिवार नियोजन कार्य के म्रांत जनता में समिय सहात्रभूति की मावना ज्याना छोर वर्षमान हान के छात्रात पर तरसम्या परामध्ये छोर हेवा के सम्बन्ध के छात्रयन का कार्य भी किया तथा (स सम्बन्ध के में पिजक जैवकीय और सास्य के छात्रयन का कार्य भी किया गया। राज्यों, स्थानीय संस्थाओं, वैज्ञानिक समस्याओं के ११५ परिवार नियोजन क्रीक्षणात्यों कोर ११ सास्यकीय स्थानीय संस्थाओं के मित खोज करने सांची योजनाओं के ब्राह्म सुद्ध में हारा सहायता दें। तूबरों पंचवरीय योजना में इस कार्यक्रम में सृक्ष करने का विचार किया गया है'।

"मह मस्ताव किया गया है कि प्रति ५०,००० व्यक्तियों के लिए प्रतिक नगर और कस्त्री में एक श्रीपपालय कोला जाय। छोटे कस्त्री श्रीर गाँवों में प्रति-सीर प्रारंभिक स्वास्थ्य संस्थाश्री के सहयोग में श्रीपपालय कोले आर्थ। इस श्रीपपालयों का कार्य जनता में इस वस्त्रम के प्रति जानकत्त्र सार्थ हों प्रति हों। इस वस्त्रम के प्रति जानकत्त्र सार्थ हों। श्रीपा श्रीर उन्हें इस उपक्ष में प्रतान श्रीर के मानविक ने में एक केन्द्रीय प्रशिक्ष विकालय (clinic) का कोला जाना विचाराधीन है। सम्बद्ध में कुंत्रम उपायों का परीक्षालय स्थापित हो यह है। प्रत्येक मैंपिक विचायियों श्रीर उपवाशिक श्रीप हों परिवार नियोजन की सिचार स्थापित होना चाहिय। यह प्रति होना चाहिय। यह भी प्रतिक श्रीपणालय से परिवार नियोजन की विचाय स्थापित होना चाहिय। यह भी प्रतिक श्रीपणालय से परिवार नियोजन के स्थापित होना चाहिय। यह भी प्रतिक श्रीपणालय के वाया। भू करोड़ के का प्रसन्ध परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लिए विनाय वस हाया गया है। यह श्राशा की जाती है कि द्वितीय पंथवरीय योजना के श्रान्त तक लगामा १०० विक्लालय नगरों में श्रीर २००० विक्लालय गांगों में स्थापित कर दिये जारीके?।

मृत्युसंख्या को दूर---मृत्युसख्या की टर शारीरीक कारखो श्रीर वाता-वरख पर निमेर करती है। शारीरिक दशा पीच्कि तको, सब्ब्हात, धिकित्या की द्विपा इरवादि पर निमंर करती हैं। इरवादि पर निमर करती है। मृत्युख्या की दर प्रत्येक वर्ष मित्र-मित्र रही है परस्तु प्राप्त श्रीकहों के श्रनुक्षार मृत्युख्या की दर प्रत्येक वर्ष मित्र-मित्र रही है परस्तु प्राप्त श्रोंकहों के श्रनुक्षार मृत्युख्या की दर पटती जा रही है। इसका कारख यह दें कि चिकित्या की सुविधा बढ़ी है श्रीर स्वकाई की श्रोर श्रविक ध्यान दिया जाने लगा है। यह आशा को जाती है कि मिबब्द में चिकित्सा की सुनिया
में वृद्धिहोने के साथ-साथ मृत्युसंस्था की दर मोपटती जायगी। बहुपूर्णी योजनाओं
के पूरा हो जाने के बाद अकाल और बाद का और कम हो जायता। भारत में
बच्चों की मृत्युसंख्या अधिक होने से मृत्युसंस्था की दर अधिक है। यह अपुनान संगाया गया है कि कुल जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें में १५ भतिरात एमा बच्चों की आयु होने से पहले होना तो हैं। सरकारी तोर यर की गई गयान के अपुनार यह पता चवा है कि इन बच्चों में से ५० भतिरात पैदा होने में एक महीने के अपूर्य मर जाते हैं और ६० भित्युत पहले सताह में ही मर जाते हैं।

भारत में प्रतिवर्ध खनेक बीमारियों जेसे हैं बा, जेवक, प्लेग, ज्वर ख़ीर डिसेन्ट्री इत्यादि से लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। है बा, जेवक छीर प्लेग महामारियाँ है। सभी धीमारियों में कुल जितने लोगों की मृत्यु होतो है उसका ५.१
प्रतिशत इन महामारियों के शिकार होते हैं। इससे पकट है कि महामारियों के कारण बहुत ख़िक मृत्यु नहीं होती है। विभिन्न बीमारियों से होने बाली मृत्यु छों के ५.७५ प्रतिशत का कारण ख़ानेक प्रकार के उबर होते हैं। श्रस्ततालों की
खिष्पा बहुत कर, स्वास्थ्य-पुधार की योजना लागू कर, लोगों की बीमारियों के ख़ाकमण से बचने की शाकि बढ़ाकर साथ ही लोगों को ख़ात्मविश्वासी छीर
मान्य पर कम निर्मर बनाकर मृत्यु संख्या की कीची दर के कारणों को दूर किया जा एकता है।

स्त्री-पुरुषों का अनुशात—मारत में पुरुषों को संख्या किया ति स्रीक है परन्तु महान, उड़ीका, त्रिवाकुर कोलीन और करक से यह स्थिति पिपरीत है। हम राज्यों में कियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। १९५५ को जन-गयान के अनुसार करक में चन से अधिक कियों है। यहाँ मित हजार पुरुषों के पीछे १०७६ कियाँ हैं। हुनों में कियों की संख्या अपने यह राज्यों में कम है। यहाँ मित हजार पुरुषों के पीछे १०७६ कियाँ हैं। हुनों में कियों की संख्या अपने यह राज्यों में कम है। यहाँ मित हजार पुरुषों के पीछे दश्व किया की संख्या किया की संख्या करने की अधिक नाता और विशेषकर हिन्दू समुदाय जह की की अपने का अधिक नाता और विशेषकर हिन्दू समुदाय जह की की अपने का अधिक नाता है को उत्तरी मित्र मुख्य हो काली है। पार्मिक मानना के अवितिष्क इसका एक कारण यह है कि समाज में शिवा का प्रसार कम है और उनकी माय: संख्य हो काली है। पार्मिक मानना के अवितिष्क इसका एक कारण यह है कि समाज में शिवा का प्रसार कम है और लोग समाज में श्री के महत्य को अक्त काली है। पार्मिक मानना के अवितिष्क इसका एक कारण यह है कि समाज में शिवा का प्रसार कम है और लोग समाज में श्री के महत्य को अक्त किया में स्था के समय अने के सिव्यों की मित्रीय से मीरियों को संख्या कम है।

श्वयस्था—मारत में बच्चे और नवसुषकी की अनसंख्या में प्रधानता है। १६५१ में १४ वर्ष तक के लोग ३८-३%, १५ से ३४ वर्ष तक के लोग ३३%, ३५ से ५४ वर्ष तक के लोग २०४% और ५५ वर्ष के ऊपर के लोग केवल द्र-२% ये। अग्य देशों में, जैसे फ्रान्य, इद्वलैक्ड, जर्मनी, उत्तरी अमरीका आदि में, स्थित इस्टे त्रियरेत है। इन देशों में ५५ वर्ष और इवके ऊपर की अवस्था वाले व्यक्ति कल जनसंख्या के क्रमश: २१४%, २१.५%, १६ १९% और १६ % हैं।

घनस्य क्रोप्ट शिनक्या-भारत में व्योसत जनसंख्या का धनस्य ३१० प्रति वर्ग मील है । धनत्य का मात्रा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बदलती हुई है । एक श्रीर दिल्ली से ३०१७ टावरकोर कोचीन में १०१५ प्रति वर्ग मील है तो दसरी श्रीर श्रवद्यान संबोधार से ३० और वच्छ में ३४ प्रात वर्ग मील है। दस बदलते हथे यमस्य का कारण प्राकृतिक बनावट, असि तथा वर्षा है। इन कारणो पर ही भूमि के ज़िल प्रयोग की बाद्या निर्मार है। इस नये प्रतत्य की समस्या का श्रद्यम प्राकृतिक भागी के श्राधार पर श्राधक यांक्तसंगत होगा। इस हिस्कीय विस्थारात के मेटान के निचले भाग में बनस्व c32 छोर अपर के भाग में धनस्व ६=१. मालाबार कोवन से ६३८, दांतिणां महास में ५५४, उसरी महास श्रीर उक्रीमा के समुद्री तट पर ४६१ है। ये माग बहुत श्राधिक वनत्य वाले कहे जा सकते हैं। दक्तिशी भाग में, उत्तरी माग में, गुजरात काठियाबाइ में, जहाँ पर जनसङ्गा का घनल साधारण कोट का है, प्रतिदर्ग मील में कमशः ३३२, २४७. २४६ और २२६ व्यक्ति निवास करते हैं। दक्षियी पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में. उत्तरी वेन्द्रीय पहाड़ियों में, पूर्वी पठार में, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियों में, हिमालय, पश्चिमी हिमालय और रेशिस्तानी भागों में जनसंख्या का बनव कमशः १६२. १६४, १६३, ११८ ६८ और ६१ व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है। जनसंख्या के इस असमान वितरण के कारण प्रत्येक स्थान पर प्राप्त प्राकृतिक सुविधाओं का समुचित प्रयाग नहीं हो पाया है।

भां में प्रयोग रामाणी ऑक में पर विचार करने से हम हम निष्कर्ष पर पर्टुचते हैं कि (श) योहर वहाँ संसार अस में अनसंख्या का पनत्स करने अधिक हैं भारत की तुलना में अधिक आमें नहीं है। शीस्त मारतीय अपनी भूमि का ४२% सेती के वाम लाता है जब कि औस्तर योखपीय केश्स ह ० मातरात ही काम में लाता है। (म) स्कुक्त राज्य अमेरिका और शांवयत कर के व्यांकरों के पास योहय निवासियों और भारतीयों की अपेचा अधिक स्था है। भारत में पूर्णि पर जनसंख्या के भार का दुख्ड अञ्चमन इस बात से स्वारता है कि बोये हुये सेतों में जनसंख्या के भार जा कुछ अञ्चमन इस बात से स्वारता है कि बोये हुये सेतों में जनसंख्या के भार जा कि स्वार्थ के सार का स्वारत करने एक है। जनसंख्या २३

यदि करियन्थों के इष्टिकीस से सनसंख्या के वितरस पर विचार किया जाय तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ६·३२ करोड ग्रथवा कल जनसंख्या का १८% है। पूर्वी भारत की (जिसमें विहार. उड़ीसा, पन्छिमी बंगाल, खासाम, मनीपर, त्रिपरा और सिकिम आते हैं) जन-संख्या ६ करोड़ या कल जनसंख्या का २५% है। दिल्ली मारत (जिसमें मदास, मैसर टावनकोर कोचीन श्रीर कर्ग श्राते हैं) की जनसंख्या ७ ५६ करोड़ या कुल जनसंख्या की २१% है। पञ्छिमी मारत की जनसंख्या जिसमें बम्बई. सीराध्य श्रीर यन्छ ग्राते हैं ४.०७ करोड़ या ११% है। मध्यभारत की जनसंख्या जिसके ग्रान्त-र्शत मध्यभारत, हैदशबाद, भोषाल जीर विन्ध्य प्रदेश जाते हैं प्रश्व करोड या १५% है। उत्तरी पश्चिमी भारत की जनसंख्या जिसके अन्तर्गत राजस्थान, पंजाब, नेप्त, जम्म श्रीर काश्मीर ( श्रांकड़े सम्मिलित नहीं हैं ), श्रजमेर' दिली, विलासपर, श्रीर हिमालय प्रदेश आते हैं. ३ ५ करोड़ या १०% है। यदि भुभागों के दृष्टिकीश से विचार किया जाय तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी मैदान की जनसंख्या है "1%. मायद्वीप पदावियों श्रीर दक्षिया पठार की जनसख्या ३० ४%, पूर्वी घाट श्रीर समुद्री तट की जनसंख्या १४%, पश्चिमी धार श्रीर समुद्री तट की जनसंख्या ११'२%, दिमालय के 'भूमाग की जनसंख्या ४ =% है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि देश के उपजाक मैदानों में श्रधिकांश जनसंख्या बसी हुई है।

मध्यमदेश का चेत्रफल खबसे आधिक है, अर्थात् ११०२७ र वर्ग मील, तथा इचके परचात् राजस्थान है जिसका चेत्रफल १३०२० वर्ग मील है, जबकि जन- वंद्या उत्तर प्रदेश की खबसे अधिक आधिक अर्थात् ६१ करोड़ है और इस्के परचात् मुस्तार, विहार, और वन्नवेह विज्ञानको जनसंख्या क्रमशः ५, ४ तथा ३ ५६ करोड़ है। विव्य परेश तथा विहार क्षेत्र कर्मा क्षेत्र क्षेत्र हैं। विव्य परेश तथा विहार क्षेत्र कर्मा जनसंख्या क्षेत्र कर्मा कर्मा १२० लाख विष्य १०,४ लाख है—किसी भी ख और द राज्य की जनसंख्या कर्मा १० लाख के अधिक नहीं है। स्वरंश कर्म जनसंख्या वाला प्रदेश अर्थक्षम और निकोशार होए हैं जिसको अर्थस्य क्षेत्र कर्म जनसंख्या वाला प्रदेश अर्थक्षम और निकोशार होए हैं जिसको अर्थस्य क्षेत्र ह १२ करोड़ अपचा १०,१% नगों और कस्त्रों में किनकी संख्या क्षेत्र ह १२ करोड़ अपचा १०,१% नगों और कस्त्रों में विवास करना भी की जनसंख्या क्षेत्र विहार क्षेत्र है। इस्ते के अर्थस्य के परिकास व्यक्त भावी की जनसंख्या किरकार नगों की और बहुती जा रही है। १६२१ में व्य.,७% जनसंख्या विरुद्ध नगों और ११ २९, नगों में १६४९ में व्य.,७% जनसंख्या विवास करती भी और ११ २९, नगों में १६४९ में व्य. क्षेत्र करती में और १३ २९, नगों में १६४९ में व्य. करा करा विवास करती की और १० २० नगों की स्वरंश करती का क्षेत्र है। स्वरंश में व्यक्त करती मी और १२ २९, नगों में १६४९ में व्यक्त करा करते कारी और १२ २९, नगों में १६४९ में व्यक्त करा करा विवास करते का क्षेत्र करने लगी और १९५५ में विवास करती भी और १२ २९ नगों में १६४९ में विवास करती में करा विवास करने लगी और १९५५ में ने वील करा विवास करने लगी और १९५५ में ने वील करने लगी और १९५५ में में भीर १९५५ में विवास करती भी और १९५० में में और

नुका है, दर•% गाँवों में और १७ दे% नगरों में रहने लगी। दिल्ली और खन-मेर के छोटे राज्यों को छोजनर नहीं कि गहर की आवादी कमराः दर्% और ४२% है, नहे राज्यों में नगरहें और शीराष्ट्र के राज्य कमसे आधुनिक हैं नहीं ३०% और ३०% जनमंज्या नगरों में उन्हरी है।

मारत के ७२ शहरों थी ब्रावादी एक लाख के ऊपर है। ब्रालाम और पेन्यू में ऐसा कोइ नगर नहीं है। 'ब' राजों के सात मागी केमल नई दिली ब्राजमें और मुपाल ऐसे नगर हैं। देश के सबसे बड़े नगरों में बनाई की जनसंख्या र= 'इंट लाख, है, कलकत्ता की र्-भ्रक्ट लाख, महास की रभ्र '१६ लाख, हैदराबाद की १० लाख, दिली की है '१५ लाख, ब्रह्मबाबाद की अपन्न लाख, और बंगाली की ७ ०० लाख है।

धर्म खोर विवाह मारत में खनेक बसों के मानने वाले रही हैं पर रिन्दुओं की सक्या प्रधान है। १९५१ में १५ ७ करोड़ की धानादी में ते १० १ करोड़ रिन्दू थे, १५६ करोड़ मुस्तमान,इन्द लाटत देशह, ६२ लाल विक्ल, १६ काल जैन, २ लाल भीद १ लाख जोराष्ट्रियम (पारती), १७ लाल प्रधिवासियों के धर्मायलमी तथा १ लाला खान्य अभी के पालन करने बाले थे।

मारत में प्रति १०,००० व्यक्तियों (शरव्यियों को छोड़ कर) में प्र११ पुरुष तथा ४८६० की है। इनमें २५६१ पुरुष व ४८६६ कियाँ क्षारियादित हैं अपने हिंदी होता कर सहस्वादित हैं। अपने होते प्रविद्या के मिलाकर कुल ननसंख्या ४४ ११ अपिवादित हैं। बाल विवाद रोक कामून के होते हुए भी रेश में अत्वविक्ष काल-विवाद होते हैं। १८५१ की जन गणना के अनुसार लगमग २८३३००० पुरुष' ६१६८०० विचादित कियाँ, ६६००० विधुद और ११४००० विचादित कियाँ, ६६००० विधुद और ११४००० विचाद कमा १९००००००० विचाद की स्वी में। इसी रिपोर्ट के अनुसार स्वामा १२०००००० विचाद वाल विवाद निरोधक नियम के प्रविक्त करने थे।

व्यवसाय—देश भर के ७०% व्यक्ति कृषि पर और ३०% अन्य व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं। शौराष्ट्र, वच्छ, अवसेर दिल्ली अन्वस्थान, नौकोशर में खेती करने वालों की सब्या की तुलना में अन्यमकार के व्यवधानियों को संच्या अधिक है। पिर्मिनों नंगाल और अन्वहं प्रदेशों में जो सबसे अधिक अधीनिक प्रदेश हैं वहींनो लेतों करने वालों की संख्या अवसायियों से बढ़ी हुई है। दिलाइल प्रदेश और स्थितिम में कृषि करने वालों की संख्या कुल आवादी की ९०% है। प्रत्येक १०० मारवनायियों में ४० तो ऐसे किसान हैं जिनके पास अपने लेत है, ६ आसायी है, ११ बना गृमि के अधिक है, १ अवसेन्दार है अपवा लगान पर ग्राध्वित है और १० ज्योगों में लगे हुए हैं अवया कृषि के श्रवितिक अन्य कार्य करते हैं ६ व्यावार करते हैं, र यातायात में लगे हैं और १२ विभिन्न प्रकार की नीकरियों में लगे हैं। १६५१ की जनगणना के अनुसार ३५% व्यक्तियों में से २५% करोड़ किसान और १०% करोड़ लेखी के असितार अस्य कार्य करने वाले लोग में। २५% करोड़ किसानों में से १६% करोड़ अपने निजी खेतों पर खेती करने बाले में। १९१६ करोड़ पेसे किसान ये जो दूसरों के खेत करने वाले में, ५%% करोड़ कृषि कार्य करने वाले मजदूर ये और ०%३ करोड़ खेती करने नाले जमीदार या लगान पर आधित व्यक्ति ये। १०% करोड़ अस्य कार्यों में लगे क्यक्तियों में से १० करोड़ कृषि के अतिरिक्त अस्य उत्सत्ति के कार्य में लगे में, २९३ करोड़ व्यापार में लगे में, ०%६ करोड़ यातायात में लगे वे और ४%३ करोड़ विभिन्न



# सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएँ

सामाजिक और धार्मिक स्वयस्थाओं का जनता के जाधिक जीवन पर धारी प्रभाव पदला है। यह मौतिक सख-समृद्धि श्रीर सम्पत्ति के सम्रह के प्रति जनता के हारकोश को, साथ ही इन उड़ेश्यों की पति के लिए जनता के प्रयक्षों को निर्धारित करती हैं । यह व्यवस्थाएँ श्रीद्योगिक श्रीर वाखिज्य सगठनो की प्रभावित करती हैं साध ही ब्यापार और उद्योग का किस प्रकार सगठन किया जाता चाहिये इस पर भी बन ब्यवस्थाओं का प्रभाव प्रक्रता है । भाग्त में जाति प्रकाली और सँयक्त परि-बार की प्रधानों का भी देश के बार्थिक संगठन पर काफी प्रभाव पढ़ा है: पदी-प्रथम काहिमा पर विज्ञास और भर्म के प्रतिसामस्य जनता के दक्षिकीया ने उनकी क्राधिक-ग्रतिविधि को निर्धारित एवम संचालित किया है। वर्दा-प्रथा के कारण उद्यन्त्राति की महिलाएँ देश के छार्थिक-कार्य में भाग नहीं सेती हैं श्रीर इस प्रकार जनता की निधंन रखने में यह प्रधा सहायक सिद्ध होती है। श्राहिसा के हांटकोण ग्रीर इस धार्मिक भावना से कि बन्दर ग्रीर तील-गाय (जो शास्तव मे गाय नहीं है। परित्र हैं इनको नए नहीं किया जा सकता। इससे फरेल तथा श्रम्य मुख्यबान सम्पत्ति की भारी स्तित होती है । शामिक संस्थाश्रों को जैसे मन्दिरी, महो भीर खखादों को जनता जो दान देती है उससे इन संस्थाओं ने बहुत भ्राधिक मात्रा में सम्पत्ति का लंगड़ कर लिया है जिसका परिचास यह होता कि / १) इन सर्याओं को चलाने वाले पतारी' पायंडे तथा अन्य लोग आलसी हो जाते हैं क्योर बेकार पढ़े रहते हैं ज्योर हम प्रकार देश उनके अस का लाम उठाने से वंचित रह जाता है: (२) इस प्रकार को धन हकड़ा होता है वह तिमोरियों में बन्द रखा जाता है और देश के शार्थिक विकास के कार्य में इसका अपयोग नहीं होता है। विश्व के अन्य उत्रत देशों में जनता हारा की गई बचत काफी पहिले देश के श्रीशोगिक तथा कृषि विकास के लिए उपलब्ध हो गई श्रीर पंजी निर्माण की प्रति-किया को प्रोतलाइन मिला। परन्तु मारत में धार्मिक सगढनों के प्रभुत्व और शास्त्रों के इस श्रादेश से कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ श्रश इस संस्थाओं को दान देना चाहिए ओर साथ ही मन्दिरों और मठों के प्रति जनता की गहरी अहा होने से देश में पूजी-निर्माण का कार्य बहुत शिथिल पड़ गया। देश के उत्तराधिकार कानूनों से भूमि तथा खन्य प्रकार की सम्पत्ति का अनचित रूप में छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजन होता गया है। यदि भारत में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएँ भिन्न प्रकार होतीं तो देश की आर्थिक प्रगति भी भिन्न प्रकार की होती।

जातिप्रथा—जाति प्रया इमारे देश की प्राचीनतम प्रथाओं में से है। एक b परिभाषा के श्रनुसार जाति परिवारों या परिवारों के समूदों का एक ऐसा संग्रह है जिसका एक नाम है, जो उसके अन्तर्गत आनेवाल लोगों के व्यवसाय सम्बन्धित होता है और इस नाम से ही उसके अन्तर्गत आनेवाले लोगों का व्यवसाय से मालम हो जाता है। इसके साथ ही यह दावा-किया जाता है कि किसीपीरासिक मानव या देवता से इसका यंश चला है: इसके अन्तर्गत आनेवाले लोगों का एक पेशा है. श्रीर राय प्रकट करने के श्रधिकारी व्यक्ति इसे एक ही समुदाय समझते हैं जिसमें समानता है। इसे यह मालुम नहीं है कि जाति प्रणाली का विकास कैते हवा। जाति प्रधा संभवतः अय-विभाजन शीर विशेषकता के सिद्धांत पर श्राधारित रही होगी। प्राचीनकाल में हिन्द समाज चार भागों में विमक्त था, अर्थात ब्राह्मण जो श्राध्यामिक नेता. विद्वान खोर प्रवारी होते थे. खांत्रय जो योदा श्रीर प्रशासक थे. वैश्य जो व्यापारी ख्रीर सीदागर थे, ख्रीर शुद्ध जी निग्नकोटि के कार्य करते थे. अन्य लोगों की सेवा करते ये-इन अन्य लांगों में अधिकार प्रथम तीनों वर्श फं लीग हो होते थे। इस चार जातियों की प्रशासी में हमें कार्य का विभाजन स्रष्ट मालम होता है । साथ ही यह प्रयक्त भी प्रकट होता है कि विभिन्न लोग विभिन्न कारों में दत्तता प्राप्त करें। श्रारंभ में जाति प्रयाली यंशगत या पुरातेनी नहीं थी श्रीर एक जाति का व्यक्ति श्रवने प्रयत्नों के बल पर श्रपनी जाति से उस जाति में मनेश पा सकता था। परन्त बाद में जाति प्रथा श्रास्यन्त कहर रूप घारण कर गई स्रीर निश्चित रूप वंशगत हो गई। इसके अतिरिक्त अनेक उपजातियाँ और इन उपजातिया के मी श्रमेक निम्म-रूपों को जन्म दिया गया जिससे यह सारी स्यवस्था श्चत्यन्त जरिल हो गई। Advantages . -आरम्भ में जाति-प्रणाली से कुछ लाम ये : (१) इस व्यवस्था से किसी

श्राप्तम कारल हा गह।

श्राप्तम में जाति-प्रवालि से कुछ लाम ये : (१) इस व्यवस्था ते हिसी
कार्य में जाति-प्रवालि से कुछ लाम ये : (१) इस व्यवस्था ते हिसी
कार्य में जाति-प्रवालि से कुछ लाम ये : (१) इस व्यवस्था ते हिसी
कार्य में बीर कान में विशेष योग्यता प्राप्त की जा ककती थी जिससे जा कुछ कार्य
किया जाता था उसके गुण में बहुत सुसार होता जाता था। पायः बेटा वर्द्ध
व्यवस्था श्रप्तगाडा था जो उसका वाप करता था श्रीर इस व्यवस्था में लिए वाप
उसे अचित शिक्षा दे देता था। इस प्रकार एक विशेष प्रकार कार्य और
तरसम्बन्धी अन एक प्रश्नार में वंश्वस्त कर ले बता श्राप्त था श्रीर देश कार से
उस व्यवस्था को योग्यता प्राप्त कर कार्य आगे बढ़ाता था। पृतिहती की मुप्तिय
विद्या, भारतीय योग्यता प्राप्त कर कार्य आगे दक्ती का भारतीय दसन
कारी सभी श्रीसिक इस से इस विशेष योग्यता के ही कल ये जो हवसे इसी जातिप्रमालि का परियाम था; (२) जाति-प्रमाली से उन करमय तथा परेशानियों के
दिनों में जब कि भारत पर विजातियों ने इसले किये थे (हन्दू-जाति की श्रुदता को

भारतीय श्रर्थशास्त्र की समस्याएँ

शिला दी जारी थी छोर उनके ग्रन्य हिला की देखमाल की जाती थी। परन्त आधीनक काल में जाति प्रवाली श्रद्धयन्त अटिल श्रीर श्रपरिवर्तन-शील हो गई है: उसमें एक प्रकार की बटाता का गई है और फलस्वरूप इससे देश की आर्थिक मगति में सहायता मिलने की अपेला हानि ही अधिक हुई है। जाति मणाली के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि: (१) यह आवश्यक नहीं है कि वैश्य का एव अच्छा व्यापारी हो और बाह्यस की प्रव अच्छा प्रवारी हो । यह विरुक्त सभव है कि ब्राह्मण या वैश्य के चत्र में ऐसी योग्यता है कि वह श्रास्थनत कराल मोचो बन सके। परन्न वाति प्रधा उच्च जाति के लोगों को ऐसे कार्य करने से रोकती है जो कार्य छोटी जातियों को सौंपे गरी हैं। इसी प्रकार यदि कोई शद्र बहत शिच्चित और विद्वान भले हो परन्त वह किसी मन्दिर का पुजारो नहीं बन सकता । यह जाति प्रथा हो उसके मार्ग में सबसे बढ़ी बाधा बन जाती है । इस प्रकार जाति प्रथा किसी व्यक्तिको ऐसे उत्तम कार्य करने से रोकती है जिसकी उत्तमे पर्यात ज्ञमता और योग्यता हो । (२) अस्पूर्यता और इसते उदस्त अन्य फठिनाइयों के कारण जाति-प्रथा जनता के सरल-स्वामाविक प्रवाह में बाघक बन जाती है। किसी देश के आधिक विकास के लिए पंजी और अम की निर्वाध गति-शीलता अत्यन्त आवश्यक होती है। जाति प्रथा ने इसकी रोक रखा है आर इस सीमा तक हमारे देश में ग्रीवोशिक तथा कवि क्रांतियों का अभाव रहा है। (३) कट्टर जाति प्रथा के कारण इस अम-सम्मान (dignity of labour) की भूल गये हैं और इससे अन्य लोगों के विश्वासों, घमों और हव्टिकोशों के प्रति इमारी सहित्याता की मावना भी कम हो गई है। इसीलिए इससे गतिरोध उत्पन्न हो गया है, हमारा समाज अस्थिर हो गया है और हममें स्वयं आगे इदहर पय प्रदर्शन करने तथा साहस की मावना लुप्त हो गई है।

सीमान्य से गत कुछ वर्षों से जाति-प्रचा टूट रही है। मारत म<u>ैं रेलों के</u> निर्माण, इसके प्रचार, यात्रा की सुविधाओं में वृद्धि, रेल, वस या इवार्ड जहा<u>ज की</u>

इसमें काफी रूकावट पड़ी; श्रीर (३) जाति प्रसाली ने शाराम से ही रिन्हुओं को श्रूप्य लोगों के विश्ववारों श्रीर धर्मों के प्रति विरुद्ध बने रहते का पाठ खिलाया है। इसी कारण विभिन्न लातियां श्रीर धर्मों के लोग भारत में शांति श्रीर माई चारे के साथ रहते श्राये हैं इसमें निक्त भी श्रुसल्य नहीं है कि श्रारम्म में मारत में जाति मणाली ने प्रायः उसी उद्देश्य की पृति की जिनकी पूरीप में मिल्ड मणाली

(Guild System) ने की जिसके अन्तर्गत गिल्ड के सदस्या की टैक्निकल

बनाये रखने में बहुत सहायता भिली। जाति-प्रकाली की कट्टरता के फलस्वरूप ही विजेताको और विजितों के बीच क्षावत्रयकता से क्षप्रिक रक्त-सम्बन्ध नहीं हो पाया

20

यात्रा में विभिन्न जाति के लोगों से होने वाले श्रनिवार्य जन-सम्पर्क के फलस्वरूप जाति-पणाली की कहरता कम हो गई रिश्रंग्रेजी शिल्ला प्रणाली श्रीर श्रंग्रेजी कानन के जन्तर्गत सभी जातियों के साथ समानता का व्यवहार किया गया और सभी जातियों के लोगी को कोई भी व्यवसाय अपनाने की छट दे दी गई। पेशा श्रपनाने में जाति-प्रथा की बाधा नहीं रही। शह जाति के व्यक्ति श्रध्यापक. मजिस्टेर और उड़न मैन्याधिकारी बने और उड़न जाति के लोग जिस्हें गुपना कार्य मित्र करना होता था रज अधिकारियों के मध्यके में बार्य कीर जाति प्रथा की बहरता का पालन नहीं कर सके र जातिन्यथा के कारण ही अनेक हिन्दश्रों ने द्यान्य धर्मों को स्वीकार कर लिया । इसकी स्वयं हिन्द-समदाय में प्रतिक्रिया हुई श्रीर श्रय-समाज जैसे सधारवादी ग्रान्दोलन हुए जिन्होंने जाति-प्रथा को तोइने में बहत बहा कार्य किया है। भारतीय उच्छीय कांग्रेस इसके बिक्ट संघर्ष कासी उड़ी ▲ है और भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की भारी अपराध माना गया है और सबको बराबार अवसर प्रदान किया गया है। केन्द्रीय सरकार श्रीर राज्य सरकार श्चव परिराणित जाति के विद्यार्थियों को विशेष खात्रवृत्ति देने की नीति अपना रही है। इन सब प्रयत्नों से जाति-प्रधा की कहरता कम हो गई है और भारत के श्रार्थानक नौजवान इसकी अधिक परवाह नहीं करते हैं। कुछ लोग या वह लोग जो श्रमी श्रपने गाँवो या करवों की सीमा से श्रपन को मुक्त नहीं कर सके हैं श्रीर जिनका दृष्टिकोण अभी भी सकचित बनाहवा है. अब भी इस जाति-प्रधाकी कद्भरता की भावना से अस्त हैं परन्त इनकी संख्या धीरे-बीरे घटती जा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि जाति-प्रथा समाप्त होती जा रही है परन्त इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अब भी बादि-प्रधा का जोर है और भारतीय आधिक प्रणाली को जससे बराबर स्रति हो रही है।

संयुक्त परिवार की प्रथा (Joint Family System)—रंबुक्त परिवार प्रथा मारत की प्राचीनतम प्रयाद्धों में से एक है। देश में सामान्यतः आर्थिक इकाई एक व्यक्ति नहीं बहिन संयुक्त परिवार है। बहुत से व्यक्तियों ने संयुक्त परिवार से अपना उम्मन्य-निच्छेद कर सिवा है और वह असना दहन तमे है परन्तु किर भी परिवार संगठन में संयुक्त-परिवार प्रथा की पूर्य प्रधानता है। संयुक्त परिवार में सामान्यतथा पिता परिवार का प्रधान होता है और परिवार के अन्य पुरुष तथा क्रियाँ उसके आधीन होते हैं। वह साथ रहते हैं साथ खाते-बीते हैं और प्रवान्यत्व करते हैं, साथ ही समान में सबके समान सम्बन्ध होते हैं। यह डीक कहा अथा है कि छोटे पेमाने में संयुक्त-परिवार साथवाद का उदाहरण है। यह डीक कहा अथा है कि छोटे पेमाने में संयुक्त-परिवार साथवाद का उदाहरण है। यह संयुक्त परिवार का उचित सगठन किया जाल

तो वहाँ यह सिद्धान्त लाग होता है कि "प्रत्येक सदस्य सब के लिए और सारा परिवार मत्त्रक के लिए" (each for all and all for each) अपांत प्रत्येक ब्यांक पूरे समूह के लिए उत्तरदायी है और पूरा समृह प्रत्येक व्यक्ति के ुलिए उत्तरदायी है। संयुक्त-परिवार प्रथा के कुछ आर्थिक लाभ हैं—(१) इससे रहन-सहन का न्यय घट जाता है क्योंकि खाना साथ पकाया जाता है, नौकर चाकर समान होते हैं और अन्य सभी सुविधाओं का संयुक्त रूप से उपभोग किया जाता है। बसे पैमाने पर किये जाने वाले कार्य की सभी सुविधाएँ इसमें निहित हैं। यदि लोग ग्रलग-ग्रलग रहते हैं तो रहन सहन का कुल ब्यय परिवार के व्यय से घटत अधिक होगा: (२) उससे सम्यन्ति और भूमि का छोटे-छोटे भागों में विभा-जन नहीं होता, भूमि पर मिलकर खेती की जाती है जिससे आधिक सेत्र में अनेक स्तास होते हैं और ख़स्य करते में भी काफी लाग होता है। संयक्त परिवार की पंजी निखरी हुई नहीं होती निलक एक साय बमा रहती है और उसकी अन्य उत्पादन कार्यों में या आगामो उत्पादन कार्य का प्रसार करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। परन्तु यदि सपुक्त परिवार द्वर जाय और लोग अलग-अलग रहने लगे तो यह संभव है कि उनके पास पर्यात पंजी न हो। और (३) संयुक्त परिवार मधा बीमारी, मृत्य या अन्य दर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के अवसर पर एक प्रकार से बीमा का कार्य करती है। विधवाध्यों, अनाधी और वृद्धों का संयुक्त परिवार में अन्य सदस्यों की तरह ही पालन-योषण होता है। यत कुछ वर्षी से पश्मि देशों में वृद व्यक्तियों की. जो कार्य नहीं कर सकते और निर्धन है. उनकी सन्तानों ने उन्हें बिमा किसी सहारे के छोड़ देने की प्रकृति हो गई है। संयक्त पिरवार प्रया के खन्तरांत पेसा संभव नहीं है ।

परम्य संयुक्त परिवारित यांची की खनेक हानियों भी हैं: (१) चूँकि प्रत्येक ज्यक्ति को सीजन, कपढ़े, रहने खादि की पूरी सुविधा उपलब्ध है इरिलिए उन लांगों में को चरित्र की हरिट से अच्छे नहीं कहे वा सकते हैं खोर किनमें दूर हाँह का खानाय होता है आलस्द पैदा हो बाता है। हम प्रधा से उनके खालपी स्थाप का खानाय होता है आलस्द पैदा हो बाता है। हम प्रधा से उनके खालपी स्थाप का खान होता है। सम्प्रवाद के खनते चूँकि सुप्रतान कार्य के ब्रामार पर निर्मा जायगा अतर्य तर यह कठिनाई उत्तव हो बायगी कि प्रत्येक ब्यक्ति से उद्यक्ती ब्याया के खनुकूल उत्तम कार्य कैसे करामा वाम। एसी प्रकार संयुक्त-परिवार-प्रणाली में व्यक्ति की समी आवश्य-कवाओं की उसके हारा कि यार्य की मयान किये किना हो पूर्वित हो बायी है इसने कुछ लोगों में निटल्ले कैठ रहने खेर आत्रवी बन बाने की प्रकृति देश हो हो सात्री है। इसने सम्बद्ध लोगों में निटल्ले कैठ रहने खेर आत्रवी बन बाने की प्रकृति देश हो वात्री है। इसने सम्बद्ध लोगों में निटल्ले कैठ रहने खेर आत्रवी बन बाने की प्रकृति देश हो वात्री है। इसने सम्बद्ध लोगों में निटल्ले कैठ रहने खेर आत्रवी बन बाने की प्रकृति देश हो वात्री है। इसने सम्बद्ध लोगों में निटल्ले कैठ रहने खेर आत्रवी बन बाने की प्रकृति देश सम

कता है जो रुपया कमाता है। इसलिए संयुक्त परिवार में झालसी श्रीर निटहते होगों के किन्छन निर्माण कमाता है। इसलिए संयुक्त परिवार प्रयाली की अन्तर्गत लोगों को भित्रशीलवा का हास हो जाता है और परियाम स्वरूप अन्तर्गत लोगों को भित्रशीलवा का हास हो जाता है और परियाम स्वरूप अन्तर्गत लोगों को सर को अन्तर्गत को मार के किए को मार्थ करने की मत्र्यिल का भी हास हो जाता है। लोगों को सर में बैठ रहने की आर्देत पर जाती है और फलस्वरूप साह्रसपूर्ण कार्य करा में प्रयाल को महार्थ भी बेठते हैं, उनमें वह स्कृतिं, स्विभ्यता और साहर नहीं रहता जो देश की आर्थिक अपति के लिये झानस्यक होता है और (३) संयुक्त परिवार में होटे-होटे कगड़े पैदा होते रहते हैं, ईम्ब्या-देश बढ़ता है और इसके फलस्वरूप मुक्तरवेशनी भी हो जातो है जो कि आर्यन्त हानिकारफ सिद्ध होती है।

क्षे इपर कुछ वर्षों से संबुक्त परिवार प्रया विभूतांतत हो रही है। यद्मि श्चमी भी यह परिवार-संगठन का प्रधान रूप है किर भी संयुक्त परिवार त्याग कर ब्रलग रहने वालो की संख्या बढ़ रही है। (१) शिज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात युवक शहरी जीवन का अध्यक्त हो जाता है और किसी कारखाने में नौकरी कर लेता है या है शहर में ब्यापार कार्य में लग जाता है ब्रीर उसे संयुक्त परिवार से पृथक होकर रहना पड़ता है; (२) जीवन-सवर्ष में वृद्धि होने से श्रीर जीवन-निर्वाह के साधनों को जुटाने की कठिनाइयों से व्यक्ति संयुक्त-परिवार के बन्धन से मुक्त होना चाइता है। अपनी पत्नी श्रीर बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त रुपया कमा लेना संबुक-परियार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त रुपया कमा लेने से कहीं अधिक सरल होता है; (१) जहाँ तक धनवान व्यक्तियों का प्रश्न है आय कर कानून स्त्रीर हाल ही में सम्पत्ति कर (estate duty) कानून बन जाने से संयुक्त-परिवार प्रथा टूटने लगी है। यदि संयुक्त-परिवार के कमाने वाले सदस्यों की ब्राय ब्रायकर के लिये निर्धारित न्यूनतम ब्राय से कम है तो वह संयुक्त-परिवार से श्रलग होकर आयकर के बीक से बच सकते हैं परन्तु यदि साथ रहें तो सभी की क्राय जोड़ कर इतनी हो सकती है कि क्रायकर से मुक्तिन मिल सके। उदाहरण के लिये यदि एकपरिवार में चार पुरुष हैं आरे वह कुल हु इजार रुपया प्रति वर्ष कमाते हैं तो उनको आय-कर देना पहेगा क्योंकि कानून के श्रनुसार हिन्दू-संयुक्त परिवार की ⊏४०० रुपया वार्षिक श्राय से श्रविक श्राय पर श्राय-कर देना पड़ता है। परन्तु यदि चारों व्यक्ति संयुक्त-परिवार से सम्बन्ध विच्छेदकर लें और अलग-अलग रहने लगें तो प्रत्येक चार हजार रुपया वार्षिक कमा सकता है और उसे आय-कर भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि कानून के अनु-सार व्यक्तिगत स्राय ४२०० रूपया वार्षिक होने पर ही स्राय-कर लगेगा। इसी प्रकार सम्पत्ति-कर कानून के अन्तर्गत व्यक्ति गत रूप से एक लाख की सम्पत्ति पर आय-कर की छूटमात है परन्तु स्वुक्त-परिवार में प्रत्येक पुरुप सदस्य को येनल ५० हजार क्यमें की सम्यत्ति पर ही सम्यत्ति-कर से छूट मात है, इसने अधिक की सम्पत्ति होने पर कर जुकाना पढ़ेगा परन्तु चिंद वह संयुक्त-परिवार से अजग हो आर्य तो एक लाख क्यमें को सम्यत्ति पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त किसी की सुन्यु हो जाने पर यह समन है के संयुक्त-परिवार को अस्पत्ति कर जुकाना पड़े जब कि प्रथक रहने पर ऐसा होना इसना अधिक सम्भव नहीं है। कर-सम्बन्धी यह कानून पनवान वर्ग ही अधुक्त-परिवार सभा को तोज़ रहे हैं।

पंचायत (Panchayat)—प्राचीन सारत में पचायत अस्यस्त सहस्वपूर्ण संस्था भी जिसे प्रशासन, न्याय और राजस्व सभी आधिकार मास थे। परमु जैसे-जैसे समय श्रीतदा यद्या आर्थिक परिस्थितियों ने परिवर्तन होने से तथा प्रशासन और स्माय के फेन्द्रीकरण से पंचायतों का महत्व घट गया और कमशा चह नगरम हो गर्यो। देश के कुछ आगों में पंचायतों स्थापित रही परस्त केसल एक सामाजिक सस्था के रूप में बहाँ लोग आयस में मिल सकते, गय्य कर सिकं और हुक्का पी सकते ये और कभी कमी आठे-मीठे मारणें भी सथ कर लिये जाने थे। परमु पचायत ने प्रशासन और स्थाप के सेन में अपना प्रभावशाल कर ली दिया। परमु पचायत ने प्रशासन और स्थाप के सेन में अपना प्रभावशाल कर ली दिया।

इयदस्या के प्रति विशेष किथ दिखायी जाने के कारण पंचायत-प्रणाली को जुनः जीवन प्रदान किया गया है और पंचायतों को कान्ती मान्यता और कुछ प्रशासन तथा न्याय अधिकार प्रदान करने के लिए कुछ दायों ने आवश्यक कानून भी बनाये हैं। परन्तु अब तक पनायते स्ट्रायजनक शर्य नहीं कर पायी हैं क्योंकि जिन लोगों को पंचायते का कार्य शीया गया है वह निर्दर हैं और प्रशासन तथा अध्यालत की कार्य-प्रणाली की उनको आवश्यक जानकारी नहीं है, खाय ही उनको जावश्यक जानकारी नहीं है, खाय ही

पंचायती का कार्यचेत्र बहाने का प्रयत्न किया जा रहा है और उन्हें द्वार्थिक नियोजन का प्रभावशाली लावन बनाने का प्रयत्न हो रहा है। संविधान के ४० में अनुन्छेद में कहा गया है कि राज्य प्राप्त पद्मायतों को स्थापना करने ग्रीर उन्हें स्वधासन की हकाई बनाने के लिए आवश्यक कर्षिकार हिलाने के प्रमुख्य में कार्रवाई करेगा। राज्य यरकारों द्वारा पञ्चायतों को कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं परसु यह उतने नहीं हैं जितने को संविधान में ज्यवस्था की गई है।

्या १६.५५ में पिमला में स्वायत-शासन मंत्रियों का सम्मेलन हुन्ना पा जिसमें यह सिर्फार्शिय की गई कि पंचायतों को ऋषिक प्रमालशास्त्री बनाने के लिए श्रिषिक न्यापक श्राधिक, प्रशासकीय और न्याय श्रधिकार दिये जाने चाहियें। यह सुमान दिया गया कि द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में 'नीचे से ऊपर की छोर' योजना बनायी जाने की न्यवस्था की जानी चाहिए खीर धाम की ही नियोजन की इकाई बनाना चाडिए। अखिल भारतीय वांग्रेस कमेटी ने जलाई १९५४ में श्रपने खजमेर श्रविवेशन में इस बात पर विचार किया श्रीर श्रनमान है कि उसने इस प्रस्ताय को स्वीकार कर लिया । योजना में यह क्यातस्था की गई है कि प्रजायतो हो स्वरायत हो रामावशाली श्राप्तारभत इकाई श्रीर तीचे से योजना इताये जाते के लिए प्राचारभत एजेन्सी बनाया जायगा। एक गाँव सभा का निर्माण सारा गाँव करेगा और निर्वाचन के छाधार पर ग्राम पंचायत बनायेगा जो गाँच सभा की कार्यकारियों होगी। पंचायत को जो कार्य संध्ये आयंगे उसमें लगान वसली, अमि सम्बन्धी कागजात रखने (इन्दराज), समान उप-योगिता की सरकारी जमीन का प्रचम्ध, काश्त के लिए लगान पर जमीन देना, बहधन्यो ग्राम सहकारी मिर्मित्यो का विकास करना और अपने अधिकार लेख के अन्दर सार्व-इतिक उपयोग के कार्यों के सिए सह से अभिवार्यंतः कार्यं करता आहि कार्य समिलित हैं। प्राप्त के विकास की नीति पंचायत निर्धारित करेगी, श्रीर भमित्त-रण, यनों के विकास, इंधन के सुरक्तित सुख जमा करने, वाँध और जलाशाय बनाने, वयरक शिक्षा, अब्छे बीजों की पृति, और काश्त के नये और सधरे हुए उपायों को लाग करने की समस्याकों पर भी पंचायत विचार करेगी और इस दिशा में श्रावश्यक कार्रवाई करेगी।

हितीय पंचयपीय योजना नीचे से ऊपर की खोर बनाई गई है। राज्य परकारों ने एक-एक गाँव के खायवा गाँवी के चमाई के लिए जैसे तहणील, ताजुका, पिकाव-पीली की इकाइयों के खायार पर योजना बनवाई है। इस कार्य में पनापतों ने चहुत महत्वालां सहयोग दिवा है पर यह कहता कितन है कि स्पानीय योजनाझों के बनाने में वे बचार्य में कार्यधील रही है खोर ये स्पानीय योजनाझें इस योग्य रही हैं कि उनको राज्य द्वारा बनाई शरका में सन्मिलत कर विषा जाता। को कुछ भी हो पनायत के सहत्यों की यह बान हो गया है कि हितीय योजना की यस्त्रता के लिये उनके सहयोग की खावस्यकता है। इससे स्थानीय लोगों का उत्थाद खबस्य बहा है खोर वे योजना के प्रसि जानकर हो गये हैं।

उरकार की नीति यह है कि "अत्येक गाँव में ख्रीर विशेषकर उन दोनों में जो राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं ख्रीर सायुदायिक विकास योजनाखों के लिए चुने गये हैं एक फान्दिन के ख्राचार पर पंचायत की स्थापना की आय। प्रथम पंचवरीय योजना काल में पंचायतों की संख्या ८३०८० से बढ़ कर १९०५६ हो गई; में वित्तीय योजना के कार्यक्रम के खनुतार १९६०-६१ तक माम पंचायतों ही संख्या बढ कर २४४५६४ हो जायगी<sup>33</sup>। यह सोचना यक्तिसंगत है कि भनिष्य में पंचायतों को अधिकाधिक सहसा दी जायशी और वे योजना को कार्य रूप में परिचित करने का एक प्रभावशाली साधन हो जावंगी। परन्त अभी तक तो ग्राम पंचायती का कार्य बहता ही श्रामतोषज्ञ करहा है। इसके अनेक कारण है जैसे (१) "शाम पचावतों के प्रभावशाली न हो सकते का सबसे बढ़ा कारण उनके पास साधन का ऋभाव रहा है। बहत सी प्रशायतो की प्रति व्यक्ति वार्षिक थाय २ था। या ३ था। रही है"। टेक्जेशन इन्क्यायरी कमीशन (१६५३-५४) ने अपनी रिपोर में इस बात की ओर स्थान खाक(पत किया था कि प्राहेशिक सरकारें "पचायतों को कहा करों के लगाने का अधिकार दे कर उन्हें अपने आप क्रमनी सहायता करने के लिये छोड़ देती हैं। इसका परिजाम यह होता है कि प्राय: पंचायतें कारम्म होते ही करों के जारम्म वरने के कारण जनता की कापभाजन बन जाती हैं और यदि करों का ग्रारम्भ न वरें तो निष्क्रिय हो कर जनता की दृष्टि में जीचे गिर जाती हैं? । इसलिये पचायतों के कार्यको सफल बनाने के लिये धवसे अधिक आयश्यक बात यह है कि उन्हे पयास विस प्रदान किया जाय। (२) दूसरी कटिनाई यह है कि पचायतों के ऊपर उनके साधनो श्रीर शक्ति की श्रपेता श्रत्यधिक कार्य मार बाल दिया गया है। प्रादेशिक सरकार किन्होंने पंचायतो को अनेक उत्तरदायत्व सीप स्वर्ख है पचायतों मे श्चावश्यकता से आधक आशा करती हैं। बिस्ट्रक्ट बीड और पनावती के हित भी ब्राप्त में टकराते हैं क्यों कि दोनों के कार्य चैत्र एक दूसरे की सीमा का श्रातिक्रमण करते हैं। इस सम्बन्ध में टेक्जेशन इनक्यायरी कमीशन ने यह चिकारिश की है कि छाथिक चेत्र और उत्पादन सम्बन्धी कार्य जो सहकारी चिमातियो हारा अधिक अञ्ची तरह किये जा सकते हैं। उन्हें नियमित रूप से पंचायतों के अन्तर्गत आये हछ कार्यों से अलग कर देशा चाहिये। इस इसे भी आवश्यक समस्ति है का पचायनों के लिये जियमावली में दिये गये अस्पर्ध कार्यों के स्थान पर थोड़े से खुने हुये कार्य ही दिये सार्वे ताकि उनका जिला बोर्ड तथा श्रन्थ स्थानीय ग्राम कोई के कार्यों से सामैजस्य सम्भव हो सर्व । (३) पंचायतों के मेम्बरी को उन कार्यों की कोई । शक्ता नहीं (मली है खो उनको (दये गये हैं। इनके विचार प्राचीन है, उधर उनके मन में स्थानीय कारणों से उत्पन्न द्वेप भावना भरी है, इस्तिये जो समस्यार्थे उनके सामने श्रक्त अभिन्ता और जास हेप के कारण उपस्थित हैं उनकी दर करने के लिये उनके विचार में वे ही पुराने दंग आते हैं जिससे वे ऋपना कर्त्तंब्य संतीपज्ञनक दश से परानहीं कर पाटे।

### च्यध्याय ४

## कृषि उत्पादन और नीति

मारत ऋषि प्रधान देश है। भारत का दुल चेत्रकल शक्तिम गणना के श्रदुश्चार लगभग ⊏१ करोड़ २० लाल ५० हजार एकट है, परन्तु श्राधि से बहुत कम भूमि ऋषि के काम श्रा रही है।

प्रथम वैज्ञानीय योजना की स्वयंत्रा बनाजे के पहिले हो योजना ह्यायोग ने कुछ प्रदेशों में विद्युले ४० वर्षों में विभिन्न फसलों के उगाने में लगी हुई भूमि की जॉच की। इससे यह पता लगा कि (१) खेती की जाने याली भूमि का चेष-फल उत्तर-प्रदेश को छोडकर कहीं भी विशेष मात्रा में नहीं बहा । एक में श्रीधिक फर्सलें उगाने बाले चेत्र में २०% को वृद्धि हुई, परन्तु यह वृद्धि बदती हुई जनसंख्या की तुलना में नगएर थी, (२) सिचाई का चेत्रपाल १०% बढ़ा जो कि मुख्यतः नहरों के विस्तार का परिशास था, (३) परती छोड़ी हुई समिका चेत्रफल १६२०-४० तक के ही स्तर पर रहा । उसके बाद कछ वृद्धि वह का उत्पादन करने बाले क्षेत्रों में हुई क्योंकि यकायक हुई उत्पादन क्षेत्र में कमी हा। गई ब्रीर जैस परती छोड़ हिये गये। किस प्रकार की फसलें ज्याने की प्रवित प्राय: लोगो की रही, इसका योजना आयोग ने अध्ययन किया और इस परियाम पर पहुँचे कि (१) पिछले १० वर्षों में बदापि दहरी फसल उत्पन्न करने के कारण फसलों के श्रन्तर्गत कुल चेत्र में वृद्धि हुई पर कोई भी नया भूभि का भाग खेती के कार्य में नहीं लाया गया, (२) मूल्यों में परिवर्तन के कारख करलों की किस्म में परिवर्तन म्रा गया यदापि मधिकाश ये फसलें छोटे-छोटे खेतो से उत्यन की सानी थीं. (२) खाद्यान तथा व्यवसायिक फसलों के बीच अदला-बदल किसी विशेष दंग पर नहीं हुई वस्तू भीतम फतलों के हेर-फेर, मूल्य परिवर्तन और कितान की द्यार्थिक शक्ति पर निर्भार रही।

खाद्यान चीर करने माल में कभी—यह याश्रयं की वात है कि कृषि-प्रधान देश होते हुए मी भारत में खाद्यान की कभी है श्रीर उद्योगों के लिए कच्चे मंग्रत का श्रमान हैं। हम श्रमाना के मुख्यतः तीन कारख हैं: (१) १६६६ में बमा को भारत से श्रना कर देने के कारण देश अस्टर हो ग्रह हो जाने वाली खाद्यान की मात्रा में १३ लाख टन की कभी होगई; (२) १६४७ में देश-विभाजन हो जाने के कारण उस मात्रा में ७५ लाख टन की श्रीर कमी हो गई; (३) देश की जनसंख्या प्रतिवय १ है प्रतिशत को दर से बढ़ रही है, परन्तु खाबान की मन्या में इसी दर से बृद्धि नहीं हुई है जिसके परिखाम स्वरूप खावान का प्रमाव हो गया। सन् १६४८-५० में देश को ४६० लाल टन अन को उत्पत्ति और सरकारी मोदाम तथा विदेशों से मेंगाये अज को मिलाकर प्रति वयस्क १३०६ और अज प्रतिदिन पहता या। यदि नमसंख्या आधिक होती वो प्रति क्यांक अत का माग और भी कम होता। पीष्टिक पदार्थ सलाहकार समिति के विचारता, प्रमात प्रति स्वरूप स्वर्क्ति (वयस्क) १४ और अज प्रतिदिन आवस्थक है। दसलिए प्रथम पद्मप्रयोग योजना ते ७६ लाल टन युन को उपक बढ़ाने का निक्षय किया था।

पौद्रिक परार्थ खलाइकार समिति के सुम्माव के श्रमुखार सन्तुलित भोजन के लिये प्रत्येक व्यक्ति को इ औष दाल मितिदिन खानी चाहिये। १६५०-५१ में ८६ लाख दन दाल पेदा हुई, मिटमें से सरकारी स्टाक, बीज इन्यादि के लिये २० मित्रिय निकाल देने के प्रधार्त मित्रिय नयस्क को मितिदिन २१९ ग्रीष दाल मिली। इस मकार प्रथम पञ्चवर्षीय योगना के अन्तर्यात बढ़ी हुई जनसंख्या के श्रितिरिक आवश्यकता ५ खाल टन नो और इ और व द्वीक्त के हिशाद से ४० लाग दन की अरमानित की गई थी।

१६५०-५१ में ५१ लाख टन तिलहन की उपज हुई जिसमें से लगभग १६ लाख ६० इजार टन तेल मात दुआ। शाबुन, 'ग तथा वार्निश बनाने के काम में मयुक्त तेल को अलग करने के पश्चात् रोध १६ लाख टन तेल घरेलू कार्यों के लिए बचा। इसके अनुसार प्रति वयस्क की प्रतिदिन ०५ औंस तेल मिला, जो ब्रावश्यकता से बहुत नम था और इसलिए उसकी मात्रा बहुानी ब्रावश्यक समसी गई। जहाँ तक क्पास का प्रश्न है, १६५० ५१ में २६ लाख ७० इजार गाँठों का उत्पादन हुआ (प्रत्येक गाठ का बजन ३६२ पींड) जब कि खपत ४० लीख ७० इजार गाँडों की थी। उत्पादन और खपत के इस भ्रानर को प्रतिवर्ष लगभग व्ह • इजार गाँठों का आयाद करके पूरा किया गया। अनुभाव लगाया गया है कि १६५६ में ५४ लाख गांठों की शावश्यकता होगी। जुट के उत्पादन के विषय में सरकारी तार पर यह अनुमान लगाया गया है कि १९५१-५२ में ३३ लाख कब्चे जुट की गाँठों का उत्पादन किया गया। और मेस्टा (Mesta) की ६ लाख गाँठें पैदा की गई, जो जूर से घटिया किस्म की उपज है और जिसका उपयोग जुट न मिलने पर किया जाता है। ब्रानुमान है कि १६५६ में ७२ लाख गाँठों की त्रावस्यकता होगी। इस प्रकार माँग और पूर्वि में ३३ लाख गाँठों का अन्तर रह गया।

इस अध्ययन से यह प्रकट होता है कि प्रथम पंचवर्षीय थोजना के आरंभ

में खायाल और उचोगों के लिए कच्चे माल दोनों का ही अमाव था। मारत को स्वावलम्यी बनाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए यह निश्चित किया गया कि देश के अन्दर ही इनका उत्पादन बढ़ाया जायगा। यदि उमस्या केवल खावाल या व्यवसायी फाउलों की पूर्ति की माजा बढ़ाने की होती, तो इसके लिये धीर और एक फाउल की जमीन के हुयरी एसल के उत्पादन के लिये व्यवहार में लाया जा सकता था। परन्तु समस्या होनों फाउलों के उत्पादन में वृद्धि करने की थी. जिससे मींग और एति के बीच का मारी अन्तर दर किया जाय।

खादास जाँच बसेटी की रिपोर्ट-कमेटी, जिसके श्रम्पन भी श्रशोक मेहता ये तथा जिसने नयम्बर १९५७ में खपनी रिपोर्ट प्रस्तत की, इस निष्कर्ष पर पहुँची कि खाद्यान की कुल उत्पत्ति १९५३-५४ के ६८५% लाख दन में घट कर १९५४-प्य में ६७१'र लाख दन तथा १६५६-५७ में ६५२% लाख दन हो गयी। इसके ब्रमन्तर प्रवृत्ति में पृश्वितन हम्रा ब्रौर १६५६-५७ में खाशोत्पादन बदकर ६८६.६ लाख टन हो गया। खादाल के मूल्यों एवम् खाद्य सामग्री के श्रमाय की वृद्धि निम्न कारणों से हुई। (1) क्रमकों ने खपनी उत्पत्ति का खिक मारा स्वय रख लिया । अनएव मुल्यों की वृद्धि से जितना विकोत-श्राविशक (marketed surplus) की कमी का हाथ था उतना उत्पादन की कमी का नहीं था। १६५५-५६ में मीटे अनाज (millets) की उत्पत्ति में ३० लाप टन की कमी हुई जिसने मूल्य वृद्धि का कम प्रारंग किया और १६५ :- भू६ में चावल तथा गेह की माँग बढ़ने के कारण खाद्यात के मूल्य बढ़ने लगे। यद्यांत बाद में उत्पादन बढ़ गया किन्द्र मूल्यों में फिर भी चूढि होती रही । (11) द्वितीय योजना के ग्रन्तर्गत होने वाले स्थय तथा वैंक उदार की वृद्धि ने भी मुल्य-स्तर के बढ़ाने में मदद की, तथा (!!!) "खाद्य स्थित के बारे में अध्यधिक श्राशावादिता ने श्रानेक राज्यों में खाद्योत्पादन की बुद्धि कं प्रयक्तों को या तो शिथिल कर दिया या उनमें तीवता नहीं आने दी"।

भारत की जन सख्या की प्रतिवर्ध १३ - २ प्रतिशत बृद्धि के आधार पर कमें टी ने अनुसन लगाया कि खावाओं की साँग में बहुती हुई जनसंख्या के कारवा १०% तथा आप की बृद्धि से ४.७ प्रतिशत बृद्धि होगी। इस प्रकार द्वितीय सीनता में लाट्यान्मों की साँग १४५ वे १५ प्रतिशत तक बढ़ जायारी अपाँत १६५५.५६ में ६६० लाल टन हो जायगी जबिक उत्पत्ति में केन्न रन रे से बहु हर १६६०-६१ में ७६० लाल टन हो जायगी जबिक उत्पत्ति में केन्न १०१ लाख टन की वृद्धि की आशा को जाती है जिसके कलस्वरूप १६६०-६१ से कर उत्पत्ति वदकर ७७६ लाख टन हो जायगी। कमेटी इस निष्कर्षे पर पहुँची कि कुछ अगामीयार्ध में प्रतिवर्ध २०-३० लाख टन खायान्त का आयात करना आवश्यक होगा।

कमेटी ने खादान्तों के सम्बन्ध में मूल्य-स्पापित्व (price stabilisation) की नीवि की सिफारिश की I (i) इस हेन उन्होंने उचाधिकारों से सुक 'म्लय-स्थायित्य परिषद' (Price Stabilisation Board) की नियक्ति प्रस्तावित की जिसके कार्य मूल्यनीति का निर्घारण तथा उमे लागू करने के उपायों का निर्णय करता या। (ii) नीति की कार्याक्यत करने के लिए खाद्यान्न स्वायित्व संगठन (Foodgrains stabilisation Organisation) के निर्माश की भी छिफारिश की गई। यह संगठन खाय और कृषि मजालय का एक विभाग हो सकता है या एक परिनियत निगम (Statutory corporation) अथवा उभित दायित्य बाली कर्यनी का रूप भी ले उकता है। यह संगठन खाबाल बाजार में एक व्यापारी की भौति काम करेगा छोर जन्तःश्य-स्कन्ध (bufferstock) का काम करेगा अर्थात मूल्य भारते पर खरीदेशा जो छीर बहने यर वेचेशा । (iii) खाद्य महालय तथा मूल्य स्यायित्य परिषद की सहायता के लिए केन्द्रीय लाख परामर्श समिति (Centralfood Advisory Council) के निर्माण की भी विकारिश की गई। (vi) प्रसंतातुक्त एवम् विश्वासनीय ग्राँकडे एक्ट करते के लिए सूहय-जानकारी-संभाग ( price Intelligence Division ) की स्थापना की मी विकारिश हुई । परामर्श समिति तथा जानकारी संभाग की सहायका से मूल्य-सामित्य परिपद का उद्देश्य मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर सतकता बरवने तथा समय समय पर न केवल सामान्य मूल्य स्तर के स्थित बनाये रखने यरमू विभिन्न परतुत्री के मल्यों में खनचित अन्तर को रोकने के लिये खावश्यक कार्यायाही की रिफारिश करना था।

हण बात को ध्यान में रखने हुये कि वर्तमान परिस्पितियों में स्वतंत्र क्यापार आयादानीय है तथा पूर्ण-निर्यंत्रण (Full-fledged Control) आर्थिक एक्स मधा-खकाव कडिनाइयों के भरा है, कसेटी ने एक सध्य-मार्ग की किसरिया की जिबके अंतर्गत निर्वंत्रण का कंट्रेशन खुले बाजार में खादाल के अध्य-विक्रय तक सीमित रहेगा, पांक क्यापार का अंतराः समाजीकरण होगा, अनुज (License) द्वारा रोग बाजार में कार्यशांक व्यापारियों पर निम्बन्ध होगा, तेहूँ और चावल का पर्यांत स्टेंक रका आया। तथा अन्य पुत्त वाष्ट्र मामग्री के अपमीय और उत्पादन की बंद के लिये प्रचार का संगठन किया आया।

इत्यादन प्रवृत्ति —स्वतन्त्रता प्राप्त होने के उपरांत भारत में खाचाज श्रीर श्रम्य कृषि-सम्भन्ते कच्चे माल के उत्पादन में कभी श्रा गई है। १९५०-५१ में साधान का उत्पादन ५०० लाख टन हुआ, जनक १९४६-५० में इसका उत्पादन ५५० लाख टन हुआ था। कृषि-सम्भन्ति कच्चे मालों की उत्पादन प्रवृत्ति

थोडी भिन्न थी। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के तरन्त बाद उत्पादन में कमी थ्रा गई. किन्त तत्पश्चात उसमें फिर बह्रि हो गई। १६४८-४६ में तिलहन का उत्पान ४५ लाख दन, क्यास का १७ लाख ७० इजार गाँठों और कच्चे जर का २० लाख ७० हजार गाँठों तक ही घटकर रह गया। गरने का उत्पादन भी कम होकर ४⊏ लाख ७० हजार दन ही रह गया । किन्त श्रमले वर्षों में इन कच्चे मालों के उत्पा-दन में वृद्धि हुई और १६५०-५१ में, जब कि खादाज का उत्पादन गिरता जा रहा था. उनको उपज बहनी प्रारम्भ हुई।

'श्रधिक-ग्रय-उपजान्त्रो' ज्ञान्दोलन के बावजद खाद्याय के उत्पादन में कमी छाई। बहत संभव है कि खाराज उत्पादन के सरकारी खाँकहे किन्द्रल ' सही न हो । परन्त इस बन्त में कोई सन्देह नहीं कि सही शाँक है चाहे कल भी हों. श्रानेक कारणों से खादास्त का उत्पादन पिछले कछ वर्षों में काफी जिए लगा :

(१) देश के करू भागों में सखा पड़ने और कहीं कहीं बाद था जाने से खाशास के उत्पादन में आंशिक कमी अवश्य हुई है, परन्त केपल प्रकृति का कीप ही जलादन की गिरायट के लिए जनस्टायी नहीं है ।

(२) यह भी सकाव दिया गया है कि कवि-सामग्री की ऊँची कीमतें भी कुछ ग्रंश तक कृषि-उत्पादन घटने का काइण हैं। साधारण रूप से श्राधिक कीमत का श्रधं है ग्राधिक उत्पादन, परन्त जहाँ तक किसान का सम्बन्ध है ग्राय की लोच (Elasticity) ऋणात्मक (negative) है। इसका तालमें यह है कि किसान कछ श्राय बाहता है श्रीर जब कीमतें श्रविक होती हैं तो वह धोडा सा उत्पादन करके उसे प्राप्त कर लेवा है. किन्त जब कीमतें कम होती हैं तो असे द्याधक उत्पादन करना पहला है। इसलिये जैसे हो खाबाब की कीमतें बढ़ी। इसने अपना उत्पादन कम कर दिया । चुँकि कीमतो श्रीर उत्पादन के पारस्परिक सम्बन्ध का विस्तारपूर्वक ग्राध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए यह कहना संग्रव नहीं है कि यह विदान्त भारत में कहाँ तक लाग होता है।

(३) ख बाज के उत्पादन से कसी श्राने का एक कारण यह भी है कि गद्धे. वर्ड ग्रीर जट की श्राधिक ग्रायश्यकता होने के कारण खाशाझ के उत्पादन में प्रयक्त मि के कल माग में अब व्यवसाई फरालें बोई जातो हैं।

भारत-सरकार के 'ऋधिक-अब-उपवाओ' आन्दोलन से खादान की कमी पूर्ति करने की जो आशा की गई थी, उसमें अधिक सफलता नहीं हुई क्योंकि (थ) इस ग्रान्दोलन में पहले से ही काश्त की जाने वाली जमीन में उत्र दन बहाने की अपेद्धा नयी भूमि को खेती के योग्य बनाने पर अधिक जोर दिया गया। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी आर इससे निकट मविष्य में उत्पादन बहाने की

त्राशा नहीं की जा सकती थी। 'श्रविक-सब-तपजासी' सान्टोजन की सीति में परिवर्तन कर श्रव श्रहणकालीन योजनाश्चों पर जोर दिया गया है, जिसके श्रन्तर्गत खाद्याच का उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज और खाद दी जाती है और साथ ही साथ सिचाई की भी व्यवस्था की जानी है। आरंग में यह जान्दोलन देश के जन भागों में चलाया गया था बहाँ सिंचोई की सुविधाएँ नहीं भी और इसलिए स्कृतोष्ट्रस्य है परिवास सही जिसते । बाद की नीति बदल ही गई और याजसाओं को प्रार्थ स्थलो पर जलाया गया है सहाँ सिंचाई की सविधा परले ही से घी बा सरलता से आवश्यकतानसार व्ययस्था की जा सकती थी। इसका परिशाम यह निकला कि 'स्थिक सम्ब स्थानको? स्थान्दोलन में सन्तोयजनक प्रगति हुई: (ब) यह आधनत खेट का विषय है कि 'अधिक-अझ-उपजाओं' आस्ट्रोलन का काय-भार जिन ऋधिकारियों को सीवा गया है यह सदैव ईमानदारी स्त्रीर लगन से कार्य नहीं करते हैं। बहत सी बातों में काम कुछ नहीं किया जाता. केवल कागजी खाना पूरी कर दी जाती है जार बहत बार पेसा भी होता है कि जो शीज या खाद खादि किसानों को मिलनी चाहिए या, उसे या तो वेच दिया गया या उसका रुपया स्वयं रख लिया गया। इस ऋान्दोलन में या किसी भी नियोजन े के अस्तर्गत योजना को सचाह क्रय से कार्योश्वित करने के लिए एड ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो कि मुसंगठित हो ल्योर जिसके समचारी पूर्णकर से हैमान-दार हो। (स) किसानों ने भी 'श्राधिक श्राब-स्पनात्रो' श्रास्टोलन को जनना सहयोग नहीं दिया जितना उनसे छाता की जाती थी।

१६५४-५५ और १६५५-५६ में हुई उत्पादन की योक्षी ची कभी को छोक कर १६५१ के उपरान्त खावाज के उत्पादन में सन्तोपजनक दृद्धि हुई है। १६५०-५१ में भारत में खावाज का उत्पादन ५०० लाख दन या जो १६५१-५५४ में इस्क काख दन हो गया। चनसे अधिक वृद्धि चावक के उत्पादन में हुई और इस्क में बाद कमया। बेहुँ, बाबता, ब्हार और जी की उपन बडी। खायाज के उत्पादन में यह वृद्धि इन कारवी से हुई, (१) भीचम की अपुक्त परिस्पतियाँ, (२) १६५०-५१ में मार्रम किए गए सपटित उत्पादन कार्यकम (Integrated Production Programme) को गण्यता, (३) चावल उत्पन्न करने की जावानी पद्धित का प्रयोग, सिचाई की अधिक सुवेषाएँ और किसानों को आर्थिक सहायकों के रूप में राशाविनक सार्दे (Pertilivers) आदि देना। १६५४-५५ तथा १६५५-५६ में उत्पादन यहक कमरा: ६०१.१ लाल

टन तथा ६५२६ लाख टन होने के कारख (i) देश के कुछ मार्गो में सूखा, (ii) टर्वरक स्था अच्छे भीजों का श्रमाय तथा (iii) राज्य सरकारों द्वारा प्रयत्नों में दिलाई देना था जो अंशतः उनकी लापस्वाही तथा अंशतः द्वितीय योजना के लाखाल की उत्पत्ति और कृषि पर अपयौत प्यान देने के फलस्वरूप हुई। १६५६ ५७ में उत्पादन के इन्दर्ध लाख टन तक बहु जाने के भावजूद भी पिछले दो वर्षों में उत्पादन के किसते से मूल्य नद गये जिसके फलस्वरूप सामान्य व्यक्ति को में भी किताई का सामान करना पड़ा। लाखाल का जायात, जो १६५१ में ५० लाख टन के जैंचे स्तर से घटकर १६५४ में ८ लाख टन तथा १६५४ में ७ लाख उन हो गया था, पुनः १६५६ में बहुकर १४५ लाख टन तथा १६५७ में ३ लाख टन हो गया था,

फर्च्य माल के उत्पादन की स्थिति कुछ भिन्न ही रही है। १६५२-५३ में रहें श्लीर जुट का उत्पादन विज्ञले वर्ष के ही स्तर पर (३२० लाल श्लीर ४६० लाल गाँठ कमशः) श्री पर तिलहरू श्लीर मने की उपन कमशः ४७ लाल टन श्लीर ५० लाल टन हो गई। अगले पर्यों में जुट की छोक्कर इन सभी १९५६-५७ में अनुमान किया जाता है कि जिलहरू ६० लाल टन, वई ४७.५ लाल गाँठ तर ४२४ साल गाँठ श्लीर गांजा ६५ लाल टन होता।

प्रधान पंचवर्षीय योजना के कान्तरीत—प्रधम पंचवर्षीय योजना का भ्रेय लाबाज तथा उद्योगों में काम प्रानं वाले कच्चे माल की उत्पत्ति इस दृष्टि-कीस से बढ़ाने का था कि (१) देश आज्ञा निर्मरता प्राप्त कर ते, (२) मारतीय उद्योगों को मौंग पूरी हो सके और (३) प्रति व्यक्ति अस्त का उपमोग यहुत्या ला सके।

।थम पंचवर्धीय योजना के लच्छ

प्रथम पन्चयपाय याजना क लच्च						
चस्तुयें	श्राधार माने हुवे साल में उत्पत्ति	पस्ताबित श्रतिरिक्त उत्पन्तिश	प्राप्त कर सैने	आधार माने हुये वर्ष की तुलना में प्रतिशत चृद्धि		
ঝাঘার	५४० लाख उन	७६ लाख टम	६१६ लाख टन	5.8		
विलइन	५१ लाख टन	४ लाख टन	५५ लाख रन	=		
गन्ना (गन्न)	५६ लाख दन	७ लाख टन	६३ लाख टन	१३		
(गुड़) रुई	२६ लाख गाँठें	१३ लाख गाँठें	४२ लाख गाँडे	8.4		
ज्ङ	३३ लाख गाँठैं	२१ लाख गाँठे	प्प लाख गाँठे	ξ¥		

क्षाबाकों के लिए श्राधार वर्षे १६४१-५० है और अन्य के लिये १६५०-५१ है।

खाराज में प्रस्तावित ७६ लाख दन की वृद्धि में से ४० लाख दन चायल. २० लाख दन गेहॅ, १० लाख दन चना श्रीर श्रन्य दालें श्रीर ५ लाख दन में अन्य अब हैं। जैसा कि जपर संकेत किया जा चुका है। उपज ६५० लाख टन हुई। (बजाम ६१६ लाख टन के जो कि लक्ष्य था) गेहूँ, चना और दालों के जवज की मात्रा एक्ताबित लक्ष्य से अधिक बट गई है परना चायल की उपज विद्वले वर्ष में बहुने के पश्चात १९५४-५५ में बाह आदि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण धट गई। यह कभी समार के सभी चावल उत्पन्न करने वाले देशों में हुई थी। पर १९५५-५६ में किर उत्पत्ति कुछ बढी । व्यवसायिक फसलों में से तिलहन ग्रीर रहें की उत्पत्ति योजना के अनुकल बढ़ी पर जट और गरे की उपज में कमी हुई।

प्रध्य योजना के काल में शक्त की उत्पत्ति में बढ़ि सिंचाई की सविधाओं कें बढ़ने, खाद के प्रयोग में ब्राधिन्य और वेकार भूमि को खेती के काम में लाने के लिये फिर से ब्राधिकत करने के कारण हुई, परन्तु यह बता सकता कठिन होगा

कि किस कारण में कितनी यहि हुई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजमा के अन्तर्गत-यविष दितीय योजना में उद्योगां को विशेष महत्व दिया गया है पर कृषि के प्रति उदासीनता नहीं दिखाई गर्ड है। दितीय योजना में इस बात पर श्यान रक्खा गया है कि प्रथम योजना के कार्य में विकास हो और क्रांप उलित तथा कच्चे माल की उत्पत्ति में हमारा देशा यथासम्भय शास्मिनिर्भर हो जाय । दूसरे, यह बाद श्रव्छी तरह समस में ह्या गया है कि खेती का चेत्रफल बढ़ा लेने मात्र से ही उत्पत्ति में झावश्यक बढ़ि न हो सकेगी। अन्त में यदापि लाखान की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है पर दूसरी योजना में उन वस्तुओं की सख्या काफी बड़ी है जिनकी उत्पत्ति बढ़ाने का ध्येय है। ऐसी वस्तुश्रों में चाय, काली मिर्च, लाख, नारियल, वृत्रक्रकल, नपाड़ी भी चर्मिलित हैं। इससे भारतीय किसानों की उन्नति में ।स्थरता छीर विदेशी विनिमय से श्रधिक भाय मास होगी।

यदि वर्तमान दर से ही श्रन्न का उपभोग चलता रहे तो योजना स्नायोग के अनुसार बढ़ी हुई जनसंख्या को ७०५ लाख उन आज की आवश्यकता होगी परना प्रति व्यक्ति अस का उपयोग १८ ३ अति अतिदिन कर देने का विवार है, इसलिये कुल श्रव की ग्रानश्यकता ७५० लाख दन होगी। इसी ग्राधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १६६०-६१ तक १०० लाख मेंन की उपज बढ़ाने का निश्चय किया गया। ग्रन्न की इस बृद्धि में चावल की ३० से ४० लाख टन, गेहूं की २० से २० लाख टन, द्यीर जन्य खर्जों की २० से ३० लाख टन और दालों की १५ से २० लाख टन दृद्धि होची गई है। बाद में ऐसा प्रतीत हुआ। कि खादान्न के

उत्पादन की यह वृद्धि पर्याक्ष नहीं होगी और इधीलिये लक्ष्य बहाकर ८०४ लाख टन कर दिया गया जो १९५५-५६ की तुलना में २४३% अधिक है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गेत कुळ संशोधित रूपि उत्पादन लच्छ

बस्	१६५५-५६ में उत्पत्ति अनुमानित	प्रस्तावित श्रतिरिक्तः उत्पक्ति	१६६०-६१ तक यृद्धि करने की सात्रा का ध्येय	मतिशत		
বাহাপ	६५० लाख रन	१०० लाख टन	८०४ लाख टन	२४.६		
विलद्दन	५५ लाख टन	१५ लाख टन	७६ लाख टन	₹७.०		
गन्ना (गुङ्)	५६ लाख टन	१३ लाख टन	७८ लाख रन	3.55		
सर्दे	४२ लाख गाँउ	१३ लाख गाँउ	६५ लाख गाँठ	५५.६		
जूर	४० लाख गाँउ	१० सरख गाँउ	५५ लाख गाँठ	५८.१		
श्चन्य फसले				44.8		
सत्र वस्तुय	509		***	₹७.⊏		
सशोधित सहयों के ब्रान्तर्गत व्यवसायिक फसलों के समान्य में यह मस्ता-						

सशीधित लक्ष्मों के ग्रान्तर्गत व्यवशाधिक फरालों के समस्य में यह प्रस्ता-दित है कि कपास की उत्पीस ५२ लाख गाँठों से बहुकर ६५ लाल गाँठ, जुट की उत्पास ५० लाख गाँठों से बहुका ५५ लाख गाँठ, जुल (गुड़) की उत्पास ५५ लाख टन से बहुकर ६० लाख टन, तथा प्रमुख तिलहनों की उत्पीस ५५ लाख टन से बहुकर ६० लाख टन की जाय। श्रान्य कृषि एक्खा के समस्य में, आशार वर्ष की दुसना में ६ प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित थी जो अप बहुकर २२५ प्रतिशत कर दी गई है। हिनीय योजना की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि (1) प्रथम पंचवर्षीय रोजना में को की खती के विकास के सम्भव्य में जो कार्य कम ग्रारम्भ किया गया पा वह जाये ग्ला जायया। दूखरी योजना के श्रान्वगत पुरस्य साव इस सम्भव में यह होगी कि लग्ने रेशे वालों कई के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जत्या। लावे रेशे की रहे के उत्पादन में काफी उद्धात की गई है। (11) जुट की उत्पास के सम्भव में बोर इस वात पर दिया रहा है कि जुट की किस्स श्रव्यक्ष की जाय न कि फेवल उत्पत्ति की साना ही। यदि सभी मिलूँ मरपूर काम करें तो उन्हें लगभग ७२ लाल जूट की गाँठी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त १५०,००० गाँठ अपन कामों के लिले चाहिये। [हांगी गन्ने अपना गुड़ का उत्पान दन बहुत देने पर यह सम्मय हो समेगा कि प्रति वास्तर प्रतिदिन १५०२ और का उत्पान कर सकेगा। (१५) अपूर्व को मज़बड़ी के कारण तम्बाकू की इत्तर कई वर्षों से उपन बड़े निम्मकोटि की हुई है जिसके कारण उत्पक्ती पिकी में बड़ी बाया पड़ी। इसके मोहालों में तहा हुई है जिसके कारण उत्पक्ती पिकी में बड़ी बाया पड़ी। इसके मोहालों में तहा कुछ उत्पक्त के अत्याह के अत्याह के उत्पादन पर कोटि की तम्बाकू के उत्पादन पर कोटि कि तम्बाकू के उत्पादन पर कोटि की तम्बाकू के उत्पादन पर कोटि कि तम्बाकू के उत्पादन पर कोटि की तम्बाकू के उत्पादन पर कोटि की तम्बाकू के उत्पादन के अपना को विद्या है।

### खाद्याञ्च नीति

मूल्य नीति—खायान्त के सम्बन्ध में सरकार की नीति है कि (१) मारत की खायान्त के सम्बन्ध में स्वावलसम्बी बनाया जाय, (२) जब तक अभाव की रिपति रहती है तब तक खायान्त के मृत्यों और नितरण पर नियंत्रण रखा जाय, विदेसे उपमोक्ताओं की करिनाई दूर ही और जर्म तक स्ववन हो देश के सभी भागों में समान आधार पर सभी को स्वायान्त सिल सके, और (३) किसान की उन्नके उलादन का उचित मृत्य मान हो सके।

पचत्रपीय योजना में यह टीक ही कहा गया है कि "मूल्य के बढ़ने-घटने में खाद्यारन पर प्रमुख रूप से प्रमान पड़ता है। यदि मन्त्र पर नियंत्रण रखना है तो यह चावश्यक है कि खाचान्न का भाव देस स्तर रखा जाय जो देश को गरीब जनता की पहेंच के बाहर न हो। भारत का बतमान स्थिति में यदि खादास्त की पूर्ति में भोकी भी कभी आहे, तो भाव अपेक्षाकर अधिक चढ आयेंगे। खादान्न का मान बढ़ जाने से रहन-सहन का खर्च बढ़ जाता है और उत्पादन व्यय में भी वृदि हो जाती है। हरुलिए ऐसी नीति जिससे सभी ग्रीर भाव बढ जाये श्रीर रुपमा लगाने का कार्यक्रम ही ठप हो जाय. उत्पादक के लिए किसी भी रूप मे लाभदाक नहीं है। इस कारण खाद्यान्न जीति निवास्ति करते समय इन सभी बातों पर विचार करना आवश्यक है।" आश्चर्य की बात है कि योजना आयोग द्वारा इस सही सिक्षान्त का प्रतिवादन किए जाने के बाद भी भारत सरकार की नीति इसके विल्कुल विपरीत है। साबान्न के भाग ऊँचे रखे गए हैं, जिससे उपभोक्तात्रों को कठिनाइयां का समना करना पढ़ा और उद्योगों के उत्पादन-रुप्य में भी वृद्धि हुई। खाद्यान्न ऊँचे जावों के समर्थन में यह कहा गया है कि (१) यदि खाद्यान्न के भाव गिराए जार्ये तो किसान खाद्यान्न के स्थान पर गन्ना, कपांच श्रीर जूट बोयेगा, जिनके भाव श्रपेबाकत श्रायिक ऊँचे हैं। किसान स्वभा-

बत: ही इन ऊँची कीमतों की श्रोर आकृष्ट होगा; श्रोर (२) खाश्रास्त्र के भाव फेवल भारत में दी ऊँचे नहीं हैं, बिल्क यह रिवित सारे विश्व में है। जब तक विश्व के श्रम्य देशों में खाशास्त्र के भाव नहीं गिरते हैं, तब तक देश में खाशास्त्र का श्रमाय होने के भारता भाव कम नहीं किए जा सकते हैं।

इन नवाँ में सत्य का श्रांश बहस श्राधिक नहीं है । प्रथम तर्क के सम्बन्ध में

यह भ्यान देने याख बात है कि गन्ने, क्यास और जट की कीमत श्राधिक टमलिये है क्योंकि सरकार ने इनको कामत केंची दर पर निश्चित कर रखी है। यदि छाएंम से ही ब्यवसायी फुनलों और खाशास्त्र के मत्यों में कछ समस्य निश्चित किया गया होता तो इस प्रकार को गड़बड़ी कमी नहीं होती। जैसा कि वहले कहा जा चका है कपिसामग्री के सम्बन्ध में मत्ना श्रीर उत्पादन में उत्ता सम्बन्ध होता है। यदि व्यवसायो-प्रमुल छीर खाद्याच्च दोनों के मरूप कम रखे जाने तो दोनों के उत्पादन में बहि होती। परन्त सरकार वारा हवनसायी-उसल का भाव व्यंचा कर हिए जाने में सारी स्थित ही बदल गई और काफी स्थति पहुँची। इसका अब एक यह उपाय है कि कपास, जुट, गरने इत्यादि के मुख्य कम किए जायें। इससे दो लाम होगे : (१) उद्योगो का उत्पादन व्यय कम होना और (२) लाखान के मान घट जावेंने । जहाँ तम दसरे तर्फ का सम्बन्ध है. भारत में न्वायान का भाव इसलिए ऊँचा नहीं है कि विश्व के बाजारों के भाव भी केंचे है। उसका कारण तो यह है कि भारत का उत्पादन बहुत कम है। कछ समय पूर्व भारत में खाद्यान का भाव विश्व-बाजार फं भाव की अपेचाकृत कहीं अधिक था। यदि यह तक सही है तो उस वमय भारतीय कीमतो को इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए था। भारत में ऊँची कीमतों की समस्या केवल दो उपायों से इस की जा सकती है-या तो उत्पादन बढाग जाय श्रथवा श्रावात में वृद्धि की जाय । क्योंकि श्रधिक ब्यय होने के काइस खाबाब का श्राधिक श्रायात कर सकता संभव नहीं है, इसलिए सबसे उपयुक्त विधि यही है कि देश में उत्पादन की वृद्धि की जाय। यदि खादाका छीर व्यवसायी क्सनों के लिए प्रयुक्त भूमि में पाँत एकड़ का उत्पादन बहाया जाय, तो दोनों फिलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक फसल मोदै जाने वाली जमीन पर दूसरी फलल बोदै जाय । सिंचाई की व्यवस्था, श्रव्छे यीज और श्रिषक खाद के द्वारा प्रति एकड उत्पादन बहुा सकना संमव है।

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त सबसे पहले ११.५४ के मध्य में सरकार का ध्यान इस ब्रोर ब्राम्हर्षित किया गया कि वह ऐसी नीति कार्यान्थित करे जिससे 'किसानों को उनके उल्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो स्के? । पिछले वर्षों में खादाल के मूल्य श्रक्षिक वे ब्रीर सरकार उन्हें नियन्तित करने में प्रवत्नशील भी । फिल्त जब ललाई १९५४ में नई फराल तैयार होकर बाजार में ऋाई, तो पंजाब में गेहूँ का भाव १० स्पए प्रति मन से भी कम हो गया। हापड़ आदि उत्तर-प्रदेश को भी कुछ मंहियों में गेहें लगभग १० ह्यथा प्रति मन के हिसाब से विकने लगा। मुल्यों मे यह गिरावट इसलिए आई कि (१) गेहूं उत्पन्न करने वाले अधिकांश चेत्रो में पिछले वर्षों की अपेजाकत अधिक उत्पादन हन्ना. (२) कय-शक्ति कम हो जाने के कारण बहुत से लोगों ने गेहें का उपयोग नरना बन्द कर दिया, जिसके फलस्परूप उसकी माँग में कमी आ गई. (३) यातायात के साधनो की श्रीयक मधिषाएँ प्राप्त न होने के कारण वह समय न था कि जिन तेत्रों में गेहैं का उत्पादन होना है यहाँ से वह उन केन्द्रों की श्रीधनापूर्वक भेजा जा सके जहाँ उसकी खपत होती है। फलतः मेडियों में उसका भाव गिर गया, श्रीर (४) जिन श्चन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने गेहें के भाव को भिराने से सहायता दी, उनके पीछे एक मनावैशानिक कारण भी था और यह यह कि विश्व मर में गेहें की पृति वह गई थी और उसके मूल्य से कमी छा गई थी। इस सकट को दूर करने के लिए पंजाब मुरकार ने स्वयं १० कपया प्रति यन के हिसाब से युद्ध गेहें खरोदा । उत्तर-प्रदेश सरकार भी छेला ही करने के लिए तैयार थी. दिन्य कालान्तर में मुल्यों मे यूदि हो जाने पर खरकार ने गेहूँ खरीदना अनावश्यक समसा। जब कि गेहूँ और चने के मुल्य में श्रत्यधिक नीचे गिरने की प्रयुक्ति दिलाई पड़ने लगी तब चुनी हुई वस्तुक्रों के मूल्यों की सहायता देने की नीति (Selective price support policy) ना अनुसरण किया गया और अबैल १६५६ में गेहूं, जून में चना और द्यगस्त में बावल इसके द्यन्तर्गत समिलित कर लिये गये। जुलाई १६५५ से खाबाक्षों के मूल्य अधिकार के बाहर जाने खगे क्योंकि बाह ब्रादि प्राकृतिक प्रकारों के कारण जानिक की फसल जिलकल नष्ट हो गयी थी। सरकार की मूल्य स्पिर रखने की नीति के कारण थोडे समय के लिये अन्त की पति में कमी आ गर्या श्रीर जनता की धारणा कछ ऐसी हो गई कि मरूप यह गया ।

मांद खांबाग्र या उचीना में शुक्त होने वाले कर्क्य सालों के मूक्तों के एक निश्चित लागा से श्रांविक कमी हो जाय, तो उनका सरकार द्वारा प्रसीदना उसी सीमा तक वांचन होना बहाँ तक उत्तमें किश्वानों का मला होता है, क्योंित उनके हिंती की सुर्रावित रक्ता उत्तमों हिंदी होने सुर्रावित रक्ता उत्तमों ही स्वयंत्रपूर्ण है जितना श्रीमकों या उपमोकाश्रों क हितों की रक्ता करना। किन्तु इस नीति से कई हानियाँ हैं: (१) यदि मूल्य व्यव्हा की एक हो सोच प्रदेश होते की रक्ता करना। किन्तु इस नीति से कई हानियाँ हैं से प्रदेश मूल्य व्यव्हा की स्वा करना। किन्तु इस नीति से क्षेत्र होती की प्रवास करना कि एक हो साथ प्रस्ते की स्वा करना किए हुए पहले को बंच न सके श्रीर उसे पर्यात उमय तक स्टाक में ही सक्षा पड़िया, श्रीर (३) यदि सरकार किसी श्रानात को एक ही माय पर

बंचने के लिए जोर देती है तो खामान्य मूल्य स्तर में कृतिमता उत्पन्न हो जायगी।
यदि कृषि सम्बन्धी उत्पादन का मूल्य गिर जाता है तो इसके फलस्यरूप थान्य
कीमतों में भी कमी था जायगी। इस प्रकार क्य-शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण
किरानों को तो लाम होगा हो, उसके अतिरिक्त सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था भी
लाभानित होगी बयौंकि खाणाज के किमतों के गिर जाने से खामान्य मूल्य-स्तर
जिन्नित कर में कम हो जायगा।

नियन्त्रसा (Controls)-सरकार की खाबारन तथा श्रन्य सामग्रियो पर नियन्त्रण लगाने की नीति की उपयोगिता पर बहत विवाद चला था। नियंत्रण लगाने का समर्थन करते हुए कहा गया है कि (१) गरीव जनता की कडिनाइयों को दूर करने के लिए और अभाव अस्त स्त्रों को खादान्त भेजते रहने के लिए सरकार द्वारा नियंत्रण लगाना आवश्यक है। नियंत्रण न लगाने से खादाज की कीमतें बढ़ेगी और इससे नियंन जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढेगा. (२) योजना की सक्लना के लिए नियत्रण आयश्यक है. क्योंकि नियोजन और विनियन्त्रख (De-control) साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। किन्त इस तकीं में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि स्वयं नियंत्रण लगान से ही ख्रमाय की स्थित पैदा हो जाती है। यदि नियंत्रण हटा दिया जाय सो बहत संभव है कि शल्ले इन्यादि के खिपाकर रखे गए स्टाक खले बाजार मे ग्राने लगें श्रीर तनके वितरण में सधार हो। वाय जिसके फलस्यरूप श्रमाव की हियति मा दूर हो जाय। चॅकि खाद्याच क सही आँकड़े प्राप्त नहीं है. इसलिए की कमी की मात्रा का ठीक पता चला सकता कदिन है। यह कहा गया है कि जिन श्रीधकारियां पर खाद्यात-नियमण लाग् करने का उत्तरदायित्व है वह श्राभाव को भावश्यकता से श्राधिक श्राकिते हैं जिससे वह काफी समय तक उस पह पर कार्य कर सकें। यदि नियंत्रण हुश दिना जायगा तो यह कृत्रिम स्थित स्वयं दूर हो जायगी। जहां तक नियोजन का प्रश्न है, यह मच है कि विदेशी ज्यापार छाँर विदेशी पूँजी पर कुछ संगातक नियंत्रण रखना आवश्यक है, परन्तु यही तक खायान-नियंत्रण पर लाग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि योजना की कार्यान्वित फरने के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस तर्क का कोई महत्व नहीं है कि योजना की सफलता के लिए नियंत्रस का होना ज्ञावश्यक है।

यदि नियंत्रण कुशलता पुर्वक लागू किए जाते श्रौर उनकी प्रभावशाली वनाने के लिए कड़े उपायों की श्रपनाया जाता तो स्थिति में सुधार होना सैनव या, परन्तु मारत में नियत्रण जितनी श्रांषक कठिगाइयाँ इल नहीं कर पाते उसके कहीं श्रांषक कठिनाइयाँ पैदा कर देते हैं। उपभोकाशों, ज्यापारियों श्रौर दुकान-

दारा सभी को खनेक कठिनाइयों का सामना करना पहला है। यदि नियंत्रण लागू म हो तो विशेष हानि नहीं होती है परता वटि लाग करके भी उनका फुराणता पुर्वक सचालन न किया जाय तो मुविधा की अपेना कप्ट अधिक बढ जाता है श्रीर हानि भी होती है। यदि इस प्रकार के नियंत्रण की हटा दिया जाय तो निध्य हो स्थिति म सुधार होगा । फिर जब तक नियंत्रण लाग रहेगा. देश की श्चाधिक व्यवस्था श्रपने सामान्य स्तर घर नहीं श्रा सकती है। सामग्री नियंत्रण समिति (Commodity Controls Committee) न इस नात की छोर ध्यान ह्या स्वीर पह बताया कि "राज्यात में कह भी हमी बनी नई है। इसलिए जब तक यातायात सम्बन्धी कहिनाइयाँ हैं और प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुर्भित्त पड़ने की संभावना बनी हुई है तब तक खादास की श्रासुभृति व उपलब्धि स सम्बान्धत आदेश (Foodgrains Licensing and Procurement Order, 1952) च अन्य पुरक आदेशा का पालन किया जाना श्रानिवार्य है"। जैसा कि बाद की स्थिति से कात होता है, नियंत्रण ने स्वयं ही खागान का अभाव त्रायस कर दिया था । बरावि भागगी जिल्लंकमा समिति व स्वत्य लोगों का विचार था कि वर्तमान पश्तियति में नियंत्रण हटाना संमय नहीं होगा, किन्तु उसे हटा देने से खाद्यास की स्थिति निश्चित रूप में संघर गई है।

भारत के उस समय लाग मन्त्री श्वांय की रक्षी श्रह्मद किदवई की यह धारणा थी कि लागाश का नियत्रण कर देने से स्थित सुघर जायगी। उन्होंने महे १९५२ को अपने एक लाग्नेजिक भाषण में कहा कि जिन नावणों में लागाक का उत्पादन उनको अपने एक लाग्नेजिक से सहा है वहाँ से नियंत्रण हर जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि जिन हो तीन रावणों के श्रन्तांत देहातों में भी राणिनिक्त (Rationing) है, नह भी हरा लेना चाहिये। किरवई लाहन की हर धारणा का सरकारी श्रीर गैर सरकारी दोनों ही लेगों में निरोण किया गया। किन्छ इस सम्बन्ध में भी चीक राजगीपालाचारी ने श्रीमणीश किया श्रीर २६ जून १९५५ को मद्रास से लागाज नियंत्रण हरा लिया। यह विनियन्त्रण की दिशा में रहता करना था। कुछ प्रारम्भिक कांठनाहर्थी अवश्य हुई, दिन्तु स्थापात विनयन्त्रण में पर्यात सक्तवा मिली। उत्तर प्रदेश, बिहार श्राहि कई राज्यों ने महास का

सामग्री नियमण सिमिति की लिखुन्ति २६ श्रवस्ट्रवर १६५२ को काउन्सिल श्रॉब स्टेट्स के उपसभापनि श्रॉ पुस० बी० कृष्णमूर्ति राव की श्रव्यसत्ता में की गई थी। इस सिमिति ने खावाब का विनियंत्रण प्रारंभ होने के योड़ा पहिले ही २० जुलाई १६५२ को श्रपनी रिपोर्ट सरकार को ही थी।

अनुसरण किया और सिताबर १६५२ तक यह विनियन्त्रण ६ राज्यों में लाग हो गया। धीरे-बीरे यह जोर पकड़ता गया और १९५३ तक फेन्द्र व राज्य सरकारों ने खाद्यान के वितरण और उसके महत्र पर से नियन्त्रण हटाने का काम विलक्त परा कर लिया ज्यार बाजरा. महका. जा जैसे मोटे अनाजों पर से १ जनवरी १६५४ को नियन्त्रण हटा लिया गयाः इसके साथ ही इन मोटे समाजों का एक राज्य से दसरे राज्य में ले जाने पर जा प्रतिबन्ध था वह सीराष्ट, मध्यभारत स्रोर उस-प्रदेश के ११ जिला की छोडकर सभी जगहीं से हट गया। बाद की यह प्रतिबन्ध भी हटा लिया गया। चावल का विनियन्त्रण १० जुलाई १६५४ से लाग किया गया। उसे एक राज्य से दसरे राज्य में से जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहां रहा है और अब देश के सभी मार्गा में उसका व्यासार स्वतन्त्रतापूर्वक किया जा सकता है। अभी तक चावल अनिवार्य रूप से पास करना पहला था. फिन्त विनियन्त्रण लागू होने से यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इसके श्रतिरक्त चावल

के मूल्य पर सरकारी नियन्त्रशा भी बन्द हो गया है।
"बिस क्रमिक विनियन्त्रशा (Gradual de-control) को राजा जी १९५२ में प्रारम्भ किया था वह चावल का पूर्ण विभिवन्त्रक हा जाने के उपरान्त अपनी चरमानस्था पर पहुँच गया"। अंतर-प्रदेशीय प्रतिबन्ध जो गेहें के एक स्थान से दबरे स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में लाग किया गया था वह नियंत्रण का ग्रंतिम का या श्रीर १८ मार्च १६५५ से यह भी उठा लिया गया। इसमे १०

वर्ष तक लागू नियन्त्रण का श्रंन हो गया। विनियन्त्रण के समयकी ने यह श्राशा दिला रखी थी कि लाग्रास-नियन्त्रण के फलस्पलप अकाल, खावात के सम्बन्ध में स्थानीय अमाव !(Local scarcity) और अन्य आपत्तियाँ उत्पन्न हो जायेंगी, किन्तु भाग्यवरा ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। उन बात तो यह है कि खाबाक नियन्त्रण के कारण अन के अभाव को कृषिम परिरियतियाँ उत्पन्न हो गई थीं और जिन अधिकारियों को खावान-नियम्त्रण का कार्य-भार सींपा गया था, स्वार्थरत होकर अपना हित साध रहे थे। नियन्त्रख हट जाने से (१) खाद्यात्र का अभाव होने की जो मनःस्थिति बन गई यो वह दर हो गई। इसक अतिरिक्त मुनाफा खोरी और चौरवाजारी का भी प्रन्त हुआ, (२) देश में लादाज के वितरण की स्थित सुघर गई, (३) लादाज का भाव कम हो गया जिसक फलर का लागा के रहन-सहन की लागत घटी श्रीर किसानी को भी श्रधिक उत्पादन करने में प्रवृत्त होना पड़ा, जिससे वे उतनी आय का उपार्जन कर सकें जो उन्हें पहले प्राप्त हो रही थी, (४) केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा खाद्याल नियन्त्रस व राशनिङ्ग पर जो व्यय होता था उसमें

भारतीय वर्णशास्त्र की मग्रन्यार्टे

4 ^

कमी आ गई। विनियन्त्रस से यदि कोई हानि हुई है तो यही कि खादान नियन्त्रण श्रीर राशनिस्त विभाग के कर्मचारी बहुत बदी सख्या में बेरोजगार हो गरे श्रीर मनाफास्त्रोरों व सीरवाजारी करने वालों की ग्राय का एक वहत वड़ा साधन दिन गया ।

खादा स्थिति विगढते जाने के फलस्वरूप १६५६ में चावल तथा गेहें के ( मरहल (zone) निश्चित करके. उचित मध्य पर वेचने वाली हकानों हारा

दिकी करके तथा खाराच के व्यापार एवम बाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा कर सीमित नियत्रक फिर से लाग किया गया। सरकारी अधिकारियों को एक वर्ग पर्या निर्मेश्वरा के पन में है तथा बोजना साबोग के अर्थशास्त्रियों ने भी हम

विचार का समर्थन किया। किन्त जैसा कि हम अपन संदेश कर चके हैं। जाताओं क्षांच करेरी के जिस्हात के बिकट निपारिश की।

# ्राण्डे अध्याय ६ ज्यानिहासी उत्मलन

द्यार्थिक दृष्टि से बमीदारी उन्मलन का विशेष महत्व है। ग्रुखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की छार्थिक नीति का यह सदैव महत्वपूर्ण छापार रहा है। विशेषज्ञी की ऋनेक समितियो ने मी समय-समय पर अमीटारी का उन्मलन करने की विफारिश की। १६४७ में भारत की स्वतन्त्रता मिलने के परचात् कांग्रेस सरकार ने जमीदारी उन्मूलन को स्रपने स्नाधिक कार्य-कम का महत्वपृष्ट स्ना बना लिया श्रीर धीरे-धीरे सभी राज्यों में इस नीति को लागू किया है। बहुत से राज्यों ने जहाँ जभीदारी या इसी के अनुरूप कोई अन्य प्रया प्रचलित थी, इन विशेषाधि-कारों का उन्मूलन करने के लिए कानून बनाए हैं और उत्तर प्रदेश तथा विहार ने तो जमीदारी का उन्मूलन कर उन पर श्रवना कब्बामी कर लिया है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योज्य है कि इन सरकारों ने मुद्र्यायजा देकर जमीदारी-उन्मूलन करने की नीति स्रपनाई है अर्थात् सरकार ने जमीदार की उसकी जमीन के बदले उपयक्त मुखायजा (Compensation) दिया है। ३१ माचं १९५६ तक लमीदारी प्रवा उन्मूलन हो गया तथा ४.३६ करोड़ एकड़ श्रयवा राज्य की 25. प्रतिशन कृषि जोवी पर भूमि मुघार के उपाय लागू किये गये।

जनमूलन के पत्त में तर्क-जमीदारी उन्मूलन करने के समर्थन में श्रनेक तर्फ दिए गए हैं। यह कहा गया है कि अमीदार किसानी का शीयक (Parasite) है और उसने अपने कब्जे की बसीन में कुछ सुधार नहीं किया, सूर्त की चक-बन्दी (Consolidation of holding) करने में सदेव रुकावट डाली है और किसान को जा अमीन जीतता बीता हैं भूम सुधार के लिये अपनी अनुमित नहीं दी है। यदि जमीदार को इटा दिया जाय तो भूमि में मुधार किया जा चकेगा, खाद्य स के उत्पादन में वृद्धि होगी त्रीर मूमि मुधार योजना की कार्यान्वित किया बा सकेगा निसकी बहुत समय से आवर्यकता अनुमव की जा रही है। यह सक बहुत ग्रंशों में सही हैं, फिर भी इस तथ्य को टाला नहीं जा सकता है कि कुछ, ऐसी कठिनाइयाँ है जिन पर जमींदार का वश नहीं है श्रीर यदिवह वश में रखना

भी चाहे तो सफल नहीं हो सकता।

जमीदारी उन्मूलन का समर्थन करते हुए यह भी कहा गया है कि इससे राज्य की मू-राजस्य (Land revenue) श्राय बढ़ेगी । यह तर्क विरुक्तन सदी है क्यों कि १६५१-५२ में राज्यों की मृत्यानस्य से आप ४७६६ करीड़ करने थी जो बहुकर १६५७-५८ में (बजट के आनुसार) ६२५४ करीड़ रुपये हो जायगी। इतसे त्राव्य प्रकारों मुझाबने की किश्त जुकाने के बाद आपनी भूमि सुधार तथा आम-जुनर्निमांग् (Rural reconstruction) योजनाआ को लागू कर छकेंगी। वरिणास्वस्तर देश के अति व्यक्ति की आप में वृद्धि होगी और किसान की स्थिति ६ में सार हो सकेगा।

जमीदारी उम्मूजन का प्रश्न आर्थिक होने के साथ हो राजनैतिक भी बताया गया है। देश के अतदाताओं में किसानों की सस्या बहुत अधिक है। किसान बतमान स्थित ने बहुत अध्यमुख्य हैं और उनका विचार है कि उनकी क्षय दमनीय स्थित तक पहुँचाने के लिए केवल कारीदार हां उतदादायी हैं। यह सर्वविद्वात है कि जनतंत्र प्रणालों में बहुमत का निर्माय होता है चाहे उनका हथ्यकोय हुछ औही। इस्विल्य किसानों के अध्यन्तीय को कम करने उनका मद अनुकूल करने के लिए कमीदारों अम्बूजन को एक साधन बनाया गया है। यिछले वैर-माय की प्रतिक्रिया के रूप में किसान मिथप में लागू की जाने वाली किसी भी मूम सुधार योजना में कमीदारों के साथ सहयोग नहीं करेंगे एखलिए स्थि मुख्य योजनाएँ तभी वक्त हो बक्ती हैं वस किसानों तथा गिल्य सरकार के मध्यरती का उम्मूलन कर दिया बाय।

जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध तक — अभीदारी उन्मूलन के विरोध में भी झर्नेक तर्क दिये गये हैं परन्तु उसमें बात नहीं है ! यह कहा गया है कि लमीदार के उन्मूलन ने गुद्धत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाये में जिन लमीदार, उनके जिलेदार, कारिन्हें हस्वादि । इसके केवल जमीदारी की आय पर निर्मेर करने वाला वर्ग बहुत कि तिहादी । वर्षके केवल जमीदारी की आय पर निर्मेर करने वाला वर्ग बहुत कि तिहादी में पह जायगा । परस्तु इसके इसर में यह कहा जा सकता है कि किसी भी परिवर्तन के साथ कुछ कि तिहाद और अवस्था का होगा अस्त्री है और इस कि तिहाद से एक लगा है । वर्षक से परिवर्तन की रोका नहीं जा सकता है । वरस्त में में स्वात नहीं हो जा सकता है। वरस्त में में स्वत नी हो जा तिहाद से से सिर्मा के कि तिहाद से से सिर्मा करता है कि जमीदारी का उन्मूलन कर देने ने अभीदारों को कि तिहाद से साथ साथ साथ से सिर्मा में सिर्मा परन्तु इससे कि सानों की दशा में मुखार मो होगा और रोर्थशांतिक हिन्दा से पर लाभदारफ कि सीपा अभीदारों के कारिन्द स्थादि कर्मवारी आरास में मेरी बतार हो जायेंग परनु वाद में उन्हें रोजवाद सिर्मा क्यारम में मेरी बतार हो जायेंग परनु वाद में उन्हें रोजवाद सिर्मा क्यारम क्या क्यारम करता है क्या कि सकता है लायें के कारिन्द स्था में क्यारम स्था सिर्मा क्यारम स्था में सिर्मा साम से सिर्मा में सिर्मा स्था यहन करने के लिए कमें स्थारम में मेरी बतार हो जायेंग परनु वाद में उन्हें रोजवाद सिर्मा स्था स्था स्था साम से सिर्मा साम स्था स्था साम स्था सिर्मा क्यारम स्था सिर्मा का साम सिर्मा क्यारम स्था सिर्मा का साम सिर्मा का साम सिर्मा की सिर्मा की साम सिर्मा की साम सिर्मा की सिर्मा की सिर्मा की साम सिर्मा की सिर्मा सिर्मा की सिर्म की सिर्मा की सिर्मा की सिर्मा की सिर्मा की सिर्मा की सिर्मा की स

सरकार जमीदारी के बदले उन्हें मुझावजा देगी और उन्हें ऋपने जीवन निर्वाह के लिये स्वयं ग्रन्य साधनों की खोज करनी चाहिए !

यह भी कहा गया है जमीदारी का उन्मूलन हो जाने से किसान को कई प्रकार से हानि पहुँचेंगी। इस समय सामाजिक तथा प्रक्रम कार्यों के लिए जमीदार किसानों को खूच देता है, लागान वसली में वह किसान की निरिदेशतियों का प्रमान रखता है और उसे अदावधी के लिये समय देता है परन्तु सरकार के कर्म-वारी किसान को यह सुधिया नहीं देते। केवल जमीदारी का उन्मूलन कर देने से ही भूम सुधार समय नहीं है, यदि सारी घटनाओं के होंगे प्रकार घटित होने दिया जायगा नो देश को लाम होने की अधेवा अधक हानि होगी। इसमें कुछ उन्देह नहीं कि किसान की रिधा में कुछ परिवर्तन अवस्य होगा परन्तु परि कार्य का सुधा सुधार सामाज परन्तु परि कार्य का सुधार सुधार सामाज परन्तु निर्माण का सुधार कार्य सुधार सामाज सुधार सुधार सामाज सुधार सुधार

उम्मूलन न किया गया तो जिस भूमि सुवार की बहुत समय से आवश्यकता अनु-मल को जातो रही है वह कमी लागून हो सकेगा। जमीदारी उम्मूलन से जो शब्यवस्था पैरा होगी उसका सामग करना पढ़ेगा और जितना शीम यह हो सके उतना हो अब्द्या है। इससे सुधार करने के लिये गागें खुल जायगा और कुछ, समय तक अन्यायी अव्यवस्था के पश्चात् भूमि का उत्पादन बढ़ेगा; किसान की दशा सुबरेगी और देश की आर्थिक समृद्धि बढेगी।

उन्मूलन योजना—जमीदारी उन्मूलन कार्य "अस्पायी बन्दोबस्त बाले देश में अमेताकृत सरका था, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, प्योकि यहाँ आवश्यक लेखा तथा इस कार्य को फरने याले अधिकारी उपलब्ध में। स्पापी मन्दोक्त वाले संग्रों में जैसे बिहार, उद्दोशा और पिच्छामी बगाल तथा जागीरदारी क्षेत्रों जैसे राजस्थान और चीराष्ट्र में सब लेखा तथार करना और नये सिरे से अधिकारियों की निमुक्ति आवश्यक थी। जो कुछ भी हो मध्यस्थों को इटा देने के कान्तर अधिकार्य प्रदेशों में लागू कर दिये यारे हैं"।

बमीरारी उन्मूलन में सावारखावया निम्म उपाया का प्रयोग किया गया है: (१) वे मूमि के भाग जो परती पड़े थे, जंगल, आवादी के खेत्र, आदि जो यदपरां के खोतार में भे प्रवत्य और सुवार के लिये सरकार के अधिकार में दे दिये गये। (२) जुदकारत की सूमा तया निजी काम के खेता, जिनकी देखारेख स्वयं जमीदार दी करते थे उन्हीं के अधिकार में रहने दिये गये और वे कारतकार जिन्होंने ऐसी सूमि पट्टे पर कमीदारों से खे रखली थी कारतकार (tenant) की

हैसियत से उन्हीं के अधिकार में छोड़ दी गई। (३) बहुत से राग्यों में प्रधान आहामी जिन्हें सम्बन्धों से सीव नूमि प्राप्त थी सीवे राज्य की सरकारों से सम्बन्धत कर दिने गने । अग्वी, हैदराजाद और मैसर में इनागों से प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में यह वात नहीं लागू की गई थी। इन प्रदेशों में मध्यस्थों को आसामियों के लेकर कुछ मूमि दो गई। कुछ प्रदेशों में आसामियों को स्थापी तथा इस्तीतरस्य का अविकार मात्र था, इस्ति दो अब स्व आवश्यक नहीं पा कि उन्हें जीर अधिक अधिकार मात्र कि उन्हें जीर अधिक अधिकार मदान किये जायें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदराजाद, मैसर और दिल्ली राज्यों में आसामियों को भूमियारी अधिकार प्राप्त करने के लिये उसका मूल्य कुकाने का अवकार दिया गया। आक्रम, महार, राजस्थान, छीराष्ट्र (लाकी क्षेत्र) मध्य मध्य प्रदेश करा वहां दिया गयें अध्यक्ष जनका लगान यदा दिया गया और उनसे कोर्र मृक्य नहीं वस्ता गयां।

"भध्यस्थों को दिये जाने वाले सुधावजे और पुनर्वास में स्ट्रायता के रूप में दी जाने वाली रकम का अनुमान लगमग ४५० करोड़ स्वया लगाया गया है। इस रकम का ७०% केशल उत्तर प्रवेश और विदार में दिया जाने वाला मुआयजा है।

मुझापजे का व्यक्तियः — पिनिस जमीदारी उत्मूलन कान्नों में मुझापजे के विभिन्न आधार दिवे गये हैं । बाहाम, विहार, उड़ीशा और मध्य प्रदेश में मुझापजे का झाधार भृमि से प्राप्त होने वाली 'वास्तविक झाय' (net income) है । उत्तर प्रदेश में यह झाधार 'वास्तविक तम्मति' (net assets) और महास में यून-भृत वार्षिक झाय और वास्तविक तम्मति के झाधार लाश्यार 'वास्तविक तम्मति' (net assets) और वास्तविक झाय और वास्तविक त्याय त्यार में ते भूराजस्य अपकर्ष (cess), प्रकृष का व्यय, रैस्यत के लाम के लिये किये गये कार्यों में व्ययन और कृषि आधार तम्मत्र है। द्वारतिक आधार तिकार कार्यों में व्यवस्तविक आधार तिकार कार्यों में व्यवस्तविक आधार तिकार कार्यों के व्यवस्तविक आधार कार्यों के (कार कार्य के जाती है। अवस्य की जाती है वह सभी राव्यों से समान नहीं है। वास्तविक आधार निर्माण करने के जरवात् हिंगी आधार पर सुझावजा निर्धारित किया गया है। महास मिन्न मुलमूत वार्षिक आधार निर्माण के प्रकृत करने और प्रकृत करने के लिए अलग कर दिशा वाता है और देश किशा क्यार के प्रकृत के लिए अलग कर दिशा वाता है ॥ इससे को आप सेण रहती है वर्श भृत्यत्व वाता के लिये वर लिया वाता है। इससे को आप सेण रहती है वर्श भृत्यत्व ताता के लिये वर लिया वाता है। इससे को आप सेण रहती है वर्श भृत्यत्व सिंप के वर्श स्वार के व्यवस्था को चलाने के लिये वर लिया वाता है। इससे को आप सेण रहती है वर्श भृत्यत्व सिंप स्वर हमारिक स्वर कर दिशा स्वर्ण का व्यवस्था के व्

सुआवजा जमींदार से पास होने वाली वर्तमान वास्तविक आय पर आधारित म होकर रच्यववाको प्रधा लागू होने के बाद भू-राजस्य के २५ प्रतिशत पर आधारित होगा।

उत्तर प्रदेश में भुशावजे की दर वास्तजिक सम्मत्ति का श्राठ गुना है। इसके साथ ही जो जमीदार १०,००० रुपये से श्रपिक भू-राजस्त नहीं देते उनको जमीदारी उत्मृतन के पर्याद्ध वास्तजिक सम्मत्ति के २० गुने से लेकर एक गुना तक पुनर्शक श्रद्धदान दिए जायेंगे। यह श्रद्धदान कम श्राप वाले जमीदारी के लिये हम श्रपक गुने होंगे श्रीर श्रपिक श्राप वालों के लिये हम श्रपक गुने होंगे श्रीर श्रपिक श्राप वालों के लिये हम श्रपक का होते जायेंगे मध्यस्थों को दिया जाने वाला गुन्नावमा तथा धुनर्वास श्रप्तक स्वत्राह्म का श्रद्ध हम स्वत्राह्म का श्रद्ध हमान हम स्वत्राह्म स्वत्राह्म का श्रद्ध हमान हम श्राप्त अपने करोड व्यया तथा ७० करोड व्यया है।

पुष्ठावने के जुकाने में उससे अधिक विचारणीय बात यह है कि सुष्ठावजा नक्द दिया जाय या वेचे न जा उफने वाले वायडों के कर में । जमीदारों के हिंदे की खं से यदि मुन्नावजा नक्द दिया जाता तो खांत्रम होता क्यों कि हिंदे की खं से यदि मुन्नावजा नक्द दिया जाता तो खांत्रम होता क्यों कि इससे यह कोई नया कारोबार जोलते या उथोंगों में क्या बाता ति अध्ये उन्हें बरावर व्याय होती रदती । परना सुश्चावजे की वक्तर को नक्द अदी करना संभव नहीं है व्यों कि राज्य उपकार है हता। अधिक धन नक्द है में की अध्यवस्था नहीं कर एकती है। उनके पाद इसके सुगतान के लिए कपया नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां जमीदार उन्मुलन कीय का निर्माण किया गया है, किसानों को अपने लगाना का १० गुना जास कर भूमियारी अधिकार लोने को प्रोत्यक्तित किया जा रहा है किर मी अपने कर भूमियारी अधिकार लोने को प्रोत्यक्ति किया जा एकते हिक प्रोत्य अध्य कि कम वपग्न इक्तर हो छका है। सुश्चवजा केचे न जा एकने चाले बाए औं के रूप में दिया गया। परन्तु इस विधि से अभीदार के प्रति पूरा-पूरा न्याय नहीं होता है क्योंकि जमीदारों को उनके मुखावजे की रक्तम और उस पर व्याव का सुमाताल कार्य सम्बे समय में किया आया और इस बीच अपना वर्तमान स्वर्च पताने में तथा कोई नया कार्यवार क्यापित करने में जमीदारों को बहुत क्याना होगी।

" श्रन्य प्रशाली—अमीदारी उन्मूलन कर देने से ही सारी उमस्या का इल होना संभव नहीं है। यदि इसके बाद श्रुमि सुवार लागू नहीं किए तो जमीदारी उन्मूलन का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। इस विषय में सुख्य उमस्यार्थ यह हैं: (२) कमीदारी उन्मूलन के बाद भूमि पर श्रमिकार की व्यवस्था, (२) कृषि के कप्प (form of cultivation). श्रीर (३) मू-रानस्य चस्त्र करने के लिए श्रीर चरागाह, बंगर जैसी जगीन की देख-रेख करने के लिए सरकार की श्रीर से निर्धारित उपस्रक संस्था। श्चन तक भूमि शुवार का मुख्य उद्देश्य कृषक को स्वामित्य के श्चिकार प्रदान करना था। भूमि के इस्तांतरख के सम्बन्ध में भूम्बामी के श्चिकारों पर कुछ प्रतिवरण इसिल्ये रखें गये हैं ताकि जोतें बहुव बको या बहुत छोटी न हो जार खोर भूमि ग्रीम् सुधार के उपायों के लोगू होने से बाद बमीदारी और वागीयों होने हे आप विकास प्रकार के मूमि सम्बन्ध स्वामित्य के, अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। इस प्रकार मीछरी रैय्यत (occupancy rayat), नियत लगान याखे रैय्यत श्वादि मुस्वामी वन गये। गैर मीछरी रैय्यत के तीचे वाले किसान, सामान्यत: मूल्य चुकावर ही भूस्वामी वन चकते हैं। यह सब तथा पूर्वकर्ती मध्यस्य को श्वयनी सीर श्वीर खुरकाइत के मालिक वने हुये हैं। श्वीयक्तर राज्य के काय्सकार कहलाने हैं किन्यु वास्तव में वे श्वयनी भूमि के स्वामी है श्वीर उनके श्वियकार रियतवारी चेत्रों के अन्वासियों की स्वाह हैं है।

"अमेक राज्यों में गैर-कुपकों को भूमि बेचने की सनाही है। बन्धरें हैररामाद, मध्यमारत और शीराहू में कानूनन गैर कुपकों को भूमि बेचने की आशा नहीं है। बन्धरें और पिर्चिमी बंगाल में अनुगति प्राप्त खरीदारों की प्राथमिकता का कम निश्चित है। प्राथमिकता में पहला नम्बर उन कार्तकारों का है जो मूर्मि पर बास्तव में कार्यित हैं। इसके बाद पढ़ीशी कुपकों का नम्बर है तथा इशी तरह लीसों कु कम निश्चित है। "

"उत्तरप्रदेश में यद्यपि भूमियार को अपनी जोतों को बेचने का अधिकार है किन्तु इस पर यह प्रतिवन्ध है कि षामिक संस्था के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेचने पर खरीइने वाले की बोत ३० एकड़ से अधिक न हो जाय । बन्दें में यह श्रीमा १२ एकड़ से ४८ एकड़ (वो सूमि की किहम पर निर्मर है) है। हैररावाद में यह सीमा परिवारिक बोत की तीन गुनी है। मध्यमारत में यह ५० एकड़, परिचयी बेंगाल में २५ एकड़ (बिचमें पर में संत्र सेत नहीं सामिल है) दिल्लों में ३० हरेन्डर्ड एकड़, रावस्थान में ६० अधियत एकड़ वा इ० विचित एकड़, आधाम में एक परिचार के लिये १५० बीचा (४६, एकड़) तथा श्रीराष्ट्र में तीन आर्थिक बोत है। ११

पग्वर्द, हैदराबाद श्रीस मध्यभारत में ऐसी कोई भूमि नहीं वैची जा तकती जो के चेने वाहे की जोत को निवादित होमा सं कम कर दे । उदाहाए के जिये नमाई से कोई भी जोति के चकर या किहती अग्र प्रकार इस तरह (वामांकत मिंक् की जा स्वत्ती कि उसके (एक मुंता वा चार वक्क नीमा भूमि परिकार्य है) दुश्के हो जॉय । हैदराबाद में एक (ट्रेटवर्ड) निश्चत चैनक्क निवादीत करते की व्यवस्था किसी भी हालत में भूमि इसने कम चेत्रों से नहीं विमानित की जा सकती हसी प्रकार सम्ब प्रदेश में वश्चा कार्यकार अपनी भूमि तमी बेच सकता है जब कि यह अपनी कुछ भूमि बेचने से तैयार हो अथवा केचने के बाद उसके पास प्रतिकृत वक्क या हुए अतिचंता एकड सांस क्वर हो हो।"

ह न वन प्रिवन्त्रों के बावजह भी, ऋषिकांध राज्यों में वर्षीदारी उन्तृतन के परवाद हुनको का मूस्कामित्र हो वास्त्रात तथा प्रत्येक कियान प्रधनी जमीन बोनेगा। यदि ऐवा हुआ तो बहुत क्यों सोस तक वर्षीदारी उन्तृतन के लाभ वर्षी हो तथे गिष्ठा हुआ तथा क्षाय हुन क्यों हो तथा करने तथा क्राय के गुझारे हैं विभाग समीन करने किया क्राय के गुझारे हुने की का समीन करने किया क्राय के तथा क्राय

स्मि से छत्वादम की मात्रा नक्षी बहाई का उकती है जब वहे चीजों में खेवी की जाय और आवादम की मात्रा नक्षी कर महानी का उपयोग निज्ञ कार । उत्तादम में वृद्धि होने में किया कार । अभ्य में भी वृद्धि होना स्वाधायिक है। उत्तर में स्वाधायिक है। उत्तर में से तरह की उद्धारिक किया मार्थ में से स्वाधियों की व्यवस्था की गई है— (१) ५० एकड या आधिक के ऐसे छोटे कार्म को १० या आधिक किसानों में स्वेच्छा से दिनाकों करने काण हो और (२) आधिक हिन्द से अनुस्युक्त आभीमों को सिलाक्त संगतित महकारी कार्म । विद दूसरे प्रकार के कार्म के बुक्त स्वस्थों के दो खिहाँ वह मौत्रा का स्वाधायिक है कि इस छोटे कार्मों की मिलाक्त संगतित महकारी कार्म । विद दूसरे प्रकार के कार्म कहती है कि इस छोटे कार्मों की मिलाक्त स्वाधायिक करती है कि इस छोटे कार्मों की मिलाक्त स्वाधायिक विद्या है कि इस छोटे कार्मों की मार्थ मान्य परिवाध स्वाधाय संगति कर विद्या कार्य से से स्वाधाय संगति कर विद्या से स्वाधाय संगति संगति

# ^५<sup>४</sup> अध्याय ७ भूमि की चकवन्दी

भारत में मिम को छोटे-छोटे हिस्सों में विमक्त कर देने से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। भारत के किसान भूमि के छोटे-छोटे अलग-अलग विखरे हुए टकरों में खेती करते हैं जिससे खाद्यान तथा अन्य सामग्री का उत्पादन कम होता है भ्रोर कियान की गरीबी बढ़ती जाती है। इतक श्रानेक कारण हैं जिनमें से मत्त्र इस प्रकार हैं. (१) भूमि पर जनसंख्या का दवाय स्रोर मौकती इक सम्बन्धी कानन । परिवार के प्रधान के मरने पर जमीन उसके पत्रों तथा अन्य सम्बन्धियों में बाँट दो जाती है। बाँटने समय इस बात का ब्यान नहीं रखा जाता है कि इन अमि के छोटे-छोटे हिल्लों से हिस्सेदारी का बीवन-निवाह नहीं हो सकेगा, इनमें को कछ उत्पादन होगा उससे वह अपना भरख-पोषख नहीं कर सकेंगे। (२) किसान के ऋषी होने तथा अन्य कारणों से भूमि का विक जाना। भारत के किसान ऋष के बोक्त से दव जाने के कारण ऋपनी जमीन रेहन रख देते हैं स्त्रीर क्रमण न ज़कासकने पर उस बमीन को ऋग्यदाता वेच देता है यास्वयं ले लेता है। इससे जा लमान पहले से ही छोटे-छोटे टकड़ों में थी अब और श्रिधिक विभक्त हो जाता है। यदि किसान के संयुक्त परिवार के एक सदस्य का हिस्सा ऋषा न चुका सकने ब्रायवा ब्रन्थ किसी कारण से बेच दिया जाता है तो शेप भूमि कम हो जाती है श्रीर जब उसका विभाजन किया जाता है तो वह श्रीर छोटे छोटे टकडो में बॅटती जाती है। (३) किसान इस बात से अन्भित्र है कि भूमि का छोटे-छोटे हिस्सों में बँट जाना बुरा है। यह अनुभव किया गया है कि किछान भिम की चकदन्दी के लिये शीम तैयार नहीं होता। इसके लिये उसे काफी समकता पडता है श्रीर दशब डालना पड़ता है। भूमि नी चकवन्दी से उत्पादन बढता है तथा अपक का चिता भा कम हो जाती है इससे हम छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त होने की गम्मीर समस्या को ही इल नहीं कर लेते बल्कि आम योजना में, खेल के . मैदान. स्कूल, गढ़े ऋादि बनाने में भी सहायता मिलती है।

हानियाँ-सृपि का विभाजन श्रीर उसका छोटे-छोटे टुरुझें में बट जाना पक गम्मीर दीप है। इससे अनेक हानियाँ होती हैं: (१) इससे भूम में सुधार नहीं किया जा सकता। भूमि छाटे दुकड़ों में वॅटी होने के कारण किसान अपनी खेती के लिये न कुछाँ खोद पाता है, न मशीनों का उपयोग कर पाता है झीर न

श्रन्य प्रकार के सुधारों को ही लागू कर याता है। इससे भूमि की उत्पादन सिक नहीं धहने पाती श्लीर उत्पादन विरता जाता है। (२) भूमि के छो-छोटे हुकड़ों में बैंटे रहने के कारण बहुत सी बमीन एक हिस्से को दूबरे हिस्से से श्लाम करने के लिये मेह बॉंधने में व्यर्ध नष्ट हो जाती है श्लीर भूमि के हुकड़े बिलरे होने के कारण हिशान श्लपनी खेली की श्रन्छी तरह देख-माल भी नहीं कर पाता है। इसम मतल में गहरी हानि होने की हमेशा श्लाशंका बनी रहती है। श्लीर (३) करता पहला है।

यह कहा गया है कि अधि को छोटे-छोटे हिस्सों में बँटे रहने से किसान को लाम है क्योंकि इससे गाँव के अनेक भागों में प्रत्येक किसान की कछ न कछ भूमि रहती है। यदि बाद तथा टिक्डी इत्यादिका संकट आ जाय तो उसकी सारी सिम नव्ट होने से बच जाती है। यदि एक भाग इस संकट से नव्ट भी हो जाय सो खान्य भाग दर होने के कारण बचाये जा सकते हैं। दसरा लाभ यह बताया जाता है कि भूमि के इस प्रकार के बँटवारे से गाँध की श्राधिकांश जनता के पास भूमि हो जाती है। यदि यह बॅटवारा न किया जाय तो बहत से मामीस दिना भूमि के रह जायेंगे। परन्त ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से पता चलेगा कि यह दोनो लाम काल्पनिक हैं। ऐसा बहुत कम संभव है कि प्रकृति के कोए से गाँध का एक ही भाग नष्ट ही और शेप भाग बच जाय। यदि कमी ऐसा हम्मा भी तो इससे किसान को वहत कम लाम होगा: वर्षों से छोटे-छोटे टकडों में खेती करने से किसानों को जो हानि होती है वह इस संभावित लाभ की अपेद्धा कहीं अधिक है। श्रीर जहाँ तक मुमि-विहीन सजदरों का प्रश्न है यह भूमि के बँदवारे या उसे छोटे छोटे हिस्सी में विभक्त करने से इल नहीं किया जा सकता है। बास्तव में मुख्य समस्या यह है कि किसान को इस योग्य बनाया जाय कि वह रहन-सहन का एक उचित स्तर बनाये रख सके। कुल परिवार के पाछ संयुक्त रूप से जितनी भूमि है यदि उसका उसके सदस्यों में विभाजन कर दिया नाय और प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ मूमि दे दी जाय तो इससे रहन-सहन का उचित स्तर नहीं रखा जा सकता। इन छोटे-छोटे मागो से किसान अच्छी तरह जीवन-निर्वाह कर सकने में श्रासमर्थ होता है। यदि भगि का इस प्रकार बेंटवारा न किया जाता तो शायद वह असमर्थ न होता । भूभि-विहीन मजदूरों की समस्या को इल करने के लिए सरकार को श्रन्य उपायी से काम लेना पडेगा।

यह खेद की बात है कि भूमि के बैंटवारे और उसके छोटे-छोटे भागों में विभक्त हो जाने की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। कृषि सम्बन्धी रावल कमीयान (Royal Commission on Agriculture) की रिपोर्ट से बयल यह स्चना मिलती है कि विभिन्न राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति के पास श्रीष्ठतन कितनी बमीन है। इस स्चना से समस्या की पूर्य कानकारी नहां होती। किसानी के पास श्रीषत सूणि उत्तर प्रदेश, महास, तिबाँकुरकोर्यन श्रीर दिमांचल प्रदेश में श्रान्य चेत्रों की अधैचा कम है। उत्तर प्रदेश में मूमि प्राप्त कुल ब्यक्तियों में में द्वर र प्रतिशाल के पास कुल कका क्रम सूम मूमि पाह कुल काइत की जाने वाली अपन का क्ष्यं प्रतिशत है।

महास में ८२१ प्रतिशत के पास १० क्याया या इनसे कम यार्थिक स्वाग्य की मूर्ति है जो कारत की जाने वाली भूमि का ४१९२ प्रतिसत है। जियिक्तर की पास ५ एकड़ से कम भूमि है जो कुल कारत की जाने वाली भूमि ४४ प्रतिशत है। ज्ञन्य राज्यों में भी यह समस्या गम्मीर है। श्रीर इससे किसतों को आप में शामि स्टार्शिय हो है।

दींत (Methods)—भूम की चक्वन्दी करने की दो सुख्य रीतियाँ हैं इ (१) स्वय कियानों में परण्या स्वेच्छापूर्वक सहयाग की भावना के द्वारा छोर (१) स्वय कियानों में परण्या स्वेच्छापूर्वक सहयाग की भावना के द्वारा छोर (१) स्वय कियानों में परण्या स्वेच्छापूर्वक सहयोग करने का महन है हसम काफ़ी देर लगती है और चक्कन्दी का कार्य में मता में नहीं हो पाता। कहीं-कहीं अम.दार या नहाजन चक्कन्दी का कार्य में ककाय्य पैदा कर देने हैं। हसके खाय ही किछानों का यह एकफ़ाना बहुत कठिन है कि चक्क-बन्दों से उनका लाम होगा। किछान न नो छापनी भूम खोडने के लिए तथार दोता है और न हस काम से छोडा-सोटा स्वय करने को राजी होता है। परन्तु यदि भूमि की चक्कन्दी आनिग्रामं कर हो जाप तो किशान हसका विराध करना देश वह समझता है कि भूमि की चक्कन्दी से उसके हितों के बोट पहुँचेगी। यदि चक्कन्दी योजना को लागू करने वाले कर्मनारी कम्मोर और अकुराल हुए हुए तो अनेक कांठनाहकों पेदा हो जाने की सभावना गहती है। परन्तु स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग करके भूमि को चक्कन्दी कराने का परिकास निराधासनक ही रहा है हसलिए हस योजना को अनिवार्य कर देने से हो अधिक लाम हो एकने की

इस दिशा में भूमि की चकवन्दी प्रयम प्रयास है। बास्तय में प्रयन इस बात का करना है कि भूमि का और उरवारा न हो अन्यमा चकवन्दी में कुछ बास अपन नहीं। यदि भूमि छोटे इस्त्रों में बैटती गई तो चकवन्दी का उरेहर ही विकता हो जायगा। भूमि का चकवन्दी के प्रवन्त का इस बाद से गरदा सम्बद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति आधिक ते अधिक कितनी एक्ट भूमि एव ककता है।

कानन--- नम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पेप्स, जम्म छीर कार-मीर में चक्रवन्दी के सम्बन्ध में विशेष कारान पास किये गये हैं। देहली ने पंजाब धकर को अपना लिया है और उद्दोशा ने १६५१ के एवं। कल्चर एकर में कुछ चकवन्दी सम्बन्धी नियम जोड़ दिये हैं। हैदराबाद, सीराध्ट, विलासपुर छीर राज-स्थान में इस सम्बन्ध में कालन विचाराधीन है। श्रारम्म में कानून श्रनुमति प्रदान करने वाले (Permissive) वे श्रीर विशेष पदाधिकारियों के द्वारा श्रदला बदली में सहायता तथा छट आदि का अवन्ध करते थे। बड़ीदा एक्ट इसी दंग का था। सहकारी समितियाँ किसानों के लिये स्वेन्छा से चकवन्दी कराने में विशेष सहायक हो चकती थी। जो कानून पास किये गये हैं उन्हें इम दो वर्गी में रख सकते हैं : (१) वे कानून जो किसानों को यदि उस गाँव में निश्चित प्रतिशत किसान राजी हों तो चकबन्दी के लिये वाध्य कर सकते के और (२) वे कानून जी राज्यों को यह अधिकार प्रदान करते थे कि वे अपनी और ने चक्कन्दी की योजनान्यों को साग करें। मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर के कानून पहिले वर्ग में और पताब पेप्स, देहली श्रीर बम्बई के कामून दूसरे वर्ग में आते हैं? । मध्य प्रदेश के कामून के अनुसार यदि किसी महाल, पट्टी अथवा गाँव के कम से कम आर्थ नियासी विनके हिस्से में गाँव की है मूमि आती है मिलकर चकवन्दी की योजना के लागू कराने की प्रार्थना करें ब्रार यदि चक्कन्दी योजना पढ़ते है । खकी है ता सब भूमि पर अधिकार रखने वालों को चक्रबन्दी योजना स्वीकार करने के लिये वाध्य किया जा सकता है। जम्म और काश्मीर के एक्ट के अनुसार यदि है किसान जिनके

अभिकार में किसी गाँव के है खेत हैं और वे चकबन्दों की योजना स्वीकार करते हैं तो वह योजना पक्षी मान लीं आयशी और लागू कर दी आयगी। इन कार्गों के कारण जो घोडे से व्यक्ति योजना को अस्वीकार करते हैं उन्हें भी योजना के अस्तर्गत लाकर उनकी सफलता निश्चित कर दी गई है।

हुए कायून के खानार यून सिखान्न निम्न हैं—(१) प्रत्येक पट्टेदार को जहाँ तक उम्मव हो उक वहां पर भूमि हो जायगी जिन छेन में उसकी अधिकांग भूमि हैं, (२) प्रत्येक गीन की भूमि का निम्मित निम्मित चेनों में किया जावगी, (क) चानक पेदा करने नाले छेन. (ल) चानक को छोड़ कर छान्य एक फतती चेन, (ग) हो कथलां चेन, हो पट्टे-दारों को उस छोन में भूमि टी जावगी जहां पर पहिले से ही उनकी भूमि है, (४) प्रत्येक पट्टेन्दार को उनने ही चक दिने जावंगे जितने कि गाँग में सेन एक सिंदी के छोड़ कर को छोड़कर) नाम के कि सिंदी गाँग में के प्रत्ये हो अने को छोड़कर) नाम के सिंदी प्रत्ये हैं जब तक कि सिंदी गाँग में सेन प्रकार हो छोड़कर) नाम के सिंदी प्रत्ये हैं जब तक कि सिंदी गाँग में के प्रत्ये हैं प्रत्ये के पट्टेन्दारों को वयालम्भव एक दुनरे के पड़ेल में हैं प्रत्ये दिने का सिंदी प्रत्ये हैं जिन को हैं स्थान की स्थान की स्थान की स्थान प्रत्ये का सिंदी छोड़ प्रत्ये हैं जि उन्हें चक देने में हम वारतों को विशेष प्रत्ये उसने कोई छुपार किया है तो उन्हें चक देने में हम वारतों का विशेष प्रत्यान रस्ता आर्था; (७) यदि कोई वक या काम पहिले छे ही है, एकइ या अधिक है तो यावपन्य वह न तो दिमानित किया जायगा और न नाँचा ही जायगा? । इन विश्वानों से न्यूनतम गड़कई तथा किशानों को अधिकतम लाम होने की वम्मानना है।

इस कानून के अन्तर्गत चक्रभन्दी के कार्य को करने का एक विश्वर कम दिया हुआ है। इसको कार्यान्वित करने के पहिले प्रत्येक किसान के प्लाटो का लेखा उनके चैत्रफूलों के साथ तथा प्रत्येक का लगान व मालगुजारी आदि के सहित तैयार क्रिया जायमा । एक ऐसी लालिका तैयार की आयारी जिसमें प्रत्येक पटतेतार के कल खेतों का सेशफल जो उनके पास विभिन्न प्रकार के शासामी श्राविकारों के श्रावतीन हैं तथा प्रमे जितनी सालगाजारी श्राववा प्रसंका लगान देना पहला है। सेवार किया जायगा । जब यह हिसाब पबके तीर पर तैयार हो जायमा तब किमानों को चक देन की शर्ने तैयार की जायमी जिसमें यह दिखाया जायगा कि कीन कीन से प्लाट प्रत्येक पटटेदार की उसके प्राने खेती के घटल में दिये आयेंगे सथा यदि नये सिरे से दिये हवे प्लाट उसके पराने प्लाटी वी तलना में कम मल्य के हैं तो क्या मुखावजा दिया जायना और उसके कथा. पेडा क्रीर हमारती के बहते में क्या महावजा दिया जायगा हत्यादि । इस प्रसाव पर किसानों को अजरहारी करने का अधिकार होगा । परन्त अजरहारी का जनाब टिये जाने पर प्रस्ताब परका हो जायमा श्रीर चरवन्दी योजना लाग हो जायमी । इसके पश्चात चक को दिये जाने का हक्य जारी हो जायगा जिसमें यह दिखाया जायगा कि योजना के श्रानसार कीन-कीन से नये खेत किसके हिस्से मे श्रागए हैं थीर उन्हें उन पर ऋधिकार दे दिया जायगा । इस बात का ध्यान रहाता जायगा कि किसानों को चक उसी सेत्र में दिया जाय बहाँ पर उनके श्राधिकांश खेत हैं। अभि पर अधिकार के सम्बन्ध में निर्शाय ऐसे निर्शायक द्वारा किया जायगा जिसे सरकार दन न्याय-कार्य सम्बन्धी श्रफत्तरों में से नियक्त करेगी जिन्हें कम में कम ७ वर्ष तक का ग्रनभव है। किसानों से भी राय ली जायशी ग्रीर उन्हें ग्रापित करने का श्रधिकार होता परन्त जब योजना पक्की हो जायगी तब सब को उसे मान क्षेत्रा पढ़िया । यह चक्रक्टी योजना न्यायालयों के कार्यन्त्रेत्र के बाहर इसलिए मानी गई है कि इस सम्बन्ध में गुरुदमेवाजी न हो। एक्ट के अनुसार चकवरदी का खर्चा ४ ६० प्रति एकड नियत कर दिया गया है जो योजना में समिति विभिन्न व्यक्तियों में बैंट जायगा ताकि सरकार को यह लर्चन उठामा पड़े। जिनके खेतों की चकवन्दी की जायगी उन्हें पेमाइश तथा श्रन्य प्रकार के शारीरिक शम बाले कार्य करने में सहयोग देना होगा श्रीर जो यह न कर सकेंगे तो उन्हें २ रु द आना प्रति एकड के हिसाब से अम के बदले में खर्च के प्रति देना पहेगा । यह कानून मूत्रफरनगर और महतानगर जिलों में लाग कर दिया गया है। योड़ा अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात पहिले यह २० जिलों में ब्रीए लागू किया जायगा। ब्राशा की जाती है उत्तर प्रदेश में इस कादन के अन्तर्भट चकवन्दी का कार्य बहुत मुगम होगा।

कठिनाइयाँ—चककरी-कार्य बहुत कठिनाइयों से मरा हुआ है। कुछ कठिनाइयाँ तो मनोवैज्ञानिक हैं और कुछ, प्रयागात्मक। (१) बहुत सी जगहों पर अस्ति जाधिकारों का कोई लेखा पास नहीं है। पंजाब में देश के बँटवारे के प्रज्वात सारे लगान सम्बन्धी लेखों के खो जाने के कारण बड़ी कठिनाइयों हा भागमा सरमा प्रदेश ।

(२) चक्चन्द्री का कार्य श्रीबौगिक हंग का है। इसके करने वालों की वैमाइशा. बन्दोबस्त, मृति के वर्गीकरण, भूगि के मूल्यांकन तथा पटटेदारी सम्बंधी जान शास्त्रवक है। ऐसे कार्यकर्ताश्ची की कभी के कारण खकरन्टी के बार्य में

लाधा पड़ी है। इस कठिनाई को दर करने के लिये कछ प्रदेशों में ऐसे ग्राफसरों को इस कार्य के लिये विशेष दैनिंग दैने का खायोजन किया गया है।

(3) इस बार्य में किसानों की बदिवादिता और पीटियों से अधिकार में हिन्दत भूमि के प्रति साह के कारण भी बाबा पड़ी है। असोंदारो और अन्य कामामाजिक शर्ती दारा बाधा उपस्थित करने से भी काम में रुकायद पहेंची है। क्यांत्वपर्वं क जनता में इस कार्यं के प्रति प्रचार तथा जानकारी की वृद्धि हाग तमा तहाँ धावरवक हो वहाँ अनिवाय रूप से लाग करने से ही हम बाधार्थी

पर धिजय पार्ड जा सकती है।

(४) चक्रकरी में अपया खर्च होता है और रुपये के प्रबंध के कारण भी इस कार्य में बाधा पहुंचती है। बादेशिक सरकारों के समज्ञ अनेक प्रकार की विकास योजनाय है इसलिये वे सदा इस कार्य के लिये पर्याप्त धन देने के लिये तैदयार नहीं रह सकता। इस सम्बन्ध में खर्च परह करने के लिये तीन उपायों के काम में लाने की अनुमति दी गई हैं। (क) दिस्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में खर्च का एक छश किसानों से चकवन्दी फीस के नाम पर बस्ल कर लिया जाता है। इस प्रकार कुछ, छाश तक व्यय सरकार द्वारा जीर कछ छांश तक किसान द्वारा पूरा कर लिया जाता है: (ख) वश्वई में सारा व्यय सरकार द्वारा सहन किया जाता है जहाँ पर किसाजों के साथ रियायत के रूप में दिना श्रीस लिये साम दिया जाता है। श्रीर (ग) जलर प्रदेश में जैशा कि कपर बताया जा चका है परा लचां किसान में ४ ६० प्रति एकड़ के हिसाब से वसक कर लिया जाता है।

सफलता की मात्रा-चकवन्दी की सफलता विधिन्न प्रदेशों में कम ही रहा है। केवल एंनाव, बन्वई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पेप्त छीर हिल्ली छाडि ने कुछ उपलता इस सम्बन्ध में पास की है। पजाब में चक्रबन्दी का साम १६२० से शारमा हुआ। चौर उत्तर प्रदेश में १६२४ से । उत्तर प्रदेश में १६५३ के चकबन्दी एक्ट के पास होने पर इन काम की गृति बढ़ गई श्रीर श्रागे चलकर एकट में भी उपयुक्त सुवार कर दिया गया । मार्च १९५५ तक वैजाब में ४० लाख एकड़. मध्य प्रदेश में २५ लाख एकड़, पेप्सू में १० लाख एकड़ से अधिक भूमि

की सकवन्दों की गई। बम्बई और दिल्ली में १०६० और २१० गाँवों में क्रमग्रः यह योजना पूर्णतथा लागू की गई है। उत्तर अदेश में २१ जिलों में यह योजना लागू हैं। अब भी विभिन्न राज्यों में इछ योजना के कार्य को बदाने का अवसर है।

यविष चक्रबन्दी का कार्य जरा पीथी गित से हुआ है और बहुत कम उन्नति इस और हो पाई है फिर मी इससे लाटों की संख्या कम हो गई है और उनका छोडत सेवक्रत बढ़ गया है। यदि प्लाटों की संख्या में कमी और खेलों के सेवक्रत में दृष्टि की इस्टि से देखा जाय तो इस कह एकते हैं कि स्वसं अधिक उन्नति मध्य प्रदेश ने की है जहां चिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जिलों में प्लाटों की संख्या दर्श कम हो गई है और उनका औरत सेवक्रत ४००% बढ़ गया है। इस और महास ने चक्रसे कम उन्नति की है और वहाँ प्लाटों की संख्या में २०% से भी कम कमी हुई है।

खेतों की चक्रमयी के फलस्वरूप प्रत्येक किछान को श्राधिक जोत (economic holding) प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि यदि किछी किछान के खेत गाँव के विभिन्न भागों में छिटके हुते हैं तो चक्रमयी ये किछान के श्रधिकार में भूमि का चेत्रफल नहीं बढ़ चक्रता। इस त्यां प्रत्येक किछान को श्राधिक जोत देने के लिये बहत बड़े प्रयस्न को श्राध्ययकता है।

#### ष्राध्याय 🕳

### भूमि-क्षरण

प्रथम पंचवपीय योजना के अनुसार भूमिसंरह्यण ते अभिप्राय केवल चरण को रोक पाना ही नहीं है परसु अपने व्यापक अर्थ में भूमि संस्कृत के अर्थना वह समी वार्त शामिज हैं जिनका जरूव पूमि को उत्पादन शासि को ऊर्च स्तर पर बनाये राजत है, जैसे भूमि की क्रियों को तूर कराये के उत्पाद राशायिक तथा देशी जाद का उपयोग, फरालों के बोने के क्रम का उचित संचालन, सिनाई तथा नाली की क्यवस्था इरयादि। इस कर में भूमि-संस्कृत का प्राय: भूमि के उपयोग के होंगों में जुपार करने से निकट सम्मय है। भूमि सरख्य के सम्मय में भारत की प्रयुक्त समया भूमि-स्तरण को रोकना है। भूमि हारख होते रहने से भूमि का चुन्न बना भाग कृषि के योग नहीं रहता।

कारण - भूमि चरण के अनेक कारण हैं परन्तु उनमें से मुख्य निमन-जिल्लात हैं :---

(१) वनों का काटना और यनस्थित का नष्ट हो जाना। जंगल और यनस्थित इना और पानी के बहाब को रोकते हैं जियसे भृषि का सल इनकी झार्नि-कारक शक्ति से बच जाता है और उवका स्था नहीं हो पाता। यदि दन काट हाले जायें और यनस्थित नष्ट कर दी जाय तो भृषि पृषेवत नहीं रही, उकती उत्तराम राखि पट जायगी। आयः हैंयन या इमारतों के उपयोग के लिए बनी को काट लिया जाता है। आदाम, बिहार, उकी वा और सम्पर्य रेग के कुछ मार्गी में कवायली जनता ( Tribal people ) एक निश्चित स्थान पर लेती नहीं करती है। वह साथ एक स्थान से दूवरे स्थान पर अपने कृषि-चेत्र वहनी रही है। वह साथ एक स्थान से दूवरे स्थान पर अपने कृषि-चेत्र वहनी रही है। वह साथ एक स्थान से दूवरे स्थान पर अपने कृषि-चेत्र वहनी रही है। इस साथ उक्त पेक काटते रहना पवता है और इस्पेव बनो का पिमाश हो जाता है। इस समीदारी उन्मूलन होते ही अमेक अमीदारों ने इसारती लककी से वयया पैदा करने के लिए अपने चेत्र के पेक काट डाले हैं।

(२) पशुओं और विशेषकर मेड़ बकरियों का घाड-पची इत्यादि वर जाना। इससे भूमि के कथा परस्पर शुने नहीं रह जाते और उउका चरण होने लगता है। वनस्पति का इस मकार चर लिया जाना भारत के लिए एक नम्मेर स्माचा वन भगा है। १९५९ में भारतीय इतिश्रास्त्रकान परिषद [Indian Council of Agricultural Research) के तत्वावधान में उसके फसल और भूमि विभाग (Crops and Soils Wing) की प्रथम बैठक में उस समय के लावाज मंत्री ने कहा कि मेट ककरियों को प्रथम देने का अर्थ है भूमि-स्रग्या और महाविनाया। परन्तु गाय-मेंस को प्रथम देकर हम भूमि की सेवा कर सकते हैं और स्वय समुद्दियाली बन सकते हैं। लाव मंत्री ने अधिक जोर देकर करर कहा है परन्तु यह सब है कि मेड बकरियों से भूमि को बहुत स्रति पहुँचती है। उचित यह होगा कि पशुओं को चारा दिया जाय और बिना रोक-टोक के हघर-उघर, विशोपकर उन देशों में जो हस कारण यहले ही खितमस्त हो जुके हैं, चरने न हिया जाय।

(३) जिस भूमि में उरगादक तत्वों की पहले ही में कमी है उसका शीप्र खरण हो जाता है। यहि भूमि उपलाज है और उसकी श्रव्यं तरह देखभाल की ग़र्र तो खराब भूमि की अपेखा हसमें भूमि-चरण कम होगा! काइत की बालो सूमि का भारत में पीढ़ियों से बिना किसी रोक टोक के बराबर उपयोग होता रहा है श्रीर उसकी उत्पादन शांत की पृति करने के खिय खाद हन्यादि या तो नहीं काली गई है या अपर्यात हो ही है। इससे देइ से के बड़े-बड़े याग भूमि चरण के संकट से महत्त हो कि हैं।

भूमि-सुरुण श्रनेक प्रकार का होता है परन्तु मारत में गुख्य प्रकार निम्न-निवित हैं :---

(१) तल चरण (Sheet Erosion)—यानी के तेन बहाव से या तेन इना के बहने के कारख जब मूमि की ऊपरी उपजाक सवह वह जाती है तब तल-सरण होता है।

(१) अन्तः च्ररण (Gully Etosion)—पानी के तेन बहाव के कारण मूमि में गहरे नाले वन जाने से अन्तः चरण होता है। प्रायः अन्तः क्ररण होने का कारण यह होता है कि बहुत समय तक तल-क्ररण होता रहे और उसे रोकने का काई उपाय म किया लाय। नार्दयों के आस-भार की भूमि में अग्तः खरण की अधिक संभावना रहतों है क्योंकि बाहु था अने से तट की निकटवर्ती-मूमि का तल करण होता रहता है और चीर-भीरे गहरे नाले बन चाते हैं।

(३) वायु क्षरण (Wind Erosion)—वायु जरण देश के मह प्रदेश में जैसे राजस्थान और पूर्वों पंजाब में होता है। तेज वायु वहने से मर जैम की बाल्, उनसी रहती है और निकटवर्ती हिस्सों में बैठती रहती है जैसा राजस्थान के मह प्रदेश के निकट होता है। इससे मूर्मि की उत्पादन शक्ति को गहरी हानि पहुँचती है।

भूमि खरण एक गंभीर संकट है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति कम होती

है, भूमि ज्यार्थ हो जाती है और जनता निर्मनता के चंगुल में मंख जाती है। इससे देश के बड़े-बड़े दोन मक्स्यल में बदल जाते हैं। उन दोनों में जहाँ नदी-भावी थोजनाएं लागू की गई हैं, जैसे दामोदर घारी, वहाँ पर भूमि इस्टण से निर्मित बाँगों को भन उत्सम्न हो लाता है। इस कारण इन बाँगों को देखभाल और बचाव के लिए खाधिक ज्याय करना पत्रता है। यह टुर्माम्य की बात है कि हमें अपने देश में मूमि-इस्टण के प्रकार और प्रवार के उपमच में धट्टी-घट्टी सूचना प्राप्त नहीं है इस सूचना के प्राप्त हो जाने पर भूमि-च्रत्य को रोकने के लिए प्रभानशाली उपायों को लागू किया जा अकता है। पिछले कुछ वर्षों में भूमि संरह्मण के लिए इस्ड काम किया गया है, बक्तई में छोटे-छोटे बाँच बाँचने और टेक लाय इस्ताद बाँचकर और उजल में बंगल लगाकर तथा पहाड़ी नाला। में बाँच हत्यादि बाँचकर और उजल प्रदेश में नाली तथा खड्डों से परिपूर्तर भूमि पर इबि करने मूमि संरक्षण किया जा रहा है। बाँच बाँचने और टेक इस्ताद का निर्मीच करने में और कटी-कटी भूमि को समस्ता विश्व इसी हस सम्बन्ध में बहुत कछ कार्य करने में का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु अभी इस सम्बन्ध में बहुत कछ कार्य करना शेन है।

राजस्थान के मकस्थल का क्रमणः उत्तर की छोर निस्तार एक विशेष चिन्ता का चिप्प हो गया है छोर भारत सरकार ने उसकी रोकपास के लिये तिम्न त्याय किये हैं ---

- (२) "दर वर्ष के मीतर ही श्रीतर ४०० मील लम्बी और ५ मील मीतर को झोर प्रीमी बङ्गल की एक वड़ी राजस्थान की पहिचयो सीमा पर स्ता देना हममें भेड़, बकरी, गाव, वैल, ऊंट, श्रादि यगुओं के चरने की श्राचा न होगी!"
  (२) महस्यल की श्रीम में बाल के क्यां को बरियाला द्वारा स्थिप करने में
- वैद्यानिक उपायो की लोज करना।
- (१) देले नलालरतानों की व्यवस्था करना जहाँ से पेष-पौधे पीनी नाकों, रेल के स्टेचनों, पुलिस के थानों, तहसीलों और स्कूलों के इर्ट-निर्दे लें जाकर लगाये जा सकें।
- (४) ऐसी जुनी हुई सड़को और रेल की लाइनों पर मनुष्यों की ब्रावादी
   में ब्रावास का प्रवन्य करना जो वासु के बहाब को काटती हुई बढ़ती है।
- ण आगप करना जा वायु क वहाव का काटता हुई बहता है। (4.) पैछी के कामके वाकी क्षीकरूपों को झंड और पीधी के बॉटने का प्रवास करना।
- (६) उपयुक्त चरागाही की स्थापना का प्रबन्ध करना जी कि समय-समय पर श्रीर वारी-वारी से चरने के लिये खोले जायें।

इन उपायों से खाशा की जाती है कि मस्त्यक्ष की बाद कक जायगी और भूमि-सुरक्ष कन्द हो जायगा तथा भूमि की उर्वरता स्थिर रह जायगी 1

प्रधम पंचवपीय योजना के अन्तर्गत—यम पंचवपीय योजना में सूमि चराय को रोकने और सूमि योजना के आवश्यकता पर निरोध कर से महत्त्व दिया गया था। मारत सरकार ने विरोधकों की एक तदर्थ-समिति (ad hoc Committee) बनाई यो जिसका कार्य पंजाब, पिटयाला संघ उत्तर प्रदेश, सीराष्ट्र और कब्ब के निकटक्वर्ती उपजाक स्त्रेश में सब प्रसार की समस्या का अध्ययन करना था। सिति ने एक विस्तृत कार्यक्रम की सिकारिय की है जिसमें यह समाव दिया गया है कि (१) राजस्थान की परिचामी सीमा पर ननस्पति का प्रभाव सिका किटयन्य लगाया साथ, (२) राजस्थान में चन क्षेत्र की बहाने के लिए नये बन तमाये गाँव, (३) भूमि के उपयोग के सरीकों में मुखार किया जाय । विशेष कर से कृषक रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए अनुसंधान के उपयोग करें और रेगिस्तान को समस्या का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान केन्द्र (Research Station) स्थापित किया साथ। भारत सरकार ने इस समिति की सिकारियों मान ली हैं।

मधम पोजना में भारत सरकार द्वारा २ करोड़ रूपये भूमि वंश्वयापर व्यव करने का आयोजन था। "भूमि वंश्वया कार्य जैसे बाँच बाँचने, खाई खोदने, नाले पाटने (gully Plugging), भूमि पर मेड़ बाँचने, पानी के बहाय पर रोक लगाने, नदी की धार्म को स्था खड्डों के बनने को नियन्तित करने आदि उपायों के अन्तर्गत जो प्रदेशीय सरकारों द्वारा किये जा रहे हैं सगमम ७००,००० एकड़ भूमि आ गई है जिसका दो तिहाई भाग केवल बनाई प्रदेश के भाग में आया है।

"प्रथम योजना में ही भूमि संरक्षण कार्य नियमित कर से खारम्म हो गया था। लगा-मग २५० कृषि और वन विभाग के अधिकारियों को भूमि संरक्षण उपायों को निरोग शिखा दी जा चुकी है। १९५२ में जोधपुर में रिगत्याम में कृष्ता-रिप्या सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की गई थी और प्रथम योजना के विद्वले वर्षों में ही प्रीच अनुस्मान तथा प्रशिख्य केन्द्रों की भी स्थापना हो गई यो। ग्यारह अग्रमामी योजना केन्द्र बन्बई, आत्म, उद्दोखा, विद्वली बंगाल, पद्राप, पंजाब, स्रीरष्ट्र प्रवक्ति, कोचीन, अक्रोर, कन्यु और मीजापुर में स्थापित स्वाप ये हैं। प्रवक्तीर, कोचीन तथा महास की वे आर्ट्य योजनाय विकास योजना केन्द्र में परिशास कर ही गई है।

इस समस्या को समुचित रूप से मुलकाने के विचार से मारत सरकार ने छ: भूमि संरक्ष्य सम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र देहरादन, कोटा, यसद (उत्तरी गुजरात) बेलारी, अटाकामणड और सोधपुर में खोले हैं। इन केन्द्रों ने बहत लागपद कार्य किया है।

दितीय पंचवर्षीय योजना — में तो और अधिक विस्तृत आयोजन किया गया है। भूमि संस्तृत्व के लिये २० करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। लगमग ३० लाख एकड भूमि जहाँ पर भूमि ज्ञरण बहुत श्रुरी तरह से हुआ है इस संस्तृत्य योजना के अन्तरांत लाने का इरादा है। इस २० लाख एकड भूमि में से २० लाख एकड़ तो उल्झा ऊँची नीची खेती के योग भूमि, २५०,००० एकड़ महस्थल तथा कटने वाले करार की मूमि, २१०,००० एकड़ नदी की घाटी वाली भूमि, १५०,००० एकड़ पहाड़ी अमि और १५०,००० एकड़ खड़ बाली भूमि होगी।

भारत में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि अभि-चरण की समस्या की गम्मीरता का जनता को ऋछ छान ही नहीं है। बुछ राज्य सरकारों ने भूमि संरक्ष्य के लिए बहुत सीमित उपायों को लागू किया है। जनता इस मारी संकट के प्रति थिल्कुल उदासील है और इस बात की खोर उसका ध्यान नहीं जाता कि भूमि चुरण को रोकने से कितना लाभ दो एकता है। इस सन्दंघ में व्यवहारिक हिंद से विचार करके प्रथम छोर दितीय पंचवर्षीय योजनाछों ने निश्चित प्रमृति की है परस्त इस कार्य के लिए जितना धन निर्धारिक किया गया है वह आवश्यकता से बहुत कम है। इस कार्य में इससे कही श्रधिक स्पया स्पय होगा । राज्य सरकारों की प्रापनी विसीय कठिनाइयों के पश्चात भी इस कार्य के लिये अधिक घन देना होगा। दीर्घकाल में इस व्यय से अवश्य लाम होगा क्योंकि मृमि की उत्पादन शक्ति बढ़ेगी और इमारी श्रनाब, कपास, तिलहन इत्यादि की उपन में बृद्धि होगी जिससे उत्पादन तथा उपमोग के बीच की वर्तमान खाई को पाटने में चहायता मिलेगी। केन्द्रीय भूमि चंरल्या बोर्ड से यह आशा की जाती है कि भृमि संरक्षण के उपायों के प्रयोग की प्रगति बढ़ाने में समर्थ होगा। यह बोर्ड "विभिन्न प्रकार की मामयों के जो खेती, जहल लगाने तथा चरागाइ बनाने के काम आ रही है संरच्या सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य का आरम्भ, सामंजस्य तथा व्यवस्था करेगा और प्रादेशिक राज्यों को तथा नदी घाटी योजनाओं को भूमि संरक्षण सम्बन्धी योजनात्रों के बनाने में तथा तत्सम्बन्धी कानून बनाने में सहायता प्रदान करेगा"। यह बोर्ड भूमि संरक्षण सम्बन्धो जानकार। की बातों के श्रादान-प्रदान का केन्द्र होगा तथा तत्त्वम्बन्धो शिला की सुविधा प्रदान करेगा ताकि भूमि सरस्य सम्बन्ध में आवश्यक कुशल व्यक्तियों को पैमाइश आदि कार्यों के लिये पूर्तिको जासके।

वर्षा ही भारत में कृषि की माध्य-विषात्री है। देश के विभिन्न भागों में भिग्न-भिन्न मात्र में वर्षा होती है जियमें काफी अन्तर रहता है। उदाहरखार्थ एक श्रोर ता चेरापूंजी जैसे स्थान पर ४६० इन्च तक वर्षा होती है जियसे बाद द्वारा फ़सलों इत्पादि की हानि होती है उत्पर्श और राजपूताना केवल ५ इन्च वर्षा होती है जहाँ पानी की कभी से फ़सलें नष्ट हो जाती हैं। चावल तथा गत्रे की खेती के लिये आपश्यक होता है कि पानी पर्याप्त भागा में निस्त्वर नियमित रूप से मिलता है। इसलिए आफ़्तिक खुविषा प्राप्त न होने के कारख भूमि के खिचाई के लिए और निरंधों के पानी को उचित उपयोग में लाने के लिए कृत्रिम उपायों का सहारा लेना पक्ता है।

भारत की नहियों से प्रात १३,५६० लाल एकड़ फुट पानी में से झीवतन केवल ५१६ प्रतिशत का उपयोग १६५१ के पहिले तक किया जाता था झीर रीप बाद द्वारा प्राय: इंगिन एईचाता हुआ चपुद्र में मिरता था। उनके परचात पानी का उपयोग वहां है। आशा को जाती है कि १६५६ में लगामा १,६६० लाख एकड़ फीट खल अथपा फुल का १०% कार्य में आ जातागा। पानी की कर भारी को शेककर हो जिनाई के कार्य में लाना चाहिए जिससे बाद का प्राथ पर्टी हो। प्राय: इस भारी चीत को शेककर हो जिनाई के कार्य में लाना चाहिए जिससे बाद का प्राय: इस भारी चीत को शेककर हो जिनाई के कार्य में लाना चाहिए जिससे बाद का प्राय: इस भारी चीत को शेककर हो जिनाई के कार्य में लाना चाहिए जिससे बाद का

सिंचाई का स्रोत

मारत में खिचाई के मुख्य साधन कुआ, तालाव और नहरें हैं। कहीं-कहीं निदयों से पानी खींचकर भी खिचाई की जाती है। खिचाई के यह सभी खोत निम्म चार्ट में टिये गए हैं



<sup>1.</sup> एक एकड़ जमीन को एक फुट गहराई सक भरने के लिए जितने पानी की ग्रावरयकता होती है वह एक एकड़ फुट पानी कहलाता है।

कुएँ—भारत में सिचाई के लिए कुएँ का प्राचीन काल से प्रयोग होता आया है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण शायन है। कुएँ या तो कच्चे होते हैं या पक्के। हमारे देश में कच्चे कुओं की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि इनका निर्माण करने में न तो अधिक ब्यय होता है और न विशेष कला के ज्ञान की हो आत्रश्य-कता है। इनसे धानी निकलने के लिये ढेकली का उपयोग होता है। पक्के कुएँ हो प्रकार के होते हैं, (१) ऐसे कुएँ जिनका पानी खीचने के लिए रहट या चरस का उपयोग किया जाता है और (२) नलकुर (Tube-wells) जिनका पानी खींचने के लिये बिजली के या जिल्ला एवरी ब्राह्म उपयोग किया जाता है।

कुएँ ख्रिषिकतर मैदानी माग में खीर विशेषकर ऐसे भागों में बनाये जाते हैं जहाँ पानी का तल बहुत गहरा नहीं होता है छीर जहाँ भूमि मुखायम होती है। पंजान, उत्तर मदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बाट के पूर्वी माग छीर कपाछ की किया कोलो भूमि ने ख्रीकहर दिवाह के लिए कुझी का ही उपयोग किया जाता है। यह कुएँ निजी भी होते हैं खीर उरकारी भी। उत्तर प्रदेश में लगामग हो हजार सरकारी हुएँ हैं।

कुलों के पानी से खिवाई करना लाभदावक है क्योंकि कुएँ के पानी में खोजा, नाइट्रेंट, क्लोराईड श्रीर सल्फेट काकी मात्रा में रहते हैं। इनसे सूमि की उत्पादन शक्ति में इबि होती है। इसके साथ ही कुश्रों से खिचाई करने का एक श्रीर लाम भी है। नहरों से विचाई करने से पानी एक स्थान पर एकत्र हो जाता है परन्द कुश्रों के उपयोग से ऐटा होना सम्मन्न नहीं है। यदि कुपकों को तलाई परन्द कुश्रों के उपयोग से ऐटा होना सम्मन्न नहीं है। यदि कुपकों को नात्रा श्रीर खायिक पक्के कुश्रों का निर्माण करने के लिये भोसाहन दिया कांग से अधिक उपयुक्त होगा। उन्हें कुश्रें खोदने की सुविधा दी जानी चाहिए श्रीर किजलों से खलने साले पम्प जमाने के लिए गाँच तक विजली पहुँचानी चाहिय विचाई से विजलों के प्रथम सरते होते हैं श्रीर खम्प सामनों की अपेचा अच्छे भी होते हैं। विचाई के लिये नात्रीन कुश्रों का निर्माण हमी उद्देश्य के लिए संगटित सह-कारी स्विधी के द्वारा किया जाना चाहिए।

वालाय—रालानों के द्वारा िषवाई करने का अधिक प्रचलन दिल्ला में और विशेषकर महाध तथा भैदर से है। पैने बड़ाल, विहार, उड़ीता, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मी विचार के तियों तालानों का प्रयोग किया वाता है। कहीं कहीं यह वालान काली बड़े हैं तिरुष्टें कील कहना अधिक उपयुक्त होंगा और कहीं क्रीटे-छोटे हैं जैसे माया गाँचों में होते हैं। इनमें कुछ प्राकृतिक है और कुछ का निर्माण किया गया है जो कच्चे-पड़के दोनों प्रकार के हैं। पड़के तालाव भूमि के नीचे थ्रीर भूमि के अपर भी बनाए जाते हैं। यह तालाब वर्षों के पानी से भरते हैं। श्री कान्य कत्र थ्रों के उनसे लिचाई के लिये पानी लिया जाता है।

के अपनी की तरह वालाव का पानी भी तरावन शक्ति बहुनियां है व्यक्ति हस्यें वर्षा का पानी और मन्दगी दोनों मिले होते हैं। यथि तालाव विचाई के महत्वपूर्ण साधन है परन्त इनकी स्थित सन्तोपकनक नहीं है। इनकी बहुर है के महत्वपूर्ण साधन है परन्त इनकी स्थित सन्तोपकनक नहीं है। इनकी बहुर है हि एवं तो सहराई मिट्टो भरने से घोरे-घोरे पटती जाती है। इसकी अश्वर्यकता इस बात की है कि पुराने तालावों को महरा किया जाते और के किया ने वालाव खोरे आर्थे। चूँकि कृपक इस दिशा में अधिक कार्य नहीं कर सकता है इसकिये तालाव खोरे को किया सम्बद्ध के स्थान से स्थान के लिये सम्बद्ध को अश्वर्यकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में श्रीपक कार्य कर रही। यह कार्य पंचायती, स्थानीय संदायां और वहकारी धानित्यों को वीचना चाहिये। पक्क तालावों का निर्माण करने में अधिक ज्या करना प्रकार के एवं है। सम्बद्ध वालावों को निर्माण करने में अधिक ज्या करना प्रकार के है। सम्बद्ध वालावों को तरह इनका आर्थक संदेश में निर्माण करना आवश्यक है क्योंकि इनमें पानी कार्का समय तक सुरक्षित रक्षा जा सकता है। क्ये तालावों को तरह इनका पानी श्रीम स्थान की पूर्ति में सुधार होगा और पानी वर्ष में नहीं जाया। वाल यह तालावों कार्ती तक पक्ष नहीं लाया। जल यह तालाव कार्ती हो लाखें तो विचाई की अश्वर्यकता न दहने पर नहीं जाया। चन यह तालावों हो लोखें तो हिवाई की अश्वर्यकता न दहने पर नहीं के पानी से इन्हें भरा ला सकता है।

नहरूँ—नहर का पानी आरत में विचार का खबसे बड़ा राधन है। पंजाब उत्तर प्रदेश माराज, बिहार, भ्रावास, भैगर, हैदराबाद, बम्बई, मध्य प्रदेश मीर उद्देश में नहरों का जात बुखा हुआ है। नहरें दोग्रकार की होती हैं (१) वादमिती कहा ना माराज का स्वाद कर का सारमारी नहरों का निर्माण किया जाता है। इन नहरों से वर्ष भर पानी भात हो तकता है। वृद्धरी और बाद निरोधक नहरों में निर्मो का पानी एक स्तर से अधिक वृद्धरी और बाद निरोधक नहरों में निर्मो का पानी एक स्तर से अधिक वृद्धरों के देवां के स्वाद्धा रक्षित हो जाता है। वारहमारी नहरें का पानी सुख जाता है तो है नमीक सुखा पड़ने पर जब बाद-निरोधक नहरों का पानी सुख जाता है तो हन नहरें से विचार माराज हो बहर्र तक निर्माण-स्वय का सम्बन्ध है बाद-निरेधक नहरों के निर्माण-स्वय की सम्बन्ध स्वयं बाद माराज से विचार स्वयं के निर्माण-स्वयं की अधिका बहुत कम व्ययं होता है। बारहमार्थ नहरों के अधिक अधिक कुरालता महानों और विभिन्न सामियों की आवश्यकता होती है।

नहरों से क्षिचाई करने से कुछ, हानियाँ मी होती हैं। इससे पानी एक स्थान पर एकत्रित रहता है श्रीर खेत में पहुँचने से पूर्व काफी मात्रा में पानी नध्य हो जाता है। परन्तु यह बड़ी सप्तस्कार्ये नहीं है। नहर्सों को पक्का कर देने से यह समाप्त हो जायँगी।

सिचाई कर — सिचाई कर की दर और उसकी नस्तुलों के दग प्रायेक फलत और प्रायेक राज्य में मिल रहते हैं। नहर और नलक्षों को सिचाई दर मी मिलन-मिल हैं। एक एकड़ प्रिम में मन्ते को खेती में जिलाई करते की दर उत्तर प्रदेश में भू रपता और हैदराशद में २३ रुपया है। कायाध के लिए पंजान में २३ रुपया और मद्रास में २० रुपया है, जायल की मित एकड़ सिचाई दर ४ रुपये ते दें दें भू रुपये तक हैं और गेहूं को ढाई रुपये से १० रुपये तक है। इससे छात होता है कि व्यवतायो-मस्तुल के लिए सिचाई कर की दर खादाव्य की अभेद्धा अधिक है। दर का यह अन्तर इस बात पर आधारित है कि मित एकड़ व्यवसायी-ससल से खादान के मित एकड़ की अपेदा अधिक लाभ होता है। आजकल पानी की लेक स्वावश्यक इति होती है उसे बन्द रुपता चाहिए और यह स्वावश्यक हो तो स्वय किये गए पानी की माला के खावार पर सिचाई कर जगाना चाहिए।

ापछते कुछ वर्षों में कुछ राज्यों ने नहे विकास योजनाओं की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति करने के लिए अपनी सिचाई वर की दरों को बढ़ा दिया है अबसे कुपक पर भार और बढ़ गया है। विचाई के कार्यों की नाओं में अपने अपनी अपने साथारण कार्यों की तरह चलाना चाहिए। विचाई कर की दर केवल इतनी होनी चाहिए जिससे हुए कार्ये को चलाने में हीने बाला क्या निकल आए और योजना हो कार्यों नियस करने में चाला क्या निकल आए और योजना हो कार्यों कि कार्यों के चलाने में हीने बाला क्या निकल आए और योजना हो कार्यों कि कार्यों के साथा क्या ना कुपनी लगाई गई है उसकी वस्ती होती रहे। सिचाई कर राख्यों के लिये आप करा साथन न होना चाहिए, जैसा कि उसर प्रदेश में बना दिया गया है, क्यों क इससे अपने वस्त अपने क्या कार्यों के इस अपने वह आप है।

भवा अपन कह जाता है।
संगठन—१६१६ है विचाई व्यवस्था राज्य सरकारों के हाथ में झा गई
है। प्रत्येक राज्य में एक विचाई विभाग है जो राज्य में विचाई के कार्यों के
किता के लिये उत्तरदाथी होता है। अन्तर-राज्य विचाई क्यारपा का लेखालन
करने के लिये उत्तरदाथी होता है। अन्तर-राज्य विचाई क्यारपा का लेखालन
करने के लिय हो केन्त्रीय सर्व्याएँ हैं। अनमें से एक केन्द्रीय अल्वियुत, विचाई
की भी। इचका उदेश्य जल शक्ति पर नियंत्य रखने, उत्तरका उत्तर ने १६५५ में
की भी। इचका उदेश्य जल शक्ति पर नियंत्य रखने, उत्तरका उत्तरीय और संस्थय
करने के लिए योजनाएँ बनाना और सभी कार्यों को सुसम्बद करने उन्हें कार्योग्य
करना है। इसके साथ हो हम्की यह भी कार्ये सींग प्रया है कि ब्रावस्थकता पढ़ने
पर स्थानियत स्थान सरकारों से परामर्थं करके कोई नई योजना तियार करें।

परिषद् को यह कार्य शींपा गया कि मारत के अनुसन्यान केन्द्रों में शिंचाई तथा इसके सम्बन्धित श्रन्थ विथयों पर किये जाने वाले खोज कार्यों का समन्वय करे। इन समस्यात्रों से सम्पर्क रखने वाली विदेशी सस्यात्रों से भी परिषद श्रपना सम्बन्य बनाए रखती है। इनके अलावा केन्द्रीय मीमिक जल सव (Central Ground Water Organisation) नाम की संस्था भी है जो १६४६-४७ से जल-स्रोती का ग्राध्ययन कर रही है।

१९५४ से भारत संघ के कृषि तथा खाद्य मंत्रालय के अन्तर्गत नलकृष योजनाओं के प्रशासक के निर्देशन में एक नलकूप विकास संघ भी कार्य कर रहा है। यह संस्था जहाँ सदा वर्षों कम होती है वहाँ इस बात का पता लगायेगी कि

भूमि के अन्तरतल से कितना पानी प्राप्त कर लेने की सम्भावना है।

विचाई की समस्या को दो ढंग की योजना छो द्वारा सुलक्षाने का प्रथक किया गया है । प्रथम बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं द्वारा तथा छोटे-छोटे विचाई के साथनी द्वारा । बहुमुखी नदी घाटी योजना श्रम्य लामा के अतिरिक्त बहुत वहें च्चेत्र को सिंचाई के लिए पानी देती है। छांटे-छांटे सिंचाई के साधन यदापि देखने में इतने आकर्षक नहीं हैं किर भी कृपकों को सिंचाई के लिये अत्यन्त आवश्यक पानी देते हैं। यह आशा की जाती है कि जब सब नदी-बाटी योजनार्ने पूर्य हो अपॅगी नो उनसे लगमग १६५ लाल एकड भूमि की खिचाई हो सकेगी।

कठिनाइयाँ - मारत में छिचाई की व्यवस्था का विकास करने में अनेक कित्रहर्यों का वामना करना पढ़ता है जिनका विवरस्य निम्नलिखित है :---

(१) वित्त की समस्या-सिंवाई योजनात्रों को लागू करने में सबमें बड़ी कठिनाई वित्त की है। इनके लिए बहुत अधिक रुपयों की आवश्यकता पहती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कड़ी विचाई योजनात्रा के लिए ५५८ करोड़ स्रीर छोटी हिचाई योजनाओं के लिए ४७ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया या। इसके साथ ही कुन्नों तथा तालावों का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों श्रीर सहकारी सामितियों को कुछ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। यह घन प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजना मे ऋण लेने, राजस्व की आय से सहायता लेने, विशेष अनुदानों, अलपूर्ति कर ऋीर लमान में वृद्धि करने और विचाई तथा विकास कर लागू करने की ब्यवस्था की गई थी। परन्तु यह कर उसके भार को ऐते समय में बढ़ा देते हैं जब कि कर-मार स्वयं काफी अधिक है। इसमें सन्देह नहीं कि इतना घन प्राप्त करने में बनता पर अनुचित भार पड़ेगा जिससे असन्तोध **फैलने** की सम्मावना है।

(२) प्राविधिक (टेक्निकल) ज्ञान का खमाव-धन के स्रमाय के

साम ही शोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अवेद्वित प्राविधिक कर्मचारियों का भी अभाव है। प्रायः सभी बड़ी योजनाओं में विदेशी प्रविधिजों को नियुक्त किया गया है और इस्ते अनावर्यक रूप से अधिक व्यव करना पढ़ रहा है। इस्तिये यह आवर्यकता है कि देश में भारतीयों के लिए अनुसन्धान और प्राय-क्या हैन्द्र कोले जाये।

- (३) आवश्यक सामान की कभी—मारत में इन योजनाओं के लिए आवश्यक इश्मत और लिमेंट की भी कभी है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसका उत्पारन और बहुपा जाय और जो कुछ सामान उपलब्ध ही सके उसकी मक्षेत्र वहने स्वित्तर के लिए जिस्सी करी के जाया जाया
- (४) पानी का अनुचित अपयोग और श्रीत—मारतीय क्रमक पानी का उचित उपयोग नहीं करता। विभिन्न चेत्रों में विभिन्न करतों के लिए श्रावश्यक पानी की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। परन्तु भारतीय क्रप्रक पानी का विना लोके समसे उपयोग करता है। पानी की श्रीकता खेती के लिये उतनी ही हानिकारक है जितनी उसकी न्यूनता। एक समस में श्रावक पानी देने की श्रीदेश बार-गर पानी देना श्रीक काभदायक छिड हुआ है। पानी की इस चृति को क्रुछ सीमा तक नहरी को पक्का बनोने श्रीर काम में लाये गये पानी की मात्रा के आधार पर सिवार कर लाग करने ते रोकर ना सकता है।
- (४) पानी का गलत वहँवारा—मारतीय कृषक बहुत समय तक अपने खेत की सीवने के जिए वर्षों के आगमन की प्रतिज्ञा करता है। जब वर्षों वे देर हो जाती है तब वह स्विचाई के जिए वर्षों के आगमन की प्रतिज्ञा करता है। जब वर्षों वे देर हो जाती है तब वह स्विचाई के जिए वह सी समय में नहरें और नल कूरों से आवश्यक वर्षानी मिलना सम्मय नहीं है क्वोंकि भारत में नहरें और नल कूरों से आवश्यक वर्षों में अपने में कहीं हो। हम प्रकार की दौड़ पूप से जिया में कि प्रवास पर बहुत आहर पढ़ता है जिसकों कम करने के लिए किसानों को अपनी आवश्यकार्य पहले से दर्ज करानी आवश्यकार्य पहले हो अपकों कम करने के लिए किसानों को अपनी आवश्यकार्य पहले से दर्ज करानी आवश्यकार्य पहले हो की क्षाना आवश्यकार्य पहले के क्षानी आवश्यकार्य पहले के स्वास्त्र मार करने का अपनी आवश्यकार्य पहले से दर्ज करानी आवश्यकार्य पहले हो जो स्वास का जिए।

यह किंकाइयाँ ब्रायाच्य नहीं हैं। उचित प्रवन्तों से इनको इल किया जा सकता है। यदि रूपक वहंगोग दें और पानी की उचित रूप से ज्यवहार में लाने की झानश्यकता को समक्तें और बहुमुखी नदो बादी योजनाओं के साम-साम करी-मृत होनेवाओं योजनाओं पर और दिया जाय तो देश की विचाई व्यवस्था संमल जायगी।

#### ऋध्याय ११

# बहुउद्देशीय योजनाएँ और बाद नियंत्रण कार्यक्रम

िष्याई श्रीर शक्ति उत्पादन योजनायें प्रथम श्रीर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाश्ची के सुख्य श्रंस है। इनयें विद्युत शक्ति के उत्पादन श्रीर विंचाई की सुविधा में वृद्धि होगी जिनका श्रमाब उद्योगों श्रीर कृष्य की उत्तित में वायक रहा है। इस योजनाश्ची से बाद पर निर्णवण्या, मलेशिया के फैलने में क्लावट, तथा देश को श्रम्य श्रमेकी लाम होंगे। प्रथम और दिव्यीय योजनाश्ची के श्रम्तवर्धन तीन प्रकार की विचाई योजनाश्ची की श्रम्यक्षीर है। (१) बहुउद्शीय योजनाश्ची, (२) वड़ी तथा साहरत्या विचाई योजनाश्ची की श्रम्यक्षीय है। (१) बहुउद्शीय योजनायं, (१) वड़ी तथा साहरत्या विचाई श्री योजनायें ।

हम योजनाकों की बीन विशेषतायें हैं। (क) हममें से क्षमेकों तो पंचव-पीय योजना के क्षारम्म होने के पूर्व हो हो चल रहीं थी। "दितीय महासमर का क्षमत होते ही बहुत सी परियोजनायें जिनमें कई बहुउदेशीय योजनायें भी घीं क्षारम्म कर दी गई थी। हममें के कुछ तो ऐसी धी बिनका कार्य तो बिना उनके रमम्प में क्षाद्यक प्राचीशिक कौर क्षाधिक छान बीन के ही खारम्म कर दिया गया था। १६६५ में जब विचार्ट क्षीर खांकि उत्पादन की योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा था, उनके पूर्य होने में कुल व्यय ७६५ करोड़ रुपये होने का अन्त-मान याग हसमें से १५३ करोड़ रुपया तो इन अपूर्ण योजनाओं पर व्यय हो चुका या क्योंकि देखा विचारा जाता था कि जितना सीम हो एके उतना सीम ये योज-नायें पूर्य की बांय जितसे कि जो कुछ धन हन पर व्यय किया जा चुका है यह स्थाफ क्षाक डाय।

(य) प्रथम योजना के अन्तर्गंत जिन परियोजनाओं को आरम्म किया गया था जन पर पुन: विचार किया गया और विचाई तथा यांक उत्पादन की योजना पर चयर पुन्न: करोड़ रुपये के बढ़ाकर ६७० करोड़ रुपया कर दिया गया। जो अन्य महत्वशाली परिवर्तन किये गये वे निम्म हैं। (१) १६५१ में योजना निर्माण के समय सदा से कभी के चीत्र को आवावश्यक्ताओं की आर विशेष प्याना नहीं दिया गया था। इन चेत्रों की जनता के निर्धन होने तथा उनके आर्थिक कार्यों में मिरन्तर प्रशुप्त की जनता के निर्धन होने तथा उनके आर्थिक कार्यों में मिरन्तर प्रशुप्त की जनता के निर्धन होने तथा उनके आर्थिक कार्यों में मिरन्तर प्रशुप्त की अर्थाण कि उपस्थित के कारण निरस्तर प्रशुप्त की अर्थाण कि अर्थाण विश्व स्थाण विश्व स्थाण कि अर्थाण विश्व स्थाण कि स्थाण की स्थाण की स्थाण की स्थाण की स्थाण कि स्थाण की स्थाण कि स्थाण कि स्थाण कि स्थाण की स्थाण क

लिये कार्यक्रम निश्चित किए सए श्रीर इस प्रकार सम्पूर्ण थोखना के दुल न्यय में ४० करीड़ रुपये की बृद्धि की गई। इन योजनात्री का ध्येग या कि वे जनता के पास धन की वृद्धि करेगी श्रीर वे भविष्य के विकास कार्यक्रम में उससे सहानता दे सकेंगे। (२) १६ १४ ५ ५५ में छोटी छोटी श्रांक उत्पादम की योजनात्रों इसमें स्थिमितित कर ली गई जिन पर २० करोड़ २० इस विचार से स्थय करने का निरुचय किया गया कि उनसे छोटे-छोटे करने होर गाँवों में जनता को कार्य पाने का श्रायम करा साह हो सकेगा, श्रीर (१) बाह पर निर्मत्रण रखने का स्थिम प्रमान पान पान पान जिल्ला स्था करना वा वा जिल्ला स्था करना वा वा जिल्ला स्था करने का निरुचय किया गया।

(ग) इन योजनाओं का कार्य इतना अधिक या और धन तथा अग्य आवश्यक साधनों का इतना अभाव या कि अवको कार्यायिन्त करना सम्भव नहीं हो सका। इसलिए उपपूर्व कार्यक्रम को अंदों में विमाखित करना आवश्यक हो यथा। मध्य योजना से यह जिल्लीय क्या यथा कि यावल, कोसी, कृष्णा, कोयना और दिवन्त योजनाओं को सम्बक्त के अभिनय काल में अगस्य कि वाय।

हत प्रकार दिलाय पचावपीय योजना सं यह निर्मय किया गया है कि कुछ बड़े काम जैसे खानम की जमनाचरा योजना, विहार की कन्छाई योजना और बम्बई की उभाई नर्मेदा, साही, खडरावाचला, विरत्ता और बनस योजनास, सम्प-मेदेश की तावा योजना और पिछली बंगाल की कासाबाती योजना सम्पूर्ण योजना काल के खनियम भाग में कावांनियन की बावसी।

योजना के जन्य कार्यक्रमों की अपेदा विचाई और शक्ति उत्पादन योजमाझों पर इनट में निश्चित ज्यम कहीं अधिक ज्यम किया गया। यह एक संतीयाद बात है, क्योंकि इसमें आरतवर्ष की आधिक स्थिति अधेदीन कीर उद्योगी
तथा कृषि में तीज गित से विकास सम्मव होगा। म्यम योजना के तीन यदी व्यतीत होने के पूर्व ही भारतवर्ष मंदि अफ के लिये आस्म निर्मर हो सका है तो
किसी सीमा तक इसका कारया सिवाई तथा शक्ति उत्थादन योजनामें हैं। प्रथम
योजना के मयम भाव पत्ती में ६७० करोड की व्यवस्था में से ४४५ करोड कपना गो
कि कुरा बना चुका था। बहुउदेशीय योजनाओं पर १८० ५२६ करोड कपना गो
कि कुरा बन्म का ७६% है, शक्ति उत्पादन योजनाओं पर, १९२ ७५ करोड कपना गो
कि कुरा बन्म का ७६% है, शक्ति उत्पादन योजनाओं पर, १९२ ७५ करोड कपना गो
कि कुरा बन्म का ७६% है, शक्ति उत्पादन योजनाओं गर, १९२ ७५ करोड कपना गो
कि इस १९ है विचाई योजनाओं पर (जिनमें कमी के सेत्रों का कार्यक्रम सम्मा
किता है) १९३.३७ करोड रूपमा को कि ६४% है, ज्यम किया, जाएगा।
१९६५-५५ के अन्त तक कृषि के अन्वर्गत लाया गया अतिरिक्त चेत्र २० स्वाल

६६२००० किलोबाट शक्ति उत्पादन धिया गया, जब कि ध्येष स्पर् १००० किलोबाट उत्पादित करने का था।

बहुत सी नहीं बोजनाओं पर बहुत उचित की जा सुकी है, और पह आया की जाती है, कि वे दिवास शोजना काल में पूर्व कर ही जारंगी। इन योजनाओं में भावजा, हीगकुपड, कोवजा, चन्त्रज्ञ और रिस्ट योजनायें आती हैं। इन सबसे २७ लाख कितोबाट विद्यास श्रीक उत्तका को जा सकेशी।

## षहुउद्देशीय योजनाएँ

कुछ गडुबर्दशीय योजनाओं थेले माकड़ा नांगल, दिराकी, रामोदर धाटी श्रीर हीराकुवह श्रादि ने पंजवर्षीय योजना के समम चार वर्षों में संतोधमर उसित की श्रीर योजना में निश्चित १८२१०२ करोड़ रुपय में से उन पर १६७१६ करोड़ वेपरा क्या किया जा खुड़ा है, इसके फलस्वकर व लाख एकड़ श्रानिक भूमि की विपाद सम्मव हो एकी है, श्रीर २०२००० किलोबाट विषुद श्राक उत्पत्त की जा सही है।

भाकड़ा नांगल योजना—यह योजना पंजाब, पेप्ट, और राजस्थान को प्राचिपाय पहुँचानेगा। इटके अन्तर्गत (१) वनलक नदी के आरापर भाकड़ा बांच मंगा, (१) नोगल वाँच नदा में बहाव की ओर द शील वाँच नदेशा, (१) नोगल नांच सहाव की ओर द शील को बनेगा, (१) नोगल नांच हात्व वर्तें और (५) भाकड़ा तहर व्यवस्था चंची। यह पोजना रह्मक में आराम की गई थी, और अब तक नोगल बांच नहरं नियानक (canal regulator), नांगल जल द्वार तथा पंजाब में सावकड़ा नहरं प्रतिकृति पूर्ण हो चुको है। हमारे प्रवान मंत्री ने क जुलारे रह्मभ को हत्व नदरं जा व्यवस्था का उद्याटन दिला था। भाकड़ा बाँच को चुने हारर ठीए अरने फे कार्य का उद्याटन रहना था। भाकड़ा बाँच को चुने हारर ठीए अरने फे कार्य का उद्याटन रहने भ नांचर रहने भी किया गया।

दामीदर घाटी योजना—योजना काल के वसन चार बच्चे में हस योजना पर धर्म १ करोफ कपना क्या किया जा चुका या, और ११ लाल एकव प्रति-रिक मूंन की निवाई और १५ लाल किलोगर निवुत्त ग्रीक का उत्पादना होने बचा। दानोदरमारी योजना एक ऐसे महत्ववाली श्रीवोधिक कीन को पियार्ष पहुँचावी है, 'ब्यूहीं के देख में मान कुल कोचले की जाजा का कर्श श्रमक का ७०%, कोनावट का ७०% कायरकों का ५०% लोहे का १८५% वांचे का १०० भिषाद और कामोनाहट का १००% पास होना हैण । वन वह योजना पूर्व हो बावनी तर यह देश के श्रीवोधिक तथा कृषि कम्यनी विकास में काकी मात्रा में सहनेता प्रदान करेगी। हीरा कुएड योजना —यह योजना उड़ीधा राज्य को मुश्चिम प्रदान करेगी, श्रीर इस योजना की प्रारम्भिक श्रवस्था में (१) महानदी की घाटी में एक बॉप फकड़ परंपर और मिट्टी का, (२) दोनों किनारों पर मिट्टी के जल घरण (dykes) (३) दोनों किनारों पर नहर, (४) बाँच पर एक पावर हाउस १८२००० किलोबाट नियुत उत्तल करने के लिये श्रीर (५) द्वान्यमिशन लाइन्स बनाई बायेंगी। (सेतों में नालियों को खुटबा देने से श्रिपकाधिक सेतों की सिंचाई की मुक्किंग श्रीर इस प्रकार १९५८-५६ तक कुल ४५४ लाख एकड़ दीन सीचा लाइन्स

## विभिन्न प्रदेशों से खोजनाओं की प्रगति

दाल्यों में खिचाई योजनाओं की प्रगति बहुउदेशीय योजनाओं की त्रसान कि कम हुई। १९५१ से ५६ तक चार ययों में बारतिक क्या १८८००८ करोई स्पता हुआ जब कि सम्पूण योजना के पुनरीज्ञण के पश्चात २००५६८ करोई स्पत्र के ब्यय करने की व्यवस्था को गई यी। आतिरिक केन विवयर विवाह की गई वह केवल १५ लांख एकइ या, जब कि योजना में ६५ लांख एकइ आतिरक सुमि पर खिचाई करने का व्यय या। इन योजनाओं की प्रगति 'क' राज्यों क कुछ मानो में वा 'ख' राज्यों के अधिकांश मानो में भीनी ही रही है। इसका कारण संगठन का अभाव, प्रशासनी और काम करने बालों का अभाव और योजना में बार-वार पारवान करना रहा है।

श्रापिकांश श्रांतिरिक्त सिंचाई ( सममत ६० लास एकड़) जो बड़े श्रीर रापारण श्रेणी की योजनाशों से होगी वह उन कार्यकर्मों की पूर्ति हो जाने के कारण होगी जो कि श्रथम योजना से ही जज रहे हैं । दितीय योजना में सर्पमिलित नई योजनाशों से लगमम ३० लास एकड़ मृमि सींची जामगी। द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत बड़ी श्रोर साधारण श्रेणी की योजनाशों के पूर्ण हो जाने पर उनकी सींचने की श्रांक लगमग १६० लास एकड़ होगी।

दितीय योजना के अन्तर्गत विद्युत-शक्ति उत्पादन के विकास-कायक्रम के तीन प्येय हैं: (क) वर्षभान पावर हाउसी पर बड़े हुवे सामान्य भार को यहन करना: (क) पूर्ति के दोनों के युक्ति संगत विकास के लिये आवश्यक विद्युत स्रक्ति का उत्पादन करना श्रीर (म) दितीय यंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नमीन आरम्म किए हुए उसीगी की आवश्यक्ताओं की पूर्ति करना ।

## बाद नियंत्रख का कार्यक्रम

सरकार ने समियत आधार पर बाद की समस्या के तिराकरण का आरक्त महत्ववाली निर्माण किया है। प्रथम योजना के आरक्त में बाद निर्मयण की कोई मी निश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी। उद्य स्वय याद बाद निर्मयण की कोई मी निश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी। उद्य स्वय याद निर्मयण पेक नार्य निर्मय पेक नार्य निर्मय के विकास समस्यो बहुउद्देशिय योजनाओं के अन्तर्गत रखी गई मी। १९५५ की अपूर्व बाहों ने प्राय सम्यति तथा यादावात की विशेषकर देश के उत्यत्य हुए वाहों ने प्राय सम्यति तथा यादावात की विशेषकर देश के उत्यत्य वाह की समस्या पर स्विचाई और विद्युत शक्त का उत्यत्व का का मान्य पर स्विचाई और विद्युत शक्त आका अनुवाद का का प्रवाद का सम्यत्य आवश्यक हो गया। प्रदेशों हारा वात्काविक बाद निर्मय के किया अपना का प्रवाद का स्वाद निर्मय की उत्यत देश से द्वित्य का को अपना का का का निर्मय की सम्या का का का निर्मय का स्वाद निर्मय की जीवना में इपीलिये १६% करोड़ कर की क्यास्था और कर दो गयी। बाद निर्मय के का पर दितीय प्रवाद विश्व यात है।

२:२१ करोड़ रुपये का ऋष् प्रदेशों को १६५४-५५ में दिया गया और केन्द्रीय सरकार के १६५५-५६ के बजट में १० करोड़ कार्य को व्यवस्था इसके लिये कर दी गई है। जिससे कि ऋषा की सहायता प्रदान की जा सके। मार्च १६५५ तक त्रिभित्र प्रदेशों में जो सफलता मिली है, उसका विवरस्य निम्नलिखित है।

	१९५४५५	<b>રદ્</b> ષપ્ર-પ્રદ્	योग
ग्रान्भ			
त्रासम	१००	२१०	₹१0
बिहार	३५	१५५	150
सम्बद्ध		•••	
मध्य प्रदेश		***	
मद्र(स	***	**	
उद्गीसा	***	***	
पजाब		***	
उत्तर भदेश	<b>₹</b> ¼.	<b>ড</b> হ	१३
पश्चिमी बंगाल	₹4,	२६७	३३२
पेप्सू	પૂર	२००	२५०
जम्मू और काश्मीर	N.	ર્યું.	E0
ग्रन्य भदेश	₹+	<b>e.3</b>	१००
सरकार के सी० डबलू० और पी०	***	२००	२००
ची भारत वर्षों भिद्रीला खाकल	≨A	१२३	१५७
विभाग इस्यादि			
कुंज	रुद्ध	१३६६	१६५०

भासाम-डिनस्गढ और पलासनाड़ी नगर रचा योजनायें पूर्ण हो तुकी है। सैलोबा, नवगांग, और सुवन्तिरी बिलों में बाद से रचा करने की योजना का कार्यं क्यारस्य किया शका ।

पश्चिमी बंगाल-अधिक महत्वशाली योजनार्ये जिन्हें श्रारम्भ किया गया, वे निम्न थी (१) जलपाईश्ररी नगर की रह्या, (२) वरनीज मेनागुरी रोमोडाल चेत्र।

विद्वार-मूरी गरडक नदी के बाँघ का ८०% कार्य समाप्त हो चुका है। भागवती बलान, खिरोही इत्यादि नदियों पर सुरज्ञा कार्य क्रारम्भ किया गया था।

उत्तर प्रदेश-- "गण्डक और गंगा नदी पर बाढ से रचा करने का कार्य जिससे बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों के लगमग ४०० गाँवों की रहा संगव

है. पुर्य किया गया।"

पंजाब — निम्म कार्य पूरे किये गये (१) ४३ मील लम्बा डेरा बाबा नानक से आकर मन्त्र तक रावी नदी के किनारे आधार बाँच का बनवाना; (२) देहली प्रदेश में बादूना नदी के किनारे जो पताबी दारार पाई गई थी उनकी बन्द कर-वाना और टकोला बाँच बनवाना; (३) कर्नोल जिले में बावेल से धानगीली तक जम्मना नदी के दाहिन किनारे बाढ़ रोकने के लिये बाँच बनवाना; और (४) अमुना नदी से तांग्रेवाला शीर्ष क्रम से नर्देच की आरे बाँच बनवाना; और (४) अमुना नदी से तांग्रेवाला शीर्ष क्रम से नर्देच की आरे बाँच बनवाना;

यह तो सर्व विदित है, कि बाद न तो सदा के लिये रोकी जा सकती है. श्रीर न रोक देना उचित हो है। इन बाढ़ों से बारीक मिटी वह कर श्राती है. जिससे पानी दृद जाने वाले लेशों की उपज वह जाती है। उन वर्षों में जब कि बाद ग्रसमान्य हो जाती है. उनमें बहत हानि पहेंचती है श्रीर जनता को कब्द पहेंचता है। बाह का प्राय: क्याना और उसके द्वारा हानि को कम करने के लिये बाटों के वनस्य पर नियमण रखना ज्यावस्थक है। उसके लिये समग्रह कार्य-इस बनाने की क्षावत्रयकता है। जिन खायों से प्राय: काम किया जाता है, वे निम्न हैं। (१) किनारे पर वाँध वाँधना (२) संग्रह जलाशय, विशेषकर सहायक धाराओं पर (३) अवरोधन गहा बनवाना नहीं पर बाद का पानी एकत्रित करके थोड़े समय के लिये रोका जा सके: (४) नदी की घारा को मोड़ देना जिससे कि एक नदी का पानी दसरी नदी में पहुँच जाय : (५) नदी का दाल बढ़ाना उसमें श्चारपार द्वार खुदवा का, (६) नदियों तक ले जाने वाली धाराश्चों को जिनमें मिट्टी मर गई है, खुद्धाना श्रीर उसकी मिट्टी निक्लवाना, (७) स्थानीय रचा के उपाय जैसे पक्की दीवार और ऊँचे टीले आदि बनवाना ताकि भूमि कटने न पार्वे, और (द) वन लगाना और स्थान-स्थान पर बहाव की दीवता रोकने के लिये गाँच गाँचना ।

स्विचाई और श्रांक मंत्रालय द्वारा कुछ दिन पूर्व हो बाहू रोकने के कार्य-कृम को रूरोका बनाई गई है। इनके तोन साग हैं। (क) तात्वालिक—इनके अन्तर्यात श्रन्थेराय योजना बनाना और क्षमय का अनुसान करना होगा। दीवार बनाना और वांच आदि सो विशेष स्थानों पर बनवाये जा सकते हैं; (य) अल्व-कालीन—इनके अन्तर्यात वांचे और नालों आदि का सुवार किया लायमा। इस मकार की रह्या के उपायों का प्रयोग उन चेवो में विशेष रूप से किया जायमा जहाँ बाहू अधिक आती हैं; (य) शीर्ष फालीन—इनके अन्तर्यात नदियों तथा उनकी सहायक घाराओं के जल स्वय्य का कार्य सिंचाई और विश्वत राक्ति उत्पादन योजनाओं के कार्य के साथ किया आयथा।

द्वितीय योजना में ६= करोड़ राये की व्यवस्था तत्कालीन ग्रीर

श्रालपकालीन योजनाश्चों के लिये की गई है। इसमें क्र करोड़ क्या परीह्यण तथा तरमञ्ज्ञ स्थाना सामग्री एकजित करने के लिये नियत किया गया है। यनों का लगाना श्रीर श्रीम सर्वे क्या के उपायों को कार्य में लाना, बाद नियवण के महत्वशाली उपाय हैं, इनको बाद नियंत्रण के कार्यक्रम में विशेष स्थान मिलना जाडिए।

केन्द्रीय बाद निरोधक मंडल ने जून १६५५ को अपनी पाँचमी सभा में १६ माद निर्मञ्ज योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें बाँघ वाँघना, नगरों की रहा के उपायों और गाँवों को स्थिति के स्तर को ऊँचा करगे के उपाय आदि समितित है। इनमें से प्रत्येक योजना पर १० लाख अपने से अधिक व्यव होगा, और ७५ का अपोक क्यने का अस्तुदान प्रावेधिक सरकारों को बाद रोकने के कार्य-क्रमों को कार्योग्वत करने के लिये दिया गया है। शेंब ने यह में सिफारिस की है कि प्रत्येक प्रदेश के बाद रोकने के कार्यों को प्रवेधीय बाद निरोधक विभाग के विभाग के निर्मण में कर देना आदिये। इससे कार्यों से समन्त्रय और उसकी गति में सीमता होगी।

आलोचना—बाद नियंत्रण की यह योजना जनता के प्राण सम्पत्ति और फरल की द्वानि को रोकने में अभी तफ सफल नहीं हो पार्ट है। इसका कारण सरकारी कार्यक्रम के दोप हैं। सुख्य दोप निम्न हैं। (१) अभी तक जो प्रयत्न सरकार द्वारा किये गये हैं. यह सर्वथा अपर्याप्त है। योजनाएँ बनाने तथा प्रशा-सन कार्य करने के श्रतिरिक्त कोई कार्य नहीं हो पाया है। जो व्यय नियत किया गया है, यह बहुत ही कम है। द्वितीय योजना में भी केवल ६० करोड़ इपये के क्यम की व्यवस्था की गई है, जब कि कम से कम इरका दुगना घन उपयुक्त होता । (२) जल विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान के श्रामान के कारण योजनार्ये दोवपूर्ण हो बन पाती हैं। प्रायः प्रयत्न विफल हो जाते हैं, और परिचाम प्रयत्न की तलना में करह भी नहीं डोता (३) बाटों को रोकने के लिये अभी तक तरवें वो पर अधिक निर्भर रहे हैं। बाद द्वारा लाई हुई मिझी तटबन्धों के किनारे जमा हो जाती है इससे तटबन्धों को ऊँचा करने की अथवा मिट्टी खदवाने की समस्या सदैव बनी रहती है। श्रीर यदि बाढ़ बहुत तीव हुई तो सटबन्धों के वह जाने का भी डर रहता है। श्रधिक अच्छा उपाय तो मूमि के संरक्षण का है, इससे बाद की तीनता कम हो जायगी। इससे एक और भी लाभ यह होगा कि बाद पीड़ित स्थानों की उपजाऊ भाम के वह जाने की समस्या भी सलक जायगी।

कठिनाइयाँ—िश्चार्र और विद्युत शक्ति उत्पादन योजनाओं को कार्याः स्वित करमें में निम्मलिखित अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा है।

- (१) दोगपूर्ण योजना जीर अञ्चल प्रवन्य के कारण वहुत सा धन श्रीर असाधन निकल हा गये। राव समिति में दामोदर पाटी कारणोरेशन के कार्य की परीज्ञा की श्रीर इस परिणाम पर पहुँची कि केवल कोनार बोजना के कुमबन्ध के कारण १ देश करोड़ चयथे की हानि हुई। सिनाई और विख्त सक्ति उत्पादन योजनायें जैसे बड़े कार्य में पन का पोड़ा बहुत नष्ट होना तो अवस्थमभावी था क्योंकि कर्मवारीमण अनुनवहीन थे, और देशी स्थित में भून होना स्वामाविक या परस्तु वास्तिक हानि श्रुतमाव के कही अधिक हुई इस्तिये प्रविष्य में इस हात का स्थान रखना पढ़ेगा कि जनता का पन स्थ्य न जाय।
- (२) "दिधरवनों और प्रधायनों के क्रय के सम्बन्ध में निदिचत नीति के आमान के कारण समय-समय पर विभिन्न प्रकार के यंत्रों का क्रय किया गया। । विचाई, शक्ति और योजना मंत्रालय द्वारा १९५६ में नियुक्त प्लान्ट और मधीनची कमेटी ने सिकारिया की है कि इस किनाई को तूर करने के लिए मुखर-मुख्य योजिक प्रधायकों को एक ही प्रमाप का होना चाहिए।

(१) श्रेपेक्षत योग्यता और सनद पात हंजीनियर और विरोपनों के श्रमाय के कारण भारत की नदी चाटी तथा श्रान्य पोलनाओं को बहुत वही कठिनाई का समता करना पढ़ता है। यह समस्या दो प्रकार की हैं, (क) विरोपनों का श्रमाव तथा (ख) जो व्यक्ति हामोदर चाटी तथा श्रम्य योजनाओं का कार्य कर रहे हैं, वे अपने भविष्य के बारे में सर्वक है कि हन योजनाओं का कार्य कर समात हो जायगा तब उनका क्या होगा। एक समय भारत सरकार श्रविल मगरतीय खिचाई तथा शक्ति विरोपनों का एक विरोप सेवा वर्ग बना रही थी, श्रमया हसके स्थान पर ऐसे कर्मनारियों का जो विभिन्न प्रदेशों से आये ये एक संवय (deputation pool) बनाने का विचार कर रही थी।

(४) िच चाई तथा शक्ति उत्पादन योजनाय मुझार-कर लगाने अपवा 'खिंचाई की दर बहुनि को बाध्य करती हैं। सुधार कर एवं विचाई की बढ़ी हुई दर 'के कारण कुछ प्रदेशों के कुषकों को अधिक मार बहन करना एका है। इकलिये यह आवस्यक है, कि इन करों के आरोपित करने के साथ ही खाय इस बात का मी ध्या-रखा नाथ कि कुपकों को कर खमना किन्नी है। यदि राज्य सरकार किंचाई की दर, सुधार-कर तथा शक्ति की दर (Power rate) निर्चय करते समय कुपकों की देय-इमता को भी ध्यान में रखें तो बढ़ा ही अच्छा हो।

#### च्याध्याम ११

## सामुदायिक विकास योजनाएँ

भारतीय अधको की निर्धनता श्रीर ग्राधिक शक्ति से विछाडे होने का प्रमख कारण है कि ये नई प्रशासियों खीर जीवन के नवीन उपायों के प्रति उदासीन हैं। उनके सम्मल जो जटिल समस्याएँ हैं उन्हें इल करने के लिए वे ससंगदित रूप मे प्रयक्त भी नहीं करते। सामदायिक विकास योजनात्र्यों के कार्य अभी ग्रीर राष्ट्रीय बिस्तार सेबाओं (National Extension Service) का उद्देश्य यह है कि उनके द्वारा "जनता के मानसिक हथ्दिकोंका में पारततन हो, उनमें जीवन के उचतर स्तर तक पहुंचने का महत्त्वाकांची और साथ ही साथ उस स्तर की प्राप्त करने के लिए इद निर्माय और इच्छाशक्ति उत्पन्न की जाय। ग्रामी मे निवास करने बाले ७ करोड परिवारों के हब्दिकोगा में परिवर्तन लाना, नवीन जान व जीवन के नवीन उपायों के प्रति उत्साह उत्पन्न करना और श्रेष्टतर जीवन व्यतीत करने के लिए उनके हृदय में ग्रामिलाया व हृद्ध इच्छा-शक्ति का संचार--यह बास्तथ में एक मानवीय समस्या है। १४ इस उद्देश्य के पूर्वा होने के लिए इस बात की ब्रावश्य-कता है कि विकास कार्य-क्रम प्रामीण जनता के उत्तर बलपर्वक न लादे जायें. धरन इस बात का प्रयास किया जाय कि उन लोगों में ही ब्रात्मावश्वास का उदय हो और वे नियोजन के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से दिन ले सकें। सामुदायिक विकास योजनायों के श्राधारभूत सिद्धान्त निस्त हैं :---

(अ) ''विकास कार्य के लिए प्रेरक-शिक स्वयं प्रामवास्यों से आर्या चाहिए। ग्रामों में विपुत्त शक्ति निष्क्रय रूप में विखरी पड़ी है निसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतपन हस बात की आदर्यकता है कि वह शक्ति कियात्मक कार्यों के लिए नियोजित को काय और प्रत्येक परिवार के सदस्य न केवल अपने दित के लिए कार्य करें यस्त् सासुदाधिक करूयाण के लिए भी समय है।'

समय दें।" (य) "सहकारिता के सिखान्त को विविध रूपों में लागू होना चाहिए,

विसंसे आग्य-जीवन की अनेक समस्याएँ इल की बा सकें।"

सामुदायिक विकास योजनाओं के तीन उद्देश्य हैं: (१) कृषि, बायवानी,
पशु-पालन, मछली-पालन आदि में नैशानिक विधियों को लागू करके और अस्य
पूरक पंत्री व कुटीर-उद्योगों को प्रारंभ करके वेरीवागारी दूर की जाय और उत्पादन

में बृद्धि की जाय (२) जनता के सहयोग से प्रत्येक बाम या कई बामों को मिलाकर कम से कम एक बहु उद्देश्योग सहकारी सत्या होनां चाहिए जिसमें कृषि करने वाले लगभग सभी परिवारों के प्रतिनिधि हो, (३) गाँव की सककी, तालाबो, पाट-पालाबों, स्वास्थ्य-केटों आदि सार्वकिक हित के निर्माय-कार्यों के लिए सुसंगठित प्रयास होना चाहिए। इसके श्राविशिक आसीण जनता में प्रगतिशील हम्टिकोण अस्व करता की भी शावश्यकता है।

यह सामरायिक विकास योजना २ श्रवतवर १६५२ को प्रारंभ की गई थी. जिसके अन्तर्भत ५५ केन्द्रों में सामदायिक विकास योजनाएँ प्रकाशित की गर्दे । इस बोजनाओं का कार्यचेत्र लगमग ३०,००० प्रामी तक विस्तत है जिनकी जनसंख्या लगभग १ करोड १८ लाख है। कालान्तर में श्रीर भी श्रधिक सामदा-विक विकास योजनाएँ चलाई गई और २ ऋक्तवर १९५३ की राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अन्तर्गत प्रसार-महलो (Extension Blocks) का भी समारंभ किया गया । इस प्रकार इस समय दो योजनाएँ साथ-साथ चल रही हैं. जिनमें से समय है सामदाविक विकास योजनाएँ और दितीय है राष्ट्रीय प्रसार सेवाएँ। पदा राष्ट्रीय प्रसार सेवाको के भी वही उहाँ हम हैं जो सामदायिक विकास योजनाकों के हैं। कृषि, पश्र-पालन, शिला, स्वास्थ्य आदि चेत्रों में दोनों के कार्य कमी में पर्याप्त समानता है। उनमें यदि कोई मेद है तो यही कि सामुदायिक विकास योजनाओ का कार्य-क्रम विस्तत है और इसके अन्तर्गत स्थानीय कार्यों पर पर्याप्त अन-राशि भी ब्यय की जायगी योजना में यह व्यवस्था की गई है कि जिन विकास-संबन्धों को प्रगति पर्याप्त रूप से संतोषजनक होगी और जहां जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा. उन्हें सामदायिक विकास योजना के शन्तर्गत ससंगठित के लिए सन लिया जायगर।

संगठन—समुदायिक विकास योजना की ज्यवस्था पंचायतो श्लीर इडी उद्देश्य के लिए निर्माण की गई क्षम्य उन्ह संस्थाओं द्वारा की जाती है। 'जनता श्लीर उन्हेश्य के लिए निर्माण की गई क्षम्य उन्ह संस्थाओं द्वारा की जाती है। 'जनता श्लीर उन्हेश प्रमेक प्रतिनिधियों से काफी विचार-विसम्यं करने के उपरान्त विकास कामंग्र-मा निधार का कार्य-मार पंचायत पर ही रहता है। नहीं विकास कामंग्र-मा का कार्य-मार पंचायत पर ही रहता है। नहीं विकास कामंग्र-मा श्रीर कामान नहीं है, वहीं यह प्रयान किया समाव नहीं है, वहीं यह प्रयान किया स्थाप है कि इन उन्हेश्य के लिए प्रामीण निकास सिम्दारी की स्थापना ही लाद, जिन्हें प्राम विकास संबल एंडल एंडल प्राम मंदल एंडल होना संव संव स्थापना ही लाद, जिन्हें प्राम विकास संबल एंडल एंडल होना संव संव संव स्थापना हो ताद, जिन्हें प्राम विकास संबल एंडल एंडल होना संव संव संव सारि कुछ भी नाम दिया जा सकता है। रन्हीं संस्था में द्वारा नियो-जन के कार्य-मम को कार्योग्वत करने के लिए जनता का स्थापन सहसी प्राप्त करने कार्य-मम को कार्योग्वत करने के लिए जनता का स्थापन स्थापना प्राप्त करने कार्य-मम को कार्योग्वत करने के लिए जनता का संस्थित सहसी प्राप्त करने कार्य-मम के कार्य-मम के कार्य-मम के कार्य-मा स्थापन स्थापना प्राप्त करने कार्य-मम के कार्य-मम के कार्य-मम के कार्य-मम के कार्य-मम के कार्य-मम्ब

होता है ! विकास-संदल के स्तर पर एक परामर्शेदात्री समिति की स्थापना की जाती है, जिसमें आम समितियों के प्रतिनिधि, विधान-परिषद, विधान-सभा व मंसद के सदस्य, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील कपक ब्राटि सम्म-लित होते हैं। यह परामर्शरात्री समिति ग्राम-संस्थात्रों द्वारा तैयार की गई योज-जाको पर विचार करती है। फिर इस प्रसम्बद्धानी समिति हारा विभीग की गर्द ग्रंडल की विकास गोजनाओं को जिला विकास समिति के दारा जिले की विकास-योजना के कार्य क्या में सम्मितित कर सिया जाता है। इस जिला विकास समिति में प्रमान भीर सरकारी क्यक्ति और जिले के शनेक टैकिनकल विभागों के सध्यत्त सक्रिम्मित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर विकास योजना तैयार करने और जनको कार्यान्वित करने के लिए सरकारी और गैंग्सरकारी संगठन साथ-साथ कार्य करते हैं। । इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अर्थमान जासन-सम्बन्धी सरकारी दाँचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जा रहा है कि वह जन-कल्यास के दायित्व का भी निवृद्धित सकें, जिसका परिसाम यह है कि सामान्य प्रशासनयंत्र से मिछ एक प्रथक जन-कल्याग विभाग स्थापित करने की ज्यावड्यकता महीं है। इसका तालयं यह है कि जिस प्रशासन-यंत्र (administrative machinery) की रचना । राजस्व-संग्रह (revenue collection) का निरीज्ञाय श्रीर नियम व व्यवस्था की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी. उसने परि-वर्तित होकर कल्यायाकारी शासन का रूप बहुया कर लिया है और सरकार के विकास-सम्बन्धी सभी विभागों के साधनों का जपयोग ग्राम-विकास की समस्यात्रों को इल करने के लिए किया जा रहा है।"

विकास-सम्बन्धी नीति के सामान्य सिद्धान्त निर्पारित करने के लिए प्रायेक राज्य में एक राज्य विवास समित (State Development Committee) की रदान हो गई है, जिससे मुख्य मंत्री और विकास-कार्य ने समब अनेक विभागों के अध्यक्ष समिता हो है। है विवास में सिरनर इस सिरनर के सम्बन्ध अनेक विभागों के अध्यक्ष समिता हो होते हैं। विवास के सिरनर के विकास के सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से यह सरकार के विकास के सम्बन्ध अनेक विभागों के अध्यक्ष और गिल्यों के दल का प्रधान मी होता है। जिले, तहसील और मंडल के स्तर पर ऐसा ही समन्यय स्थापित करने के लिए विवास स्थापित करने के समान ही कामाः कलक्टर और मंडल-विकास स्थित गरि ही। विवास सम्बन्ध स्थापित करने के समान ही कामाः कलक्टर और अस्वत करी के समान ही कामा-सेवक अन्ति का का प्रथान करी है सामान ही कामा-सेवक अन्ति का का प्रधान करने के सामान होता है और लिले के सामत का एक अन समक्ता आता है। और वह-उरेसीय कार्य करमें पढ़ते हैं। सासन के दाँचे को निर्माण करने का उद्देश्य द है कि

क्रिकारी क्रिक से प्रक्रिक कार्यचमता से काम करें श्रीर जनता से स्रक्रिकतर सहयोग जयलब्ध है ।

योजना के अन्तर्गत-राष्ट्रीय विस्तार और सामुदाधिक विकास योजनायें प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। कार्य की इकाई एक विकास मंडल है. जिसके अन्तर्गत लगभग १०० ग्राम झाते हैं, जिनकी जनसंख्या ३०,००० ते लगाकर ७०,००० तक होती है, ख्रीर उनका चेत्रकल १५० से १७० बर्गमील तक हो सकता है, १९५२ में जब से यह कार्यक्रम आरम्म हुआ है; समुद्राधिक विकास योजना के अस्तर्गत ३०० मंडल स्त्रीर राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के स्नान्तरात ६०० मंडल बना लिए गये हैं, जीर इस प्रकार १९५६ तक विस्तार मंडलों का योग १२०० हो गया है। इसके अन्तर्गत तालिका मं० १ के अनुसार १२३००० ग्राम और द करोड़ व्यक्ति आ जायेंगे।

तालिका नं ० ? विकास मंडल का कार्य जो प्रयम पंचवर्षीय योजना काल में चारम्भ किया गया

विकास मंडल का कार्य जो प्रयम पंचवर्षीय योजना काल में झारम्म किया गया					
		7 014	१९५४-५५	१९५५-५	जोड़
?85	१२-५३ १६	ध्३-५४	1640 H		
विश्वस महत्त					3,00
विश्वास मण्या सामुदायिक विकास	580	યાર	રયા્વ	३१६	003
राष्ट्रीय विस्तार	***	२५१	The Real Property lies and the least of the	385	\$500
जोड	२४७	308	२५३		
द्यास संख्या					इ२,६५७
सामुदायिक विकास	ર્પ્ય,રદ્દે ૪	७,६ <u>६</u> ३ २५,१००	२५,३००	₹2€00	E0,000
राष्ट्रीय विस्तार	***			₹€,€00	१,२२,६५७
चोड़		\$30.58	1411		
जनसंख्या (दस ला	ल मे)				20.8
सामुदायिक विका	e 88.	6	४.० E.S. १६.७	२६.	१ ५६.४
राष्ट्रीय विस्तार			961	74.	7.30 9
जोड़	१६	8 3	0.6 96.0	ळा करना '	ग्रीर <b>५१५</b> ४ प्राइ- ५००० वयस्की के
कियाम	तेत्र में १४०	oo नयेस् <del>व</del>	लाका आर	ज्ञा है. ३	५००० इयस्की के

विकास चेत्र में १४००० नये स्कूलो को झारम्म करना और ५१५४ प्राइ-मरी स्कूलों को वेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाना है, ३५००० वयस्क्रों के लिये गिज्ञा वेन्द्रों का स्यापित करना, जिनके द्वारा ७७,३०० वयस्क साझर किये

#### भारतीय ऋषेशास्त्र की समस्याएँ

٥ ء

राये हैं. तथा ४०६६ मील पत्रकी और २८००० मील कवी सहक का बनवाना श्रीर ८०,००० शीचालयों का गाँवों में निर्माण करवाना स्थानीय विकास के उदा-हरमा है। जिन्हा सामाजिक प्रमान बहुत ही महत्वशाली होगा। इस वार्य में बहुत ग्राधिक श्रेश तक सहायता जनता तथा विस्तार योजनाशों को कार्योत्नित कराने वाले सरकारी कर्मचारियां द्वारा प्राप्त हुई है, जिन्होंने पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। यदि प्राप्त उद्योगों तथा सहकारिता के चेत्र में सफलता कम प्राप्त हरें है. इसका कारण यदि सम्पूर्ण देश के हव्दिकांख से ही देखा जाय तो सहकारिता तथा नवीन उद्योगी की कार्य व्यवस्था का दोय है, जिसमें मधार करना चाहिए ।

"राष्ट्रीय विकास परिषट ने सितम्बर १६५५ में यह स्वीकार कर लिया था कि दितीय पंचवर्षीय योजना में समस्त देश राष्ट्राय विकास सेवा योजना के शास्त्रांत या जायमा स्रोर जा राष्ट्राय विस्तार मंडल सामदायिक विकास मंडली में परिवात कर दिये जायेंगे ज्यान जनकी सक्या ४०% में क्रम न होगी। यदि प्यांत्र वित्तीय सहायता प्राप्त हा सकेगी तो सम्भवतः यह संख्या ५०% भी हो लाग । वितीय जीवना य ३८०० नये विकास सेवल राष्ट्रीय विस्तार योजना के -कार्यक्रम के शहतर्गत शाहरम किये जाने वाले हैं शौर यह शाहार की जाती है कि इनमें से ११२० सामदायिक विदास ग्रहकों में परिणित कर दिये लागेंगे। योजना

के इस कार्य के लिए २०० करोड रुपयों का भी प्रवस्थ प्रवस्थ किया गया है।" 'सामदायिक योजना प्रशासन के निश्चित किए हुये कार्यक्रम के छनुसार दिलीय पंचवर्षीय योजना में, प्रत्येक वय, राष्ट्रीय विस्तार सहल तथा उनके साम-दायिक विकास महलों में परिकान किये जाने का कार्य किया आया करेगा।"

जैसा कि तालिका २०० में दिल या गया है। तालिका नं ० २

वर्ष	राष्ट्राय विस्तार सेवा	ख्या सामुदायिक विकास सहलों में परिवर्तन	
8E4E-40	400	र्प.	
<b>१</b> ९५७-५८	६५०	२००	
የድሄ <del>፡፡-ሄ</del> ደ	oxe	₹६०	
१६५६-६०	£00	३००	
१९६० ६१	\$000	३६०	
	₹⊏ee	8880	

द्वितंत्र पंचवपार बोजना के कार्यक्रम को कार्याल्य करने में ऐसा मतीत होता है, कि मत्येक बामीच परिवार में यह मानना उत्तम करनी होता कि अपने रतन-प्रत ने स्वर को प्रवारना तथा एक निरुचन कार्यक्रम का अपनुष्य करना होता है। कि राप्ट्रीय सिंद अपने सहयोग देना उनका कर्यक्य है। यह आरवा की वाती है, कि राप्ट्रीय विस्तार तथा वाष्ट्रस्तिक किन कार्यक्रम द्वारा और अस्य अपनुष्य कार्यक्रम द्वारा आपामी कुछ वर्षों में ही डींप उत्पांत में होते के अविरिक्त निम्न अस्य देशे में उन्नित होता (१) प्रवार्षिक कार्य में विस्तार होता। (१) अस्वार्षिक कार्य में विस्तार होता। (१) आमीत के कर में मान प्याची का विकास होता। (१) मूर्य की पंचकर ने करने होता करायों में किम अविराद्ध होते भी श्रीमतित करना होता किन कर में मान प्याची का विकास होता। (१) मूर्य की पंचकर ने कार्यक्रम के कार्यमित करना होता किन ने वीक्ष से किन करने होता करने कार्यक्रम के कार्यमित करना होता किन ने वीक्ष कर में साम की कार्यमित करना होता किन ने वीक्ष कर्म करने किन करने होता करने किन करने होता करने कि किन के लिये होत होता करने होता करने होता करने वाले सबदूर पर्व शिवरी इत्यादि (६) कियो शीर मयपुष्टी अपित के लिये होता कि किन होता कि विद्या आदिनों के विकास के लिये हित्त कार्यक्रम बनावे आपीं।

"देसे बहमसी कार्यक्रमों को कार्यात्वत करने के लिये जिसके अन्तर्गत उद्योग, सहकारिता, कृषि उत्पादन, भूमि सुघार, तथा सामाजिक सेवार्य छाती है. को चेप राष्ट्रीय विस्तार तथा शामदायिक विकास कार्यक्रमी को लाग करने के लिये चुने जायेंने, उनके श्रीम ही उन्नति करने की बहुत अधिक सम्मावना होगी। जब इन कार्य-कमी की संयोजित कप से बार्यान्यित किया जाता है. श्रीर स्थामीय संस्थाना का सहयान व्यवस्थित क्य से प्राप्त होता है, तो एक कार्य में सक्तुता दसरे में सहतता के लिए अवसर प्रदान करती हैं। और इस प्रकार समार्थ क्षेत्र में आधिक व्यवस्था हुद्ध हो जाती है। हिताय योजना के अन्तर्शत विकास कार्य-मस में कांव उत्पादन को सब प्रथम स्थान दिश समा है। उसके प्रश्नात प्राप्त की समसे अधिक महत्वशाली आवश्यकता कार्य करने के पर्याप्त अवसरों का प्रदान करना है। संत्रतित आस्य अधिक व्यवस्था में यह आवश्यक है, कि औरोशिक कार्यों के अवसरों की कांप कार्यों को अपेद्धा हद्धवर गति से वृद्धि की जाये। हाल के बाम तथा छोटे उद्योगों के विकास कार्य-कार्यों के सम्बन्ध में को खनभव हुआ है उससे यह संदेत मिलता है, कि ऐसी विस्तार सेवा की आवश्यकता है, जिसका सम्पर्क प्राभंश शिल्पकारों से हो और जा उन्हें आपश्यक पराप्रदर्शन कर सके. सहायता दे सके, अनकी सहकतिता के आधार पर व्यवस्था कर सके श्रीर अपने माल को जॉब में तथा बाहर क्षेत्रके में सहायता दे सके। इसका प्रारम्य २६ अप्रमाप्त्री योजनाओं को कार्यान्वित करके किया जा चुका है। यह आपस्यक है कि यथासम्भव शीव्र प्रत्येक विस्तार तथा सामुदायिक विकास च्रेत्र में एक प्रवीण प्रशिचित इन ग्राम उद्योगों के कार्यक्रम को चलाने के लिये नियुक्त किया जाय।

वित्त की रुपयस्था—इन विकास कार्य कम के लिए वित्त की व्यवस्था
धानुदाधिक योजना प्रशासन (Community Project Administration),
दाज्य सरकारों ग्रीर अनवा के द्वारा की जाती है। बीठ पीठ आर्थिक रूप से वित कम प्रकथ्य तो करता ही है, दसके प्रतिरिक्त उस पर विशेष सन्त्रों व तत्समन्त्री अन्य सामियों को अपलब्ध करने का भी द्वायित है। इस विकास कार्य-कम की कार्याध्यक्ष करने के लिए श्रतिरिक्त कर्मचारियों को रखने पर जितना व्यय होगा, उसका श्रामा पन शत्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त होगा केन्द्रीय सरकार यह प्रदास भी कर रही है कि योजना की खबांध स्थात होने तक सहस्थारी अगरहोलन और अन्य एजेन्यियों के द्वारा अरूपकारित, अतिस्तरकालीन और दीर्थकालीन खुण के रूप में कम्प्यः २०० करोड, और १६ करोड रुपये का चन प्रति वर्ष प्राप्त होने समे । सामुदायिक विकास योजना के कार्य-क्रम पर जी यान-राशि ध्यय होती है उसकी शत्यमा २०% भारतीय-अमरीकी देकनिकल सहयोग योजना द्वारा यन्त्रों और देकनिकल सरामर्या आदि के रूप में

सामुदायिक योजनाओं और विकास मंहलों के लिए १६५२-५६ ते लेकर १६५५-५६ तक कुल मिला कर ३२-६० करोड़ कार्य दन का वजद में स्वीकृत कुला है। इस प्रकार मान्य १६५५ तक प्रयम १८ मधीनों में ज्यय के लिए १६.३० करोड़ करवे निवारित में कि उत्तर हुआ है। इस प्रकार मान्य १६५३० करोड़ करवे निवारित में के उत्तर प्रवास ११। इसके अतिरिक्त इस आविष्ट में नकर भन अम्म आदि की दिन्छक सहायता के लग के क्यांचे में नकर भन, अम, सामग्री आदि की दिन्छक सहायता के लग के क्यांचे से योज ही करवा करवा का प्रमान काल की अनेक करिना और के कारल योजना की प्रयति सीमी रही, किन्द्र जब इस इस सम्प्र ए च्यान केन्द्रित करते हैं कि जून १६५५ तक क्या की कर्द पनराशि प्रवार कर करी के वार्य सामग्री आपित के साम की स्वार सीमी रही, किन्द्र जब इस इस सम्प्र ए च्यान केन्द्रित करते हैं कि जून १६५५ तक क्या की कर्द पनराशि प्रवार करने तक पहुँच गई, तो भविष्य में अधिक सीक प्रपति होने की समावना प्रकार होती है।

भीमी प्रमति के कारक्ष-वागुदायिक योजनाव्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कोर्ड काउन्डेशन के शहयोग से एक कार्य-मूल्यांकन संस्था (Programme Evaluation Organisation) की स्थापना को गई है। यामुदायिक योजनाव्यों को कार्यान्तित करने के मार्ग में निम्न कटिनाइयाँ हैं—

(१) प्रारम्भिक अवस्या में प्रगति के अवस्त्र होने का कारण यह था कि

जनता उदासीन यी श्रौर श्रन्य लोकप्रिय व्यक्तियों ने भी योजना के कार्य-कम में सिन्य रूप से भाग नहीं लिया। इस स्थित में किसी सीमा तक सुधार अवस्य हुआ है, किन्तु किर भी प्राम्वासियों का पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। प्रगति के चीमी ग्रीर श्रनिश्चित होने का यह एक प्रमुख कारए या ।

(२) पद्मायती श्रयंथा विशेष कर इसी उद्देश से स्थापित की गई श्रान्य लोक पिय संस्थात्रों से जो सहयोग प्राप्त हुआ है, वह अपर्याप्त है। पंचायतें समी क्षेत्रों में नहीं है और जहाँ है भी, वहाँ उनमें गुडबन्दी के कारण प्रायः स्वयं बलता रहता है। बहकारी संस्पार्य जपयोगी हो सकती हैं, किन्तु विकास योज-परामा परमा था अरुमार अरुमार अरुमार अरुमार हो है। उनके नियमों के नामों के समझ्य में उनकी उपयोगिता सीमित ही है। उनके नियमों के भूतुवार हासान्य रूप से सदस्य मी नहीं बनाए वा सकते, बचोंक उनका जुनाव किया जाता है। सहकारी संस्थाओं को रचना ही कुछ विशिष्ट प्रकार की होती है जिससे उनके कार्य सीमित होते हैं। विकास कार्य-कम की सहायता के लिए अनेक परामर्शरात्री संस्थाओं की स्थापना की गई है जिनके भिन्न-भिन्न नाम हैं ब्रीर तो कुशल अधिकारियों के निर्देशन में अन्तोपतनक कार्य कर रही है। किन्तु किर भी यह आशंका बनी हुई है कि जब सरकारी अधिकारी इटा लिए क्षायंगे, तो संमव है कि ये संस्थाएँ कार्य करना बन्द कर दें।

(३) घीमी प्रगांत के लिए उचित योजना का अभाव मी अधिक सीमा तक उत्तरायी है। विकास की प्रगति इचलिए योमी नहीं रही है कि आधरयक वित्त का स्रभाव था, वरन् उत्तका कारव यह था कि प्रारम्भिक अवस्था में अधि-कारियो-द्वारा बकट में कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं की गई। इंग्ले अति-रिक्त ग्रम्य कारण भी थे। बनट बहुत जल्दी में तथा ग्रस्सण्ट विचारी के साथ तैवार किए जाते थे तथा धनराशि को संबंधी देने के पूर्व विवास जानने में समय

(v) कार्य-कम की इस घीमी प्रगति श्रीर श्रनेक भूलों के लिए प्रशिचय-लगता था। प्राप्ति कर्मचारियों का अभाव बहुत बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है। किन्तु अब अपिक संख्या में कर्मचारियों को प्रशिवण देकर यह अपाल शोमता से दूर किया

४। पी॰ इँ॰ ग्रो॰ की तीसरी सफलतांकन रिपोर्ट (Evaluation Report), बारहा है। ने कार्य को समुचित रूप से चलाने के सम्बन्ध में अनेक प्रयागात्मक सुकाव दिये

र राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुरायिक विकास कार्य-कम को आशातुकूल सकत हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बनाने के लिये यह आवश्यक है कि (१) श्रीवांगिक विमागा को प्रत्येक दिशा में

श्रीर प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त मात्रा में इंड बनाया खाय । खनेक स्थानों पर प्रत्येक चेत्र तथा जिला सम्बंधी औद्योशिक विभागीय व्यवस्था की समता तथा संख्या में नधार करना जावश्यक हा गया है. (२) इसके अतिरिक्त जारवेपण के कार्य की सुविधाओं का विस्तार किया जाय, भूमि के आस-पास के सवैपाणामारी को विस्तत किया जाय श्रीर इस बात का विशेष स्तान दिया जाय कि खेतों से सब सचनार्ये गचेपग्रागो तक पट्च जाँय. (३) विभिन्न विषयों के विशेषशों पर क्षेत्र विकास कर्मचारी के (नयन्त्रका । जो आवश्यकता से अधिक हो सकता है) तथा जिली के श्रन्य प्राविधिक अधिकारियों के दूहरे नियम्बल की व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही है। (४) निर्माण कार्श ने ग्रामों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का जिनको कृषि समा कृषि विस्तार की प्रारम्भिक शिला मिली है और जिल्हा सबसे अधिक शावश्यक कर्तन्य कृषि उत्पादन बढाने का है, श्रविकांत्र समय ले लिया है. (५) प्राम पंचायतो को अपने वृद्धिमान उत्तरहायित्य को जो कि उनके उत्पर बाल दिया गया है पूर्ण करने के लिये सदैव पथ प्रदर्शन तथा नकिय सहायता मिलनी चाटिए: (६) कार्य-क्रम की कार्यान्वित करने में आवश्यकता से खिक महत्य भीतिक और व्याधिक एकलताओं पर दिया गया है. जैसे निश्चित किये हुये कार्य के, ब्यय श्रीर भवन निर्माण के ध्येवों की पूरा करना इत्यादि: श्रीर बनता को नये दण से कार्य करने की शिक्षा देने तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सभार और विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के पूर्ण करने के लिये. को राष्ट्रीय प्रादेशिक योजना के धन्तर्गत है, एक प्रभावशाली साधन बनाने की श्रीर कम ध्यान दिया ग्राया है।

कार्य करने में बुटि—अमुदायिक विकास योजनाशों ने प्रामीण जनता में शात्मियरवास उत्पन्न करने में बहुत कुछ थोग दिया है। उसने प्रामनिवासियों को इस बात का शामाण दिया है कि प्राम्य-बोबन में निश्चित रूप से कुछ गढ़-बड़ी है जिस्सा पारस्परिक सहयोग के आभार पर ही मुशार किया जा रकता है। अपनी इतना श्रापिक समय नहीं हुआ है कि इस सम्पन्न में किसी निर्मित्त निष्कर्ष पर पहुँचा आ सके, किर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि समुदायिक विकास योजना थों ने उत्पादन बहुतकर श्रीर बेरी-बागरी कम करके आयों में रहन सहस का स्तर कें बात है। किन्तु जिस कर में कार्य-प्रमा के कार्यान्य दिवस वार वह दे उसमें कई दोव हैं। किस के निर्मा वीनिदर प्रवादन-बुद्ध श्रीर क्षायों का सहस कर के आयों में रहन करने के प्रमुख्य का उपयोग करने के प्रमुख्य कार्य हों है। किस के मुम्लिक क्षाय कार्य होती है किन्तु मुसिद्धीन मान्द्री किस कार्य कार्य प्रमुख्य के अपने उत्पन्न करने किस कार्य मान्द्री के अपने उत्पन्न करने किस कार्य कार्य मान्द्री के अपने उत्पन्न करने किस कार्य कार्य मान्द्री की स्वस्त अपने कार्य करना श्री कार्य करना श्री के स्वस्त अपने स्वस्त भी कार महत्त्वपूर्ण नहीं है। बित समी विकास योजनाशों की बसाने की व्यवस्था भी कार महत्त्वपूर्ण नहीं है। बित समी विकास योजनाशों की बसाने की व्यवस्था भी कार महत्त्वपूर्ण नहीं है। बित समी विकास योजनाशों

के अन्तर्गत अस्थायी रूप से मजदरी देकर कार्य करने की आवश्यकता पहली है तभी इन्हें थोद्या बहुत कार्य मिलता है। इसके द्यतिरिक्त वे नि:सहाय. वेरोजगार श्रीर उपेद्यित-से रहते हैं, (२) यदि दूसरे हच्छिकोशा से देखा जाय तो सामदायिक विकास योजनाओं के कार्य क्रम में एक और टीच प्रकट होगा। वह यह है कि खेतिहर मजद्रों को पुरक कार्य उज्जन्य कराने के लिए ग्राम्य-उद्योगो की स्थापना करने पर विश्लेप ध्यान नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में पीत देंत श्रीत की यह धारणा है कि "मामील उलोग-धन्धों की श्रानिश्चित संमायना के पीछे चाहे जो भी कारण हो, किन्तु तथ्य तो यह है कि सामदाधिक विकास योजनाओं के वर्तमान स्वरूप और साधनों से अधिहीन सज़हरों की वेरोजगारों की समस्या हल करने की श्राशा नहीं की जा सकती? । जिल्ला पीता देव स्थोत का यह हरिएकीया सलत है। चिक सामदायिक विकास योजनाको का उत्तेष्ठय है कि उत्पादन कार्य श्रीर ग्रामीस जनता की आय में वृद्धि हो छोर बामवासियों में नई आशा का संचार किया जाय, इसलिए गैर खेतिहर वर्ग की बेरोजगारी? का समस्या को उपेक्षा की हरिट से देखना उचित नहीं है ऐसा करने पर सामदायिक विकास योजनाओं की उपयो-गिता बहुत कुछ कम हो जायगी. (३) सामदायिक विकास योजना के अन्तर्गत भूमि की समस्या को सुलकाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। चक्रवन्दी का कार्य एक अन्य सगठन द्वारा किया जा रहा है, किन्त इसने अभी अधिक एफलता नहीं प्राप्त की है। बम्बई, उत्तर-प्रदेश और सौराष्ट्र की छोड़कर सहकारी कृषि के चेत्र में अधिक प्रगांत नहीं हुई है और इन राज्यों मे भा यह आन्दोलन अपनी पार्राम्मक अवस्था में ही है। बहत से क्रवकों के पास कृषि के लिये इतनी कम भूमि है कि उस पर कृषि करना आधिक इप्रि से लाम-पूर्ण नहीं है। जब तक कृषि की इकाई के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि का चेत्रफल नहीं बढाया जाता और निम्नतम लागत से अधिकतम उत्पादन नहीं होगा, तथ तक किसान खेती की विकसित प्रणालियों का पुरा लाभ नहीं प्राप्त कर सबेंगे, श्रीर (४) सामुदायिक विकास योजना के कार्य-कम में श्रव तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसरे जन-संख्या की सब्दि पर नियत्रण रखा जाय श्रीर परिवार-श्रायोजन (Family Planning) का सचार प्रथन हो सके । जब तक यह कार्य नहीं हो जाता तत्र तक मारतीय शामोण जनता की जदिल समस्याओं को सन्दोपजनक रूप से इल करने की आशा करना रूपर्थ है। उत्पादन बहाकर और जन-संख्या की रृद्धि को नियंत्रित करके ही ग्रामन।।सर्यों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा किया जा सकता है।

#### ष्राघ्याय १२

#### सहकारी आन्दोलन

मारत में यहकारी श्रास्ट्रीलन का विकास ए॰ वी शताब्दी में हुआ। सह-कारिता का अर्थ है किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर प्रयास करना। समान उद्देश्य की स्थित से यह स्थकिंगत प्रयस्त और सहायता से किन्दुल मिल है। अन्तर्राष्ट्रीय अम संघ की परिमाण के अनुसार सहकारी सितित ऐके ब्यक्तिय की संस्या है जिनकी आधिक स्थित अन्छा नहीं है और नो समान अधिकार तथा उत्तर्दाथित के आधार पर स्वेन्छा-पूर्वक सगठित होकर अमनी ऐती समान आधिक आवस्यकताओं की पूर्वि का भार एक संस्या को श्रीव देते हैं जिनको वह अपने व्यक्तिगत प्रयक्षों के द्वारा पूर्णतः स्वन्धिक समित स्वाप्ति होते हैं। यह लोग आपस में मिलकर इस संस्था का प्रवन्ध करते हैं और समान भीतिक एवम् नैतिक लाम उताते हैं। इस मकार सहकारी समिति समान हितों का संघ है। यह समान अधिकार भाग्न स्वरूपकताओं की पूर्वि करता है और उनके समान हितों की एवा करता है।

सहनारी समितियाँ दो मकार की हैं—(१) रेफिजेन (Raiffeisen type) में र दो मकार की सह-भीर (२) शुल्ज बेलिस्न (Schulze Delitsch type)। इन दो मकार की सह-कारी समितियों में जिन व्यक्तियों का नाम सम्मिल्लित है यह जर्मनी में सहकार में आन्दोलन के मितियों में शिन व्यक्तियों का नाम समितियों में किया जाता है और दूसरे मकार की समितियों के शिक्षान्तों का उपयोग नगरों में किया जाता है । रेफिजेन-स्मितियों का कार्य खेल मान कर सीमित रहता है और इनके सदस्यों का उत्तरायिल अशीमित होता है। इन समितियों से केवल स्पर्यों को ही श्राय दिया जाता है और यह मी केवल उत्पादन के लिए। शुक्र-वेलिल समितियों का कार्य देन अधिक स्थापक है और इनके सदस्यों का उत्तरदिवल मी सीमित है। इस मकार की सीमित सदस्यों से प्रदेश शुक्क नयुल करती है और दिना आय बाला व्यक्ति इसका स्टब्स गरी बन सकता है।

वित्त, उत्पादन, वितरस्य इत्यादि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन सीमतियों को सगठित किया जा सक्षता है परन्तु भारत में ऋख देने वाली साल सिर्मातयों का ही प्रमुख है। बास्तव में भारत में सहकारी अग्नरोजन आरंभ करने का निष्चित उद्देश्य आमों में ऋषा की भवानक समस्या को हक करना और आमीचों को मुविपा अनक रीति से ऋषा देना था। भारत में बृत १६५६ में सब प्रकार की २,१६,२८५ सिर्मातयों को मुख्या में बृत १६५६ में २,४०,३६५ सहकारों सिर्मातयों थे। कृषि साल सिर्मातयों ही प्रमुख थीं। इनकी संख्या मुख सिर्मातयों के ६०६% तथा कृषि सिर्मातयों की ८०६% सी। आग्नरोजन अब भी सालस्यानत है।

विकास—भारत में सहकारी आन्दोलन के हतिहास की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण पटना १६०४ का सहकारी साल-समिति अधिनियम है। इस नियम के बनने
से पूर्व भी महास में सहकारिता के सिद्धान्तों का महत्वपूर्ण विकास हो। रहा था।
यहाँ साल-सितिसंग का कार्य 'निधियों' करती थां। देश में सहकारिता के विभिन्न
पत्ती का अध्ययन करने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम १६०१ में परक सिनित नियुक्त
को। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सताय कि जह तक सरकार अधिनियम
नहीं बनाती इस दिशा में विशेष मगति की संभावना नहीं है। इसी रिपोर्ट के
आधार पर सरकार ने सहकारी साल-सितिय अधिनियम पास किया। इसमें केवल
साल-सिनियों को क्यवस्था की गई थो। इस प्रकार अन्य देशों की अपेसा भारत
में सर्वप्रथम साल-सिनियों का है। विकास हुआ। नियम लागू होने के दश्चात्
यह अनुभव किया गया कि इसते उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। साल-सिन् तियों के पास माम में अधुस्त प्रथा समात करने के लिए आवश्यकत से बहुत कम

इस नियम के दोषों को बूर करने के लिए १६११ में तुसरा सहकारी स्मितं आपिनियम पास किया गया। इस नियम में कम-निवक्ष करने वाली खरण प्रकार की सहकारी समितियों का स्वाठन करने की स्वयस्था की गई। नगर और प्राम समितियों के ख्रेतर को मिटा दिया गया। सीमित उत्तरदायित्य और ख्रंसीमत उत्तर-दायित्व के ख्रेतर को मिटा दिया गया। सीमित उत्तरदायित्व की ख्रायार समितियों की ख्रंसिक कर से वर्गीकृत किया गया। नियम में यह निश्चित कर दिया गया कि जिन समितियों के सदस्य राजरूड सीनितियों हैं वह सीमित उत्तरदायित्व वाली समितियों होंगी और साल-समितियों तथा ऐसी अन्य समितियों होंगी। इस नियम स सहकारी ख्राम्दालन के विकास में सहायता मिली। उत्तरदान के विकास के लिए, पशु-बीग, दूध की पूर्वि और खाद इत्यादि अव के लिए नई मकार की सर्वात्व हैं स्वित्य की स्वार इत्यादि

मैक्लैगन समिति की रिवोर्ट क आधार पर सहकारी आन्दोलन के विकास

86

में एक और प्रयास किया गया । इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर १६१६ के स्वार क्रिपिन्यम (Reform Act) के द्वारा सहकारी आन्दोलन का कार्य राज्य-सरकारों को सीप दिया गया । राज्य सरकारों ने कुछ नर्यों तक इस दिशा में कोई महत्त्वपर्य प्रमति नहीं की पन्ना १९२५ में बनाई की सरकार ने अला से सहकारी

समिति अधिनियम नियम बनाया । इसके पश्चात अन्य राज्यों में भी आवश्यक

कानन हमारो गरे । सहकारिता ज्यान्टोलन के विकास का कल अन्यान रस बात से लग चकता है कि १९५१-५२ में समितियों की संख्या, सदस्या संख्या तथा कुल चालू पॅजी क्रमश: ११८५ लाख १३७:६२ लाख तया ३०६.३४ करोड २० थी । ११५५-५६ में यह बढ कर हमशः २.४० लाख. १७६'र लाख और ४६='दर करोड़ द० हो गई। विभिन्न प्रकार की समितियों के दृष्टिकीश से अन्य समितियों की अपेता काप साल समितियों में बढ़ि श्रविक हुई है। पिछले वर्षों की ही तरह साल समितियाँ ही श्राधक प्रधान रही और कुल चाल पंजी का ७५% वाल चेत्र में ही था। यह मानते हुए कि भारतीय परिवार के सदस्यों की ख्रीसत सख्या प है हम कड सकते है कि १६५५-५६ में दाद करोड़ व्यक्ति ग्रथवा जनसञ्जा के २३ प्रति-यात वयक्ति सहकारी छान्दोलन के सन्दर्क में छाये। १९५१-५२ में ६ क करोड व्यक्ति श्रथवा १६ प्रतिशत जन सक्या सम्पर्क में आई थी। इसीप्रकार (प्राइमरी) प्रायमिक समितियों, को आन्दोलन का शाधार प्रस्तुत करती है, द्वारा १९५१-५२ में दिया हुन्ना ६७ ६५ करोड़ ६० था। १६५५-५६ में यह राशि बहकर १४० ७८ करोड़ ६० हो गयो। दिये गये ऋण की इस वृद्धि से भी प्रगति का कुछ प्रतुमान लगाया जा सकता हैं। चिन्ता का विषय तो यह है कि बकाया ऋगों के प्रतिशत के रूप में कालातीत ऋगों में कुछ कमी अवश्य हुई है किन्तु उनका अञ्चपात अब भी बहत द्राधिक है।

प्रगति के इत सिंहत सर्वें ज्ञुल में हम इस निष्क्रंप पर पहुँचते हैं कि (क) सहकारिता से कनसंख्या का बन्त छोटा खशा लाभ उटा रहा है। (ख) जनसंख्या की बृद्धि के अनुकूल अनुपात में सहकारिता का विकास नहा हुआ है। (ग) यदारि गैर साल समितियों का स्था में दूब हुई है, किर भी साल समितियों का ही अपिक विकास हुआ है। इसलिये सहकारिता आन्दोलन को स्वापक बनाने के लिये वह आयस्यक है कि सहकारी समितियों में साल के अतिरिक्त अन्य पहो पर भी आवश्यक प्यान देना चादिये।

आधुनिक प्रश्नु स्था — यहकारी खान्दोलन न तो सारे देश में समान रूप से फैला है और न सभी बगह इसका सब्बन्न समान है। सहकारी खान्दोलन ने खरह 'क' के कुछ राज्यों में निशेष प्रमति की है परमु श्रन्य राज्यों में हसका उपयुक्त विकास नहीं हो पाया है। खरह 'ख' और पा' राज्यों में से कुछ में इस आरनेका का विस्कृत विकास नहीं हुआ। अपूर्ण 'देश में कुछ निशास नहीं हुआ। अपूर्ण 'देश में कुछ निशास नहीं हिंदी में कुछ निशास नहीं हुआ। अपूर्ण 'देश में कुछ निशास किरारी विद्या के अगमण 'द प्रतिशत उदस्य केनत नमई, भ्रद्रास और उत्तर प्रदेश में हैं वर्गक उत्तर प्रदेश, मदार, बम्बई, पिक्षमी बङ्गाल, पद्धान तथा हैदराबाद में कमशः ६१ तथा ६५ प्रतिशत हैं। परन्त देश में अहाँ जनसंस्था तथा होत्रफल में मारी अत्तर हैं सहकारी सितियों की प्रशास व्यवस्था कहीं। वान किराने को आंच करने के खिर क्षितियों की संक्ष्य उत्पक्त नहीं है। यह जानमा श्रावस्थक है कि इस सितियों के किराने प्रतिशत जमता लाम जड़ाती है। कुछ खराड 'ख' और 'भ' राज्यों में सहकारी सितियों का कार्य करने में प्रतिश्व के कार्य के प्रतिश्व के कार्य के प्रतिश्व के स्वत्य है। दिवर्ष के क्ष्य के सित्यों के स्वत्य है। कि सहकारी श्राव्यों का कार्य करने स्वत्य में में सहकारी सितियों का कार्य करने स्वत्य में में सहकारी सितियों के स्वत्य है। यह कार 'ख', 'म' और 'ख' राज्यों में उत्तकों कार्य कुणलता पर विशेष प्रशन्ति परा जाय। स्वत्य नित्य कार के स्वत्य नित्य कार विश्व कार करने सालव से खुंडाइति (Pyramid)

सङ्गठन—करकारी विमितियों का वज्रठन वास्तव में गुंबग्कृति (Pyramid) के समान है। इस वज्रठन का आवार वह मार्गम्भक सहकारी समितियों के हिंगन के वज्रठन का का व्यवस्था स्वाधित कर के किया कोई भी दस वर्षा कर का का समितियों के रिविद्या को आवेदन पन हे सकते हैं। विभाग के निरीस्तक द्वारा आवर्यक आव-पहनाल के प्रधात सितियों के समितियों के साल स्वाधित स्थापित करने की अनुमात दी जाती है। इन समितियों को चालू पूँकी, प्रवेश शुरूक, सरकारी श्रुण, वेन्द्रीय सितियों के पास राज्य के हो से स्रूण लेकर एकज्ञ की जाती हैं। इनमें से कुछ सितियों के पास स्थापों को सोक्कर दन सितियों के पास उत्तरी स्थाप सीतियों का साल उत्तरी स्थाप सीतियों का साल स्वाधित स्वाधित है और सार्थ कर सितियों को साल स्वाधित स्वाधित है और सार्थ क्षाया प्रकथन सितियें तथा आन-समा के क्षाय

में होती है।

हन प्रारंभिक समितियों के जपर केन्द्रीय समितियाँ और राज्यीय सहकारी समितियाँ होती हैं। प्रारंभिक समितियाँ के सहक के पेन्द्रीय समितियाँ बनतीं हैं और इम (केन्द्रीय) स्रामित्याँ कारहरूत से राज्यीय समितियाँ बनतीं हैं। प्रमुख आप्तीना को अकार परस्यर गूँगा हुआ है। यसपि केन्द्रीय सास-सितियों को अपनी पूँजी का अपिकांश माग दिवाने बैंड से ख़रूनकालीन म्हण के रूप में मात होता है किर मी इनकी और अदेशीय समितियों की व्यवस्था तथा वित्त की आर्यस्थकता की पूर्व हिला है। प्रारंभिक सीतियों की स्ववस्था तथा वित्त की आर्यस्थकता की पूर्व हिला है। से सास होने सास सित्यों को ही तरह होते हैं। प्रदेशे केनदीय समितियों को दिलाई बैंड से मास होने सति अवस्थालीन ग्रग्य की अर्था है। स्वित्यों को सित्यों को सित्यों की स्वत्यों अर्थ के सास होने सति अवस्थालीन ग्रग्य की अर्था है। सहीने सी परस्तु अप इसे बदाकर १५ महीने कर दिया गंथा है। अर्था के

धन पर ब्याज की दर खेट रूपया प्रतिशत है। यह दर बैद्ध के ब्यास की दर से दो प्रतिशत क्या है।

सहकारी समितियों के शंहाकृति की व्यवस्था में शीर्य पर सहकारी सन्न नाम की अखिल भारतीय संस्था है। इस संस्था का प्रथम सम्मेलन फरवरी ११५२

में बम्बई में हळाथा। साख-सिश्तियाँ-प्रारम्भिक कपि साल समितियों की सल्या जो वि चहकारी ऋग व्यवस्था का मुलाधार है, जुन १९५५-५६ में १३ लाख थी और

उनका सहस्यों की संख्या ७०० स्वाल भी। नालिका संव 3 पारिकार करि कार्य क्रिकारों का कारी

		~	,	
	१६५१-५२	<b>१</b> ९५२-५३	१६५३-५४	१६५४-५५
समिवियों की संख्या	१,०७,६२५	१,११,६२⊏	१,२६,१५४	2,42,220
सदस्यों की संख्या	४७,७६,⊏१६	पूर,२६,००२	थद,४ <b>२,३</b> ८०	६५,६५,४१६
		n 244		

( अब बैंक और भूमिवंधक बैंकों को सोटकर )

सदस्यों की संख्या	४७,७६,८१६ ५	१,२६,००२	<u>೩८,४೭,₹८०</u>	६४,६४,४१६
वर्षे के ब्रान्तर्गत	(करोड़ र	पथे में)		
दिये हुए ऋष् की				
घन राशि	58,50	૨૫.૬૬	48 38	₹ <b>%</b> '%¤

वर्ष के भीतर

ऋशामें बसन की २⊏'8 धनगणि 58.58 25.56 28°%⊏ वर्षके श्रन्त से बसल होने वाला ऋग 78.88 33.88 39.65 85,4

बर्धके अस्त में शेष ऋण 68.08 \$9.05 2840 E'4 ?

सिजी कीप २३'६' 2 to " E to १६ २७ રશપાપ 4.30 जभाधन 8.8.5 845 A.85 अपूर्णभेक्षियाहळाघन २३ १५५ 33.4. 38°8E 35.58 चाल पॅजी 84.55 48.88 85.81 X5 . 1E

प्रारम्भिक साल समितियाँ ब्राधिक दृष्टि से निर्वल है ब्रीर इस कार क्रयक को उतना लाभ नहीं पहुँचा पातीं जितना कि चाहिये। टालिका 🕬 से इस कह सकते हैं कि महण्य के घन में जिल्लर बृद्धि दी हो रही है। ऋसासाम, मोपाल, विहार, जम्मू और काश्मीर, विन्यवपदेश और संस्थारत में बहुत अधिक

कृषि साख समितियों की वित्त व्यवस्था दोगपूर्ण है। १९५३-५४ के स्प्रन्त धन वस्त होने के लिये शेष रह गया था। कृषि साल समितियों की पूँची का खाँचा दोषमूर्य है। निजी सम्पत्ति तमा जमा भन का कम असुपात कृषि-वाख स्वितियों की आर्थिक दुवैसता का कारण है।

कृषि साख समितियों का अभित आकार भी छोटा ही है। १९५५-५६ में ग्रीवत चहरवों की चंक्या प्रति चर्मित ४६ थी ग्रीर श्रवि-क्षीय सितित्वा अवसायिक इकार्यों की ड्रॉप्ट से अनायिक ही थीं। प्रति सिपति श्रीसत जमाधन, शेवर पूंजी, और चालू पूंची क्रमशः ४४१ व०, १०५१ व० श्रीर प्रश्य रु की प्रति स्टब्स जमायन, श्रेयर वृंजी स्त्रीर दिया हुस्रा श्रूष क्रमशः

ह द०, २२ द० और ६४ द० था। यह श्रीसत आँवह कम ही हैं।

इसी विसीय दुवैलता के कारण अभितियाँ कृषकों को सुनिधा पूर्वक कम ब्याज पर ऋष देने के उद्देश्य की पूर्ति में असमर्थ है। वर्षात ऋष दे सकने में ग्रहमर्थ रोने के कारण ही वे छपको से ब्याज की ग्राधिक दर वस्ता करती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश, विलय प्रदेश और हिमांचल प्रदेश में होता है, वहाँ व्याज की दर ह से समाकर १९३% तक है। "ऊँची ब्याज टर के प्रचलन के कुछ कारची में बहुकारी अन्दोलन या अववीत विस्तार, ठीक दिशा में वर्णात जना एकत्रित करने में सहकारी सिमितियों की अवस्ताता तथा कुछ राय्यों में केन्द्रीय वेंक और

र्वात का अपानक महारा २। १९५५-५६ में १०,००६ तीरकृषि, वाल समितियों यी जिनकी सरस्य संख्या वैकिस युनियन को अन्धिक प्रकृति है।" ३०६ लास और बाल पूँजी प्युक्तिरोड २० थी। यह बेतन भोगियों, मिल के कर्मचारियों की समितियों तथा शहरी बैंक ये जिनका काम वहीं श्रव्छा था क्योंकि इनकी पाल पूँची में बमा घन का प्रतिनिधित्व था जो ५२ है करोड़ द० था। इन सिमितियों हारा उचार दिये गरे ऋण की मात्रा ७२ करोड द० थी। हुछ संमित्यों गैर शाख २ काम भी करती थीं तथा उनके द्वारा खरोदे श्रीर वेचे माल की मात्रा का गृल्य क्रमशः २ ४२ करोड़ द० श्रीर २ ७२ करोड़ द० था। यह समिन तियाँ मुख्यतः बागई जीर महास में थी इन समितियों के ५५% सदस्य इन्हीं दो राज्यों में ये तथा उपार दिये धन का ६३% भी इन्हीं राज्यों के अन्दर या।

गैर-साल समितियाँ —कृषि सम्बन्धी तथा कृषि से श्रमम्बन्धित गैर साल समितियाँ प्रत्येक स्तर पर प्रासम्मक केन्द्रीय तथा राज्यीय पाई जाती हैं। १९५५ थ६ में ३०,२६८ कृषि गैर बाल (प्रारम्भिक) समितियाँ थी लिनके सदस्यों की संख्या २४ लाल थी इनकी चालू पूँजी २'द लाल य० थी तथा इनके द्वारा बेचे गये माल का मूह्य ३ लाल य० या। १९५५-५६ में गैर-इपीय, गैर-साल प्रारम्भिक समितियों जैसे उपमोक्ता भएडार, विद्यार्थी भएडार केन्टीन ख्यारि संख्या में २७,७४१ भी तथा इनकी सदस्य सख्या ३३% लाल खोर चालू पूँजी ५'द लाल य० थी तथा इन्होंने ५१ लाल २० के मूह्य का सामान चेचा। इनके अतिरिक्त ६२ राज्याय मैर साल समितियाँ थी विज्ञान सदस्य संख्या २९,०६४ तथा चालू पूँजी ६२,०४१ व० भी और इन्होंने ११ लाल २० के मूह्य का सामान बेचा। २७६४ केन्द्रीय गैर साल समितियाँ थी। इनकी सदस्य संख्या २९ लाल तथा चालू पूँजी २ लाल व० से कम थी तथा इन्होंने ५% २० का सामान बेचा।

ससस्याएँ—भारत में आधिकतर एडकारी समितियों का संगठन मायः
पक्त ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। मतुष्य की विभिन्न माँगी का
परस्यर समाग्य होता है ज्ञोर वह एक दूवरे पर निर्मंद भी रहती है हसलिये उपकी
विभिन्न विदेश आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक समितियों की अभेद्या एक ही
समिति अधिक उन्तोपकानक पीति से कर सकती है। विशेषकों का विचार है कि
प्रामीण समस्याओं को बहुमुकों समितियों के ब्राय कुश्वलता और अधिक क्यत के
साथ हक किया जा एकता है। अनेक समितियों की उचित व्यवस्था करने के
लाए योग्य कर्मवारियों का अभाव होने के कारण तथा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केयल महाजन से सहायता खेने के आही प्रामीयों की
विभिन्न समितियों से सम्बन्ध रखने की अनिक्का के कारण भी बहु उद्देश्यीय
समितियों की आवश्यकता अतीत होता है। हक साथ ही सख को पूर्ति और
विकार तथा गैर साख की अन्य किनाओं से पुर्क करके एक उद्देश्यीय सहकारी कृषि
साख-समिति का सस्य उद्देश्य एखाँ नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय नियोजन समिति की रिगेर्ट प्रकाशित होने के परचाद मारत में श्रीर विशेषकर उत्तर प्रदेश, आसाम श्रीर विशाद में बहु उद्देशिय चिमितियाँ स्था- चित्र करने की श्रीर निश्चित प्रयास किया गया है। १९४० में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तिकास योजना दियार की थी तिकसे यह व्यवस्था की गई थी कि १२ से ११ प्रामी की मिलाकर एक विकास-तेत्र बनाया जाय श्रीर प्रदेक प्राम में एक- एक वहु उद्देशिय खोकित चया सम्पूर्ण चेत्र में इस स्थान प्रतिकत्ता नाय। इन ध्यो का प्रकास के प्रतिकत्ता नाय। इन ध्यो का आहता श्रह प्रतिकत्ता नाय। इन ध्यो के अल्पा १९४८ न १ १८४६ में प्रयास किया। यह श्रावस्थक है कि श्रन्य राज्यों में भी बहु उद्देशिय खोनितियाँ श्राध्यक संख्ता में

स्थापित की जार्से परन्तु इसका उद्देश्य छभी कुषि खाख-छमितियों की इंटाना न दोकर उनके क्रयूरे कार्यक्रेत्र की पूर्ति करना होना चाहिए ।

धाल धमितियों का अधीमित उत्तरदायित होने के कारण एहकारी आप्दो-लन की धन्तोपजनक प्रमान नहीं हो पाई है जैसा कि बंगाज प्रदेशीय अधिकोषण जींच समिति ने कहा है "कि गाँचों में ऐसे भी न्यक्ति हैं जिनकी आर्थिक तथा सामासिक हिपति हतनी अन्छी है कि चे इन समितियों के सदस्य मनकर अधीमित उत्तरदायिक का जोखिम उठाजा पशन्त नहीं करने हैं।" अधीमित उत्तरदायिक तभी सकता है जब जनता की क्यांति समान हो और यह साह्य भी हो। इसित्य बत्तेमान समय में आन्दोलन का और तीमता से प्रसार करने के शिष्ट सदस्यों का उत्तरदायिक सोमित रखने की योजना लाग करना आयरएक हैं।

को समितियाँ स्थापित की वा जुकी हैं और जिनको क्यमी स्थापित करना है उनका कार्य सुरुपरिषत रीति से चलाने और उनका विकास करने के लिए (द्रेनिंग प्राप्त) प्रशिक्षित कर्मचारियों की खाबर्यकता है। कुछ हो राज्यों के पाव शिक्षप-केन्द्र हैं। पूना सहकारी कालेक में अन्य राज्यों के कर्मचारियों को भी शिक्षा दें। जाती है। वर्तमान समग्र कर्मचारियों की समुचित शिक्षा की उपयुक्त खुचिया नहीं है, इस्तिल्य यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शिक्षप-केन्द्र स्थापित किया लाय।

मारत को सहकारी समितियों को सबसे यही कठिनाई वित्त की है। हमकी वित्तीय रिश्ति सहुत गाजुक है। विचीय सहायता देने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को हिंद में हन समितियों का विशेष महत्व नहीं है। इसित्य रिजर्व में के के सुमाव के श्वसुतार पढ़ समितियों का विशेष महत्व नहीं है। इसित्य दे सहित्य है जह यह सुराहित को में श्वसिक पन रखने की अवस्था करें। जब तक हन समितियों का सुराहित कोय शेष पर एवं नी के बराधर नहीं हो जाता तक तक लामांस का कम से कम एक तिहाई माग प्रतिवर्ष मुराहित कोप में जमा कर देना चाहिए। इसके परचार लामांस का केवल रूप प्रतिवात मुश्तिय कोप में जमा कर देना चाहिए। इसके परचार लामांस का केवल स्थापना कर तक लेवल की मामों में अपकोष स्थापना का स्वता है। प्रामी में सपल के साधनों का उपयोग करने के लिये प्रामीखों में श्विक श्रीपए स्थमाय, का विकास करना चाहिए।

सहकारी आन्दोलन वास्तव में जनता द्वारा प्रेरित आन्दोलन नहीं है। इसका प्रारम्भ बाहर ते हुआ। इसी कारण जनता में इसके प्रति उत्साह का अभाव है। राक्ष सरकार को अपना कार्य-वेत्र इन कमितियों में प्रयम्परार्थन, निर्रोक्षण तथा थोड़ा नियंत्रण स्कों तक ही सीमित रखना चाहिए। राज्य को साक्षरता का प्रसार करना चाहिये और समाचार पत्रों, रेबियो तथा अन्य साधनों द्वारा सदकारिता के लामों का जनता में प्रचार करना चाहिए। सहकारी तथा निजी संस्थाओं में श्रेप्रतर समन्वय की ब्यावस्थकता है।

इन समस्याओं के साथ ही साथ तथा उपमोक्ता समितियों की कुछ विशेष समस्याएं भी हैं, साख समितियों के सामने अत्यधिक कलातीत ऋषों की समस्या भी है। १९५५-५६ में पारम्मिक कृषि साख समितियों के कलातीत ऋषों को धनराशि १४९६ करोड़ स्पया थी जो जून १९५६ के अन्त तक देव ऋषों का रूप प्रतिचात मी। यह सिंपत मुख्यतः उन चेत्रों में है जो पिछड़े हुए चेत्र कहे साते हैं। इसका सामान्य कारणा पन्तपात और अध्याचार है।

कुछ राज्यों में, सुख्यतः हिमांचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, सहकारी समितियों की क्याज की दर 2 से १२३ प्रतिगत तक है। यह दरें बहुत ऋषिक हैं। इस दरों की भी अन्य राज्यों की दरों के समान करने की आवश्यकता है।

नियम्बर्ण की समाप्ति के उपरान्त बैश-कृषि वैर-साल समितियाँ बहुत किताइयों का सामना कर रही हैं और व्यक्तिगत व्यापारी की तुलना में कार्य संवालन व्यय अधिक होने के कारण कुछ समितियों तो बन्द भी है। कुकी हैं। कार्य-वालन व्यय कम करने के लिए इन समितियों के कार्य चेत्र में बृद्धि करने तथा इनको और अधिक कार्य-कुराल बनाने की खाबरयकता है। यदि योक विश्ली के स्टोर स्थापित किए लायं और अनकी पूँबी तथा सुरक्षित कोए में वृद्धि की जाय तो इनकी दिश्वित सवर सकती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कास्तर्गत—विभिन्न प्रदेशों के उदकारी विभाग के मन्त्रियों की सभा ने जो कि १९५% में हुई थी यह मुक्तार दिया कि "१९ वर्ष के झादर गाँवों में ब्यायार की उपवस्था सहकारिया के झायार पर हर प्रकार को हो जानी चाहिये कि साख विकाय तथा विषायन इत्यादि की उपवस्था दिवारों के द्वारा हो को है। इस के लिये प्रार्थ में एक श्री सहकारी बातियों के द्वारा होने लगे। इस के लिये प्रारंभिक कृषि शास स्मार्थियों के स्वदासों की संस्था दितीय पंचवर्षीय योजना के झात तक ५० साख से बढ़ाकर १५० लाख कर देनी चाहिये और अल्पालानीन मूरण की राश्चि ३० करोड़ स्पये से बढ़ाकर १५० करोड़ स्पये तथा द्वारा प्रश्च को राश्च १० करोड़ स्पये से बढ़ाकर १५० करोड़ स्पये तथा द्वार्यालान ऋण की राश्च १० करोड़ स्पये से बढ़ाकर १५० करोड़ स्पये तथा द्वार्यालान ऋण की राश्च १० करोड़ स्पये से बढ़ाकर १५० करोड़ स्पये तथा द्वार्यालान ऋण की राश्च १ करोड़ स्पये से बढ़ाकर २५ करोड़ स्पये कर देनी चाहिये। १०

उपर्युक्त सुकाव के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्तृत योजना की रूपरेखा बनाई गई है। भारत सरकार के कृषि तथा अन्य विभाग ने इस सम्बन्ध में कानृत बनाकर तैयार कर रक्की हैं जिनकी सहायता से फेन्द्रीय और

सहकारी ग्रान्दोलन प्रदेशीय गोदामों की व्यवस्था सम्भव हो सकेगी। इन नोदामों का स्थान भी सोच

भारत में सहकारी आन्दोलन का मिल्प्य बहुत उन्जवल है क्योंकि सह-

कारी राष्ट्र का संगठन करना हमारा घोषित उद्देश्य है। भारत की पिछड़ी हुई लिया गया है। अपिक स्थिति के अनेक दोषों को सहकारिता के आधार पर संसुक्त प्रथल करने

से तूर किया जा सकता है। सहकारी आन्दोलन के कार्यचेत्र का विकास करते के लिये वहु उद्देश्यीय चहकारी समितियों की स्थापना वर आधिक महस्य देने की श्चावश्यकता है। वेजी-निर्माण तथा प्रामीण जीवन के सुवार के लिये सहकारी स्तितियो पर योजना आयोग ने जोर दिया है। इपि के अर्थ प्रवन्त्रन के साधन के

हर में भी सहकारी श्रान्दोलन पर भरोसा किया गया है।

# अध्याय १३

## सहकारी विकय

उत्पादन स्वतः लक्ष्य नहीं है। जो कुछ वस्त उत्पादित की जाती है मा जो कुछ उत्पादन किया जाता है अन्ततः उसे उपभोका के पात पहुँचना चाहिएँ। उत्पादक से उपभोका कर करते पहुँचने की वाधन बाजार होता हैं। इसके लिये कई स्थितमें पार करनी पक्ती हैं और इस्में अनेक समस्याद उत्पन्न हो जाती हैं। समें उत्पादित वस्तु के साथ एक था न्यवहार नहीं किया जा यकता क्यों कि प्रस्ते के प्रस्तु के साथ एक था न्यवहार नहीं किया जा यकता क्यों कि प्रस्तु कारते वस्तु के साथ एक था न्यवहार नहीं किया जा यकता क्यों कि प्रस्तु कारते तथा शोज नष्ट होने वाली होती हैं और छोटे-छोटे उत्पादक वित्तुत चुन सी तथा शोज नष्ट होने वाली होती हैं अते कहे वस्तुर्प हरको, बीफ न होने वाली और सस्ता होती हैं। इनका उत्पादन बहुत कम लोग करते हैं। इनकहा स्वाधी और सस्ता होती हैं। इनका करते पक्ते हैं। उनको एक स्थान में एक प्रस्ता की शिक्ष के लिये विभिन्न काम करते पक्ते हैं। उनको एक स्थान में एक मिन्न की लिये विभिन्न काम करते पक्ते हैं। उनको एक स्थान में एक मिन्न की लिये विभन्न काम करते पक्ते हैं। उनको एक स्थान में एक प्रसायों करण किया जाता है, यातायात की व्यवस्था की जाती है, इनका कमनत्यन और प्रमायोंकरण किया जाता है और विक्रय के लिये वालचीत बलाई जाती है, हरसार इस मनार विकाद व्यवस्था के लिये विशेषजों और कुशल व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

कुराल बिक्रय की आवश्यक बार्ते — विक्रय व्यवस्था उत्तर तभी कहना सकता है जब उत्पादक को उत्पादित क्या का श्राधिकतम मुख्य मिल सके, वन्ता के राजने हत्यादि में निम्नतम व्यव करना पढ़े और उपभोक्ता को दिये हुये मृहय के बदलें में उच्ति प्रकार का लागान मिले।

यदि वस्तुष्ठों का कम बन्धन श्रीर प्रमाणीकरण किया गया हो हो उत्पादक को दर्गोत्तम मूहप मिल तकता है। श्राधिकतम लाभ उठाने के लिये यह श्रावर्षक है कि उत्पादक गया तमय उचित स्थान पर उसे बेचे। इसके लिये उत्पादक को वित्त सम्बन्धी तथा नाजार की परिस्थितियों का जान होना चाहिये।

विकय को दृष्टि से सामान को बरवने (handling) की लागत न्यूनवम करने की दृष्टि से सचार तथा परिवहन के सापन सस्ते और अच्छे होने चाहिये। दलालों की सख्या को न्यूनसम कर दिया आय क्योंकि दलालों के बहुने से लागत तथा परिखामत: मूह्य मी बहु खाता है। इसके साथ ही बस्तु को नष्ट होने से हैसियत सं १,८२,५७३ ६० का तथा आभिकतों की हैसियत सं १,१०५ ६० का भागान बेचा। उत्पादन तथा विकय (वैर कुपीय) समितियों की संख्या १९,५४२ तथा सदस्य संख्या ६२३ कास्त्र भी। इन्होंने २२६, ६२१ ६० का सामान मालिक को हैसियत से और ८०४८ ६० का सामान अभिकर्ता (एजेंट) की हैसियत से खेवा।

शीय मंस्थार्थे—मारत में शहकारी किमत-व्यवस्था का सबसे वक्षा तीय शीय संस्थार्थे का अभाव रहा है। १८५५-५६ में १८ राज्योर विकर्य संव थे । इसमी व्याप-सरस्या की संस्था ४०६४ तथा सिप्ति वसस्यता की स्वया १५६४ तथा सिप्ति वसस्यता की स्वया १५६४ क का सामान आमिकतों की हैतियत से तथा १९६४ क का सामान आमिकतों की हैतियत से तथा ११५६ की में १, तक्षा मानवें, उन्हों सा, तक्षा की स्वया १६६ संबी में १, तक्षा में १, तक्षा मानवें, उन्हों सा, तक्षा की स्वया १६६ संबी में १, तक्षा मानवें, उन्हों सा, काम आपकतर राज्यों में केन्द्रीय विकर्य संव थे १८१५-५६ में ऐसे संबी की संवया आपकतर राज्यों में केन्द्रीय विकर्य संव थे १८१५-५६ में ऐसे संबी की संवया मा आपकतर राज्यों में केन्द्रीय विकर्य संव थे १८१५-५६ में ऐसे संबी की संवया मा आपकतर राज्यों में केन्द्रीय विकर्य संव थे १८१५ स्वर्य संव संबंध १६ तास क का सामान अपकर्ता की हैवियत संवया ।) इनमें से २१५३ उत्तर प्रदेश में १, तथा क्षा संवत्त की हैवियत संवया ।) इनमें से २१५३ उत्तर प्रदेश में १, तथा क्षा संवत्त की संवत्त कर संवत्त के का संवत्त केन्द्री संवत्त संवत्त कर संवत्त केन्द्री संवत्त केन्द्री संवत्त संवत्त कर संवत्त केन्द्री संवत्त संवत्त कर संवत्त कर संवत्त केन्द्री संवत्त संवत्त कर संवत्त केन्द्री संवत्त संवत्त कर संवत्त कर

विभिन्न राज्यों में शीर्ष संस्थार्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। "वान्यके की राज्यीय सहकारों समिति करा, सन्जी, नियमित परायं, कांगि, कृषि की आवश्यकता की यस्तुर तथा व्यायनित आदि की नियमित परायं, कांगि, कृषि की आवश्यकता की यस्तुर तथा व्यायनित आदि की स्थापार करती है। वह राज्य में सन्कर्फेट अमोनिया की याद एक बुलेटिन निकतली है । समिति ने विकार आतम्सीय भी चल्ला रखी है तथा मित्र माद एक बुलेटिन निकतली है । समिति की प्रमालत भाव दिये जाते हैं। मैत्र की प्राम्तीय सहकारी विकार समिति साद, शहर, चन्यन को लक्की का सामान तथा अन्य अनेक सामान सरीरों और वेचने का काम करती है। उद्योगों तथा यन की छोटी-मोटी उत्पायों के प्रकारी वक्तम समिति कुटी र उद्योगों तथा यन की छोटी-मोटी उत्पायों के क्रिक का कार्य करती है।

इन शीपं संस्थाओं में सबसे बड़ी और सुसगठित उत्तर प्रदेश ही विक्र. सस्या अर्थात् सदकारी विकास तथा विक्रय संब हैं। उत्तर प्रदेश की इस शीर्ष संस्था ने विशेष उन्नति की है, पर हुमाँख वश इसका कार्ष ऐसी यस्तुओं मे एम्बिन्स रहा है जिनकी यहाना कृषि उत्पांत में नहीं की आ एकती। इसके कारण कृपकों को आशानुरूप लाम नहीं पहुंच सका है। इन संस्थाओं द्वारा जो कार्य किये गये हैं उत्पांत अपके होता, साद तथा कृषि सम्बन्धी महीन और श्रीवार का वितरण, शिकोदावार में भी परीच्छा तथा कमक्यन के केन्द्र का संचालन कुषी गृहियों का विक्रय तथा विकास, विचायकां की लाख फैरटी को आर्मिक सहायता पहुँचाना, तथा वम्बई में एक कुटीर उचीमों की उत्पत्ति के प्रवर्धन गृह का संचालम श्रीहि हैं। सावच्य में संच के कार्यक्रम में इस बात का प्रवत्न है कि (क) उनसे उत्पार के बीओ को अपने कोष में सचिव करे और आगामी है वर्ष के अपने सावच्य में संच के कार्यक्रम में इस बात का प्रवत्न है कि (क) उनसे उत्पत्त प्रवास में इस बात का प्रवत्न है कि (क) उनसे उत्पत्त प्रवास में इस कार प्रवास में स्वयं के अपने कोष में सचिव करे और आगामी है वर्ष के अपने सावचा के प्रवत्न स्वयं की अपने कोष में स्वयं के विवास पर विशेष स्वयं के अपने उत्पत्त के अपने कोष में स्वयं के विवास पर विशेष स्वयं के अपने उत्पत्त के प्रवत्न स्वयं के विवास पर विशेष स्वयं के अपने उत्पत्त के विवास पर विशेष स्वयं के अपने कोष के विवास पर विशेष स्वयं के अपने के स्वयं के विवास पर विशेष स्वयं के स्वयं पर विशेष स्वयं के स्वयं के विवास पर विशेष स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं पर विशेष स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं पर विशेष स्वयं के स्वयं

शीर्ष संस्थाओं की कार्य प्रचाली की सीन विशेषताएँ हैं (१) इनकी यदस्या सहकारी समितियों तक ही सीमित नहीं है। राज्यीय संयों ने व्यक्ति यदस्यों की सप्या कुल यदस्यों की एक तिहार्य है और केनद्रीय संयों ने क्यक्ति यदस्यों की संस्था समितियों की त्यस्य संस्था की छः शुनी है। व्यक्ति वदस्यों का बाहुत्य इक्त अविश्वात उत्तरक करता है; (२) परिश्व हिस्या पूँची और इन संयों का निजी कोय मिलाकर बालू पूँची का एक बहुत छोटा अश्च है। इससे भी इनके कार्य में आध्यत्ता आसी है; (३) इन सस्थाओं का और विशेषकर केन्नीय सर्वों का प्रकार क्या बहुत आधिक है। तहकारी विक्रय को प्रमावपूर्यी मितक्ययों बनाने के लिये इन रीयों का स्थार आवश्यक है।

प्रारम्भिक स्वितिद्याँ— कृषि उत्तरिक का क्रय-विक्रय करने के लिए मार्गम्भक कृषीय ग्रैर-खाल तथा ग्रैर-कृषीय ग्रैर खाल खांमितवाँ हैं। परन्तु इनका मत्येक राज्य में समान रूप से विकास महीं हुआ है। जहाँ तक कृषि उत्तरिक श्रीर विकास का सम्बद्ध है हिश्द , पिक्योस वागल, महान और खान्न खानामी में तथा सालाम, उत्तरीत को ति प्रारम्भ के स्वाप अपना माला सामितवाँ एक भिन्न विश्व खोनत करती है। खासाम, वम्बई, महास और मध्य-प्रदेश में कर-विक्य समितियों से खान्नामामें थे। जब कि पिक्चिरी बंगाल, वम्बई, महास, खान्न और महास आहान और विवास सामितवाँ से जनामामें थे। किया सामितवाँ में अपनामी थे। भैर- कृषि ग्रीर-साल समितियों में उत्तर प्रदेश, दिमांचल प्रदेश और कुम मीनिवारी से उत्तर प्रदेश, दिमांचल प्रदेश और कुम मीनिवारी से उत्तर प्रदेश, दिमांचल प्रदेश और कुम मीनिवारी से उत्तर प्रदेश, दिमांचल प्रदेश और कुम की रिपारी विद्यारी दे हैं।

ये समितियाँ या. तो उत्पादको से माल खरीद कर विकय करती हैं, या उत्पादकों में एजेन्ट के रूप में कार्य करती हैं जिससे दलालों की संख्या पर जाती है। कहीं कहीं पर ये समितियाँ कारखाने तथा हुकानें चलाती हैं और हुए प्रकार माल का उत्पादन तथा विक्रय करती हैं। ये उन उत्पादकों को म्हणू तथा म्राम्य ग्रुवियां में प्रतार करती हैं जिनते वे माल खरीवरी हैं। उनका कार्य चेत्र माल विक्रय करने तक ही सीमित नहीं हैं वरन वे उत्पादकों में सिक्रय कर से सहाय तिक्रय करने तक ही सीमित नहीं हैं वरन वे उत्पादकों में सिक्रय कर से सहायता देती हैं। ये विमित्तर्य कामों केवल एक यहत का ही क्रय-विक्रय करती हैं और कभी अनेकों का। वहुउदेशीय सिमितियाँ, जिनका दिन मितियति स्विक्रय करा हों हो जा वहा है, अपने विभिन्न कार्यों के साथ ही साथ हिए उत्पत्ति तथा अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय का भी कार्य करती हैं। यह कहा जा सकता है कि बहुउदेशीय सिमितियाँ अपने सदस्यों को लगभग सभी हार्य करा जा सरका है कि बहुउदेशीय सिमितियाँ अपने सदस्यों के लगभग सभी कार्य कर हो हैं। ये सिमितियाँ हुनि उद्योग्त के आधिक ने निक्रय कार्य कर रही हैं और अधिकांशर राज्यों में वर्तमान हैं।

चमते अधिक महत्वशाली एकोइंशीय ठहकारी विक्री समितियाँ उत्तर परेरा श्रीर हिहार में गन्ने की, वन्तर् में कई और फलो की, मेसूर में हलायची और नारियल की और कुर्ग में हलायची, शहर और नार्रीगयों की हैं। ये चिमितियाँ निम्न कार्य करनी हैं।

- (१) यह समितियाँ अपने सदस्यों से कृषि सामग्री और कुटीर उद्योगों में उत्पादित माल तोकर उनका क्रमबन्धन और प्रमायीकरण करती हैं और विकय के लिए अपने सहकारी संघी को वे देती हैं।
- (२) यह मितियाँ उत्पादित साल के महते अपने सहत्यों को भूग्य देती हैं परन्तु पन का अभाव और गोदामों की उचित व्यवस्था न होने के कारण हस कार्य में सीमितियों को अनेक कठिनाहर्यों का सामगा करना पहना है।
- (१) मामान बेचने के लिए यह छिमितियाँ उत्पादकों के एजेल्टों का भी कार्य करती हैं। उत्तर प्रदेश और विहार की गम्ना-सिमितियाँ केवल यही कार्य करती हैं। गत छुळु वर्षों में ग्रानाज व्युली के लिए कुछु छिमितियों ने सरकार के एजेल्टों के रूप में कार्य किया।
- (४) उत्पादन और विकय समितियों का यह कार्य है कि झच्छे प्रकार के माल का उत्पादन करें। झन्य समितियाँ अपने सदस्यों को झच्छे माल का उत्पादन करने में सहायता देवी हैं।
- (५) मद्रस्य की कुछ समितियों ने विक्रय के साथ ही श्रुरण तथा श्रन्य युविधाएँ देने की भी व्यवस्था कर रखी है। कुपि साख समितियाँ इस सर्त पर

- उदस्य कृषक को मुख्य प्रकार की फसर्ले उगाने को ऋष् देती हैं कि फसल रैयार हो जाने पर वही उसका विकय करेंगी।

(६) स्कूल तथा पुस्तकालय चला कर तथा अस्पताल और सङ्कीं का निर्माण करके यह समितियाँ समाज सेना का कार्य भी करतीं हैं।

साम (Advantages)—सहकारी विकय समितियों ने कृषि विकय-

(क) इनसे दलालों की संख्या कम हो गई है। दलालों की लम्बी शृङ्कला में से पच्चा झादृतिया, पक्का झादृतिया झीर थोक न्यापारी प्राय: समाप्त हो गये हैं। यह सामितवाँ उत्पादकों से स्वयं माल क्रय कर सीचे उपमोक्ताओं को बेच रेती हैं। इस रीति में किंक्स क्यबस्था के ज्यय में कबी होसी है किंक्स उतनी नहीं कई जितनी होनी चार्किय सी।

ुद गंजिमा शाल जा। व जा।

(ख) यह छितिवर्ग छोटे उत्पादकों को विचीय सद्दायदा देती हैं और विशेष-प्रमाद हैती हैं और विशेष-प्रमाद हैती हैं और विशेष-प्रमाद हैती रहा है जिससे यह छोटे ब्यापारियों के घोखे से बच जाते हैं। उत्पादित माल के किसर तथा उसकी देख माल में होने वाली समय और प्रांक्ति की बरवादी भी बच जाती है। इन समितियों ने छुटीर उचीगों के माल को छुशालता पूर्वक और स्टर्स मूल्य में बेचने का प्रवस्य करके उचीग के लिए बहुत स्टर्श किया है।

(ग) उनमोकाओं को भी इन समितियों से बहुत लाम होता है। उन्हें इनके अच्छे प्रकार का माल भिल लाशा है क्योंकि समितियाँ उनका अंकत रीति संक्रम क्यम तथा परीच्या करती हैं। इसके साथ दी यह समितियाँ अच्छा सामान तैयार करने तथा मिलाबट रोकने में बह साथक बन लाती है। इस दिसा में पी और दथ की बहजारी समितियों ने काफी सरकला प्राप्त की है।

प्रारंभिक कृषि कर विकास स्वितियों तथा उत्पादन और विकास स्वितियाँ स्वीप इनका कार्य स्वेतियाँ स्वीप इनका कार्य स्वेतियाँ स्वीप इनका कार्य स्वेतियाँ स्वाप इनका कार्य स्वेतियाँ के किया कार्य स्वेतियाँ के तरह इन दोनों प्रकार की सिमित है, किर भी अर्थिक कार्य करती हैं। सीर्थ संस्थाओं के तरह इन दोनों प्रकार की सिमितयों की, परिस्तर हिस्सा पूँजी साल्युवाँ का एक विहाई ही है और प्रकार कर्या भी बहुत अर्थिक है। इसके कार्या इनका कार्य आर्थिय है। युक्त काल ने विशेष परिस्तर के उपस्थित हो जाने पर इन समितियों को पत वर्षों में लाभ भी हुआ था, पर परिस्थित वहल जाने से और कार्य कम हो जाने से प्रारंभिक कृषि और गैर कुर्प येर खास समितयों होनों को हानि उठानी पढ़ी। मार्थिय में इन समितियों के कार्य श्रासालों में परिस्थान करना पड़ेगा साकि ये लाभवद सिंह हो सकें।

अविष्य—चहकारी विकय गैर-शास सहकारी समितियों में सबसे महत्त्वपूर्ण है। उत्तर कहा जा जुका है कि सहकारी साख को तरह हनकी शुड़ाकृति है। "यह दोंचा खूया समितियों की भाँति न सुनिमित्र हो है और न एक दूसरे से सम्बंग्यत हो है। संस्था की मलेक हकाई खपने-अपने स्थान पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तीने की हकाहयों का माय: उत्तर की इकाहयों को कोई विशेष सहान्यता मी नहीं देती। उदाहरण स्वरूप गंची की हकाहयों को कोई विशेष सहान्यता मी नहीं देती। उदाहरण स्वरूप साव्या संस्थार्थ मीचे की हकाहयों की मातिमित्रि खपवा आहां त्यां के तो हकाहयों की सहान्यता मी नहीं देती। उदाहरण स्वरूप पांची संस्थार्थ मीचे की सकाहयों की सहान्यता मी नहीं हमा प्रमाणिक एक स्वर्ण अपाणिक एक स्वर्ण का साव्यापिक एक स्वर्ण का तरह कार्य करते हैं हैं । र यदि इनकी ओर उदिव स्थान दिया गाना तो हम कह कहते हैं कि हमारे देश में सहकारी विकय किमीयों का मिक्य बहुत उपज्ञवल है। हमारे देश में सहकारों कर दिन्त सीमीत्रों को स्थापना होने से सहकारों कर दिन्त सीमीत्रों को सेरीए सहस्व के कार्य करने हैं कि इसारे देश में सहकारों कर दिन्त सीमीत्रों को सेरीए सहस्व के कार्य करने होंगा। ए उसमें कुछ कित्रवाहर्यों हैं जिल्हें दूर करना होगा।

(२) भारत में विकार सहकारी सांमितयों को प्रायः घन के क्रभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनकी हिस्सा पूँची बहुत कम होती है। उदाहरखार्थ उड़ीमा और हिमाचल प्रदेश को शीर्थ विकार सहकारी समितियों की हिस्सा पूँची कमरा: १४,०६० और १३,४६० व्यया है। यह पूँची बहुत छोटे पैमाने पर विकार करने के लिए भी कम है। इन समिवियों को अपना कार्य सुवाह रूप से वलाने के लिए दीर्पकालीन और अल्पकालीन एंडी की आवश्यकता है। यदि यह सिवियों अपनी हिस्सा पुंधी में दृष्टि कर ले वो दीर्पकालीन पुंधी मात्र हो सकती है। मदीनी तथा अल्प प्रकार के सामान कर करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्योंक औद्योगित विद्यास निगमों से दीर्पकालीन पूंधी की सहायता लेनी चाहिए। जिन राज्यों में औद्योगित विद्यास निगम नहीं है वहां इनकी स्थापना की जानी चाहिए। इनके साथ ही भारत में लाइसेन्स मात्र गोदामों (Warehouses) का विकास करने की आवश्यकता है जिससे यह समित्यों इन गोदासों में कमा किये गये अपने सामान के बदले में भारतीय रिजर्प बैंक कानून की बारा १७ (४) (प) के अपने सामान के बदले में भारतीय रिजर्प बैंक कानून की बारा १७ (४) (प) के अपने सामान के बदले में भारतीय रिजर्प बैंक को नात है कि बकाई, मदापरेय, महार, मैस्टर और श्वांकुर-कोचीन की सरकारों द्वारा आवश्यक कानून बना किये लाने के पश्चार भी भारत में कहीं ऐसे लाइसेन्स मात्र गोदामों की व्यवस्था नहीं की गई है।

- (३) जो विनय स्वामित्याँ इस समय प्रचलित है उनमे शिचित, हैमानदार श्रीर श्रद्धमंत्री कमंजारियों का स्थापा है, इन स्वामित्यों में स्वप्तदारी का स्वप्तावर है। इससे सार्व में इस क्षेत्र कार्य में इस क्षेत्र कार्य में इस को स्वप्तावर के स्वामित्यों में स्वप्त के हिंचा रूप से संचारिया को निवास करना चाहिए जिससे सानास्यक स्वीमित का स्वप्त का स
- (४) दिनय करने वाली वहवारी विभितियों को गोदामी की उचित दुविषा प्राप्त नहीं है। बहुत वो कांमतियों के अपने गोदाम नहीं हैं और उन्हें बहुत अधिक किराये पर गोदाम लोने पहते हैं। श्रीम नप्ट हो जाने वाले सामानों को रावते के लिए दिमातियों के नाव कोई साधन नहीं हैं। राज्य वरकारों की गोदाम बनाने में हन विभित्तयों की अदावता करनी चाहिए और गोदाम निर्माण के कुले जाय ५० प्रतिकात स्वयं देना चाहिए। इस कार्य के लिए बहकारी यह निर्माण स्वमित्तयों से भी सूरण का प्रवच्य करना चाहिए। यदि बोदामी की स्थापना से सर्मात्रयों से भी सूरण का प्रवच्य करना चाहिए। यदि बोदामी की स्थापना से सर्मात्रयों को सामान रखने को कठिनाहयाँ बहुत कम हो वार्यों।
- (५) झनेक राखी में राज्य के माहर देश के श्रम्य भागों में बेचने के लिए. शीर्ष संस्थायें नहीं है। यदि कहीं ऐसी संस्थायें कार्य करती है तो वह कैयल विक्रय

समिति संघ के रूप में कार्य नहीं करती बल्कि विक्रय समितियों के अतिरिक्त अन्य लोग भी दसके सदस्य बन सकते हैं। जन्य लोगों को भी सदस्य बनाने के कारण विरोधी हितो का संबर्ध आरम्ब हो जाता है जिससे यह समितियाँ सरसता मे

कार्य नहीं कर सकती है और इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पटला है। इसलिए जिन राज्यों में अभाव है वहाँ इस प्रकार की सर्वोच्च समिनियों का निर्माण करना आवश्यक है। वहाँ तक संभव हो सके इन समितियों को संघ-समिति के रूप में संगतित करना चाहिए। ऐसी वस्त्रशां के विकास के लिए जिनका उत्पादन एक राज्य में होता है और उपमोग दसरे राज्य में किया जाता

है अन्तर्राख्यीय क्रय-विक्रय समितियों का संगठन करना ज्यायज्यक है।

(६) बर्तमान समय में इस समितियों के दित सर्राज्ञत नहीं हैं क्योंकि न्यापारी संशों में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है जिसकी वजह से एक समान कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनके दोषों की संगठित क्या में दर किया का सकता है। इस स्थापारी संघों में इसका अखित प्रतिविधित्य होता द्यावश्यक है।

यह उचित ही कहा गया है कि कम से कम न्यय पर उत्पादकों की छाधिक से अधिक मेचा करने की समता पर ही हन विकय समितियों की सफलता निर्माट करती है। यह पुन: विधायन क्रियाओं, गोदामों की सुविधा, विचीय सहायता श्रीर समसे श्रामिक समितियों के ईमानदार, योग्य श्रीर कुशक कर्मचारियों पर निर्भर करता है। ये ही बातें हैं जिनका सहकारी विकय समितियों में आभाव है।

### श्रध्याय १४

## सहकारी कृपि

उत्तम कृषि करने का उद्देश्य कम से कम न्यय पर श्रिषकतम उत्पादन करना है। उसके लिये यह आनव्यक है कि कृषि के श्रामुनिक उनायों की सहा यता से कृषि सं-वाधनों का श्रमुक्तम उपयोग किया जाय। कृषकों के पास बहुत कम भूमि होने श्रीर उसके क्षोटे-श्रोटे मार्गो में विमक्त होने के कारण भारत में प्रति एक इत्यादन की मात्रा कम है। उत्यादन में क्सी के अन्य कारण उचित कार की लाद का श्रमाय, यदिया प्रकार के बीज, सिंचाई की उपयुक्त सुविचा का श्रमाव तथा माचीन उपयों से कृषि करना है। पति एकक भूमि की उत्यादन सात्रा में दृद्धि करने के लिये कार्स में कृषि के उपायों में नुवार करना श्रास्थक है।

फृषि प्रसालियाँ - कृषि की कम से कम पाँच प्रसालियाँ हैं-

304 ने प्रांतिकात कृषि क्वकरवा— यदि कोई व्यक्ति खनेते खनी हो भूमि पर या किराये की भूमि पर अपने ही छाजनों से कृषि करता है तो उसे व्यक्तिगत कृषि भूमि पर आपने ही छाजनों से कृषि करता है तो उसे व्यक्तिगत कृषि भूमि कहा जाता है। कृषक किता कियी बाहरी हरतक्षेण के अपनी हम्झा-द्वारा कम्पूर्ण कार्य का छंचालन करता है। भारत में इस कृषि प्रयाली का ही आपिक प्रचलन है। हम्में कुछ छन्देह नहीं कि व्यक्ति के साधन बहुत शीमित होते हैं इस्तिय वह इन सीमित छाजनों द्वारा कृषि चेत्र में विशेष क्रकता मान नशी-कर सकता। हस प्रकार की प्रचाली का प्रचलन होते हुये कृषि के आधुनिक उपानों का प्रयोग कर सकता। बहुत करिन है और यहे पैमाने पर कृषि करने का लाम उठा सकता तो अधानमा है।

(१) निगम-कृषि (Corporate farming) — इस प्रणाली के इन्त-गाँव इस कार्य संचालन के लिये एक निगम व्यवस्था या ज्याहरूट स्टाफ कम्पनी स्थापित की जाती है। इसके सभी सदस्यों का जारदासिय्य शिता होता है। सामांश्व को कुल पूँजी के अंशों या शैयरों के आचार पर दिमाजित किया जाता है और इनकी व्यवस्था संचालक मरूबल करता है। इस प्रकार की कार्य के लिये बहुत अधिक मूर्ति और काफी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। यह प्रपा अधिकतर अमेरिका में प्रचलित है। आतत में बच्चई, मद्राम तथा में इस प्रपास के कृषि की जाती है। इस प्रणायी से यही लाभ होते हैं जो वड़े पैमाने पर कृषि करने से सम्भव हैं। सृमि और धन के अमान के कारबा यह मखाली भारत के लिये उपशक्त नहीं है।

- (३) सामृहिक कृषि व्यवस्था-सामृहिक कृषि व्यवस्था में कृषि साधनों पर अनेक व्यक्तियों के एक समह का अधिकार होता है । वे संयक्त होकर कृषि की व्यवस्था करते हैं और कपि के सामृहिक रूप से अधिकारी भी होते हैं। सामु-हिक कृषि के तीन रूप हैं:- (अ) कृषि के सावनों पर पूरे समृह का अधिकार ही परन्त कृषि न्यक्तिगत रूप में की आती हो, (व) सामुहिक कृषि के साथ ही रहने श्रीर खाने पीने का भी सामहिक रूप से प्रवन्ध हो, और (स) भीन पर पर्शतया समाज का श्रायकार हो और कपि का कार्य संयक्त प्रबन्धक मंडल चलाता हो। इस प्रणाली से शतेब लाग है परस्त यह जसतन्त्र के अपयक्त नहीं है।
- (४) राजकीय कृषि व्यवस्था—इस व्यवस्था के अनुसार कार्म पर राज्य का ग्राधिकार होता है और वही उसकी व्यवस्था करता है। इस प्रकार के कार्मों में वेतन भोगा कर्मचारियों द्वारा कृषि कराई जाती है। उत्तर प्रदेश तथा अन्य राख्यों में कछ राजकीय कार्य है जिनमें खोज कार्य किया जाता है और मशीनों के द्वारा कृषि की जाती है। जहाँ नई भूमि कृषि के योग्य बनाई गई है वहां भी कुछ राजकीय फार्य स्थापित किये गये हैं। इस फार्यों की मुख्यत: इपि की नई प्रचालियों तथा मशीनों के उपभोग का प्रदर्शन करने के कार्य में लाया जा सकता है।

(५) सहकारी कृषि व्यवस्था--आई० सी० ए० आर० (१९४९) की सलाहकार परिषद के स्मृति पत्र के अनुसार सहकारी कृषि समिति एक ऐसी सिमिति है जिसमें प्रत्येक कृषक को अपनी भूमि पर पूर्ण अधिकार होता है परन्तु कृषि संयक्त रूप से की जानी है। सहकारी कृषि की मुख्य विसेपपाएँ हैं । (अ) भूमि के विभिन्न भागों को सम्मिश्रित कर एक इकाई का रूप दे दिया जाता है. (व) प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमि पर पूर्ण अधिकार होता है, (स) भूमि का भवन्य संयुक्त रूप से चलाया जाता है, (द) सदस्यों को उनके कार्य का पारिश्रमिक दिया जाता है श्रीर (य) कुल लाभाँश में से सुरक्षित कोप का श्रंश निकाल लेने के पश्चात शेल सदस्यों में विमाजित कर दिया जाता है। सहकारी क्रांप स्ववस्था फिलिस्तीन में बहुत लोकांत्रय है परन्तु भारत में श्रमी इस श्रोर प्रयोग किये जा रहे हैं । सहकारी कृषि समितियों को विभिन्न रूपों में सरकारी सहायता दी जाती है । इन समितियों पर कर कम लगाया जाता है, बीज अब करने के लिये ऋण दिया जाता है, रियायती मूल्य पर खाद तथा कृषि के श्रन्य श्रीजार दिये जाते हैं स्रीर बिना लाभाँश में भाग लिये हिस्सा पुँजी में सरकार अपनी ओर से कछ रुपया देती है। दिरसा-पूँ जी में को कपबा दिया जाता है उसका भुगतान ब्याज सहित किश्तों में किया जा सकता है।

## सहकारी कृषि के प्रकार सहकारी कृषि के निम्नलिक्ति चार प्रकार है—

- (1) सहकारी संयुक्त कृषि—इस प्रकार की समितियाँ अपने सदस्यों की छोटी मोटी भूमि को एक बटी इकाई में परिशाद करती हैं परन्त प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर पूर्ण अधिकार होता है। समितियाँ नाई भूमि कम कर सकत है या पट्टे में से सकती हैं, जैला कि वम्बई को सहकारी को समिति ने सुम्तरा है, परन्त यह बास्तव में सहकारी संयुक्त कुषि-अवस्था और सहकारी सामित के सुम्तरा है, परन्त यह बास्तव में सहकारी संयुक्त कुषि-अवस्था और सहकारी सामित कि स्वार का मिश्रण मात्र है। यह समिति स्वरं हम प्रकार कार्म में कृषि और अस्य प्रकन्ध करती है। इस प्रकार की कृषि से बड़े पैमाने पर कृषि करने के प्रायः सभी लाम उठाये जा सकते हैं। भूमि के छोटे-छोटे मार्गों में विभक्त होने तथा आर्थिक हथि से स्वार्यक्त मार्ग की समस्याओं को भी इस कृषि प्रयासी सं सुलक्ताया जा सकता है। परन्तु भारतीय कृषक कहिं सार्थी और परन्यपासी के सहसारा की सार स्वार्यक है, क्लिय पर म्याली नारत में आशानात्वर लोकप्रिय नहीं हो सभी है।
- (२) सहकारी श्रेष्टतर क्रांप क्यायला इस प्रकार की सिनियों का उद्देश कृति करने के उपायों से सुधार करना है। कुरत अपनी भूमि के श्राविकारी होते हैं और अपनी भूमि का प्रकार करना है। कुरत है। सिनित का कार्य हर कुरकों को अच्छा क्षेत्र देना, खाद तथा अन्य करते है। सिनित का कार्य हर कुरकों को अच्छा क्षेत्र देना, खाद तथा अन्य कृत्य आगारे के साथ ही सिनाई भंदार की सिनाई । ये सिनियार्स अपने स्टब्स हारा उत्पादित माल को एकन कर के उत्पत्था करती है। ये सिनियार्स अपने स्टब्स को उत्पत्था करती है। इस प्रकार की भूमि से भी बड़े पिनाने पर की गई कुष्य काम उठाये आ सकते हैं, जैसे कृष्य के सिनाम उठाये आ सकते हैं, जैसे कृष्य के स्वयस्था की आ स्टब्स हो है। यस्तु इस हस्वित में भी कार्स छोटे और भिन्न-भिन्न मागों में विनक्त रहते हैं। इस कारण वड़े स्थाने पर की गई कृषि के सभी लाभ नहीं उठाये जा सकते हैं, हम प्रणाली को उन खेनों में प्रारंभिक करने लाग, किया जा सकता है कहाँ उपक अराग भूमि सहस्वार्स स्थानी के सेने का लिये प्रदान को। उत्तर प्रदेश की सन्ना समितवार्स इस प्रणाली के अनुसार कार्य करती है और उत्तर करने कार की सम्मा समितवार्य इस प्रणाली के अनुसार कार्य करती है और उत्तर कारण कार्य करती है सीर उत्तर करने कार करती है सीर उत्तर कारण कार्य करती है सीर सन्तर हा है।
- (2) सहतारी आसामी कृषि व्यवस्था ना मीरियों के पाछ या तो अपनी निजी भूम होता है या वे गूमि पर्टे पर से सेती हैं परनु कृषि स्वयं नहीं करायीं। हथ प्रपासी के अन्वर्यव सूमि को कई खराडों से निमक करके मरिक स्वयंद पक्ष कुपक को दें दिया जाता है। कुपक को सेमिट द्वारा नियारित सोजना के अनुसार कृषि करनी पड़वी है। समित अपने परन्सों को कृषि के लिये भीज,

श्रीजार श्रीर वित्त इत्यादि की सभी मुक्तियायें देती है। भारत में जहाँ कहीं नई 
भूमि कृषि योत्य बनाई जा रही है वहाँ इस प्रवाली को लागू किया गया है, जैसे
उत्तर प्रदेश की गंगा खादर योजना में। इस योजना में संगित ने कुल भूमि को
२० एकड़ के लयड़ों में विभक्त किया है जिन्हें कुपकों को पट्टे पर दे रला है।
प्रत्येक प्रमिति के पास इस प्रकार के कम से कम १०० स्वरह हैं। मद्रास में भी
इसी प्रकार को एक योजना लागू को जा रही है। यहाँ उपनिवेश समितियाँ
स्थापित ही तई है और भूमिहीन मज़दूरों को भूमि पटटे पर देने की स्पवस्था की
गई है। यह समितियाँ उन्ही स्थानों पर उपसुक्त सिंह हो सकती हैं जहाँ नई भूमि
को कृषि के योग्य सनाया जा रहा है।

(४) सहकारी सामृहिक कृषि व्यवस्था—रह प्रायाली के झन्तर्गत सिति हो भूमि की अदिकारियों होती है झयरा वही भूमि को पट्टे पर लेसी है। सिमिति स्वयं कृषि करती है और हिस्ता हूँजी पर कुछ लामांश नहीं दिया जाता। उदस्यों को जनके कार्य का पारिकाशिक दिया जाता है और इसी पारिकाशिक के अनुपात में बोलस का वितरण होता है। इस सिति का सदस्य सिमिति के झन्तरा परंग्या विवस्त्रेह करने को स्वतन्य है। सिमिति के प्रचक्त हो जाने पर उसकी पूँची पापस कर दो जाती है। जहाँ तक उत्पावन और मूस्य नियारित करने की मीति का मश्य है स्वस्त्रा इन सिमितियों के कार्य में बिक्कृत हस्तकेप नहीं करती परन्तु भारत में अभी इस प्रकार को सितियों लोकिंगिय नहीं हो चक्त हैं।

किसी मकार का सहकारिता के खाचार पर कृषि चल रही है, (ग) वे माम जर्री
पर सूमि बहुत छोटे सामों में है छोर (च) वे चेत्र जो हाल ही में कृषि के छन्वर्गत
किसे गये हो; छोर (३) ऐसी समितियों की स्थापना करने में छनावस्यक
स्पीमता नहीं करनी चाहिये छोर न हुपई को उनकी हुच्छा के विकट सहकारी
कृषि समिति बनाने के लिए बाध्य है करना चाहिये बगोंकि असी हम छान्दोलन
की यह प्रारम्भक स्थित है। हमारा थ्येय तो छुपई केस स्वर्ग ऐसी सहकारी
समितियों का सुरस्य बनने के लिखे उत्साहित करने का होना चाहिये।

सहफारी कृषि की कठिनाइयाँ—(क) वहकारी कृषि को लोकप्रिय धनाने में सबसे बड़ी कठिनाई कृषक को सहकारी कृषि के लामों के मिन विश्वास दिलाने की है। इस कठिनाई की दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि सहकारी-कृषि व्यवस्था का प्रवार तथा उसके लामी का प्रदर्शन करने के लिये सहकारी कार्मों की स्थापना की लाय।

(ब) दूसरा प्रश्न यह है कि सहकारी कृषि-व्यवस्था की अनियार्थ रूप से स्नारा किया जाय ख्रायका स्वैत्का के ख्राधार पर । कांग्रेसी कर्णाय समिति ने १६४६ में स्वेष्ट्या के द्याधार पर सहकारी कृषि का समर्थन किया था परश्त स्वेष्ट्या के सफल हो जाने पर यह प्रखाली खनियार्य रूप से लाग कर देने की विफारिश की थी। यदि इस प्रकार की समितियाँ श्रातिवार्य क्या के सक्तित की काँच हो यह सम्भव है कि सदस्य समिति के कार्य में विशेष हिंच नहीं रखेंगे छीर ममितियाँ असफल सिंह होंगी। यदि किसी ब्राम के खल्प कपकों के विपरीत स्वधिकांश क्रयक सहकारी क्रवि-फार्म स्थापित करना चाहते हो तो देशी दशा में यह प्रणाली श्रनिवार्य रूप से लागू की वा सकती है। प्रथम पद्मवर्षीय योजना में सकताव दिया गया था कि यदि किसी होत्र के अधिकांश क्रयक जिनके पास हुल क्रवि की गई भूमि का कम से कम आधा भाग है, सहकारी काम स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसी वैद्यानिक सविधा होनी चाहिये जिसके हारा सारे गाँव के लिये सहकारी कृषि समिति स्थापित की जा सके। हम ऊपर बता चुके हैं कि सहकारिता श्रीर कृषि के राज्यीय मित्रयों की समा ने यह सिफारिश की शी कि कुछकों को उनकी इच्छा के विचय ऐसी समितियों का सदस्य बनने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये, उनकी सहायता उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर होती चाहिये। बाध्य करके हनाये हये सदस्य भार स्वरूप होते हैं और ऐसी समितियाँ ऋषिय भी हो जाती हैं। इस \_ श्रान्दोलन के लिये दित की बात यह होगी कि अपनी तक कुछ समय तक कृषकों को उनके लिये विवश न किया जाय । जब वे इस प्रकार की व्यवस्था से परिचित हो जायें तब आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाध्य भी किया जा सकता है।

(स) यह कहना संगम नहीं है कि सम्पूर्ण देश के लिये किए प्रकार की सहकारों समित उपयुक्त होनी। निमिन्न बरित्यतियों में समितियों के प्रकार भी मिन्न होंगे। चारे किसी प्रकार की समिति स्थापित की नाम हुए जात पर प्रमुख रूप से प्यान देना प्रायप्यक है कि प्रमिति की सदस्यता स्थेन्छ। पर ग्राधारित हो, मिनि के अपस्था अनतन्त्री दंग से की आय और मनदूरों को बास्तविक श्रातिक में न्यायेपित भाग दिया जाय।

(व) पहकारी आधार पर कृषि में बड़े पैमाने पर कृषि के लिए मशीनों कर उपयोग करने के कारण कुछ मजदूरों के बेरोजगार हा जाने की पंमावना है। इस लिए यह समस्या उत्पन्न हो सकती है कि इन मजदूरों के लिए नयी रोजी सोजी लाग।

भारत में घहकारी-कृषि व्यवस्था की समस्याश्रों को सुलक्षाने के लिए समय समय पर अनेक सुक्ताव भी दिये गये हैं——(१) यह विदित है कि भारतीय छवक अपनी भूमि छोड़ने के लिए छोत्र तैयार नहीं होता। इसिलए जब छवक सिति को अपनी भूमि छोड़ने के लिए धात्र तेयार तर है होता। इसिलए जब छवक सिति को अपनी भूमि गोपने के लिए प्रस्तुत न हो तम तक मार्राम्मक कार्यमाई के कर्म नहीं भूमि पर सहस्वारी कृषि की लाया हम नीत से भारतीय छवक का स्थान हम म्याली की और जायगा और इस और प्रमास करने के लिए उसे प्रेरणा मिलेगी। इन मीति से सहकारी कृषि की लोक्षियता बढ़ेगी; (२) जब तक संयुक्त-सहकारी कृषि संमम नहीं है तम तक सहस्वारी करियत कृषि समितियाँ स्थापित की जानी आहिएँ। इससे भीरि-बीर सहस्योग करने की प्रकृति का सित्याँ होगा; (२) किन परिस्थितियों में किस प्रकार की सहस्वारी अपवाली उपयुक्त होगा। (३) किन परिस्थितियों में किस प्रकार की सहस्वारी अपवाली उपयुक्त होगा। वह जानने के लिए ऐसे प्रयोगात्मक कार्य स्थापित किसे जाने चाहिएँ जहरें प्रयोग किरे जा सकें; (४) धरकारी कृषि का जोरदार प्रचार किया जाना चाहिएँ आहें प्रयोग किसे जा सकें मार्थ स्थापित करने वालिएँ नीन में उपयुक्त स्वर्ण किया जा सकें और जिनके परिणामी की से लान सम्यापित करने चाहिएँ जिनमें उपयुक्त स्थापित करने वाल करने वालिएँ जान में उपयुक्त स्थापित करने सम्बार्ण करने सम्बारित हो सकें।

पंचयपीय योजना के व्यन्तर्गत—प्रथम पंचयपीय योजना म योजना-व्यायोग ने सदकारी कृषिक्यवस्था को लोकप्रिय जनाने के कुछ सुमान दिये हैं जिनका संख्ति। जियरण जिन्तर्लाखत है—

(अ) प्रत्येक सहकारी-कृषि फार्म के लिए कम से कम भूमि की माशा निर्वारित की गई है इसलिए प्रत्येक फार्म के पाछ न्यूनतम निर्वारित माशा से कम भूमि नहीं होनी चाहिए। यह न्यूनतम सात्रा परिस्थितियों के अनुकूल निर्वारित की जा सकती है, उदाहरण स्वरूप एक चेत्र में ब्रोकत परिवार के मरण पोपए योग्य भूमि का चार से छः गुना अधिक सूमि होनी चाहिए। सहकारी कृषि-फार्म के लिए भूमि की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की कीई आवश्यकता नहीं है।

(ब) वितीय एवम् प्राविधिक (टैकनिवल) सहायता श्रौर विकय ब्यवस्था में

सहकारी कृषि समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ठ) भूमि की चकवन्द्री के कार्य-क्रम को लागू करने मैं उन प्रामी की प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिनमें बहुकारी कृषि-कार्स स्थापित किये गये हों।

(द) सरकार को (अपनी या किसी व्यक्ति की विकास करने के उद्देश्य से अपने अधिकार में ली गई) कृषि योग्य खाली भूमि को एट्टे पर देते समय सहकारी कृषि समितियों को आधिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही इस भूमि को कृषि के योग्य बनान के लिए उचित सहायता भी देनी चाहिए।

(4) यह व्यवस्था की जा उनती है कि जब तक खहकारी क्राय-उभिति का मार्य चालू है तब तक इसक उन सदस्यों के विकक्ष जो स्वयं कृषि नहीं करते हैं प्रतिकृत खालारी खांधकार लागू नहीं शेंगे। इस रियायत का उन्हें पर किसी भी रूप में पर्यमान खालागियों के छांधकारों पर प्रमाव खालाग नहीं है। इसका उद्देश्य छोंडी-छोडी भूमि के मालिकों को छायस से मिलकर सहकारी समितियाँ सगठित करनी को प्रोशासिट करना है।

वास्तव में भारत के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्तमाम किंदित भूमि उत्पादन में धांकशियक वृद्धि की अग्य । इसके लिए यह आवश्यक है कि इति-चेन में को प्रेमाने पर वैद्यानिक मणालियों और सामनों का मयोग किया निवासिक में से पूँची लगाई जाय । वहाँ शूंच छोटे-छोटे खराडा में विभाजित नहीं है छीर काफी बड़े चेनी में कृषि को साती है वहाँ है न उपायों का उपयोग अपिता का लाभ उठा सकने के लिए उचित रोमाना नायों जा सकती है, उस पर बोदें जाने वाली परवा, एकती की बोने के क्रम, भूमि स्वच्छा की उपयोग वासकती है, उस पर बोदें जाने वाली परवा, एकती की बोने के क्रम, भूमि स्वच्छा (विचाई की व्यवस्था और क्रिय के माने उपयोग का लाम उठा सकने के लिए उचित रोमाना नायों जा सकती है, उस पर बोदें जाने वाली परवा, एकती की बोने के क्रम, भूमि स्वच्छा (विचाई की व्यवस्था और क्रिय के उपाने को वह मितवस्था के समस्थ में उपयुक्त प्रवास किया जा सकता है। बड़े आई को वह मितवस्था से उपलब्ध होती हैं जो छोटे कार्म को उपलब्ध नहीं होती। बड़े आकार के और दिस्तृत चेत्र वाले कार्मों को अधिक अध्या और विचीय सह।यता मिल पहली है जिसका वे अधिक लामपूर्य हैन से उपयोग कर सकती है—अपनी अर्थ स्ववस्था में विविध्या ला सकती है तथा लावाज-समस्या के इस में प्रवेशकत अधिक करा है अपकरी है।

द्वितीय पंचवर्णीय योजना के अनुसार "प्रधान कार्य धेसे आवश्यक कदमों का उठाना है जो सहकारी कृषि के विकास की ठोस नींब प्रस्तुत करें ताकि १० वर्ष को अवधि में आविकांश कपि भ्रमि पर सहकारी आधार पर खेती होने लगे।"

सात-वरस्थी भारतीय प्रतिनिधि मण्डल, जो १६५६ में चीन और जापान गया पा तथा जिलने १६५७ के मध्य में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, का निक्कर्ष यह या कि पहकारी खेती लादी म जाय बरन् धीरे धोरे विकिछत की जाय। अगले सार वर्षों में ५० गाँखों के बीच कम से कम एक सहकारी खिति की स्थापना के उहरेग से एक प्रदान कार्यका निश्चित किया जाय। इसका अर्थ लगमम १०,००० सिनिंदर होगी। १० अनुमव प्रास होने तथा खहकारी खेतों से लोगों के परिचित होने पर हसका बिस्तार किया जाय। धेंसा करने से वह हानि भी नहीं होगी जो नीन में उसे जबंदरकों लड़ने के कारख हुँदे हैं।

٠

#### अध्याय १४

# सहकारी अधिकोषण (वैंकिंग)

भारत में सहकारी अधिकोषण संघीय आधार पर संगठित की गई है। इसके तल में छोटी ग्राम श्रीर करवा समितियाँ हैं श्रीर उसके पत्रचाल देस्थीय समितियाँ श्रीर केन्द्रीय सहकारी वैद्य हैं श्रीर सबके ऊपर राज्यीय सहकारी वैंक हैं जो शीर्य बेंक कहलाते हैं। छोटी समितियाँ कपकों की कवि-कार्य तथा छान्य उत्पादन कार्य के लिये आगा देती हैं। छोटी समितियों के पास कछ तो अपना रुपया होता है ह्यौर करू वह केन्द्रीय सहकारी बैकों से लेली हैं। केन्द्रीय सहकारी वैंक जीवरों से जमा बन से जीर्घ बैंकों से अपना लेकर जीर जहाँ वे नहीं है वहाँ भारतीय रिजर्व बैंक से और न्यापारिक बैंकों से ऋषा लेकर पूँजी समिहत करते हैं। छोटी समितियों श्रीर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बीच में जो केन्द्रीय समितियाँ हैं यह या तो शीर्ष छीर छाधारभंत समितियों के बीच में सम्बन्ध कोड़ने बाली कड़ी के रूप में हैं. या निरीक्षण करने बाली यूनियन हैं, या बैंकिंग यूनियन हैं। यनियन छोटी समितियों का संघ हैं: यह या तो छोटी सहकारी समितियों के कार्य का निरीच्या करती है या केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋगा की व्यवस्था करती हैं । केन्द्रीय युनियन स्वयं विचीय सहायता देनेवाली संस्थायें नहीं हैं बरन केन्द्रीय सहकारी बैंक श्रीर छोटी संग्रतियों में सम्बन्ध जोड़ने वाली संस्थाय हैं। शीर्य वैंक जो राज्यीय स्तर पर सहकारी खान्दोलन की सर्वोच्च संस्था है खपनी याँ जी शेयरों. जमाधन, व्यापारिक वैंको, रिजर्व वैंक श्रीर सरकार से ऋण के द्वारा संग्रहित करती हैं। यह फेस्ट्रीय सहकारी बैंकों को ऋगा देती हैं जिससे पेन्ट्रीय सहकारी बैंक छोटी समितियों को ऋषा दे सकें।

कैन्द्रीय चहुकारी बैंक का नुख्य कार्य छोटी खहकारी सिनियों को ऋ्या देना है परन्तु इधर छुछ वर्षों से ये साधारण ज्यापारिक बैंको तथा नैरन्सास कार्य करने लगे हैं। एक प्रकार से केन्द्रीय सहकारी बैंक खेतुलन स्पापित करने वाले केन्द्र को तरह हैं क्योंकि यह अधिक आय वाली सिनितयों की अधितिक आय से उन सिनितयों की सहायवा करते हैं जो हानि पर चल रही हैं। इसके साथ ही ये बैंक स्पापारिक बैंको, हत्य बाजार और फ़ुरको में परस्यर सम्बन्ध बनाये रखते हैं क्योंफि जिन राज्यों में शीर्ष वैंकों की अभी स्थापना नहीं हुई है वहाँ यह बैंक स्थापारिक बैंको, रिजर्व बैंक और सरकार से ऋष्ण सेते हैं। शीर्ष बैंक फेन्द्रीय सहकारो बैंकों के लिये वही कार्य करते हैं जो केन्द्रीय सहकारी बैंक छोटी सहकारी सहितयों के लिये करते हैं। बार्य बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋष्य देते हैं सिमितयों के लिये करते हैं। बार्य बैंकों की आविरिक्त आय से घाटे में और अधिक आय से घाटे में जीन वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहायता करके सन्तुलन स्थापित करते हैं। ज्लाने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहायता करके सन्तुलन स्थापित करते हैं। लीगों को पन जमा करने की परेखा देकर तथा ज्यापारिक बैंकों, तिजर्व बैंक लोगों को पन जमा करने की परेखा देकर तथा ज्यापारिक बैंकों के बीच और सरकार से ऋष्य लेकर यह इन्य बाजार और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहायता सेक्य स्थापित करते हैं और इस घन से केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहायता करते हैं।

१६०४ के सहकारी सिंधित कायून में जो १६१२ में संशोधन किया गया
१६०४ के सहकारी स्थिति कायून में जो १६१२ में संशोधन किया गया
उसके परचात् केन्द्रीय स्थापनों, केन्द्रीय सहकारी बैंको स्थीर स्थापन कर के इन केन्द्रीय सहकारी
काभिमाति की है। १६०४ के कायून में सशोधन कर के इन केन्द्रीय सहयात्रों की संस्था संस्थायों को मान्यता पदान को गई। फिर भी इन केन्द्रीय संस्थात्रों की संस्था संस्थात्रीय इपकों को इनसे सिक्तने वाली वित्त सहयाता पूर्णत्या अपमात है। श्रीर भारतीय इपकों को इनसे सिक्तने वाली वित्त सहयात्रा स्थापन है । सासव में इस बात पर जोर देना चाहिये कि इन संस्थात्रों की संस्था में वृद्धि हो, बासव में इस बात पर जोर देना चाहिये कि इन संस्थात्रों की संस्था होते

शार्ष वेंक--- नहकारो खिकिनियण द्वारा की गई प्रगति का अनुमान इसी से लग सकता है कि १६५०-५१ से १६५५-५६ के बीच १० नई राज्यीय सहकारों बिंकों की स्थापना की गई तथा ३० जूत १६५६ को देश में २४ देखी सहकारों बिंका गाँच राज्यों---कच्छा, मनीपुर, गाँड्चिरो, त्रिपुरा झक्मन और बैंकें भी। केवल गाँच राज्यों---कच्छा, मनीपुर, गाँड्चिरो, त्रिपुरा झक्मन और निकोबार,---में झब तक राज्यों वेंक नहीं है। इन वेंको की सदस्यता महकर इस,१६४ (जिसमें १९,७४३ स्थिक, और २४,६५१ बैंक तथा समितियाँ भी) तथा चाल पूँजी बदकर ६३-३४ करोड़ दे हो गई।

शीर बहुकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, मिश्रित छोर छांमश्रित। मिश्रित बैंकों के सेपर व्यक्ति तथा बहुकारी संस्थायें दोनों हो से सकते हैं परन्तु प्रमिश्रित में कैवल सहकारी संस्थायें हो शेयर ले सकती है। यदि प्रत्येक शीर्ष बैंक छामिश्रित केवल सहकारी संस्थायें हो शेयर ले सकती है। यदि प्रत्येक शीर्ष बैंक छामिश्रित संग के ही होते तो सहकारिता आन्योलन की भावना के सर्वेषा प्राप्तुकत होता। स्राप्तु अमिश्रित बैंक तो केयल आन्त्र, पंजाब, पंच्छनी बङ्गाल छीर भैदर हो में प्रचलित हैं। शेष सब राज्यों में मिश्रित बैंक ही है।

१९५६-५६ में शीर्ष में को को चालू पूँजी में (जो ६३-३४ करोड़ करए यो) १९५६-५६ में शीर्ष में को को चालू पूँजी में (जो ६३-३४ करोड़ करण यो) निजी कोष २२-१% जमा घन ५७% तथा अन्य आते से प्राप्त ऋण ३०% या जब कि १९५१-५२ में यह प्रतिशत कमशा ११४, ५७७७ और ३०'८ ये इन वैंको फे निजीकोण का इतना कम होना बड़ी चिन्ता का विषय है क्योंकि विना निजी कोप में यदि के इन में स्थितना खाना सम्मव नहीं।

ये बैंक वर्तमान समय में भूखा श्लीर बमाधन पर अपना वार्य चलाने के लिए निनंद रहते हैं। १६५५-५६ में ३६ ६७ करोड़ का के नमा-धन में १८८५-६ करोड़ का के नमा-धन में १८८५-६ करोड़ का वैद स्वार्य की साला किया गया दिव्यं में के और सरकार से लिये नये खुरा की माला कमरा: २९ करोड़ का तया ७४ करोड़ का थी। १६-१ करोड़ का की अस्य भूखा की सांधा में स्वापादिक बैंकों लिया गया भूखा १,०५६,००० का तथा बहकारी बैंकों से लिया ग्रह्मा ८०० हो। १ स्वार्य की सांधा में स्वार्य क्षारा है की पर पहला है। इस बैंकों से लिया गया भूखा है। पर निर्भेदना घटती और सरकार, दिश्वं बैंक सथा सहकारी बैंकों पर बहुती विद्याद एक्टी है। इस बैंकों का लगभग १८-६६ करोड़ कर्या सहकारी तथा अन्य प्रतिभृतियों (द्वस्टी सिक्योनिटीज़) लगा हुआ था।

"राज्योम लक्ष्मारी बैंकों द्वारा दिये गये द्वाप्तम (advance) की माना १६५४-५५ के ६० १५ करोड द० हो गई। यह वृद्धि बैंको लगा लिमितियों की दिये गये द्वाप्तम में आंधक दर्शमीय थी। व्यक्तियों की दिये गये आप्तम में आंधक दर्शमीय थी। व्यक्तियों की दिये गये आप्तम की माना १९५४-५६ में चट गई थी किन्तु विपाद का निषय तो यह है कि १९५७-५६ में इनमें २/३० करोड़ द० की वृद्धि सुई विविदे कलकरण व्यक्तियों को दिये गए आप्तम की माना बढकर ६९७६ करोड़ द० हो गई।"

फेन्द्रीय सहकारी बैंक — हेन्द्रीय बैंकों की सख्या १९५४-५५ में ४८-५ थी। १९५५-५६ में यह पटकर ४७८ हो गई। ''यह कभी कुछ राज्यों में फेन्द्रीय विचीय एकेन्द्रियों के युक्तिकरण की नीति वरवने के परिणाम स्वक्ता हुई है! विचीय एकेन्द्रियों के युक्तिकरण की नीति वरवने के परिणाम स्वक्ता हुई है! वर्षाम एकेन्द्रिय के ति हिमांबल प्रदेश में राज्य की दो ग्रावशिष्ट बैंकिंग मृतिपन राज्योय सहकारी बैंक में विलियत हो गई। केन्द्रीय बेंकों की संख्या में कमी होने के मांबल्ड भी उनकी सदस्य संख्या १९५४-५५ के खंत में २,७२,००० (१,३२,२७२ व्यक्ति तथा १,३६,०२८ प्रितिपनी) हो बहुकर १९५५-५६ में २९६, ५९५ (१९५४-५६ वर्षीक तथा १,३६,०५८ प्रतिपति हो। हो गई। अस्त्रीय अपनीत हो। वर्षाम १,४५,५५८ वर्षीक तथा १,४५,५५८ वर्षीक तथा १,४५,५५८ संत्रियों) हो गई थे अहं १७ ज्ञानम, ज्ञासान, विहार, मध्य प्रदेश, मद्राप, हैररावाद, बम्सू और कास्त्रीर, मध्यमारत, मैदर, सीराष्ट्र और भोगाल में भिवित दक्ष के और विवंक्तर कोचीन में अमिथित दक्ष के केन्द्रीय देंक थे। श्रेष प्रदेशों में जैते वर्षादें, उन्होंग, प्रवास, उत्तर प्रदेश, प्रक्रिम स्वाल, पेस्स, राजस्थान, अबमेर, हिमाञ्चल प्रदेश में भिवित और अमिथित दोनों दक्ष के वेन्द्रीय बैंक थे। वेष स्वीत्र दिस्ति हिमाञ्चल प्रदेश में भिवित और अमिथित दोनों दक्ष के वेन्द्रीय बैंक थे।

केन्द्रीय चहकारी वैंडा के कार्य की एक विशेषता यह यी कि व्यक्तियां को दिये जाने वाले अभिम में कमी था गई। १९५५.५६ में वैंको तथा छमितियों को दिये जाने वाला अभिम न्द्र मितरात तथा क्यकियों को दिया जाने वाला अभिम १२ प्रतियात था जबकि हसते यहिले वर्ष के प्रतियात कम्पाः दर तथा १६ ये। दुरे तथा सन्देहात्मक ज्यूषों का अनुवात अथ भी अधिक है हालोंकि हस दिया

में भी कुछ सुधार हला है।

सामा विशेषमाएँ— वर्षेष और केन्द्रीय सहकारी बैंकों में बहुत कुछ समाना पाई जाती है; (१) इन दोनों संस्थाओं की हिस्सा वृंधी और सुरिश्वित निषि (अर्थात निजी वृंधी) अपर्याप्त हैं। केन्द्रीय सहकारी वैंको की स्थित कुछ अर्था है, परन्तु उनमें मी हिस्सा पूँची और सुरिश्वित कोण का पन प्याप्त नहीं है हरका एक कारण तो यह है कि इन निकें का जिन लोगों से सम्बन्ध रहता है यह निपंत है और इनकों लाम भी बहुत कम होना है जिससे सुरिश्वित लोग में प्याप्त धन-पांच एकत्रित नहीं हो पातो। यह खेद का विषय है कि दितीत महायुक्ष के समय और महायुक्त के सुरन्त प्रधात जब कृषकों की विचीय स्थित मुपरी थी, इन बैंकों की हिस्सा पूँची बहाने का अर्थास खो हिया गया। इन बैंको को हिस्सा पूँची में तमी सुब्दि की सकती है कि कुमकों की विचीय स्थित में युवार हो स्थम वृंदि वृंदि प्रवृंदि को सुक्त के अ्थकों की विचीय स्थित है युवार हो स्थम वृंदि वृंदि पर्वाचीय योजनाओं को स्थादि तक कुपकों की विचीय स्थित सुपर जायगी और तब बैंको की हिस्सा पूँची में वृद्धि को आ स्वेकी।

- (२) दोनो संस्याओं में कुछ मिश्रित तथा कछ क्रमिश्रित बैंक हैं। क्रमिश्रित चैंक सहकारिता के विदान्त के अधिक अनकल होते हैं। परन्तु मिश्रित प्रकार के हैं हो के कर लाम है कि राज्यों अधिक विन्तु पाप हो सकता है और साथ ही उन लोगों का ग्रंथिक सहयोग मिल सकता है जिनका कवि से सम्बन्ध नहीं है। इस बात को ध्यान में रखने हुये कि मारतीय क्रपक अभी अविक्रित अवस्था में है यह बहुत बहा लाम है। मिश्रित वैंकों से केवल यही हानि नहीं हैं कि इनका क्षयसाय सहकारिता के नियमों के अञ्चलर सामान्य नहीं होता बल्क नाथ ही इनका कभी-कभी हानिकारक परिशास भी होता है। विभिन्न व्यक्तियों को इस हैं हो के शेवनों को कर करने का अधिकार है इसलिये इन हैं हो से आप लोने का भी श्राधिकार है। व्यक्तियों को कृषि की उत्पत्ति के आधार पर ऋण देना सहकारिता के नियमों के अनकल नहीं है क्योंकि इससे ये बैंक उन दलालों की भी महायता करते है जिसको सहकारिता ज्यान्टोलन समाम करना चाहती है। साथ ही हस प्रकार की सहायसा से सहकारी विकय ब्यवस्था के विकास में बाधा पहॅचता है। इसलिए यह उद्देश्य होना चाहिये कि 'मिश्रित' समितियों को कछ क्रमण तह उहने दिया लाय और बाद में क्यकों की आर्थिक स्थिति की संधारने के परिशाम स्वरूप उनके द्वारा इन संस्थान्नों को विश्वीय त्रावश्यकता पर्ण हो जाने
- पर हाई द्वासिशत कमितियों में बदल दिया जाय ।
  (३) वेन्द्रीय छहकारी मैंक प्रशिक्तर निहित्तत समय के लिये लगा और
  मत्तत को स्वीकार करते हैं परन्तु धर्योष्टम मैंक इनके ख्रतिरिक्त चालू खाते में धन
  स्वीकार करते हैं। सर्वोष्टन मेंक प्रशिद ख्रुद्ध सीमा तक केन्द्रीय सहकारी मैंक सावारण
  व्यापारिक मैंको का व्यवस्थाय करते हैं। यह मैंक द्वाप्टर देते हैं, हुएडी, केन और
  श्वाप्त्रों का क्रय-विकय करते हैं और सामान की भुरिक्त रखते हैं। यह महन
  काभी विवाद प्रस्त है कि सहकारी संस्थाओं का कार्य-चित्र केवल सहकारी मैंके
  के व्यवसाय तक ही शीमित रखा वाय या ये व्यापारिक मैंकों का व्यवसाय मी
  करें। वर्तमान समय में सहकारी मैंकों का कार्य उनको व्यस्त रखते के लिये पर्याद
  नहीं है इसिलेय इन्हें क्यापारिक मैंकों का मी कार्य करना पढ़ता है। यदि यह
  व्यवसाय न किया आय तो मैंकों की आय बहत कस हो लायगी।
- (४) इन संस्थाओं को बहुत कम लाम होता है। इन सस्याक्षों का लाभ श्रीर सदस्या का दिया गया लामीश भारत के श्रन्य बैंकों को श्रपेता कम है।

व्याज दर—भारतीय रिलर्ज सेंक की हान की रिगोर्ट में नताया गया है कि अनेक राज्यों में छाटी सहकारी संसिनियों के क्यांच की दर काकी अपिक है। फेरवल समई और मदाय में बहां सहकारी आन्दोलन काफो स्पटित हैं और कापी विकस्तित है इपाल की तर कहा कम रखना संगव हो सका है। बानेक र्सामितियों ने स्म सिक्कान्त पर बोर दिया है कि योग्य कपकों को दिए जानेपाले अस्य पर अल्पकाल तथा मध्यकाल के लिए हैं। प्रतिशत से अधिक व्यान न लिया जाय और टोईक्सिक क्षाम के लिए ब्याज की दर ४ प्रतिशत होनी चाहिए। यद सिदान्त महास शीर बमाई में लाग रहा है। इन राज्यों की सरकार घाटे की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देकर सबकारी बैकी की कम ब्याज पर भाग हैने में सहायता कर नहीं है। इसके लिए सरकार वैक प्रशासन का कछ मार स्वर्ध बहुन करती है । कारत शहतो में भी इस प्रकार को स्वयस्था होना चाहिए । सहकारी वैंकी द्वारा इसल किये जाने वाले ब्यास की दर श्रविक होने के कछ कारण बिध्न है-(१) सह आरी समितियाँ स्थानीय तीर पर पर्याप्त पूँजी का संग्रह करने में अस्त्रल रही हैं: (२) बरवर्ड श्रीर महास की छोड़कर केन्द्रीय सहकारी बैंक साधारपात: छोटे हैं, इनके प्रकल का न्यय अधिक है और आधिक हिन्द से यह श्रामप्यक्त है। यह श्रापना कारोबार तभी चला सकते हैं जब ऋणा लेने श्रीर देने की ब्याज की दर में काफी अस्तर हो। और (३) विभिन्न सब्य जो उसरा तथा गाधिक महातवा में जान्होंना की महायवा काते रहे हैं जाब दुव्य शाला में अध्ययक आया एकतित करने में श्रीर परिखान राज्य उसे कम ब्याज पर विभिन्न सहकारी कार्यों में लगाने में विशेष कठिताई श्राम्भव कर रहे हैं। रिजर्व वैंक के मतानसार निम्नलिखित प्रयत्नों से व्याज की दर कम की जा सकती है-(श्र) एडकारी जान्द्रोलन का हट बनाया जाय, उसकी कार्य कशालता में सभार किया जाय और माम्य सेवों की बचत की संमहीत करने पर जोर दिया जाय: (ब) श्रार्थिक दृष्टि से अवयुक्त इकाई का रूप देने के लिए सहकारी बैकों और समितिया को एक में मिला दिवा जाय और समितियों के कार्यक्षेत्र का न्यापक प्रसार किया जाय और (स) ग्रारम्भ में राज्य सरका रें बस्वडे की तरह ग्राधिक सहायता दें जिससे सहकारी बैंकों को कम ब्यान लेने से वो पाटा होता है उसकी पति की का सके।

रिजर्ब मैंक से खाया—रिजर्व मैंक एवट की धारा १७ (२) (व) और १७ (४) (व) के अरावार यह बैंक वरकारों बेंकों को कारे उत्पादन और क्षत्र ने बने में के किए उत्पादन और क्षत्र ने बने में में किए प्राप्त के अहन-काबिक और मध्य-काबिक सूख देता है। घारा १७ (४) (अ) के अन्तर्यंत सरकार्य प्रतिस्थियों और सूचि बन्दक मैंकों के अरुवपनों की कामत्य पर भी मुख देता है। वस १६९५ को फर्नरों से रिजर्व मैंक ने घारा

<sup>1.</sup> विस्तार पूर्वक अध्यत के लिये 'आग्य विश्व स्थावस्था' का प्राध्याय देखिये

230 १७ (४) (ग्र) के अन्तर्गत तीन वर्ष की अर्वाघ के लिये मध्य कालीन ऋण देना

ग्रारम्भ कर दिया है। १६५३ के विजर्व वैंक जाफ इस्टिया एक्ट के संगोधन के कारण यह सम्मव हो गया है कि १५ महीने से लगाकर ५ वर्ष तक की अवधि के लिये प्राण दिया जा सके। इस नियम का प्रयोग करने के विचार से ही बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के स्थाबी अप्रका एक्ट की घारा १७ (४) (अ) के अन्तर्गत देना आरम्म कर दिया है, यद्यपि अधिक लम्बी अवधि आर्थात ५ वर्ष तक के थ्यावेदनों पर श्वावश्यकता यहने पर विचार किया जा सकता था। ऐसे ऋखो पर भ्याज कीर दर बैंक की दर से २% कम निश्चित की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा दी हुई गारन्टी छीर ऋग लेने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंक आधवा समिति द्वारा लिये हथे प्रतिज्ञा पत्र ही इन ऋगों की जमानत थे। जिन कार्यों के लिये मध्य कालीन अग्रा दिये जा सकते ये वे बेकार अग्रि को पन: अधिकत करना, वाँध बनाना अथवा भूमि में किशी अन्य प्रकार का सधार करता. वैल आदि जानवर खरीदना, कृपि सम्बन्धी श्रीकार खरीदना तथा जानवरो को बाँधने के बाडे श्रीर खेता में गोदाम बनाना इत्यादि थे। रिजर्च बैक दारा शक्यीय सहकारी बैंक को दिये गये अभिम की राशि १८५१-५२ में ११-२८ करोड हु थी। १८५७-५८ में यह बढकर ५७ १२ करोड़ ६० हो गई। इस अवधि के अन्त में देय ऋगों की राशि ७ दर करोड़ रु से बढ़ कर ३५. ११ करोड़ रु हो गई। १६५७-५८ में दिये गरे ५७ ११ करोड ६० के कल छात्रम में से ४१ ४१ करोड़ ६० थारा १७ (४) (स) के अन्तर्गत, १२७२ करोड़ दo घारा १७ (४) (अ) के अन्तर्गत तथा

२.६६ करोड़ र० घारा १७ (४) (अ) के अन्तर्गत दिये गये। अखिल भारतीय आमीशा साख सर्वेचरा समिति की सिकारिशों के अउं-सार १० करोड़ २० की प्रारम्भिक राशि से राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्थकालीन) कीप का निर्माण ३ फरवरी १९५६ को किया गया ताकि "राज्य खरकारों, (जिससे वे सहकारी समितियों की हिस्सा पंजी में बोग दे सकें) राज्यीय सहकारी बैंकों और भूमिवन्धक बैंको को दीर्घ एवम् मध्यकालीन ऋषा दिये जा सके ।" जून १९५६ में इस कीप मे भू करोड़ कि के वार्षिक अनुदान से वृद्धि की गई। साची १९५७ के श्रन्त तक २·६८ करोड़ र० का भूग ११ राज्यों को दिया गया ताकि वे सहकारी संस्थाओं की हिस्सा पँची में बोग दे सकें।

# अध्याय १६ भृषि वंधक वेंक

१. हपक को हुपि में पृद्धि करने श्रीर श्रम्य घरेलू कार्यों के लिये शरूप-कारिक श्रा की आवश्यकता होती है श्रीर फ़्तल कर जाने के परचान हास्त उसको सुहावा भी जा सकता है। पशु अरियने, क्रीप के श्रीजार हंग्यादि का प्रबच्च करने के लिये हुपक मरपकालिक श्रम्थ लेता है। वर श्रम्य को दीर्थ वर्ष के लिये श्रीर कमी-कमी '- वर्ष तक के लिए लिया जाता है। हुपक को दीर्थकालिक जाए की भी शावश्यकता होती है जिससे वह हुपि के लिए मशीनें तथा श्रन्य मृत्यवान सामान कर करता है, भूमि कर करता है और दुराने श्र्म को चुकावा है। वृश्वि इस प्रकार के प्रश्न की घर राश्वि कार्य करता है श्रीर हुपने श्रम लिये इस प्रकार के श्रम्यों को भू सम्पत्ति के बदले ही भारत किया जा सकता है। (दिन्यों बैंक के हुपि साल विमाम हारा प्रकाशित भूमिवन्तक बेंक (Land Mortgage Banks) नामक प्रकारत के।

संगठन किया जाय तो इससे जनता की बचत को भूमि सुपार कार्य में पहले की अपेक्षा अपिक मात्रा में लगाया जा सकता है। व्यापारिक बैंकों को क्याया लोगों को अल्पकालिक जमाधन से मिल जाता है परन्तु इसके विपरीत भूमि बन्धक वैंकों को मुख्य पत्र चला कर या जन्मक गाँडों के द्वारा घन मिलता है। ये बांस्ड बैंकों से पत्र लेने वाले व्यक्तियों द्वारा बन्धक रच्छी हुई सम्पित्त के आधार पर प्राप्त होते हैं। मुख्य परिस्थातियों में, जैसे छोटे छोटे अपकों के कार विशेष उपयोगी होने के कारण या राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में इनका विशेष महस्व होने के कारण या राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में इनका विशेष महस्व होने के कारण या राष्ट्रीय अपनिक व्यवस्था की गास्टी देती है।

भूमि बन्यक में को को क्यापारिक बैंको के आधार पर सहकारी संस्थाओं के या कार्योरेशन के आधार पर रूप में संगठित किया जा सकता है। मारत ने भूमि बन्यक बैंकों को सहकारी आधार पर संगठित किया गया है परन्तु चूँकि हुई क्या कि तिजो रूप से हुए प्रकार के की के सहस्य है इसलिए इनकी प्रकृति अप सहकारी संस्था के समाज कही जा सकती है।

भारत में छवं प्रयम शहकारी भूमि बन्धक में ह १६२० में पंताय के कंप नामक स्थान ने स्थापित की गयी परन्तु इसको सफलता नहीं मिली। मद्रास में सर्व प्रथम १६२६ में भूमि क्यक बैंक स्थापित किये गये और वहाँ हुन्हें अधिक सफलता मिली। यहाँ केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक १६२६ में स्थापित किया गया। इसके पत्रचात् कुळ अन्य प्रदेशों ने भी मद्रास की तरह भूमि वश्वक बैंक स्थापित किये।

१६२६ में रिजस्ट्रार-धम्मेलन ने भूमि बन्यक वैंकी को धमस्या पर विचार किया और कुछ सुकाव दिये। भारत से इन वैंको का विकास सम्मेलन के सुकायों के अनुसार हुआ। रिजस्ट्रार सम्मेलन के कुछ महस्यपूर्य सुकाव किम्मिलियन हैं...

(१) इस प्रकार के बैंकों का स्वयटन सहकारी समिति नियम के अन्तर्गत किया बाता चाहिये। इनका कार्य सेवन न तो इतना कम हो कि आर्थिक हॉस्ट से यह अनुप्रमुक्त सिंद हो और न इतना अधिक हो कि प्रचन्ध करना कठिन हो बात ।

(२) भूमि बग्यक वैंक इपकों को इन कार्यों के लिए श्रृष्ण दे एकते हैं—
(अ) भूमि तथा सकान छुडाने के लिये, (ब) भूमि और रूपि के शायनों में गुभार करने के लिए, (ब) पहले का श्रुष्ण बुकाने के लिए और (६) भूमि मध्य करने के लिए, वैंक को अपने उपनिष्मों में यह स्थर्ट कर देना चाहिये कि इस प्रमुख कम से कम कितना और खिषक से अधिक कितना दिया जा

सकता है। बैंक को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऋषा की घन राशि इतनी कम न हो कि उससे चेन-देन का ब्यय भी बस्छा न हो एके और न इतनी अधिक हो कि प्रारम्भिक समिति उसे सुगमतापूर्वक न दे सके। सम्मेलन ने सुमाब दिया कि ऋषा की धनराशि सम्पत्ति से मूल्य के आपे से अधिक नहीं

(३) वेंक को कुपक को ऋष्य चुकाने को शांक तथा जिस कार्य के लिए ऋषा लिया गया है उसको ध्यान में रखने हुए ऋषा चुकाने की अवधि निश्चित करनी चाहिए। इस बात का स्थान रखना चाहिए कि जिस ऋषा से लेने वाले की आर्थिक इंटर से लाभ न हो यह ऋष्य न दिया लाग। सम्मेलन ने नुम्माव दिया है कि बर्तमान परिस्थितियों में ऋष्य चुकाने की अधिकत्वस सर्वोत्तम अवधि

(y) प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहाकारी वैंक स्थापित किये जायें। इन बैंको को राज्य के केन्द्राय भूमि क्यक वेंक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, किन्द्र प्रान्तीय भूमि क्यक कार्यरिशन की स्थापना होने तक श्रस्थायी रूप में इनके इस कार्य पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिये।

(५) धरकार को श्राम्थाको पर स्थान और पूँची जुकाने की गारन्धी देनी चाहिए। कार्य चालू करने के झार्रम काल में सरकार को सूमि बन्धक बैंको को झार्थिक सहापता देनी चाहिए। इस बैंको को स्टाम्प कर इत्यापि में कुछ प्रविधार्ष दो जानी चाहिय। वाद की हम बैंको को स्टाम्प कर इत्यापि में कुछ प्रविधार्ष दो जानी चाहिय। वाध की हम बैंको को रेहन रखी बरखां के छुटाने की अवधि प्रभाप हो जाने के पश्चाप्त विमान न्यायालय की सहायता लिए उन पर झिंकतार के तो ता रा उनके विजय का अधिकार सिल जाना चाहिये परनतु देखी व्यवस्था होनी चाहिये अध्ये देखरे व्यवस्था होनी चाहिये अध्ये देखरे पड़ के हितों की भी रखा की का सके।

तालिका १ के यह स्वच्ट है कि यह खान्दोलन समान रूप से देश के विभिन्न मागों में विकित्त नहीं हुआ है। १६५१-५२ में केवल इ केन्द्रीय भूमि बन्यक वैंक ये। इसके परचात तीन और स्थापित हुएँ एक हेदराबाद में, एक अक्तमर में और एक आहम में। इस मकार १९६५-५२ से केवल इ केन्द्रीय भूमि बन्यक वेंक ६ राज्यों में स्थापित हो गये (आज्ञम, चन्यक, मद्राप, उड़ीना, हैदराबाद, मैस्स, सीराप, विवाक्त की की नीन और अवमेर) और प्रारम्भिक भूमि बन्यक वैंक ७ कि राज्यों में ३ क्या राज्यों में और ५ पण राज्यों में स्थापित हो गये। विकास स्वाक्त से अपित, सीराप्त की स्थापित हो गये। विकास सीराप्त का स्थापित हो सीराप्त की सीराप्त का सीराप्त का सीराप्त की सीर

वालिका १ मुमि वन्धक वैकों की सदस्यता १९५५-५ ६में

राव्य वै	हाका सङ्ग	व्याक्तयों की सदस्य सदया	बैंकों का सरग
चे :	द्रीय भूमि दन्धन	. चेंक	
ग्राम	\$	₹ <b>७</b> ४	મૂહ
बम्बई	₹	₹,०१७	ર દેવ
मध्य प्रदेश	**	***	হঙ
<b>मद्रा</b> स	*	३२६	20
उद्योखा	*	<b>८३</b> ६७	\$0
<b>दै</b> दरादाद	₹	***	₹७
मैसूर	ŧ	₹08	१६३
सौराष्ट्र	ę	39.4.50	•••
त्रॉबदुर कोच न	*	४,६८३	***
श्रजनेर	2		**
योग	3	80,781	838
	द्राव	।भ्यक सूमि दश्यक देक	
ग्राम	<b>પ્ર</b> ૭	६५,⊂≈२	***
श्रासाम	₽	२७६	***
सम्बद्	<b>₹</b> =	३२,६४५	**
मध्यप्रदेश	2.5	२२,४६३	•••
मद्रा च	43	१,०१,४⊏४	***
उत्तर प्रदेश	Ę	⊏94	***
पश्चिमा बङ्गाल	3	₹,88%	
<b>है</b> दरानाद	90	દ,६%४	***
मध्यभारत	₹	६२	****
मैस्र	<b>⊏</b> 3	ક્ષ્ય <sub>ા</sub> દ્દસ્ય	
राजस्यान	50	₹७१	
ग्रजमेर	4.5	ર,પદ્	•••
योग	3.2	₹,१₹,⊏२७	

मालिका नं ० २ १९५५-५६ में मृमि वन्घक वैंकों का कारोवार

१८५४.५६ में मूर्ग वेन्यप	केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक (लाख रुपयो में)	प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक (लाख रुपयो मे)
	05.0g	₩.£A
यर पूँजी		-2485
हुण ग्रीर जमा धन	२१.०२	२३.१६
4	32.088	दः३३
(क) वर्षा क्रांचित्र तथा ख्रन्य स्त्रोतो से	<b>≅</b> 9.85	٧٥٠٥
सरकार से प्राप्त ऋख	\$A£A.5≈	७.६२
	(800 /	೯೮೭,08
ऋग् पत्र केन्द्रीय भूमि बन्धक वैंक से प्राप्त ऋग		१७३.६४
ह्यास्त्रया का विभाग सम्बद्धि हो हिया गया ऋर	5€5.08	93.30
वंका आर वानायन		4046.54
वर्ष भर में चुकाया हुन्ना ऋग	१३०⊏२१	१७'द्ध
वर्ष के द्यन्त में कुल ऋण	३६॰३२	
मुर्द्धित कोष	₹७:₹٤	રૂ ૦ ' ૦ પ્
श्चन्य कोष	१८५२'६३	<b>66</b> 58.⊏X
चालू पूँनी		

हुड्यवरिषत हैं। मध्य प्रदेश में उनकी व्यवस्था साधारण स्तर की है। वहाँ घमो अन्तराप्त मृत्र बन्बक वेंक नहीं है। इन वेंको द्वारा कुरको की समस्याएँ इल कोई केन्द्रीय मृत्रि बन्बक वेंक नहीं है। इन वेंको कारों के लिये यह आवश्यक है कि प्रायेक राज्य में एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैक हो श्रीर श्रानेक छोटे मूर्मि बन्धक बैंक हो । आवश्यकता इस बात की है कि उन राज्यों में बेन्द्रीय सूमि बन्धक वैंक स्थापित किये जाँग जहाँ अभी तक इनकी रथापना नहीं हुई है। इसके शाम ही वर्तमान छोटे सुमि बन्धक वेंकों के व्यवसाय में बृद्धि की जाय तथा उन राज्यों में जहाँ यह अभी तक नहीं है प्रारम्भिक भूमि बन्धक वैंक स्थापित किये जाँय ।

१९५५ मुक्त में केन्द्रीय और प्रारम्भिक भूमि बन्यक बैंकों की चालू पूँजी तालिका र के अनुवार कमशः १८ ५३ और ११-३५ करोड़ कपया थी। फेन्द्रीय भूमि बन्धक बैकों ने २८३ करोड़ रुपये तथा प्रारम्मिक भूमि बन्धक बैंकों ने १७४ करोड़ रुपये भूत्य में दिये। इन बैंकों के न्यवसाय की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं।

(१) इन बेको ने जितना श्रमण दिया है श्रीर जितना व्यवसाय किया है, वह श्रावस्यकता को देखते हुए बहुत कम है। १६५५-५६ में केन्द्रीय तथा श्रारमिक सूमि व्यवस्य वैकी द्वारा दिये गये श्रम्य श्री मात्रा कमशः २९८३ करोड़ कर १९५४ करोड़ कर थी जब कि इससे पहिले वर्ष में इनके द्वारा श्रम्य हो हुई साशि कमशः २९४६ करोड़ कर तथा १९५६ करोड़ कर यी। क्रपकों की दोर्बकालीन श्रम्य की श्रावस्यकता की द्वलता में ये भन श्रम्य कम श्रावस्यकता

(२) चंद्रीय भूमि बच्चक बैंकों के शत्म. १६ करोड द० की चालू पूँजी तथा प्रारम्भिक भूमि बच्चक बैंकों के ११ १९ इस करोड द० की चालू पूँजी में से महास और साम क्रमण हैं को के ११ १९ इस करोड द० के लिए उत्तरहायी में महास और साम क्रमण हैं को के सकत होने के अनेक कारण हैं। इस सम्बन्ध में महात उत्तरहायों में महात उत्तरहायों के भूमि बच्चक वैंकों के व्यवस्था के लिए उत्पुक्त स्थान के चुनाव, भूमि के मूल्य इस्थादि की परीचा, अपूण लेने वाले की अपूण जुकाने की शाकि का अपूमान, बदलों में शीमता और और बेंकों के व्यवस्था का भली माँति निर्माणों किया है साम के चुनाव के साम के चुनाव का साम को साम का मानी माँति निर्माण किया, के स्थान अपूण कर्म के चुनाव का साम को मानी माँति निर्माण किया है साम के चुनाव का साम को साम के साम के

(३) राज्य क आह फदाय सहकारा बना का हा तरह सूम बन्यक वका के वास अपनी धननाश्च बहुत कम है और उन्हें अनुवादनों, सरकार से अनुवा और कमार्पूनी पर ही निर्मार करना वका है। वहाँ तक केन्द्रीय सूमि बन्यक धैकों का समय है, १४'९४ करोड़ रुपया वो कि कुत वालू पूँवी का लगमग ८०% होता है अनुवादन से बात हो से कि बार से दिन में अपने में की हारा निर्मात कुत्र वालू पूँवी का लगमग ८०% होता है अनुवादन के विवाद से दिन बैंक ने १९४० में पूमि बन्यक बैंकों की सहायता करने के विवाद से दिन बैंक ने १९४० में २०% कर दो गई थी। निर्मात अनुवाद पत्र के थे रूप के अनुवाद दी कि उन राज्यों की सरकार जहाँ से बैंक शिव है, मुल्यन और व्यान देने का अनुवाद दी कि उन राज्यों की सरकार वेने को अनुवाद ही। १९५६ में इस सहायता योजना का और अधिक विस्तार किया यया और भारत सरकार ने प्रथम यंचवर्यीय योजना के अनुवार्य वो ५ करोड़ स्पया दीर्यकाल के

लिये कृषि सम्बन्धी ऋण देने के लिये निश्चित कर दिया था. उसमें से १ करोड़ रपया भूमि बन्धक बैंकों के ऋख पत्र क्य करने के लिये नियत कर दिया गया। यह निश्चित कर दिया गया कि चेन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक दो में से कोई भी केन्द्रीय मुसि बन्धक बैकों द्वारा निर्मित कल ऋगवनों के ४० प्रति- शत ग्रथवा जितने जनता द्वारा न क्य किए जाँय दोनों में से जो कम होगा विकय करें। क्रय की दशा यह होगी कि केन्द्रीय अधि बन्धक बैंक इस स्विधा का साम के लिये यह बात स्वीकार करें कि वे एक वर्ष के खंडर सरकार श्रीर रिजय बैड हारा फिल का ही नहें बनराज़ि का कम से कम नगना जलाहक कार्यों के लिए क्रांश क्य में ब्याय करें। १९५३ प्रश्ने वेयल क्यांश के भीम सम्बद्ध बैंक की १७ साल रुप्ते की इस योजना के अंतर्शन सहायना ही गई थी। १९५५ के जुन के श्चान तक इस योजना के श्वन्तर्शत श्रामावशे के क्रय की वार्ते श्रांत्र, मदास. मेसर, श्रीर बावंकर की चीन के केन्द्रीय भक्ति बन्धक बैंकी से. जिन्होंने ऋणपत्र निर्मित किये थे, चलाई गई। मदास छोर छांछ सरकारों ने इस योजना की दशास्त्रों की स्वीकार कर लिया था। पर दिलवें बैंक से इसके क्षय में सहयोग माँगने की अगुपत्रों के जनता द्वारा श्रावश्यकता से श्राधिक हुए करने के कारण श्रावश्यकता नहीं पड़ी । मैसर और त्रावंकर कोचीन की सरकारों ने रिजर्व बैंक द्वारा उनके ऋण पत्रों के क्रय कर लिये जाने पर जोर नहीं हाता।

१९५५-५६ के अंत में यह बोजना समात्र हो गई जिसके चंतर्गत केन्टीय सरकार और रिजर्व बैक सम्मिलित रूप से केन्द्रीय भूमि बन्यक वैकों के ऋगुगुपत्री को खरीदती थीं। किन्तु अनुस्त्रापत्रों अप्राधित्य अंश या २०% में से जो भी कम हो रिजर्थ देंक द्वारा उसके योग दान की प्रथा चालू रहो। फरवरी १९५६ में राष्ट्रीय कृपि साल (दीर्घकालीन) कीच का निर्माण किया गया । इस कीप से लिये गये ऋष से राज्य सरकार भूमि बन्धक बैंकों की चालू पंजी मे योग दान कर सकती थीं।

प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों के सम्बन्ध में उसके ॥१'३५ करोष्ट रुपये की चालू पूँजी में ६.७६ करोड़ रुपया अर्थात् बुल का ८६% केन्द्रीय भूमि बन्धक वैक दारा अप रूप में प्राप्त हुआ था। इन बैकों के लिये यह तो अनिवार्य है कि वे भूरा पत्रों हारा बाजार से क्यया शाम करें तथा केन्द्रीय भूमि बन्चफ बैंको से उधार हों. फिर भी उनके व्यवसाय को स्थितता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी शैयर पॅजी तथा रिवत कीय बढाया जाय।

(४) सहकारी बैंकों की माँवि भूमि बन्धक बैंकों ने भी बहुत अधिक न्याज की दर पर ऋषा दिवा है। इसका एक कारण यह था कि केन्द्रीय बन्धक बैंकों में

ब्याज की दर बहुत श्रिषक थी। तृष्टा कारण यह या कि छोटे भूमि बन्धक वैकों ने स्वयं लाम प्राप्त करने के लिये भी अधिक न्याज लिया। इन सैंकों को कुपकों के लिये लाभदायक बनाने के लिए यह ब्यवस्था करनी पड़ेगी कि यह बैंक कम न्याज पर स्मृत्य लें अगेर अपनी न्याज की दर पटाएँ तथा आवस्यक गा पहने पर इन्हें सरकार भी शाधिक सहायता दे। इसके खाय ही यह भयक करना चाहिये कि इन अंकों का परिकुशलता वहें जिससे छोटे बैंकों ने न्याज में जो अतिरिक्त बृद्धि की है वह का हो जाय। इन वैं के का प्रश्न करना होगा जिससे स्थाज की हर में भी कमी की जा सके और जो कुछ व्यय लगाया गया है उसका जीवत लाम मार हो।

सुध।र-सन्बन्धी सुकाव

अपि बन्धक बेंकों का मदास में २३ वाँ सम्मेलन सम्पन्न हुन्ना जिसमें भूम बत्यक बैंकों के कार्य में सुधार करने के लिये अनेक सुकाव दिये गये। सम्मेलन में गर बताया गया कि बैंको ये पास पर्यास धन नहीं है. ऋगा देने में देर होती है. स्याज की दर बहुत श्रधिक है श्रीर देश के जुछ भागा में, विशेषकर मद्रास में. क्षि की स्थिति विगडने के कारण क्रपक आसानी से आया नहीं जुका पाता है और वैंको का आर वसनी का कार्य धीमा पड गया है। सम्मेलन मे इस बात पर भी प्रकाश जाला गया कि लो ऋगा लिया जाता है उसका उद्देश्य भूमि में सुधार करने की श्रपेका पराना ऋणा चढ़ाना रह गया है। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि बैक के पास जितना भी धन है उसका उपयोग इस रूप में करना चाहिये जिससे क्षपि उत्पादन बढे और किसानी को बचत करने में सहायता दी जाय ताकि वह भ्रपना पुराना भूगा चुका सकें । बचाप श्रव तक भूगा इस उदेश्य से भी दिया जातारहा है कि भूमि ख्रीर कृषि उत्पादन में सुधार हो परन्त इस बान पर श्राधिक जीर दिया गया है कि आहुणों से पुराने कर्ज को जुकाया जाय। इसका एक कारण यह है कि भूमि बन्धक वैंको का खारमा उस समय हुआ जब आधिक मदी के कारण कपक अगण के बोक्त से लंद गया था परन्त यह के सभय कपि की उपज के मूल्य में वृद्धि हो जाने से किसानों ने अपना बहुत कुछ श्रूण चुका दिया श्रीर यह समस्या श्रव किसी भी रूप में उतनी अभ्योर नहीं रह गई है जितनी कि बहु पहिले थी। वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उत्पा दन बढ़ाया जाय, सगठन में मुचार करके उत्पादन व्यय कम किया जाय शीर उत्पादन के साधनों में कुशलता प्राप्त की जाय । इसलिये भूमि बन्धक वैदों से दिये जाने वाले ऋण का अब यही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये। सम्मेलन में यह बताया गया कि वर्तमान ऋण देने की प्रणाली बृटिपूर्ण है। वर्तमान प्रणाली के श्रातुषार

मूख लेने वाले को दूधरा श्रीर तीसरा मृख श्रानुत्पादक कार्यों के लिये दिया जाता है श्रीर मृख की श्रांषकतम तथा न्यूनतम मात्रा मी निधत नहीं की जाती। यह स्थार २० वर्ष के श्रांद खुकार्य जा सकते है श्रीर उन पर ब्याज की वहीं दर लागू. भूस २० वर्ष के श्राद की बदा दर होती है। इपमें मुपार करने की श्रादश्य होती है जो मूल मृख के ब्याज की दर होती है। इपमें मुपार करने की श्रादश्य कार्त है — (श्र) दूसरे श्रोर तीसरे मृख की ब्याज की दर श्रांपिक होनी चाहिंग, कता है — (श्र) दूसरे श्रोर तीसरे मृख जा जिस्से भूमि से प्राप्त श्रांपिक श्रांप को स्थान कार्यों में लगाने से तीका जाय छके श्रीर उदका उपयोग मृख खुकाने में श्रान्य कार्यों में लगाने से रोका जाय छके श्रीर उदका उपयोग स्था चुकाने में श्रान्य कार्यों के श्रीर (श्र) मृख लेने के उदेश्य पर विशेष कर के स्थान देना व्याहिए।

वर्तमान समय में अधिक आवेदन पत्र आने के कारण, आवेदन पत्रों की वर्तमान समय में अधिक क्रमेंचारियों की कमी होने के कारण, श्रूप के सम्बन्ध जॉच करने के लिए शिक्ति कमंचारियों की कमी होने के कारण, श्रूप के सम्बन्ध में किशन को अधिक ज्ञान न होने और मालिको द्वारा आवश्यक कान जात है। इस्याद सावधानी से न रक्षा के कारण श्रूप देने में बहुत समय लगा जाता है। इस्याद सावधानी से न रक्षा के कारण श्रूप समेलन में यह मुक्ताब दिया गया कि इन किशाइयों को इल करने के लिए अमेलन में यह मुक्ताब दिया गया कि क्षा मान के किया गया है। इस पुत्तिका में स्थल करने के लिए ज्ञावश्यक है। पुत्तिका में श्रूप लेने की पूर्ण विभिन्न को प्रमुख के में उपयुक्त शिला मान कर्मचारी निमुक्त किये आग्र और मान्य खेलो जाय। वैक में उपयुक्त शिला मान कर्मचारी निमुक्त किये आग्र और मान्य खेलो जाय। वैक में उपयुक्त किये जाय जो की समुद्ध के सम्बन्ध में जनता को विभिन्न जानकारी दे सकें।

#### ऋध्याय १७

## ग्राम्य वित्त व्यवस्था

कृत्यक को अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्षकालिक ऋषा की आव-प्रयक्ता होती है। बीज, खाद, जारा इत्यादि क्रय करने के लिये यह अल्प-कालिक ऋषा लेता है, पणु तथा क्वांग के झीजार इत्यादि खरीइने के लिये यह अपकालिक ऋषा लेता है, और भूमि में रथाथी खुधार करने के लिये उने दीधका त्रयकात बनाने और कुएँ तथा इमारता का निर्माण करने के लिये उने दीधका लिक ऋषा जी आवश्यकता होती है परन्तु इव दिशा में वास्तविक किटिनार्थों यह हैं कि (१) कृत्यक निर्धन और निरक्तर है। कभी कभी तो ऋषा लेते के लिये यह आवश्यक जमानत भी नहीं दे पाता। साख के चेत्र में उसकी स्थिति प्रायः नगयय है, और (२) कृषक वाधारणाचा अभीदारी और महाजनों से ऋषा लेता रहा है, यह उसकी परम्पा रही है। परन्तु अब (अ) अभीदारी का उन्मुलन हो लोनों हो, (व) महाजनी में अनेक कान्सी प्रतिवन्ध लगा बाने से, जैसे लाइसेन्स तेना, तेला रखना, ब्याज को दर पर नियन्यल इत्यादि, और (स) महाजनी कार्य की एक प्रतिकृत समा। अध्य स्वति भी है तो बहुत कम।

कृपकों की सहायना के लिये तकाबी ऋष प्रशाली है, परन्तु यह प्रशाली लोकमिय नहीं हो पाई है क्योंकि (अ) तकाबी ऋष लेने में अनेक कारवाहर्यों करनी पक्ती है, (म) यह ऋषा विशेष कार्य के लिये दिया जाता है, और (प) ऋषा यसली में कोई रियायन नहीं दी जाती।

इस दिशा में बहकारी साख समितियो और भूमि बन्यक वेंको ने इन्छ प्रमति की है, परन्तु इनकी संस्था बहुत कम है, और महाननों तथा अमीदारों के आर्रिशक उन्मूलन से को अमाय हो अथा है उसको पूर्ण कर सकने के लिये यह संस्थाएँ न पर्याप्त हैं और न सुक्षादित । इसका परिणाम यह हुआ है कि इनक बड़ी किनादयों में अस्त दिलाई देते हैं। पिछले कुछ क्यों में इन्हिर उपन क मूल्य में बृद्धि टोने से इन्यक को वित्तीय स्थिति में कुछ सुध्या हुआ है। इस वृद्धि से इसक के दिलांग अमाय की आर्थिक पूर्ति तो हुई है, पर उमे और अधिक वित्त की आवश्यकता है। इनक के लिये यह दुष्यक है। पर्यात वित्त न होते से वह अपनी भूमि में आवश्यक सुधार नहीं कर पाता । इससे वह निर्धन रहता है और ऐसी स्पिति में रहकर क्लि भाष्त नहीं कर सकता । भारतीय कृपक की आर्थिण स्पिति मुधारने के लिये इस दुष्यक की समाप्त करना आवश्यक है। अस्म वेंक व्यवस्था खोच समिति—औ। प्रोपोचमदास टाकरदास की

अध्यक्तना में साम्य तैक दयवस्था जॉन्ड समिति ने १९५० ग्रास्य साख दयवस्था के पुनंसगठन के लिये विस्तृत सुकाव दिये हैं। ग्रामी की साख व्यवस्था को पर्नसग-दित करने के लिये समिति ने कल आधारमत सिद्धान्तों का प्रतिगादन किया है. (१) समिति का मत है कि आसीरण जनता की बचत को संबर्धत करने का कार्य श्रीर प्रामीण जनता को माख की मुखिया देने का कार्य प्रथक नहीं किया जा सकता । ये होती कार्य एक ही संस्था द्वारा किए जाने चाहियें। (२) वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बामों में आया इत्यादि देने के तिये उपयक्त सरपाओं की व्यवस्था को जाय । (३) देश के विभिन्न भागों में श्रारपकालिक श्रीर सध्यक्तालिक समाग देने की द्यवस्था करने के लिये एक ही प्रकार की संस्था से कार्य नहीं चल सकता है। व्यक्तेक सेत्र की अवसी स्थानीय विशिधारियों के श्चनसार उचित प्रकार की संस्था का निर्माण करना होगा और इस संस्था की सहकारिता के खिद्धान्ता के श्राधार पर संगठित करना होगा। (४) सरकार को अपूरा तथा भूमि सम्बन्धी कानून बनाते समय इस खोर ध्यान देना चाहिये कि इन कार्यों के लिये नई श्रीर उपयक्त संस्थार्य किसी गति से स्थापित की जा सकती हैं। इस प्रकार के निवासे का साल सस्थाओं पर जो प्रभाव पढ़े जसका सरकार को श्रध्ययन करना चाहिये।

सिति ने यह बताया कि देश में न्यापरिक वैंक व्यवस्था का महार हुआ, परन्तु हसके साथ ही उसने हस तथ्य की छोर भी संकेत किया कि न्यापरिक वैंक और विदेशकर अनुत्वित्व वैंक बड़े नगरों और करवों में केन्द्रित हैं। छोटे फरनो आप मान्य सेत्री में यह कार्य सहकारी वैंक, डाकखाने के सेविंग वैंक और गैर अनुसुवित वैंक चलाते हैं। सिति ने बताया कि स्वह् बरहों में, जिनमें भटर रायानों पर या तो जिने के प्रमान कार्याखा है या तालुका के, बैंक सम्बन्धी कीई सिवाय उपलब्ध नहीं थी।

दिमित ने मुक्ताव दिया कि यदावि व्यापारिक वैंकों की धाम्य चेत्रों में यपनी और अधिक शालारों स्थापित करने और स्थवशाय में उत्तरि करने के लिये प्रोताहन देने का प्रयत्न करना चाहिये परन्तु किर भी सम्पादना मही है कि मर्दमान परिस्थितियों में व्यापारिक बैंक सामुका या तहसील के प्रचान कार्यालगों, करमें, मंहियों और व्यापारिक तथा श्रीधोगिक महत्व के श्रन्य करमें के विवास अन्यत्र अपना प्रशार कम करेंगे। छोटे कस्बों में सहकारी बैंकों का विकास करने की आयरयकता है क्योंक (अ) उनका मामों की सहकारी समितियों से निष्ट सन्वत्म रहता है छोर (ब) उनके व्यवसाय का व्यय भी अपेक्षाकृत कम होता है। हो प्रामों में सहकारी समितियों और डाकखाने के सेविय बैंको की व्यवस्था

व्यापारिक बैंको की सहायता करने के लिये धमिति ने अनेक मुक्ताव दिये हैं, (१) सकते का निर्माण करके, आम-पातादात एवम् संचार के साधनी हा विकास करके, इन बैंको पर दुकान निर्माण निवम लागू न करके और रन्दें श्रीवीमिक पवन्यायालय के निर्माण निवम लागू न करके और रन्दें श्रीवीमिक पवन्यायालय के निर्माण निवम लागू न करके और रन्दें श्रीवीमिक पवन्यायालय के निर्माण निवम का सकते क्यापारिक वैंको का विकास करका वर्षा दिवान की सकते क्यापारिक वैंको का विकास कर सकते क्यापारिक वैंक तथा विज्ञान की स्वाच करके अमरण्य प्रीत्वाहन दिया लाव। इनको बढ़े तथा छोड़े कीप यह में अपना रुपना स्वच सुराण्य प्रीत्वाहन दिया लाव। इनको बढ़े तथा छोड़े कीप यह में अपना रुपना सुराण्य प्रत्याद वाच। वाच। इनको बढ़े तथा छोड़े कीप यह में अपना रुपना सुराण्य प्रत्याद वाच। वाच। इनको वेंको और सहस्वारी खाल सितियों को विदेश सहस्वारी वाच। तीत हन्दे नेशनल सेविया सर्दोकिकेट विकस का अधिकार दिया लाव और डाक्कान के सेविया वैंको और रह रूपना हण्या

प्रामों में सेनिया बैंक का कार्य करने वाले डाकखानों की समया में रृष्टि की जाय और उनके कार्य में सुधार करने का प्रयत्न किया जाय। सिमित के मतानुसार यह मान सेना गलात है कि मामों में काकी मात्रा में नकद बचत है। जिसे बैंकिंग की सिम्पाओं का प्रसार करके संग्रह किया जा सकता है।

दीर्वकालीन साख के लिय तीमीत ने यह मुकाव दिया कि जिस चित्रों में प्रारम्भिक तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक नहीं हैं वहाँ उन्हें स्थापित किया जाय। समिति ने देश भर क लिये एक केन्द्रीय कृषि साख कारपोरेशन की स्थापनां करने और वैंकों के प्रभार के लिये प्रोत्साहन देने के लिये नकद आर्थिक सहायता देने के अनेक प्रस्तायों को सिद्यान्तों के आवार पर और अनेक प्रसाधन सम्बन्धि किया। वर्तमान परिस्थियों में निचेष बीने को कांग्र करना और बड़े पैमाने पर चल बैंको की क्यंश्रमा करना उपयुक्त नहीं समझा गया।

समिति के प्रस्तानों की जालोचना—बाँन यमिति की उक्त योजना की ब्रालोचना करते हुये यह बताया गया है कि—(१) योजना में प्रामीण चेत्रों को विचीय सदायता देने की अपेका इस बात पर जीर दिया गया है कि प्रामीएरों की बचत को संग्रहीत किया जाय । ऐसा अतीत होता है कि प्रस्तावित व्यवस्था के जन्तर्गत पन एकव करने वालो संस्था अपने द्वारा संग्रहीत कीप में से स्थानीय जायोग के लिये कछ योगदान नहीं देगी और ऐसी स्थित में मामीश चेत्रों में च्यापारिक एवम सहकारी वैंकों के कार्य का प्रसार करने में यह आवश्यक नहीं शेमा । (२) समिति से टीर्घकालिक विसीय सहायता पर जोर दिया है परस्य पह समाय नहीं दिया है कि यह वित्तीय सहायता किन स्रोतों में श्रीर किस प्रकार प्राप्त की जाय। इसने केवल यह सम्बाव दिया है कि भूमि बन्धक वैक स्थापित किये जाँय । इस प्रकार के बेंकों की स्थापना करने में शनेक कठिनाइयाँ है शीर जहाँ यह स्थापित हो चके हैं वहाँ भी यह दोर्घकालिक वित्तीय सहायता यदि निसी केन्द्रीय कपि कार्पोरेशन से भूमि बन्धक बैंको द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त हो सके तो यह बहत उपयुक्त होगा । परन्तु कुछ कारणां से समिति ने केन्द्रीय कारपोरेशन स्थापित करने के विचार को अस्वीकृत कर दिया। (३) अल्पन किक विसीय सहायसा के लिये समिति ने सहकारी बैका को उपयुक्त साधन माना है, परन्तु समिति ने इस सम्बन्ध ये कोई सुमाय नहीं दिया है कि इन सहकारी संस्थाओं को सविष्य में किस प्रकार ऋधिक सफल बनाया जा सकता है। अखिल भारतीय मामीण साख सर्वेत्तरह-अखिल भारतीय ग्रामीण शाय

अखिला भारतीय मामीय साख खर्चे न्याय-अखिला भारतीय मामीय हाल सर्वे न्या, अथवा गीरवाला करेटी, ने माम्य अपं प्रवन्तन की दशा का विरहेतरा किया मा अध्या मारवाला करेटी, ने माम्य अपं प्रवन्तन की दशा का विरहेतरा किया मा अध्या है। अध्या अध्या की आवश्यकताओं की पूर्ण नी किया मारतीय क्रवक संतेषा क्या के अध्या अध्या की आवश्यकताओं के पूर्ण नी किया मारतीय क्रवक त्रीत क्या मामें में लिया जाता है अध्यक के कवल १% व्हकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है और २% से कुछ ही अध्यक सरकारों संस्थाओं है। अपनी आवश्यकता के १४% के लिये अपन भी मासवासियों को मामीय महानन और वाहकार के अपर निर्भर रहना पक्ता, अपवासि और अध्यासि और अध्यासि की किया वाहकार है। विमान हान और वाहकार के अध्या ने कार्य एक के लिये अपनी आवश्यकता पर स्था ने कुण है और न जिस दम से मिलता है पानि हम विभाव हम जिसका अध्यास श्रीर जीन प्रता में ही आवश्यकता अध्यार पूर्ण है और न जिस दम से मिलता है पानि के साम में की स्थान की अध्यान की उच्चे माम मां नहीं हो स्थान की उच्चे मान में ही अपने का स्थान की स्थान की उच्चे माम मां नहीं हो अपने की अध्यान के उच्चे मान चे मान है हमान वह से मान से हमान है हमान वह सी मान है कि सहसारी-स्था-आव्योक्त अपने निजी अथल क्षारा तो इसको की स्थान आवश्यकी की स्थान हमान है ने स्थान अपने निजी अथल क्षारा तो इसको की स्थान की स्थान अपने निजी अथल क्षारा तो इसको की हम्स की स्थान अपने निजी अथल क्षारा तो इसको की हम्स की

आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकता । समिति ने कहा कि भारत में प्राम्य ऋष् एमस्त देश की सजीव और विस्तृत समस्या का एक अश है । बिना उस स्टर्भ में उसे डीक-टीक समके सुलकाया नहीं जा सकता । उसकी सर्व विदित कडिनाई का केन्द्र प्राम ही है, पर उसके कालों और निराकरण के उपायों को अन्यत्र हूंद्रना होगा । इस प्रकार यह समस्या कंपल प्राम की हो समस्या नहीं है। प्रत्यन्न रूप संचा कर स्पृष्ण तेना है पर बास्तव से यह समस्या आर्थिक व्यवस्था की है, इसलिये बिस्तत आर्थिक कियाओं तथा रहेशों का यह एक अग है।

आलीचना—गोरवाला कसेटी ने सारतीय प्राप्य समस्याओं का डीकठीक विश्लपय किया और इस निर्माय एर ठीक ही पहुँची कि प्राप्त अपनी अप्रस् समस्या को बिना बाह्य सहारता के अपने आप मुलका नहीं कहते । सृतकाल में सुव्य और सहकारो श्रुप्य मुश्चिम पर दिया गया था। केहेटी का यह निक्कर्ष जब्ति ही था कि सहकारी श्रुप्य आत्योलन अपनी वर्तमान समय की स्थिति के अञ्चलार प्रामीया सनता की आवश्यकताओं को पूर्यों नहीं कर सकता। कहेटी का यह प्रस्ताव भी बहुत ही श्लावनीय है कि श्रुप्य समस्या के मुलकात को योकना को स्थम्यूष्ट कर से लेना चाहिये और साख तथा अप्य आर्थिक कियाओं को एक साथ कार्यान्तित करना चाहिये और साख तथा अप्य आर्थिक कियाओं को एक साथ कार्यान्तित करना चाहिये और साख तथा अप्य आर्थिक कियाओं को एक साथ कार्यान्तित करना चाहिये और तथा साथ अपि कमेटी ने अधिकाधिक सरकारी सहयोग की शिकारिया की है, पर उन्हें हथ बात की आर्थिका न दुर्थ के इसके सनता सरकारी सहायता पर आवश्यकता से अधिक निर्मार रहने की आर्री हो नायभी और उनकी निर्मासा सरकार के हर स्तार पर सहयोग देने से धीर-धीरे लुत हा नायभी। (२) कमेटी ने इस्पीरियल नैंक आफ इंक्श्वा के राष्ट्रीय- कारण की श्रीर श्रामों में साधारण मैंकों के विस्तार की शिक्षारिय की पर उनका इस बात की श्रीर भ्यान नहीं गया कि यह तभी सफल हो सकता है जय आमीश जनता की वैंकों के श्रमेश करने की श्राहत पर जाय, जिसकी निकट मंत्रिक्ष में तो कोई सम्मायना नहीं दिखाई पटनी। जिना इस श्राहत के स्टेट केंक श्राफ्त इंडिया की जो शालायें आमों में लोली जाँयगी ने नैकों को होनि ही गर्डे चारेंगी श्रीर कार्य के लो होनि ही गर्डे चारेंगी श्रीर कार्य कुछ न हो सकेशा; श्रीर (३) कमेटी द्वारा रह को हानि होनी श्रीर कार्य कुछ न हो सकेशा; श्रीर (३) कमेटी द्वारा सरकारों सहयोग श्रीर आर्थिक सहयता से श्राम्य श्रीर सहया कार्य है सुत्रका से स्टें है हतनी नगरण है कि समक सीजना की नहीं की जा सकती। यह समस्या इतनी विशाल है श्रीर सरकारी श्राधिक सहायता जो इस कार्य के लिये नियस की गई है हतनी नगरण है कि समक योजना की बड़ी बड़ी बातों के होते हुये भी घोड़ी सी भी सफलता प्राप्त करने में श्रीहत समस्य में में, जब कि वे उनके स्थान पर दूसरी सुविधा प्रदान करने में श्रीसना करने में, जब कि वे उनके स्थान पर दूसरी सुविधा प्रदान करने में श्रीसना क ही होती तो स्थित हतनी निरायक्ष कर ने होती।

योजना के फान्सर्गत—एवं प्रथम कार्य हम्गीरियल वैंक माज हिंडया को प्रथम मुलाहे १८५५ से राष्ट्रीय करण करके स्टेट वैंक म्राफ हिंडया को समित करके किया गया। प्राप्य अधिकोपण जींच कमेटी ने हम्मीरियल वैंक की समिति करके किया गया। प्राप्य अधिकोपण जींच कमेटी ने हम्मीरियल वैंक की १५५ नई शाखाओं के लोलने का सुकाव ११५ नई शाखाओं के लोलने के लिये प्रस्तुत हुआ था। जब से स्टेट वैंक माज हिंडया का बन्म हुआ है, नबीन शाखाओं के लोलने की जाति में वृद्धि हुई है। स्टेट वैंक माज इंडिया के लिये माज के प्रथम नोच वर्षों के फीतर स्वाप्य के माज के प्रथम नोच वर्षों के भीतर स्वाप्य हमाज के प्रथम नाच वर्षों के भीतर स्वाप्य के स्वत्य तथा हमाज के प्रथम नाच वर्षों के भीतर स्वाप्य के स्वत्य तथा हमाज के प्रथम नाच वर्षों के भीतर स्वाप्य के स्वत्य तथा हमाज के प्रथम नाच वर्षों के भीतर स्वाप्य के स्वत्य तथा हमाज के प्रथम नाच वर्षों के भीतर स्वाप्य के स्वत्य तथा हमाज के प्रथम नाच के प्रयन्ता स्वाप्य के स्वत्य तथा हमाज के प्रथम नाच के प्रयन्ता स्वाप्य के स्वत्य तथा हमाज के स्वाप्य नाच के स्वत्य तथा स्वाप्य के स्वत्य तथा हमाज के स्वाप्य के स्वत्य तथा स्वाप्य के स्वत्य तथा हमाज के स्वत्य नाच के स्वत्य तथा स्वाप्य के स्वत्य तथा स्वाप्य के स्वत्य तथा स्वाप्य के स्वत्य नाच के स्वत्य तथा स्वाप्य के स्वत्य नाच स्वाप्य के स्वत्य तथा स्वाप्य के स्वत्य तथा स्वाप्य के स्वत्य नाच स्वाप्य के स्वत्य नाच स्वाप्य के स्वत्य स्वाप्य के स्वत्य नाच स्वाप्य स्वाप्य के स्वत्य स्वाप्य के स्वत्य स्वाप्य के स्वत्य स्वाप्य स्वाप्य के स्वत्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य के स्वत्य स्वाप्य स्वप्य स्वाप्य स्वाप स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य

श्राजिल भारतीय ग्रामीण चाल वर्षेत्रण चिमित के श्रामिताची के श्रानुवार हितीय पंचवर्यीय योजना के श्रम्तर्येत श्राह्म कालिक, मध्य कालिक, तथा दीर्घ-कालिक मुद्रण मुस्रियाओं के सम्बन्ध ये निम्चित किये हुये व्येय प्रथम योजना के व्येयों की श्रम्या वृत्ति केंचे नियत किये यथे हैं जैया कि निम्न तालिका से प्रकट होता है।

द्वितीय योजना
के स्येय
१५० करोड़ ६०
५० करोड़ ६०
२५ करोड़ ६०

हमसे यह स्पष्ट है कि द्यालिल भारतीय जामीण साल सर्वेत्सण प्रामीण साख समस्या के प्रति जनता का ध्येय शाकपित करने में सफल हशा है। प्रामीण साख सर्वेत्तरा द्वारा प्रस्तावित पर्नसंगठन की योजना की दसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सारा तथा गैर साख समितियों को एक दसरे से सम्बद्ध कर देने की सिफारिश की ताकि कपक को अग्रस. बीज. खाट. कृषि सम्बन्धी श्रीजार तथा धावण्यक जयभोग की सामग्री प्राप्त हो मके और जुने जपनी जलकि को बाजर में लेजाकर विक्रय करने में भी सविधार्थ किल सकें। कार्यों के सोचे हये विस्तार के अनुसन बामीस सास सर्वेज्ञस ने यह भी सिफारिश की कि ब्राम में वर्तमान कोटी छोटी समितियों को मिलाकर बक्ते समितियों में परिज्ञित कर देना चाहिये वाकि वे अनेक ग्रामों के समह की सेवा कर सकें ग्रीर ये पहिले पहिले बनाई जाते वालां बड़ी समितियों की रूप रेखा वही हो जो सर्वेद्यण ने प्रस्तावित की है। पैसी वड़ी समितियों की सामान्य रूप रेखा कछ इस दगकी होगी कि उसके सदस्य संख्या में सरामा ४०० तक होंगे और छत्येक सदस्य का उत्तरदायित अनेके द्वारा जमा की हुई पूँजी के द्वाब्यिक मुख्य के पाँच गुने तक सीमित होगा। समिति की न्यननम शेयर पंजी लगभग १५००० ६० के होगी श्रीर वह एक उपयक्त संख्या में ग्रामी की जो एक समह के अन्तर्गत रख दिये जाँयेंगे सेवा करेती और जो यथासम्भव प्रतिवर्धं लगभग १% लाख रुपये का क्टबसाय करके हिलायेगी। ऐसा मस्ताय किया गया है कि १९६०-६१ नक १०,४०० ऐसी बड़ी समितियाँ जिनके प्रवन्धक प्रशिक्ति होंगे स्थापित हो जानी चाहिये।

सरकार को सहकारिता में सहयोग दे सकते में सुविधा प्रदान करने के विचार से रिवर्ष थें के ने एक राष्ट्रीय-कृषि-साख (दीर्ध कालीन) कोप की स्थापना १० करोड करने के है । कितीय याजना काल में प्रतिवर्ध ५ करोड़ करने का खादान दिया जायमा जाकि १६६०-६१ तक कोप में १५ करोड़ करया हो जाय । इस कोप से राह्य ने एक मुखरीन हिसा से स्थापना कि वे सहकारी संस्थाओं की शेयर पूँची क्य कर कर । एक नृत्यरे कोच की भी, जिसका कि नाम राष्ट्रीय सर्व कर पर्व । एक नृत्यरे कोच की भी, जिसका कि नाम राष्ट्रीय सर्व कर करों । एक कृत्यरे कोच की भी, जिसका कि नाम राष्ट्रीय सर्व कर्मी विकास कोप होगा, केन्द्रीय सरकार हारा स्थापना की जायगी। इस कोप से राज्य-सरकार में ने स्थापना की जायगी। इस कोप से सर्व सर्व में से स्थापना की कोप में से सरकार स्थापना को बहुन पर कार कोप में सर्व सरकार विवास कोप से सरकार स्थापना को बहुन स्थापन के किये स्थापन को सह नाम सरकार स्थापना के कार क्या कर करने पर क्या तथा सरकारी विभागों के प्रशासन को हह नाम सर क्या कर ने के लिये हारिक सरवायना हो बायगी।

मारहागार, सास समितियों तथा गैर साग समितियों के दीच एक महत्त-पूर्ण संस्थागत कड़ी के रूप में होगे । प्रायम्बिक विजी समितियों और सुरुपनस्थित साल समितियों को अधिक संख्या में भोडाम बनवाने होंगे । मामीण साल सर्वेन्नण के सुकाय के श्रमुकल ही यह प्रस्ताव किया गया है कि एक केन्द्रीय भागडागार-निराम की स्थापना की जाय और प्रत्येक प्रदेश में भी उसी प्रकार भारहागार-जिल्हा का कि किये और 1 से जिल्हा सकीय सहकारी विकास तथा भागडागार बोर्ड के निर्देशन में कार्य करेंगे। एक प्रदेश के माग्डागार निगम की श्राधिकत पूँ जी २ करोड़ रुपये तक अनुमानित की गई है पर निर्धार्मत पूँ जी विभिन्न राज्यों को उनको आवश्यकता के अनुकल होगी।यह प्रस्ताव किया गया है कि केन्द्रीय भागडागार निगम द्वारा आची पूँ जो और शेव आघी प्रादेशिक सरकार द्वारा क्रय की जानी चाहिये। यह श्राशा की जाती है कि १६ साएडागार निगम Futura किये जायेंगे चोर वितीय पंचवर्णीय शोजना में २५० भारडामार विभिन्न देखों में स्थापित किये जायेंगे, जिनकी माल मर्राज्य रखने की शक्ति लगमग लाख उन होगी। भागद्यागारों की स्थापना के लिये उपयक्त केन्द्रों की खोज की जा रही है। ऐसी आजा की जाती है कि केन्द्रीय भारहागार निगम की कल पाँची १० करोड रुपये के लगभग होगी जिसमें से केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय विकास तथा भागडागार बोर्ड द्वारा 😪 करोड क्येये तक के शेयर सम्भवतः कर कर ले और शेष पूँ जी स्टेट बैंक आफ इन्डिया, अनुस्चित बैकी, तथा सहकारी संस्थाश्ची द्वारा क्य की जाय । केन्द्रीय भाग्रहागार निगम से यह श्चाशा की जानी है कि वह मख्य मख्य केन्द्रों में १०० वहे मायदागार स्थापित करेगा । भायहासार रहीरों को क्रय-विकय योग्य ( negotiable ) माना जायगा, जिसकी जमानत पर ख्रांचकोषण संस्थायें उन व्यक्तियां को आण दे सकेंगी जिन्होंने भागडागारों में कपि उत्पत्ति समा की है। 155

सहकारी साल, विकी, विवायन तथा भागडागारी इत्यादि के सम्बन्ध में

दिलीय पंचवर्षीय योजना के श्रान्तर्शत सख्य ध्येय निम्न हैं।

### साख

बड़ी समितियों की संख्या	80800
अरुपकालीन अपूर्ण की मात्रा का ध्येय	१५० करोड ६०
मध्यकालीन ऋग की मात्रा का ध्येय	५० करोड़ ६०
दीर्घकालीन ऋण की मात्रा का ध्येय	२५ करोड ६०

#### विक्री तथा विधायन

•	date talatidat		
	प्रारम्भिक विकी	समितियाँ जिनकी व्यवस्था की आयगी	१८००
	सहकारी चीनी	कारकाते	3'2

सम्बन्धी विपन्नों का रिजर्व बैक द्वारा पूर्व प्रायश्च नियमानुकूल कर दिया गया है जीर इस बात की भी अनुभति दे दी गई है कि स्वीकृत घरेलू उद्योग तथा छोटे उद्योगों को उत्पादन में नथा उनके माल के विकय में आर्थिक सहायता पहुँचा

१६५२ से भारतीय रिवर्व वैंक ने फसल की विक्री के लिए सहकारी संस्थाओं को वैंक दर से एक प्रतिशत कम व्याज की दर पर विचीय सहायता दी है। १६५४ में इसके अम्तर्गत फसल कोने, काटने, बेचने इस्पादि का कारोबार भी समितित कर लिया गया। १६५६ में व्याज की दर में बैक दर में एक प्रतिशत संबद्धाकर केंद्र प्रतिशत कमी कर दी गई है। वैंक के व्याज की दर में ३ प्रतिशत से बढ़ाकर केंद्र प्रतिशत कमी कर दी गई है। वैंक के व्याज की दर में ३ प्रतिशत से इद्देश मिश्रात वर्ष के प्रतिशत कम कर दी गई है। वैंक क्यां की दर पर ही सहायता दी, यह दर अब २ प्रतिशत कम कर दी गई है।

रिजर्ब बैंक ने सहकारी बेंकों को कुछ अन्य द्विष्याएँ प्रदान की हैं। परके सहकारी बैंकों को सभी आर्ख प्रति वर्ष ३० सितम्बर तक चुकाने पकते ये। इससे यहकारी बैंकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। रिजर्ब बैंक ने अब यह निरंपय किया है कि सहकारी बैंकों द्वारा लिए गए ऋख अपनी पूरी अविधि के बाद भी चुकारे का सकते हैं एक्स इसी यह यह ते लाग दी गई है कि किसी भी समय इस वैंकों के पास कुछ सेप अहब उस वर्ष के लिए निर्मारित सास सीमा के स्विध है । अब सरकारी वैंकों को एक और सुविधा दी गई है। अब सरकारी वैंक रिजर्ब बैंक दाश निर्मारित सास सीमा को बद्धा भी सकते हैं, यह बैंक आर्थ की इस रकता को आप अपनी सुविधानुसार से सकते हैं और उसका ग्रासान कर से इस करने के अब अपनी सुविधानुसार से स्वत्य के सीर उसका ग्रासान कर सहते हैं कैस अप का स्वर्थ के साथ किया जाता है। पढ़ते यह स्थित यी कि आर्या को निर्मारित अया के साथ किया जाता है। पढ़ते यह स्थित यी कि आर्या को निर्मारित अयाध में चुकाने के पश्चात पुनः उसी वर्ष मिना रिजर्थ बैंक की अद्यक्ति के नया अर्थ साथ विवा जा सकता था परन्त अब किसी वर्ष की अर्थ को निर्मारित रक्ष के बराबर उपयोग में इस अर्थ मिना सी अर्थ को निर्मारित रक्ष के बराबर उपयोग में इस अर्थ मिना की अर्थ का निर्मारित प्रका के बराबर उपयोग में इस अर्थ मिना सी अर्थ को निर्मारित प्रका के बराबर उपयोग में इस अर्थ मिना की स्वायर का निर्मार सी दी है।

ग्राम्य कैंक व्यवस्था जाँच समिति की किकारिश पर रिवर्ष कैंक ने विचीय महायता देने के सम्बन्ध में सुविधाएँ बहायाँ और १ कितम्बर १९५१ ते कमीयन में ५० प्रतियत कभी कर दी हैं। वैका कपर बताया गया है रिवर्ष कैंक ने राष्ट्रीय कृष सम्बन्धी शास कीय की स्थापना की है। इस स्थाप से राव्य परकारों को दीर्पकालीन मुख्य दिया वापया जियकी बहायता से वे सहकारी सास संस्थाओं की शेवर पूँजी क्रम बरने में बोगदान दें। १९५६ में रिजर्ष बैंक ने राष्ट्रीय कृषि सास

भागतीय सर्वेज्ञास की समस्याएँ 240

सरकार को ऋण तथा ह्याधिक सहायता देने का है।

श्रीधनियम भी १९५६ में पास किया गया और उसके श्रन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास ख्रीर मारङागार बोर्ड १ सितम्बर १९५६ में स्थापित किया गया। "बोर्ड के अन्तर्गत दो कोव हैं, (१) राष्ट्रीय सहकारी विकास कीय तथा (२) राष्ट्रीय भारदागार विकास कोए। पहले कोए का उद्देश्य राज्य सरकारों को आए और आर्थिक सहायता देना है ताकि वे सहकारी समितियों की हिस्सा पँजी में भाग से छ हे पा अन्य प्रकार से उनके अर्थ प्रवन्यन में मदद कर सकें। दूसरे कीप का

(स्थायित्व) कोष स्थापित किया । कृषि उत्पत्ति (विकास श्रीर भागडागार) निगम

उद्देश्य (१) केन्द्रीय भारडागार निगम की हिस्सा पूँजी में भाग क्षेत्रे, (२) राष्य सरकारों के राज्यीय भारतामार निगमों को हिस्सा पूजी में भाग लेने तथा (३) क्षि उन्नति के संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिये भागडागार निगम अथवा राज्य

## अध्याय १८ कपि नियोजन

भारत को प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ने कृषि नियोजन धर विशेष महत्व दिवा था। प्रथम योजना के अन्वर्णत रहध्द करोक रूपये के कुल व्यय में से १५.१% (१५७ करोक रुप) के जिल व्याय समुदायिक विकास योजनाओं, तथा रूप १% (६६१ करोक रुप) सिवाई तथा विजय याकि योजनाओं पर ज्यय के लिये निर्धाचत कर दिये गये थे। हितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि नियोजन का स्थान महत्त्वपूर्ण है, पर अधिक जोर औद्योगिक विकास पर दिया गया थे। । इस प्रकार अपम योजना में जो असंत्रितिक विकास पर या गया था उसे दूर कर दिया गया है। हितीय योजना में विकास सम्बन्ध ४५०० करोड़ अपने के कुल व्यय में के कृषि तथा साम प्राप्त वास्त्रितिक विकास योजनाओं को ११% (६१६ करोड़ स्थये) और विचाई तथा शक्ति योजनाओं को ११% (६१६ करोड़ स्थये) की

प्रथम योजना में कृषि पर विशेष महत्व देने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने दो तक दिये ये--(१) जा योजनाएँ प्रचलित है उनको पर्या करने की खावश्य-कता है और (२) जब तक खादाल का और उद्योगी के लिये आवश्यक खनिज्ञ पदाधों का पर्याम जल्पादन नहीं कर लिया जाता औद्योगिक विकास के कार्यक्रम में विशेष प्रशति ला सकता सम्मय नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि उसोंगों का विकास करने के लिये खनिज पदायों और खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। ग्रांट ग्रह सामग्रियाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाँय तो भारतीय उद्योग की विकसित करने में निश्चय ही सहायता मिल सकती है। इसके साथडी भारत की खांचकांज जनता कृषि कार्य करती है। कृषि में सुधार करने से इनकी आय में वृद्धि होशी श्रीर परिवास स्वरूप रहन सहन में संचार होगा। परन्त इसमें पर भी योजना श्चायोग द्वारा कांव को प्रधानता दिये जाने की कही आलोचना की गई थी। भारत की श्रायिक व्यवस्था श्रासन्तित है, क्योंकि उद्योगों का विकास करने की पूर्ण सम्मावना होते हुये भी अब तक उचीन पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हैं। इस तहत की क्रोप श्यान न देकर निरन्तर इस बात पर महत्व दिया जा रहा है कि कृषि का विकास करने की विशोष श्रावश्यकता है। पंचवर्षीय योजना के पूर्ण हो जाने पर इस असंतुत्तित व्यवस्था के दूर होने की सम्भावना नहीं है। वास्तव में

सम्भावना में इस बात की है कि योजना के परिशास स्वरूप यह व्यवस्था हटुतर हो जायगी। यदि पञ्चवर्षीय योजना निर्माण करते समय उद्योगों पर ऋषिक स्थान दिया गया होता तो इस दोव के दूर हो सकने की आशा थी और भारत का और श्रधिक सन्तुलित विकास हो सकता था । यदि योजना आयोग उद्योगों के विकास पर महत्व देता तो इससे कांध के विकास की समस्ति व्यवस्था करने में उसकी किसी बाघा का सामना नहीं करना पड़ता। दसरे, यह बिल्कल सहीं है कि भविष्य में श्रीयोगिक विकास करने के लिए इट आधार का निर्मास किया जाप परस्तु इस बात पर कैसे विश्वास कर लिया जाय कि भारत की कृषि का पूर्ण विकास हो जाने के पश्चात् उद्योगों का इस स्तर तक विकास कर लिया आयगा कि उसने उस समय उत्पादित कब्चे माल श्रीर निजली इत्यादि का पूर्ण उपमोग हो सकेगा । यह बहुत सम्भव है कि उस समय तक अन्य देशों के उद्योग अधिक शक्ति शाली हो जार्येंगे ग्रीर भारतीय उद्योग के लिये नदीन समस्याएँ उत्पन्न कर दें। योजना आयोग उचोगों का और अधिक विकास करने और भारतीय कृषि से उपलब्ध न हो सकने पर लायास तथा कक्चे माल का आधात करने की व्यवस्था कर सकता था जैसे जापान क्रीर ब्रिटेन ने किया। यदि उद्योग क्रीर क्रांप दोनों का साथ साथ विकास किया जाय तो भारत का आर्थिक विकास और आधिक सन्तु लित ही जायगा झौर उद्योग तथा कृषि के विकास का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव हो जायगा। योजनामें कृषि पर आयश्यकता से अधिक महत्व दिये जाने से इति तथा उद्योग के विकास में सन्तुलन स्थापित कर उनका सुनियोगित विकास करने में बाधा पहुँचेगी जब कि नियोजन का ब्राधार ही सन्द्रालित ग्रीर क्रम बद्द विकास करना है।

प्रथम पोजना— प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की सर्वतीम्मुली उन्नित का प्रवस्य किया गया था। उन्नके अन्तर्गत कृषि उत्यन्ति के अतिरिक्त पशु-मुपार, स्वकारी आदिकत का विकास, गव्यशाला, वन, भूम संरक्षण तथा प्रवादि के किला अपि सुधार की योजनाएँ सम्मितित थी। भारत नो केवल काशानों और उद्योगों के लिये कच्चे माल के उत्पादन में ही आप निभेर बनाने पर विशेष प्रथम नहीं दिया गया था, वरन आमील जनता के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादन में भी वृद्धि करने का रिचार किया गया था। प्रथम योजना में कृषि वथा समुद्रिक किता योजनाओं पर व्यव व्यक्ति की साले ने सुक करीन वसले देश करीन क्यों के स्तर की उत्पाद की साले साले किया की सुक्त करीन तथा प्राप्त योजनाओं पर व्यव माने की साले करीन करी सुक्ति स्वर्ण साले प्रयास अभी पर स्वर्ण स्वर्ण

स्पातीय सुपार कार्यों पर, ११ करोड़ आस पंचायतों पर, १० करोड़ वर्नो पर, ४ करोड़ मह्नली पकड़ने के कार्यों पर, ७ करोड़ सहकारिता पर और १ करोड़ रुपये अन्य बातों पर क्यर करने के लिये नियत किये गये थे।

प्रथम योजना का सिंचाई सम्बन्धी तथा विद्यत शक्ति के विकास का कार्यक्रम बहुत ही विश्वद था। यह कार्यक्रम उन योजनाओं पर आधारित था जो थोजना के पूर्व से ही प्रचलित थीं। योजना में इन योजनाओं को आगे बदाने का प्रबन्ध किया गया था। परन्त इनकी संख्या इतनी आधिक थी कि सम्पर्ण योज-नाचा को एक साथ नहीं लिया जा सकता था। इसलिये यह निर्णय किया गया कि कीसी, कीयना, कुठ्या, चम्बल और रिहम्ड योजनाओं की योजना काल के श्चंतिम भाग में लिया जायगा । ६६१ करोड क्यों के कल क्यम में से उद्धार करोड सिंचाई के लिये, २६० करोड़ विशत योजना के लिये और १७ करोड़ बाह निर्मेश्वम तथा करूव कोज कार्यों के किये जियत किये गये । प्रथम योजना का लक्ष्य सोंची जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल ५१० लाख एकड से. जो कि १६५०-५१ में या, बढ़ा कर ६७० लाख एकड़ १६५५-५६ तक करने का और विद्यात शक्ति का उत्पादन २३ लाख किलोबाट से बढाकर ३४ लाख किलोबाट कर दैने का था। यदि इस विकास योजना को दीर्घ कालीन इब्दि से देखा नाय तो यह आशा की जा सकती थी कि २० वर्षों के अन्तर्रात हो ४०० लाख ने लगाकर ४५० लाख एक इ तक अतिरिक्त भीम शिवाई के अंतर्गन आ जायगी और वर्तभान विद्यत शक्ति की मात्रा जो उत्पादित की जा रही है उसमे ७० लाख किलोबाट की और श्रीपक वृद्धि हो आयमी। यह कार्यक्रम का बढ़ा ही श्रेष्ठ शादर्श है और यदि पूर्ण हो गया तो भारतीय मान्य व्याधिक व्यवस्था की रूप रेखा चटल जायगी।

प्रथम योजना में कृषि नियोजन की ठीन प्रमुख विशेषताएँ थीं—(१) वम्यूर्ण कार्य केवल राज्य सरकारों द्वारा संवाजित किया जाश्या और उद्योगों के विपरीत निजी न्यवस्थाय का इसमें कुछ हाथ नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि ह्व प्रश्न के कार्य में काड़ी दीये अविष के प्रश्नात् लाग अवित कियों में निजी उद्योग हर प्रश्न के रूप में दुरन्त लागोश प्राप्त नहीं होता। विश्वत वर्षों में निजी उद्योग इस प्रकार के कार्यों से प्रची अपने अर्थोंग ने इस कार्य का उत्यालन करने के लिये निजी उद्योगों को उपयुक्त साथन नहीं समक्ता। आयोग को निजी उद्योगों की कार्यवस्थान पर निश्चास नहीं हो सकता। विश्वत व्योजना के अनुवार राज्य सरकार विभिन्न राज्यों के इस कार्य में उत्योजना करायों का प्रकार करियों और केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के इस कार्य में उत्योजना कर स्वस्था स्वस्था करेगी और केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के इस कार्य में उत्योजना कर सरकार स्वस्था करी हो हो कार्य में उत्योजना कर सरवालन स्वस्था सरवायित करेगी तथा अन्य स्वायन्य स्वायन्त स्वार्थ (१) दीर्थकालीन योजनाओं पर

विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार की योजनाओं से होने वाले साम का अनुमन १५ से २० वर्ष के पश्चात् किया जा सकेगा जब कि भारत की हार्षि का पूर्ण विकास हो चुकंगा। यदापि दीएंकालीन योजनाओं पर महत्व दिया गया है, फिर भी अस्पत्व को अपाय के लिये आवश्यक रूप्पे माल के जतादन में यहि करते भी अस्पत्व स्वत्यक्षा की गई है। जैसा कि 'क्वा' उत्पादन में यहि करते भी अस्पत्व स्वत्यक्षा की गई है। जैसा कि 'क्वा' उत्पादन और नीति' शार्षिक अध्याय में बताया गया है, यह आद्या की गतारी है कि लावाफ के सम्बन्ध में भारत को योजना की अविधि में ही स्वावत्यभी बनाय जा सकेगा और कपास तथा जुड़ के सम्बन्ध में मारत की विदेशों पर निर्मरता के कम किया जा सकेगा; (१) इस योजना का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन में यहि हो नहीं बहित अम्बन्धिन का पहल्ली विकास में करता है।

द्वितीय योजना—मयम योजना का स्रभाव द्वितीय योजना में पूर्ण कर दिया गया श्रोर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया है, जो कि स्यायपूर्ण स्थीर उद्यात था। इनसे भारत के बिकाल की स्रवप्तित स्ववस्था सुघर जायगी श्रीर राष्ट्राय आप में स्वधिक तीत्र गित ते वृद्धि हों भी श्रीर कार्य करने के अधिक स्ववस्था माह से एक्सेंगे। द्वितीय योजना के स्वत्यर्गत ४८०० करोड़ क्यारों के विकाल कार्य क्रमी पर नियत क्या में से १८५% उद्योगों श्रीर खान खोदने पर, २८-१% तथा यातायात पर, ११९८% (६१६ करोड कर) कृषि तथा सामुदायिक विकाल पर, श्रीर १६% (६१६ करोड कप्ये) विवाद तथा विद्युत याक्ति के उत्पादन पर पर क्या जायमा। यदावि द्वितीय योजना में उद्योगों श्रीर यातायात के स्विक महत्वा दी गई है पर कृषि तथा विवाद को छोड़ नहीं दिया गया है। द्वितीय योजना में किस विवाद स्वातीय योजना से किस विवाद स्वातीय स्वत

(ब्र) कृषि मुचार सम्बन्धी कार्य क्रमी से यह आशा की जाती है कि वहीं
कुई जनस्वा के तिये पर्यात खाय समग्री तथा विकित उद्योग क्यवस्था के
तिये कवा माल दे सर्वेंगे और हतनी कृषि उत्यक्ति वच रहेगी कि उसका निर्वात
मी किया जा स्केगा। इसिलाये यह कहा जा सकता है कि हितीय योजना मे प्रमान
मोजना की अपेता कृषि जासा अन्य उद्योगों के जिकान कार्यम्म में आपिक पारदररिक निर्मारता का आयोजन किया गया है। इन ध्येयों को प्राप्त करने के कार्यक्रमी नी निर्माया करते समय दीर्थकालीन हिस्छोख रखना आवश्यक है ताकि
मीतिक सावनी और मानव अम का सर्वोत्तमयोग, कृषि का सर्वतीमुखी सर्वाति विकास, आर माम वास्यि की आय में तथा रहन-सहन के स्तर में प्रसाक स्व

जाय जिसे प्राप्त करने में वे प्रयक्षशील हो सर्के । द्वितीय योजना निर्माख् के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि यह ज्ञादर्श १० वर्ष के अन्तर्गत ही उत्पादन की जिसमें काशास, तिलहन, कपास, गसा, पशु पालन से प्राप्त वस्तुएँ इत्यादि सम्मिलित

 (इ) कृषि उत्पत्ति को श्रानेक-रूपता प्रदान करना खोर खादाल सम्बन्धी गी दगनी कर देशा। हमलों को ग्रव तक जा प्रधानता हो जाती थी उसे बदलना आदर्श होगा। दितीय

अपना मा अनु पूर्व के विश्व में हैं जैसे खुगहों, नारिवल, लाख, काली मिर्च, भणा । पुरा १७५० । १०५ । १०५ व उपाय के साम के स्वीति विशेष व्यान नही दिया या ।

। रूप्ताम विपन्ना अरू कर कार्या तकार प्रकार कार्या है। (त) हांप के सेत्रकल की होंद्र करने की सम्मायना तो बहुत सीमत है। (०) हमान में अनुकार के चेत्रफल में सम्भव होगी उससे मीटे झह के ही जो बोडी बहुत वृद्धि हिन्दि के चेत्रफल में सम्भव होगी उससे मीटे झह के ही भा पार्था पुरुष होता । प्रश्निक संस्थित अप्रथ में दृदि होती चलेगी वैदे-उत्पादम में दृदि की जा छलेगी। जैसे-जैसे राष्ट्रीय आय में दृदि होती चलेगी वैदे-जाना न कार किया है। बैसे मोटे अन्न की माँग गेहूँ और चावल की माँग में बदल ही जायगी। ऐसी स्थित में कृषि उत्पत्ति में वृक्षि का सुख्य स्रोत स्राधक कुशल, लामटायक तथा

्रा प्रस्ताः । द्वितीय योजना के श्रन्तगैत कृषि नियोजन की सुब्य विशेषताएँ निम्न धनी खेती ही होगा। हु-(१) सूचि के प्रयोग का नियोजन; (२) दीर्थकासीन और श्रव्यकासीन तहरों < प्रभाव करनाः (३) उत्पादन लक्ष्मी तथा भूमि प्रयोग योजनाश्री को एक दूसरे से समझ कर देना; और (४) उपयुक्त मूहण नीवि का निर्धारण करना ।

चन्त्रव पर पराह जार १९/ जाउन के इसमें के इसमें से १७० करोड़ समये कृषि कार्यक्रमी पर, २०० करोड़ क्यये राष्ट्रीय विस्तार योजनात्री पर, ५६ करोड़ वर्षे पशुपालन पर, ४७ करोड़ क्ष्ये बनी और भूमि संरक्षण पर, १५ करोड क्ष्ये रथानीय विकास वर, १२ करोड़ करवे वंचायतो वर, १२ करोड़ करवे महत्ती पक-क्षेत्र क्षत्रवस्याय पर्<sub>ष</sub> ४७ करोड क्ष्ये सहकारिता पर (अवक अस्तर्गत आयडाचार क्या विकास सुविवार्ये भी समिलित होंगी, श्रीर ६ करोड क्यरे श्रम्य विविध बार्ती पर व्यय किये बायेंगे। इस प्रकार प्रयम योजना की तुलना में कृषि पर फूल व्यय कम हो गया है। स्थानीय विकास कार्यों तथा प्राप्त पंचायतो पर लगभग स्मान ही है और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं तथा सामुदायिक योजनाओं, पशुपालन, बन तथा मूमि संरक्त और सहकारिता पर पर्याप्त मात्रा में बृद्धि हो गई है।

कठिनाइयाँ भारत में कृषि नियोगन को सफलता पूर्वक कार्यान्वत कारी में अनेक कटिनाइयाँ है बाजना को सफल बनाने के लिये सर्व प्रथम कुषक का स्वेन्द्र्य से उक्तिय सहयोग आवश्यक है, परन्तु भारतीय इपक अधिकतर हिंदुवादी है और प्रत्येक बात पर परम्परागत दृष्टिकीण से ही विचार करता है।

यह इस बात के लिये प्रस्तत नहीं कि परम्परा की रूहि छोडकर कछ नवीन प्रयोग किये जाँय। अतीत में कवकों की स्थिति में सधार करने के लिये अनेक प्रयक्त किये गये परन्त कुछकों की उदासीनता के कारण उनमें से श्रधिकांश श्रमफल रहे। पंचवर्णीय योजना में कहा गया है कि कवि के लेज में विकास कार्यक्रम की सफल बनाने के लिये और निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये यह ब्रावश्यक है कि जनता सहयोग दे। बिना जन-सहयोग के समाज करूगण की योजना सकल नहीं हो सकती। कृषि विकास कार्यक्रम उसी सीमा तक सफलता प्रवंक कार्यान्यित हो सकता है जहां तक जनता उत्साह और श्वेच्छा से उसके लिये कार्य करने को प्रस्तत हो। अध्यक्षों का सक्षिय सहयोग प्राप्त करने के लिये यह श्रावश्यक है कि (१) विभिन्न उपायों से कुषकों को यह निश्वास दिलाया जाय कि योजना उपयक्त है और इसके कार्यान्वित होने से उनका लाभ होना निश्चित है: (२) योजना लाग करके श्राप्त ही ऐमे परिखाम निकाले जाने चाहियें जिनसे क्रयकों में विश्वास उत्पन्न हो और उन्हें ब्रेरणा मिले और जितको वह स्वय श्रीकों ने देख और परख सकें। यदि बोजना का उद्देश्य दोर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो कपकों में योजना को निश्चित उपयोगिता के प्रति विश्वास उत्पन्न करना कठिन हो जायगा। मह्य श्राधिक होने से, बेरोजगारी में वृद्धि से श्रीर व्यापक श्राधिक कठिनाहयों के कारण बड़ी योजनाश्रों की सकलता पूर्वक लागू करने में सरकार की समर्थता पर क्रवकों में विश्वास घटता जा रही है; थ्रीर (३) जनता मे योजना लागू करने के लिये उत्तरदायी वर्ण श्रधिकारियों की इंगनादारी और समता पर विश्वास अत्यन्न किया जाये। यदि जनता प्रशासन के इर स्तर पर अष्टाचार देखे. उसे सब स्थानों पर कार्य में अनावश्यक देरी तथा श्रकशत्त्वा का सामना करना पढे और यदि उसे यह मालुम हो कि समाज का धोष्या कर समाज की हानि से लाभ उठाने वाले हानिकारक तत्वों के विख् उपमुक्त कार्यवाही नहीं की जा रही है तो जनता की उत्साहित कर उसका संक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकता ऋत्यन्त कठिन हो जायगा।

कृषि नियोजन की सफलता श्रन्य योजनाओं की तरह सम्बन्धित श्रिध-कारियों को कार्यक्षमता और ईमानदारी पर निर्भर करती है। योजना ब्रायोग ने बताया है कि कायंक्रम की सफलता की गति प्रशासन संगठन, उसकी कार्य-क्लता श्रीर उसके द्वारा ग्रेरित जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। प्रशासन को ग्राज गत वर्षों की अपेक्षा ग्राधिक वहीं और वटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्याएँ वड़ी और जटिल अवस्य है, परन्तु आज इनके महत्य में अतीत की अपेद्धा कहीं अधिक वृद्धि हो गई। योजना के कार्यका

सफलतापूर्वक संचालन करने के लिये शिक्षित, कुशल और ईमानदार अधि-कारियों का अभाव है। कार्य बहत विशद है, परन्तु विभिन्न योजनाओं का कार्य मंगालने के लिये शिक्ति वर्मनारी पर्याप्त सरुपा में नहीं हैं। केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के ब्रानेक जिला. राजस्व तथा श्रन्य श्रीधकारी हैं, जिनमें से कछ बहत इशल और परिश्रमी हैं, परन्त खेद है कि इन अधिकारी में से अनेक प्राचीन प्रथा के ब्रानकल चलते हैं और कपकों से ब्रापने को काफी दर रखते हैं। इन ब्राधि-कारियों की दृष्टि में रचनात्मक कार्य की अपेक्षा कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने का भ्राधिक महत्व है, इससे यह अधिकारी योजना को कार्यान्वित करने के जिये जावक मिन्न जरी हो सकते । 'कविक-अब उपवाको' तथा काम आन्द्रोलजी के मायका में बरतेका ऐसी घटनायें प्रकाश में बाई है जिनसे पता चलता है कि श्राशिकारियों में बीज लाट तथा रुपया कपकों तक पहेंचाने का श्रापेक्षा केवल काशजा में खाना पूर्ति की और रुपयों को स्वयं हहप लिया। इससे योजना को सफल इनाने में सफलता नहीं मिल सकती और जनता का उस पर में विज्ञास खंड जाता है। पंचवर्षीय याजना में इस बात पर महत्व दिया गया है कि सर्वप्रथम प्रशासन में निष्ठा, कुशलता, बचत और सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है। यालना ये इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनेक समाब टिये गये हैं। इनकी पूर्वि में अवस्थ काफी समय लगेगा। योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की छाँटने और उनकी उचित ट्रेनिंग देने के साथ ही पंचवर्षीय योजना में सम्बन्धित श्रविकारियों की कार्यक्रमता, निष्ठा आरे हैमानदारी में सवार करने के लिये अनेक सुमाव दिये गये हैं इनमें से कहा समाव इस प्रकार है-(१) प्रशासन सम्बन्धी, राजनोतिक नथा अन्य पदो पर कार्य करने वाले श्रधिकारियों पर ग्रष्टाचार के शारोपों की जाँच करने के लिये उपयक्त व्यवस्था की जाय । यदि अपराध स्पन्द हो तो तथ्यों का पता लगाने श्रीर श्रवराध सिद्ध करने के लिये तुरन्त जाँच की जाय। (२) वर्तमान कानून में ऐसे मामलों के लिये व्यवस्था की गई है जिनमें सरकारी कर्मचारी आय के गैर काननी छाचनों का उपभोग करता है और उन साधनों के सम्बन्ध में सन्तोधजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पासा । परन्त वर्तमान कानन के अनुसार ऐसे मामलों की जाँच करने की ' व्यवस्था नहीं है जिससे यह जात हो कि अगुक सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार एकाएक धनवान कैसे हो गये। इसलिये कानून के इस अभाव को पूरा करने के लिये अध्ययन किया जाय और उपयुक्त कानुन बनाया जाय। (३) ऐसे अधिकारी को जिसकी ईमानदारी पर सन्देड किया जाता है वहे उत्तरदायित्य के पद पर नहीं नियक्त करना चाहिये।

24E

भारतीय ग्राम्य जीवन की कछ ऐसी विशेषवाएँ हैं जिनसे कृषि नियोजन के कार्य में बाधा पहेंचती है। आसो में अञ्छी सड़को, विचाई तथा अन्य मुवि-धार्को का स्थान है। कपको के इस समाची की शीध प्रति करने की शावरा-कता है. परन्त यदि इस कार्यों पर ऋषिक ध्यान दिया जाय तो बहसखी ब्यापक कार्यक्रम को लाग करने में छनेक कठिनाइयाँ पैदा हो जारेंगी। यदि दीर्धकालीन योजनायो पर अधिक ध्यान दिया गया तो स्थिति में मधार करने की शीध फल-दायक योजनाएँ लागू करने की सम्मावना कम हो जायगी। यह सम्भव है कि हीर्चकालीन और अस्पकालीन टोनों प्रकार की योजनाओं पर स्वान दिया जाव परन्त इससे प्रगति की गति सन्द हो जाती है खीर कार्य तेजी से खागे नहीं बढ पाता है। जमीदारी जागीरदारी तथा इसी प्रकार की खरूप प्रधारों के उन्मलन से अनेक नई कठिनाइयाँ जलक हो गई हैं। बामों में महाबनों और साहकारों के घीरे घीरे समाप्त हो जाने से नई कठिनाहयों में विद्य हुई है। इससे एक खाई उत्पन्न हो गई है जिसको अभी तक नई ध्यवस्था से पाटा नहीं जा सका है। भारतीय क्रमक एक दश्चक में प्रसाहका है। यह निर्धन है क्योंकि अन्छे मकार का बीज, खब्छे पशु और खाद इत्यादि खरीदने के लिये उसके पास द्रव्य नहीं है, श्रीर जब तक वह धनी नहीं बन जाता तथ एक वह इन धस्तश्रो का कप कर चकते के साधन नहीं जुटा सकता है। दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि क्रपकों की ऋषा लेने की समता महीं है। वह समानत न रख सकने के कारण चहकारी बैंको तथा ऋण नहीं देने वालो अन्य संस्थाओं से ऋण नहीं ले सकता है। और जब तक कृपको को आर्थिक व्यवस्था अव्छी नहीं हो जाती वह इन

सावनो को नहीं जुटा सकता है। यही कारण है कि शतान्त्रियों से भारतीय कुषक निर्धनता श्रीर दुखों में पंचा हुआ है। ऋषि नियोधन को सफल बनाने के लिये कुपकों को इन कठिनाइयों को दर धरना अत्यन्त कावश्यक है।

### डाध्याय १६

# बडे पैमाने के उद्योग

भारत में खनेक वह उद्योग है परन्तु खीचोिएक चित्र में अभी विटेन में स्मी शताब्दी में हुई खीचोिएक कार्नित वहाँ नहीं हुई है। भारत में प्रति व्यक्ति अधिगिष्क कार्नित वहाँ नहीं हुई है। भारत में प्रति व्यक्ति अधिगिष्क उतादन की सात्रा बहुत कर है की दूर उद्योगों में देश की जन संस्था का बहुत कम भाग लगा हुआ है। भारत के कारतानों में मिहितन कार्य करने वाले आंगकों की श्रीखत संस्था १९१६ में १६ लाख यी जो बहुकर अब २५ लाख हो गई है। देश की २८ करोड़ जनसंख्या को देखते हुये यह बहुत कम है। देश में नचीन उद्योगों का विकास करने के लिये काभी बड़ा चेत्र खुता पढ़ है और बर्तमान उद्योगों के उत्यदन में भी अधिक इदि की जा एकती है।

दितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारतीय उच्चोग की दो प्रमुख विशेषताएँ थां—
(अ) कुछ उद्योगों में कैते मुत्ती कपका और चीनी उद्योग में बहुत अधिक अमिक कार्य करते थे और ये उद्योग आवश्यकता ने अधिक उदादन करते थे; (ब) इन्हें साथ ही बहु स्वामिक हैं इंजीनियिश और इन्हें खेचा के अस्य उद्योग ये ही मुद्दी। युद्धोत्तर काल में कुछ नीमा तक इन दोषों को दूर कर दिया गया है। यद्दी कुछ महास्यूच्च बर्द्धाओं के लिए मारत को आयात पर निमेर करना पढ़ता है। कि भी देश में विभिन्न प्रकार की चर्द्धाओं का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। इन्हें कुछ महास्यूच्च बर्द्धाओं का उत्पादन में इन्हें है इन्हें पहें है और ऐसी सम्पादना है कि भविष्य में अपनी अववश्यकता की पूर्त करने के लिये इनका पर्याप्त मामा में उत्पादन किया जा सकता। अपना की सार्वी अववश्य अवेजान के आयोगिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्तित करके पूर्व कर दिया वार्येग। ।

्र्रभू सूती कपड़ा उद्योग

मारवीन यती कपना उच्चीग की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका युद्ध के परवाद विशेष रूप से विकास हुआ है। विश्वयुद्ध के पश्चाद कराई। की मिलो की संख्या में काशी हुद्धि हुई है। देखा का विभाजन हो जाने से मिलो की संद्या १९५७ में ४९३ से गिरकर १९४८ में ४०८ रह गई थी परन्त नवीन मिलों की स्थापना से और प्रयोग मिलों में मधीन इत्यादि बढ़ा देने से भारतीन

सती मिली की उत्पादन शक्ति में काफी वृद्धि हो गई है । १९५१ में भारत में ४४५ मिलें थीं जिनमें १ करोड़ १२ लाख ४० इजार तकए (Spindles) ग्रीर २.०१.४८४ कर्षे ये पर १६५७ के ब्रन्तर्गत में ४६६ मिले हो गई जिनमे १२६ लाख सकुए ग्रीर २०६,१२६ कर्षे हो गये। कई नई मिलें स्थापित की जा रही हैं ग्रीर आधा की जातो है कि इन मिली हारा उत्पादन आरम्म होने पर मारतीय रही , मिलो की वान्तियिक उत्पादन शक्ति में भुरूपवः कताई मिलों (spinnig mills) में, श्रीर बढ़ि हो जायसी।

कुछ मिलों में देवल यत काता जाता है और अन्य में यत की कताई और बनाई हाजा होती है। यह के प्रधात काल की योजना समिति ने ऋनमान लगाया कि व्याधिक हर्ष्य से कसाई-बनाई दोनों कार्य करने वाली अनक्ततम आकार की स्त। मिल में २५ इजार तक्कए और ६०० करने होने चाहिये। परन्त दर्भाग्यवश ग्राधिकाश मिले जिनमें कताई बनाई दोनों कार्य होते हैं श्रीर जिनमें केवल कताई होती है ब्रार्थिक इंटिसे ब्रानकलतम ब्राकार की सिर्लेनडी कड़ी जा सकती। सती कपड़ा उद्योग की बॉकक पार्टी के बानमान के बानसार लगभग १५० मिली में क्रतार्थिक हैं। इसके साथ हो क्रविकांश मिलों में परानी क्रीर विसी पिटी मधीने हैं। बस्बई मिल-मालिक संघ के अनुमान के अनुसार बम्बई की मिलों में ६०% मधीने २५ वर्ष से भी अधिक परानी है। सती करड़ा उद्योग के सम्मुख सब से बड़ी समस्या यह है कि यर्तमान मिलों को आधिक दृष्टि से उपयुक्त स्तर पर लागा जाय, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई आधुनिक मशीनें लगाई जायं और उन्हें श्रावश्यक श्रोद्योगिक मसाधनों से सुसब्जित किया जाय । दसरो ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश के अन्य भागों जैसे महास, सध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश श्रीर मध्य भारत में इस उद्योग का विकास हुआ। परन्तु फिर भी यह उद्योग वम्बई में ही अधिक केन्द्रित है। कुल उद्योग में जितने तकुए और करवे उपयोग में लाये जाते हैं उनके ६० प्रतिशत केवल बन्बई में हैं। इसलिए भविष्य में विकास करते समय उद्योगों के स्थान-निर्धारण की समस्या पर विशेष ध्यान देना पहेगा । स्थानी करण की स्थिति में सचार ज्ञावज्यक है।

ज्त्पादन की प्रवृत्तियाँ—१६४४ में सती कपडे और १६४६ में सत का उत्पादन श्रिधिकतम अर्थात क्रमशः ४८५२० लाख गज और १६८५० लाख पौरड था। यह उत्पादन १९५० में गिरकर ३६६५० लाख गज और ११७५० लाख पीएड हो गया । १९४९ श्रीर १९५० में उत्पादन के गिरने के मुख्य तीन कारण थे--(१) १९४७ में देश का विभाजन हो जाने से कच्चे माल की कमी हो गई श्रीर पाकिस्तान तथा अन्य देशों से रूई का आयात करने में अनेक कठिनाइयाँ

उत्तव हो गई, (२) उचोगों में अमिकों के काय में वृद्धि हुई; और (३) विशुव शक्ति पर्योग्न न होने के कारण वश्वई मिलों को दों जाने वाली विशुव कम कर दी गई। धीरे-धीरे इन कठिनाहयों को दूर करके उत्पादन में धूबि होने लगी। पर्री कपन्न उद्योग में आमक तथा मालिकों के स्वस्वकों में सुध्या हुआ, उत्पादन शक्ति में दृद्धि को गई और देश में कपास की उत्पिद्धि में वृद्धि को गई और देश में कपास की पृति में वृद्धि को गई और देश में कपास की पृति में वृद्धि हो। धीरणामस्कर्भ १६५१ में सुध्या कपास और १६५१ में प्रश्चात का उत्पादन कम्मा ४०५६ लाल वाल और १३०४० लाल पीय और १६५१ में ४६६० लाल यात और १६५१ में ४६६० लाल पीय और द्वारा कपास के स्वयं पर से निर्यमय के हटकाने के कारण, वह और कप्ता के बातायात के लिये मालागांक्षियों के मिलने तथा माँग की वृद्धि से उत्पादन में और अधिक वृद्धि हुई है। इसके परि-प्याम स्वरूप सुरी कपने और सुरा का उत्पादन बहुकर १६५७ में कमशः ५३१५० लाल पास स्वरूप सुरी १५७६० लाल पीय हो। वापा।

मारत की खुती मिलों में पहले सीटे कपड़े का ही व्यक्तिकार उत्पादन किया जाता था परन्तु प्रशुलक मण्डल (टिर्फ्कोर्ड) की विकारियों के ब्रानुवार उत्तम प्रकार के कपड़े का उत्पादन पटाने के लिए १६२५ ते १६४० तक काड़ी द्वरपा लगाकर अनेक टेकनिकल खुपार किये गये परन्तु उच्चीग का पुनर्वक्षकन कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही दिवीय निश्वयुक्त आरम्भ हो गया। युक्त के लिए वैनिक मांगी तथा अन्य ब्रान्यस्वकाओं को पूर्वि के लिए उत्योग को किर मोटे तथा माध्यम वर्ग के कपड़े का उत्यादन करना पड़ा। इटमें कुछ और कपया खगाना पड़ा लिचने उद्योग पर काड़ी भार पड़ा। परन्तु इपर कुछ वर्गों से मोटे और श्रम्युक्तम प्रकार के कपड़े के स्थान पर मध्यम श्रीर उत्याप मध्यम वर्ग के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि की गई। यह एक वाच्छतीम प्रवृद्धि है और इस्य बर्ख ब्राह्मा कर वक्त हैं कि मिन्य में देश की भोग पूरी करने तथा मिर्गांत के लिए इस उद्योग को सहीन और सप्यम भेषी के कपड़ी की उत्पादन विवार मिर्गांत के लिए इस उद्योग को सहीन और सप्यम भेषी के कपड़ी की उत्पादन व्यान पड़ी। पड़ी।

उद्योग के सम्मुख कच्चे माल के अमान का गंभीर संकट उत्सन हो गया। समान्य रियति में कपास का आयात करके इस संकट को दूर किया जा सकता या परन्तु पाकिस्तान ने भारत को आवश्यकता के अनुसार कपास नहीं दिया। पाकितान के अतिरिक्त अन्य देशों की कपास का मान बहुत अधिक या और मारतीय सती कपारा उद्योग के अनुसूल नहीं या। परन्तु रेटश्य-भूम में कपास का उत्पादन १० लाख गाउँ से कुछ ही कम या और हस प्रकार आंखतः कच्चे माल की कमी पूरी गाउँ । दिवाप भ्यवपीय योजना के अंतर्गत कपास के उत्पादन में और भी वृक्षि हो गई। दिवाप भ्यवपीय योजना के अंतर्गत कपास के उत्पादन में और भी वृक्षि होने की सम्मावना है। इससे सुत्री कपका उद्योग के कच्चे माल की कटनाई की बहुत कुछ दूर किया जा सकेगा।

नियाँत—१६४८-४६ के विपरीत १९५०-५१ में ब्रुवी कपड़े और स्त के नियाँत में अपेशक वृद्धि हुई है। १६४८-४६ में १४१० लाख राज कपड़ा और ७४ लाख पीयड स्त देश से बाहर पेजा गया। १९५०-५१ में १२६६५ लाख राज कपड़ा और ७४५ लाख पोयड स्त विदेश मेजा गया। १ए प्रक्षिक का कारण यह है कि भारतीय माल का मूल्य अपेशक त कम रहा और लाय ही विदेशी बाजाय पर अधिकार कमाने के लिये अपताध किस मालियों ने जोश्या प्रका किये।

परस्त बाट में क्थिति फिर बटली ह्यौर निर्यात की इसी स्तर पर स्थिर नहीं रखा का सका। १९५२-५२ में निर्यात की मात्रा घटकर ४२३७५ लाख गर्क कपड़े और ६२ ५ लाल पौरड सत तक पहुँच गई। इस कभी के कारण निम्न-जिखित हैं -(१) सती कपड़े और सत के उत्पादन में कमी झाजाने से अधिक माल का निर्यात नहीं किया जा सका और सरकार ने कपड़े-के निर्यात पर प्रति-बन्ध लगा दिये। (२) निर्यात कर लगाने से भारतीय स्त्री माल का मूल्य वद गया। मारतीय सुती उद्योग ने बराबर यह माग की है कि निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिये सरकार निर्यात कर को समाप्त कर दे। (३) भारतीय माल को निदेशों जापान, ब्रिटेन और ब्रन्य देशों की बढ़ती प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। भारतीय सूती मिलें सरकार की अनिश्चित नीति के कारण अपने नियात की मात्रा पूर्य नहीं कर सकी और भारतीय माल की प्रकार, पैकिंग इत्यादि निर्यात की शतों के ब्रानुकृत नहीं हो सके। इसके परिस्थास स्वरूप विदेशी बाजार में मारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति गिरती चली गई। निर्यात के बहाने के सम्बन्ध में श्रानेको उपायों का अनुसरण किया गया जैसे निर्यात कर की दरों में कमी करना, निर्यात किये जाने वाले कपड़ों के बनाने में काम आने वाली विदेशी रुई पर लगाये गये श्रायात कर में छूट देना, १ मार्च १६५४ से श्रायात-कर की ही बंद कर देना और निर्यात पर नियंत्रण कम करना इत्यादि। इनके

परिवाम स्वरूप सूती कपड़ों का निर्यात बढ़ गया है। १६५६ व १६५७ में मारत ने कमशः ६८५० लाख गज तथा ८५५० लाख गज कपड़े का निर्यात किया। किन्द्र विश्ववाजार में प्रति स्पर्धा बढ़ने तथा त्रामात करने वाले देशों में लगे मित्रकारों के कारवा १६५८ में निर्यात घटकर ६५०० लाख गज रह जाने की संभावना है। मुख्य प्रकार के कपड़े को भारत से निर्यात किये वाते हैं वे चादरें, कमीन और कोट के कपड़े वायल तनवेज और स्वीट आदि हैं।

कर्-म्हेन्द्रीय सरकार सूती कपड़े पर उत्पादन कर और निर्यात कर लगादी है। वितन्त्रर १६५६ में उत्पानकर में बहुत बुविकर दी गई। इससे उत्पादन-लगात बढ़ गई। इसके अतिरिक्त राज्य स्टब्सर देती कपड़े और दृत पर बिकी कर लगाती हैं। इससे उत्पादन लगात में श्रीषक स्टिहों गई है।

१९५२ में पेन्छीय सरकार से इचकर्या उत्योग लायवा सनकरों की सहायता के लिये ६ करीब सपये का कोच एकज करने के लिये मिल के बने सभी कपड़ी पर इ पाई प्रति गज की दर से एक उप-कर लगा दिया। यह बास्तव में श्रपनी प्रकार का बिल्कल नवीन उपाय था। इसके अनुसार यह पहले ही स्वीकार कर लिया गया है कि उद्योग को बहत अधिक लाभ हो रहा है और वह इस नवीन कर का भार बहन कर सकते में समर्थ है। इस सभी प्रकार के करों से सती मिल उद्योग को अपना जलाइन इयय कम करने में आधन करिनाई का सामना करना पढ रहा है। इस-स्थिति में सधार करने के लिये यह आवश्यक है कि कर कम किये जायँ छीर मशीनों की टट फट के लिए जिस दर से धनराशि दी जाती है उसके प्रति उदार नीति अपनाई जाय जिससे सती मिल उद्योग परानी और हुटी मशीनों के स्थान पर नवीन सशीनें लगा सर्वे श्रीर कारखानों में झाधनिक टैकनिकल सविधाएँ प्रदान कर सकें। मशीनों की टूट फुट के लिये जो घनराशि निश्चित की गई है वह अपर्यास है। नवीन मशीनों को लगाने के लिये इस बात की ऋत्यन्त आवश्यकता है कि चरकार कम न्याज पर उद्योग को ऋण दे और मशीनों की टूट फुट के लिये निश्चित धन के प्रति उदार नीति अपनाये । भारतीय स्ती कपड़ा उद्योग में युक्तीकरण की अल्पन्त आवश्यकता है। परस्तु यह निम्म तीन बातों पर निभैर हैं: (१) आवश्यक धन की प्राप्ति. (२) आवश्यक मशीनी की प्राप्ति थीर (३) इस समस्या के प्रति अभिकों का विचार। फिर भी सरकारी कर नीति इस सम्बन्ध में सबसे अधिक विचारखीय है क्योंकि वही युक्तिकरण के लिये ब्यावश्यक धन प्राप्त करने का श्रोत है।

एकत्रित सामग्री का संकट--१९५७ के पारम्म से ख्वीवस्त्र उद्योग गर्मीर र्षकट का सामग्र कर रहा है। समभग २६ मिले, जिनमें से १६ उत्तर प्रदेश में हैं, बन्द होगई है तथा ३७ मिलो केवल अंग्रातः कार्यं कर रही हैं। अमेल १६५८ के अन्त में मिलों के पास बिना विके कपड़े की एकत्रित सामग्री १,०५३०० गाँठे तथा मार्च १६५८ के अन्त में बिना विके सत की एकत्रित सामग्री १,८५०० गाँठे थी। अनेक मिलों को हानि उठानी पड़ी है तथा, मिलों के अनेक मजदूर केबार हो गये हैं। इस संकट के मुख्य कारखा निम्म हैं: (१) काराज्य तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं के मुख्य अल्पिक ऊँचे होने के कारख लोगों को क्रम शास्त्र सार्वा लिंगों के क्रम होता है। तथा ही १६५८ में निर्वात में भी कमी आगहे। (२) कपड़े पर लगे उत्तादकर की ऊँची दर के फलस्वकर उत्तादक-लागत बरावर ऊँची बनी हुई हैं। (३) उद्योग का मजदूरी-बिल बहुव अधिक है। लागत के घटने का कोई सहज उपाय भी नहीं दिखाई रेता क्योंकि सार्वीनें विस्ती पटती तथा पुरानी है तथा उत्पादन के प्रक्रीकरखा में देर होती रहती है। उद्योग के बरवाही से बचाने के लिये वह आवश्यक हैं कि उत्पादन कर १६८५५ कर दिया जाय तथा अत्यादन के प्रक्रीकरखा में देर होती रहती है। उद्योग के बरवाही से बचाने के लिये वह आवश्यक है कि उत्पादन कर १६८५५ कर दिया जाय तथा अत्यादन का प्रक्रीकरखा किया आप।

उद्योग के समुख दो कठिनाइयों हैं। एक श्रोर उत्पादन पर नियंत्रण लगा दिया गया है तथा दूउरी और इपकर्षी उत्पादकों के दित में मिल उद्योग पर १ ली दिखम्बर १९५२ से मित्रम्थ लगा दिये गये हैं निनके अनुसार घोतियों के उत्पादन के १९५१-५२ के मासिक औरत के ६०% पर मिलों का घोतियों का उत्पादन निश्चित किया गया है तथा साबियों का रंगना निषिद्ध घोषित कर दिया गया है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्त्री कपका उद्योग की उत्पादन शक्ति को १९५५-४६ तक ४७०-० लाख गर्ब कपके और १०५२० लाख पाँड युत तक बदाने का अनुमान या और वास्त्रिक उत्पादन ४७००० लाख गर्व कपके और १६४०० लाख पाँड युत का करने का या। इसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति को १५ गर्व कपका प्राप्त हो सकते का या। प्रयम योजना के अन्य तक वास्त्रविक उत्पादन और उत्पादन शक्ति दोनों हो शक्ष के अनी बद्द गये।

दितीय पंचवर्षीय योजना के ख्रन्तगंत यद प्रस्ताय किया है कि कुल कपड़े री के उत्पादन की मात्रा ( मिल ख्रीर हयकर्षे ख्रीर शक्ति संचालित कार्षे से नने कपड़े मिलाकर ) की दिन्य, करीके यज से, जितना कि १८७५-५६ में या, १६६०-६१ तक न्यु० करीक्र शज कर दिया जाय और सुत का उत्पादन १६३ करोड़ पींड में १८५ करोड़ पींड कर दिया जाया । इसका बहुरेय प्रति व्यक्ति कपड़े का उपमीग १८ गज्ञ तक बद्दा देने का है ख्रीर लगमय १ ख्रुरत शक्त कपड़े का निर्यात करता है। द्वितीय योजना में कपड़ा उचीग के सम्बन्ध में दो मुख्य दोव है—(१)
मिविष्य की कपड़े की माँग का कम अनुमान करना, वर्मीक वग्नई के मिल
मालिकों की एसोस्पियान के मतानुसार यह माँग ८५० करोड़ गज नहीं वरन्
१००० करोड़ गज होगी; और (२) मिलों के विस्तार पर इस विश्वास से मितदन्य
लगाना कि इससे हथकमाँ के प्रयोग को सहायता मिलेगी। हमकर्षा उद्योग को
सहायता मिलों की उत्पत्ति को कार्यों कमेटी के अनुसार ५०० करोड़ गज तक
अपवा किसो अन्य मात्रा तक सीमित कर देने में नहीं मिलेगी वरन् हथकमें से
बने कपड़े अधिक अच्छे बनाने और उसके मुख्य के बटाने से मिलेगी।

८४९/जूट उद्योग

भारत में बुद की ११२ मिलें हैं जिनमें लगभग ७२,१६५. कर्षे चलते हैं। इनमें से ४५% क्षें बुद के टाट और ५५% बोरे हत्यादि बनाने के लिये हैं। अनुमान लगाया गया है कि यदि उद्योग में चेवल एक शिफ्ट से कार्य चलाया जाय और मिल धनाह ४८ घट उत्यादन किया गाम तो मितवर्ष ११ लाख टन उत्यादन किया गाम तो मितवर्ष ११ लाख टन उत्यादन किया जा चकता है। जुद उद्योग अधिकत्वर पश्चिमी धंगाल में केन्द्रित है। भारत की कुल रिजटब्र्ड ११२ जुद प्रिलो में से १०१ मिलें पश्चिमी बंगाल हो में सिमत है। ग्रेष मिलों में से ४ आगम में, ३ विहार में ३ उत्तर प्रदेश में और १ मध्य प्रदेश में हैं।

भारतीय जूट उद्योग अन्य यह उद्योगों ने अधिक हुसंगिठत है पराहु दुर्भायका इचकी मशीन इत्यादि आधुनिक नहीं है और वाध ही यह महीनें बनाये हु माल की वर्तमान भाँग के इिस्क्रीय ते अधिक भी हैं। भारतीय उद्योग की प्रतिकृत प्रतिकृत स्थायका की अतिशोगिता शक्ति में दुई करने के लिये यह अवस्यत आवश्यक है कि उचकी प्रतिकृती के स्थान पर आधुनिक अधीनें नागई जाँय और इस मकार उत्यादन क्ष्मय घटाया जाय। पराहु छुट्य क्रांटिनाई यह है कि उच्योग का युक्तीकरण करते में ४० से ४५ करोड़ करवे तक की दुंबी लगानी पहेगी और यतमान में उद्योग इतनी पूंजी लगा पड़िक के कुमता नहीं एलता । "अमिनवीकरण (modernisation) के लिये राष्ट्रीय आधीगिक कितार मिनाम हांग प्रयुप्त इसे मार है है। मार्च १९५६ के अन्य तक ह सिक्त कम्मनियों के लिये खुण स्थीकृत हो 'तुक है जिनसे से ७ की १.१६ करोड़ दठ दिया भी वा जुड़ा है। यतमान स्थित यह है कि घर जुट मिल कम्पनियों से से ४४ ने ३० सितावर १९५५ तक कताई सम्पन्यों आधुनिक सर्वानों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णता तथा कुछ ने अंगता अधिनक सर्वानों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णता तथा कुछ ने अंगता अधिनक सर्वानों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णता तथा कुछ ने अंगता आधुनिक सर्वानों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णता तथा कुछ ने अंगता आधुनिक सर्वानों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णता तथा कुछ ने अंगता आधुनिक सर्वानों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णता तथा कुछ ने अंगता के तथा वा तथा स्थापित वा तथा था। स्थान वा कुछ ने स्थापित वा तथा स्थापित वा स्थापित सर्वान वा है है।

सत्पादन की प्रवृत्ति—जुट उद्योग में उत्पादन १६४५-४६ में उचला तक पहुँच जुका था जबकि ११-४ लाख दन माल का उत्पादन किया गया। इसके पश्चात १६४६ तक उत्पादन दस लाख दन प्रतिवर्ध के लगभग रहा। परन्त १६४६-५० में उत्पादन दाई लाख दन तक शिर गया । इसके पश्चात उत्पादन में कुछ सुधार अवश्य हुआ। परन्त फिर भी उत्पादन पूर्व स्तर तक नहीं पहच पाया । १६५४-५५ में उत्पादन बढ़ कर १०, ४३,४०० टन हो गया था। उत्पादन में कमी का मध्य कारण करने मान की कमी भी नयोंकि देश का विभावन हो जाने के पश्चात जट का उत्पादन करने वाले श्राधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये। इस अभाव को पूरा करने के लिये देश में ही जुट उत्पादन की बृद्धि पर जोर दिया गथा। तब से देश में जुट के उत्पादन में श्रुद्धि हुई है जिसके परिखान स्वरूप जुट के साज के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जुट उद्योग में प्रति चताह केवल १२ माने अत्यादन कार्य हो रहा था और उद्योग के क्रल कर्य के १२ है प्रतिशत बन्द पहें हुये थे। परन्तु अक्टूबर १९५४ से ४८ घन्टे प्रति सप्ताई कार्य आरम्भ हो गया और १६५६ के मार्च तक बन्द क्यों में से ७१ प्रतिशत चाल हो गये थे। १९५६-५७ में उत्पादन १,०२५,२०० टन था तथा आशा की जाती है कि १६५७-५८ में भी लगमग इतना ही होगा।

करूचा काल—जुरोग की इस समय सबमें बढ़ी कहिनाई करने माल की कमी है। यद सब मिलें शक्ति भर कार्य करें तो भारतीय लट उद्योग के लिये प्रतिवर्ष परवन की ७५ लाख गाँठों की स्नावश्यकता है। परन्त भारत में १६४७ ४८ में १५ लाख गाँठों से कुछ श्रविक, १६४८-४६ में २० लाख गाँठ, १६४६-५० में ३० लाख गाँठ श्रीर १६५०-५१ में ३३ लाख गाँठ से कुछ श्रधिक का उत्पादन किया गया । भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से समझीता कर पटसन के श्रायात की व्यवस्था की, परन्तु श्रायात का यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पाकिस्तान से बहुत थोड़ी मात्रा में जुट का आयात किया गया। फलस्वरूप भारतीय जूट उद्योग के कच्चे माल की आवश्यकता पूर्ण नहीं की जा सकी। इधर हाल के वधीं में भारत में कच्चे अट का उत्पादन बढ़ गया है। १६५६.५७ में इसका उत्पादन ४२ ५ लाख गाँठे थी। १६५७.५८ में इससे घट-कर ४० लाख गांठे (४०० पी॰ की एक गाँठ) रह जाने की श्रावश्यकता है। कच्चे जूर के विषय में आत्मिनर्भरता प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले गहन व्रयत्नों के संदर्भ में १९५७-५८ में उत्पादन की यह कभी शोचनीय विषय है। द्वितीय योजना के अन्त तक मारत को पाकिस्तान से जूट मंगाना ही पड़िगा। किन्तु उन पर इमारी निर्मरता बहुत कुछ कम हो जायगी और यह सम्भव हो

सकेगा कि भारत में जूट उद्योग पाकिस्तान से जूट बिना पाये भी संतोषण्ट दंग में चले।

. निर्यात-भारतीय जुट उद्योग अधिकतर अपने माल के निर्यात पर निर्मर करता है। १०४%-४० में भारत में ११ लाख टन उत्पादित माल में से # 30.000 रज माल का विदेशों को निर्यात कर दिया गया । यहापे निर्यात की मात्रा पूर्व की श्रपेसा घटकर १९५६-५७ में द्रप्रह००० टन हो गई है किर भी यह कुल उत्पादन का बहुत नहां भाग हैं भारतीय जुट के टाट के हो बड़े बाजार युनाइटेड स्टेटस तथा यु० के० हैं।

१९५६ ५७ में इन देशों को गये निर्यात में कमशाः ५% और ५०% की कमी हाई। यद्याप यनाइटेड स्टेटस को किये जाने वाले निर्यात की कमी से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी श्रमेरिका में व्यापारियों ने टाट सामग्री कहा कम कर दी थी। किल यह पूर्ण सस्य नहीं है । अधिक सहस्त्र की बात सी यह है कि १९५६-५७ में टाट के उपमोग में (प॰ एस॰ में) १२% को कमी हुई। उपभोग की यह कमी थैंले बनाने के लिये टाट का प्रयोग कम करने के कारण हुई। सन्तीय का विषय है कि श्रीद्योगिक तथा श्रन्य उद्देश्यों के लिये जुट का प्रयोग बढ़ता रहा । य० के० में लूट के उपभोग में हुई भारी कमी वहाँ पर लागू जूट-नियन्त्रण के कारण हुई। जट से बनने वाले येलों से यह लाम होता है कि यह अपेदाकृत सस्ते होते हैं छीर इनका छानेक बार उपयोग किया जा सकता है जब कि पैकिश के लिये काराज के थैलों तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं का केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु जुट के थैलों के स्थान पर कागज तथा धान्य प्रकार की चरत कों के प्रयोग से जुट के माल की साँग काफी गिर गई है और यह जुट उद्योग के तिये चिन्ता का कारण बन चुकी है। फिर भी यदि उचित प्रयस्न किये जाँग तो अन्य वस्तुओं की अपेन्ता जुट का माल अपने लिये धावत्रयक स्थान बना सकता है। परन्तु इसके लिए यह आवस्यक है कि भारतीय जट उद्योग का उत्पादन व्यव बटाया जाय, उत्पादन बढाया जाय और उत्पादित माल की प्रकार में सधार किया जाय।

भारत सरकार ने जुट के माल पर बहुत अधिक निर्यात कर लगाया जिस से कि माल के भारतीय तथा विदेशी गुल्य का अन्तर सरकारों खजाने में जमा हो जाय । यदि यह कर न लगाये गये होते तो उद्योग अपने आविनिकोकरण तथा पुरानी विशे पिटी मशीनों के बदले नई मशीनें लगाने के लिये पर्याप्त सुरिह्नत कोप का समह कर सकता था। निर्यातकर से बहुत हानि उठानी पड़ रही थी। कोरिया सुद्ध के कारण हुई सहयी के काल में जुट के बने कपड़ों पर तो यह कर

१५०० ६० प्रति टन ख्रीर शेरी पर १५० ६० प्रति टन तक बढ़ गया था। ख्रमस्त १६५५ में पाकिस्तानी क्षये की बिनिमब दर घटने पर यह कर इटा लिया गया। इटाते कमय टाट पर यह कर १२० ६० प्रति टन ख्रीर बोरों पर मन ६० प्रति टन या। निर्मात कर के हटा देने का परियास यह हुखा कि मूल्यों में कभी हो गई ख्रीर निर्मात बढ़ गया तथा चरेल माँग भी बढ़ गई।

जट जाँच आयोग-जट जाँच श्रायोग ने जिसके श्रध्यत्त के श्रार पी॰ श्रायंगर ये श्रपनी १९५४ में प्रकाशित रिपोर्ट में यह पाया कि ७५% मिलें लगभग १२ मैनेजिंग एजेन्सियों के हाथ में थी, जिनमें से चार के अन्तर्गत ४४% कर्षे ये। मैनेजिय एजेन्टों के हाथ में सारे व्यवसाय के केन्द्रित होने और जट उद्योग के भूतकाल में ऊँची दर पर खाय प्राप्त करने के कारण इन मैनेनिंग एजेन्सियों के शेयर बहुत ही ब्राकर्षक हो गए ये ब्रीश उनके खरीदारों की संख्या बढ़ गई थी। चॅकि जट उद्योग के वर्तमान सर्वत्र की उत्पादन शक्ति वर्तमान और भविष्य की सम्माबित माँग से कहीं खबिक है इसलिये शायोग ने शीर नई मिलों की स्थापना की पसन्द नहीं किया। जसने मिलों को अपने सर्वत्रों को आधनिक बनाने की विकारिश की। इस्डियन जुट मिल एसोसिएशन की यह योजना होते हुए भी, चॅकि इसका परिस्ताम विनाशकारी प्रतिद्वन्द्रिता और उद्योग की श्रव्यवस्था हीगी, आयोग ने यह सिफारिश की कि काम के घट्टों के सम्बन्ध में जो समझीता हुआ है जिसके अनुसार सप्ताह के अन्दर कार्य के धन्टे सीमत कर दिये गये हैं और मधीनों को श्रंशतः चाल करना बन्द कर दिया गया है उसे आगे लाग नहीं रखना चाहिये। इस सममीते के अनुसार अक्रयल मिलें भी चलती रही हैं और इशक मिलों को अपना उत्पादन व्यय कम करने में बाधा पहुँची है। इससे पाकिस्तान तथा श्रन्य विदेशी मिलों को लाभ पहुँचा है। आयोग की यह विकारिश वर्षया युक्तिसंगत है और इससे आशा की जाती है कि कुराल मिलें स्राधक अब्छा कार्य कर सकेंगी। आयोग ने सिकारिश की है कि भारत को कच्चे जूद की पूर्ति के लिये निरपेस के बसाय सापेशिक आत्मनिर्भरता का सक्य सामने रखना चाहिये। इमें पाकिस्तान से उस प्रकार का बुट आयात करना चाहिये जिसका उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकता और श्रन्य प्रकार के जूट को स्वयं उत्पादित करना चाहिये। जुर की विस्तृत खेती के बजाय गहन खेती तथा किस्म के सुवार पर श्रविक जोर देना चाहिये।

श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा कि नियमित बाजारों में नियमों का लागू करना, सहकारी समितियों की अगबस्था करना, तथा श्रन्य सिकारियों को कार्या-नित करना दीर्घकालीन इंप्टि कोण से उत्पादकों के लिए श्रमिक लाभकारी सिद होगा। मूल्य नियन्त्रक के उपायों के प्रयोग को अस्वीकार करते हुए भी निर्यात बहान के लिए तथा घरेलू साँग बहाने के लिये आयोग ने मूल्य स्थिर रखने का प्रयन्न करने की सलाइ दी।

योजना के खन्तार्गत—जुर उद्योग के सम्बन्ध में समस्य 1 उत्पादन शक्ति , बदाने की नहीं है क्योंकि बाजार की माँग की हालना में तो भारतीय जुर मिलों के साघन ग्रावश्यकता से कहीं अधिक हैं। बास्तियिक समस्या तो कच्चे माल की पूर्ति सहाने और उद्योग को उत्पादन में खपनो बर्तमान शक्ति के श्रातुकृत कृष्टि करने की शि प्रयाप येचवर्षीय योजना में हसीकिये ओयोभिक प्रसामनो की दृष्टि के प्रवाप उत्यादन में स्वी करने की विकारिश की ग्रावशिक स्वापनों की दृष्टि के प्रवाप उत्यादन में स्वी करने की विकारिश की ग्रावशिक प्रसामनो की दृष्टि के

जूर उद्योग को (rated) प्रत्यंकित उत्यादन शकि १२ लाख दन पी परम्तु कच्चे माल के क्षमान के कारण इचका पूर्ण उपयोग नहीं हो छका है। प्रथम योजना में जूट के उत्यादन को ५१ लाख गाँठी तक क्षीर जूट के बने माल का छन्पूर्ण मलक्षित शक्त मर क्षमांत् १२ लाख टन तक बहाने का प्रकण किया गया था, जिसमें से १० लाख टन विदेशों को मेन दिया जायगा। परन्तु ये लहम प्राप्त नहीं किये जा सके।

दिलीय योजना में भी जुट मिलों की प्रत्यंकित शांक बढ़ाने की विकारिया नहीं की गई है। केवल आखान में १३ करोड़ करवा के क्या से एक मिल लोलाने का मस्ताय है। मनल यह होगा कि जुट के बने माल की १६५५-५६ की १,०४,००० दन की उनरित्त को महाकर १६६०-६१ में १,१००,००० कर दिया जाय। जुट का उत्पादन ४० लाल गाँठों से जो है १६५५-५६ में था बढ़ा कर १६६०-६१ में ५० लाल गाँठ कर दिया जाव। इस प्रकार भारतीन मिलों को झांपात किये हुये जुट पर मिथक्य में कुछ काल तक निर्मर रहना ही पहेंगा।

Q पिनी उद्योग

निराम्म्य ( Taniff) वेरत्वृत्त तथा वरकारी निर्योजन के फलस्वरूप भारत में चीनी की मिलों की संख्या १९३१-३२ में ३२ से बहुकर १९५५-५६ में १६० हो गई। इनमें से १३६ तो १९५५-५५ में उत्पादन कार्य कर रही भी श्रीर उन्होंने १६ लाख टन से कुछ हो कम चीनी का उत्पादन किया। १९५५-५६ में १३७ मिलें उत्पादन कार्य कर रही थी श्रीर उन्होंने १७ लाख टन चीनी का उत्पादन किया। १९५८ में सरकार ने चीनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने का निरुवय किया श्रीर नवीन मिलों की स्थापना को स्वीकृत दें। ५५ नई फैटरियो, जिनमें १८ सहस्त्री इकाइयाँ मी धीमालित हैं, की स्थापना तथा वर्तमान ६६ मिलों की उत्पादनस्त्रिक के विस्तार के लिये श्रुतका पत्र (लाइसेन्स) है दिये गये हैं। लाइसेन्य दो हुई उत्पादन इकाइयों में चार ने १६५६-५६ में उत्पादन प्रारम्भ किया वांच ने १६५६-५७ में। १६५७ के अन्त में प्रत्यंकित उत्पादन शक्ति २,०१०,००० दन थी। १६५७-५८ में नी और इकाइयों ने भी उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इसके परित्यं महत्वस फैक्ट्री निर्मित चीनी की उत्पादन श्रद्ध-५७ के २०१ लाख दन से बहुद १६५७-५६ में २१३ लाख दन होने की सम्मादना है।

चीनी उचीम के विकास की मुख्य विशेषताएँ निम्मलिखित हैं—(१) चीनी उचीम के विकास की मुख्य विशेषताएँ निम्मलिखित हैं—(१) चीनी उचीम के लिए उपपुष्ठ के सम्बर्ध और विहार में केन्द्रित है परम्तु देश के अन्य भाग जीने वन्ध है, महास, मेदर और देशवाद आदि भी चीनी उचीम के लिए उपपुष्ठ हैं पर्योक्ष यहाँ गम्ने का मति एकड़ उत्पादन अधिक है और गाना पेर के का मी में यहाँ अपेबाइन अधिक उमम्य तक किया वा अकता है। (२) मचिन कारखानों ने कभी भी अपनी पूर्व शक्त के उत्पादन नहीं किया। इनमें से कुछ तो निम्कुल बन्द रहे जिसके फलस्वकर उत्पादन सदा वास्तविक उत्पादन ग्रांकि के कम रहा। (१) चीनी उचीम में बहुत से पेसे कारखानों हैं जो अनुक्तवन ग्रांकि से कम रहा। (१) चीनी उचीम में बहुत से पेसे कारखानों हैं जो अनुक्तवन ग्रांकि से कम रहा। एक श्रीसत कारखानों को अपनी पूर्व उत्पादन ग्रांकि का साम उठाने के लिय प्रतिदिन ८०० टन गाना पेरना चाहिये परन्तु अनुमान लागा ग्रां है कि लागम ८० कारखानों हुए स्तर से नीचे हैं। इससे भारत में चीनी का उत्पादान ज्या अधिक होता है और आधिक हिन्द से अनुपपुक्त कारखानों का लाम में कम हो जाता है।

चरपादन की प्रश्नियाँ—मारत में चीनी के उक्ष्यादन में काफी उतारबद्दाव झाता रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीनो का उत्पादन गर्म की
पूर्ति की माना, गला पैरने की ख्रविष छीर गर्म से प्राप्त चोनी के प्रतिचार पर निर्मेद करता है। चीनों का उत्पादन, १६४८-४६ में १००६ लाख उन या जो
गिरकर १६४६-५० में ६०६ लाख उन हो गया नयोकि (आ) १६४५०-४८ में मिलों
के लिये गर्म का मान २ कण्ये मितान से घटाकर १६४५-४६ में उत्तर प्रदेश में
१ करवा १० खाना प्रति मन और विहार में १ करवा १६ खाना प्रतिसन कर ६वरा गया। गर्म का मूल्य प्रदान का उद्देश्य चीनों का भाव १५ करवा ज खाना
प्रतिमन से घटाकर २८ करवा म्या प्रतिमन करना चा। गर्म के भाय में १ स कमी से १६४६-४० में कारलानों के लिये गर्म की पूर्ति में कमी हो गई और परिवाम स्वरूप उत्यादन भी गिर गया; (ब) गर्म से ग्राप्त चीनों की प्रतिश्व माना
१६४८-४० में ६०६ सेन सेवस्क ६१ दिन तक खामई। इस कारण चीनों के
उत्यादन में कमी हुई नविक कारलानों की संस्था १३४ सेवहकर १३६ होगई थी।

परन्तु क्रमशः स्थिति बदली और उत्पादन बहुकर १९५०-५१ में ११'०१ लाख टन ग्रीर १९५१-४२ में १४'द्दर लाख टन हो गया। १९५०-५१ ग्रीर १९५१-५२ में चीनी का अधिक उत्पादन होने के दीन मुख्य कारण हैं. (१) मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की खूट दे दी गई। इसके श्रनुषार (४) त्या का कुल वाचार प्रवास प्रकार के कि जिस वर्ष का उत्सादन कम हो कारखानों को १६४६-४० या १६४६-४० में से जिस वर्ष का उत्सादन कम हो अरुपार का १८०० वा १८०६ में उन्हों से सुधिक उत्पादित चीनी को खुले बाजार में उन्हें समय के भार के ब्रानुसार विकय करने की अनुसिंद दे दी गई। इसके पूर्व कारखानों की अपना समूर्यो उत्पादन नियन्त्रित साव पर बेचना पहला या जिससे उन्हें ऋषिक क्षांभ नहीं हो पाता था। इस कारस उत्पादन इहि की ब्रोर उनकी प्रश्ति नहीं रही। खुले बाजार में अविरिक्त चीनी का विकय करने की खूट देने के फलावरूप कारलाने अधिक उपादन का लाभ उठा सकते ये इसलिए खामायिक ही उत्पादन य काम अक्षरी नाम के रहा । कारखाने से बाहर चीनी का नियन्त्रित भाव २८ रुपया द आना स्थिर रखा गया परन्तु पहले यह डी० २४ नम्बर की चीनी का भाव पा और अब दै० २७ नम्बर की चीनी इस भाव से विकय होने लगी। चृंकि है। २७ नम्बर की चीनी छी। २४ नम्बर की चीनी से घटिया प्रकार की है इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि कारलानों ने गत वहाँ की अपेचा चीनी का अधिक मूल्य वस्त किया। उत्तर प्रदेश में १६५०-५१ में गन्ने का माय २ झा । प्रतिमन बदाकर १ वरवा १२ झाना प्रतिमन निश्चित किया गया । कारखाने के बाहर है। २७ नम्बर की चीनी का भाव बढ़ाकर २६ क्या १२ आ। प्रतिमन कर दिया गया परन्तु इसका मिल मालिको पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ा क्यों कि एक मन बीनी का उत्पादन करने में १० मन गन्ना लगता है स्त्रीर इस क्षाभार पर जतादन अपय १ रुपया ४ क्षाना प्रतिमन बद्दा स्रीर मूल्य मी इतना ही बढ़ा; (३) गला पेरने की अवधि में भी वृक्षि की गई। १६४६-५० में रामा र पर १९ १९० विन थी जो १९५०-५१ में बहुकर १०१ और १९५१-५२ में परने की अवधि ६१ दिन थी जो १९५०-५१ में १३३ दिन हो गई। यद्यपि यह सत्य है कि गन्ने से प्राप्त चीनी की प्रतिशत मात्रा १० ०३ से घटकर ६ ५५७ हो गई परन्तु कारखानों को स्त्रधिक समय तक चालू रखने के कारण चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई। चीनी की उत्पत्ति १६५२-५३ में भिरकर १३-१४ लाख टन और १६५२-५४

चीनी की उत्पचि १९५२-५२ में गिरकर १२°१४ लाल दन और १९५१-५४ में १०°०१ लाल दन हो गई। इसके कारचा निन्म हैं, (१) उत्पादन करने वाली में १०°०१ लाल दन हो गई। इसके कारचा निन्म हैं, (१) उत्पादन करने वाली में १०°०१ लाज देश हो हो १९५१-५२ में १३६ थीं १९५१-५३ और १९५१-५४ में प्रकृष १३४ हो गई और कार्य करने के दिनों की औषत संख्या १३३ से

घटकर ऋमशः ११३ ऋरिय्यद्ध हो गईः (२) १९५२-५३ में कारखानों में पिछला बचा हजा साल श्राधिक साता में था श्रीर श्रानेकों मिलें समय से कार्यारम्भ भी न कर सकी जिसके फलस्करूप जितना उत्पादन करने की अनमें शक्ति थी उतना भी उत्पादन न हो सका: (३) बहुत सी मिलों में यंत्रादि धिसे पिटे श्रीर प्राचीन दंग के वे जिनके कारण उत्पादन शक्ति का पूर्ण प्रयोग होना सम्मव नहीं था: श्रीर (४) श्रवैथ सम से शाराव खींचने के कार्य में लाने के लिए वटी हुई गुड़ की मांग को पूर्व करने के लिये कछ गन्ने का प्रयोग गड बताने में कर लिया गया। १९५२-५३ की फसल के लिए गन्ने का सल्य घटाकर १ द० ५ ग्राना प्रति मन श्रीर चीनी का नियंत्रित सल्य २७ ६० प्रतिसन कर दिया गया। गन्ने का प्रतिसन मुल्य इतना कम हो जाने से कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना ही न मिल सका । १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ की फसलों के लिये मारत की सरकार ने गरने का मत्य १ २० ७ छा। प्रतिमन कर दिया। इस समय चीनी के मत्त्व पर कोई निर्वत्रमा नहीं है, केवल यह प्रतिश्रम है कि प्रसल की उत्पत्ति का २५% 'सरकित माल' समझा जाय जिसमें से सरकार चीनी दिखले नियंत्रित महय पर अर्थात २७ ६० प्रतिमन पर बेचती है । क्यकों के इब्टिकीया से गरने का १ ६० श्राना प्रति मन मुख्य अपयोग है और इसी कारवा फैक्टियों को वर्यात मात्रा में कवा माल मिलने में कठिजाई प्रस्ती है।

१६५६-५७ में बीनों की उत्पत्ति २०० लाख टन थी। १६५७-५८ में इससे बढ़कर २११ लाख टन होने की सभावना है। इसका कारण वर्तमान कैन्ट्रियों की उत्पादन शक्ति में बढ़ि तथा नई फैन्टियों की स्थापना है।

करपादन इसता—चीनी उधीग की मुख्य समस्या उत्पादन व्यय की अधिकता है। उत्पादन व्यय अधिक होने से उपमोक्ता पर अनावश्यक भार पश्चा है और अध्य देशों को अपेदा भारतीय चीनी का मृत्य अधिक होने के कारण निर्मात की मात्रा भी नहीं बढ़ पाती। भारतीय चीनी का उत्पादन व्यय अधिक होने के अनेक कारण है। चीन कीनी का मृत्य प्रशिक्ष कि काफी प्रयत करने की आवश्यकता है। चीनी-उद्योग के सम्बन्ध में प्रयम किटनाई यह है कि कुपकों के हितों की रखा के लिये सरकार गरने का मृत्य अधिक निरंचत करती है और वेन्द्रीय तथा राज्य सरकार उद्योग पर अनेक कर लगाती है। गरने का अधिक मृत्य, अधिक मजदूरी और अधिक कर का फल यह होता है कि चीनी का उत्पादन व्यव का होने थी अपेदा बदला जाता है। चीनी का उत्पादन व्यवस्थक होगा कि सन्ते के मृत्य की यदाया जाता है। चीनी को जैसा के लिये यह आवश्यक होगा कि सन्ते के मृत्य की यदाया जाता है। चीनी चीनी उद्योग की बीच करने वाले प्रवस्त ने मुक्त की यदाया जाता । चीनी उद्योग की बीच करने वाले प्रवस्त ने मुक्त परिदा पर कि

१६५६-५० में गन्ने के मूल्य में ३ आना प्रतिमन कमी की बाय, १६५०-६२ में इतनी कमी और को जाय जिससे भाव १ क्या प्रश्नाम प्रतिमन तक आ भी इतनी कमी और को जाय जिससे भाव १ क्या प्रश्नाम वित्तम तक आ गा । यि स्तिमन को लाग, किया जाता तो इससे प्रतिमन चीनी में गन्ने का जाया । यि स्थान के लाग, किया जाता । यह प्रश्नक सपडल के सुकाव के अतु- मूल्य ३ इत्या १२ आना कम हो जाता । यह प्रति १६५०-५१ में चीनी का माय २२ क्या प्रश्नाम प्रतिमन हो जाता । यह इससे १६५०-५१ में चीनी का माय २२ क्या प्रश्नाम अत्या प्रतिमन हो जाता । यह इससे श्रीम को का माय चाराने के बलाय बहा दिया । इसके परिवास स्वक्त किया और मित्रम का भाव चाराने के बलाय बहा दिया । इसके परिवास स्वक्त किया और मित्रम में और इसि हो गई । १६५९-५३ में गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश चीनों के मूल्य में और इसि हो गई । १६५९-५३ में गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश चीनों के मूल्य में और इसि हो गई । १६५९-५३ में गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश चीनों के मूल्य में और इसि हो गई । १६५९-५३ में गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश चीनों के मूल्य में और इसि ग्री में स्वत्र हो स्वत्र १ क्या प्रतिमन कर हिया गया परन्त स्वत्र प्रया प्राप्त स्वत्र प्रदेश प्रया प्राप्त स्वत्र के मुल्य की समस्या स्वत्रेवकान वह से सभी दिया गया।

श्या गया।

गन्ते की जत्यति—गन्ने के मृत्य की खमस्या कन्तोवजनक दक्ष से तमी

मन्ते की जत्यति—गन्ने के मृत्य की खमस्या कन्तोवजनक दक्ष से तमी

सलक्ताई जा ककती है जबकि प्रति एकक गन्ने की उत्पत्ति में बृद्धि की जाय।

सारत में प्रति एकक गन्ने की उत्पत्ति संवार भर में सब से कम है और निरन्तर

भारत में प्रति एकक गन्ने की उत्पत्ति संवार भर में सुर है।

मूत्र क्रा का रही है। वयुवा में प्रति एकक उत्पत्ति १७१२ उन, जाश में

१६ इन, और हवाई में ६२'०६ उन है जब कि भारत में केवल १४ उन है।

भू इन, और हवाई में ६२'०६ उन है जब कि भारत में केवल १४ उन है।

माने के प्रत्यादान की प्रतिचत नमुंच में १२'२६ आराश में १२'०६, आराह हिंदी

माने के प्रत्यादान की प्रतिचत नमुंच में १२'२६ और इवाई में १०'६६ छीर

में १४'३१, प्रतिटोशिकों में १२'२३, जावा में १२'भ६ और इवाई में १०'६६ छीर

मारत में १०% है। कुकक को तो भूमि से अपनी वाधारण आप चाहिये और

सारत में का सूच्य पदा दिया जाय और परि गन्ने से प्राप्त प्रति एकक आप वह

सार वी कुकक के तिने विन्ता की कोई बात न होगी।

 प्रक्रिया से अधिक मात्रा में चीनी उत्पन्न होती है और चीनी का प्रकार भी अपेसा-कृत अच्छा है। परना माइन्छ कालेज के भी डी॰ एन॰ घोष ने एक नई रीति निकार को है जिससे बिना किसी रस्थायनिक वा लाप की सहायता के विज्ञली के बार को ने ने रस स्थापन किसा का सकता है। इन दोनों प्रवालियों का अभी तक नयसाधिक देसाने पर प्रयोग नहीं किया यात्रा है परना हस्में सन्देह नहीं कि इनरे चीनी बनाने के क्या में कभी अवस्थ होगी। चीनी उद्योग में अन्द्री महोतों वे लगाने से भी उत्पादन क्या में कभी आवस्थ होगी। चीनी उद्योग में अन्द्री का

स्थिति-उत्पादन व्यय अधिक होने का एक कारण कारलानों का अद पयुक्त स्थानों पर स्थित होना भी है। यशपि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश झौर बिहार में श्रधिकतर कारखाने स्थित हैं परन्त यदि कारखाने बम्बहें या दक्षिए भारत में होते तो अधिक उपयुक्त होता। बन्धई तथा दिल्ला के अन्य तेत्रों में गन्ने का प्रति एकड उत्पादन अधिक है और वहाँ गम्ने की पिराई भी ऋषिक समय तक होती है। यदि उत्तर भारत की अपेका उद्योग दक्तिस में ही विकसित होता तो चीनी का उत्पादन व्यय अवश्य कम होता । परन्त अब यह है कि चीनी-उद्योग अधि-कतर उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार में केन्द्रित हो गया है। १६५१ के उद्योग (विकास एवम् नियमन) कानून के अंतर्गत नियुक्त लाइलेंसिन्म समिति ने कुछ कारलानी को एक साथ नये स्पानों में ले जाने की सिफारिश की थी परन्त यह समस्या का उपमुक्त हल िह नहीं हुन्ना क्योंकि (१) यदि यह योजना लागू की जाय तो एक कारखाने को एक स्थान से ग्रन्थ स्थान पर ले जाने में १० से १५ लाख रपया ब्यय हो जायगा श्रीर यातायात की व्यवस्था में व्यव होगा। इसके साथ ही कारखाने को इटाने की श्रविध में उत्पादन बन्द रहेगा: (२) जिन चेत्रों हे कारखाने हटाये जायेंगे उनकी आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायगी होर उनका श्रम्य चेत्रों से सम्बन्ध टूट जायगा। इसलिये उद्योग की स्थिति में सुघार करने का सबसे अब्छा उपाय यही है कि नवीन और उपयुक्त स्थानों में धीरे-धीरे नवीन कारखाने स्थापित किये जायँ और अनुगयक स्थानों में स्थित कारखाने जब पुराने पढ़ जायं और पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो तब उनका पुनर्निर्माण न करने दिया जाय।

निर्यात—श्रवीत में चीनी के जिये भारत विदेशों पर निर्मेर था। १९२६-३० में भारत ने जगमग ६३ लाख टन चीनी का आयात किया। परन्तु हाल में चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुईँ है जिवके फलस्वरूप श्रव आयात केवल नाम मात्रको होता है। यह बहुत संगव है कि मिथ्य में भारत चीनी का आयात करने की अपेबा निर्यात करने लगेगा। इवायन अंतर्राष्ट्रीय चीनी समीजन के कथनातुसार "बहुत भीनी का जियाँत बहुति में सबसे बड़ी कठिनाई भारतीय चीमों का अपेदाकृत अपिक मूल्य है। भारत में कारताने के बाहर चीनी का भाव (ex-factory price) एक अप्या प्रति अन है जब कि अप्या देशों में २१ से २१ क्या प्रति अन है। ह्यतिए जा वत तक तरकार या तो चीनी के निर्मात के लिये आर्थिक मान कहाया नाई देशों या विदेशों को कम मूल्य पर निर्मात करने और मारा पूर्ति के विषये में अधिक मूल्य पर नेवकों की अनुसात नहीं देशी वब तक चीनों का निर्मात महास्त कहीं नहीं का अपना का स्वाप्त करने जीने साथन प्रति के विषये देशों में अधिक मूल्य पर नेवकों की अनुसात नहीं देशी वब तक चीनों का निर्मात महास्त कहीं । इन कारता वी चीना का निर्मात बहुत कम होवा है और जब तक चीनों का उत्पादन मध्य मही पराय बाता तथ वक भविष्य में भी निर्मात में कि को कोई आधान जा दिवसों देशों।

प्रोजना के अन्तर्भव—प्रथम पक्षवर्थीय योजना के आरम्म में चीनी के नार्षिक उत्यादन में चूरि का कोई भी प्रथम नहीं किया व्यक्ति पर झाशा की साती यों कि १५% लाल दन की उत्यादन शक्ति का अनुमान और ११४५-४३ एक १५ लाक दन को उत्यादन शक्ति का अनुमान और ११४५-४३ में हो चीनी का उत्यादन १६ लाल दन के लाभम हो गया, अर्थात् योजना के लक्ष दे १ लाल दन अभिन हो गया। इस्तिय अस्य पश्चवर्षय योजना को लक्ष दे १ लाल दन अभिन हो गया। इस्तिय अस्य पश्चवर्षय योजना का लक्ष से १ लाल दन अभिन हो गया। इस्तिय अस्य पश्चवर्षय योजना का लक्ष से १ लाल दन अभिन से भी प्रथम पश्चवर्षय योजना का लक्ष से १ लाल दन अभिन की जीव १ भी प्रथम भी प्रथम

दितीय पश्चवर्षीय योजना में यह मस्तान हिया गया है कि उत्पादन सिक १७ ४ लाख टन से जितने का १६५५-५६ में अनुमान किया गया है, १६६०-६१ वर्ष देश लाख टन कर ही जाय और चीनों का उत्पादन १६५१-५६ के १७ लाख टन से बढ़ाकर १६६०-६१ वक २२ ई लाख टन स्ट दिया जान। उत्पादन बी इट दिस में सहकारी चीनों के काललाने हैं लाख टन उत्पादित करेंगे। दितीय योजना में उत्पादन की जहीं हुई बाता का व्यक्त उत्पुक्त हैं। इंडियन शुगर मिल्छ एसे। छिएसन ने अपने समारकपत्र में जो उसने छरकार को मेवा पा यह लिखा था कि वर्तमान चीनी के कारखाने पहिले से खाइसेन्छ प्राप्त कारखाने को समिलित करते हुँ रे १६६०-६१ तक २७ लाख उन तक चीनी का उत्पादन करने में समर्थ में जबकि योजना का खस्य फेवल २२१ वाख उन ही उत्पादन करने का है। यदि मरीवण्य की किटनाइयों जैसे वर्षों का न होना, भाद का आना इत्यादि की विचाराधीन रख खिया जाय तव १६६०-६१ तक वर्तमान कारखाने पहिले से लाइसेन्छ मास कारखाने पहिले से लाइसेन्छ मास कारखाने की मिलाकर प्रति वर्ष २५ लाख उन चीनी का उत्यादन कर खक्तों जो कि लक्ष्य से २३ लाख उन खिक होगा। इस बात को सोवते हुये सरकार के लिए यह आवश्यक है कि नई फेहिन्सों को लाइसेन्छ देने में सावधानी करें नहीं तो भारतीय चीन उत्योग में उत्यादन शरक का आधिस्प हो जावशा और सम्मतः उत्यादन श्री का आधिस्प हो जावशा और सम्मतः उत्यादन शरीक का आधिस्प हो

ना आपर्यक्रा कोगला ब्रह्मोन

भारत में कोवले के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है। १६६० का २४० लाख टन का उत्पादन १९५७ में महक्त ४१६ लाख टन हो गया। तर् १९५० तक कोवले का उत्पादन रूपण में महक्त ४१६ लाख टन हो गया। तर् १९५० तक कोवले का उत्पादन जगभग ३०० लाख टन तक बढ़ पाया था पर १९५० में स्पंप्रयम उत्पादन बढ़कर २२६'३ लाख टन हो गया था। आगामी गर्मों में उत्पादन उत्पत्तिय बढ़ता गया है। १९५१ में ३४६'६५ लाख टन, १९५२ में ३६४'६५ लाख टन, १९५२ में ३६४'६५ लाख टन, १९५२ में ३६'६५ लाख टन, १९५२ में ३६'६ लाख टन, व्हा था। उत्पादन में यह बुढ़ि वर्तमान खानों की खिक बनी खुदाई का कार्य आरंम करने के कारण हो है।

हत्पादन क्षमता—यवापि भारत में कोयले के कुल उत्पादन में वृद्धि हुँ एरन्द्र कोयले की खानों के उद्योग की उत्पादन चमता बहुत कम है। बहुत वी खानें हतनी खोटों हैं निन्हें आर्थिक हिन्द से उत्पादक नहीं कहा जा तकता है। खानों के यन्त्रीकरणों में मि विशेष मगित नहीं को गई है। कोयला उद्योग में सितने असिक कार्य करते हैं उनकी चंखना आवश्यकता से आवला को करते हैं उनकी चंखना आवश्यकता से आवला को साम है और प्रति अम्ब देशों के विश्वीत गार्तिय खदान-अभिक की कार्य चमता कम है और प्रति अमिक उत्पादन भी कम होता है। उद्योग में कार्य करने वाले अमिकों की चंखना १६४१-५१ के मध्य प्रदर्भ वह गई है परन्तु कोवले के उत्पादन में केवल ३२% की हो बृद्धि हो पाई है इससे अमिकों को उत्पादकता में हाप प्रमद होता है। यह प्राधिक कर (शैनकला) निव्हापन और कार्यक्रमता में कार्य, कोनले के उत्पोग की स्वर्ण पत्ति और लाम को नीच स्वर पर पत्त्र ने किये उत्परदायों है।

व्योलोजिकल, माइनिंग और मैटालर्जीकल सोवाइटी की २६ वी वार्षिक में यह बताया गया कि मारत में प्रति अभिक आठ घंटे की एक विष्ट में नेटक में यह बताया गया कि मारत में प्रति अभिक आठ घंटे की एक विष्ट में २७ टन कोगले का उत्पादन होता है बब कि ब्रिटेन में १-१६ टन, जमनी में २० टन और अमरीका में २१-६६ टन कोगले का उत्पादन होता है। इसका स्टिट टन और अमरीका में २१-६६ टन कोगले का उत्पादन होता है। इसका तालपं यह है कि उत्पादन व्यय कम करने के लिए और उद्योग की वित्तीय रिपात तालपं यह है कि उत्पादन व्यय कम करने के लिए आपना कोगला उद्योग का अभिनयिकरण करने की आय रूपका है। हाभागा उद्योग का अभिनयिकरण करने में दो कठिनाइयों का शामना रूपका है। हो एक प्रक्रिया में बहुत अभिक बन की आवश्यकता होता है करना पढ़ता है—(१) इस प्रक्रिया में बहुत अभिक बन की आवश्यकता होता है करना पढ़ता है—(१) इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं कि दिस योकना को लागू और (१) अभिक इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं क्योंक इस योकना को लागू करने के अभिक अभिक बेरोजगार हो जायंगे। उद्योग की उत्पादन-बमता में नुपार करने के लिए इन दोनों कठिनाइयों को हुर करना आवश्यक है।

परिरक्षण (Conservation)—वर्तमान समय में बातुराधन के कार्य में आने वाले उत्तम श्रेणी के कोयले की काफी चित हो रही है। इस कोयले का कुल निवना उत्पादन होता है उसका ४० प्रतिशत भाग रेलवे के कार्य में आता है, २१ प्रतिशत के लगभग लोहे और इत्यात उद्योग में और १३ प्रतिशत का निर्यात और जहाजों में प्रयोग होता है। हत्यात उत्थोग में इस प्रकार के कोयले की बहुत ब्रावश्यकता होती है इसलिये इस उद्योग के उपयोग के लिये इसका संरक्षण करना पहेगा। भेटालजीकल कोल कसेटी (१६४६) अपनी जांच पकताल के पश्चात् इस परियाम पर पर्हुची कि प्रत्येक वर्षे पूर्व की कुल खपत में से (उद्योग को बिना कुछ हानि पहुँचाये) आगामी ५ वर्षों में चीरे बीरे १० प्रतिशत की कमी की जा सकती है और इस प्रकार शातुरोधन के कार्य में आने वाले उत्तम श्रेणी के कीयते का उत्पादन घटाया जा सकता है। इस समिति ने सुकाव दिया है कि (ब्र) किसी भी विशिष्पति में इस प्रकार के कोयले की खानें न खोली जायें । यदि पुनः प्रयतित करने में अधिक धन न लगे तो उत्तम भेखी के कोयले की कुछ खानों की बन्द किया जा सकता है, (ब) कीयले के चट्टे लगाने, मिलाने श्रीर घीने को कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए, और (स) खराव कोयला छोड़कर श्च-क्षा कोयला निकालने की रीति को बन्द कर देना चाहिए। योजना अरायोग ने सुमाव दिया है उत्तम श्रेणी के कोयले का संरक्षण किया जाय छोर कोयले तथा कोयला समिति से सम्बन्धित सभी विषयों पर परस्पर उचित संबन्ध स्थापित कारने वाली नीति श्रपनाई जाय। सरकार ने घातु शोधन के कार्य में श्रानेवाले कोयले के उत्पादन की अधिकतम मात्रा निर्घारित कर दो है। १६५३ उत्पादन की अधिकतम मात्रा १५१-८ लाख ठन, १६५४-५५ में १४३'८ लाख ठन, १६५६ में १५४ र लाख टन तथा १६५७ में १६० लाख टन कर दी गई।

श्रकार की इस नीति की दो आवारों पर आलोचना की गई है। यह कहा यवा है कि (अ) उत्तम प्रकार के कोम के के उत्पादन की मात्रा पर मिरियन लगाना समस्या का उचित हल नहीं है। संस्तृष्ठ करने का अपे है रीकी आ वकते वाली चित होने की खारी संसावनाएँ समाप्त करना, उत्पादन में अधिक उपयुक्त साधनी साथा उपयोग का प्रयोग कला और कोम के विश्व में मात्र के स्वादक उपयुक्त साधनी साथा उपयोग का प्रयोग कला और कोम के व्यापक होना भी आवश्यक है, (अ) कोमले के चहे समाजे, मिलानि और योग में और संस्तृष्ठ की नाम प्रमाव पहता है। सरकार का उपयोग का प्रयाग करने पर मित्र परि का करने में आतिरक स्वयं करना पहता है जिसका उत्पादन क्या पर मित्र परि का है। सरकार न तो उद्योग को आवश्यक नित्त की सहायता देती है और न अधिरिक्त करने के लिये कोमले के मूल्य में बृद्धि करने देती है। उद्योग पर उक्त मीत्रक लगाना सरकार की न्यायकात कार्यवाही नहीं नहीं में अधीर अधिक हो मूल कि विश्व विना सरकार की कोमला संस्तृष्ट मीति से उद्योग से अधीर अधिक होनी होने की संसायना है।

परिनष्ट्रस—कोशला उद्योग की एक वनसे नड़ी कटिनाई परियहन के सामनों का अभाव है। कोशले को अन्यन मेजने के लिए प्यस्त संस्था में गारिकाँ या मालागाड़ी के कि के नहीं मिलते हैं। गाड़ियाँ मिलते में बहुत देर होती है लिखते लागों के ध्यीप कोशले के डिर लाग जाते हैं। इससे लागों के कार्य में बहुत करिनाई होती है। बंगाल और बिहार के कोशले की लागों के तेन में दे जी के स-% कोशले के उत्पादन के लिखे उत्तर दायी है) प्रतिदिन लाही जाने वाली मालगाड़ियों के डिस्के की श्रीसत स्थार १९५७ में ३६६७ थी, जब कि १९५५ तथा १९५२ थी। इससे उन्नित मालगाड़ियों के उत्पादन के लिखे उत्तर हाथी १९५७ में ३६६७ थी, इस कि १९५५ तथा १९५२ थी। इससे उन्नित मालगाड़ियों के सिंह की है पर उन्नित मालगाड़ियों के सिंह की अलाहियों की सिंह में ही इससे उन्नित मालियों की सिंह में ही इससे जी आवाह्य वालगाड़ियों की सिंह में ही अलाहियां की सिंह में ही सिंह में ही अलाहियां की सिंह में ही सिंह मालाहियां की सिंह में सिंह में की सिंह में सिंह मे

कीयते के लिये शालगाहियों के हिन्सी की पूर्ति से वृद्धि खायरथक है ताकि उद्योग द्वारा कीयला मां भवा से खोर कम मृत्य पर येवा बा सके। मालगाड़ी के हिन्सी की पूर्ति में कृद्धि के लिये रेलवे के प्रशावनों में वृद्धि खायरथक होगी। इसमें निस्त्य ही समन लगेगा। परस्तु कुछ झन्य भी उपाय हैं जिनसे कोयले की लानों के सिये मालगाहने के दिन्सी की पूर्ति में बद्धि की बा सकती है। यर्तमान मालगाहने के उन्नी के खायरेवर की प्रशाली नहीं ही चटिल है जिससे देर भी लगती है और खानों पर शरमधिक कोयला भी एकनिता हो जाता है। दूधरी समस्या होने की दर की है। भारत सरकार ने कीयले के माने की दर में ३० प्रतिश्वत वृक्षि कर दी है। भाने की वृक्षि कीयला उलोग के सम्बन्ध में मियुक्त की गई वृक्षि का वृक्षि के कायले के परिवहन नयम में हिंदी की कायले के परिवहन नयम में हैं है। इस वृक्षि से कीयले के परिवहन नयम में हिंदी हो गई और इस प्रकार कीयले का प्रयोग करने योचे उद्योगों का उत्यादन व्यय भी बढ़ गया। भारतीय उलोगों का विकास करने के लिए कीयले का परिवृक्ष नयम करने की अस्यन्त आवश्यकता है।

कीयले के नियांत में कभी की समस्या मारत सरकार ने १६५५ में नियुक्त एक कमेटी के सम्मुख रक्की थी जिसने वह रिपोर्ट दी कि मारत के कीयले के मुख्य मानार पड़ोसी देवों में ही हैं। इस किये सरमा, लंका, पाकिस्तान, दिन्तयी पूर्वी परिमा के कुछ देवों को ही मारत की अपना स्वामाधिक शालार समकना काहिये। १६५६-५-५ में को गूक्य को अधिक निर्मात हुआ था वह यूका में निर्माक के आमा, दिन्त्यों अफ्रीका में यानायात की कि अपरेंग, आस्ट्रेलिया में निर्मित अपयादी स्थिति समा हो गई और जो नवीन वाजार भारत को प्राप्त हो गये के सुझ जीनत कारणों से था। १६५३ में ये १६५१-५ की अपयादी स्थिति समा हो गई और जो नवीन वाजार भारत को प्राप्त हो गये के समाम हो गई शिक्ष के जिनमें कि समाम हो गई शिक्ष के जा निर्मात कारणों के स्थान करनेटी ने निम्म सिफारियों की १९१ कोयले का स्वकारी अप किस्त होने के दिन्य कि की विभिन्न प्रकारी पर जो नियंत्रया स्था हुआ हुआ है उसे कम करना चाहिये, (२) कोयले की विभिन्न प्रकारी पर जो नियंत्रया समा है। उसे कमने चाहिये को कन्न्रील आई में दे दिये हैं, और (४) कलकते के बन्दरगाह पर अधिक प्रविभागों के देने के उपाय करने चाहिये।

पोजमा के ज्ञान्तर्गत—हितीय पंच वर्षीय योजना में कोयला उद्योग को प्रमुख स्थान दिया गया है। धीरे धीरे हित सरकारी देज में ले आया जायना। कीयलों का उत्पादन ३६७,७ लाख दन हो वो कि १९५४ में या बढ़ाकर १९६०-६१ में ४९७७ काला दन कर दिया जायना।

१६५८ के श्रीचोगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह कहा गया था कि
प्रत्येक कोमले की नमीन सान स्वकारी दोष में ही श्रारम्भ होगी, ऐसी स्थिति के
श्रुतिरिक्त वहाँ कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण्य से स्वरूप स्वकार व्यवस्थायियों का सहयोग स्रावर्षक स्वमन्ती है। श्रारम्म में इस नीति के व्यवहार में कुछ शिधिसता दिखाई गई परन्तु अब यह निजय कर लिया गया है कि मिलप्य में कीयले के
उद्योग के नचीन उपकर्ता को सरकारी दोन में ही रखने का प्रयत्न किया वायगा
श्रीर बड़ी हुई मींग को पूर्ण करने के लिए श्रतिरिक्त कोयले का उत्पादन द्वितीय
योजना काल में श्रविकतम स्तर तक सरकारी दोन में ही किया नायगा।

**₹**#0

भारतीय श्रयंशास्त्र की समस्यादं कोहा स्त्रीर इस्पाव खद्योग भारतीय लोहे क्रीर इस्पाव उचीग के चीत्र में वीत्र मुख्य उत्तादक है, उाग शायरन एएड स्टील कम्पनी, इपिडयन शायरन एएड स्टील कम्पनी (इसमें स्टील कारपोरेशन द्वाफ वंगाल भी सम्मिलित है ) श्रीर मैतर श्रावरन स्टील वर्स ! इन कारखानों में कुच्चे लोहे का इस्पात बनाया जाता है और इस्पात से आव-श्यक बस्तर्ये तैयार की जाती हैं। इनके अतिरिक्त लगमग ६४ छोटे कारखाने हैं को हुए हैं स्त्रोहे से श्रीप लोडे के कहीं से जो जनगढ़कों द्वारा प्राप्त होते हैं या द्यायात होते हैं. इस्पान नैयार करते हैं।

भारतीय द्रम्यात ज्रकोग प्रशिया में सबसे बका है और संसार के स्वीत्तम इत्पात उद्योगों में से एक है। १९२४ में संरक्तण मिलने के पश्चात इसने महत्व-पूर्ण प्रगति की है। उद्योग की उत्पादन समक्षा में इतनी स्वीह हुई कि १६४१ में संरक्षण की कक्ष आवश्यकता नहीं रही। इस्पात का उत्पादन १९५७ में ८६ लाख दन या जो बहरूर १९५२-१९५५ तथा १९५७ में अमनः ११ लाख दन. १२ लाख टन क्रीर १३ लाख टन हो गया। १६५० में उत्पादन की मात्रा ४५ लाख टन श्रतमानित की गई है। १९५३ में इस्पात और दले हुए लोहे का उत्पादन १९५२ की श्रमेका कम हो गया। इसका कारण किसी सीमातक तो अमिकों के कराडे ये छोर किसी सीमा तक यन्त्रों के ख्राभिनशीकरण के कारण उत्पन्न यह श्राध्यवस्था थी जिसके फलस्वरूप करू समय के लिए कारखानों को गर रखना आवश्यक हो गया था। इसके अनन्तर उत्पादन में वृद्धि हुई और भविष्य में इतके ग्रीर श्रधिक बढने की संमानना है। मारत के इस्पात ग्रीर सोहे के उद्योग की मुख्य समस्याएँ (अ) इत्यात के उत्यादन में वृद्धि करना, (व) दले हुए लोहे के उसादन को फाउन्होंयों के लिये बढाना है।

लोहे और इस्पात उद्योग के लिए ब्रावश्यक कच्चा माल भारत में ही भार है। जितना करवा माल वर्तमान समय में प्राप्त है उतने से ही उद्योग के लिए इस्पात बढ़ा खेना सम्भव है।

इस्पात का मूल्य-देशी इस्पात का मूल्य आयात किये हुये इस्पात से बहुत कम है। मूल्यों में समानता लाना बहुत ब्रावश्यक है। यह मूल्य के नियंत्रण द्वारा ही ( सदकाल से आज तक ) सम्भव हो सका है। १ अवट्रवर १६३६ से ३० जून १६४४ तक युद्ध के लिये कय किये जाने वाले इस्पात के मूल्य पर नियन्त्रण् था । परन्तु इस्थात के व्यवसायिक मूल्य पर कोई नियन्त्रण् नहीं था । इरपात के व्यवसायिक मूल्य पर परिनियमित रूप से नियंत्रण १ जलाई १६४४ से आरम्भ हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार जिस प्रखाली का अनुसरण करती है उसके

अनुसार प्रत्यारच्या मृह्य (retention price) नियत कर दिया जाता है जिस पर मुख्य-मुख्य उतारक इसात विकय करते हैं, और उपमीकाओं के लिये मृख्य की २२ उट्टा उपर अभारण बुभाग प्रकार भरम थु आर अभारणाम्बाला मा एवा पर भार एक झन्य ऊँची दर नियत होती है जिस पर वे क्षम करते हैं। होती मूल्यों के श्चन्तर ते प्राप्त घन समानवा स्थापित करने वाले कीप (cqualisation method) कार प्रतास वर्ग वर्गावया र वर्गावया कार कार कार कार प्रतास कार स्थाप के आबात में सहस्वता प्रदान की जाती है जीर इस्पात उत्पादकों के ज्ञामनवीकरण तथा विकास के कार्यक्रमी में म्राधिक सहायता दी जाती है। एक जुलाई १९४४ मीर ३१ मार्च १९४६ के मध्य अगरण व्यानमा राजागा राजण उपान अपनि अगर रहे गान अवस्था राजण इस्पात के दो प्रत्याखण मृहण निर्वासित किये गाने वे। एक युद्ध के लिये क्रय कराम च था नावारच्य के लिये जीर दुवरा व्यवस्थिक प्रयोग के लिये, परन्तु १ कार नाम करनाथ कर

वर्तन के साथ प्रत्यारक्य मूल्य और विकाय मूल्य बदलते रहते हैं ! . साथ भाषारक्ष्य पूरूप आर (याप्य पूरूप पर्वाच रवा व । मग्रस्क सवहल की सिकारियों के अनुसार सरकार ने यह बात स्वीकार कर लो है कि १६५६-५६ से १६५६-६० तक की अवधि के लिये ३६३ ६० प्रति टम के प्रस्वारस्य मूह्य की एक ही दर टाटा कम्पनी और इन्डियन आयरन एवड स्टील कम्पनी के लिये निषत की जानी चाहिये। इस पुनर्निप्तिवत मूह्य के लागू करने के लिये सरकार का प्रस्ताय करवरी १९५६ में पात हुआ। इसी समय १९५४-५५ के लिये पुनंपरिचित प्रत्यारच्या मूल्य १४३ व० प्रति टन का टाटा ९८,२४,२४, च ।राज उज्जाराय्य जाजार्युय कर्म स्रायरन एसड स्टील कम्पनी के लिए और ३८६ व० प्रति टन का इन्हियन स्रायरन एरह स्टील कम्पनी के लिए नियत किया गया। इस बात की सब ने स्वीकार कर लिया कि १९५४ पत्र का समायोजित प्रत्यारक्या मुख्य छोर ३६३ वं प्रति टन के समान प्रत्यारस्य मृह्य का अन्तर प्रत्येक कायनी अपने विकास कोर में दे देगी।

भूतकाल में इत्याद का मूल्य समाई, कलकता, महाण, कारोबद्धुर क्रीर् मृतकाल में इत्याद का मूल्य समाई, कलकता, महाण, कारोबद्धुर क्रीर् बरनपुर में ५०० बस्य प्रति टन या, जीर अन्य त्थानी पर उपभीकाओं की उसके साथ परिवहन व्यय मिला कर देना पडता था। इसका अर्थ वह या कि (१) उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्पादन केन्द्री तथा बन्दरवाही से तूर स्थित नगरों के उप-भोक्ताओं को अधिक मृत्य देना पड़ता था; और (२) बन्दरमाहों के निकट उद्योग केन्द्रित होते जा रहे वे क्योंकि उन्हें वहाँ इस्पात सस्ता मिलता था। सरकार की खून १९५६ की नई नीति के अनुवार इत्यात का एक ही मूल्य (५२५६० प्रति टन) जिसमें रेल का किराया सम्मिलित होगा रेल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगा । इस प्रकार कपर बताये हुए पाँचों स्थानी पर उपभाक्ताछो को २५ ६० प्रीत टन अतिरिक्त मूल्य देना पढ़िया और उन उपमीकाओं को जो अमृतसर और कानपुर ऐसे स्थानों में हैं लगमग ३५ ६० प्रतिटन कम देना पड़ेगा। पहले मूहण में समानता लाने के लिये खिद्धान्त का प्रयोग केवल इस्पति के सम्बन्ध में ही लागू किया गया था। श्रव यह खिद्धान्त दाखे हुए लोहे के सम्बन्ध में भी लागू क्षिया जायगा। इस नई मीति के कारण इस्पाद श्रीर लोहे के मूल्य में भारत के उत्तरी भाग में रहने वाले व्यक्तियों के लिये कभी हो जायगी। श्रीर दुलेंम वसुर्वे प्रयोक से श्रीक संश्वेत मुख्य पर आस हो सक्षेत्रों।

हस्तात के मूहर पर उरकारी नियन्त्रख उपभोकाशों के लिये लामकारी खिद हुआ है क्योंकि विना हठ नियन्त्रख के उन्हें वे वस्तुर्य आधिक मृत्य पर प्राप्त होती। परन्तु कम प्रध्यारख्य मृत्य के नियन किये जाने से उत्पादकों को हानि हुई हैं। यदि उत्पादकों को उंचा मृत्य मिला होता तो वे अवस्य उद्योग के विद्यार करने में तथा आधिनवींकरण में न्यय किया जाता। श्रव उन्हें हर कार्य के तिये उपकार ते तथा अधिनवींकरण में न्यय किया जाता। श्रव उन्हें हर कार्य के तिये उपकार ते श्रवण छोना पका है और उपकार में मृत्य वमीकरण कीय (equalisation fund) ते यह श्रवण दिवा है। वृष्टरे उन्हों में हम यह कह उकते हैं कि वरकार ने उद्यादकों की वह चया हि। वृष्टरे उन्हों में हम यह कह उकते हैं कि वरकार ने उद्यादकों की वह चन श्रवण के लग में दिवा है जो कि तथा अपन इत्यात के उद्यादकों को वह चन श्रवण के लग में दिवा है जो कि तथा अपन प्रवाद हुआ है आधिक मृत्य का लाभ न उद्याने दिया जायाता तो आर्थिक मन्दी के समय जब मृत्य उत्पादन न्यय से कम होता है वे हानि का सामवा किसे करीं।

भविष्य की मांग —लोहा और इस्तात भेजर पेनेल ने १६४६ में अतु-मान लगाया कि मारत में २० लाख टन इस्तात की लगत है, जब कि युद्ध के पूर्व केवल दश लाख टन की लगत थी। परम्तु १६४० में प्रामर्भदावी नियोजन परिषद ने खतुमान सागवा कि देश में सामान्य स्थिति में १५ लाख टन इस्तत की लगत है। इपि तथा श्रीवोगिक विकास पर विचार करते हुये रोजना श्रावोग ने अनुमान लगाया कि १६५२ में कुल २२ लाख टन की खायश्यकता होगी और १६५७ तक २० लाख टन की खायश्यकता हो जायगी। लोहा और इस्तार नेमलें ने अनुमान लगाया है कि भारत को काउन्हिंगों के लिये प्रतिवर्ध ३ लाख टन टलें दुवे लीहें की आवश्यकता होगी। वाख्यक्य मन्तालय के छोटे और वह इंजीनिरिंग उद्योग के जाँच करने वाले पेनेल ने १६५१ में बताया कि मारत को भ लाख से भ-२ लाख टन तक दलें दुवे लोहें की आवश्यकता थी। दितीय पचवर्षीय योजना का अनुमान है कि १६६०-६१ में इस्तात की माँग लगमम ५५ लाल टन की और काउन्हिन्दों के लिये ढले लोहे की आंग लगमम ७५ लाट टन की होगी। ग्रुथ्य उत्पादकगण टला लोहा अपने प्रयोग के लिये तथा काउन्हियों के लिये ही पी उत्पादित करते हैं। इसलिये फाउन्ट्रियों के लिये ढले लोहे की पूर्ति में वृद्धि करने के लिये प्रमुख उत्पादनों को अपने उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी।

योजना के अन्तर्गत — दितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत में इस्तात के उत्पादन के विकास पर विशेष महत्व दिया है। उद्योगीकरण की वर्तमान वहीं हुई प्राति को बताये रखने के लिये और मारत में यन्त्री के निर्माण करने वाले उद्योग कर के स्वाप्त के अपना के स्वाप्त के उत्पादन की माना कहा है जाता दितीय योजना में १२६०-६२ तक ४३ लाख उन इस्तात के उत्पादन का प्रकार किया गया है। इसमें से बतमान तीन प्रमुख उत्पादक अपने विस्तार के कार्य कम के पूर्ण कर लोने के परचात का प्रमुख उत्पादक अपने विस्तार के कार्य कम को पूर्ण कर लोने के परचात काममा २३ लाख उन की पूर्व कर उक्तेंग । उत्पादन काममा २० लाख उन का उत्पादन हो चरमा विभा कहीं अधिक होगी।

लोहे और हस्पात के उत्पादन को प्रधानता देने के निर्याय के श्रमकल दितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी चेत्र के शान्तर्गत तीन इस्पात के कारखाजी की स्थापना का निश्चय है जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख रन होशी. और इन तीन में से एक को ३०५ लाख रन फाउन्डियों के प्रयोग में आने बाला दला हुआ लोहा तैयार करने की मुविधार्य प्राप्त होंगी । स्त्रकेला में खोले गये कारखाने में १९५६-६१ में १२८ करोड़ क्वये के विनियोग का धन-मान है। यह ग्राशा की जाती है कि ७.२ लाख दन इस्पात की चपटे श्राकार की वस्तुश्रों का उत्पादन करेगा । दशरा कारखाना, जो कि मध्य-प्रदेश में भिलाई स्थान पर स्थापित किया गया है, उस पर लगभग ११० करोड़ रुपया स्थय किये जाने का अनुमान है। उससे इस ग्राशा करते हैं कि ७७ लाख उन विकय योग्य इरपात तथा वजनी श्रीर मध्य श्रेणी की वस्तुश्रों का उत्पादन हो सकेगा जिसमें १.४ लाख दन पश्चक का भी रिनोलिझ उद्योग के लिये उत्पादन समितित होता। तीसरा कारखाना दर्शवर में, जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थिति है, खोला गया है जिसमें लगमग ११५ करोड़ रुपये के न्यय होने की आशा है। यह कारखाना ऐसे प्रसाधनों से यस होगा कि वह हरूकी श्रीर मध्य श्रोगी की उत्पात तथा पत्रक की वस्तुत्रों का निर्माण ६.९ लाख दन तक प्रतिवर्ष कर सकेगा।

सरकारी देज के समान ही व्यक्तिगत दोत्र में भी इस्पात श्रीर लोहे का स्थान श्रीयोगिक योजना में एक बहुत बड़ी महत्ता रखता है। इस उद्योग पर व्यक्तिगत द्वेत में लगभग ११५ करोड़ रुपये के विनियोग का विचार किया गया है। प्रथम योजना के श्रन्तगीत व्यक्तिगत दोत्र में लोहे श्रीर इस्रात उद्योगों के

विस्तार सम्बन्धी विनियोग तथा को कक क्यम हितीय योजना के अन्तर्गत किया गया है उस संग्र का फल १६५० के ग्रहण से जिल्ला गराच्या होता लड़कि राहा श्रायरन एएट स्टील कम्पनी तथा इक्टियन जायरन एवट स्टील कम्पनी की संयक्त अत्यादन क्रांकि बर्तमान १२ व लाख रन के स्थान वर २३ लाख रन के सराध्या हो जागाहि ।

हितीय पंचवर्षीय योजना ने इस्पात और लोडे के उत्पादन के बढाने पर उचित ही स्पान दिया है। इस्पात अधिक सात्रा में श्रीक्षेत्रीकाल का आधार है श्रीर इस्तास के जलाइज की बढ़ि श्रीवीतिक जबति के लिये श्राचान श्रावस्यक है। लोहें का उत्पादन बढ़ाने में सरकारी स्त्रेत्र पर बहत अधिक विश्वास है। रूट मई. रहम्म की घेन्तीय सरकार ने लोडे और इस्पात के लिये एक मंत्रालय की नियक्ति की जिस पर लोडे और इस्पात के जत्यादन सम्बन्धी सरकारी कार्यों का तथा सरकारी फाउन्डीयों की देखभाल का भार रवला गया। कछ लोगों के मत में यह श्रमिक श्राच्छा होता यदि इस्पात के उत्पादन में विद्य करने का भार मख्य रूप से वर्तमान उत्पादकों के उत्पर ही छोड़ दिया गया होता क्योंकि उन्हें इस बात का श्रायप्रयक श्रानभव था श्रीर सम्भवतः वे श्राधिक जीवता से श्रीर कम लागत पर उत्पादन की विक्र करने में सफल भी प्रये होते। सीमेन्ट बटोग

सीमेन्ट के उत्पादन में भारत ने जल्लेखनीय प्रगति की है। १६४५ में केवल १५ लाख टन का उत्पादन या जो १६५७ में बढ कर ५६ लाख टन हो गया । १६५२ में भारत में केवल २३ फैक्टियाँ थीं, जिनकी उत्पादन शक्ति ३७% लाख रन थी। १६५७ में २६ फैक्ट्रियों थी जिनकी स्थापित सामर्थ ६६°३ लाख टन थीं। मारतीय सीमेन्ट उद्योग की बास्तविक उत्पादन शक्ति में नह फैक्टियों की स्थापना तथा पूर्वकी फैक्ट्रियों के विस्तार के कारण वृक्षि हुई है। सीमेन्ट्र उधीग की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है: (१) मतकाल में उत्पादन की मात्रा उनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति से बहत कम थी और १६५० में जब कि वास्तविक उत्पादम शक्ति ३१ रू लाख रन थी उस समय उत्पादन केवल २६'१ लाख टन था। परन्तु इधर हाल में इस दोप का किसी सीमा तक निराकरस कर दिया गया है; (२) बहुत फैक्ट्रियाँ अनुकूलतम उत्पादन शक्ति से बहुत नीचे स्तर पर हैं, नवीन फैक्ट्रियाँ उपयुक्त आकार की है और शेक्ट्रतम बन्त्रों का प्रयोग कर रही हैं। (३) सीमेन्ट उन्नोग को आवश्यक संख्या में मालगाड़ी के डिब्ने नहीं प्राप्त होते जिनसे कच्चा माल लाया जा सके और तैयार सीमेन्ट उपमोग वेन्द्रों की शीवता पूर्वक मेखा जा सके, और (४) सीमेन्ट का नियंत्रित मूल्य सब फेलिट्रयों के हिन्दिकोण से न्यायोचित नहीं रहा है, क्योंकि अन्य फैक्ट्रियों से तन्तनार्ये वो अधिक न्यवंदियन यी कुछ फैक्ट्रियों का उत्पादन न्यय अधिक रहा है ।

इधर हाल में स्थिति में घोर परिवर्तन हुआ है। छांमेन्ट दुर्लम हो नहीं वरन् वहुत मंहगा भी हो गया है। इस बात को विचाराधीन करते हुने सरकार ने सीमेन्ट का क्रम किक्व अपने हामों में से खिना है और उठके लिये एक किक्क मूल्य १ जुलाई १९५६ से लामू कर दिया है। यब सीमेन्ट के उपायत के के प्रक अपना सीमेन्ट केटट ट्रेडिक्क कारणोरेशन आफ इन्डिया (साइवेट लि०) के हाथ फेन्ट्री के बाहर उपयोग केन्द्री तक पहुँचाने में लगे रेलवे के किरामें के अपधार पर नियत मूल्य पर बेचना होगा। यह कारणोरेशन सीमेन्ट १०२ ०० म्हाने मित उन के मुख्य पर बेचना होगा। यह कारणोरेशन सीमेन्ट १०२ ०० म्हाने मित उन के महुष्य पर बेचना है। महे १९५७ में सीमेन्ट पर लगा उत्पादन कर ६ वन सित उन के बहुकर २० क मित उन कर दिया गया। सीमेन्ट का मूल्य मी इतना है। बहु शरा ।

देश के विभाजन के फलस्यरूप कक सीमेन्ट की फैबिटयाँ पाकिस्तान में चली गई'। यही कारण था कि १९४७ में उत्पादन वट कर १५ लाख टन ही गया जब कि १६४५ में २२ लाख टन था। परन्तु देश ने बहुत शीध ही विभाजन के प्रभावों से सकि पा ली और उत्पादन में बृद्धि आरम्भ हो गई जो आज तक निरम्तर चल रही है। खुबोत्तर काल में सीमेन्ट उद्योग की विकास सम्बन्धी उल्लेखनीय विशेषताएँ यह हैं: (१) १६३६ में सीमेन्ट उद्योग प्राय: मध्य प्रदेश श्रीर मध्य भारत में ही केन्द्रित था। परस्त एसोशियेटेड सीमेन्ट कम्पनी द्वारा युक्तिकरण की योगना के लागू किये जाने के फलस्वरूप कुछ पैविटयों को नये स्थानों पर स्थापित किया गया। यहोत्तर काल में इस उद्योग का विकास प्राधिक सन्तुलित ढंग पर हुआ और नवीन स्थानों पर कारखाने स्थापित हुये। इसका परियाम यह हुआ कि सीमेन्ट के कारलाने सम्पूर्ण देश में फैले हैं। इससे देश के विभिन्न मार्गा में प्राप्त होने वाले कच्चे माल का भी उचित प्रयोग सम्भव हो गया है। साथ ही यातायात में बहत सा व्यर्थ व्यय जो उद्योग के किसी एक स्थान पर केन्द्रित होने के कारण करना पहला यह भी बच गया। (२) भृत काल में लिमेन्ट उद्योग व्यक्तिगत उपक्रम था, परन्तु श्रव सरकार ने भी इस उपक्रम में भाग लेना श्रारम्म कर दिया। मैसूर राज्य की फैन्ट्री के श्रतिरिक्त, जिसकी उत्पादन शांक ३६ इजार टन से बहा कर ६० इजार टन कर दी जायगी, उत्तर प्रदेश की राजकीय भैत्रद्री विपरी में स्थापित की है जिसकी उत्पादन शक्ति २३ लाख की है। (३) भूतकाल में अधिकाँश कारखाने < oo टन ही के अनार्थिक से भी कम उत्पादन वाले थे। परन्तु हाल में जो कारखाने स्थापित किये गये हैं वे आर्थिक

हाँच्ट से उपयुक्त हैं और प्रायः सभी कम मात्रा में उत्पादन करने वाले कारखानी ने अपनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि की है।

सीमन्द्र की आन्वरिक माँग उसकी पूर्ति से अधिक होगई। देश में उत्पादन की गृद्धि के आलावा १६५६ के प्रारंग में यह निश्चय किया गया कि उस वर्ष विदेशों ते ७ लाख टन सीमेन्द्र का आयात किया जाय। राज्य-ज्यापार निगम (State Trading Corporation) ने इस मात्रा से आयात के लिने बहु न्यवस्था कर रखी थी किन्तु बीच में देशेन का सकट उपस्थित हो लाने पर १६५६ में केवल १०८,००० टन सीमेन्द्र हो आ कका। १६५७ में ३२१,००० टन सीमेन्द्र भीर आयात और कम होगा। इसका कारण विदेशी विनयम का सकट नहीं देशे के स्व

योजना के अन्तर्गत-प्रथम योजना में यह प्रस्ताव किया गया था कि विमेंट के कारखानों की सख्या १६४०-५१ में २१ से बढाकर १६५५-५६ में २७ कर दो जाय । साथ ही इनकी ३३ लाख रन की उत्पादन शक्ति तथा २७ लाख टन उत्पादन बढाकर १९५५-५६ में कमशः ५३ लाख टन और ४८ लाख टन कर दिया जाय । सध्य प्रदेश, सध्यक्षारत छीर टावनकोर कोचीन में सिमेंट के कारखानों को अनुगणित शक्ति में वृद्धि का कोई नियोजन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश. उड़ीसा और बम्बई में नवीन कारलाने लोले जाने वाले थे। दिहार, राज-स्थान और महाए के कारखानों की शक्ति में वहि करना शत्यन्त स्नावश्यक था को पूर्व के कारखानों में आंतरिक नवीन मशीनों के प्रयोग से ही सम्भव था। इस कार्य के बरने में प्रधान कठिनाई धन के स्थाब की सी। कररखानों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने श्रीर उन्हें १३ लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन करने योग्य बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा मे धन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की विमेंट फैन्द्रों की स्थापना में, जो कि मिर्जापुर जिले में चुके में है, ४३ करोड़ रूपये की लागत लगी थी। उनकी उत्पादन शक्ति २'५२ लाख दत प्रतिवर्ध की है। पद्यपि उत्तर प्रदेश की फैन्ट्रो का कुल व्यय सरकारी कर्मचारियों की अनुमवहीनता के कारण बहत ग्रथिक हो गया है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि भारत की वह सर्वोत्तम फैनिटयों में से एक है।

प्रयम योजना में अनुगणित उत्पादन शक्ति तथा थास्तविक उत्पादन के लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाने थे, परन्तु काजी हद तक क्यकता अवश्य मिनी थी। ११५५-५६ में सीमेंट की उत्पादन शक्ति और उत्पादन कमरा: ४०४ लाख टन और ४४ लाख टन यी वनकि प्रथम गोजना में कमरा: ५३ लाख टन और ४८ लाख टन का लक्ष्य था। देश के श्रीयोगीकरण में उत्पादि हो जाने पर सीमेंट की माँग में चृद्धि होगी। इसिलिये दिवीय योजना ने १६६०-६१ तक उत्पादन सिंक को १६० लाख उन तक (विसमें से ५ लाख उन सरकारी होत्र में बढ़ेगा) और वास्तियिक उत्पादन को १३० लाख उन मद्दीने का खदब बनाया है। यद तक धारत यरकार द्वारा ५५ स्क्रीग बिनमें २५ नई हैं तथा १६ वर्षमान उत्पादन इकाइयों के विस्तार से सम्बन्धित हैं, गंब्र् की गई हैं। यह स्क्रीग प्रभति के विभिन्न स्वरों पर हैं। इनमें से १५ स्क्रीग (४ नई तथा ११ विस्तार मामन्यी) जिनकी फुल उत्पादन शक्ति १८ लाख उन है १९५८ के अन्त तक पूरी हो कांव्यों। १९५६ के अन्त तक ११ और स्क्रीग पूरी हो कांव्यों तथा आशा की जाती है कि इस सम्य तक कुल उत्पादन शक्ति १०४ लाख उन हो जायगा। शेय स्क्रीय १६६०-६१ तक प्रभी होगी।

कागज उद्योग

वर्तमान समय में भारत में कागज की १६ मिलें हैं जिनकी स्थापित जलादन शक्ति २५०,००० उन है। कागज उद्योग को १६२५ से १६४७ तक संरक्षण दिया गया था। इस उद्योग ने निःसन्देह अस्त्रेखनीय प्रगति की। १९५२ में भारत में केवल ६ मिलें थी जिनकी उत्पादन-शक्ति २७ हजार टन थी। १९५६ में २१ मिलें थी तथा उनकी उत्पादन शक्ति २११.६०० टन थी। १६५७ में मिलों की संख्या घटकर १६ होगई क्योंकि उत्पादन की दो इकाइयाँ जो बन्ट सी ही थीं सची में से हटा दी गई। किन्त विस्तार की योजनाओं के पूरी हो जाने के कारण उद्योग की स्थापित अस्पादन शक्ति बढकर २ वाल उन हो गई है। कागज त्रकोश की तीन श्रेंबियाँ हैं (१) कागज और पटा, (२) खलबारी कागज की लखी टफ्डी तथा चन्य प्रकार की टफ्तियाँ। कागज तथा पह के उत्पादन में उल्लेखसीय विक्र हुई है। सुली टिफ्तयों तथा अन्य प्रकार की दिफ्तयों के उत्पादन से विशेष प्रगति हुई है। परन्त देश में अखनारी कागज का बहुत अभाव है। सविष्य में काराज उद्योग का विकास करते समय श्राखवारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने की सम्मया पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यह के उत्तर काल में (अ) यह उद्योग नवीन स्थानों पर मा आरम्भ हो गया है और अधिकांश प्रदेशों में आज कागज बनाने वाली मिल है, (ब) अब अनेक मकार के कामज तथा दफिनयों का उत्पादन होने लगा है यहाँ तक की खप्ले और दिप्ले दिप्तयों तथा काफ्ट लपेटने के कागज के उत्पादन में तो विशेष प्रगति हुई है !

कागज उद्योग की उन्नेखनीय विशेषता यह है कि उत्पादन शक्ति की बहुत अधिक प्रतिशत मात्रा का उत्पादन हुआ है। १६४८, १६४६ और १६५० में कमग्र: ६७,००० टन, १०३,२०० टन और १०८,६१२ टन का उत्पादन हुआ था जो कि उत्पादन शकि का लगमग व्ह%, ६४% और व्हैं होता है। १६५७ में २१०,१२५ दन का उत्पादन हुआ जो कि उत्पादन शकि का दिश्र था। यह सब होते हुये भी कागब उद्योग को अभिको के मगड़े तथा पर्याप्त मात्रा में कच्चे मात्र के कादोचित मृत्य पर न मिल एकने को कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा है और निम्म स्तर के कोवते का सिक्त किये निम्म का सामना करना पढ़ा है और निम्म स्तर के कोवते का सिक्त किये मिनों के नायत्तर अनुप्युक्त हैं, प्रयोग करना पढ़ता है। बॉस और वास के मैरानों के नायत्तर अनुप्युक्त हैं, प्रयोग करना पढ़ता है। बॉस और वास के मैरानों के न्यायोचित मृत्य पर दीर्थकालीन पढ़ी पर न उठाये जाने के कारण हानि उठानी पड़ी है। इसके अतिरिक्त जब से रेल विधाग ने अपनी अधिमान्य पढ़ित (Preferential System) को माल के यातायात्त सुविचा के समझ में पिना विक्त प्रयाद की कारण होते थी उठका प्रयत्त हो पत्र है। इस कि प्रयत्न किया उत्पाद मी पातायात्त सुविचा पत्ने में प्रतिच्चा करनी पड़ती है। इस कठिनाह्यों के कारण ही कागज़ उचीग की उत्पादन सामत स्त्र हो गई है।

कचा माल-कागज और पड़ा अथवा दफ्ती उद्योग अपने रूडचे माल के लिये बाँच क्यीर सनई बास का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त कुछ कार-लाने चिथहे. रही कागज, जोनी की सीठी इस्वादि का अपयोग करते हैं। भारत में देते कश्चे माल का कुछ अभाव नहीं, परन्तु उद्योग के उपयोग के लिये स्नकी पूर्ति का संगठन करने की आवश्यकता है। कागज उद्योग में अनेक रखायनी जैसे चुना, कारिटक सोडा, सोडा ऐश, क्लोरीन, गंघक आदि का भी उपयोग किया जाता है। गंधक को छोड़ कर अन्य सब रसायनिक भारत में ही मिल जाते हैं। कुछ सीमा तक कास्टिक सोडा और सोडा देश का विदेशों से आयात करना पहला है। मध्य प्रदेश के कागज के कारखाने सवाई की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। परन्तु इसके साथ ही बीट, देवदार, ब्रीर एक प्रकार के सरों के बृज्ञ की कोमल लकड़ी का भी उपयोग किया जा सकता है जिसकी भारत में बहतायत है। यदि मुलायम लकड़ी के बनो का विकास किया जाय, लकड़ी को कारखानी तक पहेंचाने के लिये यातायात की उच्चित व्यवस्था की साथ और एक कारखाना श्रखबारी कागज श्रीर कैमिकल परूप बनाने के लिये स्थापित किया जाय तो अखबारी कागज उदांग के लिये आवश्यक करने माल की पूर्त को बढ़ा सकना सम्मव है। कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में योखना आयोग ने निम्नलिखित सुकाव दिये थे: (१) कागज उद्योग के काम आने वाले पेडों के वनों की मुरदा की जाय और इनका उपयोग कर सकने के लिये उद्योग को दीर्घकालीन पद्टे के अधिकार दिये जाँय: (२) बॉस और सर्वे धास के सारे देश में एक तर्क संगत आधार पर मुल्य

निर्धारित किये जाँग जिससे उजीग को फरुचा माल निरंतर प्राप्त हो सके। राज्य सरकारों के दितों की रखा करने के लिये कच्चा माल एक निश्चित मूल्य पर सरकारों के दितों की रखा करने के लिये कच्चा माल एक निश्चित मूल्य से उचीगों को दिया जाग और इचके आप ही उनके तैयार माल की विकय मूल्य से सानियत मन्यांत्र (premium) की कोई मात्रा लागांग्रा में से उनने यहांती सानियत मन्यांत्र (premium) की कोई मात्रा लागांग्रा में से उनने यहांती सानिया के लिये जंगांची में सहके निर्माद विश्वल पर करवे की कहरन, पटसन और जुट तथा रही कागज का निर्यात विश्वल पर करवे की कहरन, पटसन और जुट तथा रही कागज का निर्यात विश्वल पर करवे की कहरन, पटसन और जुट तथा रही कागज का निर्यात विश्वल पर करवे की कहरन, पटसन और जुट तथा रही के संबच्च में राज्य सरकारों की कोई

पह लोग नाप ।

यह लोद की बात है कि बन विकास के संबच्च में राज्य सरकारों की कोई

यह लोद की बात है कि बन विकास के साल पट पर देने में बहुत अधिक

सुतंबद नीति नहीं है और कागज की सिलों को जगल पट पर देने में बहुत अधिक

सुत्य बद्द करती हैं। रेल परिवहन के माड़े की दर मी अधिक है। भारत सर
मृत्य बद्द करती हैं। रेल परिवहन के माड़े की दर मी अधिक है। भारत सर
कार पुराने अल्लारों की रही के आयात पर भारी आयात कर बदल करती है

कार पुराने अल्लारों की देश के आयात पर भारी आयात कर बदल करती के बेव

और अपनी रही का स्टाक किना किली बात का थ्यान किये ठेकरारों को बेव

देती हैं, जो उसे वैकिंग हम्मादि के लिए बाजार में बेव देते हैं। केन्श्रीय स्था

देती हैं, जो उसे वैकिंग हम्मादि के लिए बाजार में बेव देते हैं। केन्श्रीय स्था

राज्य सरकारों की नीति में परिवर्तन करने से उच्चोगी को कथा माल पर्यात माना

में दिया जा एकता है।

पाइना के अन्तर्गत —िविभिन्न कात्रज्ञ की मिली के प्रसार कार्यक्रम को पाइना के अन्तर्गत —िविभिन्न कात्रज्ञ की मिली के प्रसार कार्यक्रम की लगा करने दे यह आशा की जाती है कि प्रयम योजना काल में उद्योग की उत्पान प्राप्त १११,००० टन कात्रज्ञ और दिश्तमाँ और १०,००० टन कात्रज्ञ और व्यवस्था की जात्रगा । और १०,००० टन अलबारी कात्रज्ञ का वास्तविक रूप से उत्पादन से जात्रगा । और १०,००० टन अलबारी कात्रज्ञ के उत्पादन से अनुमानतः १६५४-५६ वर्ष प्रसाद से बनने वाली विभिन्नयों के उत्पादन से अनुमानतः १६५४-५६ वर्ष प्रमाद से वर्षने वर्षा विभिन्न प्राप्त भ्याप्त से व्यवस्था और वास्तविक उत्पादन प्राप्त भ्याप्त प्राप्त योजना के उत्पादन प्रश्न १२,००० टन हो आयम योजना के उत्पादन प्रस्तु भ्याप्त से प्रयम्भ योजना के

उत्पादन १६,००० वन द्वार ।

कागज श्रीर कागज की दिखियों के उद्योग के खंबन्य में प्रथम योजना के

कागज श्रीर कागज की दिखियों के उद्योग के संबन्ध में प्रथम योजना के

कहर बाली वर्षममम

कहर बाली वर्षममम

कहर बाली वर्षमम

कहर बाली वर्षमम

कहर बाली वर्षमम

कहर बाली वर्षमम

कहर बाली वर्षमा

कहर बाली वर्षमा

का अव्यादन करेगी तब २०,०००

द श्रावा की जाती है कि जब यह मिल ग्रांक मर उत्यादन करेगी तब २०,०००

द श्रावा की जाती है कि जब यह मिल ग्रांक मर उत्यादन करेगी तब २०,०००

क्षावा गया है कि १९६०-६१ तक स्थानित उत्यादन ग्रांक तथा कागज श्रीर कागक

किया गया है कि १९६०-६१ तक स्थानित उत्यादन ग्रांक तथा का या और ३५

की दिन्तयों का वास्तिवक उत्यादन बढ़ा कर कम्यां ४५ लाख उत्यादन ग्रांक तथा

ताल उत्यादन कर दिया जाय श्रीर खब्बमरी कागज के स्थाणित उत्यादन ग्रांक तथा

वास्तिवक उत्यादन बढ़ाकर ६०,००० उन तक कर दिया जाय। दितीय योजना के

वास्तिवक उत्यादन बढ़ाकर ६०,००० उन तक कर दिया जाय। दितीय योजना के

अहोत के कार्य की सरलता से चलाने के लिये देश का श्राधिक बातावरण

अनुकल बनाया जाय. (२) कच्चे माल तथा तैयार माल के यातायात के लिये मालगाटी के डिब्बों की पूर्त बढाई जाय, और (३) कच्चे माल की पूर्त बढाई काय । भारत से चीनी अलोग के पर्यो रूप में विकसित अवस्था में होने के कारण गुले की सीठी का कागज बनाने के लिए प्रयोग बढ़े लाम के साथ किया जा सकता है। १९५५ के अन्त में जर्मनी के विशेषकों का एक दल भारत में इस विषय का परीज्ञ सा करने तथा जिलेह देने के लिये आया था। पश्चिमी जर्मनी की एक कर्म से सीठी पर क्षाधारित ३०० टन प्रतिदिन का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाई की स्थापना पर वातचीत चल रही है।

बाग्य जरोगों की भौति कागज उसोज के जलादन के प्रकार तथा उत्पादन व्यय कम करने के लिये उपाय करना श्रास्थन्त श्रासप्रयक है। योजना खायोग ने यह ग्रमिस्ताव किया है कि कागल उद्योग को अपने उत्पादन की प्रविधि को श्चाध्तिक बनाना चाहिये जिससे यह निम्न कश्यों को प्राप्त कर सके; (१) ईंधन तथा करने माल के प्रयोग में कमी करके कागज की उत्पादन लागत में कमी, और (२) विभिन्न प्रकार के कागजों, विशेषकर रैपिंग और क्षाफ्ट कागज, की प्रकार में

उम्मति । यदि यह सधार सम्भय हो सके तो कागन उत्योग में स्थापित्य ह्या जायगा ।



## छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कटोर उद्योग

भारत की ख्रीशोगिक व्यवस्था में क्षोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले ख़ीर कुटीर उद्योगों का स्थान कदा से ही महत्वपूर्ण रहा है। शिल्पकारों की एक बहुत बड़ी संख्या कदेव इन उजोगों पर ही अपनी जीविका के लिये निर्मर रही है। परन्तु दितीय पंचवर्षीय योजना ने छीटी मात्रा में उत्पादन करने बाले तथा छुटीर उद्योगी को भारत में कहारी की कठिन कमस्या को हल करने के साधन के कर में रख कर दितीय शोजना के अपने के साधन के कर में रख कर इनकी और अधिक स्थान आकर्षित किया है। इसके पूर्व कि दितीय थोजना के अन्तर्योत इन उद्योगों के विकास कर्यक्रम पर विचार करें यह आवश्यक होगा कि इन उद्योगों की कठिन हाई वो परीच्छा किया जान।

उसोगों को प्राय: तीन बगों में विभाजित किया जाता है: (१) बहे पैमाने पर उत्पादन करने वाले अथवा बड़े उद्योग. (२) छांडे पेमाने पर उत्पादन करने वाले अथवा होटे उद्योग. (३) कटीर उद्योग । इस उद्योगो को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक मत के अनुसार कटोर उद्योग वे उद्योग हैं जो शिलिपयो द्वारा स्वयं अपने आप ही अधना किसी कारकानेदार के निर्देशन में घर पर ही किये जाते हैं। यह कार्य कोटे कारवाने में किया जाता है थीर उसका निर्देशन उद्योगपनि हारा किया जाता है तो उसे इक छोटा उद्योग कह सकते हैं चाडे शक्ति संचालित सशीनों का प्रयोग न भी किया जाय। एक अन्य मत के श्रनुसार घरेलू उद्योग वह है "वो श्रंशत: श्रथवा पूर्वत: परिवार के ही सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है चाहे वे सम्पूर्ण दिन कार्य करें या थोड़ी देर ही निस्य कार्य करें? । श्री चिन्तार्माण देशमल के मतानुसार "घरेल स्तोग" प्राय: इम उन सब उत्पादन के उपक्रमों को कहते हैं जो बड़े-बड़े व्यवस्थित कारखानों के अविरिक्त हैं। जो व्यक्ति इन उपक्रमी में लगे हुये हैं मुख्यत: अपने ही प्रयक्त और कीशल पर निर्मर रहते हैं, सीध-सादे शीजारों का प्रशेश करने हैं और अपने घर पर ही कार्य करते हैं। विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण इस प्रकार के कछ उद्योग हाल में आरम्भ हुये हैं। ये उद्योग प्रधानत: परम्परागत है ग्रीर वर्तमान उत्पादन प्रविधि से स्पर्धा करते हुये अपनी रक्ता में प्रयक्षणील है। छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग "घरेल तथा प्राप्य उद्योगों से इस श्रम में भिन्न हैं कि उनको संचालित करने वाले उद्योगगति होते हैं जो पारिश्रमिक पर रक्के हुये अभिको से कार्य लेते हैं।"

उपर्यक्त परिभाषाओं को विचाराचीन रखते हुये इस यह कह सकते हैं कि घरेल उद्योग की निन्न विशेषतार्थे हैं. (१) ऐसे उद्योगों की घर पर ही बिना श्रीमकी की सहायता के स्वयं चलाया जाता है. (२) इनमें परम्परागत दंत का ही श्रनसरण किया जाता है, और (३) इनका स्वतंत्र तथा पूर्ण समय का कार्य होना व्यायश्यक नहीं हैं. ये कृषि तथा किसी अन्य व्यवसाय के सहायक हो सकते हैं। स्रोटे उद्योग श्रथवा योडी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की मध्य विशेषता यह है कि ये कार्य करने वालों के घर में नहीं चलाये जा सकते और कार्यकर्ता के ब्यावज्यक स्रोत निराश्त सीमित होते हैं। योशी मात्रा में उत्पादन करने वाले जलोगों के कार्य करने वाले असिकों की संख्या १० से ५० तक सीमित है। इसारे देश में उपर्यक्त दोनों वर्गों में ख्रानेवाले खनेक उद्योग हैं जैसे कर्या, जन, रेशम, गुड. राब, तेल पेरने, ताले बनाने के कार्य इत्यादि । इन उद्योगों में काम में सहायता देने वाले परिवार के सदस्यों और समय पर इनमें कार्य करने वाले उन व्यक्तियों की सख्या को छोड़कर जो कृषि आदि ग्रम्य मुख्य व्यवसाय में संतन्न है, समया २० लाख व्यक्ति कार्यं करते हैं। इस दोनों प्रकार के उद्योगों का प्रासी कीर नगरों दोनों में ही पूर्ण श्रथवा खाशिक समय के लिये श्रमुसरण किया जाता है। हैएडी क्रेफ्ट का उद्योग जैसे बेल-बूटे काढ़ने का कार्य, पीतल का कार्य, रेशम बनाने का कार्य इत्यादि पूर्ण लमय के कार्य है और इन कार्यों में संलग्न व्यक्तियों से जल्कष्ट समता भी प्राप्त कर ली है।

लाभ—(१) घरेलू उद्योग और छोटी मात्रा में उत्पादन करने वासे उद्योगों का चवते वहा लाभ तो यह है कि वे बहुत बड़ी संख्या में कार्य का अवस्व वहा लाभ तो यह है कि वे बहुत बड़ी संख्या में कार्य का अवस्व वहा लाभ तो यह है कि वे बहुत बड़ी संख्या में कार्य का अवस्व है कि तो कि तिना उत्पादन करते हैं इस सम्बन्ध में ठीक ठीक अविक ति के कितना विकास करते हैं इस सम्बन्ध में ठीक ठीक अविक ठियात नहीं हैं। राष्ट्रीय आय समिति ने यह अनुमान लगाया था कि १९६५०-११ में छोटे उद्योगों का उत्पादन है १० करोड़ रुपये का हुआ था और लगभग १९७ लाल व्यक्ति अने कार्य करते ये अविक ठीक ठियात में शास कराम प्रश्न कराम प्रश्न कराम प्रश्न करोड़ रुपया था। इन छोटे उद्योगों में कुर्यर उत्योग भी समितित ने पर वे छोटे छोटे करामलाने जो केन्द्री एक्ट के अवस्थान आये हैं। इसमिति ने उन्हें पेतिपृत्री में समितित किया था। यहि इस इस छोटे छोटे कोर कारलानों को भी परेलू और छोटी मात्रा में उत्यादन करने वाले उत्योगों में समितित कररे के अवस्थान करने वाले उत्योगों में समितित करा था। यहि इस इस छोटे छोटे कारलानों को भी परेलू और छोटी मात्रा में उत्यादन करने वाले उत्योगों में समितित करा था। यहि इस इस छोटे छोटे कारलानों को भी परेलू और होटी मात्र करने वाले उत्योग में समितित करा था। यहि इस इस छोटे छोटे कारलानों को भी परेलू और होटी मात्र करने हो। इस संस्थान करने वाले उत्यादन करने वहां सुई संख्या को भी वचाराभीन रख लें सो इस करा हो सात्र के स्वी हो। इस संख्या की भी

इत वार्षिक उत्पादन का मूल्य लगस्म १२०० करोड़ रुपये के हो लायेगा। पर यह घर गणना श्रजुमान मात्र है इसलिये विश्वस्त नहीं कही जा सकती। इन आँकड़ों से परेलू ग्रीर छोटे उचोगों के विस्तार ग्रीर मावी सम्मावना का ही कुछ श्रनमान ही मिल सकता है।

(२) कुटीर उचोग की यह विशेषवा है कि इवमें मूल्यवान् मशीनें नहीं सगाई जाती हैं, इसके लिये किसी बड़ी इमारत इस्पादि की आवश्यकता नहीं होती हैं इसलिये इसको चलाने में अधिक पूँची नहीं लगानी पहती। भारत में पंजी का अमाय है और हमें कुछ ऐसे उचोगों की आवश्यकता है जिनमें पंजी

कम लगे और अमिक अधिक।

(३) इसके विपरीत यहे पैमाने के उचीन में बैशानिक श्रीर टेकनिकल शान की विशेष श्रावश्यकता होती है। परन्तु वर्तमान समय में (टेकनिशियन) माविविशों का भारत में श्रमान है। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उचीनों में यही लाभ है कि इनमें अधिक प्राचिषक (टेकनिकल) शान श्रीर प्राविधिशे की श्रावश्यकता नहीं होती है।

(४) छोटे पैमाने के और कुटार उधोग बड़े पैमाने के उचोगों की तरह किसी निशेष स्थान पर केन्द्रित नहीं है बल्कि उम्पूर्ण देश में विस्तृत हैं। हनमें हनारत, सकाई, स्वास्थ्य हत्यादि की समस्या नहीं होती है, जिनका बड़े पैमाने के उदोगों की सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही युद्ध के समय इनके तिनाश का भय भी कम रहता है। बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के उदोगों का तुल-नातक अप्ययन करते समय और हनके लाभ-हानियों का विवेचन करते समय हमें उक्त सामाजिक क्या का भी विचार करना चाहिये।

(4) वड़े वैमान के उचोगों की अपेका छोटे वैमान और कुटीर उचोगों में रोजगार में अस्परता बहुत कम होती है। हमारे देश के मामीण व्यक्तियों का सुक्य उचम कुषि करना है और वे यहावक व्यवसाय के रूप में रहिश मानि, गुक्र मनाने, कपका बनने इत्यादि कार्यों को करते हैं। ऐसी स्थित में यदि इन सहायक उचोगों में मंदी आ जाय तो अभिक अयवा कारीगर को उतनी अधिक कठिनाहयों में सामान नहीं करना पढ़ेगा जितना किसी औदोगिक अभिक को मंदी के कारण नौकी सुट जाने पर करना पढ़ता है।

हुटीर और छोटे पैमाने के उचोगों से बड़े पैमाने के उचोगों की अपेदा कुछ अपिक लाम होते हैं। अब महन गए उठवा है कि विभिन्न मकार के उचोगों को कोन सा स्थान देना चाहिए। वित्त आयोग (१९४४-४५) के अनुसार इस सम्बन्ध में निम्मालिखित बारों पर विचार करना आवश्यक है: (१) तसोरा के प्रकार.

(२) उद्योग में टेबनिकल व्यवस्था.

(३) उद्योग के संगठन के लिए आवश्यक थम और पंजी.

(४) आर्थिक द्वारित से उत्पादन का किस सीमा तक उत्पित इकाइयों में विकेन्द्री करवा किया जा सकता है केवल व्यक्तिगत व्यव को ही नहीं बस्तु सामाजिक व्यव को मी विचाराधीन स्वते हुए।

जहाँ तक उत्योग के प्रकार का प्रश्न है उसे तीन सागों में विभाजित किया जा करता है; (१) ऐसे उद्योग जिनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से कुछ निश्चित लाम है और जिनकों छोटे विमाने पर नहीं बलाया जा सकता है, जैसे लोहा झीर इस्पात उद्योग, शीमेंट, भारी रखायनिक और खदान उत्योग इस्पादि! इन उद्योगों को कुदौर में श्चयवा छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा थकता है इस्तित इस चेत्र में चुनाव का प्रश्न ही हिस्ति इस चेत्र में चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठवा है; (२) ऐसे उद्योग जिनका छोटे पैमाने पर उत्पादन करके कुछ निश्चित लाभ उठाया जा सकता है, जैसे ताला भोमत्रची, धटन, ज्वप्यल, लायाज इत्यादि उद्योग। इनमें से कुछ में छोटे पैमाने पर उत्पादन करने में उत्पादन वयन कम होता है। खाखाज के सम्मच में यह कहा लाधकता है कि जब बरायुएँ हास से तीयार की जाती है तो उनमें पीरिक्त तल अधिक रहते हैं; (३) ऐसे उद्योग जिन्हें बड़े और छोटे पैमानो पर यलाया जारू, ककता है। इस उद्योगों के सम्भव में चुनाव का प्रश्न उठता है।

टेकनिकल व्यवस्था के आधार पर उचीय को निस्तिलिंखत मानों में किमाजिक किया जा एकता है—(१) ऐसे उचीय जिनम बहे पैमाने के उचीयों और दुर्टीर तथा छोटी मात्रा के उचीयों में कोई. प्रतिचिधिता नहीं हैं, जैते मात्रा के उचीयों में कोई. प्रतिचिधिता नहीं हैं, जैते मात्र के उचीयों में कोई. प्रतिचिधिता नहीं हैं, जैते मात्र के उचीयों के कार्य हत्यादि (१) ऐसे उचीय जिनमें छोटी मात्रा के और छुटीर उचीय के विश्वाल के उचीयों के उचीयों के उचीयों के उचीयों को उपादन किया जाता है जिनकी बड़े पैमाने के उचीयों को उपादन किया जाता है जिनकी बड़े पैमाने के उचीयों अने उचीयों के उचीयों अने उचीयों के उचीयों अने उचीयों में अवस्थान होटी हैं या उपादन की उचीय किया में कुछ छोटी को उचीय किया प्रतिक्र होटी होटी उचीयों के अन्यादन की उचीयों में अवस्थान होटी हैं या उपादन की उचीयों किया मात्र होटी हैं, जैसे, क्या में इसा कपराद की होटी में किया बाता है, और (३) ऐसे उचीयों जिनमें महे पैमाने की उचीयों में प्रतिक्षा होटी होटी उचीयों में किया बाता है, और (३) ऐसे उचीयों जिनमें महे पैमाने की उचीयों में मिलाने की उचीयों में प्रतिक्ष होटी होटी उचीयों के अन्य में की छोटी जाने माने पिमाने की उचीयों के स्वत्यों की उचीयों होटी समारा नहीं है परन्तु हुकरे वर्ग के अन्य वर्ग के छोटी छोटे तथा बहे पैमाने के उचीयों में परवर उचीय समस्य स्थापित करके इनकी किटी भी बहे पैमाने के उचीयों में परवर उचीयों के सन्य में के अन्य की होटे तथा बहे पैमाने के उचीयों में परवर उचीय समस्य स्थापित करके इनकी किटी भी

समस्याको सुगमता पूर्वक सुलकाया जासकता है। तीसरे वर्गके उद्योगों के सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाइयों का समना करना पढ़ता है।

कठिनाइयाँ करूचे माल, उत्पादन की प्रविधि, वित, विकय, कर इत्यादि के सम्बन्ध में कुटीर और होटे पैमाने के उथोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन उद्योगों को प्रायः उन वस्तुओं की आवस्यकता होती है जिनका वहे उद्योगों में उत्पादन किया जाता है। कथीं उद्योग पूर्वतया चती मिल द्वारा उरगादित सुत पर निभर करता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सुत मिलने में बहुत कृतिनाई हुई, क्योंकि जितने स्त का उत्पादन किया जाता या उनका अधिकीय मिलों की ही आवश्यकता पृति में लग जाता था। उस समय अधिकतर मिलों में कताई और दुनाई साथ-साथ होती थी । केनल कताई करने वाली मिलों को संख्या बहुत कम है। कवीं उचोग को अधिक वत उपलब्ध कराने के लिए वत की कराई करने वाली कुछ श्रीर मिलों की स्थापना की गई हैं श्रीर इनमें उत्पा-दित सुत का कुछ मिरायत कमी उद्योग के लिए मुरस्थित रखा जाता है। इलाली के कारण कुटीर उद्योग को आवश्यक कच्चे माल का अधिक मृत्य चुकाना पहता है। इस कठिनाई को सहकारी समितियों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है।

प्रविधि और महाली-इन उद्योगों में बिस दंग से और जिन सामनी से उत्पादन किया नाता है वह प्राचीन हो चुके हैं और वर्तमान में उनकी उपयोगिता बहुत घट गई है। खोज कार्य करने झोर कारीगरों के शिज्य की उपपुक्त व्यवस्था न होने से उत्पादन के प्रकार में बहुत श्वति हुई हैं। अभिकों को उचित शिक्षा देने और उत्पादन के प्रकार में सुधार करने के लिए बहुत योड़ी ऐसी संस्माएँ हैं जो श्रच्छा कार्य कर रही हैं, जैसे खरितल भारतीय प्राप्त उद्योग संघ, ग्रस्तिल मारतीय कताई संघ, खादी प्रतिष्ठान श्रीर हाल ही में स्थापित खादी

अन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने, जिसको कोर्ड फाउन्डेशन ने नियुक्त किया श्रीर प्राम उद्योग विकास बोर्ड । या, जिंदने छोटो सात्रा में उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योगों का अध्ययन करते के लिये तथा उनके पुनस्त्यान के मुकाब देने के लिये भारत का दौरा किया, १९५४ में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उसने यह शिकारिया की कि चार शिल्म कर्ता श्चान सम्बन्धी संस्थायें स्थापित की जानी चाहिये जिनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी द्दोनी चाहिये कि वे सम्मूर्ण मारत की सेवा कर सकें। भारत सरकार ने यह सिकारिश स्वीकार करली है। पर खोज का कार्य करेंगी और अपनी खोज के परिणामी की तथा नई उत्पादन विधियों, नये औजारों, और नई प्रविधियों की सचना जरपादकी तक पहेंचार्येगी।

कार्य करने बालों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जो कि उचित शिना प्रचार तथा प्रत्येक इस्तकारी के लिये स्थानीय परिषद के स्थापित करने से सम्बद्ध हो सकता है।

विक्त व्यवस्था—छोटे उचोगों और उचोगपतियों की बड़ी किटनाइयों में विक को किटनाई प्रमुख है। मयोन और आवश्यक श्रीजार कर म करने के लिए उसे रीधंकालीन यूँजों को आवश्यकता होती है। इटके आय हो कच्या साल करने के लिए उसे रीधंकालीन यूँजों को आवश्यकता होती है। इटके आय हो कच्या साल करने के लिए उसे रीधंकालीन यूँजों को आवश्यकता होती है। छोटे उत्पादकों में अधिकतर निर्धन हैं और उद्या के लिए श्रावश्यक प्रतिभृति नहीं दे पाते। आय हो ऐसे उत्पादकों की आवश्यकताएँ भी कम होती हैं, इन्हें अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती हैं, इन्हें अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती हैं हमलिए बड़े उचोगों को विजये यहायता देने वाले व्यवसारी बैंक हमको अध्य इत्यादकों को विक की आवश्यकता होते हमें अधिक हम उत्यादकों को विक की सहायता मिल चकती है। इन्हें अधिकतर प्रामीण साहुकारों और कारखानारारों पर निर्मेर करना पड़ता है। कारखानेदार इस बार्च पर ऋषा देते हैं कि उत्यादिक माल उनको वेचा जायगा। उत्यादित माल का मूल्य इप्य देते हैं कि उत्यादिक कर लिया जाता है। इससे उत्यादक को अपने माल का उचित मुख्य मही कित पाता।

क्षनतर्राष्ट्रीय योकना टीम ने यह सिकारिश की कि (१) व्यापारिक बैंको को अपनी शालाशों को अधिक शुरू देने की अपनाति देकर इन्हें दिये जाने याति अध्य की मात्रा बहा देना चाहिये; (२) ग्रहकारी वेंकों को इन ज्योंगों की वित्त चहरवता करने की और और अधिक ब्यान देना चाहिये; (३) मन्येक प्रदेश में एक राज्यीय वित्त नियम स्थापित किया जाना चाहिये जिसके कीय को इन होटे उत्योगों की ही सहायता के लिये सुरक्षित कर देना चाहिये; और (४) वास्तविक सम्पत्ति की प्रतिमृति पर ऋष्ण देने की प्रशाली प्रवित्तत की जानी चाहिय ।

व्यक्तिगत चेत्र की विच बहायता के लिये शीफ कमेटी ने भी रिजर्व वैंक को चून १६५५ में ही हुई अपनी रिपोर्ट में उन छोटे उद्योगों के विषय में विचार किया है जिनकी उपपत्ति १० हजार कार्य और ५ लाख रुपये के अन्दर है। कमेटी ने अपि के सहायक उद्योगों की अपनी परीवाज परिच के अन्दर समिनित नहीं

किया। चाल पॅनी के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि इन उद्योगी में सरकार दारा क्रय किए सबे भाल के सल्य का मगतान करने में देर नहीं होनी चाहिये । इसके श्राविश्कि अमेटी ने वह भी विफारिश की कि व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा लिखे हवे इचरारनामां की रजिस्टी की फीस मी कम कर देनी चाहिये ताकि उनको बैंकों से ऋण लेने में अधिक सुविधा मिले । दीर्घ कालोन पाँची की आवरप-कमाओं के सिने यह सिकारिया की कि प्रादेशिक सरकारों की दन उद्योगों की 'हरेट एक ट इक्टररीज एक्ट' के जन्तरांत अधिकाधिक सहस्तता देनी साहिते । रमांक्रिये क्या जलोगों को आजिक आबा हेते की सविधा प्रदान करने के लिये यह क्षावकार होता कि वाहेजिक वक्षर में इस पर व्यय करने के लिये प्राप्टिक कर का शनदान किया जाय शीर असा देने की प्रसाली को श्रविक सरल बनाया बाय । बाँग्री ने यह समाय हिया है कि 'बादिशिक वित्त कारयोरेशन' को सीटे उद्योगों को आण देना चाहिये। इसके साथ ही उसने यह सिफारिश की कि छोटे उद्योगों की सहावतार्थ एक विकित्य विकास निवास की भी स्थापसा होशी जाहिये जिसकी मार्राम्भक शेवर पँजी ५ करोड स्पया हो को कि भारत के रिखर्त हैंक. व्यवसायिक वैको, होमा कम्बनियों, तथा व्यक्तिगत लोगों द्वारा प्राप्त होती चाहिये ।

धाकार--दितीय यह के समय ऋौर ग्रह के पश्चात कुछ वर्षों तक बहत से उद्योगों द्वारा उत्पादित झाल के विक्रय की कोई समस्या नहीं थी क्योंकि माँग पति से श्राधिक थी परना फिर भी दलाली के कारण और उत्पादित माल पटिया होने के कारण उत्पादक को अपने परिश्रम का उचित महम नहीं मिलता था। इभर कुछ वर्षों से इन उद्योगों की विक्रय समस्या गंमीर होती खा रही है। काइमीर का बाल और बनारस की सिक्क जैसे मुख्यान दामानों का उपमोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि राजाओं तथा समीदारों की श्रव पहले सेसी स्थिति नहीं रही। राजाक्रों की गड़ी और सम्भादारी का उत्थालन हो चका है। समता की क्रयज्ञाकि में कमी होने के कारण मांग घट गई है। सगरण यह है कि बाजार में जन्मादित माल की माँग बढाउँ खाय और उचित मल्य वसला आय । माँग में वहि तमी की जा सकती है जन या तो निर्यात किया बाय वा बढ़े उल्लोगों द्वारा उत्पादित माल के बदले इनका अपभोग किया बाय। कुटीर उद्योगों में उत्पादित माल का उपमोग कनाहा, अमरीका, न्यूबोलेयह, श्रास्ट्रेलिया श्रीर मध्य पूर्वी देशों में बढ़ाया जा सकता है। यह देश यूर्व से ही आल क्रय करते रहे हैं और दस्तकारी की वस्तुत्रों, कलापूर्व कपड़ों, लाल तथा खेल के सामान इत्यादि के विषय में पूछताछ करते रहे हैं परना इन देशों को बड़ी मात्रा में एक साथ और नमने के

अनुरूप माल की आवश्यकता है। उत्पादित माल का बड़ी माना में श्रीर टीक नम्ने के अनुरूप निर्यात करने के लिए विकय समितियों का विकास करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकारें छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों पर कर कम लगाने की गील व्यवनाती हैं। उदाहरण्यस्थ ज्ञास्य जीनी पर कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी की व्यवहार कार उत्पादन कर देना पड़ता है। इस सरद्या का एक दूसरा पद्ध भी है। मध्म पंचवर्षीय योजना में यह युक्ताव दिया गया है कि छोटे पैमाने के ब्रोगो का विकास करने के लिए कड़े पैमाने के उद्योगो का विकास करने के लिए कड़े पैमाने के उद्योगो पर कर कामाया जाय। कथी उद्योग का विकास करने के लिए कड़े करीब करपा एक करने के लिए हात कर तथा एक करने के लिए हात के प्रवास के प्रवास कर कर तथा प्रकार करने हैं। वहे पैमाने के उद्योगों पर पूर्व ही से बहुत कर लगे हुए हैं यदि यह नया कर और लगा दिया गया तो इस्से उद्योग के विकास में बाबाद उत्यक्त हो ज्ञास भी काम हो के प्रवास के विकास के विकास के विकास के व्यवस्थ हो प्रकार की कर-नीति से पूर्व नहीं हो सकता है।

प्रकार का करनाति व पूर्ण नहा हा उक्ता हा क्षोडे और कुटीर उद्योगों के सामने विजुत और यातायात के अभाव की भी समस्या है। इनकी स्पिति सुकारने के क्षिए सस्ती विद्युव और सस्ते यातायात की सर्विद्या देना आवश्यक है।

कार्चे कसेटी रिपोर्ट —योजना झायोग ने कार्वे कसेटी, झपवा प्रास्य उद्योग और छोटे उद्योग कसेटी, की नियुक्ति जून १६५६ में इन उद्योगों की वसस्याओं का परीख्या करने और एक ऐसी योजना प्रस्तुत करने के लिए की जिवसे (१) द्वितीय योजना काल में उपभोग की बस्तुओं की बड़ी हुई मांग का अधिकांच हुन्हीं उद्योगों से पूर्ण किया जा उके; (२) उनसे उत्तरोत्तर कार्य करने के झिक अवसर साप्त हो कर्ते और (१) उत्पादन और विनिध्य की ब्यवस्था सहकारिता के आधार पर ब्यवस्थित हो सके।

पर क्यबंध्यत है। वर्क।
करेटी को यह स्वरूष्ट हो गवा था कि आस्य तथा छोटे उद्योगों की उपेबा
बहुत दिनों से होती आ रही है। प्रथम योजना में जो उनके प्रति क्यान दिया गया
या वह प्रयोग न था। प्रथम योजना के परिखासस्वरूप इन उद्योगों के विकास के
लिये छः विशिष्ट बोर्डों की स्थापना है। इन बोर्डों ने १९५९-५२ में १५-१२ लाख
स्प्रया क्यम किया था जो कि १९५५-५५ में बहुकर ६-७३ करोड़ स्पया हो गया
और १९५५-५६ में १५-५२ करोड़ रुपया; परन्तु यह भी अपवांत विव हुआ।
कर्मादों ने २६० करोड़ रुपये के विनियोग की खलाइ दो अपर्यात् दिवीय योजना
काल में प्रति वर्ष ५२ करोड़ रुपये।

कार्षे कमेटी ने उत छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले और कुटीर उत्पोगी के विकास की सिक्तरिश की घी जो नित्यकार्य में आने वालोवस्तुओं का उत्पादन करते ये जैसे स्ती कवके, कमी कवके, हाय के कुटे चावल, वनसाति तेल, गुरु श्चीर खबडवारी, चमड़े के जुते और दियावजाई इत्यादि । साथ ही रेशम के कीड़ें . पालना, रेशन बुनना, इषकर्षा उद्योगों की नारियल की जटा का कावना और अपना अपनास्थ्य का नाम का का आपना आपना हिंगा। कमेटी द्वारा हुनना, ब्राहि उद्यामा की क्षोर कमेटी ने अपना व्यान दिया। कमेटी द्वारा द्वितीय योजना के अपनर्गत प्रस्तावित कुल १६० करोड़ क्ष्यप के व्यय से आशा क्षी जाती है कि अधिक समय के लिये, बोई समय के लिये, पूर्व समय के लिये श्चीर वर्ष के विशेष महीनों के लिये यह उचीन ५० लाख व्यक्तियों को कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे। कपड़े के उद्योगों को कमेटी ने तब से आधिक महत्ता दी है। इनमें विकेन्त्रित युत कावने और विमने का काम सी सीमालिव है। इस उद्योग पर लगभग कुल ब्यय का ४४% अथात् ११२ करोड अववा ब्यय किया जायगा। क्राशा की जाती है कि यह उद्योग लगमग ३० लाख व्यक्तियों। को कार्य प्रदान कर सकेशा।

मं व्यासम्भव श्रीवोगिक वेरोजगारों में वृद्धि न होने देना जो कि प्राय: प्रस्थरागत ग्राम्य उद्योगों में हुआ करती है; (२) अधिक से अधिक सख्या में होगों को योजना काल में ग्राम्य श्रीर खोटे उद्योगी द्वारा कार्य करने का श्रवसर प्रदान करना; श्रीर (३) विकेन्द्रित समाज की स्थापना के लिये एक ज्ञाचार प्रदान करना तथा वृद्धि-मान गति से आर्थिक विकास करने की सुविधा देना। कमेरी ने समृक्षि का जो कारुनिक वित्र अपने सन में रक्का था उठको प्राप्त कर खेने के विचार से निम्न

(१) प्रादेशिक सरकारों को सहकारी समितियों को घन तथा प्रत्याभृति सुमाय दिये हैं--द्वारा सहायता देनी चाहिय जिससे वे बान्य और खोटे उद्योगों की ऋषिक सहायता कर सर्वे। कमेटी ने रिवर्ष बैंक और स्टेट बैंक आफ इशिष्टवा की प्राप्य और छीटे उद्योगों की सहायता देने के अनेक ढंगों का सुफाव दिया। उसने यह भी शिकान रिंग को कि जब तक इन उल्लोगों के लिये एक नई संपूर्तित संस्थानत ऋण की अवस्था न हो जाव तब तक अस्तिल भारतीय बोडों, प्रादेशिक वित्तीय निगमा तमा राजकीय विभागी को आवश्यक महायता देते रहना चाहिये।

(२) प्रदिशिक सरकारों हारा दिये हुये अनुदानों का प्राप्य छोरे उद्योगों की सहायता करने के स्थान पर कमेटी ने यह अधिक अञ्झा समका कि सरकार द्वारा सहकारिता के श्रामार पर उत्पादित कुछ वस्तुत्रों का निम्नतम मूल्य निश्चित कर दिया जाय जिस पर वे बेची जाँय। मूल्य से कम पर वेचने में जो प्राप्त हो उसे राज्य को परा करना चाहिये।

(३) ग्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों को विस्तार का खबसर प्रदान करने के विचार से कमेरी ने यह विचित्र सुकाव दिया कि फैर्ट्री उद्योगों के श्रविकतम उत्पादन की मात्रा नियत कर देनी चाहिये ख़ौर बितनी भी भाँग इसके उपरान्त बढ़े उसे एकाँत: खयबा श्रंशत: भ्राम्य उद्योगों से पूर्ण करना चाहिये।

(४) सभी फैन्ट्री उद्योगों के सम्बन्ध में क्सेटी ने एक उपकर आरोपित करने
 की िस्कारिश की निस्का प्रयोग बान्य और छोटे उद्योगों के विकास और उत्पत्ति

के लिये किया जाय ।

(4) कमेटी ने कुकान दिया कि केन्द्रीय मनियसदक्ष में एक एपक मंत्री प्राम्य क्षीर कोटे उद्योगों के लिये नियुक्त किया जाना व्यक्ति । इस मंत्री को सहयोग देने के लिये मनिमस्बल के स्ट्रस्थों की एक कमेटी होनी स्वाहिये निस्नका काम अगत महकार को क्षीसोमिक नीति में सामंत्रस्य स्थायित करना होता।

क्रमालोचना—कार्षे कमेटी की सिकारिशों में निस्त गंधीर होए हैं।

(अ) कमेरी ने मास्य और छोटे उचामों का आधुनिकीकरण तथा अभिनकी करण तभी करने की विफारिश की है जब कि उससे वेकारी स बढ़ें परंतु यह असम्मव है।

(ब) मिल उद्योगों के उत्पादन की अधिकतम शीमा निर्धारित करने का आर्थ यह है कि मान्य और छोटे उत्योग उपयोग की बद्ध को की बद्धी हुई माँग को पूर्ण करने में समर्थ होंगे, जो कि जनसंख्या के बद्धने तथा राष्ट्रीय आय में हृद्धि के कारत होगी। जिन न्यक्तियों की मान्य और छोटे उद्योगों का शान है वे यह अब्बंधि मुक्त र जानते हैं कि अग्रसम्ब है।

अच्छा भक्तर भागत है। (त) कार्वे कमेरी का कर्जाहत विचार यह है कि ग्राम्य और छोटे उद्योगों की मिल उद्योगों की स्पर्धों से स्हा होनी चाहिये और उनको अपने भाल को वेचने की स्वतन्त्रवा मिलनी चाहिये। परन्तु इस समन्य में केवल देश के मिल उद्योग

का ही विचार नहीं करना है वरन् विदेशी मिलें भी स्वयां करेंगी।

(द) कमेटी की इस सिफारिश के फलस्वरूप कि राज्य सहकारिता के सिद्धान्त पर उत्पादित कराओं के कव और तिक्रय मृत्य का अन्तर सहस करे और एक नमा मन्त्रालय स्थापित करें, भारत में राज्यों का ज्या बहु जायगा। केन्द्रीय तथा प्राहेशिक राज्यों के इतने बड़े ज्याय नया आया खोतों को देखते हुये इस समाज को अपनाहारिक नहीं गाना जा सकता।

योजना के अन्तर्गत-यह बड़े सीमाय की बात है कि योजना श्रायोग

क्योग सरकार ने कार्वे कमेरी की सब सिफारिशों को खीकार नहीं किया विवाद सान पाउन मिल ज्योगों के उत्पादन की श्राधिकतम मात्रा नियत करने का था. जम पर अभी निर्णय नहीं किया गया है। यह बड़े दर्भाग्य की बात है कि उपकर कल जहांगों पर हो लगा ही दिया गया है और श्रान्य पर लगाये जाने की सम्मादना है। परन्त अपनी तक तो कार्ने कमेटी की शिकारिशें उस सीमा तक 'स्वीकार नहीं की गई है कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था की असाध्य हानि पहेंच লোগে ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में दस उद्योगों के लिये एक योजना निर्माण की गई यी-प्राम्य तेल उद्योग, नीम के तेल का चायुन बनाना, घान कुटना, खजूर मा गृह बनाना, गढ़ और खरडसारी उद्योग, चमड़े का उद्योग, जन के करवस बनाना. हाथ से अञ्जे प्रकार का कागज बनाना, यहद की मक्त्री पालना और कटीर दियासलाई उद्योग । यह योजना इस विश्वास पर निर्माण की गई थी कि इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार १५ करोड हवया और प्राटे-शिक सरकार १२ करोड रुपया व्यय करेगी। प्रथम योजना काल में जो धनराणि बास्तव में इन उद्योगों पर व्यय की गई है वह ३१.२ करोड़ वपये है। इसमें से हथकर्या उद्योग पर ११.१ करोड रुपये. खादी पर द्वार करोड वपये. ग्राम्य उद्योगी पर ४'१ करोड़ क्यये श्रीर छोटे उद्योगों पर ५'२ करोड़ क्पये व्यय हुये ।

दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य प्रथम योजना काल में किये गये। उनमें से एक तो केन्द्रीय सरकार द्वारा माम्य और छोटे उद्योगों के विकास के लिए एक बढ़ी माप्रा में धनराशि का अलग निकाल देना या और दूसरा विभिन्न उद्योगों के लिये अखिल भारतीय बोडों की स्थापना था । वेन्द्रीय सथा प्रादेशिक सरकारों द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण, तथा अखिल भारतीय बोडों की कार्य परिधि के विस्तृत हो जाने के कारण, अनेकों उद्योगों का उत्पादन तथा उनमे कार्य करने

यालों की संख्या में वृद्धि हुई है।

तीसरी महत्वपूर्ण बात सरकार द्वारा स्टोर्स परचेज कमेटी की उन विफारिशों की स्वीकृति हैं जो स्टोर्स की कुछ प्रकार की वस्तकों का देवल प्राप्य श्रीर उद्योगों से ही खरीदा जाना अनिवार्य करते है, श्रीर बड़ी मात्रा में उत्पादन ि करने वाले उद्योगों की तुलना में उन बस्तुओं के मूल्य के अन्तर को प्राप्य उद्योगों को देने के लिये बाध्य करते हैं।

दितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम योजना की अपेका छोटे उद्योगों पर श्रधिक धन मुख्यत: इसलिये व्यय किया जायगा कि उससे धारत में वेकारी की समस्या इल होगी। कार्वे कमेटो की २६० करोड़ रुपया व्यय किये जाने की सिकारिया के विपरीत द्वितीय योजना ने केवल २०० करोट रुपयों के व्यय की व्यवस्था की है। आशा यह की जाती है कि जब प्रावेशिक योजनाओं का पनर्पीक्षक होगा तो यह चनराशि अवस्थ बद जायगी।

२०० करोड़ रुपयों के लिनियोग में से केन्द्रीय सरकार २५ करोड़ रुपये करेगी । योजना में द्वाप्य करेगी श्रीर प्रादेशिक सरकार १७५ करोड़ रुपया न्यय करेंगी । योजना में ग्राम्य और छोटे उद्योगों के लिये निज्ञ्चत किये हुए २०० करोड़ रुपयों के ख़ितिरक्त ११ करोड़ कपया कुटीर और मध्यवर्षी उद्योगों के विकास के लियं और प्रीयोगिक श्रष्ट के लियं और एक करोड़ रुपया विभिन्न लोगों के पुनंवास के कार्यक्रम है। ख्रान्तर्गत औद्योगिक सथा व्यवसायिक शिक्षा के लिये निश्चित किया गया है प्राद्धायिक विकास के क्यान के क्यान के क्यान के क्यान्य किये जातियों की क्यान्य के क्यान की व्यवस्था की मई है। विद्वार्थ जातियों की मुख मुक्त जातियों की मुख मुक्त कराये के ल्या क्या के लिये व्यवसाय की स्थान के लिये बनाये कार्य-क्रम में भी कुछ जुने हुये उद्योगों से सम्बन्धित व्यवसायिक और औद्योगिक शक्त कार्य कराये कार्य व्यवसाय की लिये बनाये कार्य-क्रम में भी कुछ जुने हुये उद्योगों से सम्बन्धित व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्ता का प्रवन्ध किया गया है।

द्वितीय पंचवर्णीय योजना के पहले दो वर्णों में छोटे पैमाने के उच्चोगों तथा दुरीर उद्योगों में कुछ मगति हुई है। इन पर ५६ करोड़ चयपा क्या हो चुका है और आशा की जाती है कि ठीवरे वर्ण की समाप्ति तक यह ६१ करोड़ कथ्या हो जावागा । इन व्यव का ४० प्रतिशाद खादी और प्रामोगोंगों के जिये, २५% से कुछ अधिक छोटे पैमाने के उच्चेग्र तथा और्योगीक वस्तियों (Industrial estates) के लिये तथा २०% के लगभग हाथ के कई तथा शांकिवालित कभों के लिये था। पहली दो योजनाओं में की गई व्यवस्था राज्य वधा केन्द्र की अनुमानित क्या समुद्रा एक आप्य कारण भी महस्वपूर्ण हो गया। पेन्द्र और राज्यों के पास योजनाओं को लागू करने के लिये धनराशि सीवित थी।

६२ श्रीक्षोमिक बस्तियों में से, ११ पहले दो वयी में पूरी हो गई तथा अन्य १६ के १६५६-५६ तक पूरी होने की आशा है। १६५०-५६ के अन्त तक होटे उद्योगी का प्राणिक तथा विकय सम्बन्धी सुविधार्थे प्रदान करने के लिये, ४ प्रारिशिक लघु उत्योग वैधा संस्थान (Small Industries Services Institutes), १३ वडे संस्थान, २ उप संस्थान वया २७ प्रसार-केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे। १६५६-५६ के एक और प्रारिशिक लघु उद्योग संस्थान वया २३ प्रधार केन्द्र स्थापित किये वार्येंगे।

१९५६-५७ में हथकरें का उत्पादन १६००० लाख गज या जो १९५५-५६ के उत्पादन से १२०० लाख गज़ ऋषिक था । १९५७-५८ में अनुमानित उत्पादन

203 छोटे पेमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुटोर उखोग े

१६५००लाख गज़ था। अब तक की प्रगति लक्ष्य से कहीं कम है। १६५७ के अन्त तक अध्यर सुत से जत्पारित कपड़ा ७० लाख गज था। ऐसा प्रतीत होता है कि १५०० लाख गज का संशोधित लह्य योजना काल के अन्त तक पूरा नहीं होगा। पुरानी देत की खादी का उत्पादन ३५० लाख गज के आचार भूत उत्पादन से

५० लाख गज्ञ प्रति वर्ष के हिवाब से वह रहा है। लादी उत्पादन के लिये कई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया या। शक्तिचालित करवी की स्थापना के सम्बन्ध में प्राप्त लक्ष्य भी श्रव तक नगरव हैं।

## श्रध्याय २१

## श्रोद्योगिक उत्पादन श्रीर नियोजन

प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजकीय तथा निजी उद्योग होत्र में श्रीद्योगिक जलाहरू में बढ़िकरने की व्यवस्था की गर्द थी। जनर केवल दतना था कि राजकीय उद्योग क्षेत्र में जल्पादश में बढ़ि करने का सम्पर्ण असरदायित सरकार ने अपने ऊपर से लिया था परस्त निजी ज़लोगों के सम्बन्ध में ज़लाइन के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये थे। यह आशा प्रकट की गई थी कि निजी तहींग योजना की अवधि समाम होने तक इन लक्ष्यों तक परंच जीयेंगे । पर्नपरीजित योजना को कार्यान्यत करने के लिये निर्धारित २३५६ करीड सपरों में से शक करीड रुपया ग्रामीत कल हम्म का ७.६% जलोगों सीर खान खोटने पर खाय करना था जिसमें से बहे सीर मध्यम भेगो के उद्योगों पर १४८ करोड रूपया, खानों के सचार पर १ करोड क्पया श्रीर छोटे उद्योगों पर ३० करोड़ क्पया व्यय करता था। इखन बनाने के चितरंजन कारखाने हारे रेल के लिये इस्पात की कोच बनाने के कारखाने में जो कक धनराशि लगाई गई यह रेलवे विकास योजन का एक ग्रंग थी। इस प्रकार आधार भूत उद्योगों और यातायात के लिये निर्घारित ५० करोड़ की धनराशि प्रथक करके सम्पर्ध राजकीय विकास कार्य क्रम में ५ वर्ष के अन्दर १४ करीड रुपया निर्धारित किया गया । राजकीय श्रीदोगिक चेत्र में जी रुपया लगाया गया उससे लोहे तथा इस्थात के नये कारखाने, इज्जन बनाने के चितरजन कारखाने, मैदर में गरीन ग्रीजार बनाने के कारखाने, सिन्द्रों के रसायनिक खाद के कारखानों और पैनिखिलिन, डी॰ डी॰ टी॰, यन्त्र, टेलीफोन इत्यादि बनाने के कारणाने की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्तित किया गया। जितने उद्योगों की सरकार सरलता से व्यवस्था कर सकती थी उन पर अधिकार कर लिया गया श्रीर रोप निजी स्रेष्ठ के लिये छोड़ दिये गये। इस मिश्रित शर्थ व्यवस्था से यह लाम है कि राजकीय उद्योग सेत्र का उस सीमा तक प्रसार किया जा सकता है जितना व्यवहारिकता दृष्टि से सम्भव है और निजी उद्योग को अपने राधनों. कशलक्ष एवम ग्रनमव के द्वारा देश का श्रीरोगिक विकास करने का ग्रवसर मिलता है।

योजना ऋष्योम ने ऋतुमान लगाया था कि योजना में उत्पादन के निर्मा-रित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये नित्नी उद्योग च्वेत्र में पाँच वर्ष के श्रन्दर कुल २२३ करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। यदि हसमें मशीनों को परिवर्तन तथा उद्योग का श्रापुनिकोक्सण करने के लिये १५० करोड़ और चालू पूँजी के लिये ३२४ करोड़ की घनराशि समितित कर दी बाब तो पाँच वर्ष में निश्ची उद्योग देव में कुल ७०७ करोड़ रूपमा लगाया आयमा । भारतीय उलीवपतियों ने इस योजना की आलोचना की । उनका कहना या कि (अ) उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये १५० करोच करवा अपरांत है क्योंकि अधिकांश उच्चोगों की मशीनें प्राय: व्यर्थ हो गहें हैं। योजना में निर्यास्ति सहय की पूर्ति के खिये आवश्यक मशीनी का प्रबन्ध करने में हनसे कही अधिक घरवों की आवश्यकता होगी; (व) सरकार ने केवल ग्रावश्यक धन को मात्रा बता दी है, परन्तु उसकी प्राप्ति की ब्यवस्था नहीं की है। उद्योगी के पात ऐसे साथन नहीं हैं जिनसे यह कार्य किये जा सकें। भारतीय पूँजी बाजार की ऐसी स्थित नहीं है कि इतना चन प्राप्त किया जा सके न्त्रीर विदेशी पूँची मी प्रायः उपलब्ध नहीं है। इन सब बातों पर विखार करने से कात होता है कि निजी उद्योगी का बोजना में निर्धारित उत्पादन के सहतों की परा कर सकना सम्भव नहीं है।

बोबना में उद्योगों को जिस कम से प्राथमिकता दी गई थी उससे स्पष्ट है कि आधारभुत एवम् प्रमुख उद्योगों के साथ ही ऐसे उद्योगों को अधिक महस्व दिया गया जिनका श्रपेदाकृत बहुत कम विकास हुआ था। यदि राजकीय तथा निजी उद्योग चित्रों को एक साथ मिला कर देखा जाय तो यह बात होगा कि छुल ब्यप का २६ प्रतिचत चातु शोधन उद्योगों के लिये, २० प्रतिचत पेट्रोल गोध-ग्रालाग्रों के लिये, १६ मीतशत इंचीनियरिंग उद्योगों के लिये, म्प्रतिगत सूती उद्योगों के लिबे, प्र पविश्वत सीबेंट और लगमग ४ प्रतिश्वत कागल, पट्टे तथा श्रुखनारी कागल उद्योग के लिये निर्धारित किया गया था। इत्तका श्रुर्य यह या कि जिन उद्योगों का श्रमी विकास नहीं हो पाया या उन पर श्रविक ध्यय किया जाय । वर्तमान उद्योगों को छोड़ा नहीं गवा था बल्कि उनके लिये कम घनराशि निर्वारित की नई थी। ऐसा उचित मी था। देश के सभी उपलब्ध राघनी का श्चन्छे से अच्छा उपयोग करने के उद्देश्य से ही यह व्यवया की गई थी। स्रोदोगिक विकास कार्यक्रम के लिये योजना में निम्नलिखित प्राथमिकता सम दिया गया है।

(१) ब्र ग्रौर प्लाइडड जैसे उत्पादक यस उद्योग श्रीर सूती कपडे, चोनी, सासुन, बनस्पति, रंग श्रीर वार्निय जैसे उपमोग की वस्तुओं के उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूर्व उपयोग किया जाय।

(२) लोहे तथा इस्पात, पल्लूमीनियम, सीमेंट, स्सानिक खाद, भारी

रखायनिक, मधीनों के श्रीजार इत्यादि उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्ति को बदाया जाय।

(३) जिस उद्योग को आरंभ करने के लिए कुछ पूँची लगा दी गई है उसे परा किया जाय।

(४) देश के औवोधिक दाँचे को अधिक शांकशाली बनाने के लिए अपने साधनों को स्थान में रखते हुए नये कारलाने स्वाधित किये जाएँ जैसे किस्सम से सन्दर्भ का ज्याहन किया जाए।

मथम योजना में उद्योगों के तीन वर्ग किये गये थे। (१) जुड श्रीटीमॉबाइलच, मशीन व श्रीजार कपडे की सशीन तथा चटी के उन्नोगों के सम्बन्ध में जिसकी उत्पादन शक्ति प्रयोम थी इस बात पर अहत्व दिया गया कि वे श्रापना जत्यादन बढाकर अपनी अनुसानित शक्ति के स्तर पर ले आर्थ को बटली नहीं जायगी: दले हये लोहे. हरपात. चीनी. धीमेंट, कागज और कागज के पट्टे, दियासलाई तथा केळ रसायनिक बस्तकों का अत्यादन करने बाले अलोग जिनके सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया या कि उनकी अनुमानित शक्ति बढाई तो जायगी पर १०० मितियत से कम । इनके अन्तर्गत सीमेट, सलप्यरिक पैसिड, दला हथा लोहा, वैयार इस्पात, कागज और कागज के पटटे. दियासलाई, स्टोरेज बेटरी और विजली के पंती बनाने वाले उद्योग भी सम्मिलित कर लिये गये थे; (३) विजली से चलने वाले पम्पों, डिज़िल इजनों, सीने की मशीन, बाइछिकिलों इत्यादि उद्योगों का जिनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति औंग के अनुपात में कम है काफी मसर करने की योजना बनाई गई थी। इसी श्रेग्सी में श्रन्य उद्योग भी श्राते हैं जैसे काटन शिन्दर्श, केसिकल पल्प, कछ दवाइयाँ इत्यादि जिनका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता था परन्त खब इनके उत्पादन की ब्यवस्था की गई थी। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना में देश के ख़ौद्योगिक विकास की कमी को परा करने का प्रयक्ष किया गया था।

हितीय योजना के अन्तर्गत—हितीय पंचवर्षीय योजना में श्रीयोगिक श्रीर खिनिज पदार्थों के विकास को प्रथम योजना की श्रेपेसा श्रिपेक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वास्तव में हितीय योजना श्रीयोगिक विकास पर केन्द्रित है। हितीय योजना में ४८०० करोड़ या। १८५% उद्योगी पर अप किया यायमा जब कि प्रथम योजना के कुल २,५६६ करोड़ या। १८५% अपने के या वे के प्रथम योजना के कुल २,५६६ करोड़ या वे अपने में उद्योग पर १७६ करोड़ क्यरे या ७६% व्यय किया जाना था। हितीय रोजना प्रथम की श्रेपेसा श्रिपेसा श्रीय वे श्रीर हमें व्यय में बहुत श्रीर हमें व्यय मी बहुत श्रीर साम स्था हो श्रीयोग को श्रीयक महत्व देने का कारण देश

के क्रापिक विकास को अधिक संतुक्षित करना, राष्ट्रीय ग्राय में वृद्धि और वेकारी क्रांदि को कम करना है। द्वितीय योजना के क्रन्तगैत कार्यक्रम में प्राथमिकता

निम प्रकार दी गई है।

(१) लोहे ग्रीर इस्पात तथा मारी रशायनिक उद्योगों का निर्माण करना जिसमें नाइट्रोजन युक्त खाद ग्रीर इन्जीनियरिंग तथा मर्रीनों के

(२) विकास सम्बन्धी वस्तुओं तथा उत्पादन में कार्य आने वाली यस्तुओं, निर्माण सम्बन्धी उद्योग सम्मिलित है । जैसे अलमोनियम, शीमेंट, रखायमिक परुप, रँग, कारफेट युक्त लाद श्लीर श्रायन्त श्रावरुपक दवादैयाँ आदि की उत्पादन शकि में

(३) महत्यसाली राष्ट्रीय उचीम, जो स्थापित हो चुके हैं, जैसे जट श्रीर सुती कपने बनाने तथा चीनी उद्योग आदि, उनके प्रतापनी की

(४) इन उचोगो की उत्पादन शक्ति में जिनकी उत्पादन शक्ति श्रीर वास्त-विक उत्पादन में श्रान्तर है वृद्धि करना।

(4) साधारख उत्पादम के कार्यक्रमी तथा उद्योगी के विकेट्रित श्रंग के उत्पादन सहय के अनुसार उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि

श्रीवीरिक विकास के कार्य कम के इच्छिकीय से दिवीय योजना की

(१) इसमें राजकीय सेम की व्यक्तियत सेम से झविक महत्ता दी गई है। श्च नेकी विशेषतार्थे हैं :--द्वितीय योजना की नवीनता इस बात में है कि राजकीय खेत्र में श्रीयोगिक श्रीर खतिज उद्योगों के विकास के कार्यक्रमा को प्रधानता दी गई है। मारत में कृषि, नियुद्ध शक्ति, यातायाव, दबा खामाजिक सेवाझों के निकाय के सम्बन्ध में राज-कीय उपक्रमी पर निर्मरता आर्थिक योजना की विदोधता है। परन्तु अभी तक तो राजकीय चेत्र के अन्तर्गत किये गये विनियोग में उद्योगी और खनित सम्बन्धी योजनात्री को कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त हुआ था। प्रथम योजना में राजकीय चित्र में बढ़े उद्योगों की स्थापना के लिये केवल ६४ करोड़ रुपयों के विनियोग का प्रवत्य क्रिया गया था, जबकि व्यक्तिगत त्रेत्र में २३३ करोड क्ययों के चिनियोग का श्रनुमान किया गया था। द्वितीय योजना के अन्तर्गत राजकीय होत्र में बढे उद्योषी आरे खनित्र के विकास के लिये (वैद्यानिक अन्येयस कार्य पर व्यय र्शामालित करते हुये) ६६० करोड़ रूपयो को व्यवस्था की गई है जब कि व्यक्तिगत चेत्र में उद्योगो और खानों पर ब्यय किये जाने के लिये केवल ५०५ करोड़ द्ययों का क्षी मुक्त्य है। व्यक्तिगत चेत्र को यद्यपि देशा के औद्योगिक विकास में एक बहुत बड़ा भाग लेना है किर मी यह प्रव्यच्च है कि राजकीय चेत्र की योजनायां पर ब्यक्तिगत केव की योजनाओं से अयेक्स करत अधिक सहत्व दिया गया है।

(२) योजना की दूखरी विशेषता यह है कि मुख्य और आधार उद्योगों का विकास उपमोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की अपेक्षा अपिक किया जायगा। प्रतिष्ठापित उत्पादन करने वाले उद्योगों कि अपेक्षा अपिक किया जायगा। प्रतिष्ठापित उत्पादन सम्बन्ध १६६०-६१ के आँकड़े यह प्रकट करते हैं कि लो है और इररात, उत्पादन सम्बन्ध १६६०-६१ के आँकड़े यह प्रकट करते हैं कि लो है और इररात, प्राचीन तिरात तथा स्वापनिक उद्योगों के अपिकतम प्रकार का आयोजन किया या है। अप्तत व्या जायगित निर्माण उद्योग के विकास का आयोजन किया गया है। युत वया जुट विनने की मसीनों के वया सीमेंट और चीनी बनाने की मसीनों के और खोट छोट औज आयो के उत्पादन के उद्योग तो मारत में पहिले ही रिपत है, पर उनका बहुत अधिक विद्यात कर दिया जायगा। कागन तथा अपने उद्योग के उत्पादन का मुल्य १९६०-६१ तक कमशः ४ करोड कर्य तथा २ करोड कर्य तथा हो जायगा। वर्तमान समय में तो इन वस्तुओं का उत्पादन नगरप धी है।

बहै उद्योगे और खतिन उद्योग पर वो ६६० करोड़ रूपया व्यय किया जाने वाला है यह लगभग पूर्व रूप में भूल उद्योगों के विकास के लिये है, जैसे लोहा हरगत, कोयला, खाद, हम्जीनियरिंग तथा बड़े बड़े निजली के प्रधायन हरगिर । योजना में तीन हरगत संपन्नी की स्थापना रूपकेला, निलाई, और दुर्गपुर में होगी जिनमें से प्रत्येक उत्पादन द्यांक १० लाव रूप महरात विधा में होगी। इसके अतिरिक्त इनमें से एक संयन्त ती १५८०,००० उन उला हुआ लीहा विकी के लिये उत्पादित करेगा। राजकीय दीन के अन्तर्गत वव योजनाओं से आरात की वाती है कि कुल इस्पात की उत्पादित मात्रा लगभग २० लाख उन दितीय योजना के अन्त तक हो जायगी।

इम्जीनियरिंग के बहु बहै उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम में चित्तरस्वन लोकोमीटिव फैक्ट्री में एक बड़ी इस्पात फाउन्ट्री की स्थापना भी सिम्मिलत है। इस बात का प्रकम्य किया जा रहा है कि बड़े बड़े विजली के प्रधापनों का निर्माण राजकीय चेत्र में हो। इसलिये चित्तरस्वन लोकोमीटिव फैक्ट्री का बिस्सार होना रमावस्थ के तार्कि वर्तमान समय के १२५ इन्जिनो के वार्षिक उत्यादन के स्थान पर ३०० इस्जनों का प्रविचर्य उत्पादन हो जाय। दि इस्टीमरल कोच फैक्ट्री जिसने उत्पादन कार्य १९५५ में खारम्य किया खपमग ३५० कोच प्रतिवर्ष १९५६ तक उत्पादित कर सकेगी | एक नई मीटर गेंब कोच कैस्ट्री की स्थानना का मी

प्रवस्य कर दिया गया है।

(3) दितीय-योजना में आग्य और छोटे उत्योगों को प्रथम योजना की अपन योजना की अपन योजना की अपन योजना की अपने आग्र है कि अपेजा अपिक सहत्वपूर्ण स्थान दिया गया है की अपने क स्थान पर अब २०० करोड़ उत्पर प्रथम योजना के ३० करोड़ करवे के ब्यूय के स्थान पर अब २०० करोड़ उत्पर प्रथम योजना के ३० करोड़ करवे के ब्यूय के स्थान पर अब २०० करोड़ उत्पर प्रथम योजना के ३० करोड़ उत्पर प्रथम योजना के उत्पर्ण स्थान विश्व अपने के अपने के उत्पर्ण प्रथम के विश्व विश्व अपने के अपने करने के कारण यह है कि देश की आर्थिक अयावस्य के विकेत्रित आग्र में कार्य करने के

श्रीफ श्रवसर प्रदान कर सकेंगे।

समाजी पना—हितीय योजना प्रथम योजना की श्रवेश श्रविक विचार
स्माजी पना—हितीय योजना प्रथम योजना में श्रीकी तिक विकास
पूर्य है। इठ योजना में यह उचित ही है कि कृषि को तुलना संश्रीकी तिक कि स्वार पर श्रिक महत्व दिया गया है। इठते देश का खंतित विकास समय हो हकेगा
पर श्रीक महत्व दिया गया है। इटते में श्राव वह गए वे वे पूर्य हो जानेंगे। यह
श्रीर जो देश की श्राधिक व्यवस्था में ग्रावा वह गए वे वे पूर्य हो जानेंगे। यह
श्रीर जो देश की श्राविक व्यवस्था में ग्रावा वह गया वे श्रीवी के अवीत में मिल भी बहुत उपयुक्त है कि वह मुल श्रीर सप्रोनों के निर्माय के उद्योगों के प्रवि भी बहुत उपयुक्त है कि वह मुल श्रीर सप्रोनों के स्वार्थ श्रीवी होती स्वि भी स्वी प्रविक्ता। यह वह होते हुए श्री हितीय योजना में श्रवेतों गम्मीर दोय पह गये हैं।

(१) राजजीव चेन का अत्योधक विस्तार कर दिया गया है। यदि संकार के पास चन के खात, श्रीतोगिक शान, उत्योधी के आरम करने की चमता श्रादि के पास चन के खात, श्रीतोगिक शान, उत्योधी के आरम करने की चमता शादि होती तब तो हरमें कोई हानि की सम्मानना न होती, परन्छ सरकार के पार वे वे पर्योध मना में नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने हो उत्योग को राजजीय चेत्र के स्वपंदि मना में नहीं है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त होता है। अत्याधी मना कर लिये गये हैं उनमें राजजीय चेत्र को आवस्यकता है। अत्याधी सकता है उत्यक्त अपेका अधिक जोविक्त उत्योग और साहय की आवस्यकता है। अधिक अस्त में पह भी कहा जाता है कि राजजीय चुन के लिये सुमाना पूर्वक कार्य करते दहने के विस्तृत कर देने से वाधिकार चेत्र के लिये सुमाना पूर्वक कार्य करते दहने के विस्तृत कर देने से वाधिकार चेत्र के लिये सुमाना पूर्वक कार्य करते दहने के विस्तृत कर देने से वाधिकार चेत्र के लिये सुमाना पूर्वक कार्य करते दहने के विस्तृत कर देने से वाधिकार चेत्र अस्त समाना पूर्वक कार्य करते दहने के विस्तृत कर देने से वाधिकार चेत्र अस्त समाना पूर्वक कार्य करते दहने के विस्तृत कर देन से वाधिकार चेत्र अस्त समाना पूर्वक कार्य करते दहने के विस्तृत कर देन से वाधिकार चेत्र समाना पूर्वक कार्य करते दहने के विस्तृत कर देन से वाधकार चेत्र समाना पूर्वक कार्य करते हैं। इसमें स्वत्य करते समाना पूर्वक कार्य करते हिंदी स्वत्य समाना प्रति समाना समा

लस्य को पूर्ण न कर सकेगा।

(२) यद्यपि व्यक्तिगत लेव पर कुछ वस्तुयों की एक निश्चित मात्रा के

(२) यद्यपि व्यक्तिगत लेव पर कुछ वस्तुयों की एक निश्चित मात्रा के

जलादन करने का उत्तरदायित्व डाल दिया गता है, परन्तु इपके लिये न ऐती

पर्याप्त मात्रा में दिश्व की उपनिव का को प्रश्च किया गया है प्रीर न ऐती

पर्याप्त मात्रा में दिश्व की उपनिव का को प्रश्च के लिये निर्दे अथवा करों से लूट

मुख्यियों दी प्रदान की गई है लीवे अवस्यय्व के लिये निर्दे अथवा प्रश्च के

प्रारी, जो कि व्यक्तिगन लेव के सरवता से कार्य करते रहने के लिये आवश्यक

है। राष्ट्रीय द्वीयोगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) निसकी १९५४ में स्थापना की गई थी ज्यक्तिगत चैत्र में उद्योगों के विकास में बहुत सद्वायता पूर्व कार्य कर रहा है। दितीय योजना में भी यह संस्था व्यक्तिगत चेत्र में सहायता कार्य करती रहेगी। यह सब होते हुये भी यह निश्चत रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत चेत्र को निच संकट उटाना यक रहा है. निस्ते श्रीयोगिक निकास में भाग यक रही है।

(१) भारत के श्रीयोगिक संगठन में महत्वपूर्ण स्थान राजने के कारण यह वर्षेषा उपयुक्त है कि मान्य और होटे उचीमों के दिकाय का मयतन किया आप, परन्तु वह करापि व्यायसंगत नहीं है कि यहे उचीमों पर उपकर आरोगित किया काय अपना उनके उत्पादन की माना पर प्रतिवन्त्र कामा दिया जाय, जिससे कि मान्य और छोटे उचीमों की रच्छा है छिड़ हस कामार्गरम का साहस नष्ट हो जाता है और कोई प्रमानचाली सहायता भी प्राप्त अपना छोटे उचीमों को नहीं मिलती। इन उदीमों की समस्या को उनके हारा उत्पादित बस्तुमों के गुणी की उन्नात करके, तथा उनके मुख्य को पटा कर करना चाहिये न कि वड़े उपीमों पर प्रतिकृत्र हमा।

दितीय योजना के श्रीवोधिक विकास कार्यक्रम में उपर्युक्त रोवों के होते हुये भी यह श्राष्टा की जाती है कि इक्से श्रीवोधिक विकास की पति में अवस्य दृद्धि होती, तथा श्रीवोधिक विवास सगटन के श्रमायों की पूर्व करके यह योजना संतुक्तन स्पापित करेगी श्रीर संसार में भारत का श्रीवोधिक स्वर ऊँचा उठायेगी।

योजना की प्रश्ति—"१६५७-५८ तक पहली योजना में प्रारम्म की गई स्रज के सौद्योगिक योजनाएँ पूर्ण हो गई। इन योजनाओं में स्रज के बी वी० की को को ने योजनाओं में स्रज के बी की की की को ने योजनाओं में स्रज के बी की की को निर्माण के सिर्माण हिन्दी कि सी० की की वी० की कारलाने का विस्ताण, दिख्य का बी० की को में से पर्याप्त परिवाण के स्रोण वोचेलीन के स्रोण की वोचेलीन इन्सुनेटर्स की सुपर फाफिट के स्रोण वर्षण के बार का प्रारम्भ एक स्टील वर्षण का इपापाण के सुप्त होने में से सुप्त की स्त्राप्त की स्त्राप्त के सुप्त होने में से स्त्राप्त की साम स्त्राप्त की स्त्राप्त हुई। हित्तीय योजना में इन स्त्रीण की स्त्राप्त प्राप्त करने की स्त्राप्त की से स्त्राप्त प्राप्त हुई। हित्तीय योजना में इन स्त्रीण की स्त्राप्त प्राप्त करने करने करने करने की स्त्राप्त की से स्त्राप्त प्राप्त हुई।

ामें भारत में निजी उद्योग की वर्तमान स्थिति श्रीर उत्तके संगठन तथा श्राकार-नीर पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विपरीत निजी-उद्योग चेत्र में ार २२ अञ्चल प्रस्ता चना वर्गा स्था बात लागु की गाँव हैं जिनकी अपनीमिता पर सन्देह प्रगट किया जा —सा है, जो देश के ख्रोधोसिक विकास में सहायक होने की ख्रपेदा बाघक हो

६ खप्रेल १९४८ का खोद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव— १९४८ क्षीपत जीवोगिक गीव में 'मिश्रव' अर्थ अवश्या के विद्यान को स्वीकार 3 7 31 गया है। वरन्तु राष्ट्रीवकरण का विषय इसमें विशेष रूप से समिमलित ागपा है। बास्तव में 'मिश्रित अर्थ क्यवस्या' के विद्यान्त में ही 'राष्ट्रीयकरण' ्रिवचार निहित है। यरन्तु सरकार ने अपनी बोमवा में इसकी चर्चा करके इसे क स्मष्ट कर दिया। इस पोपवा में उद्योगों को तीन श्रेषियों में विमाजित ागपा था। (१) प्रथम क्षेत्री के उद्योगों में हथियाचे ख़ीर गोला-मास्त का ीदन, प्राप्त-शक्ति का उत्पादन श्रीर नियंत्रण श्रीर रेलवे परिलक्ष्म का प्रदम्ब स्वामिल बाम्मलित किये गये वे । इन उलोगों वर शक्य को पूर्ण एकाधिकार गया । इन व्यवस्था से विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि ये उद्योग हु से ही राज्य के अधिकार में और इस बात की बहुत कम सम्मायना है कि में निक्षी उचीग इनमें से किसी एक को भी अपनाने के खिये तैयार होगा। — में दितीय और तृतीय श्रेणी के उद्योगों पर ही इस श्रीवामिक मीति का — निर्मर करता है। (२) द्वितीय श्रेशों के उचोगों में कोवला, लोहा, इसाव, नि-निर्मीच बलयान-निर्माख, टेल्लिन, तार तथा बेतार के तार के येत्री का िय क्रीर पेट्रोल इत्यादि खनिज तेल समिमिलत किये गये हैं। इन उद्योगी के न्य में यह कहा गया या कि इस श्रेशी के नवीन कारलानों को स्पापित करने ्च उत्तरदायिल केवल राज्य पर होया श्रीर जो वर्तमान समय में चालू भाने हैं उनकी दस वर्ष से पुनः बॉच की जायगी और यदि प्रावस्पक हुआ तिका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायमा । इत व्यवस्था का तिवी उद्योग पर बुरा व पड़ा। इससे उनका मिवब्य अनिष्चत हो गया। उदीय में सुधार करने ह्मये को कुछ रुपया लगाया जायगा उपका लाम उठा सकने के लिये १० वर्ष समय बहुत कम है। और चूँकि नये कारखाने स्थापित करने का पूर्ण मार ने सीकार कर लिया, इससे इस अशी के उद्योगों में निजी उद्योग के नकों की रूचि कम हो गई इस द्वेज में उनका समूर्ण उत्साह समाप्त हो गया। प्तम स्वरूप श्रीवीमिक उत्पादन घट गया, पूँबी निर्माण की प्रक्रिया पद गई और औरोसिक देव में मुद्ध सीमातक सन्दी छा गई। यदि

विशेष हाति की सभावता नहीं थी। परत्त भारत सरकार और जाउन सरकारों के वास इस कार्य के लिये आवश्यक घन, साहस और क्यस कर्मचारियों का स्रभाव है। फल स्वरूप देश की श्रोद्योगिक स्विति प्रगति करने की अपेका अवनत होती गई। (३) शेष उद्योगों को तीसरी श्रेणी में रखा गया। यद्यपि इस श्रेणी के उद्योगों को निजी उद्योग चीत्र के लिये छोड़ दिया गया परन्त यह भी कहा गया कि राज्य रस सेथ में भी कमना भाग सेगा। परस्त सामने के बानाय के कारण राज्य दम सेच से सकिय नहीं हो सका । नधीन औरोपिक नीति—३० अप्रैल १६५६ की घोषित नदीन

श्रीयोगिक नीति १६४८ के श्रीयोगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताद की क्रणरेखा से मिलली जलती है. और उद्योगों को राज्य द्वारा उनमें भाग लेने के आधार पर

३ बर्गी में विभाजिस करतो है। प्रथम वर्ग में १७ उद्योगों की गराना की गई है बिनमें कोपला, लोडा और इस्पात, लविज-तेल, सामान्य और विद्यत इन्जीनि-यरिंग के कुछ खरा खीर परिवहन सम्बन्धी कुछ ऐसे उद्योग खाते हैं जिसके भाषी विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य के कार है। द्वितीय वर्श में लगभग एक दर्जन उद्योग सम्मितित किये गये हैं, जैसे मशीन के यन्त्र, ग्रास्थित्यम, खाद, सहक श्रीर समदी परिवहन इत्यादि जिनमें ध्यक्तिगत श्रीर राजकीय जवकम साथ-साथ चलेंगे परन्त यह कमशः राजकीय अधिकार में आ जार्येंगे, इस लिये इन में नदीन उपक्रमों के स्थापित करने में राज्य त्रावगणी होगा। शेष उद्योग जैसे सती कवडे. सीमेंट, चीनी इत्यादि तीसरे वर्ग में स्क्ले गये हैं । इनका भावी विकास सामा-न्यतः व्यक्तिगत क्रेत्र से उपलब्ध कार्यारम्भ साहस पर निर्मेर करेगा। राज्य की यह भी श्राधिकार होगा कि इस वर्श के उद्योगों को भी श्रारक्ष्य कर सके।

उदांगों के इस ज़ियगीय विभाजन में कोई दोच नहीं है। १९४५ के श्रीद्योगिक नीति प्रस्ताव के श्रनसार संतोष प्रद देंग से कार्य हुआ है। परन्त नधीन श्रीयोगिक नीति के त्रिवर्गीय विभाजन में कुछ दोव शा गये हैं।

(१) राजकीय च्रेत्र के विस्तार में बहत अधिक वृद्धि कर दी गई है श्रीर व्यक्तिगत चैत्र को अत्यधिक संकचित कर दिया गया है। इससे हानि यह होगी कि भ्रौशोगिक ज्ञान वाले कर्मचारियों, संगठन करने की स्थवा, पँजी तथा श्रवु- 🕶 भव के अभाव में राज्य उन उद्योगों का प्रबन्ध न पूर्णतः और ने अधिकाँश ही कर सकेगा जिन्हें उसने अपने लिये सुरिज्ञत कर रक्खा है। व्यक्तिगत उपक्रम इस कठिनाई को मुधार सकने में ग्रसमर्थ होगा क्योंकि नवीन नीति के ग्रनुसार उन्हें यह कर सकते का कोई अधिकार ही न होगा और यदि सरकार उन्हें आमन्त्रित

भी करेती तो अनमें इतना जाता विज्वास न होता कि वे ऐसा कर सर्के। इस नीति के निर्माता इस कदिनाई से अनिमन नहीं थे । जो व्यक्ति व्यक्तिगत उप-क्रमों की कार्य प्रमाली और १९४= के श्रीक्षेत्रिक जीति प्रस्ताव के प्रभाव से परिचित हैं वे समक सकते हैं कि इस प्रयोगात्मक परिस्थित में व्यक्तिगत उपकम सम्मुख ग्राने का माइस न कर सकेरों । प्रथम दोनों वर्गों में मामालित क्यांकरात उलोगों को मरलता से कार्य करते रहते के लिये आवश्यक वातावरण का श्रमाव है। यदि मन पाँच वर्षों के जनमन का भरोसा करें तो यह आशा करना कि यदि राजकीय जपक्रम शाहिजन सहय की वरा न कर सके तो उसका स्थान व्यक्तिगत उपहल के लेंगे, यक्त संगत नहीं है। यदि प्रथम बगों में गिने गये कछ उद्योगों को तीसरे वर्ग में स्थानास्तरित कर दिया जाता. जिसमें कार्योरम्भ का भार स्थक्तिगत जयक्रमों पर है तो निक्रियत रूप से यह सम्मय होता कि वे किसी न किसी प्रकार श्रीद्योगिक शान, पंक्षी तथा श्रनभय के अभाव की पूर्ण कर सकते जैसा कि गत Dee वर्षों से देखने में आया है। यह कोई तर्क नहीं है कि आंशोशिक समता. पंती. धानमव ग्राटि का सर्वधा ग्रामाय है. श्रोर इस लिये राजकीय उपक्रम खायवा व्यक्तिगन जणकम कारा इस समस्या को सलमाने में कोई खन्तर नहीं पहता बहुत बड़ा अन्तर तो यह है कि व्यक्तिगत उपक्रमों के पास उत्साह खीशोगिक समता और कार्य करने की शक्ति है खोर राजकीय उपक्रमों के पास इनका ध्रामान है। नवीन श्रीद्योगिक नीति के कारण विकास की गति बढ़ने के स्थान पर अववह हो लायगी।

(१) १६ ४६ की श्रीयोगिक नीति मैं यर्थमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण्य के लिये १० वर्ष की श्रविध निष्यत की गई थी, श्रीर तिविदे वर्षों के उद्योगों के लिये यह स्पष्ठ कर से कह दिया गया था राज्य उन्हीं उद्योगों को हस्त्रात करिया किया माति की तियम नहीं नहीं है। इचने व्यक्तिगत उपक्रमों को कुछ आशा गयी। परस्तु अब राज्य की अस्पिक श्रविकार रेकर व्यक्ष में व्यक्तिगत उपक्रमों की सुरवा की मायना का अपहरण्य कर लिया गया है। यह राज्य के विचार अथवा अधिकार से का मायना का अपहरण्य कर लिया गया है। यह राज्य के विचार अथवा अधिकार से का महन नहीं है चस्त् यह तो व्यक्तिगत उपक्रम में विरशास और सेहेंह की मायना उपक्रम में विरशास और सेहेंह की मायना उपक्रम में विरशास की का स्वात नहीं कर सकते।

(३) व्यक्तिगत उपक्रम को बहुत ही संकुचित दोत्र प्रदान किया गया है बिछके कारण ने सरलता से कार्य नहीं कर सकते। मारत की श्रीयोगिक नीति में विस्त प्रकार राजकीय दोत्र का निष्ट्वत स्थान है वैसे हो व्यक्तिगत चेत्र का मी है। व्यक्तिगत चेत्र के विस्तार को कम करने के किसी मी प्रमक्ष का स्वामायिक

परिभारम प्राप्त के श्रीशोजिक विकास को कम करता है। वर्तपान समय में प्रचलित जाय और सम्पन्ति के जातर को कम करने व्यक्तिगत एकाधिकार की रोजने और व्याधिक शक्ति को थोड़े से ब्यक्तियों के हाथ में केन्टित होने से बचाने के लक्ष्य को पाम करने के लिये यह तर्क असंगत है। इस बात को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत में राज्य की जो क्राधिकार काज प्राप्त है जनके द्वारा बसोनों के व्यक्तिगत सेत्र में रहते पर भी बढ़ एकाधिकार तथा ब्रार्थिक शक्तिका केन्द्रित होना न रोक सके। जहाँ तक ब्राय के ब्रान्तर का सन्दर्भ है यह तो आधिक तथा अन्य उपायों से पहिले ही काम किया जा चका है। किर यह कैसे निज्ञ्चत रूप से कहा जा सकता है कि उद्योगों को राजकीय जेन्न में रखने से ब्यायिक शांक्ट केन्द्रित न होगी। ब्रम्य देशों के ब्रायमन के अनुसार इसका परिणाम अधिक डानिकारक दोगा। दसरा कारण जिसके श्राधार पर वही मात्रा में अस्पादन करने वाले अपक्रमों का विस्तार क्यकियात क्षेत्र में संकचित किया गया है वह फटीर, धाम्य और छोटे उद्योगों की बढ़े उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाकर खोर भिन्न करारोप द्वारा खथवा प्रत्यक्त खनदानी हारा सहायता करता है। भारत में आस्य और खोटे ज्योगों की फोत्साहत हैने में कोई दोए नहीं है। बास्तविक बात तो यह है कि इनका भारत की खीद्योगिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्त बड़े उद्योगों को हानि पहेंचाकर छोटे उद्योगों की प्रगति करना सर्वथा अविचारपूर्ण है। भारत की राष्ट्रीय आय और ग्रीधोगिक विकास में विद्व बड़े उद्योशों से ही सम्भव है। द्वितीय योजना का ध्येय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बद्धाना और वेकारी घटाना है। यदि वड़े उचीगों का काल्पनिक आदशों के लिये उत्तर्गकर दिया गया तो यह ध्येय कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। व्यक्तिगत द्वेत्र के विस्तार को सकवित कर देने का परियाम यह होगा कि व्यक्तिगत उपक्रम उचित शैति से कार्य न कर सकेंगे।

नवीन झौथोगिक नीति में वे शुण तो नहीं है जो कि १६४८ के झौथो-गिक नीति प्रस्ताव में में, परन्तु उसके सब दोष उसमें वर्तमान हैं। १६४८ की नीति नकारात्मक भी और उसमें व्यक्तिगत उपक्रमों पर लागिये गये प्रतिक्य को ही केवल वर्षों पा। राज्य से उन्हें क्या सहाबता प्राप्त होगी इसके प्रति को स्वेत नहीं था। यही दोष नवीन झौथोगिक नीति में जनसा को महान प्रतीत होने वाले निर्मक आदशों के सम्मिथ्य के रूप में है। व्यक्तिगत उपक्रम की अवस्थिक कर, आयकर के नियमों के अनुकृत उनके लिये पर्याप्त मात्रा में अवस्थाय बुल्ति का प्रवन्य, और सरकार की अम और मृत्य नीति के कारण स्थेत बहुते हुये उत्पादन ज्यव से रहा आयस्यक है। राज्य को इस दृष्टिकोण से व्यक्तिगत उपक्रमों को निश्चित सहायवा प्रदान करनी चाहिये जिससे ये सफलता-पूर्वक अपना कार्य कर सकें। सहायता का क्या रूप होगा और वह किस विधि से दी आयगी आदि बार्ने सरकार की औचोगिक नीति का एक आवश्यक अंग बन जानी चाहिये जिससे कि वे सम्मय हो सकें।

१६४१ का उद्योग कानून—११५१ का उद्योग (विकास और नियमन) कानून प्रथम अनुसूची में दिये गये उन १७ उद्योगों पर लागू होगा जिनमें १ लाख के अधिक पूँची लगाई गई है। यह व्यवस्था की गई है कि इन सभी औद्योगिक संस्थानों को आनिवास कर से अधनी रिकट्टी करानी पड़ेगी। कोई नयीन कारखाना स्थापित करने के लिये अधना पर्वमान कारखानों का प्रसार करने के लिये अधना स्थापित करने के लिये अधना स्थाप

कातन के अनुसार सरकार की यह अधिकार दिया गया है कि यह किसी मी अनुस्चित उद्योग की जाँच करा सकती है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। इस सिटेंशी का पालन न करने पर वेन्टीय सरकार सम्पर्ण उद्योग को या उसके किसी भाग को एक निजियत काल के लिए किसी व्यक्ति, बोर्ड या विकास-परिवद के बाथ में सौप सकती है। परन्त यह श्रवधि प्रवर्ष से श्राधिक नहीं हो सकती। यह व्यवस्थाएँ श्रस्पन्ट श्रीर विस्तत है। यह खेद का विषय है कि संसद ने जिस दिलीय प्रवर-ममिति को यह विशेषक विचारार्थ सौंपा उसने प्रथम प्रवर-समिति की रिपोर्ट में दी गई उस शतों को रह कर दिया जिनके श्राचार पर राज्य इस्तक्तेय कर सकता था। प्रथम प्रवर समिति से भिकारिका की थी कि यदि उद्योग के प्रवन्ध में अधिक अव्यवस्था फैली हो. वस्तुओं के भाव में अनुचित उतार-बढ़ान हो, वस्तुओं का अभाव हो, अभिको में अशांत एवस श्रसन्तीय हो और यदि सम्बन्धित उद्योग के कार्य में आने वाले कच्चे माल का श्रमान और उसकी शीध समान्ति की शेकना राष्ट्र हित में ही तभी राज्य की श्रपने नियंत्रण और इस्तचेत के अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। इन शर्तों में निभी उद्योग सन्तष्ट था और यदि विदेयक इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता तो त्रौद्योगिक विकास को हानि न उठानी पटती परन्तु द्वितीय प्रवर-समिति द्वारा इन निश्चित श्रवों को रिपोर्ट में से निकाल देने के कारण फिर वही ेश्रनिश्चिनता फैल गई जो सरकार की भूतपूर्व श्रीयोगिक नीति से फैली थी।

इस कारत में केन्द्रीय परामर्शदानी परिषद और विकास-परिवर्ट स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय परामर्शदानो परिषद में उद्योगपतियों, कर्मचारियों और अनुभूषित उद्योगों द्वारा उत्यादित माल के उपमोक्ताओं के प्रति-निष होंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी इस परिषद में सम्मितित किए जा सकेंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समकेंगी। श्रध्यज्ञ को छोड़ कर परिषद् की सदस्य संस्था ३० में अधिक नहीं होगी। वेन्द्रीय परामर्श्वदात्री परिषट् अतु-सचित उद्योगों के विकास और नियमन के सम्बन्ध में सरकार को सफाव देगी।

किसी भी अनुस्वित उस्तेग अथवा उसेगों के समूह के लिए विकास परिपर स्थापित की जा सकती हैं। विकास परिपर में उसीगातियों, कर्मनारियों और उन उसीगों हारा उत्पादित माल के उपमोक्ताओं के मतिनिधि होंगे। इस्में में से व्यक्त में से बहुत ब्यापित का कि में कि क्षेत्र के अपनी का में से मिल कि होंगे हैं। इस्में में से वर्ष में से दर्शन का से के निकास मार्थ के उसी अपनी अपनी का मार्थ में स्थाप उसीगों के बाता मार्थ है। मुख्यत विकास परिपर उत्पादन का कार्य निर्धारित करेंगी, इत्यादन-कार्य में सामंत्र व्यापित करने के लिए सुकाब देंगी और समय समय पर उसीग अपना उसीगों की प्रगति को समीजा करेंगी, इसके साम दायान करने के लिए सुकाब देंगी और समय समय पर उसीग अपना उसीगों की मार्थ की समीजा करेंगी, इसके साम उत्पादन करने के लिए सुकाब के मान निर्धारित करेंगी, अधिकत्य प्रजाद त्यादन करने के तिय सुकाब देंगी। विकास परिपर्व उतारित परत्र की मकार के सिप सुकाब करने के लिए सुकाब देंगी। विकास परिपर्व उतारित परत्र की मार्थ की उपाद सुकाब सुकाब के अपनी की अपनी की अपनी की अपनी की उत्पादन परिपर्व उतारित परत्र की स्था सुकाब की अपनी की अपनी की अपनी की अपनी की उत्पादन परिपर्व की उपनाद सुकाब की अपनी अपनी की अपनी की अपनी की अपनी की अपनि का सुकाब सुवा अपन अपनी की अपनी की अपनि की अपनी अपनी की अपनी अपनी की अपनी की अपनी अपनी की अपनी अपनी अपनी की अपनी अपनी अपनी अपनी अ

विकास-परिपतों से यह आशा की जाती है कि यह निजी उद्योग के लिए एक परिचारिका का कार्य करेंगी। १६५३ में ऐसी दो विकास परिपर्टे स्थापित की गई।। बाद में अन्य विकास परिपर्टे स्थापित की गई। १६५७ के अन्त में १२ विकास परिपर्टे निज्ञ उद्योगों के लिये काम कर गई। श्री।

- (१) मारी विद्युत् उद्योग,
- (२) इलका वियुत् उद्योग
- (१) Internal Combustion Engines तथा शक्तिचालित पग्प

१. ८ मई १६५२ को कन्त् लामू होने के साथ ही केन्द्रीय परामर्शवार्जी परिषद् स्थापित की गई, वाखिश्य तथा उद्योग-मन्त्री इसके अध्यक्त हैं। १६५६ में इसका पुनंतगरन किया गया और इसके सदस्यों की संत्या २६ कर दी गई जिनमें से १५ टायोगपरियों के मोजिनिए (अप्रयुक्ति उद्योग के), ५ वर्मवारी, ५ उपभोक्ता, और ५ अप्रय ब्यक्ति जिनमें प्रारम्भिक उत्यादक समिमलित हैं । इससे यह परिषद् पूर्ण रूपेण प्रतिनिधि परिषद् वन गई है।

(४) सहिक्त

(५) अम्ल (acid) और उर्वरक

(६) ज्ञार (alkalı) तथा सम्बन्धित उद्योग

(७) दवाइयाँ

(द) उसी क्या

(६) कलाएका रेजामी कपहा

(१०) चीनी (शकर)

(११) छलोड धात्रवें और मिश्रित घात्रवें: तथा

(१२) मशीन-श्रीजार

इस परिवरों का कार्य अपने-अपने उद्योगों की समस्वाध्यों पर विचार करता । इनका थ्येय है उन्नोगों को अपनी पूर्ण शक्ति मर उत्पादन कर सकने की संविधार्य प्रदान करना, उनकी (रेटेड) अंकित शक्ति को ग्रावश्यक स्तर तक बद्दाना, श्रीर उत्पादन व्यय को कम करना है।

विकास परिवरों की संस्था हम लोगों ने ब्रिटेन से अनसरवा की है जहाँ पर इसकी स्थापना अनेको उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में की गई थी। यहाँ ये परिषद असफल सिट हये पर इस खोग श्रव भी इनको अपनाए इए हैं। व्यक्तिगत उपक्रमों के सफलता पूर्वक कार्य करने के लिये यह ब्रावश्यक हैं कि उन्हें निस्य प्रति के कार्यों से प्रबन्ध कर्ता से पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त हो । जवकसी को कार्यारम्भ करने का साइस और उत्साह होना चाहिये। यही एक छाछार है जिस पर व्यक्तिगत उपक्रम से इम सफलता की आशा कर सकते हैं। प्रवस्थ करने में स्वतन्त्रता की मात्रा में कभी करने के भय, इन परिवरों की कार्यप्रवासी की अभित्रिचतता तथा किसी उपक्रम के आवश्यकता। प्रकृते पर सरकारी प्रकृत से ले लिये जाने की श्रानिश्चित शर्ते (बैसे निकास परिपद के निर्देशों का किसी उप-फम द्वारा उलंबन) ये उपक्रमी वर्ग के सन में सदेह की माबना भर दी है। इसके श्रवित्ति परिषद एक ही प्रकार की संस्थायें वो है नहीं को अपने अपने उसोगों में ने विकिशत हुई हो, इसलिये वे मनोवाछित विकास नहीं कर सकती। यह भी सम्भव है कि विकास परिषद का इस्ताचित सरकारी नियन्त्रकों से प्रस्त उपक्रमों के विनाश का अस्तिम कारण सिद्ध हो।

१६५३ का उद्योग (विकास और नियमन) संशोधन कानन--- भारत-सरकार को १६५१ के उद्योग ( विकास ख्रीर नियमन ) कानून को लागू करने के एक वर्ष परचात् ही संशोधन कानून का आधार लेना पढ़ा। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि भारत की त्रोधोगिक नीति कितनी अनिश्चित है। ऐसी स्थिति

किसी प्रकार भी लामकर नहीं कही जा सकती है। संशोधन कानून का विश्लेषण करने से जात होगा कि उसकी व्यवस्थाएँ पूर्व की अपेचा अधिक दोपपूर्ण हैं। संशोधन कानून के अनुसार किसो भी उस्तोग पर सरकार परामर्शदात्री परिपद् से पूछे मिना अधिकार कर सकती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सरकार निर्देश दे और उद्योग को सप्टीकरण का अवसर है। सरकार के इन नवीन अधिकारों को भास करने से व्यापारों में उस्तेभों के सम्बन्ध में और अवनिध्यता सेली है और इससे देश की अधिगिक प्रगति अधकह हो जायगी, इसमें सरकेट नहीं।

श्रव यह कानून ४२ उद्योगों पर लागू है, जिनमें असली रेशम, नकती रेशम, रंग बनाने की वर्लुने, खाद्धन, प्लाइंड्ड, फेरीमेगेर्नाज झादि ६ नवीग उद्योग भी उम्मिलित है। वंशोधन द्वारा चरकार को यह अधिकार मात है कि वे यदि बांह तो ५ वर्ष के पश्चाल भी (जो अवधि पश्च में दी हुई थी) किसी उपस्म का प्रमन्य अपने हाथों में रहन करती है। इन्दे कि तेये वर आवश्यक होंगे में रहन करती है। चरके लिये यह आवश्यक होंगे के कि निर्देश्य की अश्वि बद्दाने की एक विश्वति पालियामेंट के समस् उत्तरित कर दी जाय। बरकारी उपक्रमों को नई बरताओं के उत्तरित कर दी जाय। बरकारी उपक्रमों को नई बरताओं के उत्तरादन के लिये लाह्नेन्छ जेने से खूट दे दी गई है, यद्यपि एक्ट में दी हुई प्रथम दालिका में अनुस्वित उपक्रमों को लाह्सेन्छ लेना अभिवार में छै। वरकार को यह अधिकार है कि बहलिन उद्योगों को अपने अधिकार में छै उनके उंगठन की शतों और नियमायली के विपरीत भी यदि चाहे तो कार्य कर करती है। इस अधिकार ते हिस्सेदारों के बामान्य अधिकारों की अधात वहंचता है।

हन धरीभिनों से उद्योग (विकास और नियमन) कानून बहुत कहा बानून बन गया हैं। ग्रम केवल यह खाशा की जाती है कि कानून की लागू करने वाले श्रमिकारी सन्त्रालत दृष्टिकोशा ने कार्यवाही करेंचे और भारत के श्रीदोधिक उद्यों को उद्येग के किए नण्ट हो जाने से ब्याउंधे।

राष्ट्रीयकरण की नीति—सष्ट्रीयकरण की नीति अप्रस्यक्त रूप से भारत सरकार की छोटोनिक नीति का एक अंग है। इसका सकेत उद्योग (जिकास और नियमन) कानून की उस व्यवस्था से शिलता है जिसके अनुसार सरकार कुछ दिपतियों में निजी उद्योगों पर अपना अधिकार कर सकती है।

राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि उत्सादन के वाधनों पर जनता का अधिकार हो। राज्य या नो अपने उद्योग स्थापित कर सकता है या चालू निजी उद्योगों की अपने अधिकार में से सकता है। राष्ट्रीयकरण का देश की सामाजिक, राजनैतिक, क्रार्थिक स्थितियों से निकट सम्बन्घ है । राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया जाप यह

उस देश के ग्राधिक विकास पर निर्भर करता है। . स्वापन प्रमाण प्रतिस्था की नीति का कई ब्राघारों से समर्थन किया सिद्धान्त रूप में राष्ट्रीयकरण की नीति का कई ब्राघारों से समर्थन किया जा सकता है। प्रायः यह कहा जाता है कि जिजी उद्योग देश के सभी उपलब्ध साधनी कान तो पूर्ण उपयोग करना चाहता है और न वह ऐसा कर सकने में समर्थ ही है, इसलिए मिना राजकीय उद्योगों में तीनता से प्रगतिसील स्त्रीद्योगी-वनन सा चु रणार नगा रानमान वसाम न बानमा र नगामधास आर्थान करण नहीं किया जा छवता। निजी उद्योगी द्वारा उद्योग के आधुनिकीकरण स्त्रीर युक्तिकरण (Rationalisation) को स्रोर व्यान न देने की प्रकृति की आलोचना करके भी राष्ट्रीयकरम् का समर्थन किया जाता है। यह कहा जाता है आलोचना करके भी राष्ट्रीयकरम् का समर्थन किया आराजना गरेक ना पश्चमार का प्रवास है। कि राष्ट्रीयकरण हो जाने से अमिक-मालिक के सम्बन्धों में सुघार होगा श्रीर अमिकों क हुने उत्सह से कार्य करने के कारण उत्सहन मी बढ़ेगा। राष्ट्रीयकरख के समर्थकों का यह भी विश्वात है कि उद्योगों पर सरकार का ख्रिथिकार हो जाने से बेरोजगारी की समस्या भी इल हो जायगी।

परन्तु यह तर्क सन्तोपजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय करख की किसी भी योजना को लागू करने से पूर्व यह आवश्यक है कि राज्य के पाल पर्यात पूर्जी हो छीर उसे प्रशासन तथा सभी कुराल प्राविधिक केवाएँ प्राप्त हो। राष्ट्रीय करख के पश्चात् अभिक्ष श्रीर उद्योग के प्रवन्थकों के सम्बन्धों में श्रीर तमातनी होने की सभावना है क्योंकि वर्तमान में इन दोनों के बीच राज्य सेंबुलन स्थापित करता है ग्रीर जब कमी इनके बीच समझे उत्पन्न होते हैं राज्य उनमें इस्तचेप करता है। परन्तु यदि राज्य ही उद्योग का अधिकारी हो तो इत प्रकार के समाड़ों से राज्य स्वयं एक पश्च हो जायगा और इस कारण मध्यस्थता नहीं कर सकेगा । राष्ट्रीय-करण हो जाने से श्रीयोगिक सम्बन्धों में सुघार होने का सिझान्त इस बात पर श्चाचारित है कि जनतन्त्र में अभिक यह समकता है कि राज्य की वास्तियक शक्ति उसी के हाथ में है । इसलिए उसका राज्य से कोई कराइरा नहीं होगा। परन्तु यह फेनल सिबान्त की बात है। यह विश्वास कर लेने का कोई कारण नहीं है कि केवल राष्ट्रीयकरण हो जाने से ही अमिकों का स्वभाव बदल जायगा और यह ऋषिक कुरोतता से ऋषिक परिश्रम कर उत्पादन बहु। हैंमे । उत्पादन समी बढ़ सहता है और वेरोजमारी को तमी कम किया जा सकता है जब राज्य चालू उदागों की अपने अविकार में करने की अपेक्षा नये उद्योगों को आरम्भ करें।

राष्ट्रीयकरस् की ऋपनी उपयोगिता होनी चाहिए। उसकी श्रपनी विशेष-ताएँ होनी चाहिए। फेवल निजी उचीमों में दोप होने के कारण ही राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाना उचित नहीं है। राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध अनेक तर्क दिये जा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप यह कहा जाता है कि उसोगों पर राज्य का अधिकार हो जाने से प्रकच की कुरालता में अभाव आ जाता है न्योंकि राजकीय अधिकारी उतने यतर्क और उस्वाही नहीं होते हैं जितना निजी उद्योगपरियों से आसा की जाती है। राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगों में अवन्यकों को सरकार कर्मचारी होने के कारण उद्योग से निजी लाभ उठाने को संमानना ही नहीं होती, दण्लीए उन्हें न तो व्यवसाय बदाने की इन्छा होती है और न हुए और कोई आहर्षण होता है। जिन उत्तर्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा जुका है उनका विकास करने के लिए आवश्यक पूँची प्राप्त करने में अधिक कर लगाने की आवश्यकता पर सकती है और यह समय है कि आदिक हाए से अधिक विदेश की जनता 'करा के हथ आतिरिक्त मान का बहुत करने के सम्बद्ध से स्वीत है और सह स्वाप्त स्व

भारत में केम्द्रीय तथा राज्य सरकार कुछ उद्योगों की श्रीधकारियों है थीर उन्हें चलाती है जिनमें रेलवे, बाक-तार, प्रतिरह्मा धन्यन्थी कारलाने, टेली-फीन कम्पनियाँ श्रीर कुछ विजली की कम्पनिया सम्मिलत है । नत कुछ वर्षों से श्रीधोगिक क्षेत्र में पायच का मध्या महता गया है। भिक्रामिट्ट हाउरिंग फैक्टरी हरिंग किया । यह धमी राज-क्षां कारां हरिंग हर

उचीमां का राष्ट्रीयकरण कर लेने से शे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती । राष्ट्रीयकरण होने से कम उत्पादन कथ्य पर ऋषिक और अच्छा उस्तादन होना चाहिए। परन्तु मारन सरकार की राष्ट्रीकरण की नीति से यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुया है। इसके विपरीत इन उचीमों में बनता के चन की अप्यार होति हुई है और उत्पादन में अनुचित देरी हुई है। इस सम्बन्ध में बिन्दी खाद कारणाने का उदाहरण दिया ना ककता है। पछ्ले यह अनुमान लगाना यगर पा कि १०% इ करोड़ रुपने में कारखाना स्थापित हो बायवा। परन्तु अन्त में इस पर २३ करोड़ स्वया कथ्य क्रिया नामा और स्थापित होने के सात वर्ष पर्याद्ध इसमें उत्पादन कार्य आरम्म हो सका प्रीकेनीकेटेड हाउसिंग कैनररी द्वारा उत्पादित मान देश के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुआ इसलिए उत्पादन आरम्म होने के कुछ समप परचात हो विकय के लिए मकानों का निर्माण बन्द कर दिया गया।

संगठन उनमणी इन सुयारों के श्रांतिरकत यह श्रावरयक है कि उरकार इव बात का श्राश्चाचन दे कि उठके पाछ को कुछ गोमित पूँजी है उउने चालू मिजी उजोगों को अपने अपिकार में कर मुखाबबा देने की अपेका नमें कारखान खीते जामें । वास्तव में आयरपकता तो इस बात की है कि उरकार प्रधारपून जोगों तथा पेसे उद्योगों को चालू करें विनकों अनेक कारणों से निजी उद्योगपति श्रारम्भ नहीं कर सकते हैं। यदि सरकार यह नीति अपनायं तो इसते उद्योगपतियों में मिक्स के प्रति आयणा जगेगी और राजकीय तथा निजी उद्योगों में गोच स्वस्य स्थापत हो विनेश विगय विषय है। से स्थापति श्रापक तीति हो की अपनाति श्रापक तीति हो की स्थापति श्रापक विषय हो हो हो स्थापति श्रापक तीत्रता से हो का स्थापती श्रापक तीत्रता से हो का स्थापति श्रापक तीत्रता से हो स्थापति श्रापक तीत्रता से हो साथ हो हो हो स्थापति श्रापक तीत्रता से हो स्थापति श्रापक तीत्रता से हो स्थापति श्रापक तीत्रता स्थापति श्रापक तीत्रता स्थापति श्रापक तीत्रता से हो स्थापति श्रापक तीत्रता स्थापते स्थापति श्रापक तीत्रता स्थापति स्थापति श्रापक तीत्रता स्थापति श्रापक तीत्रता स्थापति स्थापति

#### अध्याय २३

# मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली

कोई भी व्यक्ति पर्भ या कम्पनी जिसे कम्पनी के साथ किए गए समझीते के अनुसार कम्पनी के सम्पूर्ण कार्यों को व्यवस्था करने का अधिकार भाष्त है मैनेजिस एजेन्ट कहलाता है। वह कम्पनी के संचालकों के नियम्ब्रण में तथा निर्देशों के समसार या नगसीते से ही गई सन्य ध्यवस्था के समसार आर्थ करते। हैं। दसरे शब्दों से यह यहां जा सकता है कि मैनेजिंग एजेस्ट से अभिप्राय उस व्यक्ति, फर्म या कवनी से है जिलके हाथ में लगभग सम्पर्श करपनी का प्रवस्थ हो जोर जिसको प्रथम करते का यह अधिकार यह नो कंपनी में किये गये समस्तीते के धानमार मिला हो या कंपनी के नियमों के खन्तर्रात निहित समस्तीने की शर्ती के बानसार मिला हो। साधारणतया प्रशासन के इच्छिकोया से प्रबन्धक या प्रेनेजर ही संसालकों के नियन्त्रण में और उनकी देख-रेख में कार्य कश्ता है परन्त क्षेत्रेजिया प्रजेतर की स्थिति इससे कहा सिल है। सैबेजिया प्रजेतर संचालको के प्रत्यस क्रथवा परीस नियंत्रण में नहीं रहता है। सचालक समसौते की शर्मों की सीमा के श्रान्दर ही मैनेजिंग एजेन्ट पर नियन्त्रण रख सकते हैं या उसे निर्देश है सकते हैं या यह सम्बन्ध तत्सम्बन्धी कानून के अनुसार निश्चित हो जाता है। इस प्रकार मैनेजिन एजेन्ट की मुख्य विशेषताएँ यह हैं कि (१) वह कम्पनी का एजेन्ट होता है ग्रीर कम्पनी के नियम्त्रण में कार्य करता है, (२) वह कम्पनी के प्रायः सभी कार्यों की व्यवस्था करनेयाला एजेन्ड होता है ग्रीर (१) कम्पनी ग्रीर उसके बीच में समसीता होने से ही एजेन्सी स्थापित हो जाती है। व्यवहारिक हांदर से देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि मैनेजिंग एजेस्ट ही कम्पनी का वारतिक स्वामी होता है। कम्पनी के संवालक मगडल का उस पर कुछ विशेष नियन्त्रण मही होता ।

जरात्ति और विकास — इसारे देश में दो प्रकार के मैनेशिंग एकेट हैं...

'मारवीय हौर योक्षीय । इन दोनों की उत्पत्ति में भेद है । मारत में उद्योगों की
स्थादना का श्रेथ श्रेमकों को है श्रीर उन्होंने होय पर प्रवासी लोका निकासी।
मैनेशिंग एकेटरी की प्रवासी की उत्पत्ति वास्तव में मारत में श्रीव्य उद्योगों की
स्थापना का परित्यास है। युरानी बिटिश मैनेशिंग एकटिश में अध्यक्ष प्रवासी से
श्री इस प्रवासी का क्रमश: विकास हुआ। वह बिटेन तथा मारत के मध्य व्यावास

करने का उत्तरदायित्व दैस्ट इषिड्या कम्पनी के हाथ से निजी ज्यापारियों श्रीर सीदागरों के हाथ में चला गया या तब पुरानी मैनेजिंग एजेन्सियों ने प्रथम बार यह श्रानुभव किया कि मारत का शार्थिक विकास करने के लिये बहुत क्यायक चित्र खुला पश्चा है। भारत में यूरोपीय मैनेजिंग म्याली की उत्पत्ति का कारण यह या कि यहाँ प्रमुख पूरोपीय ज्यापारी की संख्या बहुत कम थी श्रीर उत्पत्ति सेसे संवालक श्रापया प्रकल्प संचालकों को खुल सकना अस्पन्त कडिन था जो ज्या-पार की निरन्तर वेत्व-रेख करने के लिये श्रीषक समय तक मारत में रह सकें।

भारतीय मैनेजिए एजेन्स प्रणाली उत्पत्ति पूँगी के छंगडित बाजार के अभाव के कारख हुई। हमारे देश में लोग पूँगी लगाने से संकुचाते हैं, यहाँ घरपा लगाकर ज्यवधाय करने की मावना बहुत कम गाई बाती है। यहाँ उयोगों की श्यानम में वहायजा देने के लिये औयोगिक केंक नहीं हैं। व्यया लगानेवाली की श्यानम में वहायजा देने के लिये औयोगिक केंक नहीं हैं। व्यया लगानेवाली और अभ्य भार से मीनवादन देने वाली क्याने वहात कम हैं। इस अभाय को पूर्ति के लिये मैनेजिंग एजेन्ट व्यवसाय आरम्म करते हैं, उसमें व्यया लगाने वालों में विश्वाय उत्पन्न करते हैं। अशोगोगिकरण के आरम्भ काल में जब न कोई उद्योग चालू करने की प्रवृत्ति भी और न पूर्वी हो अशिक भावन में उपलब्ध को सा सकते थे उस व्यवसाय देनेजिंग एजेन्ट ने इस दोनों अपान में उपलब्ध को सा सकते थे। उस व्यवसाय देनेजिंग एजेन्टों ने इस दोनों अभागों की पूर्ति की। आव भारत में मुसंगठित और इह स्थिति वाले यहाँ कपाने, बूट तथा इस्पति स्थान परित्ती तथा पर्वी की की साम के साम कर की साम के साम के साम के साम के साम के साम कर कर की के साम के साम के साम के साम के साम कर की साम के साम के साम कर की साम के साम के साम के साम कर की साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम कर की साम के साम के साम कर की साम के साम क

मैनेजिंग एजेन्छी प्रणाली विस्तार का ठीक ठीक अनुसान नहीं लगाया जा सका है। एक लीत के अनुशार मारत में कमिली की संवत १२,५०० ते प्रशिक है, और उस प्रकार के उसोगों में विनियोग की कुल मात्रा प्रारम्भिक लगान के अधार एर १६०० वा १७०० करोक करवा अनुसान लगामा जाव तो तिस्तर्नेह कही आधिक होगी। मारत में कम्पनियों के उत्पादन में सहायक कुल परिसर्वाच का ट्रांक उत्त कम्पनियों को प्रतिस्थाति की अप्रीम्थ के प्रवस्य में है। यह में अप्रमान किया जाता है कि १० मी अप्रमान किया जाता है कि १० मित्रण में में निवार प्रीमित दागित्व लीति कम्पनियों है। एक अप्रमान किया जाता है कि १० मित्रण के अनुसार ११ मार्च १९५५ में १,६०० फम्पनियों की मैनेजिंग एजेट थीं।

इनमें से २५०० मेनेजिंग एजेन्सियाँ स्वत्वाधिकारी और सामेक्षरारी कमें भी और स्वामम १२०० व्यक्तिगत और २०० जनता की कम्यनियाँ थीं। मैनेजिंग एजेन्सी कमें प्रचानतः पिन्छुमी बंगाल, बम्बई, और मद्रास में केन्द्रित हैं। उपर्युक्त स्रोत के अनुसार पिन्छुमी बंगाल, बम्बई और मद्रास परेखों में कमदाः १५००, ६०० और ४५० मैनेजिंग एजेन्स्यमें काम कर रही हैं। अन्य प्रदेश, जिनमें १०० से अधिक मैनेजिंग एजेन्स्यमें हैं, वे उत्तर प्रदेश, देहली, मस्य प्रदेश और पनाव हैं।' उपर्युक्त सालों प्रदेशों में कुल मिलाकर देश की ८०% से अधिक मैनेजिंग एजेन्स्यमें कार्य कर रही हैं।

संगठन — फोर्ड भी व्यक्त, डाकेदारी फर्म या निजी लिमिटेड कम्पनी मैने जिंग एजेन्ट हो सकते हैं। इघर जुछ वयों से राकेदरी फर्म को निजी लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति हो रही है। इछ समय मारत की प्रमुख एजेन्टियाँ विकला अर्थ लिमिटेड, टाटा इन्डर्डीज लिमिटेड, राष्ट्र केन लिमिटेड, जयपुरिया अर्थ लिमिटेड, ह्यादि हैं। यह पभी निजी कम्पनीयां हैं। मिनिजा एजेन्डी फर्म बनाने के लिये वर्ज अपमा सीमित उत्तराधित वाली कम्पनी स्थापित कर ली जाती है। इस कम्पनी के सेवरों का प्राविकाय वाली कम्पनी स्थापित कर ली जाती है। इस कम्पनी के सेवरों का प्राविकाय को सीमित सेवर दिये जाते हैं। साधारवाद अर्थ व्यक्तियों के प्रयु , की जुल पूर्वी के २५ प्रतिशत सेवर दिये जाते हैं। टाटा सम्प एक कम्पनी, नयरोजी याडिया प्रयक्त एक, इत्यादि कम्पनीयों इसी प्रकार अर्थ एक कम्पनी, नयरोजी याडिया प्रयक्त एक, इत्यादि कम्पनियों इसी प्रकार आरम्भ की गई। परन्तु संगठन सारे देश में समन नहीं है।

साधारण रूप समाजा एवान्यया क कह प्रकार है जल सम्बह, आहमरा-साद और कलकणा की प्रजेनियाँ विभिन्न प्रकार की है। यह एजेन्टियाँ अपने विकासित रूप में, अपने संजठन की रूप रेखा में एक दूबरे से भिन्न हैं। अहमरा-बाद में मैनेजिंग एजेन्ट एक व्यक्ति होता है, वस्बर्द में सामेदार या निजी कम्मनी और कलकणा में अंग्रेजी प्रकार की लिमिटेड सार्वजानिक कम्मनी। समय की प्रगति के साथ इन एजेन्टियों का यह मेद समात होता जा रहा है और वर्तमान में सभी स्थानों में सभी प्रकार की एजेन्टियों दिखाई देती हैं।

मैनेजिंग एजेन्ट प्राय: धनवान न्यक्ति होते हैं और उनके बहुत अच्छे न्या-पारिक सम्बद्ध होते हैं। बड़े एजेन्ट जिनके आधीन अनेक कम्मनियाँ होती हैं अपना कार्य विभागों में विभक्त कर देते हैं। वब एरबुयनाट एल्ड कम्पनी का व्यवसाय सभाग किया गया उस समय उसके सात विभाग में, जैसे वैकिंग, जनरल एजेन्सी, द्यायात श्रीर निर्मात, खाल और चमझा, नील, क्यार और रमस्ती लकड़ी, जनरल शिषिंग और भू-सम्मत्ति और पश्चिमी तट एकेन्सी दिमाग। कुछ, मैनेजिंग एलेन्स्यो कैसे विश्वा एजेन्सी के अन्तर्गत एक से श्राधिक मैनेजिंग एजेन्सी कम्मनियाँ होती हैं जो भिन्न प्रकार के उच्चोगों का व्यवसाय देखती हैं। इसलिए प्रत्येक एन्डेसी अपने-अपने कार्य में विशेषक कही जा सकती है।

#### मैनेजिन एन्जेसी का कार्य

साधारण रूप से भारत के वैनेकिंग एकेन्ट कीन महत्वपूर्ण कार्य करते हैं—(१) यह नए उद्योगों के लिए एक प्रदर्शक का कार्य करते हैं। साथ ही उनकी स्थानन में विशेष योगदान देते हैं, (१) उद्योगों की स्थानी ख्रीर खालू क्षी कर में झार्यिक सहायना देते हैं, ख्रीर (१) उद्योगों की दिन प्रति दिन की स्यवस्था करते हैं।

पयप्रदर्शक और प्रयक्तिक के रूप में-इडलैयड और श्रमरीका में पेसी क्रमेन संस्थाएँ हैं जो नए ज़लोगों के स्थापना की वेरका देती हैं। प्रवर्तक के रूप में यह संस्थाएँ जरोगों के सम्बन्ध में खोज कार्य करती रहती हैं छौर भविष्य में विकास कर सकते वाले ज्योग की स्थापना में महत्यपर्ण सहयोग देती हैं। जब कोंई नवीन उद्योग या व्यवसाय चालु किया जाता है तो रूपया लगाने बाले की सदा यह चिन्ता लगी उहती है कि कहीं लहोग असफल न हो जाय और जसकी पेंजी इस न जाय । पाश्चारय देशों में देशी संस्थाएं हैं जो ठीक समय पर शेयरों की बिकी करती हैं धीर ऐसी संस्थायें हैं जो अविष्य में उपयक्त श्रायसर पर विक्रय करने के लिए इन शेयरों को क्रय कर लेती हैं। परन्तु भारत में ऐसी संस्थाएँ बहुत कम हैं और इनके अभाव की पृति सैनेजिंग एजेन्ट करते हैं। सारत से जिन व्यक्तियों ने सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना की उनके पास साधनो का स्थभाव नहीं या भूगीर किसी योजना को ज्यवशारिक रूप देने के पूर्व वे विशेषशी द्वारा उनकी सारी संमावनाओं की परीजा करा लेते थे। यह उन्हीं के साहस और उन्हास का फल है कि मारत में मूती कपड़े, लोहे और इस्पात, बूट, खिमेंट इस्पादि के उद्योग चल रहे हैं। विच आयोग (१६४६-५०) का मत है कि स्ती कपड़ा, जुर, लोहा श्रीर इस्पात तथा विभेट उद्योगो की स्थापना का श्रेय बैनेजिंग एजेन्सियों को दी है। इन्हीं एजेन्सियों के पथ प्रदर्शन से यह संमव हो सका। इघर कुछ वर्षों में इन एजेन्सियों ने इंजीनियरिंग, केमिकल श्रीर मोटर उद्योगों की स्थापना की है। हिन्दुस्तान मोटर्फ लिभिटेड, टैक्सटायल मशीनरी करफोरेशन लिभिटेड इत्यादि इस मकार के उद्योगी के उदाहरवा है।

यत कुछ वर्षों से भारतीय मैनेजिंग एकेन्ट उद्योग में रूपया कम लगा रहे हैं। इसका कारण यह नहीं है कि उनकी इस दिशा में पथमदर्शन की तथा नए उद्योगों की स्थापना में सहयोग देने की भावना शिषिल पढ़ गई है। इसका कारण सरकार की श्रीघोषिक नीति है। इस नीति से श्रनेक कटिनाइमाँ उत्पन्न हो गई है। सरकारी नियंत्रणों, अस सम्बन्धी कानूनों श्रीर समक्तीता बोडों तथा पंच न्यायालयों के न्याय से उत्पादन क्यय में तो बृद्धि होती जाती है परन्तु उत्पा-कित माल के सकुप में बिद्ध बादी की जाती।

वित्त व्यवस्था—मैनेजिंग एजेन्ट उत्योग के लिए केवल स्थायी पूंजी की ही स्ययस्था नहीं करते यरत् हरुके वाय ही पुनैसंगठन, आधुनिकीकरण और कारखाने का प्रमार करने के लिए टीअंकालीन पूंजी की और चालू पूंजी तथा अन्य आवस्यकरास्त्रों की पूर्वि के लिए डास्फालीन दित्त स्वयस्था भी करते हैं। मैनेजिंग एजेन्ट अनुसार के रूप में शेवर के रूप में श्रीर स्वयस्थ कर कर कर वागो में की मैनेजिंग एजेन्ट अपने समे-संविध्यो तथा मित्रों को कस्यनी के शेवर कर कर में, और स्वयस्थ कर कर वागो में की पूर्वि के स्वयस्थ कर कर कर में की प्रेरणा बेते हैं, और हसके लिए उन्हें मोरसाहित करते हैं। यह अनुसार के की प्रेरणा बेते हैं, और इस फार कनता का क्या मात्र करते हैं। यह अनुसार के की प्रारम्भ के निक्ता लिख व व्योग निर्माण किया है कि सैनेजिंग एजेन्टो ने इस सम्बन्ध में किया करता करता है। स्व मुक्त हो हो है कि सैनेजिंग एजेन्टो ने इस सम्बन्ध में किया हो किया है कि सी

	वस्बई की ६४	मिलें व	अहमदाबाद की ४६ मिलें	
	रूपया (लाखी मे)	कुल धन का मतिशत	रुपया	कुल धन
(१) मैनजिंग एजेन्टों द्वारा				
दिया गया ऋख	પ્રફેર	<b>२१</b>	<b>6</b> €&	5%
(२) बैको द्वारा दिया गया				•
श्चर्य	२२६	٤,	४२	8
(३) जनता का जमाधन	707	\$\$	४२६	3\$
(४) शेयरो की कुल पूँची	१,२१४	3¥	<b>∮</b> 80	₹₹ _
(५) अपूरापत का धन	33€	30	5	ŧ

इन आॅकड़ों से स्पष्ट है कि आधिक सहायक के रूप समेने(जग एजेन्ट्रोका कितना महत्वपूर्ण स्थान हैं। उद्योगों को अपनी आवश्यकता का लगमग एक चौथाई ग्रंश सीपे इनसे मिलता है। अदगदाबाद और शर्मों में जनता के जगा-

धन में जो क्रमण: ३० प्रतिशत और ११ प्रतिशत सहायता क्रिली जनका श्रेय भी मैरीजिस एम्बेटों की प्रसिद्ध को ही है। हमारे देश में बैंक तब तक आण नहीं देते है जब तक दो जमानती न बनें। मैनेजिय एजेन्ट ऐसे अनुसरी पर दसरी जमानत स्वयं लेते हैं। जहाँ तक युरोपियन मैनेबिंग एजेन्टों का मश्न है उनके कार्य में शिथिलता का अनुभव किया जा रहा है। वित्त श्रायश्यकता की पूर्ति करने श्रीर इसकी गारन्टी देने की ओर उनका उत्पाह घटता दिखाई दे रहा है। मैंनेजिंग एजेन्टो के आधिक सहायक के कर में चाहे कितनी ही शिधिलता हो स्वया लगाने बाला, दादा, बिहुला तथा अन्य प्रशिद्ध मैनेजिंग एजेन्टों के नाम से तरनत आक्रष्ट होता है। कम्पनी कानन समिति की विपोर्ट में कहा गया है कि मैनेकिंग एजेन्ट का जिलो जरोजों के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण साधन हैं । मेंद्री के समय जब किसी श्रम्य साधन से रुपया मिलना समय नहीं रहता है मैनेजिया एजेस्ट यथा समय पूँजी की ब्यवस्था कर देते हैं। कुछ भैनेजिंग एजिन्टों में आत्म सम्मान की इतनी अधिक मावना है कि उन्होंने अपने द्वारा आरम्म किए हए व्यवसाय की नध्ट होने से रहा करने के लिए अपनी समस्य सम्पत्ति तक तांव पर क्रमा ही। परना ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं और यह देखा गया है कि मैनेजिंग एजेन्टों ने अपनेश्राधीन उद्योगों की विशेष देख-भाल न कर प्राय: उन्हें उनके भाग्य पर ही छोड़ दिया। प्रधानय-मीनेजिंग एजेस्ट केवल उद्योग का सफल जारम्य ही नहीं चाहते

प्रतिक प्रवाद के। निवचच तो धूवा है, परन्तु शवद बहुत कस हूं।
प्रतिक प्रमुख मैनिजय एजेन्सी के शेन्द्रीय कार्यालय में उद्योगों के आधार
पर मिल मिल विसाग होते हैं, साथ ही प्रत्येक उद्योग के विसान विभागों के लिए
शेन्द्रीय कार्यालय में उपनिवास होते हैं। मैनिजन एजेन्ट अपने आधीन कस्पनियों
या कारकानों द्वारा उत्पादित माल को कय और विकय करते हैं। प्रायः यह अनेक
वस्तुओं का आधान करते हैं और निर्मात भी करते हैं। इस अकार यह बड़े पैमाने
पर मन्द्रिक्य करने का लाम उठाते हैं। यह लाभाग खदेव कम्पनियों को नहीं
दिया जाता है, एजेन्ट इसे स्वयं ले लेते हैं। इस पर भी कम्पनी को नहीं
का इस मैनिजा एजेन्टों के द्वारा क्यपिक्य कराने में बच्च हो होती है सुकरे

लिए उन्हें एक भिन्न संस्था स्थापित नहीं करनी पड़ती। इसके साथ हो जब मैनेजिंग एजेन्ट एक उद्योग के एक से अधिक कारखानों पर नियन्त्रण रखता है तब इनमें प्रतियोगिता का जोर कम पड़ जाता है और चृति नहीं हो पाता। एक स्ट्रीटी कम्पनी प्रथम श्रेषी के दिशेषताओं की सहायता खेने में अधमर्थ होती हैं परन्तु यह मैनेजिंग एजेन्ट अनेक कम्पनियों के प्रवन्य कर्षा होने के कारण प्रथम श्रेषा के अभियन्ताओं और प्रविधियों को नियुक्त करते हैं वो भिन्न कम्पनियों की देख भाल कर सकते हैं। इस में जो कुछ क्यय होता है वह इन कम्पनियों में विभाजित कर दिया जाता है।

प्रसाली की त्रटियाँ

अस्ति का नुद्वाटया भैने जिंग एजन्टों ने अने क अस्त्यपूर्ण कार्य किये हैं, परन्तु इघर कुछ वर्षों से इस प्रयाणी में कुछ दोन प्रकट होने लगे हैं। राष्ट्रीय योजना आयोग की श्रीधानिक वित्त व्यवस्था स्थान्यों उपस्मिति की राय है कि यह प्रयाणी विष्कुल व्ययं हो जुकी है। परन्तु यह दोशारोपना अन्यायपूर्ण और असंद्वालत है। मारत के श्रीधानिक और आर्थिक विकास में दोयों के होते हुए भी भैनेजिन एजेन्सियों का बहुत बक्का हाथ रहा। जो कुछ भी हो, अब तक इसका स्थानापम म मिल जाय हम इस प्रयाली के बिना कार्य चला नहीं सकते। कायनी को लाम होने पर लाम का कुछ प्रविशत भैनेबिंग एजेन्ट को वेतन

कंपनी की लाम होने पर लाम का कुछ प्रविद्यात मेनीवंग एजेन्द्र की बेतन के रूप में दिया जाता है। परम्य लाम न होने पर कार्यालय का कार्य चलाने के लिये कुछ प्रमा दिया जाता है। हरके साथ ही एजेन्द्र कमीपान के रूप में भी कम्पनी से छुछ छीर पन बस्तुलता है। हरके सार हीय कि कम्पनी का वर्ष में भी कम्पनी से छुछ छीर पन बस्तुलता है। हरके सार हीय कि कम्पनी को वर्ष मर में जो वासतीयक लाम होगा उसका निश्चित प्रतिवद्य एजेन्द्र को बेतन के रूप में दिया जायगा और उपित लाम न होने पर कुछ म कुछ पन हिया जायगा। हर हर्ष से पूर्व मेनेजिंग एजेन्द्र माल ही बिकी के आभार पर ख्रयना बेतन लेते थे। यह दंग कम्पनियों के प्रति न्यायसंगत नरी था। १९३६ के कान्द्रन से स्थिति में काफी सुपार हुया है परन्तु क्योकि बारा ८० (मी) उन कम्पनियों पर लागू नहीं होती है जो १५ जनवरी रहरेश से पूर्व ही रिक्टर से चुकी थी, इसलिये कुछ मैनेजिंग एजेन्ट छपना वेतन छन भी उची पुराने आधार पर ते रहे हैं। कुछ मैनेजिंग एजेन्ट छपना वेतन छन भी उची पुराने आधार पर ते रहे हैं। कुछ मेनेजिंग एजेन्ट छपना वेतन के क्या क्या से सेने के अधार पर वेतन पाते हैं। मैनेजिंग एजेन्ट के वेतन के रूप में एक से खपिब आधार पर पन वित्तन के हैं। को रोकने के लिये कम्पनी कान्द्रा सिमीस (१९४२) में सुक्ताव दिया कि भैनेजिंग एजेन्ट को कप्पनी के वार्षिक लाभ का १२६ प्रतिशत से अधिक श्रंश न दिया जाय !

वालिका नं॰ २ लाम तथा मैनेजिंग एजन्टो का वेतन (करोड़ रूपयो में)

वाम वया मनाजन रजन्द्रा का नवन (कराइ स्वया न)			
	\$5.78	SERS	
मैनेजिंग एजन्टो का वेतन	95.0	\$0.28	
奪て	₹७,≂≂	34,75	
वितरित लाभ	<b>24.45</b>	₹0.8₹	
रोका हुआ लाम	₹0.05	\$3.0\$	
योग	₹₹,४⊂	83.F0	

१६५५ के करारोप जाँच आवाग को यह जात हुआ था कि मैनेजिंग एजेन्टों को १६५६ और १६५१ में रोवर होल्डरों के लाभ का आधा मास हुआ था. जैसा कि उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट है।

मैनेजिय प्रजन्टों की श्रीवत श्राप काम के प्रतियत श्राप्तात में १६४६ में १२% यो श्रीर १६५१ में बदकर १४% हो गई। यविष १९५१ में श्रीवत १३'% (श्रयात १४% के लामना) था, पर विभिन्न उत्योगों के सम्बन्ध में प्रतियत की माश मी विभिन्न थी। वहानाती, बट्ट के बने माल, बिजली, कीयला, सुती कपड़े, बीनी, चीनेंट, सोहा श्रीर इत्यात श्रादि उद्योगों में श्राप का प्रतियत कमय: २१४, २०'ई, १८८१, १६'७ १६'४, १५८८, ०'३ तथा ७'३ था।

पर्यात लाभ न होने पर मैनेलिंग प्रेचरों को कम से कम कुछ घन दिया जाता है। प्राय: समझीते के समय यह धनराशि निश्चित कर दी जाती है। कम्पनी कान्स समिति ने सुकाव दिया है कि कभी-कभी यह धन ग्रस्यधिक हो जाता है इसलिये ५० हजार क्यें संग्राधिक नहीं होना चाहिये।

लाभाँश के कुछ निश्चित प्रतिस्वत के रूप में श्रीर कुछ परिस्थितियों में दिये जाने वाले न्यूनतम पन के श्राविरिक्त मैनेनिंग एजेन्टों को कार्यालय का भला भी भिलता है। कार्यालय के भन्ने में कार्यालय का विस्तार और उसका किराया, टैक्स निश्चला, पंचे, क्राकों का दूभचर, पन इत्यादि मेरियत करने का व्यय, जॉन तथा वर्ययेते को व्यवस्था करने वाला विभाग, सीनियर एकडान्टेन्ट और सेक्सिंट्र के कभ्नेवारियों की सहायता, डाक-व्यय, कामक, भित्तवर, और चपराची इत्यादि पर किया काने वाला सभी व्यव सीमोलित है। श्रावीद मैनेनिंग एजेन्ट

कम्पनी भी श्रोर से कार्यालय में जो कुछ ज्यय करता है कार्यालय के मन्ते के रूप म उसको वस्तुल कर लेता है। परन्तु सामारणतया मैनेजिंग एजेन्ट व्यथ से कहीं श्रीषक धन वस्तुत हैं श्लीर उसको अपनी श्रतिरिक्त श्राय के रूप में उपमोग करते हैं। कम्पनी कानून समित (१९६५२) ने सुकान दिया है कि मैनेजिंग एजेन्टों को कार्यालय का भत्ता न दिया जाय बरत् इसके स्थान पर जो कुछ बास्तव में ब्यय किया गया हो उत्तनी धनशिय ही जाय। इस सुकाव की इस श्राधार पर आलोधना की गई है कि इस व्यवस्था से कार्य-मार बह जायगा और हिसाक कितान रलने में किताई होगी परन्तु यह किताई एक दोव को समास करने के लिए सहन की जा सकती है।

मैनेजिस एजेन्सी प्रजाली में छीर भी होय हैं । मैनेजिस एजेस्ट रीर बाहरती कार्यों के लिए भ्रमण लेते हैं, ज्यापार के उद्देश्य से नहीं वरन मित्रों की देने के लिए प्राण लिया जाता है, जन्य कारखानों से लगा कर रुपया फॅस खाता है और बिल-रियति शिथिल हो जाती है। जिन कारखानों या कम्पनियों की वित्त स्थिति हद है उनकी सम्पत्ति को रेहन रख दिया जाता है, कम्पनी को रुपयों की ध्यावश्यकता न रहते हुए भी भैनेजिय एजेस्ट की आयश्यकता पूर्ति के लिये या उनकी कोई योजना कार्याम्बत करने के लिए आखपत्र प्रचलित किये जाते हैं। इन दोषों को दर करने के लिये कम्पनी कानन-समिति ने अन्त सकाय दिये हैं :--(१) मैनेजिंग एजेन्टों हारा लिखे गये ऋण की न तो कम्पनी गारन्टी दे छोर न स्वयं उन्हें ऋण दे, (२) एजेन्ट के पात कम्पनी का चालू लाता २० इजार से अधिक का नहीं होना चाहिये और (३) कम्पनी के रुपये को अन्यत्र किसी कारलाने इत्यादि में लगाने पर प्रतिबन्धे लगाना चाहिये। वरन्त इनमें से इ.स मतिबन्ध ऐसे हैं जिनके लाग हो जाने से मैनेजिंग एजेन्ट को कार्ट करने की रवर्षत्रता कम हो जायनी श्रीर कोई नया कार्य करने या किसी कठिनाई को हल करने के लिए मैनेजिंग एजेन्ट पूर्व की सी तीव गति से कार्य नहीं कर पायेगा। उसमें कुछ उदासीनता श्वाने लगेगी।

बग्ध के शेयर होल्डर एवोधिनेशन ने इस श्रोर संकेत किया है कि अनेक बार मैनेकिंग एकेन्द्री के अधिकारों को विना सरीदार को विच दिस्ति श्रीर असिंद्र का पता लगाये श्रीर शेयर होल्डसे तथा अन्य कर्मचारियों के दितों पर विना दिचार किने दूसरों को चेन दिया गया। विमाद क्यों में कम्पनी के स्वाधियों श्रीर मैनेकिंग एकेन्सी के नियन्त्रण में निकट सम्पर्क रहने के कारण खरेन उद्देश्य की एकता बनी रही श्रीर एक दूसरें के हितों का हनन प्राय: न हो सका परन्तु श्रध मैनेकिंग एकेन्ट श्रीर उनके अभीन कम्पनी के प्रथक व्यक्तियों का निकट सम्बन्ध आपः धमात हो जुका है। ऐसे भी अवसर आए हैं जब मैनेजिंग एकेमी के अधिक संकट में पढ़ गए। इससे स्थित इतनी विवाही कि १८५१ में सरकार को मारतीय कभागे कान्त की बारा ५० (बी) में संबोधन करने के खिये एक अध्या- हैता की घोषणा करनी पढ़ी । सरकार ने इस अध्यानेश के आरा पह ज्यास्या, की कि मैनेजिंग एकेट यही अपने अधिकार किसी को सीवार है तो गढ़ कार्यस्या कि तब सक बैच नहीं मानी आपगा जब तक कम्पनी इस परिवर्षन के जापनी वासा

इतिस्थान बहरवतीचा एकतः १६९६—१६५६ का भारतीय कम्पनी एक्ट मैनेजिंग एजेन्ट्रों वर करे चानिवन्छ जाना करता है। यह एवट १६३६ के एकर की श्रावेला श्राविक विशाद लगा एवा है। एक्ट में यह दिया हुआ है कि केन्द्रीय सरकार साकारी राजेट में अधिसन्दान जारा विशेष ध्यवसायी तथा उत्तीरों में मंत्रता सह सहयतियों के अध्यक्ष में यह होस्त्रत कर सकती है कि किसी विजित्तत सिधि के तीन वर्ष पश्चाल से शबका १५ खमस्त १६६० से जो भी बाद में पड़े. में मैनेतिंग एजेन्टों के प्रकृष में नहीं रहेंगे। दसरे ग्रंश में यह व्यक्त किया गया है कि इस एसट के लाग होते के प्रशास कोई भी सैनेनिय एपोसी कम्पनी किसी मान्य मैनेजिम एजेन्ट के प्रजन्म में स रहेती। मान्य कम्पतियों के सम्बन्ध में मैनेजिम एजेन्टों की नियक्ति ज्याका प्रतिकृति सर्वेष्ट्रमा कम्पनी वारा सर्वेशायास की सभा में और नत्यश्वान बेश्विय सरकार द्वारा स्वीकत होना खायण्यक है। ऐसे ग्रवसरों पर सरकार अपनी स्वीकति तभी देने को तैयार होगी जब कि उसे यह विश्वास हो जायगा कि (१) ग्रेनेकिश एकेन्ट की नियस्ति से जनमा से हित की हाति की सम्भावना नहीं है और (२) जिस सैनेबिस एसेस्ट की नियक्ति प्रथवा पुनर्नियुक्ति की जानेवालो है, वह बर्बधा उपमुक्त है तथा भैनेजिय एकेन्सी संविदा की रातें न्यायमुक्त तथा सर्कर्तगत है। इन दो ग्रंशो से सरकार को बहुत स्त्र धक ग्राधिकार माप्त है। इसके अतिरिक्त भैनेशिंग एजेन्टों के कार्य परने की श्रविद. वेतन, श्राधिकार इत्यादि पर अनेको प्रतिकन्य समाये गये हैं। एवट में निगन बातें दां हुई है :---

(१) कोई भी नतीन मैनेबिंग एकेन्सी का खेलिरा १५ वर्ष से खालिक के लिये नहीं किया जा सकता और किसी भैनेबिंग एकेन्ट की पुनर्तियुक्ति २० वर्ष से अधिक के लिये नहीं जी जा सकती:

(२) अमस्त १६६० के परचात कोई मी व्यक्ति एक समय में दस कम्मियों में अभिक का कर्मचारी नहीं वन सकता । जो मैनेदिन एकेट वर्षमान समय में है उनकी कार्यनिधि का १५ अगस्त १६६० मो अन्त हो वाषमा, यदि उनकी पुनर्नियुक्ति इस तिथि के पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार नहीं कर दी जाती;

(३) यदि कोई एजेन्ट दिवालिया है अथवा उसे कम से कम ६ माह का कारावास का दश्व मिला है तो उसे स्वतः अपना पद त्याग देना होगा। यदि कोई एजेन्ट पोखा देता है अथवा विश्वास्थात करता है या क्ष्तंब्य से गिर जाता है और कुमबन्ध करता है तो उस कथ्यनी अथवे तत्यंबन्धी प्रस्ताब हारा पद से हरा करती है।

(४) मैनेजिंग एखेस्ट द्वारा कार्यालय के स्थानान्यरित करने के संक्ष्य में कंपनी छोर सरकार दोनों की स्थीकृति परमायर्थक है। बिना उसके यह सम्भव नहीं हो सकता।

अहाँ तक एलेम्टों के वेतन का प्रश्न है एक्ट में यह बताया गया है कि किसी भी मैनेजिंग एलेम्ट को सामान्यतः कायनी के वास्तविक साम के १०% से अधिक वेतन के रूप में नहीं दिया बादगा पर आतिरिक्त आप के लिये कम्मती को एक विशिष्ठ मस्ताव बारा अनुमति प्रदान करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आधार परस्थित मान्यकरण कोगा।

यह एएट मैनेजिंग एजेन्ट्रों के अधिकारों पर भी प्रतिबन्ध लगाता है।
मैनेजिंग एजेन्ट अपने अधिकारों का प्रयोग क्यानी के निर्देशकों की निर्मित के
निर्माच्य, जिमक्य और निर्देशन में हैं। कर उक्ता है जो कि कमानी के नियमों
है जैसे (१) मैनेजिंग एजेन्ट्री को अध्या में अभी में भी प्रतिबन्ध लगाये गये
हैं जैसे (१) मैनेजिंग एजेन्ट्री को प्रकास में क्यानियों द्वारा ऐजेन्ट्री को म्ह्यूप
देना; (२) एक ही मैनेजिंग एजेन्ट्री के प्रकास में एक से अधिक कम्पनियों का
आपक्ष में एक वृद्धरे को श्रम्य वेना; (१) एक कम्पनी द्वारा उसी वर्म कम्पनी के सेवरी को अप करना; (४) मैनेजिंग एजेन्ट्री को म्हयूप
कम्पनी कम्पनियों के व्यवनाय से स्था करने वाले व्यवसायों के कार्य करना ।
इन नियमों की उपेक्षा करने पर कठोर दश्वर की भी व्यवस्था की गई है। अन्त
में निर्देशकों की निर्मुक्त सम्मन्यों मैनेजिंग एजेन्ट्रों के अधिकारों में भी अनेक प्रतिबन्ध लगा दिने मचे हैं। अब एजेन्ट्र ऐसी व्यवसायों के कार्य कर्म पाँच क्रया निर्देशकों होते हैं दो से अधिक नहीं और जिनमें केवल पाँच तक निर्देशक होते हैं दो से अधिक नहीं और जिनमें केवल पाँच तक निर्देशक की निर्मुक्त कर सकता है।

#### मैनेजिय एजैन्सी का भविष्य

श्रतीत में इस प्रणालों में श्रनेक दोष रहे हैं श्रीर अध्याचार के लिए पर्याप्त चेत्र रहा है। राष्ट्रीय योजना श्रायोग ने सुकाव दिया है कि सर्वप्रथम इस प्रणाली का उम्मलन कर देना चाहिए जिससे श्रीयोगिक वित्त व्ययस्था के नाम पर इस प्रणाली के समर्थक अपने कार्मगत तर्क प्रस्तत न कर सकें। परन्त, बम्बई के मिल मालिक संघ दे इस खोर सड़ी सकेत किया है कि मैनेजिंग एजेन्सी प्रशाली की अगवज्यकता रमिलये कानमव की जाती है कि देश में बैंकों की वर्तमास स्थिति की देखने हए व्यवसाय चाल करने के लिए शैयरों की पंजी मिल सकता कठिन है थ्यार किसी प्रचोश को सलाने के लिए शावस्थक विस की पति नहीं की जा सकती है। इसकी पति के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को सहायता की खाब-प्रयक्ता होती है जो मैनेजिंग एजेन्ट से अपलब्द की जा सकती है। कापनी कानन समिति का यह सकाव अंचत है कि देश की वर्तमान आर्थिक रियति में मैनेजिंग एजेन्सी प्रकाली पर निर्भर करने से लाभ ही होगा। वास्तव में सम्पर्क प्रकाली ही को भग करने की गाँग करने की अपेसा इस बात की आयश्यकता है कि उपयक्त कानन बनाकर प्रकालों के दोवों को दर किया जा आया अध्यनी एउट के मैनेजिंग प्रणाली पर सम्पर्क प्रभाव की सभी से कल्पना कर खेना कठिन है। इसमें सदेह नहीं कि इससे जल महान दोष प्रणालों में अवस्य मिट जायेंगे पर इस्से मैनेजिंग एजेन्टा द्वारा नवीन कम्यनियों के आरम्म में भी संकचन आयेगा क्योंकि (१) मैनेजिंग एजेन्सी संविदा की अवधि घटा दी गई है: (२) मैनेजिंग यजेन्टों के वेतन में क्यों कर दी गई है, और (३) विस्तृत प्रतिबन्धों की लगाने से एक निरोधी मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न कर दिया गया है। परन्त हार एनर दांच के मतानुचार मविष्य अधकारमय नहीं है। उनका कहना है कि कोपारयस श्रीर मन्त्रा के सम्बन्ध में जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे बर्तमान मैनेजिंग यजेन्तियां को इस बात का अवसर प्रदान करते हैं कि वे अपने को अधिक उपयोगी कार्य सचालक के रूप में परिश्वित कर सकते हैं। यह ठीक है कि कोपाध्यञ्च श्रीर मन्त्री की बास्तविक लाभ का केवल ७३% ही श्राय के रूप से मास हो संग्रा: उन्हें करवनी द्वारा निर्मित माल के विक्रय करने का अधिकत न होगा: और न उन्हें मशीनों, स्टोर का सामान, और कवा माल, आदि अथ करने अथवा उनका व्यापार करने का अधिकार ही होगा। परन्तु ये सब प्रति-्बन्य वर्तमान संबिधाओं में साधारण कमी मात्र ही है और इसका कोई खीठो-गिक उपक्रमी पर श्राहितकर प्रभाव न पड़ेगा । सारत के उपक्रमिकों ने भतकाल से ऐसी सहनशीलता दिखलाई है कि उनके भिन्न और उनके कठोरतम समा-लीचका को भी आश्चर्य हुआ है। इसके कोई कारण नहीं कि वे इस नवीन बाधा का जो उनके सम्मल लड़ी कर दो गई है सफलतापूर्वक सामना न कर सकें। सम्बन्ध में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि कार्षेरियान राज्य का हो या हिस्सेदारों का हो। राज्य कार्योरेशन के लाम अधिक सुदृहता और किछी भकार के भेरभाव का अभाव है परन्तु चूंकि इस प्रकार का कार्योरेशन स्थापित करने के लिए भारत का अभाव है परन्तु चूंकि इस प्रकार का कार्योरेशन स्थापित करने के लिए भारत कार्याकार के वास प्रावृत्त्व का प्रकार मात्रा कि कार्योरेशन सिक्तारों की संस्था की। राज्योंय कार्योरेशन तब उपपुक्त होता जब बैंकी और उद्योगों हस्वादि का भी राष्ट्रीयकरण हो जाता। परन्तु यह सन निजी उद्योगांशियों के हृष्य में दे इसलिए हिस्सेदारों का कार्योरेशन ही अधिक उपपुक्त है। कार्योरेशन की सुद्ध इस कार्योक लिए वह निज्या का कार्योर हम हो सुद्ध इस निजी उद्योग स्थारियान की सुद्ध में कि सुद्ध में सुद्ध में कि सुद्ध में कि सुद्ध में कि सुद्ध में सुद्ध

कार्यिरेशन के शेयरों की वृंबी १० करोड़ करने हैं जो ५,००० वरने के शियों में विभक्त है। आरम्भ में ५ करोड़ रुपये के पूर्व अगतान किये जाने वाले शेयर प्रवालत किये गये जो सब कव कर लिए गये। इनमें से भारत सरकार और तिर्मा बैक को एक करोड़ रुपये के शेयर दिए गए हैं, अनुस्वालत बैकी को १६ करोड़ रुपये और वीता कर्मणी तथा वित्तायोग्त इंटो को १६ करोड़ रुपरे के श्रेयर दिये गये। भारत सरकार ने पृंधी को खुकाने की गारस्थी दो है और हिस्सेदारों को न्यूनतम वार्षिक खामांश (जिब पर कर नहीं कृतिया); मी दिया जायगा अगड़ अग्रका हर वर्तमान में २३ प्रतियत है।

कर्मना) मा दिया जायमा जिसका दर वर्तमान में २६ प्रतिशत है।

कार्पोरेशन का उपालन १२ उपालकों का मयडल करता है जिसमें तीन उपालकों को केन्द्रीय उरकार नियुक्त करती है, दो यंसालकों को रिज़र्व बँक नियुक्त करता है, ह पंचालकों को अन्य हिस्सेदार निर्वाधित करते हैं जिनमें से दो का निर्वाचन अद्वर्धाचन वैंक करते हैं, दो यचालकों को घरकारी वैंक और दो को बीमा कम्मनी जुनती हैं और प्रबन्ध पंचालक केन्द्रीय बैंक नियुक्त करता है।

कार्य-कार्पोरेशन को निम्नशिखित कार्य करने का अधिकार दिया गया है :---

(१) यदि कोई श्रीवोगिक चैस्पा ऐसी शर्तों पर बिन पर दोनों पद्म वहमत हो जनता से श्राप्त सम्रहीत करें श्रीर यह श्राप्त २५ वर्ष के श्रन्दर हो वापस किया जाने वाला हो तो कार्पोरेशन उसकी गारन्टी दे सकता है।

(२) श्रीशोगिक संस्थाओं द्वारा प्रचलित किये गए स्टाक, रोपर, बीयड श्रीर स्थापनारों को कार्परिशन स्वयं कव कर उनके तिकव को स्वतस्या कर कता है परन्तु बहु आवश्यक है कि इस प्रकार के स्टाक, श्रेयर इत्यादि यात बस्ते के श्रन्टर निक लायें। (३) कार्पोरेशन ऋष दे सकता है और किसी उद्योग के ऋष्एक कर कर सकता है परस्त क्राण नापस करने की अविधि २५ वर्ष से अविध न हो।

कार्षिरियन किसी कम्पनी के स्टाक अथना शेयर नहीं क्रम कर सकता। इस प्रतिबन्ध का उद्देश्य कार्षिरेशन की अनुनित क्रम से रज्ञा करना है। कुछ अन्य देशों में इस प्रकार के कार्षिरशन यह कार्य करते हैं परन्तु भारत सरकार ने प्राचीन शित के अनुसार कार्य करना पसन्द किया है, इसलिए यह कार्यिरशन प्रेस कार्य नहीं कर सकता है जो प्राचीन शित के प्रतिकृत्व हो। जनता का घन संप्रह करने के सम्बन्ध में कुछ शर्ते लगा ही गई हैं और अंतिम सीमा १० करोड़ करवा कर ही गई है।

कार्योरेशन ऐसे सार्वजनिक लिमिटेड कम्यानियों को और सहकारी समितियों को मस्यकालिक और दीर्घकालिक श्रुख देवा है जो उत्पादन कार्य करती है, लदान कार्य करती हैं और विजली उत्पन्न कर उपका वितरण करती हैं। १९५२ में एक संशोधन के अनुवार कार्योरेशन से वित्तीय सहायता पा सकता बाले अन्य उद्योगों में जलवानों को भी साम्मलित कर दिया है। परन्तु सामेदारी और निजी लिमिटेड कम्यनियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। कान्त्र के अनुसार कार्योरेशन किसी एक कारलाने को अपनी परिदल पूँजी का १० प्रतिशत पा ५० लाल कप्यों (जो भी कम हो) की चहायता दे सकता है। १९५२ में एक संशोधन के अनुसार अब एक करोड़ की सहस्वता दे सकता है। १९५२ के प्रतिशत पा ५० लाल कप्यों (जो भी कम हो) की चहायता दे सकता है। १९५२ में एक संशोधन के अनुसार अब एक करोड़ की सहस्वता है। स्वाधन करने का कारल पर था कि कुछ उत्योगों के लिए ५० लाल को सहस्वता अपर्यांत थी। साथ ही देती रिपत्ति में जब कि विश्व कैंक से अनुस्य लिया गया हो तो कार्योरेशन को एक करोड़ कपने से अधिक की सहायता देनी पड़ सकती है।

कार्योर सम् अपने विशेषत कर्मचारियों की सहायता से आवेदन पत्रों की क्षांच करता है और ऋषा स्वीकृत करते समय निर्माणकित बातो पर ध्यान देता है:—(१) उद्योग कर राष्ट्रीय महत्त्व, (२) उपयहचापकों की योगयता, (१) योजना को व्यवहारिकता और कुल व्यय, (४) उत्यादन का प्रकार, (५) जमानत, (१) कच्चे माल और टेकनिकल कर्मचारियों की व्यवस्था, और (७) उत्यादन की देश को आवर्षर करता ।

साधन-कार्पोरेशन बाजार से बीखड और ऋष्पत्र द्वारा रुपया एकत्रित कर सकता है जिसकी मात्रा कार्पोरेशन द्वारा दीं गई गारन्टी और बीमा के अन्तर्गत देय को सम्मिलत करके उसकी परिदत्त पूँजी और सुरक्तित कोष के दस गुने से अधिक नही होनो चाहिये। इस प्रकार जब कार्पोरेशन की उस्त सेवार की पूँजी १० करोड़ ६० हो जायभी श्रीर सुरक्षित कीय में भी १० करोड़ रुपया संग्रह हो जायमा तो श्रापने पूर्य विकसित रूप में कार्पोरेशन बाजार से २०० करोड़ रुपया एकवित कर सकता है ।

१६५२ के संशोधन के खनुसार कार्योरेशन १८ मास के लिये रिजर्व वैक से ३ करोड़ क्यम ऋण ले सकता है। इसके साथ ही कार्योरेशन पुनर्निर्माण और विकास के लिये अन्तर्रोष्ट्रीय वैंक से क्यम ऋण से ले सकता है। इतना होते हुये भी कार्योगमा के साधक सीमित ही हैं।

कींचोगिक विक्त कार्पोरेशन (संशोधन ) अधिनियम १६४७ :— उद्योगीकरण की गति बहु जाने से कार्पोरेशन उत्तरहायित और अधिक हो गया है। अत्तर्य १६५७ में आधिनियम को संशोधित कर निम्म वार्तो की व्यवस्था की गहे।

- (२) कार्पीरेशन परित्त पॅजी तथा सुरक्षित कीय के पाँच गुने के चलाय दछ गति तक प्रत्या के सकता है।
- ्यन तक ऋष सं चकता है। (ii) कार्पोरेशन श्रव केवल जनता से ही नहीं बरन् राज्य सरकारों तथा स्थानीय ऋधिकारियों से भी निचैप (denosits) स्वीकार कर सकती है।
  - (iii) यदि श्रायात करने वाले निर्माताश्रों के साथ विलिध्त शुगतान की व्यवस्था कर सकें तो कार्यिन्शन इन विलिध्त सुगतानों की गारन्टी
    - दे सकता है।
- (10) कार्पोरेशन से अब और अधिक प्रकार के श्रीशोषिक संस्थान सहामता प्राप्त कर सकेंगे। इस देख सशोधन की वारा २ (धी) में 'वरसुआं के विश्वासन' की रेसी व्यास्था की गई है कि श्रीर प्राप्तक प्रशिणीयिक संस्थान कार्पोरेशन ने म्हण्य की शहायता प्राप्त कर सकें। राज्यीय विश्व स्वर्णोरेशन श्रिप्त अविश्वासन १९९१ में को संशोधन १९९५ में किया गया था समित अपाय पर उपर्युक्त महारा में भी संशोधन किया गया थी श्राप्त स्वर्ण के प्राप्तार पर उपर्युक्त महारा में भी संशोधन किया गया है। साथ ही बारा २३ की उपधारा (२) में इस प्रकार संशोधन किया गया है कि वे श्रीजीविक संस्थान मी श्रीय की शहायता पा सकें जो राष्ट्र के दिश्लोख से प्रोप्तारित करने गोया है। शर्य यह है कि इनको दो जाने वाली सहायता के गृत्वधन और व्याज श्रदायगी की मारन्टी फेन्द्रीय सरकार, रास्य सरकार, एक श्रनुश्चित व त्रैंक श्रयवा राज्यीय सहकारी वैंक दे ।
- श्रालोचना-कार्पोरेशन की श्रालोचना मे श्रानेक वार्ते कही गई हैं। (१) कार्पोरेशन का कार्प रुद्धिनाडी टंग से चलाया गयर, इससे विशेष सहायता

न सिल सकी। कापीरेशन के अधिकारियों ने बताया है कि इन आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने का कारण यह था कि इनमें उचित योजना नहीं दी गई यो। योजना निर्माण से पूर्व टेकनीशियनों, इंखीनियरों तथा अन्य अनुमधी व्यक्तियों ते परासरी नहीं किया गया था। मशीनी तथा कच्चे माल को प्राप्त करने माल को प्राप्त करने साल को प्राप्त करने साल को प्राप्त करने साल को प्राप्त करने साल को विश्वत रूप से कुछ नहीं कहा गया था और यही अनिश्वत रियति उत्पादित माल के विक्रय के सम्बन्ध में थी। परन्तु कार्पोरेशन दन वालों को अपनी कार्रवाह न्याय संगत विक्र करने के लिये तक के उपयोग में नहीं ला सफता है। क्योंक यदि आवंदन पत्र ठीक प्रकार से नहीं दिये गये ये तो यह कार्पोरेशन का कर्तव्य था कि वह आवेदन पत्र ठीक प्रकार से मस्तुत कराता। वास्तविक कठिनाई यह है कि कार्पोरेशन को इस सम्बन्ध में कुछ, चिनता नहीं है और वह अपनी प्राचीन रीति से कार्य करता रहा। यह बाल उपलेखनीथ है के कार्पोरेशन अपनी आवाचाना से सुक्ष स्वर्क हुआ और प्रार्थी की मुलों के है कि कार्पोरान अपनी आवाचाना से कुछ स्वर्क हुआ और प्रार्थी की मुलों के है कि कार्पोरान अपनी आवाचाना से कुछ स्वर्क हुआ और प्रार्थी की मुलों के है कि कार्पोरान अपनी आवाचाना से कुछ स्वर्क हुआ और प्रार्थी की मुलों के है कि कार्पोरान अपनी आवाचाना से कुछ स्वर्क हुआ और प्रार्थी की मुलों के हैं कि कार्य करता हुआ और प्रार्थी की मुलों के हैं कि कार्य करता हुआ अपनी प्रार्थी की मुलों के हैं कि कार्य करता हुआ आरे प्रार्थी की मुलों के हैं कि कार्य करता हुआ और प्रार्थी की मुलों के हैं कि कार्य करता हुआ अपनी प्रार्थी की मुलों के हैं कि कार्य करता हुआ सार्थी की मुलों के हैं कि कार्य करता हुआ अपनी स्वर्ध करता हुआ और प्रार्थी की मुलों के ही कि सार्य करता हुआ सार्थ कार्य करता हुआ करता हुआ से सार्थ की स्वर्ध करता हुआ करता हुआ सार्य कार्य कार्य कार्य करता हुआ सार्य कार्य करता हुआ सार्य कार्य कार्य करता हुआ सार्य कार्य कार्य

वास्तिविक किताई यह है कि कार्योरेशन को इस सम्बन्ध में कुछ चिन्ता नहीं है और वह अपनी माचीन रोति से कार्य करता रहा। यह बात उक्लेकनीय है कि कार्योरेशन अपनी आलाचना से कुछ स्वकं हुआ और प्रार्थों की भूखों के होते हुने भी अरबीकृत आवेदन पत्रों की संख्या पटने खयी।

(२) आलोचकों का कहना है कि कार्योरेशन ने सहायता में बहुत कम समराशि दी। जून १९५७ तक ६ वर्षों में कार्योरेशन ने स्थापता में बहुत कम समराशि दी। जून १९५७ तक ६ वर्षों में कार्योरेशन ने स्थापता में बहुत कम अपनाशि दी। जून १९५७ तक ६ वर्षों में कार्योरेशन ने स्थापता अपनाशि का मत है कि इवका कार्या उपयुक्त आवेदन पत्रों का अभाव है। इवके विपरीत यह कहा गया है कि उपयुक्त आवेदन पत्र न आने के कार्याय अभिकाशि के अपनाशि है। कार्योरेशन ने अपनाशि आवेदन पत्रों पर निर्णय देने में अनुचित दिलान है। कार्योरेशन ने अपनाशि कार्योशि है कि उपयुक्त की रोवर की गारन्टी की है और न अरुपाय स्थीरे हो है। हार्योरेशन स्थापन स्थीरे हो है। हार्योरेशन स्थापन स्थीरेशन के स्थापन स्थीरेशन से स्थापन स्थापन स्थापन स्थीरेशन से स्थापन स्थापन स्थीरेशन से स्थापन स्थीरेशन से स्थापन स्

यह कहना छन्नाचत है कि चर्तमान समय में पूंची बाजार की रिथति ऐसी महीं है कि कार्योरेसन नीमा का कार्य करे। कार्योरेसन के अध्यन्त लाला भी राम ने चीपी खामण्य देवक में बताया कि खोचोगिक दिच्छा कार्योरेसन का उदेश्य पूंची बाजार के पूरक के रूप में कार्य करना है, न कि पूंची बाजार की पिरकुल देवान राम के पार करना है, न कि पूंची बाजार की पिरकुल हुए मार स्वय उपका स्थान वे चीना। इच्छे स्वय है कि कार्योरेसन के उदेश्य को उचित प्रकार में मी हिएकोण उचित नहीं है। यदि भारत में पूंची बाजार विकक्षित होता तो खौदांगिक संस्थार्ट्र आवश्यकता पड़ने प्रची एकंडिय सर वक्ती भी खौर तब कार्योरेसन की कीई आवश्यकता नहीं रह बातो। यस्य चूँकि पूंची बाजार विकसित नहीं है इसलिए कार्योरेसन की आवश्यकता नहीं रह बातो। यस्य चूँकि पूंची बाजार विकसित नहीं है इसलिए कार्योरेसन की आवश्यकता नहीं रह बातो। यस्य चूँकि पूंची बाजार विकसित नहीं है इसलिए

- (३) कार्यरिशन ने जो कुछ श्राण दिया उस पर बहुत श्रिष्ठिक स्थान लिया है। करवरी १६५२ तक कार्योग्यान की ज्यान दर ५६ प्रतिश्वत की सूर ति कार्योग्यान की ज्यान दर ५६ प्रतिश्वत की सूर दी जाती थी। तहन्तर स्थाज की दर ७ प्रतिश्वत को चुंच तो गई और खूट केवल १ प्रतिश्वत हो रही। श्रीणीरिक कारवानों को देखिकां लिक श्रीण की शानश्यकता होती है, श्रीर कारवाना चालू होने से पश्चे कार्यो प्रमान तक उन्हें उक क्यरे से आप नहीं होती है। इस हरें हरें से ६१ प्रतिश्वत ज्यान की दर वास्त्र में महुत अधिक है श्रीर गई कारवाना होती है। के श्रीर में के अधिकारिक संस्थाम के पान श्रीण के लिए श्रीवेदन पम नहीं मैजती है। कार्योरिशन के श्रीपकारिया का कहना है कि श्रीणीरिक संस्थाम अधिकारियों का कहना है कि श्रीणीरिक संस्थाम के श्रीपकारिया के पान श्रीण की ते पर स्वर्य के वा पर सर्व के स्थान देना पर सर्व है। कार्योरिशन के श्रीपक ते स्थान के स्थान देना पर सर्व है। परन्तु कार्योरिशन की व्यवस्था को श्रीपक लोकप्रिय मनार्व के लिए ज्यान की दर कम करते के लिए ज्यान्य कक करना चारिय माने के लिए ज्यान की दर कम करते के लिए ज्यान्य कक करना चारिय माने के लिए ज्यान की दर कम
- (४) यह कहा गया है कि कापेरिशन ने ख्रव तक सहायता उन्हीं राज्यों को दी है जो पहले से ही विष्ठित हैं, द्वीर उन्हीं उच्यों को दी है जो समृद्धि-शाली हैं। जून १९५७ के खन्त तक ह वर्षों की खर्वाय में ५५.१२ करोड़ द० की अनराशि में में १६-११ कर के का ब-उवांगों को ८५४ कराड़ दे वस्त उद्योगों को, ७५१ करोड़ दे कहा खारन्त ख्राबांगिक स्वायन उद्योग को, ४५२, करोड़ दे का कान उद्याग को, तथा १,७७ करोड़ द० वीमेन्ट उद्योग को दिया गया।

यह कार्पोरेशन के लिये गर्व की बात है कि जून ११५७ के अन्य तक मंजूर की गई ५५.५२ करोड़ द० की धनराशि में से १३८० करोड़ द० अयाँत ६१% उन संस्थाओं की दिया गया जिन्होंने १५ अगस्त १६४७ के बाद उत्पादन प्रारम्म किया। इसके अतिरिक्त जान १६५७ के अन्य होने वाले वर्ष में राज्यानुसार ऋष्य की मंज्यों में भी बहुत परिवर्तन हुआ। उदाहरण के लिये आँम, केरल, पंजाह, और उत्तर प्रदेश की कम विकित्त राज्यों को मंजूर किये गये शृत्य की माना अधिक थी।

एक अन्य सन्तोपननक नात यह यी कि १६५६-५७ में यद्यांप कार्योरोग के पास आने नाले आवेदन पत्रों की संख्या कम था किन्तु ऋषा विवारित फरने की गति आविक थीं। १९५६ ५७ में ६.७८ करोड़ ६० का ऋषा दिवा गया जन कि १६५५-५६ में २.२० करोड़ द० का ऋषा दिवा गया था। इसके निम्म कारण थे।

- (i) कार्योरेशन के दफ्तर में प्रशासन सम्बन्धां सुधार पूर्ण हो गये ये।
- (स) क्योर क्राधिक कानन-व्यक्तिकारियों की निर्याक्त हुई ।
- (iii) पर्याप्त सम्मत्ति के आधार पर (दस्ताचेजो क पूर्ण होने तक) अन्तरीय अन्या मजर करने की विधि की सरल बना दिया।

जांच की रिपोर्ट — कार्पोरेशन क कार्यों की शतीखा के लिये श्रीवीधिक विचीय कार्पोरेशन जांच कमेटी की नियुक्ति दिस्त्यर १९५२ में श्रीमती सुनेता कृपलानी की श्रम्यख्ता से हुई। इस कमेटी ने ७ मई १९५३ को अपनी रिपोर्ट हो। कमेटी ने कार्पोरेशन को उसके विकस लगाये हुने पद्मागत के श्रीमयीग से मुक्त कर दिया। यर वर टीका कि जैयरमैन लगा श्रन्य । नर्वेशक जिन श्राविदकों के प्रति परोप कृपणा होते हैं उनके लाय वार्पोरेशन का ज्यवहार श्रीक उदार होता है और उनका कार्य भी श्रीम कर दिया। यत्र अपक उदार कार्यों से श्रीम कर दिया। यत्र अपक उदार की प्रवृत्ति उन उपममों के प्रति, जिनका कार्य सुचाव करा से चल रहा है तथा जिनसे कि से सुव्यात करने की रही है। इसमायों के सुव्यात करने की सुव्यात स्थानी

प्रशासन सम्बन्धि—(१) कार्पोरखन का खंगठन परिवर्तित करके एक स्वाची देतीनक चेपरमैन नियुक्त क्रिये काना चाहबी जिवली उद्याचना के लिये एक जनरल मैनेजर होना चाहिबे । वर्तमान क्षणठन जिनमें अवैतिनक चेपरमैन देताम एक एक व्याचित करके होने होने होने होने होने होने होने कार्योर है, उपयुक्त नहीं हैं। (२) मैनेजिंग बायरेक्टर और उद्याचन केंनेजिंग बायरेक्टर के आध्वाचे को विचार पूर्य दंग से निश्चत कर देना चाहिबे और यह ध्यान रखना चाहिबे कि कियी के हाथ में अनावश्यक दंग से आध्वाचार वेदित न हो जीवा (१) कारिरेक्टन के कोई में उच्चीगविधों का आध्वाच नहीं होना चाहिबे, उरकार को नोर्म में अवत अवय यह ध्यान में रखना चारिबे कि उनमें एक अर्थाण की, एक छंगठन में खुशक ध्याक और एक चारटक एकाउन्टेन्ट अवस्थ हो; और (४) मध्येक चाला कार्योज्य में उत्त पात्र विशेष के सलाहकारों का एक पैनल अवस्थ हो जिनमें से कुळ नो मध्येक खुशक के बार विशेष के सलाहकारों का एक पैनल अवस्थ हो जिनमें से कुळ नो मध्येक खुशक कि बार विशेष के सलाहकारों का एक पैनल अवस्थ हो जिनमें से कुळ नो मध्येक खुशक के बार विशेष के सलाहकारों का एक पैनल अवस्थ हो जिनमें से कुळ नो मध्येक खुशक के बार विशेष के सलाहकारों के प्रविचार करने के लिये निवर्धन विश्व वा स्वयं विश्व क्षा करें।

कार्ये प्रशासी सम्बन्धी — (१) यदि कार्योरशन वे किसी अरयत्त का सम्बन्ध सिसी ऐसे उपनम से है जिसन म्हणू के लिये आयोर्न दिया है तो उसे श्रापना सम्बन्ध तरन्त स्वक्त कर देना चाहिये। ऐसे उपक्रम जिनमें श्रीरोधिक वित्तीय कार्पीरेशन का कोई डायरेक्टर मैनेजिंग डाइरेक्टर है अथवा डायरेक्टर मामीटार या शेयर होल्हर जसकी मैनेजिस एजेन्सी में है तो वह धारा पाम करने का ग्राधिकारी नहीं सप्तका जायगा । ऐसे उपक्रम जिसमें कार्पोरेशन का द्वार्थरेकरर एक साधारण हायरेक्टर अथवा शेयर होल्हर है. उसे आण पाने के लिये यह आवश्यक होता कि जायरेक्स्पों के बोर्ड की बैठक में जिसमें चीर तेसे के चाल-कारी ? सरस्य अपस्थित हो असे (अपने अपना के आवेदन पर) सर्व सम्वति से स्वांदर क्रिले । यहि कार्णीरेशन का कार्र जायरेकरर किसी क्रमा सरक्रिली ब्याबेटन में सम्बन्ध रखना है तो उसे होई की कार्यकारिया। समिति की बैठक में ब्द्रम कि वह प्रारा का व्यविद्रन विचाराधीन ही उपस्थित न होना चाहिये। (२) कार्पीरकाम को अपनी वार्षिक विवरता पत्रिका को आधक विवाद बनाना चाहिये ह्या अपनी पंच वर्षीय वियोर्ट में काला पाप व्यक्तियों का अध्य हेजा चाहिये। हथा जनके कार्य थ्रीर रूपलता का वर्णन करना चार्वाये श्रीर सम्वर्ण जलोग के विकास की प्रकृति आदि पर मी प्रकाश डालना चाहिये: (३) कम से कम ५०% तक आए देने की सीमा नियस करना चाहिये; (४) ऋण को स्वाकृति देने तथा स्पया देने में देर कम करनी चाहिये. विशेष कर जा समय स्वामित्व सम्बन्धी कामनी कामजी की जीच में लगता है उसे कम करना चाहिये: श्रीर (५) बब कोई उपह्रम श्रीरा)-विक विकीय कार्पेरेशन कारा ले लिया जाय तब सामान्यतः जनका प्रदेश विमास व्यवता मैनेजिस एजेन्सी को सींपने के बताय मनोजीन जावरेकररी के बोई को सोप देना चाडिये।

नीति सम्बन्धी—(१) कार्षीरशन को श्रीशोगिक विकास सम्बन्ध में जो प्रधानता शोजना आयोग द्वारा दी गई है, श्रीर ४२ उद्योगों के सम्बन्ध में जो विकास का कार्यक्रम बनाया गया है उसी के अनुकुल कार्य करना चाहिए। सामान्यतः उन उद्योगों को जो अपने विकास को उच्चतम स्थित पर पहुँच गया है कार्य भूष न देवा चाहिये; (२) जिन विद्यानों के प्रधान पर कारपीरण को कार्य करना चाहिये उनके सम्बन्ध में सरकार को निर्देश देने चाहिये। सरकार को उन चेना के सम्बन्ध में बिन्हें पिखुड़ा हुआ समकता चाहिये निश्चित निर्देश 'देना चाहिये ति कार्य एक लाख करने के प्रधिक मूख्य के अपनेना को निर्देश देना चाहिये कि वह ५० लाख करने के प्रधिक मूख्य के अपनेना को प्रधानामां तीन वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के मिन्नस्थाइल में स्वांकृति के लिये में ने, (४) विचीय कार्योरेशन के निरस्ताति के कार्य में केन्द्रीय संबद्ध के सहस्ता का कार्पोरेशन तथा नियमों के आधार पर स्थापित ऐसी श्रन्य कार्पोरेशनों के कार्यों को श्रिपिक नियमित रूप से परीक्षण करने की श्रुपिश प्रदान करने के लिये एक पिलक कार्पोरेशन कार्यों के नियुक्ति पर विचार करना चाहिए; श्रीर (५) सरकार को यह घोचना चाहिए के कार्पोरेशना की श्रनुत्पादक कार्यों के लिये श्रमुण देने की नीति के समझक में कार्यों न निर्देश दिये जाँग।

सरकार ने कमेटी के कुछ महत्वशाली झिमस्तायों की छोड़ कर लगभग सभी को श्रीकार कर लिया है। १६४८ के झीबोगिक विचीय कार्पोरेशन एक्ट की बारा ६ की उपचारा (१) के झनुसार मात झिकार के झन्तर्गत केन्द्रोप सर-कार कार्पोरेशन को निन्न निर्देश दिये हैं:—

(१) कारपोरेशन बोर्ड को समय पर नम्बई, कलकत्ता, मद्रास खारि केन्द्रीय स्थानों पर, ख्रपने प्रधान वेन्द्र दिल्ली के ख्रतिरिक्त, समाएँ करना चाहिये।

(२) कार्गेरिशन के डायरेक्टरों को ऋ्षण के लिये मात आवेद को है अपना सम्बन्ध (जिसमें ऋष्य मांगने वासी कम्मनी का दिस्सेदार होना, अथवा उसकी मैनेजिंग एजेम्सी के दिस्सेटार होना शिम्मलित होगा) अवस्य ज्यक्त कर देना चादिये और शिस समय उनके ऋष्य के आवेदन पर विचार होने समें में सम्मलित नहों। एक पीनस्टर जैसा कि इन्डियन कम्मनीच एक्ट की घारा ६१ ए (३) मैं बताया गया है बैसा ही कार्योश्यन को भी स्वता चादिये।

(३) कार्पोरेशन का वार्षिक विवरस्य अधिक विराद होना चाहिये और

स्रिपिक के स्रिपिक स्वनाय उनमें दी बानो चाहिये। इस विवरण में उचोगों के विकास का नर्यंन स्रोर विशेष कर उन चेत्रों का वर्षन विनमें स्ट्राय दिया गया है होना चाहिये। जिन उपक्रमों को रुपया उभार दिया गया है उनका नाम भी इसमें छुपना चाहिये।

(४) ऋण की स्वीकृति देते समय ५०% की न्यूनतम शीमा का स्येप बनाना जादिये और ऋण लेने वाले उपक्रम की आप अर्जित करने की खमता का विशेष रूप से अपना लगा लेगा चिरेषे । अपरेक्टरों और आवेदकों के एकेटों के किए समय का निचार किया जाना चाहिये और जहाँ पर वे विच सम्बन्ध, कार्योशन समय का निचार किया जाना चाहिये और जहाँ पर वे विच सम्बन्ध, कार्योशन समय वीच, वहाँ उपरेक्टरों और मैनेजिंग एकेटों को भूख लेने वाले उपक्रमों के अपने निजी सेक्टरों को निना कार्योरान के अनुमित के विच डालने की स्वतन्यता नहीं होनी चाहिये।

(4) जिन निरोप आविदकों को कार्पीरेशन ५० लाख रुपये से अधिक का भ्रम्य देने का निर्णय करें उचकी रिपोर्ट पूर्य निवस्य सहित सरकार को में श्री जानी चाडिये। उन सर प्रथा खेने वाले उपकमों की भी रिपोर्ट सरकार को में श्री जानी चाहिये जिनमें कापोरेशन का कोई डायरेक्टर श्रुख लेने वाले उपक्रम की मैनेजिन एकेन्छी में डायरेक्टर, साम्बीदार या मैनेजिन बायरेक्टर असवा हिस्मेदार हो। उन कम्पनियों को श्रुख प्रदान करने की रिपोर्ट निममें कापिरेशन का डाय-रेक्टर एक साधारखडायरेक्टर अथवा हिस्सेदार है, उस स्थित में मेनान चाहिये जबकि मुख्य की स्थीकृति ऐसी मीटिंग में दी गई हो जिसमें आहेर से कम डायरेक्टर उपस्थित रहे है, असवा मुख्य की स्थीकृति ऐसी मीटिंग में दी गई हो जिसमें आहेर से कम डायरेक्टर उपस्थित रहे ही, अथवा मुख्य की स्थोकृति सर्व समाति से न प्राप्त हुई हो।

सरकार ने क्रोरी की वह निकारित स्वीकार नहीं की कि जान खोरोसिक विस कार्जीरेशम का कोई जायरेश्वर आण के जयकारी मैंत्रेलिंग जायरेक्टर या सामीदार इत्यादि तो उन्हें भाग पाने का अधिकारी न समका जाय। इससे श्रीद्योगिक उपक्रम अनावश्यक करिजाई में पर जॉयेंगे, तथा जब तक कि कार-पीरेशन की समस्त रूपरेखा और पंजी का संगठन पूर्ण रूप से न बदल दिया जाय पैसी शर्त सुगाना अन्यवहारिक होगा । सरकार ने अनुत्यादक कार्यों तथा विशेष क्षेत्रों को अपण प्रदान करने की नीति सम्बन्धी कार्पेरेशनों को दिये जाने वाले निर्देशों के सम्बन्ध में की हुई सिफारिश की मो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि श्रीहोतिक वित्तीय कारपोरेशात जीशोतिक विन्त महत्त्वी एक तवीन प्रयोग है श्रीर श्रमभव से घीरे धीरे इसके सिटान्त विकसित होंने तथा उसको कार्य प्रणासी निश्चित होगी। इसके श्रतिबिक्त क्योंकि हो बढ़े सरकारी कर्मचारी कारपोरेशन के बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं सरकार के खिये ऐसे निर्देशों को देने की कोई आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती। १९५२ में कानन द्वारा कार्पेरिशन का अधिकार बढ़ा कर ५० लाख दुपये से भी अधिक अगा देने का कर दिया गया था. क्योंकि इतना आया लेने वालों की संख्या भी बहुत कम रही है, इसीलिए सरकार को वर्तमान स्थिति परिवर्तित करके कार्पोरशन के लिये ऐसे अपूरा के प्रदान के सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति लोना अनिवार्य कर देने का कोई न्यायोचित कारण समझ में नहीं आता। ५० लाख रुपये से श्रावक के भूग की सरकार को सूचना देने की बात तो अनिवार्य कर ही दी गई है। इस लिये सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि वर्तमान परिस्थिति में पालियामेंट की पब्लिक कार्पेरेशन कमेटी की इस कार्परिशन और अन्य कानन द्वारा बनाये हुए कार्पोरेशानों की कार्यवाहियों की देख रेख करने के लिये नियुक्ति की कोई आव-रयकता नहीं है। जाँच कमेटी की रिपोर्ट, तथा सरकार द्वारा उसकी विकारिशों के अनुकूल किये गये कार्यों से यह आशा की वाती है कि कार्योरेशन के कार्य में तथा कार्य करने के ढंग में बहुत कुछ परिवर्तन आ जायगा।

#### प्रास्तीय श्रथवा राज्य वित्तीय कारपोरेशन

э:: मितानर १६५ १ में राज्य वित्त कार्पोरेशन कानन पास हन्ना । यह कानन काम्मीर खीर जम्म राज्यों को छोड़कर समस्त भारत पर लाग होगा थीर इसके कातमार पहलीय सरकारें काणेरेशन स्थापित कर सकती हैं । भारतीय जीते विक विस्त कार्पोरेशान संभित दाधित्व वाली कम्पनियों को सहायमा देना है। प्रश्यक्र खोर छंटे उद्योगों को भी सहायता देना बाच्छनीय समका गया है क्योंकि ये कर्ताय कार्पोरेशन के अस्तेगत नहीं आते इस्लिय प्रास्तीय विसीय कार्पारेशनी का ध्येथ हैसे ही उद्योगा की सहायता जदान करना होगा। इस राज्य विसीध कार्योरशानी की स्थापना लगभग उसी रूप में हांगी जिसमें भारतीय खीदोंगिक हिसीय कार्पोरेशन की स्थापना हुई है। बहुत थोड़े से ही परिवर्तन होने । राज्य विक्रीय कारवीरेशन के सम्बन्ध में अपा २० वर्ष के ही लिये दिया जायगा न कि Du वर्ष के सिये जैसा कि भारतीय खोलोशिक विसीय कारगेरेजात के सरवन्य में हैं। राज्य वित्तीय कापीरेशन की शेयर पाँची ५० लाख काये में लगाकर ५ करोड़ रुपये तक शेती है। शेयर पुँजी का तीन चीथाई प्रान्तीय राज्यो. रिजर्थ वैंक श्चनम्बित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा कम्पनिया, बिनियोग इस्टो तथा श्रम्भ वित्त सस्थाको द्वारा और शार खन्य व्यक्तियो वारा प्रतान की जानी चाहिये। इस प्रकार राज्य विक्रीय कार्पीरेशनों को व्यक्तिगत विवन्नेशा करने बालों का भी सहयोग प्राप्त है। इन कार्पोरेशनों के सम्बन्ध में जनता द्वारा जमा की हुई धन-राशि कार्पोरशन की मास पूँजी की मात्रा से अधिक नहीं हो सकती। राज्य यितीय कार्पीरेशन किसी एक उपक्रम को श्राधिकतम विक सहायता १० लाख रुपयो तक की दे सकता है।

राज्य विक्तोय कार्पोरेहान (संशोधन) खांधानियम १६४६ -- राज्य विचीय कार्पोरेशन ब्राधानियम में संशोधन अधिनयम द्वारा खनेक परिवर्तन किये गये जो १ अबद्वर १६५६ से लागु हुये । संशोधन ब्राधिनयम में निम्म बातों की व्यवस्था है ।

- (६) दी या ऋषिक राज्यों के लिये समुक्त वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना ऋपवा अन्य राज्यों तक कारपोरेशन के श्रथ का विस्तार करना।
- (ii) केन्द्रीय श्रयना राज्य सरकार श्रयना श्रीनोतिक वित्त निगम द्वारा दिये गये श्रूय, या मन्त्र किये गये श्रविम या श्रीनित श्रयपत्रों के सम्बन्ध में इनके एनेन्ट के इन में किसी श्रीनोतिक सरवा से न्यवहार करना ।
- (iii) राज्य सरकार, अनुस्वित बैक ख्रयना राज्यीय सहकारी बैंक की गारन्टी पर उद्योगों को आर्थिक खनुबह प्रदान करना ।

(iv) कारणेरेशन द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के वल पर श्ररूपकालीन श्रष्टण लेना।

(v) निजर्व कैंक द्वारा कारपोरेशनों का निरोक्क्स, राज्य पुनर्सगठन अधि-नियम १६५६ जो १ नवम्बर १६५६ से लागू किया गया कि धारा १०१ (३) और (६) के अन्तर्यत किये यमें विलयम के फलस्कर परण्य विचीय नियमों को संस्थर दो से घर गई। वस्मई ओर जीराष्ट्र के कार्योरेशन मिलाकर बस्मई राज्य विचीय कारपोरेशन बना दिया गया। आत्म और हैराज्य राज्य के कार्योरेशन मिलाकर आत्मधरेश राज्य विचीय कारपोरेशन बना दिया गया। विस्मयर १६५७ में निम्म राज्यों में से प्रत्येक में एक राज्य विचीय कारपोरेशन या। सहस्य पंजाब, बन्धई, फरल, परिचनी बंगाल, आवाम, उद्देश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बच्चर प्रदेश, विद्वार और आत्म प्रदेश।

१६५७-५८ के अन्त में १२ राज्य-विचीय कार्योरेशन की कुल सम्पत्ति १८ अप सरोइ कर यी जिसमें से १-१५ करोड़ कर अप और आंध्रम ये। अतः १२ कार्योरेशन का परिष्ठ पूँजी १३/१० करोड़ कर यी तथा सुरिक्ष के कुल ५ लाज कर या। १६५६-५० में मज़्र किये तथा दिये गये अप दिश्य प्रभी माजा कमारा ४/१३ करोड़ कर तथा १८६६ करोड़ कर यी जबकि १६५५-५६ में यह राशि कमारा ४/४३ करोड़ कर तथा १८६ करोड़ कर यी जबकि १६५५-५६ में यह राशि कमारा १/७५ करोड़ कर तथा १८० करोड़ कर यी। कार्योरेशन द्वारा दो आने वाली शहायता कार्योरेशन पूर्ण विकलित होने पर दे वहंगा उससे अभी बहुत कम शहायता कार्योरेशन पूर्ण विकलित होने पर दे वहंगा उससे अभी बहुत कम शहायता कार्योरे

आरम्भ में कार्गरिशन को बहुत बी किताइयों का वामना आवेदकों के अज्ञान, विशेषतों के अभाव तथा अधिक करों के कारण करना पड़ा है। इन यब वसस्याओं पर राश्य विचीय कारीश्वन की प्रथम और द्वितीय वभा में जो अध्यक्त १६५५ में जोर त्वावत १६५५ में को अध्यक्त १६५५ में जोर त्वावत १६५५ में जोर त्वावत १६५५ में जोर त्वावत शिवाय विचाय किया गया था। अथभ वभा का उद्धारन करते समय तिवर्ष वें के के शवनीर श्री बीव रामा राज ने विधिय राज्यों में मन्यवर्ती और खोरे उद्योगों के विचाय के लिये ऐसे वार्गरिश्यनों की महत्ता पर बहुत और दिया। यह अस्पन्त आवश्यक हैं कि प्राराम्भक अवस्था में अनुवस्यक की वार्ने वार्लो नीति की रूप रेखा पर पत्र एकस्पत हो, व्यवत्त कार्याय अध्यक्त विध्य अधिकत्त लामकारी विद्य हो। इर बात में एकस्पता लाजे के ब्रवाय प्रयेग में तथा कार्य विधियों निश्य को बीर और प्रीचोशिक कर्मचारियों तथा कार्य चेत्र आदि में समानता

लाने का प्रादर्श होना चाहिये। कार्णोरेशनों को जो गंभीर कठिनाइयाँ उठानी पट रही है. उनमें से एक तो प्रौद्योगिक कर्म चारियों के श्रमाय की है जो श्रूण के किये सावेदन करने वाले उपर्शासकों की योजनात्रों की अपयक्तता का परीचण कर सर्के। कार्पोरेशन ६-७ प्रतिशत का बो ब्याज वसल कर रहे हैं वह बहत कारिक है। पारिभक कावस्था में इस कार्पोरेशमों का स्वयं अवश्य बहत अधिक है और सभा ने अनको राज्य सरकारों की स्टाम्प क्वरी से मफा करने की तथा केन्द्रीय सरकार के जाय कर से सक्त करने की सिफारश भी की थी। सबसे बडी कठिनाई इस बात की है कि आप के लिये आवेदन करने वाले उपक्रम अपना हिसाद किताब टीक से लिखने तथा बन्य लेखा खीरोगिक बैंकिंग के मान्य स्तर पर निर्माण करने के प्रति उटासीन लगते हैं। इससे ब्रावेटनों पर कार्यवाही करने में बानावत्रवक रूप से विलम्ब होता है। कार्पीरेशनी की व्यक्तिगत सीमित दावाच वाली कम्पनियों. साफेदारी. संयक्त पश्चिम व्यवसाय. तथा प्रकाकी स्वामित्व वाले उपक्रमों से भी सम्पन्न उसका प्रदश है । ये उपक्रम सामा-स्यतः ऐसे कारत सम्बन्धी कामजों को जिससे उस उपक्रम के उसका सम्बन्ध निश्चित होता है सर्वात रखने के प्रति लढासीन रहते हैं। बहुबा यह देखा गया है कि सबक परिवार के व्यक्ति बिना किसी बँटवारे सम्बन्धी कानूनी लिखा पढी के प्रथक हो जाते हैं जार सामेदारों के मध्य हिमाब किताब समकते का कोई साधन नहीं रहता। ऐसे संयुक्त परिवारो और सामेदारियों के आवेदनों की जाँच करने में समय और व्यय बहुत लगता है। येसा पता लगा है कि छोटे उद्योगों के बोर्ड की स्थापना के कारण, जो ऐसे उद्योगों को सहायता देने में अधिक उदार है, तथा सरकार द्वारा हाथ से धान कटने तथा घानी द्वारा तेल पेरने के उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये चायल तथा टाल की मिलों के विस्तार पर सगाये हुये प्रतिवन्धों के कारण, राज्य विश्वीय कार्णोरेशन के कार्य में बाधा पड़ी हैं। ये सब दोप धीरे-धीरे प्रयत्न करने से दर हो सकते हैं।

### श्रीद्योगिक विकास कार्पेरिशन

१६५४-५५ की दो महत्वपूर्ण बरनायों में से एक तो २० ग्राक्टूबर १६६४ को राष्ट्रीय श्रीधोगिक विकास कामीरेश्चन लिगिटेड की स्थापना श्रीर दूसरी रे मार्च १६५५ को भारतीय श्रीचोगिक साल ओर विनियोग नागीरेशन लिगिटेड की स्थापना थी। इन दोनों काभीरेशनों का भ्येय उद्योगों के लिये दूंची की पूर्ति में यूदि करना है परन्तु इन दोनों संस्थाशों कीकार्यीवांच श्रीर कार्योंकों प्रिकृति में यूदि करना है परन्तु इन दोनों संस्थाशों कीकार्यीवांच श्रीर कार्योंकों से किसीने की स्थापना क्रीकर्म स्थापना स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स

हार्षे० छो० आर्थे० छे० एक व्यक्तियत स्था है और इसकी रिकार्ट्स रिकार्ट्स कमानील एक्ट के कारती में कारती है स्था में में भारत सरकार ने लाई० सी० आर्थ है शी० अराथ है स्था के लाई० सी० आर्थ है सी० अराथ से एक एवं के प्रश्नात है प्रश्नात ने लाई० सी० आर्थ कोने कारती है स्था पर स्था के लाई० सी० अराथ सी

वीशरी बाषिक रिपोर्ट के अनुशार कारगोरान १८५७ के अस्त तक ११ सार्यों के लिये १९५५ करोड़ कर का सुराय देने के तिने बहार्यत दे चुकी थी। १८५५ में में एक कोड़ कर देन के तिन के शहर्यत देश में १९६५ में १९ कारों के लिये केवल व ००१ करोड़ कर दे (कार्या १९६५ में १९६६ में १९६ में १९६ में १९६ में १९६ में १९६ में १९६ में १९६५ में १९६ में १९६

मंत्र किये श्रुखों की राशि में जो तीन वृद्धि हुई उसका कारण यह या कि पहली बार विदेशी करेन्सी में पाँच श्रुख दिये गये थे जिसकी राशि २'२१ करोड़ कुरुती।

कारपोरशन से लाम उठाने बाले उन्नोगों का चेत्र बहुत विस्तृत है! इनमें कागज़, रसंयन तथा और्वाव, इन्जेक्शन का सामान (fue injection equipment), बिजली का सामान, वस्त्र, चीनी, धात, चूना और सीमेन्द्र, तथा शीरों का निर्माण सम्मिलत हैं। इस विनिधता के अविरक्त कारपोरियन की सहायता की एक विशेषता यह मो रही है कि इसके अन्तर्गत नये उनकमों के विस्त्र तथा क्षम विकासत चेत्रों की आवश्यकता पर खिक कोर दिया गया है। इस्था के अन्तर्गत कर आर्थिक सहायता प्राप्त करने बाले ३६ संस्थाओं में से १६ नये उनकम से।

राष्ट्रीय श्रीवांशिक विकास कार्यरिशन तिसिटेड (एत० श्राई० हो०) एक सरकारी संस्था है और इनका न्वेय सुक्रवत उन उचा यो को विक्त सामाज देना है जो पंचयर्थिय योकना के स्थानवांत आ आते हैं। २० झब्दूबर १९५४ की एकसी रिकर्ट्सा एक व्यक्तिन सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप हैं हैं हैं। इक्त श्रीकृत पूँजी १० लाख क्राया है जो कि भारत चरकार हारा ही प्रदान की गई है थी। कार्यरिशन को स्थानी पूँजी बढ़ाने का खरिकार प्राप्त है। प्रदान की गई है। कार्यरिशन को स्थानी पूँजी बढ़ाने का खरिकार प्राप्त है।

एन० ब्राइँ० डी० खी० ने प्रथम योजना के ब्रन्तमैत खाये हुए उपीमों को सहायता दी है। द्वितीय योजना काल में इसके कार्य का झौर ब्राधिक दिलार होगा थीर इसके पास लगान पर करते के लिये होगा। 'इस पन रास्त्रि का एक ख्रय (बो लगानम २० या २५ करोड़ इसमा ब्राग्रमन किया जाता है) धाशा की जाती है सुती करड़े और जुर के सामान निर्माण करने नाले उपोमी के ब्रामिनगीकरण में उपन किया जावगा। शेप २५ करोड़ के लगानम क्या नये मूल तथा बड़े-पड़े उद्योगों की स्थापना ख्रोर विकास के लिये क्या किया नावगा। जिन उपक्रमों के सम्बन्ध में लोब का कार्य एन० आई० ही० खी० ने ख्रापी उपार लिया दे वे काउड़्यों पोजें स्थापन, स्ट्रक्चरल फेकीन्यान, रिक्रो क्रें स्थापन, स्ट्रक्चरल फेकीन्यान, रिक्रो क्रेंगे क्रायन, स्ट्रक्चरल फेकीन्यान, रिक्रो क्रेंगे ख्राप्त, स्ट्रक्चरल फेकीन्यान, रिक्र क्र्यों के स्थापन उपार के स्थापन क्रायों के स्थापन क्रायों के स्थापन ख्री के एन० आई० हो। की इस इस उपक्रमों के ख्रातिक वर इस द्वार की वार्त है। इस उपक्रमों के ख्रातिक वर इस द्वार की वार्त है। स्थापन क्रायों क्राय ख्राय व्यान ख्रायों का एक क्रायान ख्राया लोक को मूर्प क्रायों क्राया ख्राय का प्रथम क्रायों क्राया ख्राया ख्राय का स्थापन स्थान ख्री का स्थान क्रायों क्राया ख्राय ला व्यान ख्राया ख्राय का एक क्रायान ख्राया ला क्रायों मूर्प ख्राय ख्राय ख्राया ख्राय ख्राय ख्राय ख्राया ख्राय ख्राय ख्राय ख्राया ख्राया ख्राय ख्य ख्राय ख्याच ख्राय ख्य ख्राय ख्या ख्राय ख्

क प्रमायनों के निर्माण का कारखाना खोला नाय । स्यापार तथा उद्योग मंत्रालय हारा हाल में एक कमेटी की इसालये नियुक्ति की गई है कि वह इस बात की सलाइ दे कि दितीय योजना के अन्तर्गत नई अलापूनियम प्रदावस्त्राला की स्थापना के लिये सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कीन सा है ताकि ३०,००० स्न के उपरादन का स्थेय जिलाशे इस उद्यास के सम्बन्ध में सिकारिया की गई है पूर्ण की सा एके ) प्रकृष किया जा रहा है कि बढ़ा-नहीं कार्यक्षों, फार्ज तथा स्ट्रक्यराल खाल्क के उपक्रमों के सम्बन्ध में रियोट तैयहार की जाव । यह आशा की जाती है कि हम उद्योगों के सम्बन्ध में रियोट तैयहार की जाव । यह आशा की जाती है कि हम उद्योगों के सम्बन्ध में रियोट तियहार की जाव । यह आशा की जाती है कि हम उद्योगों के सम्बन्ध में रियोट तियहां की निर्माण तथा इनके विकास की सिवालकों के उपाय किये आध्यों।

"कारगेरेशन द्वाग अपेक्षित वित्त केन्द्रीय चरकार द्वारा अनुदानों और स्त्रुत्य के कम में दिया जाता है। १९५६-५० में १९४६ करोड़ वं की व्यवस्था की गई थी। १९५७-५८ के बकट अनुमान में ४९५० करोड़ वं की व्यवस्था की गई थी। १९५७-५८ के बकट अनुमान में ४९५० करोड़ वं कि व्यवस्था की गई है। जह और सुती वक्त अयोग के अमिनवीकरण के हेत्र ऋष्ण देने के लिये कार्योशन सरकारी एजेन्सी के कम में कार्य करता है। अब तक कार्योरियान ते ६ सुती मिली तथा वा जूर भिली को अभगाः १९६५ करोड़ वं तथा ५५ लाख कर भेन्द्र किये। कारगेरेशन द्वारा दिये गये ऋषा के बयाज दर ४५ मिरात अपित के स्वा के स्वा दर ४५ मिरात अपित के स्व क्षा करा है। स्व व स्व व १९ वार्षिक किस्ती में अकार्य नात हैं?

## पुनर्विच कार्पेरिशन (Refinance Corporation)

मध्यम आकार के उद्योगों की सहायता के लिये ५ जून १६५८ को हन्दियन कम्पनील एक्ट १६५६ के अन्वर्गत पुनर्वित्त कार्पोरेशन (प्राइवेट) लि॰ की रिलस्त्री हुई ।

यह कारगिरेशन बावई में होगा। इसके संवालक मण्डल में छात सदस्य होंगे जो इस प्रकार है:—रिवर्ष केंक श्रांक इंक्टिया का गयदर (अप्रवह), रिकर्ष केंक का एक डिस्टी गयनरे, स्टेट बैंक खाक इंक्टिया का अध्यक्, जीवन बीमा कारपोरेशन का अध्यक्ष तथा माग सेने वाली बैंकी के तीन प्रतिनिधि।

कारयोरेशन की खाँचकुत पूँजी १ लालक के २५,०० शेयरों में वियाजित २५ करोड़ का होगा। प्रारम्भिक निर्मासत पूँजी २२,५ करोड़ का होगी निसमें में ५ करोड़ का स्वर्ण केंक्क, २,५ करोड़ का जीवन बीमा कारपोरेशन, २,५ करोड़ रेट मैंक आफ इन्डिया तथा २,७ करोड़ का १४ जुनी हुई अनुस्वित मैंकी द्वारा प्राप्ति होगा।

वैंकों में निम्म सम्मिलिए हैं। सेन्ट्रल बैक, पंजाब नेशनल वैंक, इलाहाबाद

वेंक, बेंक स्त्राफ इंग्डिया, द इन्डियन वेंक, द मरकेन्टाइल बेंक स्त्राफ इंग्डिया हैदराबाद बेंक. बेंक श्राफ बढ़ीदा, नेशनल बैंक श्राफ इविडया, यनाइटेड कर्माग्रक बैंक. ल्याडस बैंक. चार्टड बैंक. द यनाइटेट बैंक आफ इश्टिया श्रीर द डेन

वैंक (Dena Bank)।

श्रूरण ५० लाख ६० से अधिक के नहीं होंगे और उनकी अवधि तीन व से कम सथा सात वर्षसे ऋषिक नहीं होशी।

यह सविधा कवल उस कीदोशिक संस्थाओं को प्राप्त होगी जिसकी परिस्त पूँजी तथा सुरक्तित कोष (करार्य तथा सामान्य ब्रवज्ञयण के सुरक्ति कीप की छोड़कर) २३ करोड़ ६० से अधिक न हो । ऋखा प्रधानतः द्वितीय तथा अल योजनात्रों में सम्मलित उद्योगों का श्रीद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये होगे। इस उद्देश्य के लिये कार्पोरेशन को अपने साधनों के अतिरिक्त २६ करोड़ द० के

ऋण का भी लाभ मिलेगा जो भारत सरकार यनाइवेड स्टेटस की इसी प्रकार ही धनराधि में से देगी। यह ऋश ४० वर्ष के लिये होगा स्त्रीर इस पर सन्भवत: सरकार यु॰ एस॰ ए॰ को ४% प्रतिवर्ष का न्यान देगी।

कार्पोरेशन स्वयं ऋग नहीं देवी। योजना में भाग लेने वाली ए भारतीय तथा विदेशो बैंके ऋण दिया करेंगी। कार्पीरेशन की इस उपलब्ध साधन ३८३ करोड़ २० है (अर्थात् १२३ करोड २० अथवा तथा २६ करोड़ द०

यूनाइटेड स्टेट्स का)। इस धनराशि में से प्रत्येक भाग लेने वाली बैंक का कोडा निश्चित कर दिया जायगा जिसके अन्तर्गत से कारपोरेशन से पुनर्विस की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे ∎

### अध्याय २४ विदेशी पँजी

किसी भी देश की पिछड़ी हुई आधिक व्यवस्था की दो विशेषताएँ हैं--ीग्रपर्याप्त बचत तथा पूँचो का अमान और मशीन, टेकनिकल सामान, टेकनिकल कुरालका श्वादि का श्रावश्यकता की अपेबा श्रमात । मारत इन दोनों दोवों से मस्त है और स्थित पर विसय प्राप्त करने के लिए यह आसप्यक है कि विदेशी पूँजी का आयात किया जाय । विदेशी पूँजी की सहायता से हम देश की वयत का धार्थिक सावनों के विकास में जबबोग कर सकते हैं। यदि इस केवल अपने सीमित सामनों पर ही निर्मार रहें तो यह विकास सम्मय नहीं हो सकता। बिदेशी पूँजी से विदेशों से मशीनें टेकनिकल सामान और टेकनिकल कुशलसा इत्यादि को आयात कर सकते हैं। यह विदेशी पूँजी नहीं हो वो इस कार्य के लिए हम भुगतान सन्तुलन के छाधनों का उपयोग कर सकते हैं परन्त यह साधन भी सीमित है छीर बर्तमान में भारत का अगुकान सन्तुलन प्रतिकल है। यदि यह श्रमुकुल भी हो तब भी इससे बहत अम धन आप्त होगा । विना विदेशी पँजी की सहायता के सन्ताधसनक ज्याधिक प्रमति नहीं हो सकती। सारत की ही नहीं श्चपित संसार के अन्य देशों को अपने आर्थिक विकास के आरम्भकाल में विदेशो पॅक्षी की सहायता सेनी पढ़ी है। पश्चिमा और सहर पूर्व के आर्थिक सम्मेलन ने रिर्धात का अध्ययन करके इस बात पर महत्व दिया है कि पिछड़े हुए देशों की श्रार्थिक स्थिति का पिकास करने और उन्हें समृद्धशाली बनाने के लिए बिरेशी पॅनी का जायात अत्यन्त आवश्यक है।

मारत में योजना आयोग वे अनुमान खगमा है कि १९४०-४२ में १९१० करोक की राष्ट्रीय आप में हे लोगों ने खपती आप के ४५ प्रतिवाद माप को बचत की, अपोत्त कुल ४५० करोड़ कामे प्रति वर्ष बचत हुई और १९४४-४६ में ७२० करोड़ की बचत की बां कि १०००० करोड़ की राष्ट्रीय आप की ७.३% भी। यह कराब व्यावाद, यह निर्माण, सम्मिक के बन्न, वीबरी हस्माद में समाना

में द्वितीय योजना में यह ज़रताब किया गया है कि बारत की राम्भीय वचन भीर चित्रियोग की मामा में बृद्धि १६६०-६९ ठक १,५४० कोई स्वस्त्र कर्मीय राष्ट्रीय भाग का १,५४% कर दी आप जो कि भारत की जाती है उस समय तक ११४८० कोई इत्तर हैं। आवशी।

गया। इसके साथ ही कुछ नकद रुपये भी नवाये गये। इस कुल बचत में से देश के खीयोगिक विवास के लिये बहुत कम रुपया समाया गया। लोग खपती खाय में से बहुत कम बचत कर पाते हैं इपीकि खिकमर जनता इतनी निर्पम है कि कुछ भी बचत नहीं कर पाती खीर जो व्यक्ति कुछ वचन करते भी हैं उन्हें वे पूंजी के बाजार में नहीं लगाते। इन पारिस्पतियों में यह खावश्यक है कि हम भारत में पिरेशी पंजी का खाबश्यक हैं

मिदिश शासन के बाधीय—मारत में विदेशी खासनकाल में विदेशी पूजी स्वारं गई। यह पूँबी रेलने, जाय, जूर, कोयले की लातों, उद्योगी खीर क्यापार श्रवादि में साम है जिहिया पूँजी सना उद्यागी पर लागाई गई। किहिया पूँजी उन उद्यागी पर लागाई गई। किहिया पूँजी उन उद्यागी पर लागाई गई जिसते देश पर उनका ख्रांपकार इद्ध रहे जा जिसन उन्हें ऐशा शामान मिल सके जिसकी विदेशों में ख्रायात करने की खावरनकता है या जिससे उन्हें ख्रांक लाभ होता है। उन्हें देश के छोयोगिक विकास में कोई किन मही थी खोर जो कुछ निकास हुखा वह उनकी ख्रवने स्वार्थ के कार्यों के पूर्व करन से प्रकारत हो होता हो गया। इसमें कुछ सेदेह नहीं कि भारत ने श्रीधाणिक तथा ख्रापिक हिट से को योड़ा बहुत सिकास है यह किटिश पूँजा के ख्रमान बाग पर ख्रोयोगिक खार पूँचीपियों ने देश का कमकद खाँप खुन्नायोजित ख्राचार पर ख्रोयोगिक खार ख्राप्त का करने के प्रसून पर प्यान दिया होता तो अगरत का इस जैस में कार्यी क्वार्य कार्या क्वारा था ध्री ध्राप्त वा सकता था।

रको का प्रकार था। इसी कारण विदेशा पूँजी का ठीज विरोध हुआ वसीकि (१) जब श्रीप्रेमी में आरविक लाभ कमाया तो भारतीय अध्याय से देखते रहे। श्रीप्रेमी की सरकार ने अनेक रिवायतें भी दी क्योंकि सरकार भारतीयों की अपेद्मा विदेशियों का पद्मात करती थी। इस मेद भाव से भारतीयों को भारी खांत जठात्री पड़ी जिसका स्था-मार्थक ही विरोध किया गया।

(२) विदेशा पूँजो से चलाये गये उचोगो इत्यादि में ऋषिकतर चिदेशियों को ही नीकरी दी गई जिससे भारतीयों में अध्यत्तोच फैला। अपने ही देश में भारतीय अवहान ये और विदेशों वह सभी खुलियाएँ प्राप्त कर रहे ये जिन पर वास्तव में भारतीयों का ही अधिकार था।

(१) डाक्टर जान चन्द ने बताया है कि यह सत्य है कि हमारे देश में रेलवे, चाय, कहवा, अवस्क' तींवा, बूट और अन्य अनेक उद्योगों के विकास का अप विदेशी पूँकी को है परन्तु विदेशा पूँबी ही के कारख मारत में औद्योगिक शक्ति का केन्द्राकरण हुआ विवक्त विषय में अधिक ज्ञानवाही है। इसके ही कारख उद्योगों के प्रति मेद भाग की नीति के विकद सुरहा के वैश्वानिक प्रयत्न सम्मव हो मके। प्रास्तीय उसेग चेत्र में टाटा, विद्रता और दाल में टालमिया और वाल चन्द्र के आने पर मो ब्रिटिश उद्यागपतियों का ही प्रमुख है। एन्डब गूल, बर्ड, श्वनालेच, खोक्टेनियस स्टील और कुछ अन्य विदेशी कम्यनियाँ भारत की ब्रीयासिक आधिक व्यवस्था पर अन्ता प्रमुख जमाये हुए है; इसके साथ ही वित के साधन जुट, क्यास, कोयला, चाम, यातायात, जिलली, इंबोनियरिंग छोर अनेक उद्योगी पर नियमण रखते हैं। श्रीचींगण शक्ति के इस प्रकार केन्द्रित करने की प्रवृत्ति का भारतीय उचीमपतियों ने भी अनुकरण किया है जिबसे देश को काकी स्रति पहुँची है।

 (४) १६२६ में प्रशुल्क चंरल्ख का विदेशी उद्योग ने पूर्व लाम उठावा न्त्रीर भारत में अपने कारणाची की शालाएँ स्थापित की जिनके नाम के आति (भारत) लिमिटेड ओड़ दिया। बालाय में यह संरक्षण मारतीय उद्याग की प्रोत्साइन देने के लिए या और अब विदेशी उद्योग ने इसका लाभ उठाया ती

१६२५ में विदेशी पूँजी सामात ने इस बात की जीन की ग्रीर सुकाव इससे ग्रहन्तीय पैलना स्वाभाविक ही था। दिया कि विदेशी पूजी का भारत ये प्रोत्शहन दिया जाय। परन्तु जब सरकार बिरेगी उद्योग की कोई विशेष रियायत दे तो इच बात का व्यान रखे कि उचते मुस्पतः भारत को ही लाम पहुँचे। बाँद खुविषा किसी विशेष उद्याग की न देकर हमी को सामान्य रूप के दी गई, हो, केते प्रशुल्क संरक्ष की सुविया, हो किसी प्रकार का मेद भाव करना ब्यवहारिक इच्छि से सम्भव नहीं है। परन्तु यदि किसी विरोप कारलाने को द्रम्य की सहायता दी जाय तो इव बात का ध्यान रखना चाहिए कि मारतीय व्यावारी वे हित को हानि न पहुँचे। इसके छाप ही इस बात का भी ब्यान रखना चाहिए कि अब तक आरतियों को तत्तनशन्त्री शिला की उचित व्यवस्था न की जाम तब तक किसी विदेशी कम्पनी को काई मुदिया न दी नाय। सार्वजनिक कम्पानियों के सम्बन्ध में यह सुकाय दिया शया है कि उनकी मास्तीय कम्पनी कानून के अन्तर्यंत राजस्यू करावी आव, उनकी पुँछी भारतीय मुद्रा में हो और उनमें भारतीय संचालकों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित संख्या के बरावर हो। किन्तु खनियों के विकास के लिये सुविवाएँ देने के लिए निदिचत नियम नहीं बनाये जा सकते। परन्तु भारत सरकार ने इन क्षिमारियों को स्वी-कार नहीं किया और विदेशी पूँची प्रशुल्क संरक्षण की सम्पूर्ण सुविधाओं का और सरकार द्वारा दी गई ग्रन्य रियायती का लाम उठाती रही ।

सरकार की नीवि-यद सत्य है कि अवीत में विदेशी पूँजी के कारण

भारत में अवन्तोय फैला परन्तु अब भारत स्वतन्त्र देश है और इसका कोई कारख नहीं है कि इम विदेशी पूँजी के प्रति अब भी प्राचीन भावना को प्रश्य दें। विदेशी पूँजी ते अब किसी मंकार का राजनीतिक प्रभुत्व नहीं ही सकता और न जनतंत्रीय सासन कार्य में किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व नहीं ही सकता और न जनतंत्रीय सासन कार्य में किसी प्रकार का इस्तेच्य ही हो सकता है। इसके साम हो विदेशी पूँजी को भारतीय उद्योग को अपेका किसी प्रकार की अविक सुविशा भी नहीं मिल सकती। भारत की प्रयम्भ पंच वर्षीय योजना में २,३%६ करोड़ रुपया व्यय करने का प्रवन्ध था। इसके अपित क्या व्यय करने का प्रवन्ध था। इसके अपित क्या अपित की प्रवाद करने का प्रवाद की पूर्ण नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त औद्योगिक तथा आपित विकास के लिये मी हमें विदेशी पूँजी की आवश्यकता है क्यो हम की स्वीपति के साम के से इस में है अपित इस अप के विकास के लिये पूँजी की आवश्यकता है और स्वीपति के अप के विकास के लिये पूँजी की आवश्यकता है। भी है।

इधर कल वर्षों से सरकार और भारतीय उद्योगपतियों के सम्पूर्ण प्रयत्नी के पश्चात भी विदेशी पूँजी पर्यास मात्रा में नहीं छा रही है। इसके निम्नलिकित कारण है। (य) भारत में विनियोग के मधिष्य के विषय में अमिश्चितता का यातायरण है। विदेशी पूँजीपति को इस बास का विश्वास नहीं है कि मविष्य में इसकी पँजी सुरक्षित रहेगो। पँजीपति बपया अगाते समय पूँजी की सुरक्षा और उससे लाभ इन दा बातों का विशेष ध्यान रखता है। परन्तु विदेशी पूँ जीपति को भारत के सम्बन्ध में इन दोनों बातों पर सम्देह हैं: (ब) भारतीय पूँ जी की ही तरह विदेशी पूँजी पर लाभ कम होता है क्योंकि उत्पादन व्यय अधिक है श्लीर सरकार ने अनेक अतिबन्ध लगा रखे हैं। पुंधी पर लाभ की दर कम होने के कारश विदेशी पूँ जी स्वामाविक रूप से भारत की श्लोर खाकपित नहीं होती. (स) अतीत में भारत में अधिकतर बिटिश पूँजीशति विनियोग करते वे परन्तु हितीय महामुद्ध के पश्चात से त्रिटेन की वित्त कठिनाइयों के कारण ब्रिटेन का विदेशी विनियाग सब देशों में, भारत को लम्मिलित करते हुये, घटा है। अब ब्रिटिश पंजीवितयों को इमारे देश में विनियंग करने के लिये अधिक घन कमाना सम्भव नहीं है। अम--रीकी पॅजीवित रुपया लगा सकते हैं, परन्तु अभी वह भारत में रुपया लगाने के ब्राटो नहीं हुए हैं। ऐसा प्रतीत हुआ है कि अमेरिकी सरकार विनियोग से पूर्व यह चाइती है कि मारत सरकार श्रमरीका का श्रनुसरण करे। आरत सरकार की विदेशी भीति किसी मी राष्ट्र गुट के साथ सम्मिलित होने की नहीं है। इसलिये भारत की तटस्य नीति से अमेरीकी पूँजी के आने में बाघा उत्पन्न हो गई है।

अमेल १६४८ तथा १६५६ में श्रीचोशिक नीति सम्बन्धी घोषणा में श्रीर

पंचवर्गाय योजना में भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में विदेशी पूँजी को मोस्वाइन देने की आवश्यकता है। संवद में प्रधान मंत्री ने इस विषय पर प्रकाश बाला था कि सरकार विदेशी पूँजी को सभी उत्तित सुविषय और प्रांताहन देने के लिये प्रस्तुत है। विदेशी पूँजी को सहत को बताते हुमें प्रधान मंत्री ने सत्या कि अवीत में विदेशी पूँजी को किय प्रकार उपयोग में लाया गया है उसी के परिवास स्वक्त आवा इस बात पर महत्व दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय हिंत में विदेशी पूँजी के कार्यों हैं कि राष्ट्रीय हिंत में विदेशी पूँजी के कार्यों हैं कि राष्ट्रीय हिंत में विदेशी पूँजी पर त्वान्त्रण एकते का उद्देश यह होना चाहिये कि उसका मारत के अधिकत्तर साम के लिए उपयोग कि सम कि ति प्रकार के प्रशिक्त सक्ता आप के लिए उपयोग कि ति हम कि सम विमान पर देश का विकास करना चाहते हैं उसे पूर्ण कर वर्तों । इसके लिये मारतीय पूँजी के आभाव को पूर्वि करनों के लिय मारतीय पूँजी के आधाव को पूर्वि करनों के लिय परत्वीय पूँजी के साथ ही विदेशी पूँजी के साथ ही हम मार्गीन है कि निकास और होता हम की हम कि विदेशी पूँजी के साथ ही हम मार्गीन हम कि ति हम की स्वार्ग के हम आव हो हम स्वर्ग हम कि हम कार्य ही हम स्वर्गन की हम की हम साथ ही हम स्वर्गन की हम साथ ही हम स्वर्गन की हम साथ ही हम स्वर्गन कर सकते हैं।

प्रधान मन्त्री ने रुपट शब्दों में बताया कि (अ) समी भारतीय अपया विदेशी-उद्योगों को भारत सरकार की आंधोगिक नीति का अनुसरण करना पड़ेगा, (व) सरकार सिदेशी उद्यागों पर इस का कोई प्रतिक्व नहीं लगायेगी और न कोई ऐसी सदेशी उद्यागों पर इस का कोई प्रतिक्व नहीं लगायेगी और न कोई ऐसी सर्वे ही लगायेगी जो अन्य सामान भारतीय उद्योगों पर लागू नहीं हैं, (व) विदेशी कंपनियाँ उन्हों नियमों के आधार पर लाग कमाने के लिए स्वतन्त्र होगी जो अन्य उद्योगों पर लागू हैं, (व) विदे कमी विदेशी उद्योग को सरकार अनिवार्थ कम से अपने अधिकार में लेगी तब उद्यक्त उचित सुन्नावका दिया जावगा, और (व) सरकार की किनाई नहीं है और अरकार विदेशी ह्वान स्वत्रावका स्वत्रावका ने स्वत्रावका की सर्वमान सुविधाओं को लागू रखने में कुछ की किनाई नहीं है और अरकार विदेशी हुना चाहती है और अरकार विदेशी हुना चाहती है। परन्तु लाम का अन्यतान विदेशी दुना-विनियम की स्थित पर निर्मेद करेगा। यह सरकार किसे विदेशी कारखाने को अनिवार्यत अर्थ अपकार में करेगी तो उसके अरव के सुमतान के लिए उचित सुनियम की स्थित पर निर्मेद करेगा। यह सरकार किसे विदेशी कारखाने की अरिवार्यत अर्थ अरकार में करेगी तो उसके अरव के सुमतान के लिए उचित सुनियम की स्थात पर निर्मेद करेगा। यह सरकार किसे आपनान के सिर्मेद पर का स्वत्राव की स्वत्राव

विनियोग को माद्या—मारत ये गत वर्षों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई यो इसके जान के लिए सही आँकड़े माप्त नहीं हैं। एक अनुसान है कि दो विश्व युद्धों के मध्य भारत में ६० करोड़ पीयड़ विदेशी पूँजी लगी हुई थी। एक श्चन्य श्रद्धमान में बताया गया है कि यह पूँजी ८० करीड़ पीएड थी। एसोटिए-. टेड चेन्नर श्वान फामर्ग ने छाड़मन कमीशन को बताया था कि छुल १०० करीड़ पीएड विदेशों पूँजी भारत में क्याी हुई है। यह सम्भव है कि द्वितीय सुद्र है पूर्व ब्रिटिश पूँजी की वापसी ह्यादि के परचात मारत में ३० से ४५ करोड़ पीएड के मण्य विदेशों पूँजी लगी रही।

"पूर्णे देश को ब्यान में रखते हुये स्थित इस प्रकार थी। यू० के० तथा पाकिस्तान भारत के ख़्यां वे (४०८% करोड़ क० तथा २६९% करोड़ क० क्रमका) जब कि यू० एस० प० तथा शेष ख्रन्य देखों के मित्र भारत ख़्यां था। १९६४%-५५ में नमी के १८८ करोड़ क० के ख़्या को व खदावती के कारण भारत बर्मा के मित्र ऋषी हो गया।"

"पर्वाप १६५५ के अन्त में भारत एक साहकार देश या किन्तु १६५७ के अन्त तक देश की स्टिलिश सम्पत्ति घटने तथा यू ० एस० ए॰ अन्तरांष्ट्रीय-मुद्रा कीय तथा अन्तरांष्ट्रीय बैंक के प्रति देवता बढ़ने के कारण वह अन्तरांष्ट्रीय नोहा साथा।

### विदेशी व्यवसाय वितियोग

र्हभूभ के झाल में ब्याजारिक उपझ्यों की कुल देवता भू२२ करोड़ क० व्यापारिक विनियोग था। यह धिनियोग मुख्यता शाखाओं में (equity bolding) था। विनियोग का श्रावकांद्र प्रस्त मुख्य वाले कागातों में (equity bolding) था। विनियोग का श्रावकांद्र प्रस्तव प्रकार का था। विभिन्न व्यापारिक कियाओं के मध्य व्यापारिक विनियोग के वितरण में कुछ महत्तपृष्ट अन्यर हैं। विदेशी शाखाओं ने मध्य व्यापारिक विनियोग के वितरण में कुछ महत्तपृष्ट अन्यर है। विदेशी शाखाओं ने अधिकतर पूर्वी व्यापार, वार्वकांकि व्यापार के अध्यापार के अध्यापार के अध्यापार के अध्यापार के अध्यापार के व्यापार है।

इसमे ज्ञात होता है कि विदेशी विनियोग में प्रत्यब विनियोग का श्रेश मुख्यतः निरेशी कम्यनियो में बहुत बड़ा है। व्यक्तिगत चेत्र में विदेशी विनियोग के विग्रतिपण् से जो कि ४८० ६ करीड़ रुपया का या (श्रीर जिसकी निशेष विवेचना भ्रागे करने जा रहे हैं) बह जान होता है कि निर्माण करने वाले उपक्रमों में सबते भ्राविक धन (१६३ करोड रुपया) लगाया गया था; उसके परचात दूसरा स्थान ब्यापार का है जिनमें १०३ करोड़ कपया लगाया गया या और तीस्सा स्थान रोपण का है जिसमें दान करोड़ करवा लगाया गया था। वेंक, परियहन ग्रीर लात खोदने के उचीगों में भी विदेशी पूंजी लगी हुई है। व्यापारों में जो पूंजी लगी हुई है उसका विश्लेषण निम्न है :--

हुई है उसका विश्लेषण निम्न है :		करीड इपये में
311		\$65.5
निर्माण		१०२'३
		<i>⊏</i> 0.5
बमापार		પૂર્* દ
रोपण		₹£*₹
उपयोगितायें तथा परिवहन		8'3
विच	4	24.8
खानें		कुल ४८०'६
বিবিঘ	_	The state of the s
		त्नी रही। १६५५ के झन्त में
	िकारा चीवा व	ना रहा । २०००

प्शाहुकार देशों में विटेन की रिधति प्रमुख बनी रही। १९५६ के स्नन्त में ब्रिटेन के प्रति रेयना ४०० कराव से अधिक भी तथा कुल विदेशा ब्यापारिक देपताश्रों की ७७% थी। यू एस ए० ने ४५ करोड़ की विदेशी पंजी प्रदान की जिसका अधिकांश पेट्रांखियम में लगाया गया। शेष देशों ने ७४ करोड़ ६० की धनराशि दी जो इमारी विदेशी वित्तीय देवताओं की लगभग आधी है।"

9E8= क्योर 9E8द के सध्य-रिवर्व वैंक की प्रथम रिपोर्ट ३० जूर १६४⊂ तक के लिये थी। दूसरी रिपोर्ट में रिजर्य बैंक ने विदेशी विनियोग के दिसमर १८५३ तक के आंकड़े दिये हैं। उसके अनुसार विदेशी व्यापारिक विनियोग में ३० जून १६४८ से लगा कर ३१ दिसम्बर १६५३ तक बास्तविक वृद्धि १३२ करोड़ कपये की हुई विसमें से ११२ करोड़ समना (अर्थात न्यः%) प्रत्यह विनियोगया जिसका वितरण निम्न है :

# mango

(करोड़ रूपयों में)

नियन्त्रित भारतीय स्वाइन्टस्टाक कम्पनियाँ विदेशी कम्पनियों की शास्त्रार्थे

8.5

"ब्रिटेन ग्रीर ग्रामेरिका के विनियोग में कमशः १३७ करोड़ ग्रीर १३ करोड रुपयों की संद हुई और पाकिस्तान तथा लड़ा का क्रमश: अ करोड़ और २ करोड ४०वा घट गया । विनियोग में वांड का व्यापारों के हस्टिकीश से विश्ले-परा करने पर यह जात होता है कि निर्माण सम्बन्धी चेत्र में ६४ करीड़ क्पये. , ब्यापार में ३० करोड़ रुपये, बागवानी में २० करोड़ रुपये. उपयोगिताच्यों में १६ करोड़ रुपये और शिव्य में ह करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। ब्रिटेन और अमरीका का नवीन विनियोग अधिकांश नियम्बण युक्त या और यदि कल बिनि-योग की बृद्धि से नियन्त्रण युक्त विनियोग का प्रविशत लगाया जाय हो बिटेन का = ५% श्रीर अमेरिका ६१% था। श्रमें का का नवीन विनियोग विशेषकर व्या-पारिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा परन्तु बिदेन का विनियोग भिन्न क्षेत्रों में विभक्त है जैसे निर्माण (५६ करोड़ दपया) शायक्ती (२१ करोड़ दपया), व्यापार (२० करोड़ दवया), उपयोगितायें (१६ करोड़ दपर्यं) और वित्त (१४ करोड़ दपया)। ३० जून १९४८ के परचात् रिकटर की हुई कर्यानयों में लगाई हुई विदेशी पूँजी की मात्रा तेल परिष्कर्राण्यों को छोड़कर जिनमें लगी हुई पूँजी राखाओं में बढ़े हये विनियोग में सम्मिलित की जा चुकी है-लगमग ११ करोड़ रुपये के थी, जिसमें से ७ करोड़ रुपयों का नियन्त्रण विदेशों से होता था। ब्रिटेन से पात पँजी की मात्रा ह करोड़ रुपये के लगमग और श्रमेरिका से मात लगभग १ करोड़ रुपये के ज्ञानमान किया गया या।

१६४३ क्रीर १६४४ के मध्य-बिर वर्तमान मर्बेचण की तुलना १६५३ के सर्वेचण से की लाय तो पता चलेगा कि इन दो वर्षों में विदेशी विनियोग में ६१ करोड़ के की बृद्ध हुई है। ३१ दिवस्तर १६५५ को विदेशी विनियोग की माना १६६६ करोड़ के थी। बुद्धि इस बीच में मूल्यांकन सम्मची कुछ परिवर्तन हुये हैं इसलिये ६१ करोड़ क्या पूँची की यास्तविक गतिशीलता नहीं दिखाते। ऐसे परिवर्तन झाय-ब्य लेखा के चल और अचल रोनों ही प्रकार की सम्पत्तियों में बी सकते हैं।" द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में, ऐसा अनुमान किया जाता है, कि ४२८ करोड़ करवा की बाग्न बहायता प्राप्य होगी। (३८ करोड़ कर १८५६ ५७ में, ४० करोड़ कर १८५८ ५७ में, ४० करोड़ कर १८५८-५६ में)। यदि यह मानलिया जात कि द्वितीय योजना के शेष दो वर्षों में ६०० करोड़ कर की बाग्न खाता कि दिया प्राप्त उपलब्ध शोगों से वृत्युं योजना काला में उपलब्ध शाया १०३६ करोड़ कर की बाग्न होंगी तो व्यक्त करी की सम्बाद्ध स्वापता उपलब्ध शोगों से वृत्युं योजना काला में उपलब्ध शाया १०३६ करीड़ कर होंगी जो वरकारी खेत्र के खिये खनुमानित ८०० वर्ष की शाश्च से २३८ करीड़

वस्यता उपलब्ध होगो तो चंपूर्य योजना काल में उपलब्ध राशि १०३८ करोड़ ६० होगी जो चरकारी खेत्र के जिये श्रामानित ८०० ६० की राशि छे २६८ करोड़ ६० श्रापक होगी। किन्यु मूल्यों के जेंचे होने तथा ब्रिटीय योजना की प्रदेशी विनिमय की आयश्यकता बङ्जाने के कारण विदेशी विनिमय की उपलब्धि का उपर्यक्त बहित माल योजनाशों के लिये सो श्रपर्वास्त खिड होगी।

### अध्याय २६

63

## उद्योगों का स्थान निर्धारण

किसी उद्योग का स्थान निर्धारण अनेक आर्थिक, मनोवैशानिक तथा प्राकृतिक कारणों पर निर्भर होता है। यदि अपर्यक्त निर्भव कारणों से किसी ज्ञतोग की श्रमेक फैकिस्स किसी एक स्थान पर वेस्टित हो जाती है तब वह वरोग का स्थानीयकरण करलाता है। इस सरदन्य में 'वैंदर' का सिझान्त यक दीवों के होते हुये भी सबसे अधिक विचार पूर्ण है। यह सिदान्त आर्थिक कारणी पर भी विचार करना है जैसे उन-मीलों परिवडन स्थय जिसमें माल की मात्रा तथा जसके ले जाये जाने की दरी का पूर्ण विचार रक्खा जाता है। किसी फैस्टी के स्थापित करने के लिये सब से अधिक उपयुक्त स्थान यह है जहाँ पर कच्चे माल तथा निर्मित माल दोनों के ही दृष्टिकोश से दन-मील परिवधन व्यय स्थनतम हो। वैवर ने कच्चे माल को दो भागों में विभाजित किया है (१) सर्वत्र प्राप्य माला जैसे हुँट, मिट्टी, बालू, पानी इत्यादि जो सर्वत्र प्राप्त हैं ग्रीर (२) 'स्थानीय माल' जैसे लीह श्रमस्क, बीवसाइट, चीनी, रुई, कीयला ब्रादि जी विशेष स्थानी से ही प्राप्त हैं। स्थानीय माल को फिर वैवर ने शब तथा चीख-भार नामक दो भागों से विभाजित किया है। शब में पैसी वस्तयें जैसे कपड़ा विनने तथा सत कातने के लिये हुई, सीमेंट बनाने के लिये बाल और चुना ग्रादि की अपने सम्पूर्ण भार से निर्मित माल में मिल जाते हैं, समिलित किये जाते हैं। चीए-मार (weightlosing) माल में वे बस्तवें है जिसका भार छीज जाता है जैसे गन्ना, कोयला श्चादि सम्मिलत किये गये हैं। क्योंकि पहले प्रकार की वस्तुयें सर्वत्र प्राप्त होती हैं इस्लिये उनका किसी उद्योग के स्थान निर्धारण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होला: परन्त विशेष स्थान में प्राप्त होने वाली वस्त का प्रभाव उद्योग के स्थान निर्धारण में बहुत अधिक होता है। इनमें भी वे वस्तुर्ये जिन्हे चील-मार वहा गया है विशेष महत्य की है। इन धरतुश्री का भार निर्मित वस्त के निर्माण में छीज जाता है इसलिये इनका प्रयोग करने वाले उद्योगों की. जहाँ पर ये वस्त्यें प्राप्त हैं. वहाँ फेस्टित होने की प्रवक्ति होती है। वैदर ने 'माल का इस्टेक्स' निर्माण किया साकि उसके भाषार पर यह जात किया जा सके कि कच्चे माल की प्राप्ति का स्थान श्रथवा निमित वस्त के विक्रय का स्थान दोनों में से कौन किसी उद्योग के केन्द्रित होने में श्रिषिक प्रभावशाली कारण होता है। यह 'हन्देनस' स्थान विशेष पर

प्राप्त कब्बे क्राल के मार को निर्मित वस्तु के मार से विमाजित करने ते प्राप्त होता है। यदि 'माल का इन्डिनस' किसी उद्योग के सम्बन्ध में बड़ा है तो इसते वह समसना चाहिये कि कच्चे-माल को प्राप्ति का स्थान अधिक प्रभावशाली कारण है जीर उदोम की स्थापना के लिये वह स्थान श्रविक उपयुक्त होगा परन्तु यदि 'माल का इन्डेक्स' छोटा है तो उसमे यह समझना चाहिये कि कन्त्रेमाल की प्रान्ति कोई विशेष महत्वशाली बात नहीं है और उच्चोग को स्थापना अच्छी

परन्तु जैसा इस सिक्षान्त में बताया गया है उसके श्रनुसार जहीं स्पृनतम प्रकार बाजार के विकट की जा सकती है। परिवहन स्थम हो यहाँ छपेदा उद्योग स्थापित नहीं किये जाते। इसके कई कारण है, जैहे (१) उद्योगपतियों को कच्चे माल की प्राप्ति के स्त्रोती और बाजारों का पूर्व ज्ञान नहीं होता कि वे ठीक-ठीक आवश्यक आनुमस्यन कर सकें होता यह है कि ज्ञीसत दर्जे का व्यवसायी वर्तमान उद्योगों की स्थिति का अनुमान लगा लेता है और जहाँ पर उसकी समक्त में यह झाता है कि यह झिकतम लाम उठा सकेमा वही अपना कारखना खोल देता है। सामान्यतः वे उद्योग जो किसी स्थापन विशेष में केन्द्रित हो गये हैं कुछ ऐसी लामकारी स्थिति वहाँ उत्तन कर देते हैं जिनके कारण नमीन कारलाने नहीं स्थापित होने लगते हैं जितसे वहाँ श्रीर ग्रुपिक स्थानीयकस्या हो जाता है, (२) उद्योगपतियों के समञ्ज स्थान निर्भारण मे सदा आर्थिक ही कारण नहीं रहते। वे सामाजिक सुविधायें तथा जीवन की अन्य सुविदाजी की प्रान्ति का भी विचार करते हैं जो नसरों में सुसमतापूर्वक प्रान्त हैं। इस कारण से भी दे बहुआ बढ़े-बढ़े नगरों में या उनके श्रावदास श्रदने कारखानों के लोलने का निश्चय करते हैं चाहे देवा करने में उन्हें ग्राम में कारलाना खोलने को अपेदा लाग कुछ कम ही वर्गो न प्राप्त हो; और (१) पुड़-काल में हवाई हमला से रचा का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है इनिलये बहुषा उद्योगों की स्थापना खुले हुने नगरों से दूर तथा नदी के किनारों से दूर देश के श्रान्तरिक साग में करना पड़ता है चाहे इसमें ब्राधिक हानि ही क्यों न उटानी पहें ।

प्रमुत्ति-भारत में उद्योगों का स्थान-निर्धारण मृत्रिप्ण है। एक स्रोर 'बार कि वम्बई, पश्चिम बंगाल और विदार में ख्रपेदाहत श्रविक क्रीदोमीकरण हुआ है तो दूसरी छोर अन्य राज्यों से श्रीदोमीकरण के प्रायः सभी साथन होते हुए भी तिश्रोप निकास नहीं हो पाना है। इसके साम ही दूर प्रामी की अपेचा क्ष पहोता में ही उद्योगों के केन्द्रित हो जाने से मारत के बढ़े नगरी का ग्रनुचित प्रसार हो गया है।

-

र वालिका १ भारत के खोशोधिक श्रीधकों की कल संख्या का प्रतिशत

-1160		me me Parce cer	2-11 101 -110-71	
प्रदेश	<b>१६२१</b> %	₹E₹E\$8	\$£8.588	१६५१
बगाल और बम्बई	₹ 5.\$	45.5	₹0.€	48.3
बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश छोर बिहार	दहे•१	€4.€	<b>८</b> %⋅₹	Œ≡·Y
शेप भारत मे	₹₹′€	4818	₹५,4	₹₹'६

क्षश्चिमाजित भारत के श्राँकडे

तालिका १ के खानुसार १६५१ में भारत के कुल धौद्योगिक अभिकों के ५५१३ प्रतिशत बँगाल बीर बनर्श के हो राज्यों में कार्य करते थे ख़ीर प्रताप प्रतान काल, कार्य, करते उ. उत्तर प्रदेश खीर बिहार के पाँच राज्यों में कार्य करते थे। राज्यों में कार्य करते थे। राज्यों में कार्य करते थे। राज्या ख़र्म है कि धौद्योगिक विकास की दिस्ट ते ख्रान्य केन पिछा है दुए हैं जिनमें सुक छीदोगिक अभिकों के केवन ११०६ प्रतिशत कार्य करते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वन्यई खोर वंगाल चीन में कुल छीदोगिक अभिकों की संख्या १६२१ में ६२०१ प्रतिशत थी जो वरकर १९५१ में ५४०१ प्रतिशत हो गई बाद कि महास, उत्तर प्रदेश खोर विद्यार में राज्यो १६२१ में १४०१ प्रतिशत के १४०१ प्रतिशत के एवं प्रतिशत के एवं एक खोगों में कुल खोद्योगिक अभिकों की सर्पा प्रतिशत के प्रत्य चीनों में कुल खोद्योगिक अभिकों की सर्पा राज्या १६२१ में १९५६ प्रतिशत थी जो परनर १६४१ में १५०६ प्रतिशत खोर १९५१ में १९०६ प्रतिशत थी जो परनर १६४५ में १५०६ प्रतिशत खोर १६५१ में १९०६ प्रतिशत हो गई। इसका यह ख़र्म है कि बंगाल खोर वन्धई तथा देश के खार चेना की खप्ता स्वास, उत्तर प्रदेश और तहार से उत्ता स्वासक केन्द्रत हुने हैं।

तालिका २ भारत के कुछ नगरी की जनसख्या

	(61)		
	\$538	\$88\$	१६५१
कलकत्ता	₹3°EE	₹₹*0€	२५.४६
ब स्बई	<b>११</b> -६१	<b>የ</b> ፍ•ይሂ	२८•३६
कानपुर	5.88	<b>γ∘⊏છ</b>	10.04
महास	<b>६</b> ∙४७	<i>৩•७७</i>	१४-१६
दिल्ली	₹"४७	પ્રવ્	€٠₹५

तालिका २ के श्रांकड़ों को देखने से पता चलता है कि १६२१ से १६५१ के बीच के ३० वर्षों में भारत के बढ़े नगरी कलकत्ता और बावई की जन-संख्या में बहुत अभिक वृद्धि हुई है। कलकता और बम्बई की जन-संख्या अपने दो सुने से भी अपिक हो गई है जब कि कानपुर की बन-संख्या तीन शुनी हो गई है। हशका एक कारण तो यह है कि अन्य नगरों की मीति गाँव से लीग आकर इनमें बद्धत गये हैं और साथ ही हम दीनों में उद्यागों के वेल्द्रित हो जाने से भी

्रानियाँ — नगरी और वड़े करवों में उद्योगों के केन्द्रित हो जाने से अनेक जनसंख्या में बृद्धि हुई है। हानियाँ होतो हैं जिनमें से अमुख निम्नलिखित हैं:-(१) इससे जन-संख्या ्राणा । १९८८ में बहुत छांचक वढ़ जाता है और इससे मोड़ एवस विवर्गपत हो जाती है। इतका कनता के स्वास्थ्य पर तुरा क्रमाय पहला है, उसाई नहीं रह दा जापा द। रूपण जापा पर्याप्त १५ जाता है और इन देवों में झनेक समान पाती, रहने के लिए परी का श्रमाव हो जाता है और इन देवों में झनेक समान नागु कर मार्थित होते होते होते लगता है। यदि उचीमों को उचित रूप से शिमन उपयुक्त स्थानी में स्थापित किया जाता तो इनमें से बहुत सी हुराईयों से बचा जा सकता था; (र) उद्योग केवल बड़े कस्बी और नगरों में ही केन्द्रित नहीं हुए हैं बरन फुछ मुख्य प्रकार के उद्योग खास-खास राज्यों में केन्द्रित ुर है। बीनी उद्योग श्रविकतर उत्तर प्रदेश श्रीर विदार में, सूती उद्योग वन्नई, इन्दर्भ जीत अनुसर्वे में, लोहा और इस्थात उसीम निहार में, जूट बनाल न्यन्त्रस्य अरुपार न्युपार क्षेत्र के स्वदानी की उद्याग बंगाल श्रीर बिहार में केन्द्रित हैं। इसका एक कारण तो यह है कि इन चेत्रों में अपने उद्योगों के लिए बावस्पक कच्चा भारत के बात के और दूबरा कारण उद्योगपतियों की बचि भी कहा नाच आर निर्माण का पान ना कहा जा सकता है। इस प्रकार की स्थित से यह हानि होती है कि यदि इनमें से किसी उद्योग में मेदी आ जाये तो उसका उछ च्रेत्र पर बहुत सुरा प्रभाव पक्ता है। यदि जना पर जी में मंदी जा जाय तो इसते उत्तर प्रदेश और विदार की जनता पर चीनी के उद्योग में मंदी जा जाय तो इसते उत्तर प्रदेश और विदार की जनता पर विपाल का पहारु हुट बायगा और बती उद्योग में मदी आगे से बन्नई, मध्य प्रदेश और उत्तर-प्रदेश की जनता संकट में पह जायगी। यदि उद्योग देश में चारी और विवस्ति हुए होते वी शायद यह स्थिति नहीं होती। यह विल्कुल संमय है कि एक उचीम में मंदी आते ही दूखरे उचीम में भी मंदी नहीं आ जाती है और बिद उद्योगी की उचित रीति से सम्पूर्ण देश में फैला रखा हो तो मेदी आने वे उदाम को चति अपेसाइत कम होगी, (३) राही कुछ चुने हुए चेत्रों में उदोगां के केन्द्रित हो बाने से अन्य चिनों की प्रायः उपेत्ता की गाँ है। यह हो सकता है कि शन्य होत्र इनके समान उत्तम सिंद न हो फिर भी उनमें उद्योगों की स्थापना ने कुछ झार्षिक लाम होने की संमानना है। इन चेत्रों को सामाजिक सुविधाओं श्रीर उद्योग के लिए आवश्यक प्राकृतिक साधनों का प्राय: दिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है। इन चेत्रों की जनवा अपेशाकत श्रीषक वेरोजनार है और अंतिका की उपयुक्त क्वरणा न होने ने उनके रहन-गहन का स्वर मी निग्न है। यदि इन चेत्रों में उद्योगों को चालू किया नाता, जैसे उत्तर देशों के दुर्जी जिले, दिल्प मारत और पंजाब के कुछ, रणान, सो देश में उत्तरक साधनों का और अव्वाद उपयोग किया जा सकता थां, (४) हमारे देश में उद्योगों की जैशी कावरणा है वह सुद्धकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। युद्ध के समग क्यानों के इसकी मारी चीत्र होने की उमावना है। यदि उद्योग कुछ स्थानों पर वेजित होने की अपेश्वाद के सिंग में उपयोगों की वेशी कावरणा है वह सुद्धकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। युद्ध के समग क्यानों के इसकी मारी चीत्र होने की उमावना है। यदि उद्योग कुछ स्थानों पर वेजित

आधुनिक प्रश्नति—यद्यार स्थानीकरतः की दृष्टि से मारतीर उद्योग में द्यनेह होए हैं परन्त रचर कल दर्जों से स्थिति में समार रोजे की संभावता दिखाई देती है। सर्वी उद्योग के लिए झारम में बन्धई नगर और असका समीपवर्ती चैन विशेष महत्त्वपूर्ण वसमा जाता या परन्तु बारे-बार मन्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और श्रम्य स्थानों में सदी उद्योग के नये कारखाने खोले गये हैं। इससे बन्दई का महत्व कमरा: कम होता गया। यदाचे बस्बई ऋब भी बहुत महत्त्वपूर्ण रपान है क्रन्य स्थानी ने भी क्षत्रमा महत्त्व बढ़ा लिया है। चीनी उद्योग के सम्बंध में द्यव मी उत्तर प्रदेश छोर विहार प्रमुख है परन्तु सदास, बन्दई छीर भृतपूर्व रियावतों में भी इच उच्चेंग की श्लोर ब्लाकर्पण बढ़ा है। १६३१-३२ में कुल ३२ चीनी के कारखानों में २६ कारखाने उत्तर प्रदेश स्त्रोर विद्वार में पे परन्तु १६५२-५१ में कुल १६४ कारलानों में से इन दोनों राज्यों में केवल ६३ कारलाने ये। १६३१-३२ ब्रीर १६५२-५३ के बीच बदास में चीनी के कारलानों की संख्या २ से बद्ध दर १३, बम्बई ने १ से बदकर १४ श्रीर खरड 'ख' राज्यों में जहाँ एक मी कारलाना नहीं था १२ हो गई। इससे प्रकट होता है कि पदानि उत्तर प्रदेश श्रीर विदार श्रव मी महत्वपूर्ण राज्य है परन्तु श्रन्य राज्यों में भी चीनी के कारखाने खुल गरे है श्रीर उनका मी महत्त्व कुछ बढ़ गरा है।

बहीं तक कामल के उच्चोग का प्रश्न है हमके कारलामों को स्पापना सर्प-प्रथम बेगाल में हुई विजका सुख्य काररा कोवल को पूर्ति की लुक्या थी। कारलानों में कागल बनाने के लिए हिसालय के बहाबी चेजों ते प्राय:६०० मेल दूर ते सवाई पास लाई जाती थी। परन्तु चूँकि एक टन कागल बनाने में दर्श टन बास श्रीर ५ टन कोवले की श्रावश्यकता होती थी। इसलिए कोवले को प्रायमिकता दी गई। कोयले के च्रेत्र के निकट कारखाना स्थापित करना अधिक उपयुक्त समझा गया। परन्तु भीरे-और वॉंध ख्रीर विज्ञा के प्राथीय होने खगा। इससे कागज के कारखाने ख्रम्य स्थानों को हटाये गये। छिमेंट उचोग सबैप्यम मण्य-प्रदेश और राजपूतानां में स्थापित किया गया परन्तु भीरे-और सिमेंट उचोग के कारखाने उन चित्रों में स्थापित किया गया था तो छिमेट का उपभोग करनेवासी च्रेत्र हैं या छिमेंट का उपभोग करनेवासी च्रेत्र हैं या छिमेंट

उद्योगों की स्थानना में उपर्युक्त विवस्त के आनेक कारण है जैसे (१) स्पर्वेशी बाजार का महत्व बहुना, परिवहन की मुविधाओं में वृक्षि तथा देश के आनतिक मानों में हुब्ब वाजार की मुविधाओं की प्राप्ति; (२) उत्पादन मिलिक में विकास के सामा के उत्पादन के उन्धन्य में हुब्ब (३) उत्पादनों का विकास के सामा तथा उद्योगों की स्थापता में मुझार की प्रवास नीति का विवास त्याना तथा उद्योगों की स्थापता में मुझार की प्रवृत्ति लीवा कि विजन्त के उद्योगों में दिलाई पडा है; (४) देशी रियानतों का जो कि 'का राज्य कहनाते हैं उद्योगों को अपनी और आक्रम्ट करने की नीति का अनुत्रस्त करना निकल अनतोत तब प्रकार की मुविधाय प्रदान करना जैसे अम सम्बन्धी उदार-कानून काना, तथा उनकी पूँकी में भाग लेना आहि, और (५) हाल में लागू की हुई उद्योगा को इन्बस्तीन एकर के अन्वर्यंत लाहस्त्म दिये जाने की दरकार की नीति हत्यादि ।

सरकार की नीनि—१६५१ के उद्योग (विकास एवम् नियम) कातृत के आतुक्तर भारत सरकार को उद्योग के स्थान-नियमित्य पर पूरा नियम्या रखने का आविकार है। कारखानों के अपनी रिकार्य करनी पकरी है और अपना उरवाइन या उरवान ग्राक्त में चृष्टि करने ये पूर्व आवश्यक आवुमित लेनी पकरी है। मारोक औरपीतिक इनाई अपना कानखाने के पान लाइनेन होता है। लाइनेन्न दोन बाली मिति लाइबेंस देते समय उद्योग कानृत के अतर्थत कारखानों के आकार-मकार और स्थान इत्योद का निर्मेश्व नियस्य देती है। चीनी के कुछ कारखानों की अवुक्त रापनों निया इंटाने के लिए यह प्रिमेशित पहले ही अपनाति दे सुकी है और सुती मिलों को करने की जुनाई के लिए वहीं नयी शाखा खोलने की अनुमित देना अस्वीकार में कर बहुता है।

कुछ उथोगों का लाइकेन्स इसिलये अस्तीकार कर दिया गया है कि जहां नगा कारखाना खोलने का निश्वत या वहां पढ़ते ने ही अधिक कारखान या तो रिषत में अपया जो स्थान आवेडन पत्र में कारखाना खोलने का बताया गया था लाइकेन्स देने वाजा समिति द्वारा उपयुक्त नहीं समक्र गया। लाहकेन्स देने में उन आवेदनों को प्राथमिकता दो बाती है जो किसी नये उपयुक्त स्थान

नीति का उद्देश्य बड़े करवों और नगरों में उद्योगों के अधिक जमाव की घटाना है। सरकार का जरेंच्या है कि जिल राज्यों में पहले ही उपीनाकत साधिक

कारकारों कोले जा चने हैं वहाँ और व्यक्ति कारकारों को स्थापन न होने हिया

जाय । इसके विपरीत सबे कारम्बानों को जब सेवों की खोर ध्याक्रफ किया जाय

जिसका ग्रामी विकास नहीं हथा है। परस्त भारतीय उद्योगों के जन्मि स्थानीय-करण की समस्या केवल लाइस्टेन देने की ब्ययस्था से ही इल नहीं की जा सकती

है। उरोगपति पिछडे ४० छोर कम विक्रित सेक्षे में २० कारखाने खोलना नहीं चाहते हैं इसका एक कारण तो उनकी पूर्व धारणा हो सकती है परन्त बास्तव में बात यह है कि इस लेजों में उद्योग स्थापित करने के लिए न विजली की सबिधा मिलती है, न कब्चे मान की और न उपसुक्त अम की। इन पिछड़े श्रीर विकति चेत्रों की श्रीर उद्योगों की आश्रष्ट करने के लिये यह श्रावश्यक है कि (१) इस तेथे। का विकास किया जाय जिसमें उद्योगपति इसकी छोर ग्राकण्ट हो सर्वे थ्रौर (२) ब्रारम्भ मे उद्योगपतियों को कम से कम कछ मविधार्ये ही जायें. जैसे मूमि रियायती दर पर टी जाय, रेलवे का भाड़ा कम किया जाय. श्रीर जहाँ ब्राइप्यक हो जबत तथ्य से सहायता की खाय । मारत में उद्योगों के स्थान-निर्धारण की समस्या तभी इल की जा सकती है जब सरकार इन सब वालों को

ध्यान में रखकर एक उत्तरात्तर विकासमान नीति अपनाये।

पर कारखाना खोलने के लिये होती है । उद्योगों के स्थान-निर्धारण की सहकारी

भारतीय सर्वेशस्य की सम्बद्धाँ

2146

#### ग्रध्याय २७

## युक्तिकरण

युक्तिकरण् उच्चोग की कार्यव्यस्ता में वृद्धि करने और उत्पादन २०४० को मदाने की लग्बी प्रक्रिया है। किवी उज्जोग के युक्तिकरण्यों से आभागय यह है कि काराजा में प्रतान के लिए अम बचाने के उपयो तथा रच्चालित मशीनों का उपयोग किया जाए और उच्चोग को व्यर्थ की प्रतिमेशिता से बचाने के लिए उनके संगठन में मुचार करके सभा उचकी क्षावरण को वैज्ञानिक आधार पर समाजित करके उत्पादन कार्य की गति में वृद्धि की आयं। ''शुक्तिकरण्य का अर्थ यह है कि कार्य करने की प्राचीन परिपादी, निश्चित करन तथा अनुप्रविक्ष नियमी और शोधमां के स्थान पर पैसे देंग का प्रयोग होने लगे को कि वर्षों के व्यक्ति करने की प्रयोग होने लगे को कि वर्षों के स्थान पर पैसे देंग का प्रयोग होने लगे को कि वर्षों के व्यक्ति करने का स्थान हो तसने की अर्थ का प्रतान की अर्थ का स्वत्त करने का है विसर्ध कि उत्पत्ति के प्रयान की अर्थक इक्ताई का अधिकतम कासकारी परिवास हो।"

युक्तकरण का उद्देश्य उत्पादन-क्यय घटाना, उत्पादित यस्तु की प्रकार में युवार करना और उत्पादक को हानि उठाने से अवस्ता है। यदि उत्योग का प्रकथ उदिन रीत से किया नाय तो युक्तिकरण उपभोक्ता तथा भाभनों और उत्पादकों के लिए लाभकारी छिब होगा। पण्यु वास्तव में यह देखा गया है कि युक्तिकरण से मात लाम को उत्पादक स्वय ले लेते हैं और वस्तुकों की मकार में सुधार करके तथा मूल्यों में कमी करक उपभोकाओं और पारिभमिक बहाकर भामकों को लाम नहीं उठाने देते। अभिक युक्तिकरण का विरोध करते हैं, हक्की सीना से उनमें अर्थनों पे किया के अन्य प्रवादों होता है। सीना से उनमें अर्थनों के अर्थन प्रवादों के स्वाक्तिक स्वाति हैं कि स्वाक्ति स्वाति से साम अर्थन वे के अर्थन प्रवादों के प्रवाद प्रवादों के प्रवाद प्रवादों के प्रवाद प्रवाद कि स्वाक्ति से साम अर्थन वे के अर्थन प्रवादों के अपनाकर और पुरानी मधीनों के स्वान पर नवीन आधुनिक मधीनों का उपयोग कर अनेक अधिकों को बेरोकतार कर दिया जाए। हथी कारण धनिकों ने मारा युक्तिकरण का विरोध किया है। अध्यत्ने की यह सौंग वहुत कुछ न्यार प्रवाद की स्वाक्ति की स्वाति से युक्तिकरण का वह पूर्व लाम नहीं उठा सके हैं। परन्यु परि उदाने के प्रकार के प्रविक्तरण का वह पूर्व लाम नहीं उठा सके हैं। परन्यु परि उदाने के प्रविक्तरण का वह पूर्व लाम नहीं उठा सके हैं। परन्यु परि उदाने के प्रविक्तरण का वह पूर्व लाम नहीं उठा सके हैं। परन्यु परि उदाने के प्रविक्तरण का वह पूर्व लाम नहीं उठा सके हैं। परन्यु परि उदाने के प्रविक्तरण का वह पूर्व लाम नहीं उठा सके हैं। परन्यु परि उदाने के प्रविक्तरण का वह पूर्व लाम नहीं उठा सके हैं। परन्यु परि उदाने का प्रविक्तरण का वह पूर्व लाम नहीं उठा सके हैं। परन्यु परि उठा के प्रविक्तरण का वह पूर्व लाम नहीं उठा सके हैं। परन्यु परि उत्तान कर स्वति के प्रविक्तरण का वह पूर्य लाम नहीं उठा सके हैं। परन्यु परि उत्तान कर स्वति के प्रविक्त कर स्वति के प्रविक्त कर स्वति के आप उत्तान कर स्वति के प्रविक्त कर स्वति के प्रविक्त कर स्वति के प्रविक्त कर स्वति के स्वति के प्याप कर स्वति के स्वति क

पर वस्त मिल सन्ती है तो फिर आंग्रको द्वारा इस प्रक्रिया के विरोध होने का हों) करणा नहीं रह जाता । यहे पैमाने के उत्योग केवल यक्तिकरण के दारा दी उसनि कर सकते हैं और तसी अधिकों तथा उपभोक्ताओं की स्थिति सधर सकती है। जह मत्य है कि यक्तिकरण की योजना लाग करने में आउम्म में अब बेरोज-मारी फेलतो है परन्त उत्पादन स्थय और यस्त का सस्य कम हो जाने से भविष्य . में उक्सोकाओं को साँग में विदे होगी। इस माग की पति के लिए उद्योग में श्रीर श्रधिक लोगों को रोज़ी मिलेगो। इससे स्पष्ट है कि यक्तिकाण योजना लाग होते से फैनने बाली बेरोजगारी शहपकालीन होती है श्रीर उद्योग के उस्ति करने क माथ इसे दर किया जा सकता है। समस्या वास्तव में अमिक की श्राय श्रीर उद्यानहरून के हैतर की है। यदि यक्तिकरण के साथ पारिअमिक में भी वृद्धि होती है की इसमें अभिकों की छात्र में बढ़ि होती है और रहन-सहन के स्तर में भी सधार होता है। इस रूप में इस प्रक्रिया का उद्योग चेत्र में स्थागत करना चारिता। बात में यह एक महस्वपर्ण एवम विचारगीय प्रश्न है कि यदि भारतीय प्रजोत का ग्रस्तिकरण न किया गया तो विश्व बाबार की प्रतियोगिता में यह विवेको की ससंगठित उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकेगा। यदि अधिक व्यक्तिकरण का विरोध करते हैं तो इसका एक ही परिजाम हो सहता है कि अनेक कारखाने नष्ट हो जाएँगे, उनकी बन्द करना पड़ेगा ख्रीर इससे अनेक धमिक देशेजगर हो लाएँगे। गस्तव में हमारे सम्मल दो स्थितियाँ हैं कि या तो इस इस बात का समर्थन करें कि अधिकरण की योजना लाग कर अमिन। की सनियोजित प्रयम नियंत्रित आधार पर नीकरी से प्रथक किया आग्र और क्रमशः नवीन कार्यों में स्थान दिया बाए या कही प्रतियोधिता का सामना न कर सकते के कारण खानेक कारखाने बन्द करके बड़ी संख्या में अभिकों को बेरोजगार होने दिया जाए । इमारे चम्मूख समस्या रोजगार श्रोर बेरोजगार की नहीं बल्कि एक प्रक्रिया लागू करने से थोड़े शमिका की थोड़े समय के लिए बेरोजगारी श्रीर दूसरी प्रक्रिया द्वारा प्राय: सभी अमिकों की अधिक समय तक वेरोजगारी की है। इमें इन दो प्रक्रियात्रों में से एक को जनना है।

मारत में जब धक उत्पादित माल की खपत संगय यी और पूर्ति के अमाप के कारण उपभोक्ताओं के विभिन्न वस्तुओं के लिये अपिक मूल्य देना पड़ता था तब तक अक्तिकरण की समस्या सम्मावता इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। यदि बस्तुओं का मूल्य अपिक रहता तो मिल मालिकां को अक्तिकरण की आवश्यकता का अन्तुमय नहीं होता। मिल मालिकों ने पति महीन अपिक व्यक्तियों को कार्य में लगाया और पुरानी तथा न्यर्थ हुई भशीनो से कार्य लेकर भी लाम उठाया। परनु जब से बाजार में बस्तुओं की पृर्ति में बृद्धि हुई है और उपमोक्ता बस्तुओं का अधिक मून्य देने को प्रस्तुत नहीं है तब से युक्तिकरण्य को आवश्यकता में का अधिक मुन्ति होती वा रही है। मिल मालिक अपना आवश्यकता से अधिक अमिकों को निर्दे होती वा रही है। मिल मालिक अपना आवश्यकता से अधिक अमिकों को मात है राक्ति में असमार्थ है और किमोकों के स्थान पर मशानों का उपने मात है। यदि उपनोक्ता नहीं का अधिक मूल्य देने को अद्वात मिला में हो यदि उपनोक्ता उसके लिए प्रस्तुत नहीं हैं। ते। यह हिमति उपन नहीं है। तो यह हिमति उपन नहीं है। तो यह हिमति उस्तु का मूल्य कम करने के लिये उत्यादन-अपन कम करने इस्तिस उसपारित वस्तु का मूल्य कम करने के लिये उत्यादन-अप कम करने इस्तिस उपनो लाम के अंग में बृद्धि करने की हिंदि से उत्यादक को युक्तिकरण का अर्था में बृद्धि करने की हिंदि से उत्यादक को युक्तिकरण का सहारा होना पहता है।

श्रीयोगिक विकास समिति की योजना—श्रीयोगिक विकास समिति
श्रीयोगिक विकास समिति की योजना—श्रीयोगिक विकास समिति
ने १६५१ के श्राटम्म में युक्तिकरण की शमस्या पर विचार किया श्रीर इस बात
की स्थीकार किया कि उत्पादन क्यय पटाने और मारतीय उद्योग की कार्य जमता
की स्थीकार किया कि उत्पादन क्यय पटाने और मारतीय उद्योग की कार्य है।
में दिन करने के लिए युक्तिकरण श्रावयण है। एक्सु समिति ने इसके ताम ही
सुद्ध बात को मी माना कि अभिकों के हितों की रच्चा करना श्रावयण है।
सुक्तिकरण की प्रक्रिया को तीव यति से नहीं लागू किया जाना चादिय। समिति ने
सिम्निलितित नियाप किए।

(१) पुक्तिकरण योजना लागू करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इससे (१) पुक्तिकरण योजना लागू करने से पूर्व यह आवश्यक की कार्य कार्यनाई केरोजगार होने वाले अभिकों की संख्या यथासम्मन कम करने के लिए कार्यनाई की जाने आहे पुक्तिकरण के फलस्वरूप होने वाली खरनी और वेरोजगारी को कम करने के लिए समिति ने यह सुकाव दिये है कि (अ) कर्मवारी का मृत्यु, पर-करने के लिए समिति ने यह सुकाव दिये है कि (अ) कर्मवारी का मृत्यु, पर-करने के लिए समिति ने यह सुकाव दिये है कि (अ) कर्मवारी को मिना वेरत जाय, (व) अन्य विभागों म कार्य करने वाले अविशेषक कर्मवारियों की विभाग वेरत जाय, (व) अन्य विभागों म कार्य करने वाले अविशेषक क्रेने कार्य है कार्य देया जाये, में कमी किए इसे और विशा वाले करने वाले कर्मवारियों को उचित्त मुझावाजा दिया जाये (व) स्वेष्का ते कार्य ओडलों वाले कर्मवारियों को उचित्त मुझावाजा दिया जाये और (ए) टेक्निकल सुवारों के कारण बेरोजगार हुवे अभिकों को लगाने के लिये और (ए) टेक्निकल सुवारों के कारण बेरोजगार हुवे अभिकों को लगाने के लिये और संमद हो कार्य में वृद्धि की जाय।

बहा समय हा काव अ पाक का जान।

(३) प्रति इकाई उत्पादन की स्टैन्डर्ड मात्रा निस्चित की जानी चाहिये

की स्वीमकों का प्रमाचीकरण होना चाहिये। यदि किसी प्रकार का सत्मेद हो तो

की स्वीमकों का प्रमाचीकरण होना चाहिये। यदि किसी प्रकार का सत्मेद हो तो

उसकी जीच होनी चाहिये और स्टैन्डर्ड दोनों पत्नों के विशेषकों हारा तिक्षित किया

उसकी जीच होनी चाहिये और स्टैन्डर्ड दोनों पत्नों के विशेषकों हारा तिक्षित किया

उसकी जीच होनी चाहिये और स्टैन्डर्ड दोनों पत्नों के विशेषकों हारा तिक्षित किया

जाना चाहिये।
(१) सम्बन्धित उद्योग की रिवांत और कार्य की सात्रा इत्यादि को और
समान उद्योगों के ब्रह्मकों को ध्वान में रखते हुये नई मकार की मधीनों को
समान उद्योगों के ब्रह्मकों को ध्वान में रखते हुये नई मकार की मधीनों को

लगाने से उत्पन्न टेकनिकल परिवर्तनों का कुछ समय तक परीइस किया जाना चाहिये।

- (४) जिन श्रीमकों की खुटनी की जाय उनके पुनर्वास के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। श्रीमको को ट्रेनिय देने श्रीर ट्रेनिय की श्रावध में जीवन-निर्वाह की ब्यवस्था करने की योजना मालिकों तथा श्रीमकों द्वारा संयुक्त कर से निर्माण की जानी चाहिए।
- (५) वेतन ख्रथमा पारिअमिक में वृद्धि करके अमिक को मी युक्तिकरण के साम में से भाग देना चाहिए।

इस योजना में युक्तिकरण के महत्व पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है परम्य उसके बुध्यरिणामों जैसे बेरोजगारी, अमिकों का शोपण और अधिक कार्य लेकर भी बेतन में शुद्धि न करने की समस्या को टालने का प्रयक्त किया गया है ! मालिकों तथा अमिकों के प्रतिनिधियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। विभिन्न राज्य सरकार अपने-अपने चेत्रों में उसे समस्या पर त्रिदलीय अम सम्मेलनों में प्रवास कर राज्य प्रयक्ति स्वास पर विवस्त अम सम्मेलनों में प्रवास व्यागया है और त्त्री तथा चीनी उद्योग के सुक्तिकरण का विशेषकों ने स्वानिक आधार पर आध्ययन किया है।

के निर्मायों में दिये गये िक्कान्तों के ब्राधार पर ही भारतीय उद्योगों में अभिकों की छटनी की जाती है। इन्हीं िक्कान्तों के ब्रनुधार यह निश्चय किया जाता है कि किछ मकार ब्रीर कितने अभिकों की छटनी की आया। पंचम्यायालय के निर्मयों में कहा गया है कि छटने। करने का पूर्ण उत्तरदाभिश्य उद्योग के व्यवस्थापकों पर है। यदि उद्योग के व्यवस्थापक मुक्तिक त्या अथवा बचत करने या अम्य पर्योत कारणों के आधार पर यह छिद्ध कर देते हैं कि छटनी की जानी चाहिए तो इसके परचात इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि किसी ग्रीमा तक छटनी की वायगी; इस वियय में इस बात पर भी निचार किया जाना चाहिए कि क्या स्थानमा वाहिए कि क्या अम्यन्तित उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो छटनी नहीं कर रहे हैं। छटनी करने के परिणाम स्वरूप बचे हुने कार्य करने वालों पर कार्य भार बढ़ाना मिल मालिकों को अभिकों के प्रति अनोति जीर अन्याय तथा स्थार्य का एक उदाहरण है। छटनी करने की अप्रति वेक्ता तभी दी बाती है जब यह खिद हो बाता है कि ब्यवस्था-पत्नों की मींग न्यायसंगत है, उत्यक्ता उद्देश्य अनुचित स्वार्थ ग्राधन नहीं है और किसी ग्राउ है इस्ट की पूर्ति के लिए छटनी नहीं की जा रही है।

इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि छटनी लागू करने में व्यवस्थापको को दो महत्वपूर्ण सिद्धान्ता को मानना पढेगा-(१) नई भर्ती के अभिक की खुटनी पहले की जायगा और (२) यदि उद्योग में नई भर्ती हो और यदि लटनी में निकाले अये योग्य श्रीमक प्राप्त हो सर्कें तो नियक्ति में उन्हें प्राथमिकता री जायगी। श्रयोल पंचन्यायालय के निर्श्यों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कोई कथानी केवल लाभांश कम हो जाने के कारण श्रपने अभिकों की छटनी नहीं कर सकती है यदि बाजार में उत्पादित माल की माँग कम है या करते माल के अभाव के कारण व्यापार में श्रान्यकालीन गतिरीय श्रा जाय तो हैसी स्थिति में मालिक को अमिकों की छटनी कर उनकी आय छीन लेने की अनम्बि नहीं ही जा सकती है। यदि हलांग अथवा कम्पनी के स्थायी आवेशों में व्यवस्था हो तो मालिक ऐसी स्थिति में मास में कुछ दिन कारखाने में बैठकी करा सकता है। स्थायी आदेशों के अनुसार बैठकी कराने से ३३ वीं पाग का उल्लंघन नहीं होता है। बाटे पर चलने वाले कारलाने को बन्द कर देने का मालिक को परा ऋषिकार है परन्त यदि पचन्यायालय के सम्मूख मामला प्रस्तुत होने की श्रावधि में ऐसी स्थिति था जाय तो कारखाना बन्ट करने के लिए न्यायालय से श्रानसति लेसी श्रावण्यक है।

प्रपीत पंचन्यावालय के निर्णयों के आधार पर विकसित मणाली काफी धंवोधनमक रही है परमू अमिकों की शिकायत है कि (आ) मालिक अपनी रियति का हुरुपोंग करते हैं और आवश्यकता न रहते हुए भी अमिकों की छटमी की जाती है और (व) स्वये काफी वही खंडया में अभिक ने दोखारा हो गये हैं। इसके विपादी सालिकों की शिकायत है कि उन पर अनेक ऐसे मितिकश्य लगामें गये हैं किसे उत्तरात सालिकों की शिकायत है कि उन पर अनेक ऐसे मितिकश्य लगामें गये हैं किसे उत्तरात हमा कि सालिक की शिकायत है कि उन पर अनेक ऐसे मितिकश्य लगामें गये हैं किसे उत्तराद क्या को कम नहीं किया था। यका है और आवश्यक्त म रहते हुए भी उन्हें अधिक अमिकों को कार्य पर लगाये रखना पहता है।

सरकारी नीति—भारत सरकार की नीति युक्तिकरण को प्रोध्माहित करने की है (छ) यदि किसी उत्पादन इकाई के मालिक और अमिक दोनो परस्पर इस बात को स्थीकार करते हैं अथवा (थ) औरवोधिक दिकास समिति की योजना के अनुसार युक्तिकरण आवश्यक्ष है और अपील पंज्यासालय के निर्वापों के अपुक्त है। इन निर्मायों में यह भी दिया हुआ है कि अधिक को अल्काल के लिये कार्य से पुणक कर देने के बदले में अथवा खुटनी कर देने के बदले में इस्ताना देना पश्चमा। अब सक कोई मिला सालिक आवश्यक इस्ताना देता है और दी हुई संपूर्ण बातों को संबोध्य करता है तो युक्तिकरण में कोई आपति नहीं को जा फक्ती। मार्च १९५५ में लोक स्थान करता हैता युक्तिकरण में कोई आपति नहीं को जा फक्ती। मार्च १९५५ में लोक स्थान करता हैता युक्तिकरण में कोई आपति नहीं को देशमुल ने केन्द्रीय सरकार के बजट पर वादविवाद का उत्तर देते हुये कहा ग्राकि:---

"संगीत उद्योगों में २५ लाख से कुछ थोड़े से अपिक व्यक्ति लगे हुये हैं जिनके सम्बंध में युक्तिकरण का प्रश्न उठाया जाता है। यह तो सर्विदित है कि उद्योगों में रोजगार के अवसरों की पर्यात वृद्धि किये विना कुशल व्यवस्था की मृष्टित बहुने के कारण तथा जन संस्था की पृष्टित के कल्लाव्य अमिकों की निरन्तर बहुनी हुई सस्या के कारण देना परम्पत्त न से कागा। इसके अतिरिक्त प्राम्भ आर्थिक व्यवस्था के अस्वगंत अगर्वित संस्था में ऐते व्यक्ति भी हैं जिन्हें पूर्ण युक्ति में स्थान अस्य के अस्वगंत अगर्वित संस्था में स्थान स्थान के स्थान स्थान के मौद्योगिक मौद्योगिक विकास के मित्र अपूर्य स्थान के प्राप्त है। इस बात से तो सभी सहस्य होंगिक मौद्योगिक विकास के मित्र अपूर्य होंगि के मौद्योगिक विकास के मित्र अपूर्य होंगि विश्वस है कि युक्तिकरण द्वारा अस्थानी हुए से स्थानास्यरित व्यक्तियों को जो ज्ञांति होती है यह जनता के हित के लिये आर्थिक व्यवस्था के असार की नीति बारा पूर्ण हो जाती है। यह स्थान एक और उद्याहरण है जिस धार्मांकक न्याय की वौद्धिनीयता को आर्थिक महत्वा के आर्थ कुकान पढ़ता है?"।

"समासदा को यह तो जात होगा ही कि हाल में ऐसे कानून बना दिये गये हैं जिनके अन्तर्गत अभिकों को अवकाश माप्त करने पर सहायता तथा कार्य करने के काल में यदि अस्थायी रूप से कार्य से प्रथक होना पड़ तो भी उसका हरनाना दिया जायगा । समा सदी को समस्या होगा कि एक उद्योग विशेष में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि सरकार ने लोक सभा की बैठक का समय न होने के कारण श्रय्यादेश द्वारा इन कानुनों को प्रचलित कर दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार ऐसे अमिकों के हित की रहा के लिये जो छटनी के अन्तर्गत आ गये हैं बहुत अधिक महत्य देती हैं। मैंने पहिले भी कहा है कि अस्थायी रूप से अपने कार्य पर से हटाये हये अभिकों की कठिनाइयों की दर करने के लिये जा कुछ सम्भव हो, किया नाना चाहिये, पर मेरा मत है कि हमें ऐसी नीति का अनुसरण न करना चाहिये जिससे प्रीशोगिक विकास अवस्त हो साय और कार्य करने के द्यवसरों का विकास भी क्क आया किसी भी समय इर उद्योग में रिभिन्न ज्ञामता बाले अनेक उपक्रम उत्पादन-कार्य करते रहते हैं। उनमें से कुछ तो हाल में ही आरम्भ किथे हुये होते हैं या आरम्भ होते रहते हैं, कुछ में प्रसरण और कुछ मे र्गेकुचन की प्रवृति लातित होती है और कछ की ऐसी स्थिति होती है कि उनका अन्त होता रहता है। इसलिये उद्योग के समुचित विकास और वृद्धि के लिये यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक उपकम द्वारा अपनी परिस्थिति के अनुसार नियक्त अभिकों

की संख्या के सम्बन्ध में कुछ लोच अवस्था रहे। हमें कुल कार्य करने के अपनारों के योग पर निरोध ध्यान देना चाहिये। यह नीति को अपने आश्वासनों द्वारा छड़नी असंभय करती है नये दंगों से अन्य उपकारी द्वारा उत्तरी असंभय करती है नये दंगों से अन्य उपकारी द्वारा उत्तर द्वारा देश की आधिक ब्यवस्था को निर्चय ही रोक देगों और संभवतः उत्तर द्वारा देश की आधिक ब्यवस्था को जिसमें अभिक अवस्थ संभावित हैं उन्तर कि जुलना में किसे सचाने का प्रयुक्त किया जा रहा है कही अधिक सुत्र पहुंचातीं?

मारत के वित्त मन्त्री द्वारा स्थिति का यह ऐतिहासिक वर्षन हर बात को स्पष्ट करता है कि हमें एक या दो उपकमों में छटनी किये जाने में चिनितत नहीं होना चाहिये, हमन हमें सम्प्रां स्थिति को वित्तृत हाँ एक छिये हमें वित्तृत नहीं हों प्रांच हमें तो खुक्तिकरण हमारे लिये (१) बढ़ती हुई जन-संप्या के तिये यदि हम ऐसा करेंने तो खुक्तिकरण हमारे लिये (१) बढ़ती हुई जन-संप्या के तियं कार्य के अववश प्रदान करने का, (२) श्रीमां की आय नया उनके रहन-सहन के तत्र को बढ़ाने का और (१) उद्यागों की उत्पादन लागत कम करने तथा प्रौदीगिक विकाश निरुचय करने का लाधन होगा। परन्तु यह आवश्यक है कि व्यक्तितत श्रीमकों की आवश्यक कठिनाहया से रहा की जाय। हस संवय में कार्य के है एयक किये जाने पर हरताना देने का कार्यन हारा ही प्रवन्य कर दिया है और उस श्रीमक विशेष के लिये अन्य कार्य कार्य है के बता भी हि एक किये जाने पर हरताना देने का कार्यन हारा ही प्रवन्य कर दिया हो और उस श्रीमक विशेष के लिये अन्य कार्य कार्य है जे का मी प्रयस्त किया जाना चाहिये।

स्ती मिल ख्योग—१८२६-२७ में प्रशुक्त भरडल ने हम और ध्यान आकर्षित क्या कि स्ती मिल उदीन में आवश्यकता से अधिक पूँजी एकन हो रही है और उदमें खावश्यकता से अधिक अधिक लगे हुए हैं। वीहें के करवन्। उत्तर १६१७ और १६२१ के मध्य उदोग की कुल पूँजी २० "८४ करोड़ से बढ़ कर ४० "९८ करोड़ हो गई जो उत समय उदोग को मधान हरवादि संगरित के रेसते हुए वहुत अधिक थी। वोह इन सम सातो का अध्ययन कर इस परिणाम पर पहुँचा कि मास्तीय स्ति मिलो में अम का पूर्ण उपनोग नहीं किया वा रहा है। मारत में एक अभिक १८० तकुआं में कार्य करता है जय कि आधान का अभिक १४० तकुओं में कार्य करती का आधाक हा अधिक ११० तकुओं में कार्य करती का अधाक ११० तकुओं में कार्य करती का अधाक ११० तकुओं में कार्य करता है। मारत में प्रशुक्त के सात्र अधिकत र को दें जय कि इनकी सक्या जागान में २१ ब्रिटेन में ४ से ६ और अमरीका में ८ हैं। महास्त में सात्र में सारत में सात्र करती है। महास्त में सात्र करते के कारण मारतीम सात्र मिलो में लागु तरा वोग ने लोड़ की कुछ मिलो में लागु करने के स्थान पर दें। कात्र वेशी मधीन सत्र वाना की विशेषता यह भी कि एक स्वित रक्ष के स्थान पर दें। कात्रने की मधीन स्वीपरा और

एक युनकर रो के स्थान पर ३ या ४ कर्षे बलायेगा। परन्तु अभिको ने इस योजना का विरोध किया और इसे लागू नहीं किया जा सका। १६३२ में जींच करने के परचात् प्रशुक्त मस्टल ने पता लगाया कि यदि यद योजना लागू की गई होती तो उत्पादन व्यव में १७ से २० प्रतिशत तक कभी हो जाती। वती मिल उद्योग ने उत्पादित वस्तु के प्रमाणीकरण, क्रय और विकत, व्ववश्वाध मु गुनंसाठन और आर्थिक द्रिट से अनुषमुक्त भशीनों को अलग करने के लिए ७ भैनेतिन एकेंन्सियों को एक में एकजिंग करने की योजना निर्माण की। इन एकेंन्सियों के पास १४ मिलें थीं। इस योजना में यह ब्यवस्था की गई भी कि प्रत्येक मिल को पूर्व निर्भारित मूल्य पर ले लिया जायगा, मूल्य साधारण शैपरों में दिया नायगा, न विके हुये माल का स्टाक बाबार माल पर क्रय कर लिया जायगा और नाम के लिए कुक्त धनराशि नहीं दी जायगी। परन्तु पिच के स्रभाव के कामण स्थेत नाम के लिए कुक्त धनराशित नहीं दी जायगी। परन्तु पिच के स्रभाव के कामण स्थान का प्रतिवादन नहीं की जायगी। परन्तु पिच के स्थान

इन योजनाओं के विकल हो जाने पर भी सती मिल उद्योग ने निरन्तर युक्तिकरण योजना लाग करने का प्रयक्ष किया है। बावई अस समिति हारा प्रचलित की गई प्रधनावली के उत्तर में बस्बई मिल मालिक संघ ने बन कात पर महत्व दिया कि भारतीय उद्योग ने उत्पादन में सभी आधुनिक उपायों की आपनाया है। अनेक सती मिलों की पूँ जी भी घटाई गई और १६२७ और १६४० के बीच सुतो मिल उद्योग ने प्रशुक्त भएडल के मुक्ताव के अनुसार मोटे और परिया प्रकार के कपड़े के स्थान पर अच्छे प्रकार के कपड़ों का उत्पादन बहाने की नीति अपनाई। परन्तु इस सुधारों के होते हुये भी सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादन बमता कम है और उसके अकिकरण की आवश्यकता है। सूती मिल उद्योग सम्बन्धी विकिंग पार्टी ने १६५२ में यह पता लगाया था कि लगभग १५० वर्तमान खती मिलों जो कि कुल मिलों की संख्या की लगभग ३३ ६% थीं, आर्थिक हिन्द-कीय से अतुपयुक्त और दीन खमता बाली मिलें थीं । ब्लोरूम के बाइन्डिय विभाग में तथा रंगाई विमान में जिन मशीनों का प्रयोग हो रहा है वे अनुपयुक्त यीं। इस प्रकार कर्षों की संख्या के सम्बन्ध में जो प्रत्येक श्रमिक की देखरेख में था वर्किंग पार्टी ने पता लगाया था कि दिल्ली की एक मिला में और मद्रास की दो मिलों में स्वचालित कर्षे ही लगाये गये हैं और एक एक बिनने वाला अमिक ४, ६, ⊏ और १६ कथों पर कार्यकरता है। अहमदाबाद की एक मित्र में १८ कर्षों पर एक श्रमिक और बम्बई की एक अन्य मिल सें ६ कर्षे पर एक श्रमिक कार्य करता है। फिर भी अधिकांश मिलें उत्पादन चमता में हीन हैं और पुरानी मशीनों का प्रयोग करती हैं।

विक्क पार्टी इस निकार्य पर पहुंची कि उन मिलो का कार्य जो स्वचालित कर्यों का प्रयोग कर रही है उंतोपननक हैं । अन्य मिलों में भी स्वचालित कर्यों के आधुनिक और मसीनों के प्रयोग किये जाने तथा उत्पादन का युक्तिकरण करने की खायरयकता स्वष्ट हो जाती हैं । वितम्बर १९९४ में कानूनमी कोटी ने यह विकारित कर्यों, विदायर को थी कि उच्चोगों के सभी विमानों जैसे मिलो, खिक संचालित कर्यों, हाथ कर्यों हा सुक्ति स्वचार हुए ५ वर्षों के अन्वर्यत हो जाना वाहिये। विकार कर्यों जी सक्ति भी।

उत्तर प्रदेश में कानवर की मती-मिलों की विशेष कठिनाइयों का सामना इसलिये करना पर रहा है कि जन्होंने अपनी आवश्यकता से अधिक श्रीमर्तों की स्तार रवावर है। इससे यहाँ की फिलो का जन्माहत हवस देशा के सहस प्राणी सी मिलों की अपेका बहुत आविक है। यदि इनमें यक्तिकरण स किया गया तो इस भिलों के इन्ट हो जाने का भय है। यह बड़े सीधारय की बात है कि अधिक श्रीर मालिक दोनों ही ने जन १६५४ में नैनोताल में हुई जिस्लीय समा में इस बात को स्वीकार किया था कि कानपर की खतो मिलो के उत्पादन का प्रक्तिकरण किया जाना चाहिये। इसका ऋर्थ यह होगा कि प्रत्येक अभिक, जैसा कि बस्बई में हो रहा है. दो कहाँ के स्थान पर चार कहाँ पर कार्य करेगा और कार्य भार की मात्रा में भी सामान्यत: वृद्धिहो जायगी। इससे मिलों का बन्द होना दक्त जायगा श्चीर श्रमिकों को बरवल बेकार न रहना पड़ेगा। इस योजना के सम्बन्द में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अम मंत्री सम्पर्णानन्दती ने कहा था कि. "हाल में सेन्टल हिस्पारम एवर में जो मधार हम्रा है उसने मालिकों के लिये श्रतिरिक्त अधिकों की छटनी करना इरजाना देकर अपेताकत अधिक सरल कर दिया है। अनेकों मिल मालिक इसमें अपना लाम देखेंगे कि वे खटनी करके इरजाना देकर अपने मिल में स्थापी बचत कर लें। हमारी समस्या जन श्रीमकों की जिसी प्रकार प्रधा करने की है जिनके छाँट दिये जाने का भय है। सरकार को युक्तिकरण की देशो योजना बनाने के निर्याय घर, जिसके अन्तर्गत ५००० और ६००० के मध्य श्रनुसानित छाँट दिये जाने वाले अभिकों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके. इस प्रत्यामि के समज विचार करना चाहिये? । कानपर की अनेक मिलें जो असी तक बड़ी कठिमाई से दो शिफ्ट में कार्य कर पा रही थीं अब तीन शिक्ट में कार्य कर सकेंगी जिससे कार्य करने के अधिक अवसर आप हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त युक्तिकरण को यह योजना कानपुर के सुती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों की श्रीसत पारिश्रमिक जिसमें मेंहगाई भी सम्मिलित होगी. दश ६० से बढाकर ११५ ६० प्रति मास और दिशेष द्वामता वाले अमिकों के लिये १५० ६० प्रति मास कर सकेगी।

१९४२ की ग्रांसियों से सारत सरकार से भारतीय जर किल सालिक सह को सकाव दिया था कि कीयले तथा परिवहन का सरक्षण करने के लिए जसीग का यक्तिकरण ब्यायज्यक है। सरकार के कथमानसार रेलवे विभाग जट उद्योग के कल वास्त्रविक उत्पादन को पश्चिमी भागों तक ले जाने की स्वयस्था कर सकते में ब्रासमर्थ था। जॉच करने पर पता चला कि जुट की वस्तुश्री की कल मांग, जिनमें देश के अन्दर का उपभोग भी समितित है, सग्रमग्र ५५ इजार उन प्रति सास होगी जब कि कल १५ हजार टन साल का उलादन किया जा रहा था। इससे स्पष्ट था कि उत्पादन में कमी की जानी चाढिए। भारत सरकार ने सकाव दिया कि उत्पादन कम करने के लिए केवल उन्हीं मिलों में उत्पादन कराया जाय जिनमे विदात संचालित मशीने हैं। भारतीय जुट मिलों ने इस सुकाव को स्वीकार नहीं किया और युक्तिकरण की एक नवीन योजना लागू कर दी जिसके अनुसार न्यय की बचत करने के लिए कोयले के केन्द्रीय स्थाक स्थापित किए गये श्रीर कोयले की उपलब्ध मात्रा की पूर्ति को नियन्त्रित किया गया। तदपर्चात् एक 'समह योजना' लागुकी गई जो १ जुलाई १९४४ से ३१ मार्च १९४६ तक प्रचलित रही। युक्तिकरण की इस योजना से उद्योग कोयले के व्यय में बचत करने में छफल हुन्ना श्रीर कुछ मिलों को युद्ध की परिस्थितियों से निवश होकर जो हानि उठानी पढ़ी उसका और श्रविक समान वितरस किया जा सका ।

युक्तिकरण वर्तमान समय में ख्रपनी पुरानी ख़ौर विसी हुई मशीनों को परिवर्तन करने के लिए श्रीर श्रन्यदेशों के उचीयों की मीति उत्पादन के बिल्कुल श्राप्तिक उपायो का उपयोग करने के लिए जुट उच्चीय की युक्तिकरण की योजना लागू करने की श्रायम्त ग्रावश्यकता है। चूं कि मारत के वट उद्योग को विदेशी उत्तादकों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है इसलिए अन्य देशों द्वारा प्रमुक्त प्रावि-विक कुरालताओं का वहाँ भी उपयोग किया जाना चाहिए। भारत की कुछ मिली ने ग्रापुनिक पशीनों का उपयोग आरम्भ कर दिया है। उत्पादन ब्यव कम करने के लिए ग्रन्य उद्योगों को भी ऐसा करते की आवश्यकता है। इन योजनाश्ची को कार्याचित करने में दो सब से नहीं कठिनाहवाँ यह हैं कि (१) इनके लिए पर से ४५ हरीड़ वपये की आवश्यकता है, जो वर्तमान समय से उपलब्ध कर सकता कित है स्त्रीर (२) इन योजनास्त्रों के कार्यान्वित हो जाने से लगमग ४० इजार कोयला उद्योग—कोयला उद्योग में कोयले की छोटो छोटी श्रीर श्राधिक अभिक बेरोजगार हो जायँको।

हार से अतुनुयुक्त लानों को लिमसिलत कर एक यही इकाई का रूप देने, विभिन्न उनायो से बाहुकोचन के कार्य झानेबाले बहिया कोयले का संरक्ष्य करने झीर कोवले की खानों में मधीनों का उपयोग करने के लिए युक्तिकरण की योजना

कोयला उद्योग में मशीनों का उपदोग करने से अभिप्राय यह है कि लान लागू करना ग्रावश्यक है। में कोवला काटने ख्रीर उसे नियत स्थान तक खे जाने के लिए मधीनों का प्रयोग किया जाय और कोवला निकालकर नियत स्थान तक ले जाने की दोनों कियाएँ हाय-साप हो। भारत में महीनों का प्रयोग ऋमी बहुत कम हुआ है। १६४४ म कोपता निकालने की २१० मधीनें थीं जिनसे २१ लाख टन कोपता निकाला जाताथा। १९३व में इस प्रकार की केवल १८६ और १६३५ में केवल ६५ महीनें भी । १६५१ के मध्य तक भारत में २७४ मशीनों से प्रति माछ लगमग भ लाख ६० इचार टन कीपला (श्रयात् ७० लाख टन कीयला प्रतिवर्ष) निकाला गया जो औरत मासिक उत्पादन का लगमय १९६ प्रतिशत था। भारतीय कोयला-खान स्मिति ने १९४६ में विद्यारिश की कि भारतीय कोयले की खानों मे मरीनो का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि मशीनों के उपयोग से ही उत्पादन शीप्र बदाया जा सकता है जो कि अविष्य के लिए आत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में मशीनों के उपयोग के प्रति योड़ी प्रतिकृतता होने के कारण शायद सस्ते श्रम की उपलब्धि है। जब अस महँगा पढ़ने लगेगा, पारिश्रमिक बढ़ने लगेगा तो अवस्य ही इस प्रतिकृत्तता में परिवर्तन होगा और तब गरीन और अम के बीच उपयोगिता की होंदर में विचार कर उपयक्त साधन कॉरने के सम्बन्ध में निर्णय किया जा महेशा। कीयला जुशीस के सम्बन्ध में १६०० में शर्किक पार्टी ने सकार दिया कि खानों में संशीनों का उपयोग करने से ही सनियोजित उपाय से जीप जलादन बटाया का सकता है और अविष्य में देश के जीहोगीकरण की व्यायक्रयक्षताच्यों की पार्त की जा सकती है । सम्पर्क व्यवस्था का सन्तिसत विकास करने के लिए खानों में बीब ही मधीनें नहीं लगानी चाहिएँ। इसके लिए एक द्यविक निश्चित की जानी चाहिए । यह उचित नहीं है कि एक साथ सभी खानों में मशीनों की सहायता से उत्पादन खारम्म कर दिया जार । इसके लिए एक एक खान बढके बर्गात करनी होसी। क्रमणः संजीतों का जबबोस ध्रहाने पर भी कोयले की खान के अभिकों में बेरोजगारी फैल सकती है। वर्किक पार्टी हर परिशास पर पहेंची कि खानों में मशीनों का उपयोग करने में बेरोजगारी के भर से बाधा जलब कहीं होती चाहिए। मशीनों के जपयोग से हानियों की श्रपेदा लाभ कही शक्ति हैं। इसकी सफलता के लिए वर्डिक पार्टी ने सकाव दिया है कि (1) कोरी-कोरी कोयले की खानों को कम से कम १० इजार उन प्रति सार उत्पादन करने याली इकाई के रूप में सगडित कर दिया जाय श्रीर (२) कीयले की खानों में लगाई जानेवालो मशोनों का मारत में ही निर्माण किया जाय । भारत के अधिकांश उद्योगों में कम से कम तीन खेत्रों में युक्तिकरण की

मारत के ब्रांगकांत उद्योगों में कम से कम तीन चित्री में मुक्तिकारण को योजना लागू करना अत्यस्य आवश्यम है (१) कारखानों के स्वानिकारण में ब्राह्म से बीनों और कुछ लीमा तक लोहे तथा हरगत के कारखानों में। १९५५ के उद्योग (विकास एक्स नियम ) कानून के अत्यस्त स्थापित लाई- शिन्तंग संभित्र होनी ते वे कुछ कारखानों को अधिक अच्छे स्थान पर स्थापित लाई- शिन्तंग संभित्र होनी ते दे दी है। लोहे और इस्थात उद्योग के सन्वस्य में आया की लाती है कि नये लोहे और इस्थात खेगाने पर स्थानिय कि जामें में स्थानों पर स्थापित कि जामें में स्थापों के साम करने के लिए चीनों उद्योग में अध्याप के साम आप के साम करने के लिए चीनों उद्योग में अधि उत्यादित साल का प्रकार सुपारित की उत्यादन के अव्योग में और उत्यादित साल का प्रकार सुपारित की वालिक से का में सुपार करने की आवश्यन हो है। अध्यानों के लिये उत्यादन के दंग में सुपार करने की आवश्यन हो है। अध्यानों के लिये उत्यादन के दंग में सुपार करने की आवश्यन हो है। अध्यानों के लिये उत्यादन के देव में सुपार करने की आवश्यन हो है। अध्यान थी के लावें उत्यादन के स्थान सिक्त करने के लिए प्रता मधान थी के कार्य करने वाले अधिकों की यस्था में कमी करने आवश्यन हो है। अध्यान के लोहे तथा इस्थात, चीनों, सती, कपका, नर तथा अपन उत्योगों में प्रत्येक मधीन पर आवश्यन करता है अधिक अधिक निम्हण किये आवश्य उद्योगों में प्रत्येक मधीन पर आवश्यन करता है सी उद्योग की सिक्त परिवार करता है। सारत के लोहे तथा इस्थात, चीनक किये की स्थान होता है और उद्योग की स्थान विद्या किये व्याव की सिक्त परिवार होता है और उद्योग की स्थान विद्या करता होता है और उद्योग की

प्रतियोगिता शांक शिष्ठिल पह जाती है। प्रत्येक उद्योग के अधिकांश कारखाने ऐसे हैं कि उनकी उत्पादन शांक अनुक्ताम स्तार से नीचे है। उत्पादन स्वमता में कभी का यह भी एक कारख है कि चीनों की अनेक मिलों में प्रतिदित ८०० टन (जो गचा पेरते की अनुक्ताम शांकि है) से कम गना पेरा जाता है। यह उत्पादन की शांकि का पूरा उपयोग किया जाय से १००० टन महा पर जा सकता है। यही रिपति अन्य उद्योगों की भी है। सामज के कुछ कारखाने प्रतिवर्ध ६ तहार टन कामज अनुक्ताम उत्पादन करने की स्वमता नहीं रखते हैं, कुछ विसेंद के कारखानों का वार्षिक उत्पादन करने की स्वमता नहीं रखते हैं, कुछ विसेंद के कारखानों का वार्षिक उत्पादन कर जो अनुक्ताम अन्याक से किया दिन कामज अनुक्ताम स्वार के कम है। अनेक स्त्री मिलों की अनुक्ताम उत्पादन शांकि भी कीता प्रतिवर्ध कहा जा खुक है आवश्यक तो से कम है। मिलों की अक्टिंत इनाई में कामम रूप,००० तकुए और ६०० वर्षे चलने चाहिएँ। युक्तिक स्त्र से रोजना लागू करके अधिकांश कारखानों को अनुक्ताम उत्पादन शक्ति के स्तर पर लाया आ

सकता है श्री उत्पादन न्यम कम किया जा सकता है।

पुक्तिकर खु की योजना लागू करने में सबसे बड़ी किनाई अमिकों का

विरोध श्री बहुत बड़ी मात्रा में यिन्त की आवश्यकता है। कुछ ऐसे उत्पादन मी

सुक्तिकर खु की योजना लागू करने में बाया उत्पन्न करते हैं जो इस योजना के

लाम को नहीं समन्त्री श्रीर इस लागू करने के लिये मस्तुत नहीं होते हैं। परन्तु

अगिकों का सहागा मात्र कर नदुत उत्पादकों और सरकार को भारतीय उद्योग

की ग्रीचों मिक कार्यक्रमता में सुकार करने के लिय भीरे-धीरे सुनियों जित आधार

पर सिक्तकर खु की योजना लागू कर देनी वाडिये।

#### श्रद्याय २५

### वेरोजगारी की समस्या

यह आरवर्षनक वात है कि आर्थिक हाँट से बहुत कम किसित दें में वस्तुओं और विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के आमान के साथ वेरोजगारी र और बहुत कही माना में अम-पाकि अप्रमुक्त पत्नी हो। भारत आर्थिक हिंदर है बहुत कम किशन कर जका है परन्तु यहाँ वेरोजगारी मीनप कर पारप कि हुए है। इस कारण भारत की राष्ट्रीय आप बहुत कम है, इहन-सहन पा स्त बहुत निम्म है और जनता कुली तथा असन्तुष्ट है। मारव में नेचल धिक्ति लोगों और उद्योगों तथा कृषि दोन में कार्य करने वाले अभिक्षों को ही वेरोजगार का सामना नहीं करना पढ़ रहा है वरन, नायरिक एवस मानीय दोन की मार सम्पूर्ण जनता हरके चंगुल में केंश्व हुई है। पारचारन देखों में में दोजगारी परन्तु उत्तका कारण क्याता में मन्दी आ जाने से कुछ सम्म के लिए बरहाओं में मारव की कमी है। इचके साथ हो बहुत कुछ देने कारखाने हैं जो वर्ष में कुछ मारव जलने के परचात् रोग मात्र बन्द रहते हैं और इन मानों में बहुर वेरोजगार कैंत जाती है। प्राव: एक कार्य छोड़न के प्रस्वाद उपन्त दुसरा कार्य नहीं निय गावा और एक वीच को अवस्था के स्वाहत होज आ दिसारा वेरोजगारी रहते है तथा अस्म मुकार की अस्वाहत होजा की बीचारी होती है।

भारत में बेरोज़गारी तथा श्रांशिक रोजगारी श्रोधकांग्र जनता के जीव-का स्थायी श्रंम बन खुके हैं। इतका कारण यह है कि देश की जन-संप्या में निरन्दर वृद्धि होती जा रही है श्रीर देश के श्राधिक साधनी का बहुत कम विकास किया गया है। तत कुछ वर्षों से इस समस्या ने गम्मीर स्थिति उत्पन्न कर लैं

है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके निम्नलिखित कारण बताए गए है :--

(ग्र) जन-संख्या की तीन गति से सृद्धि;

 (व) प्राप्य उद्योगों का नष्ट हो जाना विनमें आमों के बहुत से व्यक्तिये को ब्रॉशिक व्यवसाय प्राप्त हो जाता था-

(e) व्यवसाय की दृष्टि से कृषि के श्रांतिरिक्त श्रन्य उत्पादन चैत्रों क श्रदसंह विकास (ययापे गत ४० वर्षों में काफी विकास दुशा है फिर भी १६११ के परचात कृषि चेत्र में व्यवसायों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति ३ प्रतिस्त रही है)  (द) देश-विभाजन के परिकास स्वरूप जन-संख्या का बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित होता !

आंकड़ों के असान में यह निश्चित कर में नहीं बताया जा सकता है कि
भारत में बेरोजगारी या अधिक व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की संस्था कितनी है ;
कुछ अधिकारियों का अनुसान है कि प्रायों में जन-संस्था कर लगमग १० मिरारात
केरोजगार है और ऐसे व्यक्तियों की संस्था वहन अधिक है जो अप्राप्त कर केरे रोजगार पाए हुए है। अन्य अनुमानों के अनुसार देश की कुल जन-संस्था
आभीए एवं नामारिक रोनों सेजों में बेरोजगार और आंशिक व्यवसाय प्राप्त
व्यक्तियों की संस्था भू या ६ करोड़ के बीच में है। यह बेरोजगारी की
महुत बड़ी संस्था है। पश्चिम के कुछ काफी विकसित देशों में स्मृत्य केर समस्य
कुछ जितने व्यक्तियों की स्थवसाय प्राप्त है उनके एक से तीन प्रतिशात से भी
कम व्यक्ति वेरोजगार रहे हैं। वरन्तु भारत की स्थित विन्कुल भिन्न है। भारत
कम स्थित काल में स्थवसाय प्राप्त व्यक्तियों के अनुश्व में बेरोजगारी की स्थवसाय में स्था में स्थित साल में स्थवसाय प्राप्त व्यक्तियों के अनुश्व में बेरोजगारों की स्थित साल में स्थित साल में स्थालय प्राप्त व्यक्तियों के अनुश्व में बेरोजगारों की स्थालया स्थालय से से स्थालया से स्थालया से स्थालया में कि स्थालया से से स्थालया से साल में स्थालया से से स्थालया से स्थालया से स्थालया से स्थालया से स्थालया में कि स्थालया से स्थालया स्थालया से स्थालया से स्थालया से स्थालया से स्थालया से स्थालया से स्थालय

"भारतीय कमस्या का वानम्य देवा की उम्यूर्ण ग्राधिक व्यवस्था की अकृति से हैं। इकिलये इस पर विचार हुनी हरिटकोस्य से किया जाना चाहिये। सिहित वर्ग की बेकारी की विशेष अप्रका के प्रदर्शन से, जो कि स्वामाधिक भी है, इस वर्ग के विशेष प्रकारत होने ज्ञीर राजनैतिक अभाव कालते की हमता स्थले के कारण इस आदित से पढ़ उसके दें। वर्तमान दिस्ति में सबसे अधिक हानि उठाने वाले भूमि हील कुथि तथा बैर-कृषि ग्राम्य अभिक, नगर में रहने याले साधिक अभिक, ग्राम्य तथा नगर के छोटे-छोटे उद्योगों में कार्य करने वाले अभिक, तथा प्रटक्त कार्य करने वाले दसकार हत्यादि हैं। इन यस से वे अभिक जो ग्राधिक तथा छामाजिक हथ्यिक जीतियाँ, ज्ञादिवाधी तथा निकृत्य दस्तकारी का नार्य करने वाले विशेष जो ग्राधिक तथा छामाजिक इंग्रिकीस विशेष विशेष वालियाँ, ज्ञादिवाधी तथा निकृत्य दस्तकारी का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं।

पारचात्य देशों में वेरोजगारी एक श्रस्थायी समस्या के रूप में होती है श्रीर सरकार तथा मिल मालिकों द्वारा ठोक अमय पर कार्यवाई कर देने से उसके इत हो जाने की आधार इती है परन्तु पारचात्य देशों में मुद्दक उपायों द्वारा मारत की समस्या का इल नहीं किया जा चकता। भारत में इस समस्या को दीएं लोगों ने हिए की यह श्राया के हिए की मूर्य की तथा हो जा कि कृषि की मूर्य के तथा के हिए हो से हिए की यह श्राया के कि तथा और तथा श्री उस पर राज्य के लिए ने श्रीर उस पर राज्य के तथा श्री की कर पर राज्य के तथा श्री की कर पर राज्य स्थाय स्थाय

करने की आयश्यकता है। किसी भी सरकार से यह आशा नहीं की बा सकती है कि वह प्रतिवर्ध है प्रतिशत की दर से बहने वाली जन संख्वा की व्यवसाय के सामनों में भी इसी ग्रांत से वृद्धि नहीं होती। जूँ कि प्रवास के द्वारा जन संख्वा की समस्या की सुलकाया नहीं जा सकता है इसलिए सभा की व्यवसाय का स्वाय संगत अवसर प्रवास करने के लिए यह अवस्थक है कि भूमि पर और आयोगिक सामनों पर जन संख्या के दवाय को कम करमे के लिए का समस्य की स्वाय को सम करमे के लिए का समस्य की स्वाय को सम करमे के लिए का समस्य की सम्बद्ध को रोका लाए। परन्तु इस व्यवस्था को लागू करने में अधिक समय लगेगा और वेरोजगारी को समस्या को इतने समय तक दिना इस किए कोन्द्र के ने समय तक दिना इस किए कोन्द्र के ना समय नहीं है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कल जये न्यवसाय के ग्रायसर प्रदान किये पे । परन्त योजना के तीसरे वर्ष से निरस्तर खेळारी के बटते रहते के कारण आयोग को यह स्पष्ट हो सबा कि देश के झीबोसिक और बार्धिक विकास दारा इस समस्या के सलकाने के उपाय को सर्व-प्रधानना देनी आवश्यक है। इसी हरिटकोशा से प्रथम योजना पर हवय की जाने बाली धन राशि श्रवटंबर १६५३ में १८० करोड क्यम बहा ही गई जिससे कि नवीन विशेष योजनाओं के लिए. जो कि व्यवसाय के अवसरों की बृद्धि करेंगी और बहती हुई बेकारी रोकेगी, पर्याप्त वित्त मास हो एके । इसके व्यतिशिक्त विस्थापित व्यक्तियों के प्रनवीय के कार्यक्रम को १६५३-५४ के गत निर्णय के अनुसार अन्त कर देने के स्थान पर पूर्ण योजना फाल तक चाल रखने का भी निर्माय किया गया ! बेकारी की समस्या को इल करने के पनपरीजित कार्यक्रम के अस्तर्गत यह प्रस्ताव किया गया कि (१) राज्य-वित्त निगम स्थापित किये आँय, (२) केन्द्र से राज्यों को देश की दरिद्रता कम करने के लिए नई योजनाश्चों के चाल करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाय, (३) सहकों के निर्माण के लिए तथा छोटी-छोटी शक्ति उत्पादन की योजनाओं को कार्यान्त्रित करने के लिये अनदान दिये जाँग और (४) श्रीसीगिक शिज्ञा की सुविधाओं का विस्तार किया जाय । पर जैशा सम या उसके अनुसार यह समस्या सुलकाने का आशिक प्रथतन असफल रहा । आमों और नगरों दोनों स्थानो पर ऐसे व्यक्तियों की सख्या जो आंशिक व्यवसाय आस या वेरोजगार है निरन्तर बढ़ती का रही है। यह आशा की जाती है कि इस समस्या को वास्तविक रूप से सलमाने का प्रयत्न किया आयभा जिसमें देश के ख्रीयोगिक विकास पर क्राधिक महत्व दिया जायगा और साथ ही साथ जन संख्या की वृद्धि पर कुछ नियंत्रस भी खुला जायगा । यही उपाय दितीय योगना का मुलाघार है ।

यदि भारत के कारखानों द्वारा निर्मित वस्त के उत्पादन श्रीर विकय में.

वृद्धि हो तो झीवोगिक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। यह तभी सम्मव है जब मित इकाई उत्पादन व्यय कम किया जाए। बहुत से उदोगों में पारि-श्रमिक उत्पादन क्यय का एक महत्वपूर्व झंग है। गत १० वर्षों में मारत के श्रमिक के पारिश्रमिक में पूर्व स्तर से देरे में भट्टे गुना खिक वृद्धि हुई है परन्त मुख वृद्धि के साप ही श्रमिक को कुशलता में वृद्धि नहीं हुई है। इसका स्वामाविक परिचान यह हुझा कि कुछ कारखाने बन्द कर देने पड़े किससे श्रमिकों में बेरोजगारी ऐसी। यह स्थिति बहुत कमय पूर्व ही झा गई होसी परन्तु पुत्र के समय व्यद्धिश्रों का अभाव हो। गया था और यह अभाव जुल समान हो जाने के परन्तात् भी रहा। बस्तुओं का उत्पादन क्यय अधिक होते हुए और मानों का स्तर अधिक रहते हुए भी अपने समान का विकत कर सकते में उत्पोग सकत है। परन्तु अब उपभोका इस स्थिति का जागे निवाह कर एकने में असमर्थ है। इसिलिए केरोजगारी को कम करने के लिए या तो भारत के अभिकों को कम पारिश्रमिक सेने के लिए प्रस्तत रहना होगा या उन्हें कार्य श्रीक करना पड़ेगा।

हफ के प्राय ही फेन्द्रीय तथा राज्य खरकारो द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाने के, विभिन्न सरकारी नियम्त्रकों और निजी उचीग में अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध लगा देने से भारतीय उद्योगों के उत्पादन क्या में बूढ़ि हो हो है। भारत के जीविश्य लगा देने से भारतीय निजी उद्योगों के हो बोल बाला है। ह एकिएए अधिक उद्योगि कर के के लिए अधिक उद्योगों में व्यवस्थाय की सभावना में बूढ़ि करने के लिए निजी उद्योग खेत के विश्व निविध्यार और उपके मार्ग में चरकारी प्रतिबन्धों द्वारा बाचा नहीं बालनी चाहिए। यदि खरकार अपनी कर, अस तथा उद्योग सम्बन्धी नीतियाँ में देखा परिवर्गन करें लिक्से उत्यादन तथा नियाँत में बृढ़िक लिए उद्योगों को प्रोरसाहन भिन्त सके तो उद्योग खेत्र में वेरोकारीय कहत अंशी में कम की जा सकती है।

यह पुक्ताव दिया गया है कि आरतीय उद्योग च्हेन में युक्तिक स्या की योजनाकों को लागू करने की अनुभात न दी लाय क्योंकि इस्से उद्योग चेत्र में के रोजगारी में द्वांस होती है। यदि यह मुक्ताव मान लिया गया तो आयोगिक चेत्र में केरोजगारी घटने की अपेक्षा और अधिक वहेगी। चल बालार में पूर्ति मौंग से कम हैं तो इस जात का विशेष महत्व नहीं है कि भारतीय उद्योगों द्वारा उत्यादित यस्त्र की मींत इकाई का उत्यादन क्या कितना है। परन्तु जूँकि अब खरीदार अपनी म्यय शक्ति के अमुकूल कर करना वाहता है जिसके कारण्य बालार की स्थित उद्योग है, उद्योगों की परस्य प्रादित में स्थान में कर कर करना वाहता है जिसके कारण बालार की स्थान उद्यो हो। यह के उद्योगों की परस्य प्रादित चाहता है। यह केरोज महत्व भी बात हो। स्थान कर मानत यो विदेश में अपनी हो से सर्व है। यदि किसी कारखाने का उत्यादन क्या मानत या विदेश में अपनी हो स्थान कर मानत या विदेश में अपनी

प्रतिहर्दी कारलाने के उत्पादन ब्यय से अधिक है तो यह कारलाना ग्रयश्य नष्ट हो जायगा युक्तिकरण उत्पादन व्यय को कम करने का एक उपाय है। यदि युक्तिकरण की योजनाओं को लागू किया बायगा तो इससे कुछ देरोजगारी अवश्य मैलेगी परन्तु यदि युक्तिकरण योजनाओं को लागूही न किया गया तो यह सम्मय हो सकता है कि कारलाना सदैय के लिए क्टर कर देना पड़े और-पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या में व्यक्तियों को वेरोबगारी का सामना करना पड़ें।

कुछ व्यक्तियों का मत है कि भारत सरकार ने जून १६४४ में जो वोजना मकाशित की थी श्रीर जो अब तक वैकल्पिक रही है उसे श्रामिवार्य कर देना चाहिए। इस योजना के अनुकार केरोजनार ज्यक्ति को अपने वेरोजनारी मास के पूर्वार्थ में पारिक्षांक को कायारख दर का ७५ मितवात मिलेगा और उत्तरांध में ५० मितवात मिलेगा और उत्तरांध में ५० मितवात मिलेगा और उत्तरांध में ५० मितवात। इस बोजना में पहले ही मान लिया गया है कि मारतीय उद्योग इस श्रातिक परिक्षांमक के घन मार यहन कर सकते से समर्थ है, परत वास्तिव हिंध आरती उद्योग पर श्रायिक मार पहला ताम होता या उत्तरी मात्रा पट गई है और यदि उद्योग पर श्रायिक मार पदला तो यह यहन कर सकते में अपना पट गई है और यदि उद्योग पर श्रायिक मार पदला तो यह यहन कर सकते में अपना पट गई है और यदि उद्योग पर श्रायिक मार पदला तो यह यहन कर सकते में अपना पित हो।। भारत के श्रयेक कारखाने पहले ही बन्द हो जुके हैं। यदि यह योजना श्रानियार्थ की गई तो कुछ श्रीर कारखाने भी कन्द हो जायेंगे।

'प्रथम योजना काल के अनुभव से यह आवश्यक हो गया है कि वैकारों को समस्यापर केशल समृद्धिक रूप से ही नहीं वरन प्रामीण और नागरिक सेत्रों के हिस्सोण से भी विवाद करना चाहिये। इस स्वरूप के विस्तार का, जो कि आगागी कुछ वर्षों में होगा, ठीक-ठीक अनुमान करने के लिये यह आवश्यक है कि देश के विभिन्न भागों के प्रामीण और नागरिक चेशों में इसकी वास्त्रविकता की समक्ष लिया जाव। यह भी आवश्यक है कि शिखित वर्षों की बेकारी की अन्य लोगों की बेकारी से अलग कर लिया जाय?।

"प्रपम योजना के आकब्दों के परीच्या से यह शात होता है कि आपी योजना कार्यान्वित होने पर वेकारी निरन्तर बढ़ती ना रही थो। प्रथम योजना, काल में रिजटर किये हुने वैरोजगार लोगों की संख्या निरन्तर बढ़तो रही यह मार्च १९५१ में १९५० लाव कार्या दिख्या १९५५ में सढ़कर प्रश्त लाख हो गई श्रीर १९५६ के मार्च में ७००५ लाख हो गई। योजना आयोग की विका-रिश के अनुतार नेयानल सैन्यित सर्वे ने जो मार्यामक परीक्षण नगरवासियों में वैरोजगारों का किया या उसके परिखाओं के इच्टिकोल से यदि इन आंकड़ों को देखा जाय तो इत्से बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पहता है। इत सर्वे के अनुसार तागरिकों में बेरोजगारों, की (१९५४) संस्था २२ ४ साल खाँकी गई थी। इस सर्वे ने बेकार लोगों की संख्या खार जिनका नाम रिकटर किया जा जुका या उनकी संख्या के बोच खानुपातिक सम्बन्ध भी स्थापित करने का प्रयत्न किया है। सर्वे का खानुमार परिलयम्भ २५% बेरोजगार व्यक्ति एक्सिन के देशकर एक्सिन स्थापित के स्थाप्त राजस्टर करवाते हैं। इस खानार पर नगरवासियों में बेरोजगारी की सख्या सर्वमान काल में २५ लाख के लगभग खाती है। वह खानुमान सागायतः देश के सिमित मागों के नगरों में किये गये परीक्षणों की रिपोर्टों के समान है। सामित बेहारी, को जो कि विकालमान खारिक स्थवस्था में खत्रस्थमायों है, खुट रेते हुये इस यह कह सकते हैं कि नगरवासियों में बेनार लोगों की संख्या २५ साल के लगभग खनुमान को जाती है। इस संख्या में नगर के अमिकों की संख्या बहाने के लिये नवीन खालन्दुकों को भी जोड लेना चाहिये। यह खनुमान किया जाता है कि खानामी ५ वर्षों में समान इस लाख व्यक्ति इस कारण बेहारों में जोड़ दिये जातंगे।

आगामी ५ वर्षों में अभिकों की गलना में वृद्धि आने वाले नवागन्तुकों की गंख्या १ करोड़ अनुमान की गई है। इस संख्या में से नागरिक अभिकों में नवागन्तुकों को अनुमानित ३८ लाख संख्या घटा कर १९५६-६१ के मध्य भाग्य अभिमी की गाया। में वृद्धि करने बाले नवागन्तुकों की राख्या में वृद्धि करने बाले नवागन्तुकों की राख्या ६२ लाख के लगमग आवेगी। निम्न तालिका यह वतलाती है कि द्वितीय योजना काल में यदि बैकारी को समस्या को समाप्त करना है तो कितने व्यवसायों के अवसर प्रदान करने वर्षों में —

(१० लाख में संस्थार्ने) नगरों के ग्रामो के कींग ਜ਼ੈਸ਼ ਜ਼ੋ सेत्र में भगिको में नवागन्तको के लिये 3.€ 6.5 80'0 वर्त्तमान भग्निकों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिये 4.5 ₹.८ योग £ 3 6.3 8**4.**3

यदि इच प्रकार रोजगार के श्रवकरों को पैदा करना सम्मव भी हो संक तो भी श्राधिक रोजगार की समस्या को जो वेकारी की समस्या को ही तरह महत्व यात्री है जुलमाया नहीं जा सकता। दितीय योजना का प्यान प्रधानयः वेरोजगारी और आग्निक वेरोजगारी की समस्या दर है। इस्तिये दितीय योजना में एक और वही माना में उत्पादन करने गांले खंकुक पंजी वाले उपक्रमों के विकास के प्रति और तुपरी और मान्य तथा खोटे उद्योगों के विकास के प्रति इस आशा से प्रधानता दो गई है कि ये किसी टीमा तक वेकारी की समस्या को खुलका सकरें। सरकारी ज्ञेत्र में कुल व्यय लगभग ४८०० करोड़ कार्य का खुलका करेंगे। सरकारी ज्ञेत्र में केवल देशक करोड़ करवे विनियोग दिखाते हैं। इसके खुतिरिक व्यक्तिगत केन में विनियोग की माना २४०० करोड़ कार्य खुतान की गई है। राज्यों पर्व नेन्द्रीय नेनालयों द्वारा पूरित खोकड़ों तथा व्यक्तिगत की को है है। उत्पादन यक्ति में इसि समझ्यी मान्यताओं को विचाराधीन रखते हुए जो स्थेय निश्चित किए गए हैं उनके खाधार पर दितीय योजना द्वारा प्रदत्त रोजी के खतिरिक अवसरी का खानान लगाया जा उकता है। निन्त तालिका में इन परियोगों का निम्कर्य विवारण में है।

इन	परिज्ञामी का निष्य
20 €	ाख की संख्या में)
***	₹'₹#
***	'0¥,
***	°રમ
* * *	'१८
•••	•હધ્
***	*84
ť ••••	*¥₹
***	*₹₹
***	***
	.\$.
***	**
	<b>५</b> °२०
***	₹"७०
	o3°0

हितीय पंचवर्षीय कोजना द्वारा कितने जनीन व्यवसायों को श्रवसर प्रदान किया जा सकेगा उसका ठीक-ठीक अनमान लगाना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। "आयोग द्वारा परीजा करने से यह जात होता है कि प्रथम योजना काल में जो प्रत्यन व्यवसाय के श्रवसर सरकारी श्रीर व्यक्तिगत लेश में पटान किये गये जनकी संख्या ४५ लाख के लगभग थी। इस ग्रानमान में वाशित्य ग्रीर व्यापीर आहि के सेन के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यवसाय समिमलित नहीं किये गये है। विकास सम्बन्धी प्रयत्न की दिशिखत करके जा दितीय योजना में अतिरिक्त व्यवसाय के खबसरों के प्रदान करने का ध्येय बनाया गया है वह कछ विशेष श्राधिक नहीं होता । इसका कारण यह है कि द्वितीय योजना में विकास सम्प्रन्थी इय्य प्रथम गोजना काल के क्या से कोई विशेष शायिक नहीं हो पायेगा, क्योंकि सरकारी चीत्र में योजना का व्यय शहब्र-ब्रह में ६०० से ६३० करोड़ रुपयों के लगमग निश्चित किया गया है, अब कि विकास योजनाओं पर १६५०-५१ में २२४ करोड काया ही व्यय किया गया था। प्रथम गोजना के अन्तिम वर्ष में सरकारी केत्र में काय की माजा १६५०-५१ के व्यय की मात्रा से लगमग ४०० करोड हुएये श्राहिक होते की सम्भावना है। यह भी सम्भव है कि प्रथम योजना के श्रस्तिम वर्ष की तलना में विकास योजनाओं पर न्यय में बढि डिसीय योजना के अस्तिम वर्ष में लगभग ६०० करोड़ व्यया हो। इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना में विनियोग के दंग को देखकर यह बात स्पब्ट हो जाती है कि भारी उद्योगों श्रीर यातायात पर, जो कि श्रास्पकाल में बहुत कम व्यवसाय के श्रावसर प्रदान कर सकते हैं. बहुत क्राधिक धन व्यय किया जाने वाला है।" इसका झर्थ यह है कि परम सीमाग्य होते हये भी 🕿० लाख से आधिक व्यक्तियों के लिये (कृषि को छोड़ कर) दिसीय योजना के उपायो हारा ध्यासाय प्रदान करना सम्मव न हो सकेगा जब कि वैकारी की समस्या को पर्या रूपेया हला करने के लिये १५२५ स्वास्त ध्यक्तियों के लिये व्यवसाय प्रदान करना आवश्यक है। मई १९५% में योजना ग्रायोग हारा जारी की गई पुस्तिका 'हितीय पंच-

शह १६५८ म याजना प्रायाम द्वारा जारा का गह पुस्तक 'श्वताय पक् वर्षाय योजना की सम्मारनाय मुल्यांकन के अनुसार 'धरहवे दो वर्षों में कृषि के बाहर रोजों के २० लाख अवसर प्रदान किये गये। स्वाममा १० लाख अम-दाकि रे१६५८-५६ में रोजी पा स्केमी। यह स्मरता रखना चाहिये कि योजना में ७६ लाख व्यक्तियों के कृषि के बाहर तथा १६ साख व्यक्तियों के कृषि के झन्दर रोजी पाने की सम्मानना है। विभिन्न योजनाओं की लामत में सुद्धि हो जाने के सल-दस्तर कृषि के बाहर सरकारी चेत्र में ४८०० करोड़ क के व्यय के अनुमान पर लगमग ७० लाख व्यक्तियों को रोजी मिल स्रोतमी। यदि यह स्थय ४५०० करोड़ द० हो तो रोज़ी पाने वालों की सख्या ६५ लाख के लगमग होगी। यह अनुमान भित्कुल वही नहीं है किन्छु इनसे दवना तो पता चलता ही है कि हमारी अर्थ व्यवस्था में अय-वाक्ति की वार्षिक वृद्धि के अनुस्थ वितियोग नहीं हो रहा है।"

### रोजगार के दफ्तरों का कार्य

भारत में रोजगार के उपवरों का एक जाल सा किया हुआ है जो वेरोमगार क्यांकरों के आवेदनों को स्वीकार करते हें और उन रिक्त स्थानों के लिये उन्हें भेज देते हैं जो सरकार तथा अन्य न्यांकरों द्वारा विज्ञाति किये जाते हैं। इसमें सेंदेइ नहीं कि शेवागर के इपतर वेरोजगारी कम करते में सहायक हैं, स्थीकि वे बेरोजगार क्यांकरों का सम्यन्य क्यांकरात कर वालां से स्थापित के वेते हैं एक्तु ये रोजगार के इपतर हो मनुष्य की अप्रयुक्त शक्ति की समस्या को सुतकानों के सकल उचाय तो नहीं हैं। इनका कार्य चेत्र प्रचित्त आर्थिक और सामाणिक स्थित के अन्तर्शत ही सुविधार अवान करना है। ये दपतर नवींन व्यवसायों को तो उसका कर नहीं सकते । ये तो वेवल वेरोजगार व्यक्तियों को जो कार्य करने देश अपना रखते हैं और करना चाहते हैं निर्देश मात्र ही दे सकते हैं। वे उन व्यवसायों के लिये वो निच्चाित हैं सिर्देश मात्र ही दे सकते हैं। वे उन व्यवसायों के लिये वो निच्चाित हैं और जनके लिये स्थान रिक्त हैं। वे उन व्यवसायों के लिये जो निच्चाित हैं और जनके लिये स्थान रिक्त हैं

यह पर होते हुए भी नेरोजनार व्यक्तियां को मास्त स्थानों के लिये निर्देश देना भी नेरोजनारी की समस्या के सुलकाने में एक नड़ी सहायता है। हसके स्राविश्चित यद्यान रोजनार के दफ्तर में नाम रिकस्टर करावे हुए नेरोजनार व्यक्तियों से हमें बेकारी की समस्या का पूर्ण चित्र नहीं भाष्य होता, पर उत्तके निःश्चेद नेरोजनारी की वरकती हुई प्रवृत्ति कात होती है। यह का विन्ता का स्थित के स्वाप्त के स्वर्ण के कि रोजनार के दफ्तरों म राजस्टर किये हुने व्यक्तियों की एक्सा १९५५ में ७,५५,५०३ थी। १९५७ में यह बहुकर ६,२२,०६९ हो गई। १९५५ में महत्त स्वर्णन कहकर १,६२,०६९ हो गई। १९५६ हो गई। १९५० में यह सरस्य बहुकर १,६२,६९१ हो गई।

रोजगार के दफ्तरों को आधक प्रभाव शासी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उनना पुनंसगठन किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रशित्वय और ब्यवसाय क्यबस्था चिमित ने जिसे प्रापः बी॰ शिवा राव कमेटी कहते हैं भारत सरकार को द अपने संस्था में दी हुई रिगोर्ट में निन्न सिकारिश की :—

- (१) रोजगार के दफ्तरों की व्यवस्था को विस्तृत करके उसे राष्ट्रीय सेवा का एक स्थायी व अधिक अधिकार प्राप्त विभाग बना देना चाहिये :
  - (२) मशासन विकेन्द्रित होना चाहिये। इसका यह अर्थ है कि नीति

चाहे सरकार द्वारा क्यों न निर्धारित की चार्य पर उनका नित्य प्रति का प्रेसाछन राज्य सरकार द्वारा होना चाहिये;

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा रोजगार के दस्तरों को जो अरुदान घरायतार्ष दिया जाता है यह चालू रहना चाहिये, पर उसकी भाजा को सेत्रीय प्रधान कार्यालयों तथा राज्यों के रोजगार के दस्तरों के कुल ज्यय के ६०% तक सीमित कर देना चाहिये, और १९५१-५५ फं वजट में जो धनराशि निर्धारित की गई हो अथवा १९५२-५६ में जो वास्तियक ज्य किया यार हो, इन दोनों राशियों में से जो राज्य की करकार के अधिक सामकारी हो, उसे अन्द्रात की अधिकतम मात्रा नियत कर देनी चाहिये.

(४) रोजाार के दफ्तरों के कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिये और जनके कार्यों में निम्म कार्यों को भी जिम्मिलित करना चाहिये: (क) मालिकों और कार्य करने कार्यों में निम्म कार्यों को भी जिम्मिलित करना चाहिये: (क) मालिकों और कार्य करने वाला रे कार्य करने कार्य करने वाला रे लिए के कार्य करने के स्वीकर के अपने कर कर कर के कार्य कर कर कर के अपने कर कार्य कर कर कर के अपने कर के अपने कर कर कर के अपने कर कर कर के अपने कार्य के बार्य कर के कार्य के निर्माण करें और उनकी स्वावश्यकत परीचा हों; (ग) रिजस्टर कराये हुए व्यक्तियों की काहतों निर्माण करें, आवश्यकत परीचा हों; (ग) रिजस्टर कराये हुए व्यक्तियों की काहतों निर्माण करें, आवश्यकत परीचा हों; (ग) रिजस्टर कराये हुए व्यक्तियों की कार्य के निर्माण करें, और योग्य आवश्यकत के आपने वार्य कर कार्य के बाले व्यक्तियों के पार्थ में और अपनित्र कर कार्य के आपने कर कार्य के वाले व्यक्तियों के पार्थ कर कार्य के बाले व्यक्तियों के पार्थ कर कार्य के स्ववश्यक कर कर कार्य कर कार्य

(५) अदब अधिकों को म तो रिकस्टर करने की आवश्यकता है और म उनके आवेदनों की । को व्यक्ति ऐस अधिकों की सेवायें चादते हैं उनको पोपवाा द्वारा या किसी अन्य रूप से सुनित कर हेजा ही पर्याप्त होगा । इसके पश्चात् को कार्य करना चाहते हैं उनहें सोचे मालिकों के पास पहुँच बाता चाहिये। ऐसे क्यक्तियों के सम्बन्ध में वो प्रतिदिन रोजगार के दफ्तर पर इकहा होते हैं तथा पीपवा हारा जिन रिक्त स्थानों की स्वना दो जाती है उनके आंकड़े तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। और

(६) सरकारी तथा अर्थ सरकारी संस्थाओं द्वारा नियुक्त किये जाने के

सम्बन्ध में ये दफ्तर जो सिकारिसें करें उनके परिवास की कुछ दिन तक जीव करने के परचात् व्यक्तिगत चेत्र में भी इन दफ्तरों की सिकारिसों पर नियुक्त करना व्यनिवासे कर हैं।

सरकार ने बीठ जिल्लान क्योरी के ग्रामिस्तादों को ग्राशिक रूप में स्वीकार। कर लिया है ज्योर रोजगार के रफ्तरों को अधिक प्रमानगाली बनाने के लिये निम्त उरायों को दिवीय बीजना में कार्यान्वत करने का निर्शय किया है : (१) रोजगार दिलान के विमाग को १२५ नये रोजगार के दफ्तरों की स्थापना करके विस्तृत करना ताक अन्य बहुत से ब्यवसाय के केन्द्र इनके अवगंत ग्रा सर्वे। (२) ध्यवसाय की सबनात्रों के एकतित करने तथा लोगों तक पहुंचाने भी योजना निर्माण करना. (३) चने हुये स्ववसाय के रफ्तरों में जनसबक रोजगार सेवा संस्था की स्थापना करना तथा अवस्थों के लिये बाबसाय की सनाह देना तथा 'केरियर पेम्फलेट' श्रादि उपयक्त तत्थ्यक्यी साहित्य प्रकाशित करनाः (४) रोजगार सम्बन्धी विश्लेपण समा खोज के कार्य-क्रम बनाना ताकि विभिन्त व्यवसायों के नाम ह्या परिमापा मान्य शतर की बनाई जा सकें: और (४) रोजगार के दफ्तरों में ध्यवसायिक परीचा सम्बन्धी कार्यक्रम धनाना । इन उरायों से भारत की व्यवसाय दिलाने वाली सेवाओं की कार्य कुशुलवा अधिक वद जायगी परन्तु यह तभी धम्मव है अब कि शिक्तगार के दम्तर राष्ट्रीय सेवा विभाग के रूप में यिकतित हो जाँव और तमा उनके लिये वेरोजगार क्यक्तियों को व्यवसाय तुहना और दिलाना भी सम्मव हो सबेगा। कमेटी ने प्रशासन को विकेश्वत करने की विकारिय की है क्योंकि ऐसा करने से राज्य सरकारों को भी इस संस्था के भीत सहानभारि उत्पन्न ही जायगी श्रीर बेरोजगार के दफ्तरों का राज्य की सरकार तथा राज्य के अन्तर्गत व्यक्तियत मालिकों से सरहत्व स्थापित करने में भी यह सहायक मी सिद्ध होगी । विकेन्द्रियकर्या से प्रान्तीयता के बहुने तथा अन्तरमान्तीय जनसंख्या के श्रावासमन में बाधा पढ़ने का अय निर्मल है क्योंकि इन रोजगार के दफ्तरों की नीति तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निर्धारित होगी। इन संस्थाओं के कार्यों के प्रसार के सम्बन्ध में जो सुस्तात दिये गये हैं उनसे मातिकों तथा रोजगार के दश्वरों के बीच और बेरोडगार व्यक्तियों और रोजगार के दश्वरों के बीच श्रन्छ। स्वत्य भी स्वावित हो सकेगा । श्रदच श्रमिकों के सम्बन्ध में उनकी रजिस्टी न करने की धलाइ देने में ऐसा लगता है कि कमेटी इस कार्य के विस्तार तथा सम्मावित अधिक व्यव से विशेष अमावित हो गई थी। पर ऐसा करने से इसमें संदेह नहीं कि रोजगार के दफ्तरों की वेरोजगारी की समस्या सुलकाने के सम्बन्ध में उपयोगिता अनश्य कम हो बायगी।

#### श्रध्याय २६

# श्रोद्यांगिक गृह निर्माण

क्रीशोसिक ग्रह निर्माण की समस्या अधिकों की क्रम दिस्पे पर जपयक्त आवास प्रदान करने की है। दिनीय महायुद्ध के पूर्व भी बढ़े-बढ़े करवी श्रीर नगरों में विशेष कर श्रीशोशिक केस्टों में, रहने के लिये धरों का समाब था। अभिक लोग चील तथा वस्तियों में बड़े अस्वास्थ्य वातावरण में रहते हैं। गत कहा वर्षों में जन संख्या से बढ़ि होने, पाकिस्तान से सरखार्थियों के आने तथा व्यक्तिगत लोगो द्वारा कम संख्या में नये घनो के निर्माण के कारण दशा और भी ऋधिक कोचनीय हो गई है। १०३१, १६४१ और १६५१ की जनगणना के अनुसार जनसङ्गा म क्रमशः ११. १४'३ श्रीर १३'४ प्रतिशत वृद्धि हुई परन्त नागरिक चेत्रों में यह दृद्धि कमदा: २१, ३२ और ५४ मांतरात हुई। पाकिस्तान से लगमण द्धार लाख शरणाधियों के ब्रा जाने से नागरिक चेत्रों में जनसंख्या का दवाव बद्धा जिसके प्रभाव से बढ़ने की व्यवस्था और जटिल हो गई। शरणार्थियों ने गाँव की अवेद्धा बढे करवा और नगरों में ही रहना अधिक पसन्द किया। इससे नगरीं और करवों में रहने के लिए वरों की माँग बढ़ी परनत पति न हो सकने से यह अभाव की खाई चौदी होती गई। साँग के अनुसार वर्षे की पति न हो सहने का कारण यह है कि इमारत बनाने के सामान का अधिक महत्र होने के कारण श्रीर बाजार में सामान के श्रामाय के फलस्वरूप नई स्मारतों को पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाया जा सका। इसके साथ ही मकानों को किराये पर देने और किराये की दरों पर सरकारी प्रतिकृष्य लगाने से भी इस दिशा में प्रतिकल प्रभाव पहा श्रीर इसी कारण बढ़ती जनसंख्या के साथ मकानों की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

गृह निर्माख की प्रयूक्ति—वर्तमान में मुख्य यह निर्माण एजेन्सियाँ निर्माल विविद्य हैं :—(१) सरकारी अथवा अन्य एजेन्सियाँ, (२) उद्योगपति, (३) तहकारी अधवा अन्य एजेन्सियाँ, (४) उद्योगपति, (३) तहकारी समितियाँ, (४) अपने उपयोग के किए प्रकान कनाने वाले व्यक्ति, और (३) निजी उद्योग | निजी उद्योग के मालिकों की और अपने उपयोग के लिए यहनिर्माख कराने वाले व्यक्तियों की अथ यहनिर्माख की और गति मन्द हो गई । गत कुछ वर्गों में इस दिशा की और सरकारी वाग अन्य मिली-जुली एजेन्सियाँ, उद्योगपतियाँ और सहकारी समितियों की मिति में विरोप रूप से वृद्धि हुई है ।

प्रथम योजना काल में ७६,६७६ किराये के वर्श के निर्माण के कार्यक्रम

को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से १६,१६५ बलाई में, २१,७०६ उत्तर प्रदेश में. 4.600 हैटराबाद में. 4.१८१ मध्यप्रदेश में. ३.४४४ मध्यभारत में तथा इससे कम संख्या में शब्य राज्यों में बनवाये जाने वाले थे। जिसनी किराये के घरों का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के पर्व किया जा चका था उनकी सख्या ४०,००० के लगभग थी। जितने किराये के घरों के निर्माण की अनुमति दी गई है उनमें से ६८,२०० अथवा ८५% के लगभग राज्य सरकारी द्वारा, १०,१६१ अथवा १३% अभिकों के निजी उद्योग हारा और १.३१८ या १.६% उद्योगों में काम करने धालों की सहकारी समितियों हारा धनवाये जा रहे हैं। जब यह योजना निर्माण की गई थी उस समय सहकारी समितियों श्रीर मालिकों फे सहयोग की व्यधिक व्याशा की थी। योजना के इस पन्न पर विचार किया जा रहा है और ऐसे उपाय मोचे का रहे हैं किया कि मानिकों और कारखानों के अभिकों की सहकारी समितियों का अधिक सहयोग मात हो । इनके अतिरिक्त पनवांस, रहा, रेलवे, लोहा और इस्पात, उत्पादन, सूचना, निर्माख, यह निर्माख तथा पूर्ति द्यादि मत्रालयों द्वारा भी एड निर्माण के समस्त्रित कार्यक्रम कार्यात्यत किये जा रहे हैं। राज्य सरकार और ऊछ स्थानीय अविकारियों के अपने निजी यह निर्माण के कार्यक्रम भी चालु हैं। यह अनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पुनर्वास मन्त्रालय ने नगरों में ३,१३,००० किराये के घर वनवाये और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों ने. निर्माण, यहनिर्माण तथा पृति के मन्त्रासयो को छोड़ कर लगभग ३००,००० गरी का निर्माण करवाया। श्रान्य गृहनिर्माण की योजनाश्रों को, जिनका ऊपर वर्णन किया जा चुका है, समितित करते हुए सरकारी विभागों ने प्रथम गोजना काल में लगमग ७,४२,००० यहाँ का निर्माण करवाया । व्यक्तियत लोगों ने कितने यहाँ का निर्माण कराया उसकी संख्या जानना कठिन है। बर जाँच ब्रायोग के इस सम्बन्ध में परीचा करने से आत हुआ कि नगरों में गृहनिर्माण के सम्बन्ध में कुल विनियोग १९५३-५४ में सागमग १२५ करोड़ क्यबा था। यदि इसे हम पाँच वर्षी की श्रवधि का श्रीसत मान लें श्रीर एक घर के बनवाने में श्रीसत व्यय १०,००० ६० के लगभग मान लें तो यह जात होगा कि प्रथम बोधना काल में लगमग ६००,००० गहों का निर्माण व्यक्तिगत होत्र में हुआ। इस अकार प्रथम योजना वाल में लगभग १३ लाख घर नगरों में बनवाये गये ।

प्रथम योजना काल में प्रायों में भी रहने की शिवति में युधार के कुछ उपायों का प्रयोग किया गया है। धायुराविक विकास योजना चेत्रों से ५८,००० भ्राप्य शीचालय, १६०० भील लाखी नालियाँ और २७,००० कुँये वनवाये गये हैं

च्योर लगभग ३४,००० कुँबों का जीखोंद्वार किया गया है **स्त्रीर राष्ट्रीय** विकास देत्रों में ८०,००० ग्राम्य शीचालय, २७०० मील लम्बी नालियाँ. ३०,००० नये क्रेंगे श्रीर ५१०० पुराने क्ब्रों का जीगोंक्षार किया गया है। राष्ट्रीय विकास तथा सामदायिक विकास योजनाओं के जेत्रों में लगभग २६००० घरों का निर्माण , हुआ है और लगभग उतने ही पराने घरों का जीखींबार किया गया है। अनेकों राज्यों में ब्रामों से हेंट के सददे स्थापित किये जा रहे हैं। कहीं-कहीं पर सहकारी समितियों की सहायता इस कार्य में ली जा रही है। उदाहरखार्थ उत्तर प्रदेश में १६५ a.५१ में १६ सहकारी हैंट के मही खोले गये थे: १६५४-५५ तक उनकी संख्या बहकर ७५२ हो गई और महों के आस-पास के प्रामों में अधिकाधिक नय दंग के प्रके मकान बनते जा रहे हैं। बहुत से राज्यों में हरिजनों के आवास की स्थित की. विशेष भूमि चेत्रों की उनके लिये नियत करके तथा सहकारी ग्रहीनमां स समितियों की स्थापना हारा, सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत निर्माण, पूर्ति तथा पहनिर्माण मन्त्रालय ने शान्य गृहतिमांचा आगार की स्थापना की है जिसका ध्येय इस क्षेत्र की विभिन्न समस्वाओं का अध्ययन करना और एही के नये-नये आकारों, अभिन्यासीं, निर्माण के दर्तीतथा स्थानीय कबचे माल के प्रयोग करने के उपायों की जीज कामा है।

कठिनाइयाँ—प्राधक मकानी के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं:

(१) प्राप्त और नगर से सूमि, इस्लाव, ईंट, सिमेंट, लकड़ी की चीखट इस्वादि के मूल्य में बहुत वृद्धि हुई। यह वभी चीजें सकान बनाने के लिए बहुत श्रावरण हैं। इन बराइजों के मूल्य खावक होने पर भी यह-निर्माण संमय था परन्त प्रवेत वशी कितारों यह हैं कि इसके लिए पर्यांत पन नहीं मिल पाता हैं। पृथ्पी और यदि अधिक व्यय पर सकान बनाया जाय तो उत्तका किराचा भी श्राप्तिक होना चारिए परन्त यह निर्माण का कार्य तीन गति से करने का मुख्य उदेश्य यह है कि अधिक व्यय पर सकान बाय जो जी को तो के सत्ते कितारों पर मकान दिये जा सकों इस्वित्य धार है कि अधिक ते जा सकों इस्वित्य धार है कि अधिक ते सहान बनाने के सामान का मूल्य घटाया जाय; महंगे सामान के स्थान पर सरते मूल्य का कोई पूर्वा उपयुक्त सामान तमायों का प्रवेत अधिक तमाने के लिए सकान के आकार-जकार और उपके हीने इस्वादि के स्वाद सामाने के सामान के मूल्य पराने से का कार्य किया सामा परन्तु पर यह हिम्माण के स्थान में के समन्त्र में सोज कार्य किया सामा परन्तु यह यह दिस्तार्य के समन्त्र में सोज कार्य किया सामा परन्तु यह यह एक निर्माण के व्यय में पर्यांत करने में सामान कर सी यह निर्माण वीकारा को कार्यांत्र करने कर निर्माण कर निर्माण के सामान्त्र करने कर निर्माण कर निर्माण को कार्यांत्र करने कर निर्माण कर निर्माण कर निर्माण कर कर निर्माण कर निर

लिए रुपये की आवश्यकता होगी और जब तक पर्याप्त घन, जो कम से कम १०० करोड़ रुपया होगा, प्राप्त नहीं होता तथ तक सभी आवश्यकतामस्त लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। बाजार में २०में की तगी है और जनता के पास पर्याप्त घन नहीं है। इसलिए घर बनाने के इस्कुत लोगों के जनता के पास पर्याप्त घन नहीं है। इसलिए घर बनाने के इस्कुत लोगों का बनाव पर रुपया देने के लिये कुछ उपाय सोज निकालना आय्यन्त आवश्यक है।

(२) मकानो का किराया बहाने पर राज्य उरकारो ने प्रतिवन्ध ताना दिवा है। सकार तथा अन्य एकेस्तो, उद्योगपति और सहकारी समितियों लाम की चिन्ता किये मिना यह निर्माण कार्य में कृति कर पकती है। परन्त किराये पर निर्माण कार्य ने कृति कर पकती है। परन्त किराये पर निर्मय का जाने के और नमर्थे तथा कर्लों में मकानो का एकीटमैंट करने की व्यवस्था से तिजी उद्योगों के मालिक नये मकान वनराने की और से स्यामान निराश हो चुके हैं। कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि एक निश्चत तिथि के परचाद वने नमें मकानो पर जह नियमकाथ लागू नहीं होते हैं इस्ते नमें मकान वन्त्राते के कार्य की प्राप्त करना के कार्य की स्थापना कर किराये मकान

१६५२ में पशिया बीर सुदूर पूर्वी ब्राधिक अम्मेलन का यह निर्माण विययक अधिवेदन दिल्ली में हुझा था। इस जम्मेलन में मुक्काव दिने गने में कि (१) ब्राइश्चे पोजनाएँ खालू की जॉन जिनमें इस्पात और इमारती सक्यों के स्थान पर मेंस तथा सम्य लक्षकियों के उपयोग की जॉन की जाय और (२) हुसी प्रकार की ब्रुट्ट योजना हो जॉन की जाय और (२) हुसी प्रकार की ब्रुट्ट योजना हो हो हो भी भी जाँच की जाय। इस प्रकार की ब्राइश्चे योजनाओं के हारा इस अभिकी तथा प्रभन लोगों के लिये सत्ते और सुल्हाई सकानों का निर्माण करने के उपाय लोग क्रम्बर हैं।

सरकारी योजनाएँ— जीवोगिक शांति प्रस्ताव में सुकाव गये यह निर्माण कार्य कम के आधार पर मारत सरकार ने १६४६ में एक यह निर्माण योजना तैयार की। इस योजना में यह बादस्या की गई कि राज्य सरकारों तथा कमेंचारियों इस्थादि के द्वारा बनाये जाने वाले मकानों में जितना क्षया लगेगा उसका हो तिहाई के न्द्रीय सरकार ब्याज मुख्य के कर में देगी, परन्तु इसके लिये मालिकों को मी कुछ शर्वे माननी पड़कों। इस योजना के अनुसार मालिक तथा राज्य सरकारों को एक दिहाई व्यय को स्वयं व्ययस्था करनी पड़ती है। केन्द्रीय परकार के उन्हें केन्ज इस हाना ही लाम प्राप्त है कि आवश्यक धूंनी का है अंग क्यावसुक्त सुख्य के रूप में प्राप्त है जाता है।

परन्तु इस योजना के ग्रासफल हो जाने पर मारत सरकार ने यह ग्रामुभव

दिया कि तह निर्माण कार्य को पोत्साहत देने के लिये राज्य सरकारों और कारखाने इत्यारि के मालिको को इसके लिये नकद आर्थिक धहायता देनी पडेगी। इसी विकार से एक शोबका विस्तान की गई और उसे प्राय: सभी राज्यों की सरकारों के पाम विचारार्थ भेजा गया। इस योजना में यह प्रस्ताव स्वा गया था कि गृह fapin कार्य को पोत्साहज हेते के लिये राज्य सरकारों सथा निजी उद्योगपतियों को भूमि के मूल्य का अधिक से अधिक २० प्रतिशत केंद्रीय सरकार सहायता के कप में देशी । परन्त इसके लिए यह अलेलगाई गई कि (१) मकान बास्तय में अमिकी को किराये पर दिया जायगा. (२) किरायेदार से घर की कुल लागत का. जिसमें भीम का मन्य भी सम्मिलित है, केवल ढाई प्रतिशत ही वसल किया जायगा परन्त यह किराया अभिक की आय के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये. (३) धर वेन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आकार प्रकार के बनने चाहिएँ और (४) घर का निरीक्षण करने के लिये केन्द्रीय लघा राज्य सरकारों के निरीक्षको श्रीर गृह-निर्माण बोर्ज को सभी श्राधश्यक सविवारों दी जानी चाहिएँ। इस योजना का कार्यक्रेत्र सीवित या ह्यौर राज्य सरकारों ने इस ह्योर विशेष स्थान नहीं दिया। इसलिये भारत सरकार ने १९५२ के खंत में एक अधिक व्यापक योजना तैयार की जिसके अन्तर्गत यह व्ययस्था की गई कि फेन्ट्रीय करकार ग्रहीनर्माण कार्य को मोत्लान देने के लिये राज्य सरकारों और यहनिर्माख बोर्ड को कुल न्यय का ५० प्रतिशत तक सहायता के रूप में देशी। इसमें भूभि का मुख्य भी समिमलित किया जायमा ! शेष ५० प्रतिशत के लिये सरकार ४ - प्रतिशत व्याज पर ऋशा देशी जिसे २५ वर्ष के श्रम्दर खकाया जा सकता है। सहकारी समितियों के सरवन्त्र में यह ब्यवस्था की गई कि गृह निर्माण के कला ब्यय का २५ प्रतिशत सरकार सहायता के रूप में देशी और साथ ही कुल निर्माख्-व्यय का ३७ई प्रतिशत धन ४८ प्रतिशत वार्षिक स्थाल पर अपूरा देशी जिसे १५ वर्ष के अन्दर चकाया जा वकता है। उद्योग के मालिकों को सरकार कुल लागत का २५ प्रतिशत श्राधिक सहायता के रूप में श्रीर कुल ब्यय का ३७ मतिशत तक ४ मिनशत वार्षिक व्याज की दर से ऋगुण देगी। यह ऋगुण १५ वर्ष के श्रान्दर चुकाना होगा। इन सम के सम्बन्ध ने ऋणा तथा अनुदान की मात्रा स्टेन्टर्ड लागत के आधार पर अनुगणित मात्रा पर हो सीमित कर दी जायगी। बम्बई और कलकत्ता के सम्बन्ध मे १ कमरे वाले कई मजिले मकानों की स्टेन्डर्ड लागत ४५०० रुपया श्रीर श्रन्य स्थानों में २७०० रुपया आँकी गई है। दो कमरे वाले कई मंजिले मकानों की बम्बर्ड ग्रीर कलकत्ता में लागत ४५३० स्पया (जो कि श्रव बढाकर ५६३० स्पया कर दो गई है) और अन्य स्थानों में २४६० रुपया आंकी गई है। एक मंत्रिले -सकानों के लिये स्टेन्डर्ज लागत का अनुमान कम यन गांश है।

इस पुर्नगरोद्धित योजना की दो गुरूव विशेषवायें हैं: (१) बहकारी सांमितयों को क्या की ५०% तक ऋषु रूप से यहायता मिल सकेगी जबिक मूल योजना के ख़रवारंत नेशक १५६ दें मिल सकती थी और १६ वर्षों में ख़्या के सुकता करने के स्थान पर कहा १५ वर्ष का समय भी मिल आयगा; और (१) स्टेन्स्ट कि हाया कि सिल आयगा; और (१) स्टेन्स्ट कि हाया कि सिल आयगा; और (१) स्टेन्स्ट कि हाया कि सिल प्रकार के मकानों के लिये दम्ब तथा कलकचा में १० करवे से लगाकर २० करवे से लगाकर १० करवे से लगाकर १० करवे से लगाकर १६ करवा तक नियल कर दिया गया है। इससे योजना ख़िरक पूर्वे बन गई है। यह असात की आनतों है कि यह निर्माण कार्य की इस योजना के अन्तर्गत प्रिक्त प्रकार करवे के स्वन्तर्गत प्रिक

आर्थिक खहाबता मात्त एह निर्माण योजना के अन्दर्गत, जो जितन्तर १९५२ में लागू हुई, १९५७-५८ केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्दर की गई पनराधि १५-७६ करीक व० थी जिलमें १३-१८ करोड़ व० श्रु या के रूप में तथा १२-५१ करोड़ व० आर्थिक खहाबता के रूप में बी इसके अन्तर्गत ९१,२५० घर ये। नवस्नर १९५७ तक पूर्ण हुने मकानों की संख्या ६६,७०० थी तथा शेष निर्माण के विभिन्न बरणों में से।

हितीप पचवर्धीय योजना के अन्तर्गत अधिशिक तथा अन्य यह निर्माण योजनाओं के लिये अधिक धन सहायता में देने का निश्चय किया गया है। प्रथम योजना में इन्से करीक कथां की सहायता का प्रवस्थ किया गया था परन्त दितीय योजना में १२० करीक दश्यों की सहायता का निम्न तालिका के अनुसार प्रवस्थ किया गया है:—

प्रया करीड रूपये सहायता प्राप्त श्रीशोगिक यह निर्माण 12 निस्न द्यायन्यर्ग के जिये गई निर्माण Y0 प्राम यह निर्माण 80 वस्तियों की सफाई स्त्रोर भंगियों के लिये यह निर्माण 12 11 20 सध्य वर्ती आय वर्ग के लिये गृह निर्माण ... 3 m \*\* रोपणोयोग के लिये यह निर्माण 2 11 33 15 योग १२०

द्वितीय योजना के अन्तर्गत व्यय की योजना अधिक विस्तृत है और अनेको नये व्यय के शीर्ष उसमें सम्मिखित कर लिये गये हैं जो कि प्रयम योजना में नहीं ये और कार्य का व्यय जिस्स है :----

ग्रीयोगिक गृह निर्माण	३०१
श्चादातिक दूर त्या	गृहीं की संख्या
	१२८५,०००
सहायता प्राप्त ग्रीद्योगिक घर	६८,०००
तिम्न स्त्राय वर्ग के लिये घर बस्तियों में रहने वालों के लिये नये घर	220,000
: •+नी भी समिलित ह	4,000
अ वर्ज के लिय घर	११,०००
रोपण उद्योग के अमिकों के लिये घर	१,३३,०००

٠.

3.

v.

u.

ग्रामीण गृह निर्माण योजना 8,44,000 6. स्रम्य केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा, राज्य सरकारो तथा स्थानीय स्रिषकारियों जोज अन्य प्रश्नात प्रशासना करण, अन्य वाले अमिकों के लिये यह निर्माख द्वारा तथा कीयलें की खानों में कार्य करने वाले अमिकों के लिये यह निर्माख सम्बन्धी कार्यंकम के कारण व्यक्तिगत लोगों द्वारा बनवाये घरों के अतिरिक्त ७५२,००० गृहों का (जिनकी संख्या ८००,००० के लगभग द्वितीय योजना काल में श्रीकी गई है) निर्माख होगा। इस प्रकार द्वितीय योजना में कुल १९ लाख घरी के निर्माण का अनुमान है जबकि प्रथम योजना काल में केवल १३ लाल घरों का

. . . . . . द्वतीय योजना के पहले तीन वर्ष में ग्रह निर्माण के ऊपर किये जाने वाले ही निर्माण हुआ था। कुल ब्यय का अनुमान ४० करोड़ है। "आधिक सहायता प्राप्त आँचोमिक यह कुण प्रमाण के अन्तर्गत १९५६-५६ इन तीन वर्षों में ४२,६०० इकाइयों के निर्माण की ब्यवस्था है। निस्न स्त्राय वर्ग के स्नन्तर्गत २२,००० इकाइयों के निर्माण की तथा भीगयों के गृह निर्माण के अन्तर्गत २२००० इकाइयों के निर्माण की ब्यवस्था है। माभीख ग्रह निर्माख योजना १९५८-५९ में प्रभावपूर्ण दंग से लागू की जारही है। चूँकि द्वितीय प्वयर्पीय योजना में काट-छाँट हो रही है स्नतप्य गृह्मिर्माण के लिये संशोधित राशि १०० करोड़ ६० होगी जो प्रारम्भिक सांश से २० करोड़ ६० कम है। ४५०० करोड़ ६० के कुल ब्यय में यह निर्माण पर किया जाने वाला व्यव ८४ करोड़ इ० है। इसमें ६४ करोड़ इ० राज्यों के लिये है तथा २० करोड़ ६० केन्द्र के लिये है।"

## श्रध्याय ३० श्रम की कार्यक्षमता

यह लोक प्रसिक्ष है कि भारतीय श्रीमक निपुष्य नहीं है। उसकी प्रति घंटा उत्पादन राक्ति भी बहुत कम है। यदि धारचारय देशों के उसी प्रकार के श्रीमकों की उत्पादन राक्ति से तुलना को जाय तो पता चलेगा कि भारतीय श्रीमकों का उत्पादन यहुत निरा हुआ है। जापान, ब्रिटेन ख्रीर अमरीका के श्रीमक की अपेक्षा उतने ही समय में भारतीय श्रीमक बहुत कम कार्य कर पाता है।

सूती मिल उद्योग संबन्धी प्रशासक मण्डल (१९२६-२७) ने बताया कि भारतीय श्रमिक ख्रयचा ख्रापरेटर ने १८० सक्कश्रों पर कार्य किया जब कि इतने ही समय में जापान के अमिक ने २४०. हंगलैंड के श्रमिक ने ५०० से ६०० के बीच श्रीर श्रमरीकी श्रमिक ने ११२० वक्तश्रों पर कार्य किया। मारतीय द्यनकर श्रीवतन २ कर्ने चलाता है अब कि जापान का बनकर २५, ब्रिटेन का ४ से ६ तफ ब्रीर ब्रमरीका का ६ कर्षे चला लेता है। इनसे भारतीय अमिक की सापेश्विक कार्यच्चमताका द्याभाष मिलता है। यहाँ यह बता देना द्यायरपक है कि गत कुछ वर्षों से कतित्रव सती मिलों में कार्यज्ञमता में काकी बुद्धि हुई है। सूती उद्योग सम्बन्धो वर्किक्त पार्टी (१६५२) ने जाँच करके पता लगाया कि दिल्ली की एक श्रीर मद्रात की दो मिलों में एक बनकर ४.६. द और १६, ब्राइमदापाद की एक मिल में १⊏ श्रीर बम्बई की एक मिल में ६ कर्षेचला लेता है। कार्यह्ममता में इस दृद्धि का कारण यह है कि इन मिलों में स्वचालित ब्राधुनिक मशीनें लगी हुई हैं निससे अभिक अभिक काम कर सकता है परन्त कार्य में इतनी प्रगति होते हुए भी द्याज तक यह मात स्य माना जाती है कि भारतीय अभिक ब्रिटेन या जापान के अपने ही प्रकार के अमिक से कम निपुत्त है। काथला-पदान उद्योग के सम्बन्ध म भारत की निश्रोणांजीकल. माइनिंग ग्रीर मेटालर्जीकल सोसाइटी के २८ वें वार्षिक श्रिषिवेशन के अरुपद्म के भाषण में बताया गया कि भारत में एक अनिक का उत्पादन २'७ टन है जब कि ब्रिटेन के मजदूर का ६'२६ टन, जर्मनी के अमिक का ८ १६६ टन ग्रीर श्रमरीका के श्रमिक का २१ ६८ टन है। भारतीय श्रमिक का प्रतिषरटा उत्पादन गत कुछ वर्षों में गिरा है। योजना त्र्यायोग ने बताया है कि कोयला खदान उद्योग में कार्य करने वाले श्रामकों की संख्या १९४१ में २, १४, २४४ से बहुकर १९५१ में ३,४०,००० हो गई है जन कि इसी अवकि में कीयले

का उत्पादन २ करोड़ भूम लाख ६० इवार उन से बदुकर ३ करोड़ ४० लाख टन हो गया। इस प्रकार जब अभिको की संख्या में भूम प्रतियत चृद्धि की गई तो उत्पादन केवल ३२ प्रतियत बढ़ा है परन्तु अभिक्त का प्रतिषण्टा उत्पादन १२७ टन से गिरकर सनभग १०० उन हो गया।

यदार सभी उद्योगों के सम्बन्ध में विम्तृत सुचना प्राप्त नहीं है फिर भी १९५५ में प्रकाशित कतिपय उद्योगों की उत्पादकता और खर्जित खाय के परियतनों से निम्म बार्ते शांत होती हैं :

(i) कोयला उचोग में १९५१-१९५४ के बीच खोदने तथा लादने यातों की उररादकता में ०°०५६ मति माह वृद्धि हुई जशकि मति सप्ताह नकद स्नाय में ०'२६ की वृद्धि हुई।

(ii) कामाज उद्योग में, १९४८-१९५३ के बीच सजदूरों की छौधत छाप में तो वृद्धि हुई किन्छु इनकी उत्पादकता बढ़ने का कोई चिन्ह सबी था।

(iii) जुट उद्योग में १९४८-१९५३ के श्रीच उत्पादकता की दृद्धि २'६ मतिवर्ष भी जबकि खर्जित छाप की दृद्धि ३७ भी तृष्टा.

(iv) स्ती वस्त उद्योग में उत्पादकता की वृद्धि की वार्षिक दर १६४८-१६५३ के बीच २०२८ यी जबकि आर्जित आय की वृद्धि १.१४ यी ।"

इसके विपरीत अमरीका और क्रिटेन के असिक की कार्यक्रमता में निरन्तर वृक्षि होती का रही है। अमरीकी अभिक की ग्रांत्वपदरा उत्पादन समता में १६१० तथा १६४० के बीच कर भिवात वृक्षि हुई। विपात १५ वर्षे में इतमें और अधिक वृक्षि हुई। वर्ष के अप के अप के अप के विप्त के कि यदि उत्पादन समता हुए अनुपात में बढ़ती गई तो १० वर्षे में रीगुनी हो बावगी। उत्पादन सिक की आंव करनेवाली एक आंक्ष-अमरीकी परिषद ने ब्रिटेन के लीहे और इस्पात के कारवाने के कुछ विभागों की जांच की। परिषद की रिवोर में बताया गया है कि १६१६ से १६५६ के बीच रहील पंडिंग में १५ से २० प्रतिश्वात की और द्वाप-शिक्ष में १० प्रतिश्वात की वृक्ष द्वाप-लोडिंग में १० प्रतिश्वत की और द्वाप-लोडिंग में १० प्रतिश्वत की वृक्ष द्वाप के स्वर्थ के अल्व भारतीय अभिक ही उत्तरायां गरी है। इसका बहुत कुछ कारवा साम महीने और रीप पूर्ण जीवा की साम की महियोगीमत संगठन है। परन्त इसका परिवाम यह अग्वरण प्रवृक्ष के विकास महीने और रीप पूर्ण जीवा की प्रतियोगीमता सांत वर रूप में है और विश्व बालार में अपने माल की निकासी करने में उसे अस्वरण करिनाइयों का सामना करना पर रहा है।

कारण-श्रमिक की कार्यसमता श्रथवा उसकी निपसता की परिभाषा करता बहुत कांत्रन है और यह अनेक बातों पर निर्धन करती है। अधिक की कार्यक्रमता की जाँच करने का एक व्यवहारिक दंग श्रमिक के प्रतिचरटा उत्पादन की जॉच बरता है। एक अमिक की एक जिपट के कल जलाइत के हिसाब से भी कार्यसमता का पता लगाया जा सकता है। एक शिफट में ७३ या ध्र घएटा कार्य होता है। इसके साथ ही अगिक के वार्थिक उत्पादन की मान्ना को मी हमदा साध्य द्वाया जा सकता है। अभिक की कार्यन्याता केवल अभिक के अस कर ही निर्मार नहीं रहती है । करूने माल के प्रकार, मजीनों के प्रकार स्वीर उनकी क्षिति और सम्पर्ध औरोोगिक सगठन का भी उस पर प्रभाव पहला है । अकशलता व्यथवा निप्रण न होने के लिये सारा दीप भारतीय अमिक पर धी नहीं मदा जा सकता । कल दोष प्रावण्य अभिक का भी है परन्त जिस प्रशाली के प्रान्तर्गत वह कार्यकरता है उसे इस धारोप से वंचित नहीं किया जा सकता। जद इस मारतीय अमिक की कार्यसमता और ब्रिटेस, खमरीका या खन्य देशों के अमिकी की कार्यक्रमता की तलना करते हैं तो हमें दोनां देशों के कारखाने में लगी मशीनी क्रीर कार्य की स्थित पर भी विचार करता चाहिए। परत्त फिर भी इन सभी बाती पर विचार करने के बाद भी यह सही है कि भारतीय अभिक की कार्यचमता द्यमरीकी तथा ब्रिटिश अमिक की कार्यचमता से कम है।

दुवेल रारीर तथा बुरा स्वास्थ्य—रिंग्से कुछ जन्देह नहीं कि भारतीय अमिक का स्वास्थ्य मिटिया या अमरीकी अमिक की अपेका विशा हुआ है। मस्त भारतीय अमिक और विश्व या अमरीकी अमिक की अपेका कि स्वास्थ्य की दुलना करना नहीं है। वास्तव में प्रश्न वह है कि भारतीय अमिक वो काम करता है वह उर्च काम के लिये उपयुक्त है या नहीं। यदि वह उर्च काम के लिये उपयुक्त है तो यह कहांग उचित नहीं कि ब्रिटिश अथवा अमरीकी अमिक की अपेक्षा स्वास्थ्य अधिक सहांग उचित नहीं कि ब्रिटिश अथवा अमरीकी अमिक की अपेक्षा स्वास्थ्य अधिक सहांग डिंग के कारख भारतीय अमिक की कार्यक्षमता अपेक्षकत कम है। स्वास्थ्य ठीठ न रहने पर विश्व , अमरीकी भागः उमी अमकी का उत्पादन विर वाता है, उनकी कार्यक्षमता कम हो वाती है। इचित्रंय भारतीय अमिक की अकुशालता का कारण उचकी बीमारी या दुबेलता नहीं हो सकते हैं।

- (ii) प्रवासी प्रशृत्ति—मारतीय अभिक की प्रवासी प्रवृत्ति से भी उसकी ग्रुकुरालता नहीं सिद्ध की जा सकती क्योंकि जबतक श्रीमक काम करता है तबतक श्रीवोगिक केन्द्रों में रहता है और इस बीच वह अपनी सम्पूर्ण योग्यता के अनुकृत कार्य कर सकता है। बीच-बीच में गाँव चले जाने से एक निश्चित लाभ यह होता है कि कारलाने के काम से कुछ दिन का ख़बकाय ले कर कारलाने के नियमित कार्य से इस्र जाने के कारण एक नई शक्ति प्राप्त करता है इससे पुन: कारलाने लोटने पर यह पहले की अपेचा अधिक कार्य कर सकता है।
  - (iii) कुरालता का प्रभाव—रंची प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि ्रा अरावाया का नमाथ-रण नगर निर्माण कर है, क्योंकि यदि अमिक कुराकता न होने के कारण ही उसकी कार्यक्रमता कम है, क्योंकि यदि अमिक एक विशेष कार्य करता है तो इसका कारण ही यह है कि वह इस कार्य की छन्य कार्यों की अपेचा अव्ही प्रकार कर सकता है। कुशलता का अभाय तभी होता है जब कुराल टेकनीशियनों का अभाव हो परन्तु बहाँ कुशल टेकनीशियन काम करते ई वहाँ उनकी कार्यक्षमता उतनीही शिक्षा पाये हुए श्रम्य देशों के टेकनीशियनों से कम नहीं होनो चाहिये। जहाँ तक ऐसे कार्य का सम्बन्ध है जिसको करने में विशेष कुशलना की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ कुशलता के ग्रमाय का प्रश्न ही नहीं उठता।
    - (iv) कम मजदूरी —यह कहा जाता है कि पारिश्रमिक कम होने के कारण ही अमिक की कार्यचमता कम है। इसके समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि कम पारिश्रमिक होने से श्रमिक श्रपना श्रीर श्रपने परिवारका ठीक से भरण-पोषण नहीं कर पाता है। इससे उसकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पक्ता है। परन्तु यह जानना चाहिए कि इन सब बातों का कारण पारिश्रमिक कम होना नहीं है वरन् मूला स्तर की तुलना में पारिश्रमिक का श्रभाव है। यदि श्रमिक का पारिश्रमिक कम हों और जिन बस्तुओं पर वह अपना पारिश्रमिक ब्यय करता है उनके भूरूप और भी कम हो तो उसे अपने परिवार का भरण-नोपण करने में कुछ क्रितनाई नहीं होगी। यह अपनी आवश्यकता पृति के लिए सभी बस्तुएँ क्रय कर सकता है। वास्तव में गुख्य समस्या यह है कि पारिश्रमिक बस्तुत्रों के मूल्य की अपेक्षा कम है। इसी कारण अभिक अपने परिवार को पेट मर मोजन नहीं दे पाता है श्रीर उसकी अन्य आवश्यकताएँ मी पूर्ण नहीं हो पाती। इससे उसकी कार्यं समता की स्नांत होती है। प्रश्न पर्याप्त मोजन न पाने आरे जीवन को सुखी बनाने के प्रसायनों को न पान का नहीं है। वास्तव में अमिक यस्तुख्रों के मूल्य की श्रुपेश्वा पारिश्रमिक कम होने के कारख परिवार का ठीक 'तरद के प्रबन्ध भी न**हीं** कर पाता । इससे उसे सदैव चिन्ता लगी रहती है जिससे खंत में उसकी कार्यस्मता

पर प्रभाव पहला है। इस प्रकार एक दुष्चक स्थापित हो जाता है, उसकी कार्यव्यमता पर जाती है और तल्यादन कम हो जाता है। पारिश्रमिक होने से कार्यव्यमता नहीं बढ़ पाली है और जय तक कार्यव्यमता में बृद्धि नहीं होते से कार्यव्यमता नहीं बढ़ पाली है और जय तक कार्यव्यमता में बृद्धि नहीं होते पारिश्रमिक नहीं बढ़ सकता। बढ़ी कारण है कि भारतीय श्रमिक हतने वर्षों के प्रचात मी खान निर्धेन ही बना हुआ है। यदि श्रमिक का पारिश्रमिक वह जाय और हसके फलस्वरूप उसकी कार्यव्यमता में भी वृद्धि हो तो वह भविष्य में और अधिक पारिश्रमिक कमा सकता है। जहाँ तक पारिश्रमिक का सम्बन्ध है, द्वितीय महायुव से शमकों की स्थित में खुषार हुआ है। रहार से १९५२ के शिष्मारातीय श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई परन्तु दुर्भाग्य से पारिश्रमिक वहने मारातीय श्रमिकों की मजदूरी में सी वृद्धि हुई और खनेक वस्तुओं की कीमतों में मजदूरी की अपवा बस्तुओं के कुमतों में मार्श्विक की अपवा बहुत ख़िक हुई। १९५२ और १९५२ के शिष्म मजदूरी की अपवा बहुत ख़िक हुई। १९५२ और १९५२ के शिष्म मजदूरी की अपवा बहुत ख़िक हुई। १९५२ और १९५२ के शिष्म सम्बर्ध के बास्तिक पारिश्रमिक में बहुत बृद्धि नहीं होती ख़र्णात ख़पने द्वासिक पारिश्रमिक से वस्तुओं और सवा खो की अपवा समा में नहीं खरीर पारा श्रमिक की कार्यव्यमता में वृद्धि नहीं हो उसती ख़रीर सवा श्रमिक की कार्यव्यमता में वृद्धि नहीं हो उसती कराता श्रमिक की कार्यव्यमता में वृद्धि नहीं हो उसती ख़रीर सवा श्रमिक की वा स्थापन सम्बर्ध की कार्यव्यमता में वृद्धि नहीं हो उसती ख़रीर सवा श्रमिक की कार्यव्यमता में वृद्धि नहीं हो उसती ख़रीर सवा श्रमिक की कार्यव्यमता में वृद्धि नहीं हो उसती ख़रीर सवा श्रमिक की कार्यव्यमता में वृद्धि नहीं हो उसती ख़रीर सवा श्रमिक की कार्यव्यमता में वृद्धि नहीं हो उसती ख़री ख़री हो सा श्रमिक की कार्यव्यमता में वृद्धि नहीं हो उसती हो स्वरमा हो हर स्वरमा हो हर सवा हो हिस्स सवा में नहीं हो उसती हो सा स्वरमा हमा स्वरम्ध की कार्य सवा में नहीं हो हो ख़री हमा स्वरमा हमा स्वरम्ध की स्वरम्ध की स्वरम्ध की स्वरम्ध कार्य हमा स्वरम्ध की स्वरम्ध की स्वरम्ध की स्वरम्ध की स्वरम्ध कार्य हमा स्वरम्ध की स्वरम्ध की स्वरम्ध की स्वरम स्वरम्ध की स्वरम्ध की स्वरम्ध कार्य स्वरम स्

इसमें कोई छन्देह नहीं कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय अभिक की मजदूरी कम है। यदापि हाल में द्राव्यिक तथा वास्तविक मजदूरी में दूखि हुई है किन्तु इसके साथ भारतीय अभ की अमता में देशी दूखि नहीं हुई है। अम-मंत्रालय के अम-कार्यालय हारा १९५६ में कैन्द्री की अजिंत स्राय सम्बन्धी प्रकारित विवरण में किन्तु कि स्वार्थी प्रकार सम्बन्धी प्रकारित विवरण में किन्तु कि स्वार्थी प्रकारित विवरण में किन्तु कि स्वार्थी प्रकारित विवरण में किन्तु कि स्वार्थी प्रकार किन्तु की स्वार्थी प्रकारित विवरण में किन्तु कि स्वार्थी प्रकार किन्तु की स्वार्थी प्रकार किन्तु की स्वार्थी प्रकार किन्तु की स्वार्थी की स्वार्थ

१—मारत में फैन्ट्री में काम करने वालों की कुल अर्जित आय (रेखने वर्कयान योग्मालत नहीं है) १६४७ में १३७१३ करोड़ रु० थी जो १६५५ और १९५६ में बहुकर कमशाः २५५ करोड़ रु० २६६५ करोड़ रु० हो गई। स्थापी उद्योगी में लगे तथा २०० रु० मति आह से कम वाले वाले व्यक्तियों की वार्षिक आय १६४० में ७३० रु० थी। १६५५ और १६५६ में बहुकर यह कमशाः १,१७४ रु० तथा १२१३ रु० हो गई।

२—१६४७ से १६५६ तक दस वर्षों में मारतीय उद्योगों में मजदूरों की वार्षिक आम में मदत्वपूर्ण दृष्टि हुई है। चमहा उद्योग में ४% तथा सीमेन्ट उद्योग में १६३% हुई है। सम्बन्ध देश को व्यान में रक्तरी हुई कहा जा सकता है कि प्रति मनदद वार्षिक आम में ६३% को जहि हुई है।

३—भम कार्यालय द्वारा प्रकाशित आॅकड़े वास्तविक आय अथवा रहन-सहन के स्तर में कोई सुवार नहीं प्रकट करते। १६४७ से १६५६ के बीच में अमिक वर्ग से सम्बन्धित मूल्यों में २१% की वृद्धि हुई है तथा सामान्य मूल्य स्तर में ३९% की वृद्धि हुई है जब कि ब्रौसत द्राव्यिक सबद्री में ६३% की वृद्धि हुई है। इससे रहन-सहन के स्तर में होने वाली वृद्धि का अनुमान समाया जा सकता है। यद्यपि द्राव्यिक एवम वास्तविक मसदरी में वृद्धि हुई है किन्त भारतीय श्रम की उत्पादकता में उस ग्रानपात में बढ़ि नहीं हुई है।

(v) जलवाय-अधिक की कार्यज्ञमता में कमी होने का एक महत्वपूर्य कारण भारत की जलवाय है। वर्ष के अधिकांश माग में न केवल खीधीनिक अधिकों को बाज सभी लोगों को शासत्य और शिथिलता चेरे रहती है। इससे कदिन परिश्रम का काम एक प्रकार से असंगव हो जाता है। ब्रिटिश तथा जापानी अभिक की अपेसाइत अधिक कार्यसमता का एक कारण उन देशों की जलवाय भी है। भारत में भी विभिन्न खेत्रों के शमिकों की कार्यखमता में जलवाय

के अनुरूप श्रंतर है।

(vi) भारतीय बढ़ोगों दारा घटिया माल का उपयोग-भारतीय श्रीमक की कार्यचमता कम होने का दूखरा महत्वपूर्ण कारण यह भी हैं कि भारतीय उलोग षटिया प्रकर के कच्चे भाल का उपयोग करते हैं, कारलानों में पुरानी और विसी दरी मशीनें हैं, मिली के नियोजन में दीय है और औद्योगिक सगठन खराब है। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व (मल-मालिको पर है। यदि वह अब्छे मकार का कच्चा माल दें और कारखानों से अच्छी मशीनें लगाये ती मारतीय अमिक की कार्यक्रमता बढ़ेगी और अभिक के प्रति धरटा उत्पादन की मात्रा भी पहले की अपेडा अधिक होगी। कारखानों में पुरानी मशीनों के स्थान पर आधिनिक मशीनों को लगा सकता वर्तमान में संमव नहीं हो सका क्योंकि (१) इसके लिए श्रावश्यक वित्त का अभाव है. (२) मशीनों इत्यादि और टेकनिकल सामान का उपलब्ध हो सकता कठिन है. (३) भारतीय मिल-मालिक आधुनिक मशीनों के लाभ से अपरिचित हैं और (४) कारखानों के बुक्तिकरण का अभिकी द्वारा विरोध किया जाता है। मारतीय अभिक मशीनों के यक्तिकरण का और परानी विधी मशीनों को बदलने का तीव विरोध करता है। असिकों का कहना है कि इससे वेरोजगारी होती है। मारतीय अभिक की कार्यक्रमता कम है क्योंकि कारखानी की मशीर्ने परानी और विश्वी-विटी हैं इसलिए जब अभिक इन मशीनों को बदलने का विरोध करता है तब बास्तव में वह अपनी कार्यक्रमता में सवार को रोकता है। युक्तिकरण के ऋष्याय में बताया गया है कि मशीनो के युक्तिकरण से बेरोजगारी फैलना आवश्यक नहीं है, यदि बेरोजगारी फैलती है तो समी खोगों की तरह अमिकों को भी प्रगति के लिए यह कब्ट केलना ही पड़ेगा ! यदि मशीनों में सुधार होने से बेरोजगारी फैलवी है ब्रीर अभिकों की कुछ चित होती है तो दीर्घ काल में अभिक की कार्यदास्ता में बृद्धि होने से ब्रीर खांघक धारिश्रमिक रिकटो से कह हाति लाम में बदल जाती है।

श्रीमक की कार्यच्याता की कभी बहुत कुछ उसकी मानसिक स्थिति पर निर्मेर करती है। कार्यच्याता में कभी होने के सभी कारचों में प्रमुख यह है कि मारतीय अभिक विवास प्रिय है और उसमें श्रुत्यावन का श्रामाव होता है। जब तक अमिक अपने उसरदायित्य को नहीं समकता , श्रीर जब तक मिल-मालिक क्षेत्र अपने हितों को समान नहीं समकता तब तक वह श्रुप्ती पूर्ण योभवा प्रमुख हमता ते कार्य नहीं करता है। उत्पादन शक्ति रखते हुए भी श्रुपनी कार्यच्याता से क्ष्मी धनाये रहता है। वह दुर्भाय की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अभिक्रों की विचार धारा में पहले की खपेचा और दुराई खा गई है। अभिनें में कारवालानों में काम धीरे करते की नीति अपना ली है जिसका श्रुप्य यह है कि कार्य करने के स्थान पर कार्य श्रुत्यनत बीरे-बीरे करते की नीति अपना ली है जिसका श्रुप्य में वह कि कार्य करने के लिए निर्मारित स्थान कर एक कारच्या पालिकों को श्रुपना में मानने के लिए मजबूद करना है। परन्तु हस उद्देश के पूरे होने के स्थान पर हकते विपरीत उत्पादन कम हो गया है और इसने उत्स्व हिस्सी होती श्रुपराद में ही विषय निर्मार करने हिस्सी करना है। परन्तु हस उद्देश के पूरे होने के स्थान पर हसके विपरीत उत्पादन कम हो गया है और इसने उत्स्व हिस्सी हमते भी विग्र वर है है।

भारतीय अभिकों में अनुसाधन के अभाव को गत कुछ वधों में (१) उत्तादन के आधार पर नहीं विश्व के क्वाच उपरिश्व के आधार पर नहीं विश्व के क्वाच उपरिश्व के आधार पर सहगाई मन भीनत हरवादि सेने से बढ़ाया मिला है। महागाई मन को अमिक के रहन-धहन करवा में उत्तर देवा गया है। अमिक चाहे अपना कार्य पूर्य करे या न करे उसे में हात सिता कर दिवा गया है। अमिक चाहे अपना कार्य पूर्य करे या न करे उसे में हात अपना सहाय अपने कार्य निता है। इस कार्य अमिक अपने उत्पादन अपया अपने कार्य की किवित सात्र भी विश्वा नहीं करवा है। यदि में ह्याई अपने को उत्पादन पर आधारित कर दिया जाता विश्व अमिक ऐसा नहीं करवा। साथा ही निर्याशित मात्रा हे अपिक उत्पादन करने पर अमिक का बीनच और मेंहगाई मचा बहुता और उत्पादन बहुता; (२) इन्हिस्ट्यल इस्त एन्ट के पात्र होने के पहिले तक और्योगिक कार्यो र समलों वर समजीत और पन्यतिर्थ प्रयाल के अपने के अपने के अपने के सात्र के सिता है। सात्र के सात्र के सिता के निकालने का अधिकार नहीं या, चाहे कर्मवारी के निकाल के सिता है। से अधार न्यायालय सात्र का निवास सात्र का निवास करते हों से अधार निवास करते वार सात्र का निवास सात्र हों हो से सात्र हो या का निवास का निवास सात्र हो या निवास करते हों सात्र का निवास सात्र हो या का निवास का निवास सात्र हो या निवास करते हों सात्र हो या सात्र हो या अधिकार सात्र हो या अधिकार सात्र हो या सात्र हो सात्र हो या सात्र हो सात्य

ये । इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्मता को चृति पर्तृची है श्रीर श्रीमक के प्रति घन्टे जलाइत की भाषा ग्रिरी है।

दोप दर करने के उपाय-भारत में अमिकों की कार्यक्रमता की हिथति बहुत बिगड़ सुकी है और इसको सुधारने के लिए सरकार की, मिल-मालिकों और अमिक नेताओं को बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। यदि इस दिशा में पूरी शक्ति से प्रयत्न नहीं किया गया और केवल श्रांशिक प्रयत्न किय गये तो धमस्या सलकने की संभावना कम है। भारतीय अभिक की कार्यश्चमता बढ समती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि (१) महगाई भता, बोनस इत्यादि उत्पादन के आधार पर दिए जार्चे । यह आवश्यक है कि असिक का न्यनतम पारिश्रमिक और उसके कार्यकी मात्रा निश्चित कर दिए जाँग। अमिकी के लिये एक न्युनतम पारिश्रभिक इस शर्त पर निश्चित कर दी जाय कि यह एक निश्चित मात्रा में कार्य करे। इसके उपरान्त पारिश्रमिक में बढि हो सकती है पर वृद्धि का अनगरान ऐसे सत्र के आधार पर होगा जिसमें रहन सहन की लागत क्यीर अभिक की उत्पादकता दोनो ही बातों का विचार सम्मिलित हो। इससे अमिकों के दित की रत्ता यदि रहन सहस के क्यय में बढि हो गई तो होगी और साथ ही साथ यदि जनकी जत्यादकता घट जायती ते। मिल मालिकों का भी हित उपैक्षित न हो सहेगा. (२) काम धीरे करो? नीति को औदोगिक सगड़े के ग्रम्तर्गंत समस्ता चाडिए । यहि अधिक 'काम चीरे करो' मीति अपनाएँ तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विल-मालिक सम्मीता होई इत्यादि के द्वारा प्रपत्नी शिकायत दूर करा सकें, (३) यदि श्रांमक ग्रब्छी प्रकार कार्य न करें क्योर निर्धा-रित मात्रा में उत्पादन न करें तो उद्योगपात श्रधवा मिल-मालिक को उन्हें निकालने का श्रविकार दिया जाना चाहिए, (४) श्रालस्य, उत्तरदायित्व को टालने की भावना श्रीर श्रनुशासन के श्रमाव की दर करने के लिए सरकार की श्रीर श्रीनक नैताओं श्रादि को निरन्वर प्रचार कार्य करते रहना चाहिए। यदि उसका ध्यान बारम्बार इस दृश्य की ओर आकर्षित किया जायता कि उसकी कार्यवाडी से वह उद्योग नव्ट हो सकता है जिस पर उसकी समृद्धि निर्मर करती है तो अवस्य दी श्रमिक की स्थिति में मुचार होगा श्रीर उसका हाँग्टकीस बदलेगा। यद्यपि यह कार्य बहुत धीरे-धीरे होगा परन्तु दीर्घकाल मे अभिक की कार्यज्ञमता बढ़ाने में इसका बहुत अधिक प्रमाव पड़ेगा, (५) श्रमिक की उत्पादन शक्ति का श्रम्ययन करने के लिए और उसको प्रोत्साइन देने के ब्रिटिश प्रोडिक्टिविटी कॉॅंसिल के समान एक विशेष संगठन मारत में भी स्थानित करना चाहिए। श्रन्तर्राष्ट्रीय अम सम के उत्पादन शक्ति का भ्राप्ययन करने जनोती में तत्सम्बन्धी बाध्ययज्ञ की व्यवस्था की जानी साहिए ।

बोधीर अध्ययन करने के नाट ज्योग के संगठन को गोजना बनाई जाय। त्रीरोतिक कार्यच्याता में इदि करने के लिए आयुरुवक समाव देने को विभिन्न

बाले दल ने बम्बई सती मिल उद्योग में जो कार्य किया है उसमें भारतीय

सती जहोग का उत्पादन बटने की संमावना है । इस दल ने समाव दिया है कि कारखानों में सभी कार्य आधनिक रीति से किया बाय और वर्तमान स्थित का

### श्रध्याय ३१ श्रोद्योगिक सम्बंघ

श्रीचोशिक उत्पादन बहुाने, श्रांभकों की श्रांधिक स्थिति को सुषारने श्रीर देश को श्राधिक हथि से समुद्धमाली बनाने के लिये श्रीचोधिक शांति का श्राध्मक महत्त्व है। यदि इवतालें होती हैं, दिलो-कारखानों में तालावन्दी की जाती है श्रीर खोंधोशिक सांति भंग की वाली है वी उत्पादन पटने लगता है, उत्पादन प्याप्त में बृद्धि होने लगती है श्रीर आय कम हो ना से श्रीमकों को श्रमेक किताहां का सामना करना पढ़ता है। बालार में बत्तुओं की पूर्ति नियमित कर से न होने या उनकी पूर्ति में किती प्रकार की बाया था जाने से उपभोक्ताओं को भी किताहां में किती प्रकार की बाया था जाने से उपभोक्ताओं को भी किताहां से से किता हमें किता हमें से किता की साम नहीं होता। पूर्वीवादी व्यवस्था में वालावंदी का होना श्रावस्थन नहीं है। यदि उचित प्याप्त व्यवस्था में वालावंदी का होना श्रावस्थन नहीं है। यदि उचित प्याप्त व्यवस्था और कम से कम दाला श्रयस्थ वा बकता है।

आपुतिक प्रष्टुलियाँ—भारत के श्रीयोगिक बेन में शांति बताये रलता सदैन समन नहीं रहा है। दितीय विश्य पुत्र के काल में श्रीयोगिक कराड़ी की संख्या और हन काशों के काश्य नय्ट हुए कार्य के दिनों की संख्या कार्य कहा है। है। श्रीक में में मन कि सुत्र श्रूपनी चरम सीमा पर साह होता है कि १६५२ में नव कि पुत्र श्रूपनी चरम सीमा पर या हवताला पदम तालाविन्शों से केवल देव लाल कार्य के दिन नय हुए। १६५४ में यह संख्या बद्दर ६५ लाल दिन और १६५५ में ५१ लाल दिन हो गई। यह संख्या बद्दर भी श्रीवाहक कम रही, इसको श्रूपतिक नहीं कहा ला कार्य के एक श्रीयोगिक मामा श्रीयोगिक समा है। इसको श्रूपतिक नहीं कहा लाल हो कर सामा श्रीयोगिक मामा कार्य करों है। सामित १०० प्राप्त

गई। यह संज्या फिर भी अपेबाकृत कम रही; हराको अत्यिक नहीं कहा जा सकता है। यह के समय औरोमिक समस्य काफी अच्छे रहे स्यंकि (१) अपिक ने सरकार को लाबाई में सहस्योग है समस्य काफी अच्छे रहे स्यंकि (१) अपिक ने सरकार को लाबार में किसी प्रकार की बाबा पड़े और युद्ध का उफल संयालन कर सकने में किसी प्रकार की बाबा पड़े। (२) उस समय नरसुओं के मान में तया रहन-सहन के क्या में यूद्धि की समस्या उत्पन्न मही हुई थी। इभी समस्या से ही बाद में औरोमिक कराड़े उत्पन्न हुए १९४४-४२ और बाद के बाद पर्यो में सामन्य मूल्य के देशनांक कमस्या रहुए १९४४-४२ और बाद के बाद पर्यो में सामन्य सुरूप के देशनांक कमस्या रहुए १९४४-४२ हो। सुरूप से देशनांक कमस्या रहुए १९४४-१ रहे। सुरूप से देशनांक कमस्या रहुए १९४४-१ रहे। सुरूप से देशनांक कमस्या रहुए १९४४-१ रहे। सुरूप से सुरूप में में अधिविक विक

हो गई थी। इससे मालिक स्था कमैचारियों के सम्बन्ध विशेष खरात नहीं हुए; (३) युद्ध के समय मारतीय प्रतिरद्धा नियम की घारा दर-ए लानू थी। तसके अनुसार श्रीयोतिक काश्चों का निपटाग करने के लिए सरकार की संकट कालीन अधिकार दिने गये थे। सरकार अशांति के विषद्ध कही कार्यवाद्धी करने की

परस्तु युद्ध के समाप्त होते ही, श्रीर विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्त होने के श्रे पत्रचात श्रोद्योतिक क्यांचे की संख्या बही श्रीर उत्पादन में कमी श्रा गई। १६४६ श्रीर १६४७ में क्रमश: १ करोड २७ लाख श्रीर १ करोड़ ६८ लाख कार्य के दिन नष्ट हो गये जब कि १६४% में केवल ४१ लाख कार्य के दिन नष्ट हर । श्रीचोगिक क्रमहों में इतना बढ़ि होने का कारण यह था कि (छ) स्वतन्त्रता माप्त होने के पण्चात श्रमिक के हिल में नई खाशाएँ जगी थीं। अमिक खापनी खार्थिक स्पिति को स्थारना चाहते ये और इसी के परिगाम स्वरूप हड़तालें हर्डे। सरकार की धम नीति ने भी जिसका उद्देश्य अभिकों का पारिश्रमिक बढाना छौर कार्य की स्थिति में सुधार करना था, इसमें काफी योगदान दिया, (व) युद्ध काल की ग्रापेसा चीजों के भाव में अधिक बृद्धि हुई। १६४५-४६ में थोक विकी के भाव का देशनांक २४४% था परन्त १६४६-४७ में बढ़ कर २७५४ और १६४७-४८ में ३०७ हो गया। बस्तुश्रों के सूक्यों में तो बृक्षि हुई परन्तु वेतन श्राथवा पारिश्रमिक में इसी अन्यात में वृद्धि नहीं हुई। इससे अभिक को अभेक विनाइयों का समना करना पड़ा । परिखामस्वरूप अभिकों ने वेतन श्रथना पारिअभिक बहुवाने के लिए इइतालें की: (त) मारतीय प्रतिरक्ता नियम के लागू न रहते से अमिको ने एक छट का अनुभव किया। अब अभिको की हरूछा भी बुद्ध के समय की तरह कहोर परिश्रम करके उत्पादन बढ़ाने की नहीं रही थी।

स्पित कांकी गाभीर रूप धारण करती गई श्रीर १६४७ के दिएवर में भारत चरकार को श्रीयोगिक धार्वि उमकीता कराने के लिए इस्तिचेन करना रहा। इस्ते भारत में श्रीयोगिक धार्यत स्वकार में बार में कर कार्या प्रदा । इस्ते भारत में श्रीयोगिक सम्बन्ध सुधारने में काशी शहायदा मिली। इसिक अपन्तिक श्रान्तिक से बृद्धि हुई, में इगाई मचा, रोनच श्रीर जामांच में अभिने के मान में भी बृद्धि हुई । यह करा गया कि द्वन्य में अभिक का पारिश्योक बद्धने से अभिक का वास्तविक पारिश्योक नहीं बदा श्रीर यदि कपये को क्य शक्ति को हांच्य से देखा आय से आत होगा कि अभिने के रियदि युद्ध पूर्व के याण की अपने सा कही श्रादिक कि मान गई। इस्त के से इस्त बात पर प्यान नहीं दिया गया है कि मूल्य बद्ध बाने से केवल अभिक को हों नहीं बहु स्वान सर प्यान नहीं दिया गया है कि मूल्य बद्ध बाने से केवल अभिक को हों नहीं बहु सा स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान को किटनाइयों का सामना करना पहा।

प्रभन यह नहीं है कि असिक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ाया नहीं: यास्तव में विचारणीय बात यह है कि क्या श्रामकों को समाज के अन्य लोगों की अपेबा अधिक कष्ट सहने एडे ! यदापि अमिकों के कछ वर्ग ने अधिक वेतन अथवा पारिश्रमिक की गाँग करते हुए आन्दोलन जारी रखा परन्तु जहाँ तक परे अभिक वर्ग का प्रश्न है वह एन्तुब्ट रहा और हड़तालों की छख्या भी घट गरे। फिल मालिको ने सालाइन्दी घोषित नहीं की क्योंकि पारिश्रमिक में वृद्धि होने के साथ ही उत्पादित माल के मूल्य में भी चृद्धि हुई श्रीर बाजार विकेता के अनकल इट होने के कारण मिल-मालिकों को अधिक हानि नहीं उठानी परी। इसके साथ ही खीद्योगिक मुन्दे सम्बन्धी काचन के खन्तर्गत मुन्दे सलकानेवाली संस्था हमा: अधिक प्रभावशाली बनाई सई और सममति तथा अनिवाय एंचिनिर्माय के द्वारा अनेक होने नाले औरोशिक सगरी को जो अवश्य उसस होते रोक लिया गया। १६५० में छल नच्ट हुए अम-दिनों की संख्या १२८-१ लाख हो गई परन्त इसका कारण सर्वत श्रीजोतिक सम्बन्धा का विशवना नहीं बिक्त सनी मिल उद्योग की लम्बी इक्ताल थी। कल नव्ट हए १२८४ लाख दिनों में से १३ लाख दिन अकेले सती उद्योग में ही नष्ट हुए । खीयोगिक समझौते के परचात से भारत में जीदों।शिक शांत श्राधिक मग नहीं हुई है और उक्त तालिका के अनुसार नष्ट हुये अम-दिनों की सस्या घटकर १९५१ में ३८. र लाख. १६५२ में ३३'४ लाल, १६५३ में ३३'म लाख और १६५४ में ३७'र लाख ही गई। १६५६ में ६६ ६ लाख अम दिन नव्य हुये। श्रीयोगिक क्ताका की सख्या १.२०३ तथा उनसे सम्बन्धित अभिकों की संख्या ७१५,१३० थी। १६५७ में ६४ लाख अमंदिन नच्ट हुये तथा श्रीदीगिक क्रगडों की सस्या २.०५६ तथा उनसे सम्बन्धित अमको की संख्या १,०१८,६२५ थी। नब्द हुये ६४ लाख अस-दिनो से मुती वक्ष उद्योग में १५ लाख दिन, कीयला तथा अन्य खदान उद्योगों में लगमग १० लाख. रोपण तथा जुट उद्योग में लगभग ५ लाख अम दिन नध्ट हुये।

कानुनी व्यवस्था—एक जनतंत्रवादी देश में जहाँ उचीम स्वतंत्र है अपनी मीग के अनुसार उचित वेतन अथवा पारिअधिक म मिलने पर असिक की अग्य उपाय असकत रहने के परचात् अत में हटताल करने का अधिकार है और यदि मालिक अनिकों के कार्य के सन्तुष्ट नहीं हो तो उसे भी तालावन्दों गीवित करने का पूर्ण अधिकार है। यचित जनतंत्री शासन व्यवस्था में यह अधिकार निहित्त है कि स्तुष्ट मालिक है। असिक स्वाप्त के स्वत्य में यह अधिकार निहित्त है किर मी जिना सार्वजनिक हित पर विचार किये दन अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिते। हन्द्राल होने से या तालावन्द्री भोषित की जाने से उपमोक्ता को मी अनेक कठिनाह्याँ उदानी पढ़ती हैं। अधिक तथा मिल

मालिकी द्वारा कमयः इत्ताक्ष और तालावन्दी के अपने मूलभूत श्रिकारों के प्रयोग के प्रति जनता और सरकार उदाधीन नहीं रह सकते। अचित रीति सं समस्रीता बातां चलाने और एक दूबरे की कित्नाह्यों को समस्रेत हुए औद्योगिक समग्रे को अल्फाना स्वैत संभव है। औद्योगिक क्रयाई रहन्यों कान्त्र का उद्देश्य यह है कि कमाइ होने पर गालिकों तथा कर्मचारियों के बीच सम्मीत करने के लिए साधन खोजा बाय। इस कान्त्र में क्रिका प्रधान खोजा बाय। इस कान्त्र में क्रिका प्रधान खोजा क्रया है। इसके मान्त्र की अल्प्रकाल सिक्त-भिक्त खाया वाया है इसके इसके अल्प्रकाल कित्र-भिक्त खाया प्रधानक क्रयाई ने समस्रेत तथा प्रधानक क्रयाई ने समस्रेत तथा प्रधान क्रया का ग्राह हमें अल्प्रकाल क्रयाई में स्वता का स्वीत क्रयाई के सम्मान का स्वात क्रयाई मान्त्र कर दो गयो है। इसमें प्रामले पर विचार करने की पूर्ण विधि विस्तार ते दी ग्राह है। भारत तथा संवार क्रयाई का बाता और इसके अल्प्रीमिक मतमेह हो जाता है। अस्य कान्त्र का वह उद्देश्य है कि इस प्रकार के अरमी को उत्पन्न हो वा है तो उत्पे वुर किया जाय।

१६२६ का भारतीय व्यापारिक विश्वह कानून-इंच कानून में चार्य-बनिक उपयोगिता की सेवाओं तथा श्रान्य जलांगों के लिए प्रथक श्रायस्था की गई भी । सार्वजनिक उपयोगिता सेवायें जैसे रेल्ड डाक तथा तार, विजली और जल पूर्ति विभाग के कर्मचारियों तथा भगियों इत्यादि की इड़तालों पर प्रतिक्रय लगाया नाया था। ये कर्मचारी मालिक को १४ दिन पूर्व मोटिस देने के पश्चात् ही इडताल कर सकते थे। अन्य उद्योगी में इस्ताल अथवा तालायन्टी की घोषित किया जा सकता था परन्तु इन कगडों को सुलुकाने के लिए एक निश्चित साधन नियुक्त किया गया था। श्रीयोशिक क्याहो के सम्बन्ध में तटर्थ बाँख समिति श्रीर समसीता परिषद् नियुक्त करने की भी व्यवस्था की गई थी। जाँच समिति में एक या एक से छाधिक निश्यस व्यक्ति रखे आ वैंगे। यह समिति मामले की जाँच करने के पश्चात् श्रपनी रिपोर्ट नियुक्त करने बाली सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। सममोता परिषद् इस बात का प्रयक्त करेगी कि दोनों वस साथ बैठकर अपने मतमेदों को दूर करके समकीता कर लें। समकीता न हो सकने पर मामले की रिपोर्ट सरकार के पास मेज दी जाती थी। इस कानून में अनिवार्य पंचनिर्णय की क्यवस्था नहीं की गई थी। इसके श्रानुसार सरकार ने केवल यही प्रयत्न किया कि दोनों पत्त एक दूसरे के और अधिक निकट आ जाएँ और मामले तथा उस मगड़े के कारणों को जनता की बताव जिससे सममौता करने के लिए जनता की राय का भी बल प्राप्त हो। जनहित की सुरक्षा के लिए कानून की हिन्द में वे इइसालें श्रीर तालावन्दियाँ गैर कानूनी थो (क) जिनका अदेश्य उद्योग के श्रान्दर कमाड़े का प्रषार करने के अविरिक्त कुछ और भी हो या (ख) जिनका उदेश्य जनता पर अपनेक कठिनाहयाँ लादकर संस्कार को विशेष कार्यवाही करने को मजबूर करना हो।

यह कानून उपयुक्त किद्र नहीं हुआ। श्रीकोभिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिए यह पर्याप्त नहीं या क्योंकि (१) समकीता श्रीककारी श्रयवा मगड़े का श्रीम निपरारा करने वाली श्रन्य संस्थाओं के स्थान पर तदये सार्वजनिक जीच को अधिक महत्य दिया गया और (२) स्थाई श्रीबोभिक न्यायालय की स्थापना के निय क्रक उपस्था नहीं की गई।

बस्बई में १६३४. १६३८ ग्रीर १६४६ में ग्रीग्रोगिक विग्रह कानून बसाकर उक्त कालन के दोयों की कछ सीमा तक दर कर दिया गया। इन कालनी के श्चन्सर्गत मालिको द्वारा अमिक संबों को मान्यता दी जाने की देवसरधा की गई थी। इन काननों से कराओं को मलकाने की परी विधि खोर निश्चित खबधि ही गई थी। केवल छावंजनिक जॉच करने की अपेदा समसीते और सगड़ा सलमाने पर अधिक महत्व दिया गया । इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कार्य की शर्ते करपदर और अनिश्चित न हो क्योंकि इससे सताहै अत्यन होते हैं। इसके लिए यह व्यवस्था को गई कि समस्तीते की शर्ते और स्थायी समार्थे लिखिन और रिजरुटर्ड हो । अन्य प्रभावशाली साधनों के साथ ही स्थामी श्रीदोगिक न्यायालय का विकास हजा है। पहले के कानुनों में त्याय का मानना अनिवार्य नहीं था परस्त इडताल अथवा ताले-अन्दी से पर्व सम्पर्श मामले शांतिपर्या उपाय से सलमाने के लिए प्रस्तुत करने श्रावश्यक थे। परन्त बस्बई के १६४६ के कानन में पंचनिर्णय के लिए सामला प्रस्तत करना अनियार्थ कर दिया राया छीर अपील करने के लिए एक अदालत की व्यवस्था की गई। वास्तव में बन्दर्ड ने इन काननों का बनाकर भविष्य में शासिल भारतीय पैमाने पर श्रविक उपयक्त कानन बनाने के लिए सार्व दशीया ।

भारतीय प्रतिरत्वा नियम के अन्वर्गत कार्यवाही—पहले कहा जा सुका है कि युद्ध काल में श्रीवोशिक क्षमार्थ को इल करने के लिए धरकार ने सुद्ध कालीन अधिकार प्राप्त कर लिये थे। यत्तीय प्रतिरत्वा नियम भारा पर (ए) के अन्वर्गत, जो अन्वर्य १९४२ में लागू को गयी थी, यह ज्वस्थम की गई यी कि बिटिश मास्त की प्रतिरत्वा के लिए, वार्यवीनक मुस्का के लिये, शांति श्रीर व्यवस्था बनाये रखाने के लिये युद्ध का कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिये समुद्दाय के जीवन के लिये आवश्यक सामान की पूर्वि बारी रखने के लिये सामार स्वया विशेष आदेश द्वारा चन्द्रीय वस्कार वालावन्द्री तथा इन्ताल पर रोक लगा सकती है और आयोगिक कगाओं को समकीते या अदालती कार्यवाही के लिये मेन सकती है और अदालत के निर्णय को लागू कर एकती है। इस कार्यम में यह भी व्यवस्था की गई थी कि इत्याल अपया तालवन्दी की पहले से स्वना टी जाय। समकीत की कार्यवाही की अविध में इत्याल अपया तालवन्दी पर रोक लगा दो गई थी। नेवीकि सरकार को अदालती निर्णय अनिवार्य कर से लगा दो गई थी। नेवीकि सरकार को अदालती निर्णय अनिवार्य कर से कहा अभिवार मान्य था इस्तिये इस कह सकते हैं कि इस नियम के हारा पंचनिर्णय अनिवार्य कर दिया गया था।

१६४७ का खोखोगिक विम्रह् कानून — फरवरी १६४७ में केन्द्रीय सरकार ने श्रीयोगिक विम्रह कानून स्थोक्रव किया। इस कानून ने अम्बर्ध के श्राप्तमय का लाम उठाकर १६२६ के श्रीयोगिक विम्रह कानून के कुछ दोषों को यूर का लाम उठाकर १६२६ के श्रीयोगिक विम्रह कानून ने कुछ दोषों को यूर कर दिया। इस कानून में कार्य समिति, तमकौता शों की श्रीर कार्य-श्राप्त निप्तक करने की अ्वरस्था की गई है जिसने उस अस्थायी श्रीयोगिक न्यायालय स्थायित करने को अ्वरस्था की गई है जिसने उस न्यायालय के स्थायाशीश होंगे। इस कानून में परस्थर समकौता करने पर अधिक स्थायाशीश होंगे। इस कानून में परस्थर समकौता करने पर अधिक स्था कार्य स्था कार्य स्था कार्य स्था कार्य स्था कार्य स्था कार्य स्था कार्य स्था कार्य स्था कार्य स्था कार्य स्था कार्य का

रधार में आवागिक विदाह (विद्यापन) अध्यादेश जारी करके एक जानून के कुछ किसरों को दूर कर दिया गया। इस अध्यादेश के द्वारा के और्यागिक हकाहवाँ मी अदालती काग्रेवाही के चेल में आ नामें अब तक कोई कमका नहीं हुआ या परस्तु भविष्य में होने की समावना थी। भविष्य में एक ही बात पर अन्य श्रीयोगिक इकाहयों में कमावा न होने देने के लिए यह अध्यादेश आवश्यक समक्ता गया। १६९० के श्रीयोगिक विद्याह (अम अपील न्यायालय) कानून से सम अपील न्यायालय श्रापित करने की न्यवस्था की गई है जिसमें तिभन्नों श्रीयोगिक प्रवासालय श्रीयोगिक अदालतों, बेतन परिपदों इत्यादि के कैछले पर की गई अपीलों की सुरवाई होगी। अम अपील न्यायालय के किसी अदालत कैछले अथवा निश्चय के विरुद्ध की गई अपीलों पर विचार करने का अधिकार है पर नुहान इसकी दो सर्ते हैं: (१) कैछले अथवा निश्चय में कोई विशेष कानूनी पैंच

हो या (२) उसका संबन्ध वैतन, बोनस, छटनो इत्यादि से हो। विभिन्न राज्यों में कोलोकिक क्यायानमों तारा पारम विशेषी फैसने दिये जाने के कारण निसंस देश में जोशोगिक सबस्य ग्राधिक जरिल होते जाते ये अम ग्रापील न्यायालय स्पापित करने की ग्रावश्यकता अनुमव हुई। इसके साथ ही ग्रापील करने के लिए कोई ब्यवस्था न होने के कारल वह श्रीशोगिक श्रदालतें उदार निरंक्श शासक की तरह ग्राचरण करते लगी थीं। इस प्रकार की निरंकशता ग्रोर स्वच्छन्दता सम-सत्री शासन प्रणाली क अनुकुल नहीं है। मूल कानून की ३३ वीं घारा में यह इप्रकार की गई थी कि समझीते के लिए किसी भी सगड़े के विचाराधीन होने के काल में कोई मालिक समसीता श्राधकारी, बीड श्रापका पंचन्यायालय की लिखित कानगरि जापन किये जिला न किसी कमचारी की दशह दे सकता है और न निकाल सहता है: साथ ही मामला अस्तत होने के ठीक पहले की नौकरी की शासन में यह किसी प्रशार का परिवर्तन नहीं कर सहता है। इस धारा की क्यवस्थाको को धारा ३३ (ए) जोबकर श्रीर बढा दिया गया है। धारा ३३ (ए) में यह स्वयस्था की गई है कि यदि मालिक धारा की मंग करता है तो उससे पीढ़ित कर्मचारी विधियत लिखित रूप में खपनी शिकायत उस पंच खडालत के सामने पेश कर सकता है जिसमें मामला विचाराचीन है। यह पचग्रदालत उस शिकायत पर उसी रूप में विचार करेगी जैसे वह कानन की व्यवस्था के धानसार पच श्रदालत में पेता किया गया श्रीदीशिक सगहा हो। इस संशोधन के सनसार पीडित कर्मचारी को मामले के विचाराधीन होने के काल में नौकरी की हालत मे परिवर्तन, छप्रनी, दसड इत्यादि के मामलों की सीचे पंचन्यायालय में विचारार्थ प्रस्तत कर सकते का अधिकार प्राप्त है। इससे पंचन्यायालय में प्रस्तत होनेबाले कराड़ों की सख्या भी श्राधिक बढ़ने से बच जायगी और निर्याय भी शीघ हो जायगर । श्री घी० बी कीरि का हरिटकीरा -भारत के श्रम-मंत्री श्री गिरि ने

आ वार्ष वा शाहर का द्वार कर का स्वार के अस-अभ आ तार ज अस्ति अस्ति के अस्ति

जिल्हें के लिए सीपने का चांत्रकार होता। श्री सिर्दिका प्रताया कि अस व्यक्ति न्यायालय को समाप्त कर दिया जाय क्योंकि फगड़ों को छापस में सलका लेने के पत्रचात इस स्यायालय की कोई ज्यावस्थकता नहीं रह जाती। भी गिरि दारा मक्तर गरे गोजन के जन्मग्रीत मालिकों तथा कर्मनाश्यों के बीच के सभी स्ताही पर स्वेच्छा से सम्भीता करता होगा। समभीता वार्चा के संबन्ध में सराडे से संबन्धित कोर्ड भी पन समझौता व्यधिकारी की सहायता. जैने को स्वतंत्र होगा और दसरे पत्त को यह स्वीकार करना पहेगा। यहि इस प्रकार की सममौता वार्चा ग्रमफल हो जानी है और टीजों पंच भागले को पंचरियाँय के लिए सौंपने को प्रस्तत हो तो पंचा का निर्वाय होतों पत्तों को सानना प्रदेश । प्रटि पंच परस्पर सहसत नहीं हो तो कवाड़े से संबन्धित पार्टियाँ एक निर्मायक छाँट सकती हैं जिसका फैसला दोनो पत्नों को माग्य होगा। यदि दोनों पार्टियों में निर्वायक काँटने के प्रश्न पर मनमेट हो तो वह दोनों एक राय से मामला पंच श्रदालत को सीप सकते हैं। समक्रीते की इन विभिन्न स्थितियों के लिए श्रविष निश्चित होगी। रास्य सरकार केवल संकट काल में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेकर की मार्वजनिक उपयोग के उसीवों के मामलों की स्विन्धर्य प्रस-निर्दाय के लिए सीप सकती हैं। परस्त यह अधिकार श्रम्य उत्योगी पर लाग सही होगा । गिरि-योजना के अन्तर्गत अभिक समितियाँ, समस्तीता अधिकारी, समस्तीता बोर्ड, श्रीयोगिक स्थायालय श्रीर पच श्रदालत पर्धवत रहेगी परन्त अस अपील-त्यायालय कत्र हो जायमा ।

इसते दो मुख्य प्रश्न उठते हैं: (१) न्या श्रानिवार्य पंचनिर्णय हो या स्वैधिक म पंचनिर्णय और (२) न्या श्रम ग्रापील न्यायालय रहना चाहिए या नहीं!

सिनियर अंतर (२) नेवा अंत अंतर अंतर विश्व कर विश्व में नियं यं पंकरिये में स्वापा नियं है अंतर नियं में पंकरिये से श्रीयोगिक क्षेत्र में प्रोर्थाहन मिखा है और भारत में इत्तर अंतिक संग्व कालो हो गए हैं। 'श्विक संग्व के व्यवस्था मंद इस्ते कुतारायात होता है। अंतिक संग्व के वरस्थों में पक्ता नियो त्याप के प्रदस्थों में पक्ता नियो त्याप के शिरा है। यंदि अंतिक संग्व के स्वरं में पक्ता नियो त्याप के स्वरं में वंद बात ये कि एकता के स्वरं में वंद बात से ही उनके संयुक्त होने के लिये अग्य किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रह वाली। श्वनियर्थ पंकरियं वक्ती है से वाने के लिये कोई कारणा नहीं उपस्थित करता कि उनमें हम सकता में एक से हम से प्रवे प्रवेति के लिये कोई कारणा नहीं उपस्थित करता कि उनमें हम सकता से एक हम से प्रवेति हों।

पदान करता है जिससे अपन्तर्रोग्ट्रीय शाजार में शिकने वाली सस्तुओं के लिये बहुत करितारि उपस्थित हो जाती है।

परन्तु श्रानिवार्य पंचृतिवर्षय का समर्थन भी किया गया है। कहा गया है कि श्रापिक हरिन्द से कम विकस्तित देश मे श्रीवोगिक कमझों के कारण यदि उत्पादन कर जाता है तो हससे राष्ट्र के हितों की हानि होने की संभावना है। उत्पादन में गिरावट रोकने के लिए श्रीर परिलामतः राष्ट्रीय श्राप कम न होने के लिए श्रीनवार्ष पंचिनवर्षय को लागु किया जाना चाहिए। पंचिनिवर्षय की सक्तता के लिए बावचार्य के हित्स श्रीता जाता प्राप्तकों के कुराल संपदन हो और (२) उसकोते की कार्यवाही में उत्परदायित्व सममने वाले अनुभवी नेताओं को आगल के दिया जाय। चिक्र मासत में अमिक संगठन ग्रम भी बहुत कमओर है, श्रीर समझीते तथा पंचिनवर्ष के लिए निवर्ष वर्षाक्ता का स्थाप है हित्स स्थाप हर्षाक्ता का स्थाप है हित्स स्थाप की सहत कमओर है, श्रीर समझीते तथा पंचिनवर्ष के लिए निवर्ष वर्षाक्ता का स्थाप है हित्स स्थाप सुधार स्थापन कर निक्र ।

इन सब बातों को च्यान में रखकर इस इस परिशास पर पहुँचते है कि यद्यपि सार्वजितिक उपयोग के उद्योगों के लिए अनिवार्य पंजित्यूय आवस्यक है और संकट काल में भी यह लामदायक साधन खिद हो सकता है परन्त श्रीयोगिक कामड़ें का मुककानि का यह कन्तीपजनक दंग नहीं है। इससे प्रायः श्रीयोगिक कामड़ें उत्पन्न होते रहते हैं, अपिक संगठन कमजोर होते जाते हैं श्रीर देश की स्वार्यिक स्वरूप्त पठीर होने लगती है।

परन्तु भी गिरि का अपील न्यायालय को समाप्त कर देने का सुक्ताय पूर्णदेवा स्वय नहीं है। देश के विभिन्न भागों में समाप्त अप स्थित उत्तक करने में अपील न्यायालय शिशेष उद्दावक रहा है। वेतन, बोनर, कार्य की स्थिति स्पादि प्रत्नो पर अपील न्यायालय के दैठलों के और्थायिक पंच अद्दावतों को कांकी लाभ पहुँचा है। इत्ये कुछ सन्देद नहीं कि परसर समक्रीता करके या स्वेत्स्कुक पंचानचीय द्वारा मामला तय करके ऐसी स्थिति आ सक्ता है कि भविष्य में अपील न्यायालय की आवस्यकता न रहे परन्तु जब तक औद्योगिक पंच-अदावत है तब नक देश के विभिन्न भागों में अभ सम्बन्धी समान स्थिति लोने और विभिन्न अशोगों में भी एकस्पता लाने के लिए अपील न्यायालयों को समाप्त न क्रिया लाग ।

१६४६ का श्रीषोगिक विमह कानून—एक बिल अभिकों के छनन्य विषयक सेसद में १६५० में रक्सा गया, पर उस पर कार्यवाही नहीं हो सकी, क्योंकि मिल मालिकों और अभिकों के नेताओं ने उसका बहुत विरोध किया। १९५५ के लितम्बर में पुनर्परीतित रूप में एक विषेषक १६४० के खीबोमिक विग्रह कान्न का संद्योधन करने के लिये लोक तमा में मस्तुत किया गया और १९५६ में औदौगिक विग्रह (संज्ञोधन तथा विभिन्न शतों के साथ) कान्न पास किया गया। यह बढ़ दुर्भीय की बात है कि इस कान्न में भी गिरि के विचारों को बहुत ही सीमित मात्रा में सिम्मिलित किया गया है। ऐसा लगता है कि उत्तम शोबोगिक कान्न में विस्तार होगा और समकीता कठिन होगा। इस कान्न के सुख्य प्रविधान, जो कि बग्बई के १९४७ के कान्न के खतुरूप हैं,

- (१) असिको की परिमाण विस्तृत कर टो गई है, श्रीर अब श्रीयोगिक कर्मैवारी तथा रेल रेल करने नाले पदाधिकारी भी जिनका वेतन ५००) माधिक में अधिक नहीं है अमिकों के अन्तर्गत क्षिमित्रत कर लिये गये हैं। प्योक्ति बहुत से हम त्रकार का कार्य करने नालों को गोधिमीय और संगठन सम्बन्धी कार्य दिया नास अधिकों के अपने माधिक के हो विशेष श्रीय है, इनसे यह मय है कि मालिकों को नोई करिनाइयों का सामना करना वीता।
- (२) १६५० के खीचोंगिक विग्रह (अनील न्यायालय) कानून का प्रत्यावयन कर दिया नया है और अभिकों के अपील न्यायालय को समास कर दिया नया है। इस न्यायालय के कारण देश के विभिन्न भाग में अभिकों की स्थिति में समानता आ गई थो और इसने अनेकों ऐसे लामदायक सामान्य नियम बना दिये वे जिनके विख्यत्वन से मरिवस में नंभीर कठिनाइयों का सामान्य कना पड़ेगा। इसके इस कुछ एक ही अच्छाई की आशा कर सकते हैं कि अपील न्यायालय के अभाग में सम्मयता मालिकों और अभिकों को स्थिति की वास्तविकता पर विचार करने की मेरणा मिले।
- (क) इस कान्त्र के अनुसार तीम प्रकार के मीलिक न्यायास्य मनेंगे।
  (छ) अम न्यायास्य (श) श्रीशोधिक न्यायास्य और (ह) राष्ट्रीय न्यायास्य । अम न्यायास्य के ऐसे श्रीयोधिक मगजों के निर्मय करने का अधिकार है जो मालिकों की ऐसी श्रायाश्री के समन्य में उत्त्या हुए हैं जिनका श्रीनिय तथा नियमानुद्ध- लता संदिग्ध है और को स्थायी आशाश्री के अन्तर्भत हैं तथा कर्मचारियों को नेनां के सम्भाय श्रीर इस्त्राल श्रयमा सालावन्दी के सम्भाय हैं।
  श्रीयोधिक न्यानात्य ऐसे कमाई। या निर्मय करेगा जो कि पारिअधिक, कार्य के वन्दे, बोतम, बुक्तिक स्थाय और खुटनी क सम्बन्ध में हैं। राष्ट्रीय न्यायास्य ऐसे कमाई। का निर्मय करेगा जो कि पारिअधिक निर्मय करेगा जो कि पारिअधिक स्यात्र के स्थाद करेगा जो कि पारिअधिक स्थाप के स्थाद करेगा जो कि पारिअधिक स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याद्ध है। निर्मय करेगा जो कि परकार के सत में ऐसे मामले हैं जिनकी राष्ट्रीय श्रिक्तिय से सहसार है, अथवा ऐसे मामले हैं जिनका सम्बन्ध एक से श्रिक

राज्यों से है। इन तीन न्यायालयों के निर्वाय पर अयील करने का कोई अवसर नहीं है इस्तिय इनके कर्मचारियों की नियुक्ति में उनकी योगवता पर विदोष ध्यान दिया गया है। यहाँ यह बता देना आवस्पक होगा कि राष्ट्रीय न्यायालय प्रापील

स्यायालय का स्थानावज्ञ नहीं है।

(थ) यह कानून रियापी आजाओं के सम्मन्य में आपिकानक परिवर्तन करता है। मालिको की कियी विदेश मामलों में कार्य करने की रियति के सम्मन्य में दिना उन अभिकी की कियी विदेश मामलों में कार्य करने की रियति के सम्मन्य में दिना उन अभिकी को, जिनसे इसका सम्मन्य है, २१ दिन पूर्व अपने विचारों की स्वयना दिने परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह कानून और्थ मिक रोजतार (स्थायी आजाआ) कानून का संशोधन करता है और समाया पत्र देने वाले दियेश वहाधिकारी को तथा अन्य अधिकारियों को इस बात का अधिकार माना करता है कि वे प्रमाया पत्र देने के पूर्व स्थायी आजाओं में प्रतिकर्तन करने के लिये आवेदन देने का अधिकार मान्त पा। यह कानून अभिकी को मो मालिकों के ही स्थाया प्रमाया पत्र देने वाले अधिकारी को स्थायी आजाओं में परिवर्तन करने के लिये आवेदन देने का अधिकार मान्त पा। यह कानून अभिकों को मो मालिकों के ही स्थान प्रमाया पत्र देने वाले अधिकार मान्त पा। वह कानून अभिकों को मो मालिकों के ही स्थान प्रमाया पत्र देने का अधिकार प्राप्त पा। वह कानून अभिकों को मो स्थानी करानी के लिये आवेदन देने का अधिकार प्राप्त पा। वह कानून अभिकार में परिवर्तन करने के लिये आवेदन देने का अधिकार प्राप्त प्राप्त कान्त है। स्थानी आजाओं में परिवर्तन करने के लिये का स्थान प्रमाया पत्र देने का अधिकार प्रप्त कारा है। स्थानी आजाओं में परिवर्तन करने के लिये आवेदन देने का अधिकार प्रप्त कारा है।

(\*) मालिकों के लाग एक विशेष रियायत की गई है, जिसे इस रियायत के स्थान पर पदि न्याय का प्रस्तीन कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। इसके श्रम्तर्योत सालिक को किसी कर्मवारी को, जब कि सत्तम्बार्स विचाराधीन हो, इस कराने से अस्तमक्ष किसी दुराचार के लिये निकाल देने अस्पता स्वा देने का अरिकार प्राप्त है। येसी स्थित में सालिक को आसमुक्त असिक को एक सास का पारिअमिक देना पड़ेगा और अपनी आखा के सिथे अधिकारियों की अस्तुनति सेनी होगी। इससे कारखानों में अनुसासन ठीक रहने की आसा हो जाती है।

हैच कानून का वनते वका दोप यह है कि लरकार को श्रीयोगिक निर्मुंथों को परिवर्तित कर देने का श्रिकितार दे दिया गया है। बड़ी किटेनाइयों के पश्चात् मालिकों और अभिकों के पारस्परिक निरोधी दितों पर कमकीता हो पाता है श्रीर पिर ऐसे सममीतों को वर्ख देने का श्रीधकार सरकार को प्राप्त है तो इसने मामनों के श्रीर अधिक उलक जाने का मय है। कानून में ऐसा प्रकर्य है कि सरकार को परिवर्षन सम्बन्धी श्राज्ञाओं को संबद के समझ रूप दिन की अवधि तक के लिये रख्या जाय जिसके मीतर प्रस्ताव द्वारा संबद उसे स्वीकार करे श्राप्ता श्रस्तीकार कर है, इसने रिश्वित के सुनार की श्राणा नहीं की जा सकती। वास्तियक बात तो यह है कि यह बानते हुवे कि सरकार को अपने इच्छा चुकूत निर्माय बदल देने का अधिकार प्राप्त है कमा जा कि न वक्षों के बीच है वे अपनी बात पूरी-पूरी ज्यक न करेंगे और जल्दी समझीता न करेंगे। कातून की अच्छी बात यह है कि अब कमाड़े में पड़े हुवे टोनी पक्षों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे किसी समझीत के निर्माय पर इस्ताइत कर सकते हैं। इस प्राप्त के किसी पंच निर्माय को सैतला करने के लिये बीप करते हैं। इस प्राप्त के किसी पंच निर्माय को सितला करने के लिये बीप करते हैं। इस प्राप्त के के अधिका करने के लिये बीप करते हैं। इस प्राप्त के के अधिका करने की योजना को कोई स्थान नहीं देता। यहि गिरी के अभिस्ताय इसमें समितला कर लिये गये होते तो अधिक और मालिक के हिरी को दिना कोई हानि पहुँचाये ही पारस्परिक समझीत की नुविधा कुछ अधिक ही सम्मय करें होती।

श्रीधोगिक श्रमुशासन संहिता (Code)—१६५७ मे भारतीय धम कान्में स की स्थायी अत-कांमति ने 'क्षीयोगिक श्रमुशासन खिता' श्रयनाई निर्मे कर्मचारियों तथा नियोक्ताश्रों के छंधों ने भी स्थानित किया । उसने भारत में क्षीयोगिक रमस्यों के सुधारते की श्रासा की जाती है। इसके प्रदूषार कर्मचारों तथा नियोक्ता भविष्य में होने वाले क्ष्माडों को पाररांकि पश्र-श्यवहार, समझौता तथा श्रममें इस्का क्ष्मा करिया स्थाप है। इसके श्रम्यानी इच्छा ने बीच-बचाव करता के इस करने के स्थिय शाध है। इसके श्रम्यानी हम्मा नियोक्ता प्रीच-बाव करता के इस करी की चाल, तालावन्दी, किना, नोटिस के इस्काल, धमकी तथा अनुसासन हीनता के अन्य कर (नी प्रायम् श्रीधोगिक समझे के कारय होते हैं) को नहीं अपनायों।

मार्के की बाव तो यह है कि वंहिता में इन्हें लागू करने तथा इसके परियान आकने की व्यवस्था भी है। १६५८ में केन्द्र में लागू करने तथा खाँकने के लिये एक छोटी संस्था का निर्माण किया गया। यह संस्था विभिन्न समूर्त से खराद या न लागू होने के सम्बन्ध में विश्वस्था एक करेगी। एक के अम मंत्रालय में रिवर्श एक करेगी। एक के अम मंत्रालय ने राज्य सरकारों से २० करपरी १६५८ तक तथा भविष्य में प्रतिभाइ की इस तारीख तक प्रशायिक के उत्तर के रूप में सूचना देने की प्राप्ता की थी। अच्छे छोशोंगक सावन्य कार्य स्वता ही दिया में यह एक प्रभावपूर्ण करम है। प्राधिन्य मार्थ करने तथा संदिता स्वीकार करना ही काफी नहीं है। भविष्य में इसके खनुसार काम होने के लिये यह खायस्थक है कि उसके लागू करने तथा लागू मार्थ है के उसके लागू करने तथा



भारत में अभिक आन्दोलन बहुत पुराना नहीं है। ययपि २० वीं शताब्दों के आरम्भ में भारत में ट्रेड यूनियन थीं परन्तु उनका कार्यद्वेत बहुत सीमित था और बहु उन कार्यों को नहीं करती थीं जिनकी एक ट्रेड यूनियन से अपेक्षा की लाती है। भारत में इनका विकास बहुत बीरे-बीर हुआ और जो कुछ प्रगति हुई मी है वह अनेक कार्यों से करतीथलक नहीं कही जा सकती। अभिकों में किसी समान उहेरन की पूर्ति के लिए संगठित होने की मावना होने के लिए यह आयर्थक है कि उन्हें इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता प्रतीत हो। १८ मीं में मिटेम में अधिशीशक कार्यित हुई और उनके परवात कुछ देशों में उसकी पुनरावृत्ति हुई। परन्तु भारत ने अब तक इस प्रकार की और्योगिक कार्यित हो में उसकी पुनरावृत्ति हुई। परन्तु भारत ने अब तक इस प्रकार की और्योगिक कार्यित की स्वाद्यक्त साम के संगठन की आवश्यकता उत्पत्त हो जाती और एक अभिक संगठन की आवश्यकता उत्पत्त हो जाती और एक अभिक संगठन की आवश्यकता उत्पत्त हो जाती और एक अभिक संगठन कर कारता। और्योगिक कार्यित होना प्रवाद स्वत्त हो जाती और एक अभिक संगठन कर कारता। और्योगिक कार्यित होना आवश्यक हो जाता। भारत के और्योगिक विकास से हुछ समस्याएँ उत्पत्त हो जाती विज्ञी पूर्ति के लिए अभिको का संगठन होना प्रवाद यह समस्याएँ उत्पत्त हो जाती निक्री नहीं है जितनी और्योगिक कार्यक होती पर होनी पर होनी में किसी में स्वति पर होनी में स्वति होनी में स्वति स्वति होनी में स्वति साम से स्वति होनी में स्वति स्वति होनी में सिति पर होनी में सिति होती।

अनेक कारवा से भारत में अभिक आन्दोलन का विकास नहीं हो पाया है;
(१) यह पहले कहा जा जुका है कि भारत की अधिकतर अभिक जनता निरस्दर
है और उसका हिक्कोल व्यक्तिवादी है। अभिक भाग्य पर विश्वास करता है और
यह मानता है कि रथमें प्रयस्त करके यह अपनी दिश्वात महीं सुधार कर एकता है।
यह भानता है मेरित होने के कारण वह अपना सम्युक्त कार्य भगवान के भारेस
होज देता है। यदि अभिक शिवित होता तो उसे अपनी दिश्वात सुधारने की आदरंपकड़ा प्रतीत होती और उसे यह आत हो जाता कि स्वयं प्रयस्त करके यह अपनी
दिश्वात कोवहुन सीमा तक सुधार सकता है। ऐका अनुभव कर यह हस उदेश्य
की यूर्त के लिए अपने अस्त अभिक साथियों को स्वतित कर सकता था। यदि
पारतीय अभिक भी पाश्चात्य देशों के अभिकों को तह मीतिकचादी होता तो यह
निरस्त होते हुए भी संगठित हो सकता था पग्न भारत में निरस्तादा और मायवाद के कारण ही आज तक अभिक का प्रभावशाली संगठन नहीं हो पाया है।

श्रमिक श्रान्दोलन सम्बन्धी अनेक कार्यवाहियों के होते हुए भी भारतीय अभिक की

स्यक्तिगत भावना कुम नहीं हो पाई है। अस्ति (१) भारत का श्रीव शिक श्रीमक फेबल कारखानों पर ही तिर्मर नहीं है।

बीब-बीच में यह गाँव जाता रहता है और फिर काम करने कारखानों में आ जाता है। समान हितों की पूर्वि के लिए संगठित होने में उनके स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति सब से बड़ी बायक रही है। हथर कुछ वर्षों से स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है और शब बीयोधिक अमिक के एक वर्ग का उटमब हो रहा है।

- (३) अधिकों के पारिक्षमिक में कृष्टि हुई है परन्त इसके स्वाय हो रहन-सहन के रूप में भी कृषि हुई है। अभिक झरोति को तरह ऋब मी ट्रेड यूनियन के लिए <u>योका सा स्वदा होने के लिए परतत नहीं होता है</u>। यदि उसे संगठन का लाम मालूम होता तो ट्रेड यूनियन की सहस्यता के लिए आवश्यक सन्दा देने से वह पीके नहीं हटता।
- (४) <u>भारत के उच्चोगपित</u> भी श्रीचोगिक विकास के आरम्म काल के झान देखों के उच्चोगपितियों को तरह ट्रेड युनियनों का बिरोब करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि ट्रेड यूनियन उनकी प्रतिदृद्धी शक्त है। यदि उच्चोगपित छुछ श्री बिनारपूर्व हिंक्कोच अपनात्रों तो हर आगरोलन की बहुत प्रमति हो गयी होयी। हथर छुछ वर्षों के उच्चोगपितयों ने श्रीचोगिक क्याड़ों के नियदारे के लिए श्रीर उच्चोग में शांति बनाये रक्षने के लिए ट्रेड यूनियमों का महस्य समक्ता है।
- (५) वृद्धमान में भारतीय अभिक खेषों पर स्वयं अभिकों का नहीं बहिन वाहरी लोगों का निर्माय है। यदि ट्रेंड यूनियनों का नेतृत्व स्वयं अभिकों के हाय में होता तो वह अभिकों के हित में ट्रेंड यूनियनों का लेगुत्व स्वयं अभिकों के हाय में होता तो वह अभिकों के किए में ट्रेंड यूनियनों का लेगुत्व करने का नहत्व समक वकते ज्ञीर रचने अभिक आग्योलन तेशों से बहु वकता था। परन्तु नेतृत्व स्वयं अभिकों के हाय में महीं है और आहरी लोग हेड यूनियनों का उपयोग अपने राजनीतिक स्वागों की पूर्ति में करते हैं। उनकी हिष्ट में अभिकों की रियति में खुवार करना गीय विषय होता है। होतीलिए अभिक लोगते हैं कि ट्रेंड यूनियनों का संगठन में यह स्वोध होने में ट्रेंड यूनियन हों हो भारतीय ट्रेंड यूनियन संगठन में यह स्वोध होने में स्वाध्य संगयों का के क्षेत्र में मार्थ का स्वोध होने संगठन में स्वध्य संगयों कोई कार्यवाही नहीं की वा खबी है। पारतीय ट्रेंड यूनियन संगठन संगवित का संगयों के रूप में कार्य की सालिक या सरकार के विवस आग्योलन करने की एकेन्सी के रूप में कार्य हो। हा नीति के कारण मारतीय ट्रेंड यूनियनों का कार्यचेत्र महुत संकीर्ण हो गया है।

१६५५-५६ में (जिस अवतन वर्ष के आँकड़े प्राप्त हैं) मारत में फर्न्य६ अभिक संव वे जिनके सदस्यों की संस्था २२% लाख थी। निम्न तालिका से यह स्वष्ट होगा कि १६५२-५६ से र्राजरदर्ध अमन्यस तथा उनकी सदस्य संस्था में ग्यांत सुदें हैं। संबो के इस विकास के होते हुए भी राजस्टर किये हुये अभिक भंगों के सुल सदस्यों की संस्था उद्योगों में कार्य करने वाले अभिकों की कुल संस्था नहीं है। संबो कुल सहस्यों की संस्था उद्योगों में कार्य करने वाले अभिकों की कुल संस्था कर स्था मार्थ है।

रिजन्दर्भ अग्र-संघ तथा जनकी सहस्य-सक्या

वर्ष	अमस	व का संख्या	सदस्यों की कुल छंख्य
		_1	
	र्गजस्टर्ड रजिस्टर्ड	युचना देने वा	ाले
१६५०-५१	३७६६	9009	१७,४६,१७१
<b>१</b> ६५१-५२	• ४६२३	रप्रप्रह	<b>१६,६६,३</b> १
१९५२-५३	88.5K	₹७१=	₹0,8€,00
<b>₹</b> E <b>५</b> ₹-५४	६०३६	३२९५	72,27,58
የፎኳሄ-ኳኳ	6680	<b>इ</b> ११३	28,00,896
શ્દપપ્ર-પ્રદ	७८४६	38.88	२२,२५,६१

#### काननी व्यवस्था

ट्रेड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने का उदेश ट्रेड यूनियन की क्यास्वा करना, उसके कर्तस्यों और उत्तरदायित्व को निश्चित करना और ट्रेड यूनियन सम्बन्ध उसित कार्यवाही के सम्बन्ध में उनकी रक्षा करना है। कानून यह निश्चित करता है कि उद्योगपीत ट्रेड यूनियन को सान्यता देंगे और ट्रेड यूनियन सम्बन्ध उचित कार्यवाही करने पर किसी अदास्वत में उन पर एकदमा नहीं कारा प्राप्त परिता कार्यवाही करने पर किसी अदास्वत में उन पर एकदमा नहीं कारा प्राप्त परिता कार्यवाही भी अस्य अर्थों में अर्थिय पीरित की वा सकती है।

१६२६ का भारतीय ट्रेड यूनियन कानून—१६२६ के भारतीय ट्रेड यूनियन कानून में १६२८, १६४८ और १६४७ में शंशोधन किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियन की यह परिभाष दी गई है कि कोई मो क्षेत्रक चार्ड अस्पारी हे ट्रेड यूनियन की यह परिभाष दी गई है कि कोई मो क्षेत्रक चार्ड अस्पारी हो या स्पारी यदि अभिक और उद्योगपति या मालिक और कर्मचारियों के बीच अपना कर्मचारियों के बीच पारस्वरिक जनित राजन्य बनाये रखने के बिचर कराया गया या हो या हो से ऋधिक संघो का संगठन हो तो उसको भी टेड यनियन ही कहा जायगा । इस प्रकार टेड युनियन की श्रेखी में श्रीमकों और मालिकों टोनों के

संगठन समिलित कर लिये गये हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी यनियन के ७ या उससे अधिक सदस्य कानन के अन्तर्गत नियक रिजासार के पास युनियन की रजिस्टी कराने के लिए आवेदन पत्र भेज सकते हैं। परन्त इसके लिए यह शावत्रयक है कि यनियनें निर्धारित शर्ते पूरी करती हों। यह भी ब्यवस्था की गई है कि रजिस्टर्ड युनियन के पदाधिकारियों में से आधि वास्तव में उस उद्योग के कर्मचारी हों जिसके अभिकों की यह यनियन हैं। इससे बाहरी व्यक्तियों को देव युनियन संगठन में काफी स्थान मिल जाता है। यदि युनियन के कानून सम्मत उद्देश्य को प्राणे बढ़ाने के लिए किये गये समझौते के सम्बन्ध में महादा हो तो यह कानून युनियन के पदाधिकारियों और सदस्त्रों की कौजदारी के दावे से मरबा करता है। इसके साथ ही यदि मालिक अधिकों के अगरे के बारे में कोई कार्य किया गया है ह्यीर शिकायत केवल यह है कि इस प्रकार के कार्य से कहर अमिक द्वारा काम छोड दिये जाने की सम्भावना है या यह ब्यापार में प्राथता किन्हीं लोगों की नियक्ति में हरतत्त्वेय करना है तो इस कानून की वजह से युनियन के पदाधिकारियों श्रीर सदस्यों पर दीवानी सकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। इस कानून द्वारा रिक्टर्ड ट्रेड युनियन के कीय पर शिवेडम्ब लगाया गया है। इस कीय का केवल उन्हीं कार्यों में उपयोग किया वा सकता है जिनका कानून में विवरण दिया गया है परन्यु एक प्रथक् कीप का निर्माण करने की श्रदुमति दे कर यनियन के सदस्यों के नागरिक एवम राजनीतिक हितों की भी रचा की गई है। प्रत्येक द्रेड युनियन की प्रतिवर्ष अपना दिखान छुपे फार्मी में भरकर राजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करना पढ़ता है। इसके साथ ही आय-व्यय का आदिट किया हुआ विवरण भी भेजना पड़ता है। यदि मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन के (१) श्राधकतर सदस्य श्रानियमित इस्ताल मे भाग लें, (२) युनियन को कार्यकारिएी ख्रानियांगत इड़ताल की सलाह दे, अससे सहयोग करे या उसे भहकाए, या (३) युनियन का अधिकारी शलत वक्तव्य प्रकाशित कराए, तो कानून के अनुसार ये कार्यवाहियाँ अनुचित समकी खाँयगी और इसके लिए

दरडस्वरूप युनियन की मान्यता वाग्स ले लेन की व्यवस्था की गई है। दसरी श्रोर यदि उद्योगगति या मालिक (श्र) अपने श्रमिको के ट्रैंड यूनियन सर्गाटत करने के अधिकारों में इस्तचेत करे या पारस्परिक सहायता एवम् सुरह्या के उद्देश्य से की जाने वाली कार्यवाही में गड़बड़ों पेदा करे, (ब) किसी ट्रेड प्रनियन के

बनने या उबके प्रशासन में इस्ताहेन करे, (श) किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के अधिकारी को ट्रेंड यूनियन का अधिकारी होने के कारण नीकरी से निकाल दे या उसके साथ मेर-भाग की नीति वरते, और अभिकों को कामून के अस्तर्गत चलने वाली किसी जाँच इरवारि कार्यवासी में गवाही देने पर या आगोग लगाने पर निकाल दे, या (द) मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ समसीता बातों करने से इनकार कर दे या कानून में दो गई खुनियाओं को देने से इनकार कर दे तो उच्चोत्तपति अथवा मालिक की यह कार्यवाही कानून की दिष्ट में अनुचित समझी जायां। अनुचित कार्यवाही के लिए उस पर इकार करवा जुमीना करने की ज्यास्था हो गई है।

इस कानन से यारि टेड यनियनों को मान्यता सिली और उनकी काननी

हक कानून से क्याने ट्रेड यूनियनों को मान्यता मिली और उनको कानूनी आवार दिया गया किर भी हली मारत में ट्रेड यूनियन रोगवन का विकास करने का उद्देश पूर्ण न हो मका । हलमें क्रानेक रोग हैं : (१) हफ कानून के अनुवार ट्रेड यूनियन केवल मज़्दों के संगठनों तक ही सीमिन नहीं है, जैवा कि होना चाहिए था, परन्तु उनमें मालिकों और उन्नोगपतियों के संगठन भी शामिल किये गये हैं। इस्के अनावश्यक गक्का पैदा हो जाती है; (२) कानून के अनु-सार ट्रेड यूनियन का रिनट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। इस कानून में उन प्रांतननों को सारतीय व्यव प्रियान के अन्यर्गत की बत्राय के सुकर से लेखूर नहीं नी गई है जिनको रिकर्शन कहीं हुई है, इससे ट्रेड यूनियन के सामान्य कोय और राजनीतिक उद्देशों को पूर्ति के लिए मिर्मित कोय में अवैज्ञानिक सम्बन्ध न्यावित किया गया है। सामान्य कोय स्वय करने के लिए आरयन संजीव व्यवस्था की गई है।

क्याचररा-सिहिता (code of conduct) —यचि भारत में अम संघो की बाहुत्यता है तथा विभिन्न संघो (federations) के शामेनस्य सिहत काम करने की कोई खाखा नहीं है फिर भी मई, १९५६ में नैभीताल में भारतीय अम-काफ़ैन्स में मान सेने वासे अम संगठनों के मितिनिधियो द्वारा अपनाये गये आवरण सिहता से खाला का संचार होता है।

श्रावर्त्त शिक्षा को प्रचार हाता है।

इस संहिता के अनुसार "(1) किसी उच्चोग अपवा इकाई के कर्मचारी
को अपनी इच्छा की यूनियन का सदस्य बनने की स्वतन्त्रता होगी। इस संबंध में कोई दाना नहीं इ.ता आयगा। (1) यूनियन की दोहरी सदस्यता नहीं होगी।
अतिनिधि-युनियनों के सम्बन्ध में यह तथ किया गया कि उपरैक्त नियम की और

परीचा की जाय। (iii) अम-संबं के प्रजातंत्रीय ढंग पर कार्य करने की स्त्रीकार

किया जाय तथा आदर की हिन्द से देखा जाय। (iv) ट्रेड यूनियन फे पदाधिकारियों तथा प्रधासकीय निकायों के जुनाव नियमित तथा प्रधासकीय दंग पर होने चाहिये। (v) अभिकों की अज्ञानता और पिछडेचन का कोई संगठन कायदा नहीं उठायेगा। कोई संगठन अनावस्थक मीने नहीं पेशा करेगा। (vi) हर एक संव जातीयता व प्रान्तीयता से दूर रहेगा। तथा (vii) अम संधों के बीच कोई हिंगा, दवाय, घमकी तथा व्यक्तियत बदनामी आदि नहीं होगी। " यह सव बढ़े ही अच्छे प्रस्ताय है किन्दु हनकी चल्लता इस पर निमंद करेगी कि रेड-प्रनिवस नरीं कार्य कर करेगी कि

अम संघों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई वेन्द्रीय द्याधिनश्य नहीं है। मारतीयश्चम-काफ्रेन्स ने ट्रेड बूनियन के प्रान्यता देने के सम्बन्ध में निम्म कछीटियाँ प्रस्तावित की। "(i) जहाँ एक से ब्राधिक युनियन हो यहाँ मान्यता प्राप्त करने वाली यनियन रिजस्टी के बाट कम से कम एक वर्ष तक काम करती रही हो किन्तु जहाँ एक ही यनियन हो वहीं यह शर्स लाग नहीं होगी । (ii) सस्थान के कम से कम १५% श्रामक उसके सदस्य हो । (iii) किसी स्थानीय च्रेत्र में एक यूनियन को किसी उद्योग का प्रतिनिधि यूनियन शाना जा सकता है बशरों कि क्षेत्र में उद्योग के २५% अमिक उसके सदस्य हो। (iv) यूनियन को मान्यता मिलने पर, दो वर्ष तक रिधित में कोई सुधार नहीं होना चाहिये। (v) जब किसी उद्योग अथवा संस्थान में अनेक यानयन डॉ ती सबसे अधिक स्टरय-संख्या बाली यनियन को मान्यता देनी चाहिये। (vi) किसी चेत्र मे विसी उद्योग की प्रतिनिधि यूनियन की देश भर के संस्थानों के श्रीमकों का प्रति-निधित्व करने का अधिकार है। किन्तु यदि किसी संस्थान के असिकों की यूनियन मे उसके ५०% अभिक सदस्य है तो उस केवल स्थानीय दित के मामलों पर कार्य-बाही करने का अधिकार होना चाहिये। (vii) प्रतिनिधित्य का रूप निर्णय करने के लिये कानबीन करने के दंग को और अधिक पर्याप्त कर देना चाहिये। जब इस सम्बन्ध में वैमागिक छान-बीन के परिणाम दलों को मान्य न ही तो वेन्द्रीय श्रम संघ के प्रतिनिधियों से निर्मित एक समिति को इस प्रश्न की जाँच कर इसे हल करता चाहिये । इस कार्य के लिये केन्टीय श्रम संगठन निर्मान भागों के लिये आवश्यक धन श्रीर व्यक्ति अस्तुत करेंगे। यदि इससे काम नहीं होता तो प्रश्न का निर्णय न्यायालय के सुपुर्द कर देना चाहिये। (viii) सिर्फ वे यनियन मान्यता पा सर्वेगी जो श्रीद्योगिक श्रनुशासन संदिता को मानेगी। (ix) उन श्रम-संधों के सम्बन्ध में जो श्रम के चार वेन्द्रीय संगठनों से . सम्बन्धित नहीं है. इस प्रकार अलग से विचार करना चाहिये !" यह कसीटियाँ

विस्तृत तथा सुविचारित हैं। यदि इनका अनुसरण किया गया तो ट्रेंड यूनियनो की नींव हह हो जायेंगी। भाष्त अनुसव के आधार पर वे इस वियय पर अधि-नियम बनाने का आधार भी बन सकती हैं। अधिराय की ग्रोन्जा---वर्तमान में भारतीय अभिक शास्त्रोलन में कछ

रे श्राचारभत दोष हैं और स्थिति सुधारने के लिए इन दोवों को दर करना बहुत आवश्यक है। इस समय एक ही उद्योग में एक ही चेत्र से अनेक टेड यनियनें हैं। बहुत श्राधिक टेड यनियन होने से श्रीमक का पत्त कमजोर पढ़ जाता है और श्रांसक के श्राधिकारों की रखा में भी बावार्ये श्रा जाती हैं। इसलिए ट्रेड यनियनों के संगतन की संगठित करने ज़रीर इनकी एकता के सब में श्रीधने की खरगन्त काराज्यकता है। यह कायुक्यक है कि एक सेत्र में स्थित किसी मुख्य उद्योग में अभिको का प्रतिविधित्व करने के लिए केवल एक में अधिक टेड यनियन न हो। यदि एक सेन्न के विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले सभी श्रीमकी का प्रतिनिधित्य करने के लिए एक टेंड यनियन होती तो सर्वोत्तम होता । परन्त यह संमय नहीं है क्योंकि कमी क्यों कि किया जाते हों के बार्य करने वाले श्रीवकों की समस्याएँ प्रिय होती हैं। साथ ही विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले अभिक एकता के सन्न में महीं बंध पाते हैं जब कि टेड यनियन चान्दोलन की सफलता इनकी एकास्मकता पर निर्भर करती है। भारत के ट्रेड युनियन संगठन में वृत्तरा बढ़ा दीय यह है कि यह अपनी सम्पूर्ण शक्ति प्रायः इंडताल में और मालिकां से सामृद्धिक माँग काने में लगा देते हैं। बहत कम ऐसी यनियन हैं जिन्होंने अपने कार्यसेत्र को व्यापक बनाया है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सामृहिक रूप से माँग करना और इवताल करना ट्रेड युनियनों का महत्वपूर्ण कार्य है परन्तु इसके साथ ही अन्य कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में द्रेड यूनियन का कार्यक्रम ख्रीर विरन्त करने की आवश्यकता है। इसमें वयस्कों की शिक्षा, सहकारी-आव्होलन का गटन, जनसेवा कार्य इत्यादि भी सम्मिलित विये जाने चाहिये। इससे ट्रेड योनयनी की अपयोगिता बह जायगी।

ट्रेड युनियन आन्दोलन का एक बहुत वहा दोष बेन्द्रीय संगठनों का बाइल्य है। इस १५३१ यूनियनों में ने आहे एसन टी० यू० सी, ए० आहे ० टी० यू० सी। ए० आहे ० टी० यू० सी। ए० साहे ० टी० यू० सी। से संपीतित पूनियनों की संस्था कमाया ११७, ५५४८, १९६, और २३६ और उन के सरसों की संस्था कमाया ११५६ लाख, २०४ लाख, और १५६ लाख १६५६ के अन्त में थी। इन केन्द्रीय संगठनों को एक शाक्षशाली संस्था में संगठित करना समा है। इसमें संदेह नहीं कि इन केन्द्रीय संगठनों के राजनीतिक-

करने झीर अमिकों के यास्तविक हितों की रह्मा करने का प्रश्न है इनका आधारभून आर्थिक कार्यकल समान है। यदि यह केन्द्रीय संगठन एक में मिल जाँव तो
अमिक के हितों की वर्तमान की अपेन्ना कहीं अच्छे रूप में रन्ना की जा सकती
है। यदि इन संगठनों को आरंभ में पूर्यंतया एक में मिला देता संभव न हो तो

जरेणमें में बहत अधिक श्रंतर है परन्त जहाँ तक श्रमिकों की स्थिति से स्थार

आर्मक के हिता का विश्वान का अपचा कहा अच्छ क्या में रही का जो सकता है। यदि इन संगठनों को आरोप में पूर्णतया एक में मिला देना संभव न हो तो कम से कम समान हिता की कुछ समस्याओं को हल करने के लिए इनमें परस्थर एहस्योग तो हो ही सकता है। इससे स्थिति में मुखार होगा और मिनिंद्र में इन संगठनों का एक किस्सा करने के लिए मार्ग लल जाया।

### श्रध्याय ३४

# रेल यातायात

भारतीय रेलों ने उल्लेखनीय प्रयति की है। १८५३ में भारतीय रेलये लाइन की लग्याई केवल २० योख थी, १८०० में यह २४,७५२ मील हुई और १८५५ में स्वका प्रवार ६५,११८ शील और १८५६ में से १५,७५४ मील हों गया, जिसमें १५,२६१ मील वर्षात प्रवार के अवन्यत्व था। १८०० में मारतीय रेलों से १७ करोड़ ६० लाख यात्रियों ने यात्रा की, ४ करोड़ ६० लाख यात्रायों थे संख्या १३८० में सामतीय रेलों से १७ करोड़ ६० लाख यात्रायों है संबंध १३८० में सामियों की संख्या १३८० में १६ करोड़ ६० लाख और दोये जाने वाले माल की माला १२ इस्तेष्ट ५० लाख यन हो गई। १६ अमैल १८५६ को मारतीय रेल ने वाल्ड पाद से थाने १०० वर्ष पूर्व १६ अमैल १८५६ को प्रयात प्रवार से थाने वाल्ड भील को धूरी तय की थी। यात्राय रेलवे संगठन में कुछ शुटियों हैं और कुछ दाय मी हैं पान्तु किर भी जिल गति से उसने प्रयत्त की हैं उस पर मारतीय रेलवे गत्र कर से उसने हिं।

मलय विशेषसाएँ-भारतीय रेलवे के विकास में कुछ उल्लेखनीय विशेष-ताएँ है। (१) भारत में रेल का कार्य निजी उद्योग के रूप में प्रारम्भ किया गया। रेल-उद्योग करने वालो को सरकार ने कुछ सविधाएँ दीं जैसे इन्हें भाग सफत दी गई और पूँजी की वस्ली की गारन्दी दी गई। इससे रेखने निर्माण के व्यय में बांड हुई और सारे देश को इसका भार बहुन करना पढ़ा। ऐसे समय में जब रेलों का निर्माण करने के लिए उद्योगपति पूजी लगाने को प्रस्तुत नहीं में यह सविधायें देश समवतः ग्रायन्त ग्रायम्यक था परन्त बढि इस ग्रोर किवित सावधानी से कार्य लिया जाता ता इनका काकी कम भी किया जा सकता था। रेली का प्रकर निकी उद्योगपतियों के हाथ में होने से इसकी काफी आलोचना की गई है। श्रालोचका ने प्रश्नचको द्वारा पत्तपात किये जाने और कच्चे माल के निर्यात तथा तैयार माल के आयान के भाड़े में रियायतें देने की शिकायतें कीं, क्योंकि बन्दर-गाडी से देश के श्रन्दर सामान लाने और बन्दरगाहों तक सामान पहेंचाने के लिए रेल के माडे की दर ग्रन्य दरों की अपेता कम रखी गई थी। एकवर्थ समिति (Acworth Committee) ने सुकाव दिया कि राष्ट्रीय हित में रेल के निजी उद्योग को कमश: राष्य को श्रपने हाथ में ले लेना चाहिए । इस दिशा में १६२५ मे प्रथम प्रयास किया गया। सरकार ने ईस्ट इस्डिया और जी, खाई, पी, रेलवे को अपने अधिकार में ले लिया परन्तु इस प्रक्रिया को पूरा होने में २० वर्ष लगे और जहाँ तक ब्रिटिश भारत का सम्बन्ध है १९४४ में निजी उद्योग समान्त कर राज्य ने इसको पूर्वत्या अपने अधिकार में ले लिया। १९५० में संबीम वित्तीय एकोकरण के परचात् मृतपूर्व रियासतों की रेलों को भी मारत-सरकार ने अपने हाभ में ले लिया और अब रेलने एकमात्र राजकीय उद्योग वन चका है।

रेख उचाग निजी उचांगपियों के हाथ में होने की अपेता सरकार के हाथ में होने से अनेक लाभ हैं—(अ) इससे साधनों की अनावर्यक हानि और विभिन्न रेखने-महन्यों में मतियोगिता समास हो जाती है। (ब) राजकीय उचांग होने के कारण देश के अधिगोगिक और कृषि साधनों के विकास के महत्व की हांग्ट में स्वते हुए रेख के माई की उचित दर निहिन्त की जा सकती है और (ब) इस उचोंग के जो लाभ होगा नह केन्द्रीय थन कोष में जमा हो सकता है। (२) दो विश्वसुकों के कारण, १९३० की आधिक मंदी और १९४७ में

(२) दो विश्वसुदी के कारण, १८६० की आधिक मेदी और १८५० में देश के विभाजन से रेलों पर बहुत मार पड़ा है और उसका परस्पर सम्बन्ध में विश्विद्ध हो गया। युद्ध के कारण रेलों की कार्यक्रमता पर प्रांपिक ध्वान नहीं दिया गया, पुराने कल गुजों हत्यादि को नहीं बदला गया और नहीं मशीनें लगाने की पोजना स्थिति कर दी गई। दितीन विश्वयुद्ध के समय द्र प्रतिशत मीडर-मेज में हजान, १५ प्रतिशत भीटर-नेज के बैगन, ४ हजार भील लग्नी पटिएपाँ और ४० काल स्लिप्ट प्राप्तीय रेलों से लेकर भ्रव्यपूर्व देशों को भेजे गये। युद्ध के समय रेलों के सामान का और पटिएयों का अत्याधिक उपयोग किया गया, उनको न बदला ला सका और न नया सामान लगाया जा सका। इसते रेलों नी कार्य-स्मता पट गई। देश का विभाजन हो जाने से रेलों का कुछ सामान पाडिस्तान के भाग में चला गया और अर्याधियों को लाने-पहुंचाने के कार्य में रेलों पर और अधिक भार पड़ा। गत कुछ वर्षों में रेलों पर आवर्यकता संक्षिक भार कुछ कम किया गया है, पुराने सामान को बदला गया है और सामान की मान्ना बदाई गई है परसु हस दिशा में अभी सहुत कुछ करना रोग है।

(4) त्रतीत में इसनों, बादलरों, हिन्जी इस्तादि के लिए भारतीय रेखों को आयात पर निर्भर करना पहला था। इससे देश का बहुत-सा पन विदेश चला जाता पा और देश को विदेशों विनिमय सामनों को गम्भीर होते होती थी। ज्य पर कुछ वर्षों से स्थित में सुधार हुआ है और अब देश में ही इसना हिन्दी इस्थादि बनने लगे हैं। भारतीय कारखानों में हिन्जी का उरशादन बढ़ रहा है और रेखने की आवश्यकता की अधिकाधिक पूर्ति की जा रही है। चिष-रखन के इखन बनाने के कारखाने में इखन के स्वगमण ७० प्रतिचात कल पुनों का उत्पादन किया जाता है ज्ञीर वेयल २० प्रतिशत का आयात करना पड़ता है। .प्या गणा णापा २ आर प्यत्य द्रण्यसम्बद्धाः आराज प्रया गणा २ । ( ४ ) भारत में खनेक रेखें सी परन्यु पुनर्वर्मी-करख बीजना लाम्, करके

इनको ७ चेत्रों में संगठित किया गया है । एकीकरण से पहिले भारत में १५ ने अप जिनमें से २२ खरकार के अधिकार के थी। रेलवे बोर्ड की बाँच करने ь लिये नियुक्त चीमति (१९५०) की सिकारिय पर मारत सरकार ने भारतीय रेलों की ६ चेत्रों में संबंधित करने का खिद्रान्त स्वीकार कर लिया। रिचिणी रेलवे का १४ अमेल १८५१, पितमी और केन्द्रीय रेलवे का प नवन्तर १८५१ की भीर रोप तीन उत्तरी, उत्तरी पूर्वीचर और पूर्वी रेलवे का १४ अमेल १६५२ को उद्शादन हुआ । पहली झगस्त १९५४ में सातवें चेत्र का निर्मास पूर्वी रेतवे की दो चेत्रों में दिमाजित करके दिया गया: (१) पूर्वी रेलवे क्रियमें पुरानी हैं। न्नादै न्नार का सुगलतस्य तक का आग (स्थितहर विविजन को से कर) सामितित थी, और (२) इहियों पूर्वी रेलवे जितमें सम्पूर्ण बी॰ एन॰ झार॰ समितित थी। इत प्रकार मारतीय रेखने को निम्न छात चेत्रों में विमाजित कर दिया गया।

(१) रिल्लियो रेलवे-एसमें एम॰ एन्ड एस॰ एस॰, एस॰ आई॰ और

मैदर राज्य रेलवे सम्मिलित है।

(२) पश्चिमी रेखवे—इसमें भूनपूर्व बी० बी० स्नाई॰, सीपापूर, राजस्थान तथा जेवुर रेखने और बोधपुर रेखने का कुछ माग सम्मिक्ति कर दिया राया है।

. (३) केन्द्रीय रेलवे—इतमें जी० आर्दे० पी०, एत० एस०, सिन्ध्या

राज्य स्रीर भीलपुर राज्य रेलवे सम्मिलित है।

(v) उत्तरी रेलवे—इसमें ईo पीo, जोबपुर और बीकानेर रेलवे, ईo श्चाद् । श्चार के इलाहाबाद, लखनक श्रीर सुरादाबाद हिद्योगन श्रीर बी । बी । पुग्ड छी॰ आई॰ रेखवे का दिल्ली रेवारी-क्रजिलका चेत्र सम्मिलित हैं।

(५) दिसकी पूर्वी रेलचे इसमें बी॰ एन॰ आर॰ शामिल है।

 (६) उत्तरी पूर्वी रेखने—इसमें श्लो॰ टी॰ एन्ड श्रासम रेखने, ६० श्लाई० श्चार का कुछ मान और बी की बार सी अपाई के रेलवे का करेहगढ़ चेत्र **2** 1

(७) पूर्वी रेखवे—इसमें पुरानी ई० आई० का मुगलसराय तक का माग

७ देवों का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ है कि जिसमें विभिन्न देवों का भ्रीर तियालदह डिवीबन सम्मिलित है। कार्यका व्यय के बाद चलाया जा सके और विभिन्न चेत्रों में यातायात की उचित मुक्ति प्राप्त हो। विभिन्न सेन्नों के रेल पयों का विस्तार २३३१ मील से लगाकर (जो कि पूर्वी रेलने का है) ६३३६ मील तक है। (जो कि इत्तरी रेलने का है) इस बात का स्थान रखा गया है कि कर्मेनारियों और अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम से काम हटाना पड़े और चेनल ईस्ट ट्रिया और बीठ सीठ परन सीठ आईंठ रेलने को छोड़कर नहीं तक सम्मय है वर्तमान रेलने क्यवस्था को बिना छिन मिल्न किए एक या दूसरे भाग में समिलत कर लिया जाए।

ार्य। रेलवे के पुनर्वर्गीकरण योजनाकी श्रालोचना को गई है। क्या गया है कि (य) पनवंगीकरण से एक रेलवे के कर्मचारियों को दसरी रेलवे में परिवर्तित किया गया, उनमें अनेक को नौकरी से खलग कर दिया गया, (ब) इससे कम से कम दो रेलवे—इंस्ट इन्डियन और बी॰ बी॰ एन्ड ॰ सी॰ शाई॰ रेलवे—सोसी गई जिसमे अनेक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो गई, और (स) इससे भारतीय व्यापार एवम उद्योग को अनेक कठिनाइयाँ हुई हैं। रेलवे के पुनर्धर्गीकरण जैसे वडे परिवर्तन में योद्या-वहत सम्बन्ध विच्छेद होना और कहर कर्मचारियों को नीकरी से ब्रालग कर दिया जाना व्यानियार्थ था। उससे बचा नहीं जा सकता था। परन्त इतने मे ही पुनर्वर्गीकरण की योजना अवाखनीय और अनुपयुक्त सिद्ध नहीं होती क्योंकि इस योजना के लागू हो जाने से जो लाभ होंगे वह इसने होनेवाली हानियों की अपेडा कहीं अधिक हैं। यह भी कोई तक नहीं, जैसा कि कुछ सम-तियों ने सुकाध दिया था, कि यह बोखना पाँच वर्ष बाद लागु की जाय श्रीर सरकार को इस समय इसे स्थागत कर देना चाहिए था। यद पुनर्वगींकरण की नीति स्वीकार कर ली गई है तो इसे जितना शीध लागू किया जाय उतना ही ग्रब्हा है। इस योजना के लागू करने से तीन निश्चित लाभ है: -(क) इससे बह सभी लाभ प्राप्त हो सकेंगे जो प्रबन्ध व्यवस्था बढे पेमाने पर संगठित करने में डोते हैं। (ख) इससे एक ही काम अनेक बार करने से खटकारा मिल जायमा ग्रीर हानिकारक प्रतियोगिता भी नहीं हो सकेगी श्रीर (ग) इससे रेलवे नी आर्थिक रिपति इट् होगो और कार्य के स्तर में सुधार किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के परचात् रेल के माड़े और कियाये की दर, यात्रियों की सुविवाझों, मजदूरों के वेतन और सुविधाओं इत्यादि के सम्बन्ध में सारे देश में समान नीति लागू की जा सकेगो। यह कोई छोटी सफलता नहीं।

(4) भारतीय रेलवे को कार्यचमता अपी भी बहुत नीचे स्तर को हैं। युद आरंभ रोने के पूर्व की कार्यचमता के स्तर तक भी अभी भारतीय रेलवे नहीं वहूंच सन्नी है। इस सात का प्रमाख माल के डिब्बों का चनकर लगाकर अपने स्थान पर पहुंचने में दस अववा खारह दिन के समय का लगना है जब कि सुद के पूर्व केनल नी दिन समते थे। रेल के शामान के अभाव के अदिस्कि कार्य प्रवस्थ में देर लगना भी माल क एक स्थान से दूसरे स्थान तक देर से पहुंचने इस प्रधान कारण है। समय की पाजन्दी तथा माल के डिक्बो के प्रयोग स्पक्त इस प्रधान कारण है। समय की पाजन्दी तथा माल के डिक्बो के प्रयोग स्पक्त अक बहुत नीचे स्तर पर हैं। छोटी सारन की स्थिति और भी विगली हुई है।

मारतीय रेल हे में कीय हो का इयम सी बहुत ग्राधिक है। वर्तमान समय में १०५ लाख उन कीयला १०५ कोड़ क्यार्य को लागत का प्रयोग में आता है। १०५ लाख उन कीयला १०५ कोड़ हमार्य राज वे पह करी कि कमेरी ने विभिन्न उपायों द्वारा २०% वयत करने का हमार्य राज वे पह करी कि हमार्य हो यह जो रेल हे को प्रति चर्य ६ करी कि द्वार्य की दिया था। मार्ट यह समय हो लाका तो रेल हे का प्रति त्यार्थ कराय विश्व क्यार्थ के प्रवाद की पूर्व की सम्मा । इक्त आर्तिएक अप्याधितकामता के वच्च अपने ती वाहिय लिंद में रेल वे उपायों की पूर्व की हो मार्थ हो अपने दे ले कि इस प्रवाद की स्वाद की स्वाद स्वाद अपने हो लाग तथा आया में दृष्टि हो जायती।

रेलवे की विक्त ब्यवस्था — एकवर्ष समिति के सुकाव पर १६२४ मे रेलाने की यिच अपनस्था केन्द्रीय सरकार की शामान्य वित्त अवस्था से निल कर दी गई। १६२४ के प्रयक्तरण समफीते में यह व्यवस्था की गई थी कि रेलने में लगी हुई पूँजी वर स्थाल के लाथ ही स्थलवाय में लगी पूँजी का एक प्रातशत, अतिरिक्त नामीय का देशांग और रेखवे के मुरांबत कीय में १ करोड़ कराया जमा कर देने के बाद बचे प्रस्तिवक अधिरिक लाभाँग का है माग राजस्य के हास में जमा करेगी। महत्वपूर्ण रेखों की हानि का भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। रेलमे के सुरजित कीय में से सामान्य राजस्व दिवा जावगा झीर यदि श्रावश्यकता पड़ी तो हर-फूट के लिये पूँ जी श्रीर रेलवे की श्रापिक स्थिति की हदु बनाने के लिए भी इसमें से धन लिया जाएगा। रेलने के लामान की बरतने न्त्रीर तया शामान संगाने के लिए १ अप्रैल १६२४ से टूर-पूर के लिए एक भिन्न सुर्राचत कीप बनाया गया है। केन्द्रीय शरकार की शामान्य वित्त व्यवस्था से रेलवे की बिच व्यवस्था को मिल करने के दो लाम हुये हैं: (अ) अर्तात में सामान्य वित्त को कठिनाह्यों और अनिश्चितता पर ही रेलवे का मिश्य निर्मर करता था। इस कारण वह पहले ते ही अपने विकास की योजना निर्माण नहीं कर पाते थे। अनुसान है कि पृथवकरण समझेते के अनुसार वित्त व्यवस्था थकष्ट कर देने से रेलवे की रिपति अधिक सुरीलत हो जायगी और इसके प्रशार करने के लिये तथा इसमें सुघार करने के लिए निश्चित घन राश्चि प्राप्त हो जायगी। (व) अतीत में यह निव्चित नहीं या कि वेन्द्रीय राजस्य को रेलवे से कितनी ग्राय क्षोगी परन्तु पृषककरण् समकौते के अनुसार इसके अन्तर्गत घन राशि निश्चित कर दी गई है।

प्रधानकरमा समसीते में संशोधन किया गया जो १ अप्रैल, १९५० में लाग हुआ। इस संशोधन के अनुसार (१) जनता को रेलवे का हिस्सेदार माना गया है ग्रीर को ऋग ली गई पूँजी रेलवे में लगाई गई है उस पर सरकार को (ग्रयांत् जनता को) ४ प्रतिशत का निश्चित रूप से लाम मिलेगा । यह धन रेलचे की जाय में से केस्टीय सरकार की दिया जाता है। पहले १२२४ के समस्तीते के ब्रामगर मामान्य राजस्य में दी जाने वाली धन राशि की कोई निश्चित तिर्धारित मात्रा नहीं थी पर इस संशोधन से यह निश्चित कर दिया गया कि रेलवे में जो कछ पूँ भी लगी है उसका एक निर्वारित प्रतिशत सामान्य राजस्य में दिया जायगा। (२) समसीते में रेलवे विकास कीय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इस कोष से (ब्र) नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने में विचीय सहायता दी जायगी। इन नई लाइनों से आय होना आवश्यक नहीं है. (व) यात्रियों की सुनिधा के लिए व्यय किया जायगा श्रीर (स) अस कल्यारा कार्य इत्यादि में व्यय किया जायगा । (३) समकीते के संशोधन के अनुसार प्रथम पाँच वर्षों में रेलवे के टूट-फुट कोव में कम से कम १५ करोड़ रुग्या संग्रह किया जाना चाहिए और शेप अविरिक्त आय से एक ऐसे कीप का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे श्राधिक सन्तुलन रखा जाय। रेखने का सामान अधिक महँगा होने के कारण १९५० के पृथक्तरण समझौते के पश्चात से टूट-फूट के कीय में ३० करोड़ रुपये की नियत धनराशि समह कर दी गई है। पुराने समसीते में सामान्य राजस्व के ब्रान्तर्गत जमा की जानेवाली धन-

पुरान एसकात में धामान्य रानत्व के झान्यरात जसा के। खानवावा बन्न रासि निश्चित नहीं थी परन्तु नये उसकीते में यह रक्षम निश्चित कर दी गई है। इस्के रेख़रे का योननावस विकार किया जा सकता है, युरिवत कीप का निर्माय किया जा सकता है और पुनर्वात तथा प्रधार का कार्यक्रम कार्योग्वित किया जा सकता है। टूट-फूट के कोव में प्रति वर्ष जमा की जाने वाली पनराशि में इस् आधार पर वृद्धि कर दी गई है कि कल पुजी, मस्तोन, इजाद इत्यादि वहल के के ज्यम का मूल व्यय से और उपयोग में खाई नाने वाली सम्पत्ति के जीवन काल से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब तक इन्हीं दो आधारों पर टूट-फूट के कीप में योगदान निर्धारित किया जाता था। नये समकीते के अनुसार व्यय का मार बहाने का उदेश्य रेलवे की आव्यधिक पूँजी संग्रह करने से गैकता है। विकास कीप की स्वापना के समय यह वात मान ली गई है कि मविष्य में रेलवे का विकास कीय का व्यवस्थिक इंटरकीय से खीसेस मही रखा जा सकता है। देश के आर्थिक विकास में रेलवे को जिसका राष्ट्रीकरण किया जा जुका है एक महत्वपूर्ण और निश्चित योगदान देना है।

स्वतस्थाता विकास के प्रधात रेजने की नितीय विवति में निरस्तर सधार हुआ है। नास्तविक जाय जो कि १६४८-४६ में ४२°३४ करोड कार्य थी अद्यक्ष कर के बहुकर हर लाग करोड़ कावा हो गई है और शहपूटनार के वजह के बातमार १६६ ६ व करोहर कपया जानमान किया गया है। १६५ १.५० में सामाना ज्याय के प्रति ३३% र करोड क्या दिया गया था और १८वट-यह में प्रत्यान करोड स्पर्धों के दिये जाने का अनुमान किया समा है जब कि १९४८-४९ से केवल 4.3 अंगेर रुपये ही दिये गये थे। इसने पर भी रेलवे की अतिरिक्त आप जो कि १९४८-४६ में १९-६८ करोड़ रुपये थी १९५१-५२ में बहकर २८-३४ करोड रुपये श्रीर ११५८-५१ के बकट अनमान के अनमार २५१३५ करोड रुपये काली गर्द है। यह सारी रहता विकास कीय में लगा कर दी गर्द है जब कि 98 VE.VE में बेबल १० क्रोइ स्पये ही इस कीय में बता किये गये थे। रेलवे की वित्त रिधित में इस सुधार का कारण यह है कि (१) याशियों की संख्या में ह्यीर माल के यातायात में वृद्धि हुई है और (२) रेलवे के किराये तथा भाडे में भी शक्ति हुई है। देश के श्रीयोशिक विकास में दृद्धि शेने से और श्रापिक कारोबार -बहाने में रेलों हारा यातायात भी बढ़ा है। बास्तव में रेलें बढ़ते यातायात की साँग परी कर सकने में असमर्थ रही हैं, यातायात बढ़ने के साथ ही रेल का किराया भी बदा है। १६४६-४६ में रेलवे को वात्रियों से ८४ करोड़ क्यांगे और शहभ १-५२ में १०६ च्या करोड़ रुपयों की खाय हुई । शहभू क्ष्म के बत्र में लगाये हए श्रनमान के अनुसार यह आय १२४,७३ करोड़ द० होती। इसी प्रकार माल होने से आय जो कि १६४८-४६ में १०८-२६ करोड़ रुपये थी. १६५१-५२ में बतकर १५६ छ। करोड रुपये हो गई श्रीर १६५८ में जानसान है कि २५० छ। करोड रुपये हो लायती।

हैं है वावायात कम होने का वास्ताविक कारण १९५१-५२ और १९५५-५६ के दीच यह चा कि १९५८ में रेह के किरावे में और भारे में अर्राधिक वृद्धि हुई है। प्रद्र के तुरस्त प्रवादा ते को किरावे और भारे में इतनी नृद्धि नहीं हुई किरहा यावायात पर प्रतिकृत प्रभाव पत्रना परन्तु १९५६ में देत से किरात की स्वादी की भारे में वर्षीय वृद्धि हो नाने से यावियों और साल से होनेवाली आप कम हो तहे ।

	यात्रियों से होनेवाली ग्राय (करोड़ रुपयों में )	माल ढोने का ग्राय (करोड रुपयों में)
₹E¥5-¥€	₽K.00	35 208
<b>१६४६-५</b> ०	⊏६.५६	6 \$ 0 . \$ 0
<b>१६५०-५१</b>	<i>የወሚ</i> ያ	<b>१</b> ४३'०१
१९५१-५२	\$0€,£≅	<b>१</b> ५६*७६
<b>₹</b> E५२-५३	<b>₹</b> ००'₹⊏	<b>१</b> ४६*१२
<b>\$</b> E44-48	₹00'00	₹89.4⊏
<b>१</b> ६५४-५५	१ <b>०२</b> '६२	<b>१</b> ५⊏"६९
१९५५-५६	90009	<b>१</b> ⊏०°२⊏
1545-40	\$\$6.33	₹08.8#
१९५७-५८ (चंशोधित)	\$2°E+	848,00
१९५८-५१ (यजट)	१२४७३	२५०५०

पिछले तीन वर्षे में यानियों तथा माल के बातायात में श्रीयोगिक विकास के कारण बृद्धि होने से स्थिति में उन्नति हुई है।

रैलवे के किराये और भाडे की दर सम्बन्धी नीति—रेलां के किराये-श्रीर माड़े का उद्योग, कृष्, व्यापार श्रीर वाश्विच्य के विकास में श्रीर स्वयं रेखी की विचीय स्थिति को इह बनाने में बहुत महत्व है। यद माहा अधिक होगा तो उन्ने उत्पादन व्यय पर प्रभाव पढेगा श्रीर तत्पादन व्यय में वृद्धि होगी। इन्ने देश फे खीद्योगीकरण को प्रोत्साहन नहीं (प्रतेशा । इसके विपरीत यदि आहे की दर निश्चित करने में अटि वह गई है तो उससे उद्योगों के स्थाननिर्धारण पर श्लीर श्रीद्योगीकरण के दाचे पर बरा प्रभाव पडता है। रेल का किराया श्रीर भाका अधिक होने से यातायात की भोत्साहन नहीं मिलता है, यातायात रेलों के द्वारा न डोकर अन्य साधनों से होता है जिसमें रेलवे को लात यह चती है। यदि माड़ा कम है तो इसमें श्रीयोशिक तथा अधिक विकास में अवश्य सहायता भिलेगी, परन्त यदि इससे रेलवे की हानि पहॅचनी है और वह अपना व्यथ परा करने के पश्चात उचित लाभ नहीं उठा सकती है तो यह व्यादसायिक सिद्धान्तों के प्रतिकृत तथा अन्चित है। इस लिए रेल के निराये तथा माड़े की दर सम्बन्धी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे रेलने के दित में और उद्योग तथा कृषि के दितों में छन्तुलन स्थापित किया जा सके छौर जिससे देश में श्राप्त साधनों के छाचार पर देश का कृषि सथा ब्रीडोशिक विकास पूरी तीवता से किया जा सके, पंचवर्षीय योजना में

निर्घारित लच्य पूरे किये जा सर्के ग्रीर रेलवे को विचाय स्थिति पर्याप्त सुदृढ़ रखी जा सके।

. १६४८ से पहले मारत में रेलने के किराये तथा माड़े की दरें इसके. अनुकल नहीं भी और असको कहा आलोचना की गई है

(१) भारतीय रेलवे में किराये तथा भाड़े का दर निर्धारित करते समय दूरों का व्यान नहीं रखा गथा। इससे लम्बी यात्रा करने वालों को या काफी दूर छामान में को यालों को बहुत अधिक भाड़ा हेना पड़ता था। इससे माल की खपत के लिए बालार की स्थित तथा अपने कारयों के अनुकूल रहते हुए भी उद्योगों को कच्चे माल के सोतों से दूर स्थापित करने को मोत्याहन न मिला। उद्योगों को कच्चे माल के सोतों से दूर स्थापित करने को मोत्याहन न मिला। उद्योगों के लिए रोतों के माड़े की दर कुछ कम थी, छाथ ही विरोप स्टेशनों के सीच दियाय सी दी शई याँ परन्त इससे ज्यापार और द्वांगों की विशेष लाम नहीं हुआ।

(२) भारत से कच्चे माल को विदेशों को निर्यात और विदेशी माल के आवात को सरता करने के लिए रेलवे ने देश के किसी माग से मन्दरगाहों तक आपित सरवा होने से स्वाप्त को स्वर्धा मान सम रखा। मारत में विदेशी सरकार की इस मुध्यूण नीति से मारतीय उद्योग को खांत पहुँची और किसी मारतीय उद्योग को खांत पहुँची और किसी मारतीय उद्योग को खांत पहुँची और किसी मारतीय उद्योग को स्वाप्त में स्वाप्त में स्वीप्त मारतीय अधिक प्रोप्ताहन मिला।

(द) भारतीय रेलवे के कुछ भागों में किराये की दरे सीलों के झाधार पर निश्चित की गई और क्लाफ रेर की मधाली अपनाई गई स्थात् एक रेल द्वारा कम दूरी तक माल दोने पर प्रति मील शिक किराया स्वक किया गया। इसका उद्देश्य यह या कि माल कुछ दूर दोने के बाद दूबरी रेल के न द्वारा काथ पहिक लग्नी यात्राझों में उसी रेल का उपनाम करें। इसके परिखामस्वक्त ब्लाक-रेट मीलि के बचने के लिए सामान की आवश्यकता से अधिक दूर तक ले जाना पढ़ता था। इसके लग्नात बढ़ती थी और यात्रायात के साथनों पर भी अप्रीचत मार पढ़ता था।

(४) एक ही सामान के लिए विभिन्न रेलों की विभिन्न टरें थीं। इससे व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। इसके ऋतिरिक्त विभिन्न सामनों के माड़े की दुरों में भी काफी आतर था।

१६ भन में रेल के किराये तथा माढे की दो की कुछ बुटियाँ दूर कर दो गई। किराया प्रति मील की दर से निर्धारित किया गया, साथ दी अनाज, राल, आटा और बीन दरवादि की दरें निर्ध्यत कर दो गई। इसके खिए उर्वययम दूधरे समूद की रेलो—आसाम, ईस्ट इंडिया, बी० आईंट बी० और औठ टी० रेलवे— में दर निश्चित की गई और वत्परचार पहले बगूह की रेलों में । दोनो बनूहों में 'इस अगर का कारण यह था कि दूधरे बगूह की रेलों की दरें पहले समूह की रेलों की इसें पहले समूह की रेलों की अग्रेश पहले हो हो का भी आर्थ प्रदिश्चा पहले ही रेलों की दरें एक साथ बहुत ही जाती तो उनमें अग्रिक करिनाई होती है।

रेल के किराये तथा माड़े की दरों में इस प्रारम्भिक परिवर्तन के पूरे हो जाने के बाद ? अमेल १६५२ को कुछ और परिवर्तन किये गये। दूरी के आघार पर किराये की हर निर्धारित करने की नीति त्याग दी गई। शोध दरों का प्रमाणी-करख हुआ और इस्पात उपोग के लिय निरित्तत विद्योगिय दरों को लाम करके नई संज्ञीवित हरें लागू की गई के लिय निरित्तत विद्योग परों को लाम करके गई संज्ञीवित हरें लागू की गई के रेटैन्डर तरकर की दर से कम रखी गई। इस्ति की चीनों के यातायात को रिपायती दर्रे लास कर दी गई। कोयले के माड़े में ६० प्रतिदात की बूस कर दी गई शिव्यो की स्वादायत की रिपायती दर्रे लास कर दी गई। कोयले के माड़े में ६० प्रतिदात की बूस कर दी गई और यह कहा गया कि पहले की दर न्यय से बहुत कम यी। १६५५-५६ के बजट में भाई की दरों में अन्य परिवर्तन किये गये। अल्ल तथा लाद का मित जाड़ी माड़ा कम कर दिया गया तथा विभिन्न अधियों का यात्रियों के लिये किराया ६० मील से अधिक विद्योग का किराया बढ़ा दिया गया पर ३०१ से बहुत कम किराय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

इससे रेलवे को श्रमायरथक हानि उटानी पड़ी जब कि रेलों द्वारा कुल जितने सामान का यातायात होता है उकका ५० प्रतिशत कोयला होता है। यह ग्रमाय दिया गया कि कोयले के भावें की दर श्राधिक होने से रेलवे की लाम होगा हमसे रेलवे के दिलों की नवा होगी।

रेलावे भाड़ा पर जांच कमेटी—जो कमेटी जून ११५५ में नियुक्त की गई थी उनने १९५६ के आरम्भ में सरकार को अपनी रिपोर्ट दो। सरकार के विचाराधीन होने के कारण अमी तक वह कार्यामिव नहीं की गई है। कमेटी यह विश्वारित की है कि किया के डी देरे निम्मत्वत के को के उच्चतम के शो शक विचाराचार पर होनी चाहिये। इच विचार को कार्यामिव करने के तिये कमेटी इस निकर्ष पर पर्वेची कि सबसे सरल और संतीयद देश आधार रूप में एक दर निश्चित करना और अन्य दरें हसी पर के प्रतिश्वत करना और अन्य दरें हसी पर के प्रतिश्वत करना और अन्य दरें हसी पर के प्रतिश्वत देशि के आधार पर नियव करना होगा। इसके खित्र कोटी ने एक सामान्य दर नो कि मान दश्व होगा नियव किया है जिसे (Class 100 rate) ये १२० चर कहा नावमा। कमेटी ने यर्वमान चर्म ह को सबसे अधिक श्रीविश्वत करनाया (Norm) और अन्य चर्मा की स्वर्थ करना देशिय पर के यादि भी स्वर्थ करनाया (Norm) और अन्य चर्मा में स्वर्थ करने तथा नीने मान है। इसी प्रकार याद्वी मर माल की दरे

भी १०० के नये वर्ग के आधार पर प्रतिशत छोकों में व्यक्त किये गये हैं। प्रत्येक वर्ग कितने प्रतिशत होया व्यक्त कर दिया गया है। प्रत्येक वस्तु के लिये गाडो-भर माल के आधार पर दर्गोकरण किया जाना चाहिये और साय ही साय छोटी मात्राओं (smalls) का भी वर्गोकरण होना आवश्यक है। कमेटी ने छोटी मात्रा में माल की दरों में गाड़ी भर माल की दरों की अपेजा १५ से लगाकर ३६ प्रति-शत बढ़ि करने की अन्तर्भात दी है। "

क सेटी ने यह मल दिया था कि (i) जीमा कर रह कर दिये जाने जाहिये पर मये दरों के बनाते छमय इस बात को विजाराचीन रखना चाहिये, (ii) थोड़ी दूरी के लिये अतिरिक्त माड़ा बयुलना अपुचित समका जाना चाहिये, (ii) थाड़ी दूरी के लिये अतिरिक्त माड़ा बयुलनो अपुचित समका जाना चाहिये, (iii) थाट स्वस्त्रायी और स्थानान्तरण सम्बन्धी वम्त्री बन्दी कर दी जानी चाहिये और (iv) भाषा वसुनने की म्युनतम दूरी एस मील तक नहा दी जानी चाहिये और चाहे माल एक रेल अपया कहे रेली द्वारा ले जाया जाय एक ही बार उसकी लुकिस होनी चाहिये; (v) माल गांवयों हाया मेंने जाने के लिये न्यूनतम सजन २० लेर होना चाहिये; श्रीर (vi) ओ १ दे० १२ आ० प्रति याहो माल पर न्यूनतम समितित समितित की को जाती के अन्य कर हो जानी चाहिये।

कसेटी ने यह भी खिपारियां का है कि ३०० मील की दूरी की प्रथम सीद्वी को भाड़े की दर नियत करने के लिये चार भागा में बाट देना चाहिये; जैसे १ से २५ मील तक, २६ ते ७५ भील तक; ७६ ते १५० मील तक; और १५१ से ३०० मील तक। रपट रूप से उसने यह खिपारियां की है कि "कर्मचारियों की यह निश्चित नीति होनी चाहिये कि जहाँ तक सम्भव हो सके योजी मोड़ी दूरी के लिये रेल का प्रयोग न किया खाय बरन् श्रम्य परिवहन के सामनों का उसके स्थान प्रयोग बढ़े।"

इस बात की विचाराधीन रखते हुने कि (१) दरे लब्बी दूरी तक संजाने बाले माल पर मार स्वरूप न हो, (२) अनमें बीमा सम्बन्धां तबा अन्य सम्बन्धों में को बन्दाती की जाती है वांम्मालत हो; (३) आय और व्यव के बीच जो ३०० करोड़ रुपयों का व्यवधान है उनसे पूरा हो जाय। कमेटी ने निम्न दरों के लागू किये जाने की निर्णारण हो है र----

bय जारू	का सिपारश का ह:			
मील		प्रतिमील प्रतिमन पाइयो की इकाई में दरे		
₹	से २५ वक	<b>३</b> -६०		
२६	से ७५ तक	<b>१</b> ४०		
હદ્	से १५० तक	··· \$*?o		
१५१	से ३०० सक	\$"04		

पाइयो की हकाई से दरे

मील—	प्रविमील प्रविमन	
३०१ से ५०० तक	•••	o 531
५०१ से ८०० तक		0.120
<b>⊏०१</b> से १२०० तक		0.40
** * *		

करें। के विधारियें (1) रेलवे की मार्थ की ट्रॉ को सरल और सुनाम वेना देगी और इस प्रकार उनकी अनेकों जिटलावों और असंगतायें दूर हो जायेंगी; (11) उनसे रेलवे की आय में वृद्धि होगा जिस्की बहुत आवश्यकता है। (i11) रेलवे को इसमें आवश्यक सुविधा प्राप्त होगी और सहक द्वारा छोटी दूरी क परिवहन को प्रोत्ताहन मिलेगा। परन्तु उद्योगों की सरवारन लागत पर रेल के हिरायें का अस्वपिक और अनुचिव भार पढ़ेगा। वर्तमान मूद्रा स्कीति की दशा में उससे हानि होगी। बाहर भेजे जाने साल में सरवार्थ महिष्य मार देगी कि उस सरवार के सरवार के असे भारतीय माल की बही हुई वह भारतीय माल की विवेशी विनियय की कि उसके और भी अधिक बट जाने का मार होगा।

जनवरी १६४६ में यात्रियों के लिए भारतीय रेलों में प्रति मील किराये की समान हर निश्चित की गर्क। परन्तु कुछ रेलों में किराये की दर कम थी। उसे भी ग्रन्थ रेलों की किराये की हर के समान ही कर दिया गया। १६५१ में रेल का किराया २० से ४५ प्रतिकात तक वटा दिया गया।

१९५५.५६ के बजट में किराये की दरें निम्न प्रकार निश्चित की गई हैं

and one with the week

	नाइ भाग नाथ नाय नाना		
~	११५० माल	१५१-३०० मील	३०१ मील श्रीर इससे श्रधिक
एयर कन्डीशन अंखी	₹¥	źĸ	३२
प्रथम श्रेणी	<b>%</b> =	१६	₹%.
द्वितीय श्रेणी (मेल/एक्छप्रेस)	3.5	\$02	٤3
,, ,, (साधारग्)	€3	3	=3
त्रितीय श्रेषी (मेल/एवसप्रेस	) ξ <sup>*</sup>	Ę	ધ્
,, " (साधारण)	યુર્	4	Υ <sup>2</sup> .

रेलों का पुनः सगठन करने से रेल के किरावे तथा आहे में जो तुषार किया जा सका उससे (१) रेल का किराया निर्मारित करने का खाचार सरल हो गया, (२) रेल की दरों में जो खन्यनस्था फैली हुई यो वह दूर हो गई, खीर (३) रेलये का विकास कर तकने के लिए आधिक धन भी प्राप्त हुआ। रेल के किराये के सम्बन्ध में यह कहा बाता है कि सुधार करने से किराये और माड़े में कुछ वृक्षि कर दी गई है। इससे उद्योगों का उत्पादन चग्य बहा है और यात्रियों तथा सामान के यात्रायात से प्राप्त होनेवालों आय पटी है।

रेलों की कार्य प्रशाकों से दोप—फेडरेशन आफ इन्हियन चेम्बर्ध आफ कामसे ऐड इन्हर्ट्य ने अपने स्मारक पत्र में भारतीय रेलने कार्य प्रशाकी के अने दोशों और वृद्धियों की और प्यान आफ़र कराया था, जैसे गाड़ी के डिक्मों का न मिलना, बहुत दिनों तक माल के धतायान में प्रतिस्थ का लगाना, यांडे सामन के यातायात की दुविश में अभान, माल ने डिक्मों की माँग करने और मान्त करने में प्रमय का लग्ना, ब्रह्म के इन्हें में स्मान के यातायात की दुविश में अभान, कहा के डिक्मों की माँग करने और मान्त करने में प्रमय का लग्ना व्यवचान, कुछ जंकशनों में लाइनों का अमान, बड़ी और छोटो लाइनों में परसर अहरता बदली की दुविभाषों का अमान, कुछ राल्तों में लाइनों का अमान, मार्ग में माल का चोरी होगा और को बताय पा चोरी हुए माल की द्वानि निश्चित करने में अधिक देर लगना, और कमैचारियों को कार्यव्यवता में शामान्यतः अमान स्ताह । इस सम्मान में मुख्य समस्या तो यह है कि छिप और उचोगों की आयश्यकता के अतुवार रेलने की द्विभा कम है। इस देश में आर्थिक व्यवस्था विकाशिश्व है, यहाँ छांप एए उचोगों के उत्पादन में निरन्तर इसि हो रही है और वर्गनान यागायात द्विवार्य पूर्णकरेख अपयान हैं। फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में मुक्त प्रताम वागायात द्विवार्य पूर्णकरेख अपर्यान हैं। फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में मिल प्रताम वागायात द्विवार्य पूर्णकरेख अपर्यान हैं। फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में मिल प्रताम वागायात द्विवार्य पूर्णकरेख अपर्यान हैं। फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में मिल प्रताम वागायात द्विवार्य पूर्णकरेख अपर्यान हैं। फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में मिल प्रताम वागायात द्विवार्य पूर्णकरेख अपर्यान हैं। फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में मिल प्रताम वागायात द्विवार्य प्रताम के इस सम्बन्ध में मिल प्रताम वागायात द्विवार्य में क्राया कर स्वार्य में स्वर्ध में कार्य मान्य स्वर्ध में स्वर्ध में स्वर्ध कर स्वर्ध में स्वर्ध में

(१) रेल के के विस्तार और खुनार के लिए ४०० करोड़ रुपयों का प्रथम एंचवर्धीय योजना में नियत करना अपर्यान्त था और कम से कम १०० करोड़ स्वयं प्रति वर्ष और अधिक नियत करना चाहिये था। इस प्रकार द्वितीय योजना के अन्तर्भात १५८० करोड़ रुपये व्यय किये जाने को गौत रेलाये बोर्ड ने की थी मिसे योजना आयोग ने घटा कर ११२५ करोड़ करये कर दिया है। यह धम भारतीय रेलावे की आवश्यकता के अन्तर्भार व्ययंग्न को होगा।

(२) प्रथम योजना में रेखने के वर्तमान वामान की मरमात पर ख्राविक जोर दिया गया था जो यत बीध वर्षों से यदके भी नहीं गये। यद्यपि यह बहुत ख्रावर्यक है, किर भो अब ख्राविक ब्यान रेखने के विस्तार पर दिया जाना चाहिये। विस्तार हतना होना चाहिये कि म केवल यातायात की ख्रावर्यकतार्ये ही पूर्ण हो वर्के, वरन् मनिष्य में कही हुई ख्रावर्यकता की भी पूरा कर लेने की पर्योत्त शक्ति हो। यद्यपि द्वितीय योजना में ख्राविक जार विस्तार पर दिया गया है किर भी यह ख्रावीच है।

- (३) रेलवे के कार्य करने की जमता में वृद्धि होनी चाहिए। देश के भीरोगीकरण में गोत्साहम हेने के लिये बावश्यक है कि रेज हारा यानायात की मिनिया सब्दी हो । इसके लिए यह ज्यावश्यक है कि बेलने का चाल ब्यय कम हो । भारतीय रेलवे की वल किरावे माहे से प्राप्त ग्राय १६५८ को २१३ करोड क्यमों से बद्धकर ४०७ ४८ वरोड़ रूपये १६५८-५६ के ब्लार में अनुमान की गई है। कल ह्यय १७३ करोड से बद्रकर २६८-३५ करोड हाये हो गया है। इससे यह पता लगता है कि बही हुई ज्ञाय का जाधिकाश ब्यय की बढ़ि में प्रयक्त हुना है और यह सम्भव है कि किराया और माहा घटाया जा सके।
- . (४) माल के यातायात में सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसे म्रास्थायी जनायों से बाय लेना चाहिए जैसे महामा घाट. जागरा श्रीर सोबरमती जीर ग्रान्य स्थानों पर मधीनों हारा माल को स्थानान्तरित करना, कन्वेयर प्रणालो कर प्रयोग करना और मगलस्थाय वाल्टेयर, मामलपुर आदि जक्शनों पर माल की माहियों की खरला-कदली की गति में तंत्रता लाना क्योंकि इन स्थानो पर बढी भीड रहसी है। जिन रास्तों पर खाइनों के ग्रामाय के कारख किताई हो जाती है वर्गश्राधिक लाइनों का खेलना और विशेष प्रकार के साल के किसी की एंख्या बढाना ।
- (y) ब्यापारियों को मार्ग में माल के चोरी हो जाने श्रीर खो जाने श्रीर इट्ट देश में हानि मिलने के कारण बहुत कठिनाई उठाना पदती है। रेलवे व्यवस्था को इस प्रकार की सभी हुई चोरियों के रोकने छोर रेलने कर्मचारियों की इ.साक्षानी क्यीर चरित्रई,नता के कारण गांकी में साल के जाने की रोक थाम के लिये विशेष प्रयक्षशील होना श्रावश्यक है। हानि जल्दी नकाने के उपायों की भी सीचना आवश्यक होगा। विभाग का विकेन्द्रीय करण करना, बुल माल के खो जाने पर डानि तरन्त जुदाना, इस दशा पर कि यदि एक वर्ष के भीतर डी भीतर माल मिल गया तो पाया हुआ हुजा रेखवे को वापिस दे देवें। ऐसी क्रीमड पडवाइसरी कमेटी की स्थापाना करना विसके सदस्य उन उद्योगी श्रीर क्यापारी के प्रतिनिध हो को क्रीस्ट विभाग के कर्यचारी से सम्बन्धत है आदि सद देसे उपाय है जिनके प्रयोग में लाने से रेलवे के टांव सिट सकते हैं।

रेल वे के कर्मचारी इस बात का प्रयक्ष कर रहे हैं कि रेल के कार्य प्रशाली की तमता बढ़ जाय और सविषायें भी बढ़ जाँय, माल की सधी चोरियों और उनके खोने पर रोक याम करने के लिए रेखवे करपशन इनक्वारी कमेंटी की नियक्ति की गई है जो शीम ही अपनी रिपोर्ट सरकार के समज्ज उपस्थित करने बाली है। रेल वे के चाल स्थय पर शेक दाम में सहायता करने के लिये और रेलने का विकास करने के लिए, विकास में वैज्ञानिक दंग का प्रयोग करने के लिये तथा बड़ो-नदी योजनाओं को कार्यानिवत करने के लिये, जिन्हें पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलने को पूर्ण करना है, रेलने बोर्ड की सदस्य संख्या चार के स्थान पर पांच कर टी गई है।

योजना के धानतात-अयम पंचवर्णीय योजना में ४०० करोड रुपये के क्यम कर परनाव रेलवे के जये सामान के अब करने तथा परान की मरस्मत के के लिये किया गया था। वास्तव में यह आशा की जाती है कि प्रथम योजना के ममान होने नक लगभग ४३२ करोड उपया व्यय हो जायगा । शन्त्रयामानि सीर च्यीर सर्वात सर्वत्र पर व्यय प्रस्तावित धन से बहुत अधिक हो गया है । गन्त्रया-मादि पर ऋधिक व्यथ होने के कारण यात्रा और डलाई १६५३-५४ और १६५४ ५५ फें बीच साढे आड प्रतिशत बड गई और आशा को जातो है कि योजना के क्रांन्तम वर्ष में सी प्रतिशत बट जायेगी। प्रथम योजना के जारम्भ के समय रेलंदे के पास 520 हरवन, १६२२५ यात्रियों के डिब्बे और २२२४४१ माल के बिब्बे थे। इसमें से २११२ इन्सन, ७०११ बाजियों के दिक्वे और ३२५८५ मास्र के दिन्ने प्राने थे। प्रथम योजना में १०३८ इस्जनी और ५६७४ यात्रियों के डिन्ने श्रीर ४६१४३ माल के जिल्हा के लग करने का प्रवन्ध किया गया था। वास्तव में उपर्यक्त सख्या से कछ श्रधिक इन्जन श्रीर माल के दिख्वे श्रीर कछ कम यात्रियों फें डिब्बे प्रथम योजना के जानार्शन कय किए जा सकेंगे। इतनी अधिक प्रशासन स्रोर नये सामान के क्रय किए जाने के पश्चात भी भारतीय रेखवे का सामान बहुत पुराना श्रीर पुराने ढंग का है। दितीय पंचवर्णीय योजना के आरम्भ में ६२६२ इन्जन. २३७७६ यात्रियो के डिब्बे श्रीर २६६०४६ माल के डिब्बे काम में आते हुये होंगे जिनमें से २८१३ इन्जन और ६३०५ यात्रियों के दिव्वे ग्रीर ४६५६८ माल के डिक्ने बहत पुराने थिसे हुये होंगे श्रीर उनके स्थान पर नये लाने आवश्यक होंगे। इससे यह पता लगता है कि रेलवे के विस्तार की इसनी आवश्यकता होते हये भी उनकी सरम्मत श्रीर उनके स्थान पर नये सामान लाने की जरूरत बहुत बड़ी है।

का जनाव बहुत भाग है।

दितीय पोजन के अनुवार्त ११२५ करोड़ क्यम भारतीय रेलचे पर व्यव
किया जायगा जिसमें से ७५० करोड़ सामान्य आय में से, २२५ करोड़ रेलचे के
अवस्या कोय से, १५० करोड़ रेलचे की आव से आस होगा। रेलवे बोर्ड के
१४८० करोड़ प्रायं के ब्या किये जाने के प्रस्ताव के स्थान पर ११२५ कर का
व्यव किया आया।

दितीय योजना में १६०७ मील के रंकाय के हुमने किये जाने का, २६५

ह्योटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर देने का, जगमम प्रश्र मील तक विजली पहुँचाने, १२६२ भील तक पीडच्वाल्स सुविधा देने का, प्रश्र मील नई लाइन विद्याने, २००० भीत लाइन की मरम्मत करवाने और २२५८ इन्मनी को मन्द करने तथा ११३६५ पाणियों के डिन्मी और १०७,२४७ माल के डिन्मों को स्मा करने का अध्योजन किया गया है।

मारतीय रेलवे १२ करोड़ टन माल के ढोमे के स्थान पर १६५५-५६ में ११ करोड़ ५० लाख टन माल ढोयेगी और इस मकार ५० लाख टन माल के ढाये जाने की कमी रह जायेगी। यदि हतीय योजना के अन्त तक जो ६ करोड़ २ लाख टन माल के ढोये जाने की खाबरणकना यह जायेगी उसका विचार टिंग जान तो इम कह एकते हैं कि १६६०-६१ तक १८ करोड़ ८ लाख टन फे ढोये जाने की प्रावश्यक्त होगी। ऐसा मण है कि जितना चन रेलवे के विकास के लिये नियत कर दिया गया है उसके प्रयोग से रेलवे इतना माल न डो सके और जिन नुरिधाओं के प्रदान करने का हरादा किया गया है वे आदश्यकता से १०% गननपानादि के सम्बन्ध में और ५% अपनी स्राव्ध के सम्बन्ध में कम कर

दितीय पचवर्षीय योजना के खाधार पर योजना खायोग के मतानुसार (मई १६५८) "जी कार्यक्रम ११२५ करोड़ करवी के क्यब का बनाया गया या उत्तम छव मुक्ती में बुद्ध हो जाने के कारण १०० करोड़ करवी के छीर छिपक क्यर होने का छनुमान किया गया है। इस समय ११२५ करोड़ करवी की छान हों करती। इसलिये रेलवे की योजना के अन्तर्गत कुछ निकास योजनाओं को स्पीगत करना पड़ेगा। विदेशी विनिमय की किताहर्यों भी इसला योजनाओं को स्पीगत करना पड़ेगा। विदेशी विनिमय की किताहर्यों भी इसला एक कारण होगी। जिन विकास योजनाओं को स्पीगत करना पड़ेगा। विदेशी विनिमय की किताहर्यों भी इसला एक कारण होगी। जिन विकास योजनाओं के स्पिगत करने का उरादा है वे (१) तन्वाराम क्लियुम केत्र तथा कलकत्ते के अन्तर्गत विवालदा होत्र में विजली पहुँचाने की योजना; (२) मोदर गंज कोच फैट्टी (३); इन्द्रीयरल कोच फैट्टी के प्रसाद विभाग तथा (४) गुना श्रीर उस्कीन के बीच नई रेल के लाइन विद्वान से योजनाई हैं "

"अपने स्थेय को पूरा कर लेने के प्रश्न का जहाँ तक सम्बन्ध है यह आशा की जाती है कि १६६०-६२ तक रेलवे ४२० लाल टन माल टोकर अधिरिक्त आय प्राप्त कर सम्मी। पर न्या यह आय पर्याप्त होगो। निरिन्त रूप से कहा नहीं जा करता। निरेशी निनिमध तथा अस्य कठिनाइयों के कारण दिक्स योजनाओं के कार्यान्तित करने में दील देने के कारण दुलाई की मात्रा योजना के अधिता वर्ष तक आरम्भ में किये गये अनुमान से जो कि ११० लाख टन या कम हो जायमी कर हो सकता है कि ४२० लाख दन से ग्राधिक हो। कछ भी हो योजना

में की गई रेल दारा माल दोने की माता के श्रनमान में कल परिवर्तन तो ज्यापत ही होगा । जहाँ तक वाजियों के दोने के ध्येय में सम्बन्ध है-अपर्धत 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की बढ़ि-वह सम्मवतः परी हो जायगी । १६५५-५६ की अपेक्षा

१६५६-५७ में रेल के वाजियों में प्रतिशत बढ़ि ६% हुई थी। शुरार यही रही तो देल में भीर की समस्ता और भी कविक खाव से जायगी।"

हिलीय को बना में मारलीय रेखने की माल दोने श्रीर वर्षात्रमें के बाते-जाने की शक्ति में नहि की हरायरथा की गर्द है। परस्त नहि देश की बानवरतस्त्रक में बहुत क्रम सरमय हो सकेती। देवल सरकार की ही नहीं बहुत जनमा की था

श्रविक मात्रा में यातायात की मधिया की स्थावत्रयकता पहेंगी । प्रथम योजना ने भी जनता को यातायात की मुविधा में कभी का अनुभव हुआ था। दिलीय योजना में तो स्थिति और भी खराब होता । रेलवे के सरबन्ध में यही सर्व प्रधान ग्रालोचना है। विदेशी विनिमय की कठिनाइयो तथा मल्यों में वहि होने पर भी योजना में रेल दे के विस्तार के प्रति ध्यान आधिक रखना चाहिये था और न्या

के लिये प्राधिक धन नियम करना चाहिये था।

#### श्राध्याय ३५

## सडक यातायात

सारत में सदकों का बहुत द्यागाय है। १९०० में सहकों की लग्याई कुल १,५६,००० मील थी द्योर १९५२ में २,५६,००० मील थी। प्रथम योजना के अन्त तक कुल एकको की लग्याई बहुकर ११६,००० मील हो गई जिएमें से १२१,००० मील पक्की एकक थी। इनमें से केवल है भाग पक्की उन्हों हैं और करवा। एक ऐसे देश में जिसका चेवकल १,९२६,००० वर्गमील है, जिसकी जानसदा लगामग १५ करोड ७० लाल है और जिसके उच्चोग तथा कृषि का काफी विकास हो चुका है २९५,००० मील सक्की बहुत कम है। भारत में प्रति वर्गमील में बहुत हो कम नक्कों है, ज्याय देशा की नुलाग में यह शियति अप्रयन्त योजनीय है। भारत के प्रति वर्गमील चेवकल में सक्की की लागाई ०१२ है कब कि इन्गलैएड में २०, वेलाजयम में २०, काल में २०४ झोर स्थारीका में २१ है।

इसमें कछ सन्देह नहीं कि देश के व्याधिक विकास में सबकों का विशेष महत्य है। सबकें होते से ही प्रामों से कच्चा माल श्रीर कृषि उत्पादन कारणाती. करवी और नगरों तक पहेंचाया जाता है और बन्दरगाही तथा कारखानी से माल ग्रामी तक भेजा जाता है। देश के विभिन्न भागों के व्यक्तियों के लिए सहके यादायात की सविधा प्रदान करती है। सबकों की सविधा से ही व्यक्ति एक दसरे से सम्पन्ने स्थापित कर सकते हैं । बर्शमान काल में परस्पर सम्पन्ने स्थापित करने के जिए यातायात के इतगामी साधनों की ओर खब्की सबकों की ऋत्यन्त आय-रएकता है। रेलों तथा विमाना की सहायता से देश के बढ़े-वड़े नगरों और व्यापारी केन्द्रों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है परनत देश के दर-दर के स्थानों तक पहेंचने के लिए और उनका लाभ उठा सकते के लिए श्रन्छी संस्कों का होना अत्यन्त ज्ञावस्यक है। युद्ध के समय यदि सटकें अन्छी हैं तो सेना को शीध एक स्थान से दसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है, युद्ध-सामग्री ग्रावश्यक स्थानी तक पहेचाई जा सकती है और इस प्रकार देश की शत्र के आक्रमण से रत्ता की जा सकती है। वास्तव में मारत की कुछ प्राचीन बड़ी सहकें इसी उद्देश्य से बनाई गई थीं। यदि देश में खब्खी सहकी का बाल विका हो तो उठका शांतिकाल में तथा युद्ध के समय हर स्थिति में विशेष महत्व होता है।

श्रतीत में दिल्ली से कलकता, कलकचे से महास, महास से बम्बई श्रीर बम्बई से दिल्ली को मिलाने वाली चार वड़ी सड़कों के चारों श्रीर छोटी बड़ी सड़कों का जाल फैला हुआ था। इन चार बड़ी सड़कों को बारहों मार कार्य में नहीं लाया जा सकता है। पुल न होने के कारण और टूट-फूट तथा सामान्यतया रिपित खराब होने से नृत सड़कों का बराबत में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन बड़ी सड़कों को देश के सामों से मिलाने नाली प्रदेशीय सड़की तथा अन्य छोटी-छोटी सड़कों की रिपित और भी खराब है।

देश की छाज उनसे नहीं आवश्यकता यह है कि उनके बहाई आयें। राष्ट्रीय उनके हैं वसंगान समय की माँति केवल पूर्व से पश्चिम तक के जेज़ में ही न फैलें बर्स इमका प्रशार उत्तर से दिख्या उक मी किया जाय। इस्के साथ ही मन फैलें बर्स इमका प्रशार उत्तर से दिख्या उक मी किया जाय। इस्के साथ ही मन नकतों को छीर प्रदेशीय तथा अग्य छोटी उनकों को समी श्रुद्ध हमीं में कार्स में लाने योग्य बनाने की आवश्यकता है। मोटर याताथात के लिए मी कुछ उनकीं का शान आवश्यक है। इसके लिए उनकों के मोड मुगम होने लाहिएँ, कहाँ त वनक निकाली जाय वह भूमि पक्की होनी चाहिए और वनकों को सतह तथा झालर या छिपट के प्रयोग से पक्का बनाना चाहिए। इस वन्कों की ततह को विकता होना खाहिये। इसके साथ हो जैलगाड़ियों तथा शासपात के अग्य अपने के लिए भी पीडी उनकों सोनी चाहियों जो मोटर की वनक को माँति अधिक अथवधील तो न ही परन्तु ऐसी हो जिनकों वर्ष भर प्रयोग में लाया जा चकता है। यह बहुन आवश्यक है कि उन्हों के निर्माय की मुसम्बद्ध योजना निर्माय की लाय जिसमें मन्नी राष्ट्रीय उनकों, प्रदेशीय उनकों और प्रामें हलाई की पिनलों नाती छोटी-छोटी उनकों की विशेष महत्व दिया नाय।

 ही एक्क कुटनेवाले, साप से चलनेवाले इक्कनों स्था डिजिल इक्कनों का भी भारत में उत्पादन द्यारम्भ हो गया है परन्तु किर भी एक्काल्ट के लिए विदेशों पर ही निमेर दरना पडता है। आखा है कि पेट्रोल खोधशालाओं का निर्माण पूरा हो वाने पर देश की व्यावरण्डता हुए के दिले के लिए एक्काल्ट मात हो जावगा; (द) देश में चित्र का क्रमाव है। नगर पालिकाओं और जिला बोडों की देल-रेल में जो एक्कें हैं वह वित्त के क्रमाव के कारण अच्छी दशा में नहीं रह पातीं। दाल्य वरकारों के पाल विकाल के लिए कोच है परन्तु उनका उपयोग सक्कों के निर्माण में कम और क्रम्य क्रमाव के लिए कोच है परन्तु उनका उपयोग सक्कों के निर्माण में कम और क्रम्य व्यावर्थ है।

सङ्क कोय—चयक विकास समिति (१६२७) की विकारिश पर १६२६ में सबस विकास कोय स्थापित किया गया और प्रति शैलन पेट्रोल पर कर ४ आ ने में बढ़ाकर ६ आ ने कर दिया गया जिसमें से प्रति शैलन वे ह्याना सक्क दिकार कीय में बढ़ाकर हु आ ने कर दिया गया जिसमें से प्रति शैलन वो ह्याना सक्क दिकार कीय में बमा किया गया। बार में पहेल पर क्रातिक कर समास्त सक्क विकास कोय में आ में की काइ ढाई आना कमा किया गया। परन्तु हुमीन्यवश सक्क किया में को प्रनि का उपवित उपयोग नहीं किया गया है। उक्क दिकार कीय स्थापित हो जाने के बाद राज्य सक्कारों ने अन्तर-प्रवय वया अन्तर-जिला सक्कों के विकास में स्वयं अपने बजट से क्या कम कर दिया। इसके साथ ही प्रामों को मिलाने वाली छोटी छोटी सक्कों को अपने भाग्य पर छोट दिया गया। इस मासर सक्क विकास कोय निर्माण का उद्देश्य हो स्थापी । सक्कों का विकास करने के लिए उपलब्ध साथनों में अपनी छोर से सहायता देने को अपेसा राज्य सरकारों ने अपने छाय में करीती कर दी।

भारत सरकार ने उटक विकास कीय के चन को व्यय करते में कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये। सरकार ने यह व्यवस्था की कि (१) इस कोय का धन सहकों के निर्माण तथा सुधार में क्या किया लाय परन्त इस कोय का वर्षमान राज्य के मिनाण तथा सुधार में क्या किया लाय परन्त इस कोय का वर्षमान राज्य के मोगरान का कम से कम न्य प्रतिवास को दे राज्य के योगरान का कम से कम न्य प्रतिवास कोटी खोटी सहकों में क्या किया जाय और उन सहकों पर रूप मितास के सिर्माण के प्रतिवास कोटी खोटी सहकों में क्या किया जाय और उन सहकों पर रूप मितास के अधिक व्यय न किया जाय ओ रेल मार्ग को अतियोगी हैं। यह स्वय मितास के सिर्माण के स्वय की स्वय की हिमा के स्वय के स्वय की सिर्माण के स्वय की योजनाओं को स्विकृति अद्भान की जा चुकी यी और १७ करोड़ क्या व्य किया जा खुकी या। १९५१-५५ से दे स्वय कर २० करोड़ क्या व्यय किया जा खुकी था। १९६१-५५ से देवस्वर १९५% तक २७ करोड़ क्या वे व्यय की

योजनाक्षों को स्वीकृति दी जा चुकी थी और मार्च १९५५, तक लगमग १२ करोड़ रुपया उनके कार्योन्वित करने में ब्यय किया जा चुका था।

सरकार श्रवती वर्तमान श्राय में से सहका के निर्माण में पर्याम व्यय नहीं कर सकती है साथ ही इस कार्य के लिए सहकी का उपयोग करने याली पर स्माता गरे को से भी वर्याप्त जाय नहीं होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि महाको के जिस्सीया के लिए भागा लिया जाय । यह सीचना बिल्कल निर्माध है कि सकतों पर करण किये जाने वाले रुपयों से प्रत्यस रूप में ऐसी शाय नहीं होती है जिससे इस कार्य के लिए उपलब्ध अवा का ब्याज चकाया जा सके इसलिए यह व्यय अनत्यादक है और इसको नहीं करना चाहिए। यह संभव है कि सहकों के बिकास से प्रत्यक्त रूप में कोई आय न हो परन्त इससे तिरसन्देह देश की व्याधिक सम्बद्ध बदली है और साथ ही जनता की कर देने की शक्ति में बढ़ि होती है। भारतीय सबक एवम यातायात संघ ने कछ वर्ष पहले एक जॉन्स की जिसमें पता चला कि एक विशेष चेत्र में सहक का विकास करने से १२ लाख दपये का वार्षिक लाम हन्ना जब कि सहक निर्माण में तथा उसकी देखभाल में केवल ४३ लाल क्यया वार्षिक व्यय किया गया । इससे स्पन्ट है कि सडको पर व्यय किये गये प्रति १०० दण्यों पर जनता को २७७ दण्ये का लाभ होना है। सहकों के विकास से जनता समहिशालो बनती है, सरकार की आय में वृद्धि होती है. इस्रिय अप्रया लेकर सहको पर निर्माण करने में किसी प्रकार की आपन नहीं होनी चाहिए। नागपर योजना-१६४३ में विभिन्न राज्यों के मख्य इक्षीनियरों की

नागपुर प्रोजना—१६५६ में विभिन्न राज्यों के गुरुष इक्कीनियरों की नागपुर में एक बैठक हुई श्रीर देश की व्युत्तम श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में राजते हुए एक एकक निर्माण-वीजना निर्माण की गई। इस योजना का दिशेष महत्त्व है वयीकि इसके पश्चात भारत में सकते के निर्माण की समी पोकनाश्रों पर इसका प्रभाग पवा है। नागपुर योजना में सकते के स्वर्म है। हिंग की निर्माण किया है। नागपुर योजना में सकते अर्थ है। हिंग की निर्माण की एक है। राष्ट्रों पान में स्वर्म का पार श्रेणियों में विभक्त कीरी एक ग्रेण की सकते हैं। योजना में इन चार प्रकार की सकते की रूप कर वर्ग के प्रमाद प्रकार की सकते का रे॰ वर्ग के प्रमाद प्रमाद की सकते का रे॰ वर्ग के प्रमाद प्रमाद विभाग की स्वर्म का रे॰ वर्ग के प्रमाद प्रमाद प्रकार की सकते की स्वर्म का एक प्रमाद प्रमाद प्रकार की सकते की स्वर्म कर वर्ग के प्रमाद प्रमाद प्रमाद प्रकार मोल सकते और अर्थ कर की सकते हैं। इसके साथ ही योजना में बर्दभान सकते में सुप्तर करने का मी सुक्त दिया गया। नागपुर योजना का उद्देश्य पर पा कि विकर्षित करि के का कीई भी प्राम सुक्य सहक से ५ मील से श्रीषक दूर न वर्ष श्रीर कोई

मी गाँव चाहे कहीं हो सहक से २० मील से अधिक दूर न पहे। इस योजना के अनुसार युद्ध पूर्व के मुह्यों में ५० प्रतिसत दृद्धि के आभार पर निर्माय-कार्य में २७२ करोड़ करवा लगेगा निसमें से ६६.५ करोड़ करवा राष्ट्रीय सहकों पर और २०५ करोड़ करवा अग्य सहकों पर न्यार किया नायगा। यदि मूल्य सुद पूर्व के स्तर से २०० प्रतिशत बढ़े मान लिये नार्यों निसमें क्या के युद्धा निसमें निसम के मूल्य के अधिक निकट ज्ञा परे तो, जैसा कि योजना-आयोग ने यताया है, नागपुर योजना के कार्यों न्वित करने में कुल ७४४ करोड़ रुपया स्वय होगा निसमें से १३६ करोड़ रुपया स्वय होगा निसमें से १३६ करोड़ रुपया स्वय होया स्वयं सहस्रों के लिए और ६११ करोड़ रुपया स्वयं स्वयं स्वयं विद्या नायगा।

रेल सारी से सन्यन्य-मारत में सहकें अपयांत होने और सहकों ही दिवाद दोग पूर्य होते हुए भी १६६० के आवपास सहका पान कि सार को को गहरी मांतमोफिता का समम करना बना। निजी वस सिंदों हो हो हो ते हिए ती १६६० के आवपास सह सिंदों हो और रेल को गहरी मांतमोफिता का समम करना बना। निजी वस सिंदों हो और रेल के यो हो के सार सिंदों हो मुरियाननक समझा गया। मोटर यावायांत माया और सुगमता से हो जावा है हस्ते रेल की गहरी हान उटानी पड़ी। अनेक रेलने जीव सिंदों ने रेलने तथा सम्य पारत की मित्रों में सुगमता की मित्रों में सुगमता की मित्रों में रेलने क्या सम्य पात की मित्रों में सार पित्रों में स्वा के सार पित्रों में सार पित्रों में रेल के सार पित्रों में रेल में रिप्राय में रेल में रिप्राय के स्व में सार की मित्रों में रेल में रिप्राय देनी ग्राप्त की मित्रों में स्व को सहस्य की स्व की स्व में रेल में रिप्राय देनी ग्राप्त कर हो, कुछ विशेष समय के लिये टिकट दिये, अच्छी विश्व और कम कियो के स्व में स्व कियो स्व क्या हो। पर सार सिंदों में सिंदों सिंदों के स्व में सिंदों में सिंदों सिंदों सिंदों सिंदों सिंदों सिंदों सिंदों सिंदों सिंदों की स्व कियो सिंदों की सिंदों सिंदों

रेल दे के हितों की रचा करने के लिए सरकार ने झनेक उपायों का आश्रम लिया और १६६६ में मोटर गाड़ी कानून लागू किया गया जितमें यह न्यवस्था की गई के लिए लाइतेन्स लिया आय! कामून में बखें के लिए लाइतेन्स लिया आय! कामून में बखें के स्थान तथा झपिक यात्री ने हैंडिने और वसी की चाल हस्यादि पर नियंत्रण की खतें माननी झनिवार्य कर दीया है। बखों का बीमा झावर्यक कर दिया गया। इस कामून से यावियों के हितों की रच्चा के साम बियदस्था के सीमा को रोकने का प्रमान करके रेलवे के हितों की रच्चा की भी पव्यवस्था की में। एवस चक्क प्रमान करके रेलवे के हितों की रच्चा की भी पव्यवस्था की में। एवस चक्क योजायात की रोकने का और १९५६ में इस मिलगीमता प्रचलित रही और १९५६ में इस मिलगीमता को रोकने के लिए एक जिदलीय संगठन का निर्माण करने की नीति अपनाधी गई। इस संगठन में भीटर मालिकों, राज्य सरकार और रेलवे की नीति अपनाधी गई। इस संगठन में भीटर मालिकों, राज्य सरकार और रेलवे

के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। परन्तु इत योजना को श्राशा के अनुक्त राफलता नहीं मिली। बाद में मारत सरकार ने सहक यातायात कार्पोरेशन कानून (१६४८) लागू किया जिसके स्थान पर १९५० में एक और व्यापक कानून लागू किया गया।

वर्तमान में रेल और सबक की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है न्यों कि (१) यावायात का अमाब है और वर्समान समय में रेल और मोटर यावायात को साथ साथ कार्य करके लाम उठावे का काफी अवसर है; (२) कुछ तो उरकार के प्रतिवन्त्रों के कारण और कुछ मोटरों के तथा उनके विभिन्न-कल-पूजों के मूल्य अधिक होने के कारण और कुछ मोटरों के तथा उनके विभिन्न-कल-पूजों के मूल्य अधिक होने के सबक यावायात का ब्यय बहु गया है; और (३) अनैक राज्यों में यावायात का ब्यय कह ने से रेलवे तथा रोडवेज में अधिक उचित समस्य स्थानित हो तथा है।

राज्य द्वारा धचालित सहक यातायात के च्रेन निश्चित है और मोटरें यानियों तथा सामान को उसी च्रेन के अन्दर लाती वे नाती हैं। इस यात पर महत्व दिया गया है कि यातायात हम प्रकार संचालित किया नाय जिससे रेल-सहक यातायात का सुरुग्ध्व निकास हो। यातायात इस प्रकार नियोगित हो कि यात्रियों तथा सामान को रेलने केन्द्रों तक पहुँचाया नाय नहीं से आगे का यातायात रेलने संमानित को रेलने केन्द्रों तक पहुँचाया नाय नहीं से आगे को दी नानियाली पुनिचार्ट बढ़ी है, अधिक भीक-भाइ पर नियंचया रखा गया है और गावियाँ अपन्धी दशा में रखी गई है।

यह योजना १६५६ में बनके में प्रारम्म की गई और १६५० से १६५० तक वाई वर्ष में यातायात के भागों की र्यख्य द से ५६५ तक बढ़ गई। आरम्म में २५० मीत तक यातायात की व्यवस्था थी। १६५० में यह व्यवस्था १५,०३६ मीत तक प्रता गई और १६५० से १६५० तक कमाशः कुत १,०५,०५० और १,८१८,२५० मीत के बीच यातायात किया गा। १ दण्डे बार से वर्षों में इस्ता में प्रति कीभी रही है परन्तु सभी हिएकोंथों से रोडवेन ने उसति की है। उत्तर प्रदेश में १८५० के में ११ सरकारी रोडवेन सर्विष व्याल हुई जो १६५५० ५५ में १३ यह यातायात व्यवस्था ६,००० मीत तक पीती हुई है। यह अनुमान लगाया गया है कि कुल १०,००० मीत के स्वेत में यातियों के यातायात का राष्ट्रीकरण करने में २,३०० वर्षा को आवस्य कता होगी। दितीय योजना के अन्तर्भात इस यातायात धुविश्य का विस्तार ६६६५ मीत हो जायमा और उपमें १६०० वर्षे को।।

बम्बई में राजकीय रोडवेज ने 🖒 से ६ पाई प्रति मोल किराया वत्त्

किया । इसमे पहले इस क्षेत्र में किराये की यही दर वसली गई थी. परन्त गजरात में भीजन मालिकों से जेलवे की प्रतियोगिता में किराया कम वमला था। बस्वई में प्रशांत किराया क्या नहीं किया गया है परन्त रोडवेज की मांत्रस में निस्सरदेड काफी संघार हुआ है और जनता की राष्ट्राकरण में पहले की अपेका अधिक र्मायधार्षे प्रदान की गई हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है रोडवेज का श्चपर तथा लोजार बलास का विराया अवटवर १६५२ में अमशः ६ पाई ग्रीर ७३ पाई से बहाकर १०३ पाई और द्वाराई प्रति माल कर दिया गया। किराये में वृद्धि करने का उद्देश्य मोटर इत्यादि के कल-पूजी तथा श्रन्य सामानों की बढी मुल्यः को पूर्ण करना था। परन्तु चेंकि केन्द्रीय कारखाने स्थापित कर देने से मरम्स इत्यादि मे पहले की श्रिपेला कम न्यय करना पड़ता है उसलिए १९५३ मे कराये में कभी बर ही गई। अब किराये की दर अवर क्लास के लिए १०2 पार्ट प्रति मीता से घटाकर ६ वार्ट धान कील कर टी गई और लोगर पलास के लिए किराये का दर ८ पाई में बलाकर ७३ पाई कर दी गई। अवतवर १६५२ से पहले किराये की यही दर थी। लोकार बलास का किराया काब भी रेल के तीसरे दर्जे के किराये से अधिक है। रेल में तीसरे दर्जे का १५० मील का किराया यदि हाक गान्दी या एवसके से सकर किया साथ तो ६% पाई प्रति भील है और यदि सामान्य गाड़ी के कफ़र विया जाय तो दर ५, पाई प्रति भील है परन्त आशा की बाती है कि भविष्य में शेक्त्रेज किशया श्रीर घटायेंगा।

राक कीय रोक वेज प्रधाली करतीयजन क शीत से चल रही है परन्तु (१)
गाहियों को रलने तथा प्रस्मत हत्यादि करने का क्यय अधिक है और रोज वेज
को उतना लाभ नहीं होता है जितना की आशा थी। (२) अपनी कुछ दिशाओं
मैं याहियों को और अधिक मुंचियादें अधान की जा सकती है। परन्तु है स्थान कुछ
हम्में की को रोज के ले सक सातायात की अवस्था में काफी मुखार किया है
को हमारत में रोज वेज यहाताबात क्या स्थान करने के लिए कोई वाषा नहीं है।

निजी उद्योग की कठिनाइयाँ—भारत के सड़क यातायात के विकास में अनेना कारणों से बाधायें पहुंची हैं: (१) भाटर साहियों को बहुत अधिक नर देना एकता है जिससे क्यांक्यों की इस कार्य को करने की शिक्त इट जाती है। मोटर माईग कर जाँच कमेटी ने यह नात कही थी कि भारत में मोटर माईग कर जाँच कमेटी ने यह नात कही थी कि भारत में मोटर माईग कर पांच क्यांक्यों पर संसार मर में सन से अधिक कर लगाया जाता है। हभी रिपोर्ट ने अद्भावर प्रत्येक लारी पर प्रति वर्ष कुल कर महास में स्वार्थ के अध्योग करने वार्ष श्री अपने कर सहार में सुरुष्ट कर सकर महास में सुरुष्ट करने सकर साम कर पुरुष्ट कर सकर महास में सुरुष्ट करने सकर सम्बन्ध में प्रति वर्ष कर स्वार्थ में स्वार्थ में स्वार्थ में प्रति वर्ष स्वार्थ में स्वार्थ मे

श्रीर श्रन्य राज्यों में श्रीधत कर लयमग ५,१३४ क० था। इस कमेटी ने यह भी अनुमान लगाया था कि माल दोने वालो लाग्यिं केन्द्रीय श्रीर स्वदेशीय राज्यों की लितना कर देती हैं, (स्यानीय करों की छोज़ कर) यदि ने २० हमार मील में श्रीवफ थात्रा करती हो तो वह रेल द्वारा प्रति टन प्रति मील छुनाई के श्रीवत किराये से को प्रतिशत श्रीक या। विखले तीन वर्षों में लाशियां पर यह भार वास्तव में श्रानेको राज्यों में श्रीर श्रीफ बहुत ही हैं।

- (२) प्राविशिक सरकारा ने सड़कों पर बहुत कम यन व्यव किया है श्रीर सनकी देख-रेख मा टांक नहीं होता। इससे व्यक्तियों को वस चलाने के कार्य में बड़ी किटनारें पड़ती है। ''फोरर गाड़ी कर जाँच कमेरी ने पता लगामा पा कि 'क' राज्यों को १६५६ में रिकरटर की हुई मोटर गाहियों और नदाओं को स्वत्र हैं कि स्वत्र हैं कि सहस्त्रों के मार पड़े वहां के मार पड़े 'दे कर करोड़ क्यां के लगामा थी जब कि सहकों की सरमात पर केवल ११% करोड़ क्यां वस्प किया गया था जा कि पत्र का कि सुं पर के आपे में मा कम है। यह स्थित बड़ी विध्व है कि सहक यातायात पर कर इतना अभिक है कि पात्रियों और माल डोने में उनका प्रयोग करने में बाधा पड़ती है, पर किर भी मोटर गाहियों और माल डोने में उनका प्रयोग करने में बाधा पड़ती है, पर किर भी मोटर गाहियों से बदल हुये कर के धन का पूरा प्रयोग सड़कों के बनाने में नहीं किया जाता। 'ग सड़क को ठेक प्रत्मक्त न होने से सबक यातायात' क्या मां पढ़ि हो जाता है। कमेरी ने अतुमात लगाया था कि एक इस साथारण स्वाह और बहुत खराज सड़की पर एक वर्ष में १६०० मील चता में क्या अध्यक्षी सड़क में चलाने में क्या का अपीवा २६०० कि अधिक होगा।
  - (१) १६६६ में मोटर याडी एक्ट ने उन लगी यात्राधों पर जो उस समय प्रमुद्दे और कलकते, बग्वई और देहली, बंबई और प्रसादर और कब्बई और प्रसाद आदि के बीच प्रचलित यी प्रतिवन्य लगा दिये हैं। इस एक्ट की पोजना है कि स्वक यातायात को राग्यों के छोटे-छोटे चेत्रों में ही स्थानत कर दिया लग्य निवसे कि कोई मोटर राज्य की एक शीया से दूपनी शीमा तक विवा अनेको यातायात अभिकारियों की आग्रा के ने शा को। ऐसी आग्रा बहुत हो कम दी जाती है। ऐसी स्थित में अन्तर प्रदेशीय यातायात की कोई सम्माज्या ही नहीं हो सकतो । मोटर पाड़ियों के स्वापे वानों के चेत्र को धीमा कर प्रविच्या भी प्रसा में प्रमान किया हुआ है कि वे अपनी उच्छा के अनुमार विभिन्न दोषों में प्रवाई जाने वाली मोटर वर्षों शे स्वान का स्था के हैं। मोटर गाड़ी एक्ट ने छोटे-छोटे चेत्रों में अनेको अधिकारियों को बनाकर सहक के यातायात को छोटे-छोटे सेत्रों में अनेको अधिकारियों को बनाकर सहम

कर निहित स्थाय का अवसर प्रदान कर दिया है। इसके परिसाम स्वरूप सङ्क वातावात के वैशानिक संग पर विकास में बाधा पढ़ी है।

(४) जिस मकार सहक यातायात का राष्ट्रीयकरण विभिन्न राज्य द्वारा किया गया है उससे राष्ट्रीयकरण की योजना के अन्तर्गत अधिक महत्वस्थाली योजनाओं पर जो पन व्यव किया जाना चहिये या वही नहीं रोका गया वर्र वर्षाकरों के यह कार्य करने में इसी भागी वाचा मी पहुँची है। इस दोप को रोकने के लिये योजना आयोग ने १६५३ में आदिशिक राज्यों से अपनी-अपनी लाइचेंच देने की मीति को सुवारने की आशा दा यी वर्षोंक वह व्यक्तियों को सकस यातायात का कार्य करना आरम्भ करने में बहुत वाचक थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मार्सशिक राज्यों ने इस आशा को अनुमुनी कर दिया है क्यों के हक इसक कार्य मार्मशिक वह व्यक्तियों को हक यातायात का कार्य करना आरम्भ करने में बहुत वाचक थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मार्सशिक राज्यों ने इस आशा को अनुमुनी कर से परिवर्तन नहीं दिखाई वेता। अपनी आशा को मनवा उकने के लिये योजना आयोग को अपनी आशा निश्चत राज्यों में निश्चत निश्चते योजना आयोग को अपनी आशा निश्चत राज्यों में निश्चत निश्चते कार्यों मार्मशिक से सिंग मार्मशिक के स्वयं मार्मशिक के स्वयं योग से इस परने अनित परीक्षण में शिकाम आयोग के महीय मार्मशिक से स्वयं विश्वालों के स्वयं विश्वालों का अनुनारण आय्वायक है।

माल की देलाई के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त निम्न हैं :--

- उड़क द्वारा डोने वाली संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना १६६९ तक अर्थात द्वितीय योजना के अन्त तक नहीं सोची जानी चाहिये।
- २. १६१६ के ओटरगाड़ी एक्ट के अनुसार कम से कम तीन वर्ष के तिये ऐसी सस्पात्रों को जो पनय सकती हैं परिमेट स्वतन्त्रता पूर्वक देना चाहिये। मोटरगाड़ी एक्ट के अन्तर्गत अधिक से अधिक पाँच यर्ष तक का परिमेट केंद्र प्रीत्साइन डेना चाहिये।

यात्रियों के यातायात के लिये निम्न सिद्धान्तों की शिकारिश की गई है-

- (१) जो प्रादेशिक राज्य यात्रियों के यातायात सेवा संस्थान्नों का राष्ट्रीय-करण करना चाहें उन्हें योजना आयोग के समझ क्रमिक कार्य-कम बनाकर विचार करने के लिए रखना चादिये जिवसे वह कार्यक्रम को योजना में धर्मालत कर सेके। इस कार्य-कम को उन्हें १९६०-६१ तक जिन होत्रों में राष्ट्रीयकरण करना १ उनका शिक्टियत कर से विकास दिवा जाना कारिये। इसका विचार आयोग द्वारा तमी हो सकता है जबकि शर्ते प्रादेशिक राज्यों द्वारा स्वीकार कर ली आयें।
  - (२) राष्ट्रीयकरण योजना के बाहर की सहकों परायातायात के लिये

परिमट कम से कम तीन वर्षों के लिये १६३६ के मोटर गाड़ी एक्ट के द्यातुसार दिया जाय।

(१) उन नेत्रों में जो स्वीकृत राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत स्राते हैं परमिट अधिक से अधिक समय तक के लिये, जो कि विस्तार के कार्य-कम के अन्तर्गत मोटरजाड़ी एक्ट की सीमा के अन्दर ही है, दिये जाने चाहिये।

(v) अहाँ पर सरकार के सहयोग की सम्मायना है एक त्रिदलीय संस्था स्थापित की जानी चाहिये जिसमें प्रादेशिक सरकारें, रेखवे श्रीर इस कार्य में सेसना कार्या सम्भातित हो।

(५) उन चेत्रों में जिन्हे पूर्णतया व्यक्तिगत लोगों के ऋषिकार में छोड़ दिया जाय प्रतिहर्गणें दलों को विशेष भोत्साहन दिया जाना चाहिये।

राज्यों में सबकों के विकास में बाधा दालने वाली अनेक कठिनाइयों में में एक तो निर्देशन करने वाले उपयुक्त कर्मचारियों का श्रभाव है जिनका कार्य मोटर द्वारा परिवहन की व्यवस्था पर व्यान देता. सहको के नियोतित विकास की अपेसा विशेष हो। १९५८ के शाराम में मारत सरकार से एक कमेटी इस मामले की जाँच करने के लिये श्री॰ एम॰ खार॰ मसानी की ख्रध्यज्ञता में नियुक्त की थी। सरकार ने १९५८ के आरम्भ में एक अन्तर-राज्य यातायास आयोग की भी नियक्ति की यी जिसको मोटरगाडो ( संजोधित ) एक्ट की 63 ए घारा के श्चनसार नियन्त्रण तथा निर्देशन के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत अधिकार मास है श्रीर जिससे यह श्राशा की जाती है कि (१) वह परिवहन की गाहियों के संचालन सथा उनके विकास सम्बन्धी योजनाओं को तैयार करे और अपनी योजनाओं में माल लादने वाली गाडियों का जो कि श्रन्तर्राख्यों में यह कार्य कर रही है विशेष ध्यान रक्लें, (२) इस सम्बन्ध में को कुछ भी क्याड़े श्रथवा मतमेद उत्पन्न हो उन सब को निक्टॉर्स ग्रीर उन पर निर्शय हों: (३) श्रीर दो ग्राथवा दो से अधिक राज्यों में पहने वाले मार्गी पर मोटर गाड़ी चलाने, नये परिवट देने, पुरानों की किर से चाल करने तथा रह करने के सम्बन्ध मे राज्य विशेष के यातायात श्रीवकारी को अथवा देत्र विशेष के बाताबात अधिकारी को निर्देश दें ।" इस आबोग से श्राशा की जाती है कि यह अन्तर राज्य यातायात की सुविधाओं का प्रभावशाली ) रूप से विकास करने में सपल होगा।

योजना के अन्तर्गत--जब कि प्रथम पेचवर्धीय योजना आरंम हुई मारत में १७५४६ मील पक्की सहकें और १५१००० मील कच्ची सहके थी | योजना के अन्तर्गत परिले ११० करोड़ कपया व्यय करने के लिये रक्का गया या जो कि वाद में बहुक्द १३५ करोड़ रुपया कर दिया गया जिसमें से प्रथम योजना काल में लगभग १२४३ करोड़ कपये धास्तव में खन्नं कर दिये गये थे। इसके परिणाम स्वरूप २४००० मील नथी गूँम के समतल सबतें, और ४४००० मील नीची सबकें बनवार्द गर्द और इस प्रकार सहने की लम्बाई १२१००० मील पक्की और १६५००० मील कन्ची अर्थात् दुल २१६००० मील हो गई बन कि नागपुर पोजना का भ्येय केवल १२३००० मील का या २०८००० मील कन्ची अर्थात् दुल

हमके कार्निक्क अनेको सहको के रीच के स्वयंत्रानो की किलाने स्था पत्नी के बताने की भी ब्यवस्था की गई थी। "उहली क्रमील १६४० को कब कि भारत भरकार में राजयथ कही जाने वाली सहकों के विकास तथा बनाये रखने का विकास हास्त्रिक स्टब्से अध्य लिया जस समय लागी लग्धी दरी तक सक्षेत्रों के ब्यब्रधान पढे दये ये तथा सख्य-मुख्य स्थानी पर त्यनेको सदको पर पल नहीं ये । प्रथम योजना क श्रास्थ्य तक ११० माल सहकों हो सबकों के बीच के व्यवधान को जाउन के लिये तथा तान बडे-बडे पल बनवाये गये छोर १००० मील सहकों का प्रस्मान करवाई गर्ट । प्रथम योकना काल के जासभा में ही केटनीय सरकार ने सहकों के विकास तथा संघार का कार्य क्रम जारस्थ किया जिसके न्त्रस्तर्गत १२५० मील वेट्य की शायन सहको तथा ७५ बहे-बहे पत्नों का बनवाना तथा ६००० साल सहको की भरम्मत करवाना सम्मालत था। इसमें से योजना काल में ६५० मील बीच की गायब सडके क्या ४० वल तथा २५०० मील पुरानो सबकों की सरम्मत पूरी हो जाने की आशा की गई थी। योजना के खत्म हात-होते ६३६ मील वंच की गायब सबके, ३० बड़े-बडे पुल और ४००० मील परानी सबकों की मरम्मत हो पाई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितनी की च की शायन सबकों के बनवाने का ध्येय बनाया गया था यह लग भग पूरा हो गया और वर्तमान राजप्यों की मरम्मत का काम सोची हुई मात्रा से लगभग द्याना कर लिया गया। योजना में २७,८० करोड़ इपये राजपथी पर क्या के लिये नियत किये गये थे जिसमें से २७ ६२ करोड़ रुपये ह्यय कर दिये गये।

प्रथम योजना में सबको द्वारा शतायात पर १२3 करोड़ ६२वे व्यय किये तथे। दाव्यों में १००० मोटर गाड़ियाँ श्रांर श्वाह विससे कुल मोटर गाड़ियों की सख्या तो सरकार की श्वार से थातायात की सेवा में लगी हुई थी ११००० हो गई। प्रथम योजना ने श्वात तक मोटर द्वारा जनता की यातायात सेवा का २५% सरकारी विभाग द्वारा निया जाने लगा था। माल परिवदन व्यक्तिगत एजेनियों के ही श्रीधकार में रहा।

दितीय योजना में (सहनी के विकास के लिये) २४६ करी कायी के

क्ष्य को व्यवस्था की गई है जिसमें से ८२ करोड़ वर्षये केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रीर १६४ करोड़ दर्षये राज्यों द्वारा ज्ययं किया जायगा। यह रकम केन्द्रीय सहक कोष से प्राप्त होने वाले १५ करोड़ रुपयों के श्रांतिरिक है। दिलीय योजना के पूरे होने पर यह श्रात्ता को जालों है कि पक्की सहके बढ़ कर १४३,००० मील श्रीर कच्चो सहकें र्वे,,००० मील श्रार्थात् जुल गोग ३७८,००० मील हो जायगा। यह श्रात्रा नागवर योजना से कहीं श्रांविक है।

द्वितीय योजना का कार्यक्रम पहिली योजना ही की तरह बड़े-उड़े पुलों का निर्माण तथा बड़े-इड़े राजायों का मिला देने बालो चड़कों के निर्माण का और पुरानी सड़कों को मस्मात का हो है। इस योजना के अन्दर्भत आरंभ किये हुये निर्माण कार्य पर कुल ब्यय लगभग ८७% करोड़ कार्य का है। यह व्यय निरम

धरका ६ ।		
प्रथम योजना के श्रपूर्ण निर्माण कार्य पर		
जिसमें यनिहाल टनल सम्मिलित है-	₹0°0	करोड़ दपया
महे-मड़े राज पथीं को मिलाने वाली		
सङ्को पर (६०० मील)	१०%	7)
बड़े-बड़े पुलों के निर्माख पर (६०)	₹0°0	33
छोटे-छोटे पुलो क निर्माण पर	У	
पुरानी सङ्की की मरम्मत पर	৬*৩	1)
सङ्कों के (१२ कीट से २२ कीट) चौड़ी		
कराने पर (३००० मील)	\$4.0	0
<b>बुल</b>	হ্লভ'ধ	0

दिनीय योजना काल में वास्तविक व्यय लगसमा भ्रम्भ करोड़ क्यये का अतु-मानित किया गया है। राष्ट्रोय राज्यायों के छातिरिक्त केन्द्रीय चरकार ने कुछ महत्त्वशाला खक्कों का निभीषा प्रथम योजना में करवाना आरम कर दिया था। यह कार्य हैन यानना में मर्थालत रहेगा और लगममा ह करोड़ कराया इस पर क्यय हो लायगा। कुल मिला कर केवल १५० मील नहें सबस बनाई लायगी और लगममा ५०० मील सक्कों को उच्चस्तव कर दिया लायगा।

द्विताय योजना मे १३१ करोड़ क्यमों की राज्यों की सहफ यातायात संक्यों विकास काय-कमों के लिये व्यवस्था की गई हैं। १९५० के रोड़ ट्रान्स्थार्ट कारयोरेशन एकट के प्रमागित राजा सरकारों को कारयोरेशन स्थापित करने की सताह दी गई हैं और रेलवे योजना के प्रस्तांत १० करोड़ स्पर्यों की व्यवस्था की गई है कि 38. भारतीय ऋषेशास्त्र की समस्याएँ

क्छ कमी अवश्य ही व्यावेगी।

रेलवे इस कारपोरेशमों में सम्मिलित हों । इसके श्रतिरिक्त यातायात मन्त्रालय की योजना में देहली टान्सपोर्ट सरविस के लिये एक ३ करोड रुपये का कार्य-क्रम भी स्वीकत कर लिया गया है। इस प्रकार सरकारी सहक यातायात पर कल

विजियोग दिलीय योजना में ३% करोड़ हुएयों के लग मग होता है।"

श्रीर १९५७-५८ के लिये संशोधित श्रातमान ४४ ३२ करोड रुपयों का है हस

प्रकार प्रथम तीन वर्षों से कल ज्यय १२६ २६ करोड स्थया होता है। बचे हथे दी वर्षों के लिये ११६ का अपोड कपया यह जायगा । अहितम हो वर्षों के लिये बजर में इस रक्षम की व्यवस्था सामय हो सकेगो इसमें सदेह मालम पहला है। इसके द्यतिरिक्त लोडे की कमी के कारश पत्नों के निर्माण में बाधा प्रदने का भय भी है। इसलिये इस यह कह सकते हैं कि योजना के विकास कार्यक्रम से

१९५६-५% में कल सदकों के कार्य क्रम पर व्यय ४२% ह करोड कपया था

# खध्याय ३६

### ञ्ज यातायात

भारतीय यातायात स्त्रभी अपनी प्रारम्भिक स्ववस्था में है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत के पास १८,५०० जी० झार० टी० (प्राप्त र्यजस्ट ट्वेन) के जलयान है। प्रथम योजना के स्वारम्भ में भारत के पास १,८०,५०० जी० झार० टी० भारतीय हटाँपर झीर १,७३,५०२ जी० झार० टी० भारतीय हटाँपर झीर १,७३,५०० जी० झार० टी० भारतीय हटाँपर झीर १,७३,५०० जी० झार० टी० के जलयान विदेश में ब्यापार कार्य ने ब्यापर के प्रथम योजना के स्वन्त में कुल टनेज ४,८०,००० जी० झार० टी० या जिसमें से २,४०,००० जी० झार० टी० व्हीय ब्यापार मथा स्थापवर्षी देशों से ब्यापर का या और २५००० जी० झार० टी० वृद्ध विदेशी क्यापर का । लायब के जलयान के विवस्त के स्वनुदार का तो हिंद प्रयाप के सुल टनेज के १% ते कुछ स्विक्त था जब कि भारत का बुल टनेज क्यापर के कुल व्यापार का है से सुछ स्विक्त था जब कि भारत का बिदेशी क्यापार संवार के कुल व्यापार का स्वर्ध सुब्ध के स्वर्ध भागी के द्वारा भारतीय जलयान भारत के सद्भी व्यापार के विवस के सुळ स्वापार के विवस के स्वर्ध क्यापार के विवस के स्वर्ध के स्व

भारत के लिए जिसका समुद्री तट ४,१६० मील (अयहमान हीए समिलित करके) तक विस्तृत हुआ है और वो बहुत बड़ी मात्रा में अल्तर्राष्ट्रीय ज्यापार कर करता है नासत्त में जलवान का बहुत अविक महत्व है। यदि हमारे पास अपने कलवान है। तो भारतीय उद्योग का चातावात व्यय कम हो जायमा छोर विदेशी बाजारों में उनकी प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि हो जायगो। यदि सामान का भारतीय जलवानों के हारा यातायात किया जाय तो हम उत्तमी विदेशी विनिमय मुद्रा बचा सकते हैं अवको अल्प्या इन जलवानों में ज्यय करना पहला है। इसके सचा हो। तारत को अपने समुद्रत्यीय जेन की रखा करने के लिये और युक के समय अपने ज्यानार की सुर्खा के लिए एक शक्तिशाली जल सेवा की आवश्य-कता है। संकट के समय अवापारों जलवान प्रतिरक्षा की दूसरों संक्ति का कार्य देते हैं। यह स्वरायक रोता के रूप में ही सहायक नहीं होते विलक्त हमते नी-तेना की शिवा दी जा सकती है और युक के समय अवापार सकता है। संकट के समय अवापार अल्यान प्रतिरक्षा की होते विलक्त हमते नी-तेना की शिवा दी जा सकती है और युक के समय अवापार सकती हमान स्वरूपक सामान समुद्रपर पहुँचाने के लिए इनकी अल्यन्त आवश्यकता पर सकती है।

मादय विशेषताएँ--भारतीय अल यातायात के विकास की कछ उल्ले-लनीय विशेषताएँ हैं :---

- (१) भारत में ऋँग्रेजी शासन के समय भारतीय जलयानों को ब्रिटिश नभा विदेशी जलयानों की कही प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा और उसे विकास करने का श्रवसर हीं नहीं दिया गया । १६२० के लगभग श्रनेक जलयान करपनियाँ बनी परन्त प्रतियोगिता का शामना न कर सकते के फलस्वरूप ज्ञा हो शर्र । इस कम्पनियों के सब्द होने में विदेशी जलयान कम्पनियों की आहे की टर सम्बन्धी जीति का भी बहत योगदान रहा है। इन विदेशी कम्पनियो ने भारतीय कम्यानयों से प्रतियोगिता के कारण माडे की दर घटा दी श्रीर जब यह कम्पनियाँ बन्द हो गई तब भी भाड़े को दर में पुनः वृद्धिकर ली। इसके साथ इस इंजिस्सा से यह अवस्था की कि बार्ट किसी स्थापारी ने एक सिश्चित समय तक नियासत रूप से इनके जलयानों के द्वारा ही सामान भेजा और सँगाया तो उस ग्रामिय में यह जितना भाषा देगा असका एक ग्रांश उसे वादिस कर दिया जायमा । इन विदेशो कर्पानयों की प्रतियोगिता का केवल सिंधिया स्टीम नैयी-गेशन कम्पनी ही सामना कर सकी। विदेशी कायनियों ने इसे नक्ट करने की छनेक बार चेप्टा की परन्त वह सफल नहीं हो सके। इससे सिंधिया कम्पनी को भारी स्तति अठानी पड़ी। सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के इद्ध रहने पर १६२४ मे एक सम्भौता हुआ जिसके अनुसार इसे ७५ हजार टन सामान प्रतिवर्प ले जाने की अनुमृति दी गई। भारतीय अलगान कम्पनियों के नक्ट हो जाने का एक कारण यह या कि विदेशी कंदिनयों की प्रांतयोगिता शक्ति बहुत इंडी-चढ़ी थी श्रीर दसरा कारण यह था कि भारतीय कार्यानयों के पास दिन की उपयक्त ब्यवस्था नहीं भी श्रीर इनका कुल ब्यय भी बहुत श्रधिक था। थोड़े बहुत परि-वर्तन के साथ यह प्रतियोशिता स्वतन्त्रता मिलने तक चलती रही और स्वतन्त्रता मिलने से भारतीय जल यातायात का भारन के तटीय व्यापार में महत्व वह गया है और साथ ही विदेशी व्यापार से भी एक सीमा सक इसने आपना विशेष स्थान बना लिया है।
- (२) ब्रिटिश शासनकाल में सरकार ने भारतीय जल यातायात की कुछ भी सहायता नहीं दी और स्वतन्त्र ज्यापार नीति का बहाना लेकर भारतीय उद्योग को टाल दिया गया हारेर हापने लिए स्वयं मार्ग बनाने को छोड़ दिया गया। इसका यह परियाम हुआ कि इस अविधि में भारतीय जल यातायात ने विशेष प्रगति नहीं की । स्वतन्त्रता सिलने के पश्चात भारत सरकार ने इस ग्रोर थ्यान दिया है। भारत सरकार ने जलयान उद्योग को ऋगु तथा श्रन्य द्यार्थिक

सहायता हो। सरकार ने जलयान निर्माताओं से जिस मन्य पर जलयान क्रय किए भारतीय जलवान कम्पनी को उससे कस ग्रहण पर बेचे श्रीर श्रन्तर को श्रपने कोष में दिया। लाहमेन्स की प्रथा लाग करके शहश्रद में भारत के तटीय व्यापार पर नियम्भा स्थापित किया गया और १६५० में तटीय न्यायार केवल भारतीय जनयामां के लिये मरनित कर दिया गया । इसके फलस्वरूप भारतीय सपट तट पर १६४८ में जितने दना के जलयान न्यापार करते ये उसमें ५३ प्रतिशत की वांद्र हो गई और १६५२-५३ तद ज्यापार में १०० प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक जल यातायात बोडे स्थापित किया गया है जिसका कार्य जल बातायात के कार्य का संबालन करना है। सरकार की सहायता प्राप्त करके ग्रव भारतीय कम्पनियाँ विषय जन गामणान मधीनम की महस्य हैं।

१६४७ में भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा कि तीन जल वातायात कार्यों-रेशन बनाये जायें, प्रत्येक के पास १० करोड़ रूपये की पेंजी ही और तीनी कापीरेशन तीन मांगों में ज्यापार इत्याद करें। परन्त १६५५ तक मार्च १६५० में १० करोड़ रुपये की अधिकत पूँजी का केवल एक कार्पोरेशन, पूर्वी कार्पोरेशन लिमिटेड, स्थापित किया जा सका था। सरकार ने दो करोड साये की नियमित पाँची का केवल है भाग दिया और शेष पाँची मैनेजिंग एजेन्टों ने लगाई। जन शह्य में इसरे कार्पोरेशन (पश्चिमी शिविंग कार्पोरेशन) की स्थापना हुई। यह पूर्ण रूप से राज्य के आधिकार में है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ईस्टर्न शिषिण कार्पोग्शन से यागामी पाँच वपाँ के ग्रस्टर यह भाशा की जातीथी कि ४०,००० जी। भारत टीन व्यापार और अधिक कर सकेगा। परन्तु वह केवल २१,६०० बीठ आर० टी॰ ब्यापार अथम तीन वर्षों में बढ़ा पाया । सरकार ने जलगान उद्योग की और अधिक विसीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दी है। इसलिये यह आशा करना सर्वधा यक्ति संगत होगा कि कुछ समय में भारतीय जल यातायात टक्कति की सरम सीमा पर पहेंच जायसा ।

(३) प्रारम्भ में देश-विदेश स्थापार में मारतीय जनयानों ने भी भाग लिया। परन्तु उनमें से अधिकतर छोटे वे और अधिकतर सेलिंग वेशिल, टम्स, आरजेज, कोस्टर्स इत्यादि ये। ब्रावीत में एक सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि देश में जलयान उद्योग नहीं था जिससे खत्तयानों का न्यय श्रन्यधिक हो गया था। अब विशाखापट्टम् में जनमान कारखाना है। यह जून १९४१ में स्थानित किया गया था। यह आशा को जाती थी कि २,१५,००० जी० आर० टी० में से जो कि अथम योजना के प्रथम तीन वर्षों में प्राप्त कर लेना चाहिए, या हिन्दुस्तान शिष्याडे १ लाल जी० आर० टो० की पूर्त करेगा। परन्त शिष्याडं की उनित वहीं धीमी रही है और प्रथम तीन वर्षी में वह केवल २५,८०४ जी० आर० टी० ही की पूर्ति करने में सबर्थ हो सका है। भारतीय जल यातायात कम्पनियों की विज्ञासापट्रम् शिष्ट वार्ड से अधिकाधिक संख्या में जलयान के पाने की आशा भी जा सकती हैं। इस्में स्थम किताई ललयान के विभिन्न कल-पुओं की प्राप्ति में में किताई है जिन्ह विदेशों से मेंगान पहता है । वैच ही यह किताई दूर हो लायती और शियपार्ड की उत्पादन शिक्त में बृद्धि हो जायती, भारताय जलपानों के टनेज के शिक्त स्थार में बास्तविक सहायता पहिंच सकती।

(४) प्रारतीय जल यातायात के विकास में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमारे देश में कल्लयानों को बन्दरगाह की अब्वित सुध्याय नहीं मिल पाती हैं। प्रारत के पाँच कहें बन्दरगाहों, कलक्ष्या, बन्दर, सहाय, क्ष्य क्षेत्र रात्र को प्रेहेल, कल्लयान में कलानेयाला कोयला हत्याद को छोड़ कर केवत दों करोड़ दन सामान प्रतिवयं उतारा लादा जा सकता है। १६४६-५० में पेट्राल तथा कल्यान में बलने वाले कोयले को सम्मिलत करके हम बन्दरगाहों में दो करोड़ दन सामान लादा उतारा गया। प्रथम योजना के अन्दर्गत विकास के कारण मात्र लादने उतारों गया। प्रथम योजना के अन्दर्गत विकास के कारण मात्र लादने उतारों की शक्त बढ़ कर दो करोड़ प्यास लाख दन हो गई है। बन्दरगादि पर यथाशांक कार्य है। बन्दरगादी के बहुत देर तक प्रवीदा करनी पदती पर प्रथाशांक कार्य है। इस है। बल्यानों को बहुत देर तक प्रवीदा करनी पदती है। माल डॉक से पड़ा रहता है इसके पूर्व कि लादा जा सके। यह प्रस्ता पत्र प्रथम गांव है कि नये बन्दरगाह बनाये जा रहे हैं। हम्दरगादी पर अगांव के सामान, आकांवायीय तथा अन्य स्विधार्य बहाई ला रही हैं।

पुनर्निर्माण नीति उपसमिति—पुनर्निर्माण नीति उपसमिति (१६४०) ने भारतीय जल यातायात की पूर्णतया जॉच की ख्रोर निम्नलिखित विदारिर्ण की :—

- (१) भारत की प्रति वर्ष १ करोड़ टम नामान लाने से जाने के लिये श्रीर १० लाख पानियों को से जाने के लिये झोटे जलपानी को छोड़कर २० लाख टम के कलपानी की शावज्यकता होती।
- (२) इमारा उद्देश है कि १९५७ तक भारत के तटीय ब्यापार का २०० मारात, भारत-मां लंका चपा अन्य पढ़ोधी देश से ब्यापार का ७५ मित्रात, दूर देशों से भारत के व्यापार का ५० मित्रात कुर देशों से भारत के व्यापार का ५० मित्रात मारा क्यों व्यापार का ३० मित्रात क्यापार का २० मित्रात क्यापार क्यापार
- (३) मारत सरकार की नीति का उद्देश्य भारतीय जल यातायात का प्रसार होना चाहिए और दर्शे में कभी और निश्च होने से इसकी रत्ता की जानी

चाहिए। इन उद्देश्या को पूरा करने के लिए जल यातायान बोर्ड को पूरे श्रिषकार देने चाहिएँ।

पुनिर्मास नीति उपसमिति ने को लक्ष्य निर्घारित किये से भारतीय जल यातायात ना स्तर यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है। यह निजी उद्योग तथा भारत सरकार के लिए ख्रायन्त खेद की बात है। वर्तमान में भारतीय जल यातायात का दनेज कवल ५ लाख दन है जब कि समिति ने २ वाल दम का सुकाय दिया था। भारतीय जलयान कुल विदेशी क्यायार का केवल ५ प्रतिशत पूरा करते हैं जब कि भामति ने मुकाब दिया था कि भारतीय जलयानों को ख्रयने कुल विदेशी क्यायार का ५० प्रतिशत स्वयं करना चाहिये। केवल तटीय व्यापार के सम्बन्ध में सिक्ति की ख्रिमिलाया पुर्ण कर्ष है।

भारतीय जल यातायात के प्रसार एवय् यंगठन के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के ज़िये जल यातायात के मालिकों की परामर्शदार्थी समिति की १९५६ के मध्य में एक मैठक हुई। धर्माति ने स्रमेक सुक्ताव दिये। समिति ने स्रमेक सुक्ताव दिये। समिति ने स्रमेक स्वार्थ कार्य में एक मैठक हुई। धर्माति ने स्रमेक सुक्ताव दिये। समिति ने स्रमेक योजना में इस कार्य के जिए जितने यन की व्यवस्था की गई है बहु अपवात है। सरकार को अधिक से अधिक रूप मित्रश वार्षिक क्याल पर मारतिय जलयात कम्पनियों को श्रमुख देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पूजी उरजात ते खुकाई जा सके। समिति ने यह भी सुक्ताव दिये कि (१) पुराने जलयानों के स्थान पर नये जलयानों को स्थादने के लिए जो जामांग जमा किया गया है उस पर आय कर न लगाया जाय, (२) भारतीय जलयानों में जलने वाले तेल पर खुली न लगाई जाय और (१) जलयानों का सामान बेचने वाले स्टोरी पर विकी-कर न लगाया जाय।

यह भी सुमान दिया गया है कि तटीय व्यापार करनेवाला जलायान बेका कम्मुलित होना चाहिये। इसने विभिन्न आकार प्रकार के जलयान होने चाहिये को तटीय ब्यापार की विशेष वस्तुओं लेते नमक, कीयला और तेल लाने से कर उपयुक्त हो। कुछ लोगों का निवार है कि नमक और कीयला ले जाने के उपयुक्त हो। कुछ लोगों का निवार है कि नमक और कीयला ले जाने के लिए, ००० से रू,००० वी० वर्च्यू टी० के जलयान आधिक उपयुक्त होते हैं और खायान की समामी इस्थारि का यावायान करने के लिए छोटे आकार के जलयानों का प्रयोग किया वा सकता है।

इस समिति ने बताया कि मारतीय बन्दरगाहों में सामान लादने श्लीर उतारने की श्रन्छी व्यवस्था नहीं है। विशेषकर कोयला लादने के लिए वर्षों (जलयान खड़े होने का स्थान) का श्रमाय है श्लीर कुछ दृदी-कूटी रिधति में ह श्रीर उससे कार्य श्रन्छी प्रकार नहीं लिया ना सकता है। समिति ने सुकान दिया कि बन्दरगाईं में माल लादने और उतारने इत्यादि का कार्य तीत्र गति से करने के लिए मधीने लगाने की श्रीर वर्तमान सामान को श्रीर बढ़ाने की अग्रजशकता है।

पंजनर्गात गोजना के अन्तर्गत-प्रथम प्रचवर्णीय योजना में मारतीय कलयानों की सख्या बदाने पर श्रोर बन्दरगाडो इत्यादि की सविधाएँ बदाने पर कोर दिया गया था। योजना में कहा गया था कि सटीय क्यापार में जो पराने क्रीर विरे-192 जलवान प्रयक्त किये जा रहे हैं जलवान कम्यानयों की उन्हें बदलने में महायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विज्ञासायनाम में समयानी के निर्मास हेत हत्या लगाया है। व्याना की जाती है कि प्रचवर्णीय योजनाकाल में ही विशाखापद्रम के कारखाने से कल १ लाख जी० थ्वार० टा० के जलयान प्राप्त कियं जा सकेंगे। इनमें से ६० इजार जी० छार० टी० के जलवानों से पुराने घित-पिटे जलयानी की बदला आयगा छ।र शेप जलयान विशेष कर सटीय व्यापार में प्रयक्त किये डायंगे । विकाश्वापरसम् कारवाने भी जलगान कार्यासयों के हाथ जलयान उचित सहयो पर बेचे जायेंगे । यदि निर्माण व्यय से और दिही सहय में कछ ग्रन्तर रहेगा ता उसके निए सरकार जनगान निर्माण उद्योग की ग्रार्थिक सद्दायता देगी। इस प्रकार जलयान निर्माण कार्यका प्रसार करने का विशाखा-पटनम कारलान के विकास से गहरा सम्बन्ध है जिससे विशालापटनम की उत्पादन शक्तिका पूर्ण अपयोग किया जा सके। योजना के जानसार तटीय व्यापार की सरकित बनाए रखने के लिए कम से कम इ लाख जी। ग्रार० टी॰ के जलयानी का होना श्रत्यन्त आवश्यक है। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि पाँच वर्ष के श्चन्दर भारतीय जलयान कम्पनियों को ४ करोड़ रूपया श्राम दिया जायगा श्रीर जलयान कम्पनियाँ अपने साधनी से शेष २ करोड़ रुपया एकत्रित करेंगी। बानमान था कि इस ६ करोड़ रुपये से आरतीय जलयान कम्पनियों के पास पर्याप्त जजयान हो क वेंग। पचवर्षीय योजना के अन्तर्यात विदेशी व्यापार के लिए १,००,००० बी॰ डब्लू॰ टी॰ के जलयानों की और आवश्यकता समसी गई थी जिसमें ईस्टर्न भाषिम कार्पोरेशन के लिए श्रावश्यक ६० इजार डो० डब्लू॰ टी० के जलयानी को सम्मिलत नहीं किया गया था जिसके लिए सरकार ने अपने भाग के ४.४ करोड ६पये की न्यवस्था कर दी थी।

प्रथम योजना में १९५५.५६ तक ६ लाख जी० छार० टी० तक जलयानो के श्रदाने का विचार किया गया था। पर वास्तव में योजना काल के श्रन्त तक कुल ५,८०,००० जी० छार० टी० का कार्य किया जा सका। जी प्येय ६,००,००० जी० आरा० टी० का सोचागपा यावह तो तभी पूरा हो सका जब कि योजना काल में ही में साथे हुये जहाज प्राप्त हो सके।

जल यातायात उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रथम योजना के ऋन्तर्गत ब्यवस्था की गई है उसकी लोगों ने निम्न ब्रालोचना की है: (१) सन् १९५६ तक ६,००,००० जो० आर० टी० के जलयानों की वृद्ध पुर्नानमीय नीति-उपसमिति की सिकारिश की तुलना में बहुत कम है। सिमिति ने सिकारिश की थी कि १९५. तक २० लाख टन के जलयान हो जाने चाहिएँ परनतु इस काय में ग्रानेक कटिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वित्त के सत्य ही आवश्यक सामान का ग्रामाय है श्चीर व्यवहारिक दृष्टि से पचनपीय योजना समिति के कार्यक्रम को श्रपना तथ्य नहीं बना सकती थी। योजना से ज्यावहारिक टॉब्टकी खु के ऋषार पर लक्ष्य निर्धारित किये हैं। (२) भारतीय जलयान समिति ने सुम्ताव दिया है कि मरकार तटीय एवम् विदेशी ब्यापार में जा क्यया ब्यय करेगी यह जलवाना छोर ग्रान्य सामान के बढ़े हुए मूल्यों को देखते हुए बहुत कम है। पचवर्षीय योजना में जी सक्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा वरने में भा कहीं अधिक कामा लगगा; (३) सरकार श्रुण दी गई पूँजा पर कितना ब्याज यस्त रही है श्रीर श्रुण के साथ जो शर्ते लगी हैं उनसे ऋष लेना उद्योग के लिए असुविधालनक हो गया है। उद्याग को यह ऋष भेंहगा पड़ता है। यह सुमाव दिया गया है कि सरकार को २० वर्ष के लिए ऋण देना चाहिए श्रीर पहले ५ वर्षों में उस पर कुछ ब्याज नहीं लेना चाहिए। छठे वर्ष से ३ प्रतिशत वार्षिक ब्याज वस्त किया जा सकता है और इसी समय से ऋण ली गई पूँबी भी किश्तों में चुकानी आरम्म होजायगी; (v) योजना की अन्य सुविषात्रों की कुछ चर्चा नहीं की गई है, जैसे जलपान में जलने वाले तेल पर से चुद्धी इटाना, जलयान सामान के स्टोर पर से विकी-कर इटाना श्रीर श्राय-कर पर रियायत देना। जल यश्तायात उच ग ने इन सुविधाओं की भौग की है। इनक बिना भारतीय जल यातायात की तेजी ने प्रशसि नहीं की लासकती है।

द्वितीय योजना में यह मस्ताच किया गया है कि ६० हजार जी० आरं रहे के सिते-पिटे जलसानों को निकाल कर ३० लाख जी० आरं है है। के जल-टी० के सिते जी जार। इस मकार दूसरी योजना के अन्त तक कुल टनेज ६ सानों की दिसे की जार। इस मकार दूसरी योजना का स्पेय है (३) तरीम ब्हायार खाख जी० आरं टी० हो जाना चाहिए। योजना का स्पेय है (३) तरीम ब्हायार को आदश्यक्ताओं को रेखने द्वारा प्राप्त माल और याजियों की मात्रा को स्थान में की आदश्यक्ताओं को रेखने द्वारा प्राप्त माल और याजियों की प्राप्त में एखते हुए पूर्व करना; (२) भारत के विदेशी व्याघार का अधिक से आधिक भाग

भारतीय जलवानों के लिए प्राप्त करना; (३) टैकों का बेड़ा वैय्यार करने के लिए केट्ट स्थापित करना।

नीचे लिखे निश्चित ध्येय को पूरा कर होने के पश्चाल भारत का १२ से १५ प्रतिवात समुद्रपार देखों से व्यापार और आस्त्र-पास के देखों से ज्यापार का ५,०% भारतीय जलयांनी के भाग में आ जाययां जब कि वर्तमान में इन व्यापारों का जेवल १५ और ४० प्रतिकात उनके भाग में हैं।

जीव हारव ही व योजना के प्रथम योजना विसीय योजना से साइन मे ले सराज में पत्रले तरीय स्थीर तिकारस्थ 250202 382202 V12200 समट पार Va VEas Va VESS Va V Pa Y रेस्व Eccac रैकार्स 23000 4000 सेल देख रग 2000 202000 কল BE ALBAIS 200003

प्रथम योजना में १६ % करोड़ क्यम बाल यातायात के लिये नियत किया गया था। बाद में यह धन बढ़ा कर २६ ३ करोड़ रुपया कर दिया गया। योजना काल में बातायिक ध्यम १८.७१ करोड़ द्यारे किया गया। दितीय योजना में जल यातायात के विकाश के लिये ५% करोड़ द० की ध्यस्या को में है। जल बातायात के विकाश के लिये ५% करोड़ दण्यों के ध्यस्या च्यापि की गई है किर मी क्योंकि पिछली योजना का द्यार द्यारा के ब्यस्या च्यापि की केवल ३७ करोड़ व्यया ही इच योजना में विकाश कार्यों के लिये मात होगा।

योजना श्रायोग के दितीय पंचयर्षीय योजना के कार्यों तथा यानी एकलवा के मत के श्रमुखार (मई १९५६) जितने व्यम की दितीय योजना में व्यवस्था की गई है उवका क्या वी हो ही खुका है और उनके फलस्कल जो जल यातायात का कार्य होगा (टनेज मिलेगा) वह लगमग १८०००० जी० आरठ टी० होगा जबकि योजना का व्येव २६०,००० जी० आरठ टी० होगा जबकि योजना का व्येव २६०,००० जी० आरठ टी० टनेज प्रायंत करने का था, विजमें ६०००० जी० आरठ टी० टनेज पुराने जहांगी के स्थान पर नये प्रयोग में ले आने के कार्य प्राप्त होने वाला था। अपने प्येव को पूरा कर एकने के लिये लगमग ४५ करोड़ क्यों की और आवस्यकता होगी।

बन्दरगाह-भवम योजना की रूपरेखा जब उपस्थित की गई थी उसमें बन्दरसाहों के विकास अथवा सघार का कोई स्थान नहीं था। इस अभाव की पति की महत्ता समझी गई और जब योजना की संशोधित रूपरेखा बनाई गई तो उसमें ३३ करोड रूपयो की व्यवस्था की गई थी। बाद में यह मात्रा बद्धा कर 35° श करोड़ कर दी गई थी। चेंकि बन्दरगाहों के सवार का कार्यक्रम देर से भारम हथा. इसलिये योजना-काल में व्यय की मात्रा देवल २७'५७ करोड रुपयों की हो पाई। कछ भी हो यह विकास कार्यक्रम जो आरम्भ किया गया बढे महाद का था। कारहता के नये बन्दरगाड के बनवाने के अतिरिक्त जिस पर 22-2 करोड़ दपयों की व्यवस्था की जा चुकी थी, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य योक्षनाएँ बम्बई और कलकत्ता में थी जिनके लिये योजना में ११ तथा ८ करोड कपयों की ब्यवस्था कमशः की गई थी। योजना के शस्त तक काराष्ट्रका पर द'प करोड बन्दे बन्दई वर ११ करोड, और कलकला पर ३'भ करोड बन्दे वनय किये का चुके थे।

"पुल्य मुख्य बन्दरगाडों की समता प्रथम योजना काल में २०० करोड टर से बहु कर २५० करोड़ उन हो गई। १६५०-५१ में कुल माल जो इन मुख्य बन्दरगाही द्वारा उतारा श्रायवा चढाया गया १८०-२ कराई टन या जिसमें ११२-५ करोड टन छायात का माल और ६७% करोड़ टन निर्यात का माल समिलित था। १६५५-५६ में अनुमान है कि उतारे और चढाये जाने वाले कल माल की सात्रा २२० करोड दन थी जिसमें १३० करोड दन ग्रायात शीर ६० दन मिर्यात का माल था। 🕫

लगभग २२६ छोटे-छोटे *बन्दरगाह २६.०० मील फे तट पर* फैले हुये हैं जिनमें १५० बन्दरगाहीं से माल श्राता-जाता है। १६५१-५२ में इन बन्दरगाही हारा ३७६ करोड़ टन माल उठाया गया, और १६५४ तक यह माना वह कर ४१'५ करोड़ दन हो गई। प्रथम योजना में इन छोटे-छोटे बन्दरगाहों के विकास कार्यक्रम में मदास, सौराष्ट्र, बम्बई, उड़ीसा आदि गुख्य स्थान सम्मिलित किये गये थे । कल व्यव जो किया गया या वह २ करोड़ कायों से कुछ हो कम था।

दितीय योजना का साधारण ध्येय है कि प्रथम योजना में जो कार्य ग्रारम्य ) किया जा चुका है उसे पूर्ण कर दिया जाय और सर्व सुविधाओं का प्रचन्य करके डॉकों को आधुनिक रूप प्रदान कर दिया जाय ताकि देशा के आर्थिक और श्रीदोगिक विकास के कारण जो आवश्यकतायें हों पूर्ण की जा सकें। ४० करोड़ रूपये की व्यवस्था बड़े-बड़े बन्दरसाही के सुवार कार्य-क्रम के लिये की जा सुकी है। जो निर्माण कार्य आएम किये कार्येंगे, जिनमें प्रथम बोजना के अवरे कार्यों को पूर्य करने का कार्य भी सम्मिलित होगा, उनमें लगमग ७६ करोड रपया व्यव होगा। योजना में व्यवस्थित ४० करोड रूपये के अर्तिरिक्त कुछ धन नन्दरगाहों के अपने निजी कोषों से भी मास होगा। योजना में निर्धारित धन सरकार
हो ओर से काप्यला में लगाया जावगा और पोर्ट ट्रस्ट की कहायता के लिये
दिया जायगा। वर्तमाने ध्यायती ऋषु की पोर्ट ट्रस्ट के लिये सुविधा तृत्वरी
योजना काल में भी रहेगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वहे-बड़े वन्दर गाहों के
सुधार के कार्यक्रम में कलकत्ते में १९ ह नरीड व्यया व्यय किये जाने वाली,
बामहे में १९ १ करोड व्यया व्यय किये जाने वाली, कोर्बान में ४० करोड व्यया व्यय किये जाने वाली और कार्यक्रम में १९०० करोड व्यया व्यय किये जाने

भारत में लगभग १५० छोटे अन्दरगाह हैं जिनमें से १८ विशेष महत्य में हैं। उनका सुधार क्षायरण क्षायरणक है। प्रथम योजना में छोटे-छोटे अन्दरगाहों के सुपार की योजनाएँ सम्मिलित की गई थीं जिनसासुक व्यय २५४१ नरीक क्ष्या नियत था, रुप्ते से १ करोफ के स्त्रीय कोय से प्राप्त होना या छीर शेष बन्दरगाहों के कर्मचारियों की छापनी छोर से एकतित करना था। द्वितीय योजना में छोटे-छोटे बन्दरगाहों के सुधार के लिए ५ करोड़ क्या नियत किया गया है।

## श्रध्याय ३७

# हवाई यातायात

वर्तमान युग में देश के श्रीद्योगिक श्रार्थिक श्रीर श्रन्य कार्यों का मुलाधार 'गति' है और यातायात के मलाधार हैं यात्रियों एवम सामान का तीन गति से वातावात कर सकते वादि साधन । मारत जैसे विशास हैश में इसाई वातावात कर विशेष महत्व है। विमानों द्वारा यात्रा करने से समय की बहल बन्नत होती है, अनेक अस्विषाओं से बचा का एकता है: व्यापारी, सरकारी कर्मचारी तथा झन्य लोग बड़ी कशलता से कार्य कर सकते हैं. अपने कारखानों से सम्पर्क रख सकते हैं, दूर-दूर स्थित कार्यालयों से सम्बन्ध बना रह सकता है और नियंत्रण के साथ ही साथ उपका शब्दी प्रकार निरीत्रण किया जा सकता है । संकरकाल में बाद श्रमवा भक्तम्य के समय इवाई यातायात का महत्व और मी श्रमिक हो जाता है। इसके श्रांतरिक शांतिकाल में नागरिक उड़यन के कर्मचारी जो श्रानमंत्र प्राप्त करते हैं उसका मह के समय सहपयोग किया जा सकता है। दिसीय विश्वयुद के धमन और देश विभाजन के पश्चात भारत की डवाई कम्पनियों ने यात्रियों तथा सामान का यालायात करने में, निरीक्षण करने में और सरकार के निर्देश घर शरकार्थियों को एक स्थान से दूखरे स्थान पर ले जाने में प्रश्तक्तीय कार्य किया ! हवाई पातायात का यथासंभव विकास करने की अत्यन्त जावश्यकता है: इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं।

विकास—यह सेंद का विषय है कि भारत में इवाई पातापात झभी अपनी प्रश्तिक अवत्या में है। यदानि भारत में १६११ से ही विमानों का उपयोग आरामा ही गया पा श्रीर प्रधम विश्वद्ध के समय इट दिशा में कुछ प्रगति भी लों मंद पारत्य मारतीय दगाई मारतीय है विद्याप मारतीय दगाई पातापात में दितीय विरयद्ध के समय और उठके एश्वात् ही विशेष प्रगति की सा सकी। भारत के हवाई पातापात है किसास में कुछ उश्लेखनीय सात हुई हैं: (१) १६२७ में नागरिक उद्धुपन विमाग स्वापित किया गया और १६९५ में दिल्ली, कलकत्ता, यवाई और करींची में प्रसाद पता योद गों। भागान-मालको और टेक्नीश्विनों के प्रिक्त के मायत्य में स्वाप्त पता में श्रीर करींची में प्रसाद में हिल्ली तक प्रदेश में दिल्ली तक प्रदेश में हैं किया गया। भारत में हवाई वातावाद के विकास क्रां प्रशास करने का प्रसन्त क्यां गया। भारत में हवाई वातावाद के विकास क्यां पदी प्रारंभकाल पा; (२) १६३२ में टाटा एयरवेज लिसिटेड ने इलाहाबुद,

कलकत्ता स्वीर कोलम्बी के प्रध्य हवाई यानायात स्वारंध किया स्वीर तरपञ्चात कराँची श्रीर मदास तक इसका प्रसार कर दिया । देश के कल मार्गों पर इरिडयन नेशानल एयरवेज ने भी यातायात कार्य श्रारू कर दिया। (३) १६३८ में एम्पायर प्यरमेल योजना लाग की गई जो अब प्रारम्म होने पर स्थमित कर दी गई परन्त नत्यश्चात बहत सीमत पैमाने पर इसे फिर लाग किया गया: (४) १९४६ में कुछ सुरंगदित विश्वासनीय निजी व्यवसायिक संस्थाओं की आवश्यक सरकारी सहायता देकर देश के सम्दर तथा विदेश से इवाई धातायात की मविधा का विकास यनम् मधार करने को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने एक निश्चित उद्भयन नीति निर्धारित की । १६ ५६ में हवाई थानायान लादमेंसिंग बोर्ज स्थापित किया गया। यह निश्चित किया ग्रंग कि लाइसेन्स देते समय बोडे इस बातों पर पर विचार करेगा: (अ) कम्पनी की विच स्थिति. (व) कार्यक्रमता का उचित स्तर, (स) यातायात की माँग खोर (ह) बनदा की ब्रावश्यकता के ब्रम्कल कम्पनी की इवाई यातायात का विकास कर सकने की समता ! बोर्ड को लाइसन्स-प्राप्त कम्पनियों क किराये तथा भाड़े की अधिकतम तथा न्युन्तम दर निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। बोर्ड ने अपने कार्यकाल में अनेक कम्पनियों को लाइसेन्स दिये । इसका परिशाम यह हन्ना कि इसाई यातायात में बहुत सी कम्पनियाँ चाला हो जाने से बटिलता ह्या गई और इनमें परस्पर हानिकारक प्रतियोगिता चलने लगी। इससे कृष्यनियों को स्रवि भी उठानी पड़ी: (५) मारत सरकार ने टाटा के सहयोग से विदेशी हवाई वातावात के लिए एपर हरिडया इन्टरनेशनल की स्थापना की। टाटा के साथ यह समझीता किया गया कि इस मई करानी में ४९ प्रतिशत शेयर सरकार लेगी जो ५१ प्रतिशत तक बढाये जा सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त भूवर्षतक यदि घाटा हजा तो इस घाटेको भी सरकार पूर्ण करेगी।

ह्वाई यातायात जाँच समिति (१६४२)—हवाई यातायात जाँच समिति
ने, जो राजाध्यत्त कमेटी के नाम से अधिक प्रांवस है, भारतीय हवाई कम्मित्य
की स्मिति और उनकी समस्याओं को पूर्ण जाँच की और इस परिणाम पर पहुँची
कि हवाई यातायात लाइसिन्सिय बोर्ड ने अपना कार्य सन्तीय-ननक रीति से नदी
किया और निना किया प्रकार का मेंड किया नार्य से ले लेक्टर दि ते जियका
तिर्णाम यह हुमा कि दो वर्ष के अन्दर ११ कम्पनियों को लाइस्नेट मिल गर्य
क्व कि संपूर्ण कार्य केयल चार कम्पनियाँ अच्छी मकार चला सकती थी। इतनी
अधिक कम्पनियाँ होने से उन्हें हानि उठानी पढ़ी, इसके साथ ही हवाई कम्पनियों
ने सत्यंता से कार्य गर्दी किया और कम्पनी के सज्ञठन हत्यादि में बहुत अधिक

रपया व्यय किया जब कि यातायात की स्थित को देखते हुए यह उचित नहीं या। कम्पनियों का उत्पादन व्यय भी पेट्रोल के मूल्य १ रुपया १४ झाना प्रति गैलन (१६४६) में बदकर १६४६ में २ रुपया १ श्वाना प्रति गैलन हो जाने से, बढ़ गया।

छिमित इयाई कम्पानियों के राष्ट्रीयकरख के पढ़ में नहीं थी। सिमिति का मत या कि इयाई यातायास के खेल में समय के अनुक्त परिवर्तनशील नीत की और साइस-पूर्वक नयी योजना कार्योन्तित करने की आवश्यकता है परना यदि इवाई कम्पनियों को सरकार अपने अधिकार में ले शेती तो इसकी संपावना कम कम्पनियों को सरकार अपने अधिकार में ले शेती तो इसकी संपावना कम कम्पनियों के एकी करा क्या और समई, कलकमा, दिक्ली तथा है दराबाद में उनके अब्दे स्थापित हों। इसमे झानिकारक प्रतियोगिता कम हो झायगी और कम्पनियों में कार्य का वितरण भी बैंशानिक तथा सेशीय आपकार पर किया आ कम्पनियों में कार्य का वितरण भी बैंशानिक तथा सेशीय आपकार पर किया आ स्वर्तेमान कम्पनियों की महार्थ के मिलारित कर दिया जाय, विशानी की स्थ्या बंदा दी जाय, अतिरिक्त कमेखारियों की खुटनी की जाय, और दबाई यातायात के संखालन-स्थय, उचित लामांश और विभानों का प्रयोग करनेवाले यात्रियों की ब्यर सांक्त पर विचार करके किराये तथा आड़े की दर में चुकि की जाय । सिमिति ने सिकारिया की किरटैंटकई-स्थय के आधार पर इबाई कम्पनियों को सरकार आर्थिक स्थायन है।

राष्ट्रीयकरख्य-हवाई कंपिनयाँ स्वेच्छा से एकीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं हुई विसे कि हवाई यातायात जीन समिति को झाशा थी। हवाई यातायात में अध्ययस्था के कारण कथानियों की भारी खित उठानी एकी और उनकी रियति विवाद होने लगी। यथांव जीन सांति ने राष्ट्रीयकरण के विवत्त अपनी राष्ट्र विवाद होने लगी। यथांव जीन सांति ने राष्ट्रीयकरण के विवत्त अपनी राष्ट्र प्रकर की थी परन्तु हवाई कथानिया हो विवादती दशा को देखते हुए सरकार के राष्ट्रीय करण करने का निश्चय किया। यह तर्क किया गया कि (१) राष्ट्रीयकरण हो आने से उड़ान में जो समय स्वयं नष्ट होता है वह कम हो जायगा, एक ही कार्य के तर्क हाता गई। करगा, एक ही कार्य के स्वयं अध्य होता है वह कम हो जायगा, एक ही कार्य होता कार्य के स्वयं क्ष्य होता हो जायगी; (२) राष्ट्रीयकरण में संसुक्त अपने प्रकर्ण होता होता की कार्यक्रमा बढ़ेगी और (३) नार्गरक उड़ियन का आच्छा स्वयं कि स्वयं क्षय कार्य के स्वयं कार्य विधान चालको, टेक्नीयियनों इत्यादि के अभाव का सम्मान सही करना पढ़िया।

इवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के खिये संसद ने १६५१ का हवाई यादायात कार्गेरेशन कानून पास किया है जिसके अन्तर्गत १ अगस्त १६५१ को दो कार्गेरेशन स्पापित किये गये जिलमें से एक देश के अन्दर के इवाई यातायात

मुद्रावक की कमस्या १६५५ में ६००१ करोक क्या देकर सहा के लिये निश्चित कर दी गई। जहाँ तक राष्ट्रीयकरण के परिवासस्वकर बेकारी का मरन था, यह निश्चित कर लिया गया कि वे खब कर्मेबारी जो ३० जून १६५२ के पूर्व करगनयों द्वारा नियुक्त किये गये में उनकी बदलों कारपीरेशन में कर दी गई और इस बात का पूर्ण प्रयान किया जा उसा है कि कर्मवारियों को पुनैव्यवस्था और विस्तार के कार्य-कम में खबा लिया जाया।

वर्तमान स्थिति—१६५३ के शाराभ में भारत में ६ हवाई करनियाँ धी जिनके पात २१% कराइ रुपये की श्रामकृत पूँची श्रीर हट-कृट के कीय में ६ करोइ करये स कुछ कम ये। इन कम्मनियों के विमान कुल २६,००० मील के दील में बतते हैं। ब्रत १६५२ के शारत कर मारत में २०० राजस्टर विमान ये, जिनमें २०१ दिमानों को गायता के प्रमान्त-यह दिये वा चुके थे। इताई श्राष्ट्रों पर कार्य करने वाले जाईनम्प-मास विमान चालकों की लेखा ५५० थी तथा ए लाइसेन्ट मास चालकों की लेखा ५५० थी तथा ए लाइसेन्ट मास चालकों की लेखा ५२६ थी। इसने पहले वर्ष श्री शतार देन्द्र प्रमान चिमान चालकों की लेखा ५२६ थी। इसने पहले वर्ष श्री शतार देन्द्र प्रमान चिमान चालकों की लेखा ५२६ थी। इसने पहले वर्ष श्री शतार में स्क्रीनियरों तथा 'ए' लाइसेन्ट मास्त चिमान चालकों की लेखा कर स्वाप चालकों की लेखा में विष्ट इंद परन्तु ए—१ चालकों श्री सो. लाइसेन्ट प्राप्त चालकों की सल्या पर्री।

१९५२ और ५३ में हवाई यात्रा की स्थिति में ख्रवनित होती रही और, यात्रियोंकी रंख्या श्रीर यातायात के माल को मात्रा में कमी श्राई जिसके कारण १९५३ में यात्रियों की संस्था घटकर ४०४ लाख ख़ीर हुलाई के माल की मात्रा घट कर ८४४८ लाख पींड हो गई जबकि यह संख्या १९५२ में क्रमश: ४१ लाख एयं ८६०४ लाख पींड थो। इसका कार्य्य हुछ तो जनता के पात्र घन की कमी ख़ीर कुछं भारतीय इसाई सर्वेस को हुव्यंवस्था थी। पायपि डाक की मात्रा १९५२ में महेकर ८५ लाख पींड क्षोर १९५३ में ८८ लाख पींड हो गई (इस भी मात्रियों और पातायात के माल की कमी का घाटा इस्ते पूर्व न हो सका।

भारत में इवाई कम्पनियों के कार्य के असंवीयजनक होने के अनेक कारण हैं : (१) इबाई कप्यनियों के कार्य-संचालन का क्यय बहुत श्रधिक है। इसमें विमानों में प्रवक्त होनेवाले पेटोल और विमानों की देखरेख इत्याहि का क्या सम्मिलित है। कल संचालन व्यय का ५० प्रतिशत पैटोल विमान के कल-पर्जी और स्टीर में व्यय होता है जोर ४० प्रतिशत पारिभमिक तथा वेतन में । अस न्यायालय के निर्णय के अनुसार पारिश्रमिक और बेतन अधिक निर्णारित किये गये हैं और पेटोल, स्टार इत्यादि के न्यय में वृद्धि हवाई कम्यनियों की शक्ति के बाहर है। संभालन न्यय अधिक होने का एक कारण तो सरकार की नीति का दोष है श्रीर कह दोप उन परिश्वितयों का है जिन पर प्रवाई क्रेनियों का कोर्ट नियंश्रम नहीं और इसके लिए कम्पनियों की दांधी भी नहीं ठहराया जा सकता है. (2) डवाई कम्पनियों की सक्या पातागत को देखते हुए आवश्यकता से अधिक है, इस कारण किसी भी कम्पनी को पर्याप्त कार्य नहीं प्राप्त होता । इस दोष के लिए हवाई यातायात लाइसेन्सिंग बोर्ड उत्तरदायी है । बोर्ड में क्रानेक कामियों को उद्योग चालु करने की श्रानुमति दी और आवश्यकता का . ध्यान रखे विना विमानों की संख्या बढाने दी: (३) कम्पनियों की फार्यक्रमता को देखते हुए कार्य पर्यास नहीं है परन्तु यह व्यवसाय ऐसा है जिसमें कुछ विमान चालको, इझी नयरों और देकनी शयनी को नियुक्त करना पहता है। इसके फलस्वरूप कम्पनियों को आवश्यकता से आधिक कर्मचारियों का भार यहन करना पहता है: (४) किराये श्रोग माहे की जो न्यनतम श्रीर श्रधिकतम दरें सरकार ने सिश्चित कर दी है वह पर्यास नहीं हैं। प्रति यात्री से प्रत्येक मील के लिए द्याधिक से श्राधिक ४ श्राना किराया वसल किया जा सकता है परन्त रात में चलनेवाली बाक सर्विस के लिए किराये की दर २% ज्ञाना प्रति भील है। यह किराया भार-लीय वायपान कम्पनी क व्यय से बहुत कम है। यदि एक विमान पूर्ण वर्ष में १५०० घरटे चलाया जाय तो प्रति घरटे का स्टेन्डर्ड ज्यय भूद्ध कपया होता है। इसलिए प्रत्येक सीट का प्रांत मील का किराया विमान की ७ प्रतिशत जगह भरने

तालिका नं० ? ग्राममंत्रित भारतीय इवाई मेवाओं के त्र्यांकटे

वर्ष	यात्रा मीली में (दस- लाख मे)	याजियों की संख्या	यातायात माल की मात्रा (दस लाख पैंब में)	डाक की मात्रा (दर्स लाख पींड में)			
- 1284	४.स.६	रेण्यर्यर	\$.EE	5.0\$			
1880	€-3€	₹५४६६०	ય્ર.દ્દપ્	6,40			
1575	્કર-દ્ય	<b>३</b> ४११⊏६	27.55	6.4⊏			
\$ <b>8</b> 48	<b>१५</b> °१+	इसक्रइस	२२'५०	¥.°\$			
१९५०	र⊏•६०	<b>४५१८</b> ६६	50 02	द <b>ःइ</b> ६			
१६५१	१६ ५०	MEYER	<b>=७</b> °६६	७-१⊏			
१६५२	\$6.44	8j&k≥•	€£.0.A	ج٠ <b>١</b> ج ِ			
<b>\$</b> E4. <b>\$</b>	₹€:२०	X+3662	८४:८२	E,24			
8848	₹8"८#	2.546A	द६.८६	१०-६७			
<b>የ</b> ደሂሂ	55.50	¥4€000	<b>६८.</b> ५०	११७४म			
<i>૧૯૫૬</i>	२१-४८	446०००	६६.५३	१२"६६			
1840	<b>5</b> \$.\$8	488000	30.65	\$ \$ .E.R.			
From surface L and security with a second contract of a second of							

के आधार पर ४६ आना होना चाहिए। चूँकि किराया कम है इसलिए हवाई

कम्पनियों को हानि होना स्वामाविक ही है।

राष्ट्रीयकरण के वस्तात् हवाई सेवाछो कीश्यित में बहुत सुवार हुआ है। उदने का विस्तार रहभू को रहन करोड़ मी० से बहुकर रहभू को २३३५ करोड़ भील हो मचा १ मेल तथा चालियों की सच्चा भी नहीं है। मेल की माना रहभू में १०६७ करोड़ पींट यी जो कि रहभू में बहु कर ररहभू करोड़ पींट हो गई और यात्रियों की संख्या जो कि रहभू में भ्रश्यभ्य थी बहु कर ररभक्ष में प्र£४००० हो गई। लादने वाले साल की माना १९५६ में ६६२ १ करोड़ पींड थी जो कि १६५७ में थोड़ा घट गई और ८५० ६ करोड़ पींड हो गई। इस उन्नित का खेशतः कारखा खापकी जिनासकारी प्रतिहान्द्रता का समाप्त हो जाना तथा कुशना संगठन रहा है जो कि कारपीरेशन की ब्यवस्था के कारख समय हो सका है, खोर खेशतः औथोगिक और आधिक विकास रहा है जिसके कारण कार्य सेमाओं को खिलक सींग की गई हैं।

दोनों एवर कारपोरेशनों ने बहुत ही सन्तोपजनक उजति की है। उन्होंने कार्य-तेज बहुत परिकार के हैं। "वे कारपोशन कार्य-तेज बहुत में सिकार परान की हैं। "वे कारपोशन अपनी वायुपान संबन्धों कार्यों के एक कि उनके कुश्तक संगठन में स्थार परिकार के प्रतिकार का प्रतिकार के प्रतिकार का प्रतिकार का प्रतिकार का प्रतिकार का अपने का प्रतिकार के प्रत

हपिडयन एक्षर लाइन्छ कारपोरेशन का कुल कार्य-वेज सीन भागों में दिमाजित कर दिया गया है। प्रत्येक भाग एक भैनेजर के क्षिकार में है और बम्बई, कलकता और देहली के किसी न किसी खड़ है से नियंत्रित होगा! खाईक ए सीं को निरन्तर थाटा हो रहा है। १६५४-५५ में इस चार्ट की एक्स ६०'१५ लाख क्या, १६५५-५६ में ११६'४० लाख कर क्षीर १६५६-५७ में १०८'६६ वया थी। परन्तु १७के विपरीत एसर इन्डिया इन्टरनेश्मल को निरन्तर लाम होता रहा है। खाई० ए० सीं के याटे का कारख श्रंशतः कमेवारियों को क्षर्यांक एएया का होना है तथा श्रंशतः विषय की श्रस्थिक लागत कीर वे करिनाइयों है, जो इसे उन प्राइवेट कम्पनियों से विलो थी जिन्हें इसने से लिया था।

ह्वाई भाड़ा—अपनी आषिक स्थित को सुधारते के लिये तथा हानि बचाने के लिये ए० आई० थी० ने अपने भाड़े को दर में वृद्धि की घोषणा १५ जुत, १६५८ से एआ ट्रान्यार्ट काउन्सिल की सलाह के आनुधार की। किसी-किसी मार्ग के भाड़े में वृद्धि २०% हुई है और अब नथई से कलक के लिया गानाय २२० ठ० के २५२ ६० हो गया है। इस माड़े की वृद्धि से ए० आई० सी० को १० लाख सपने बार्षिक आविर्तिक आव होगी। इससे इसाई सेवा पर लगाये टेक्स के कारण तथा पेट्रोल पर लगाये टेक्स तथा अन्य टेक्सो के कारण हवाई सेवा की लागत में बुद्धि का प्रमाव धटाया का सकेगा—

ए ब्राई० सी॰ के लिये एक्सर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल ने हवाई भाड़े में स्टिकी निवारिश की और निम्न देशें का सफाब दिया ॥

मील		प्रति मील प्रति यात्री भाड़ा अपना पाई में
१ से ३० तक	***	•—-ξ <del>—</del> -ξ
<b>३१ से १००</b> तक	***	o
१०१ से २०० तक	••	3-4-6
२०१ से ५०० तक	***	•¥Ę
५०१ से ६०० तक	***	•-8\$
६०० से ऊपर	•••	•—-Y—- •

काउल्यक्त की विकारिया का आधार—"आर्थिक इन्टिकोया से आधिकतम संख्या में यात्रियों को आधिक काम में आते वाले मार्थों की तथा का प्रयोग करने का प्रोस्ताहन देना था ताकि कम प्रयोग में लाये जाने वाले मार्गों से होने वालें थारे के कारता को सेवा की लागत और आय में अन्तर शैला या वह न रहे और हवाई यात्रा के लाभों के फाहचा लोगों के मन में हवाई यात्रा करने की हब्धा स्थायी कर से उत्पन्न हो जाय। १० आधिक अच्छा होता पदि सरकार देन्सों की मात्रा कम करके उनकी शहायता करती और कारपोरेयन अपना खर्च कम करने का प्रयस्त करते। हवाई यात्रा के भाड़े के बढ़ वाने से उसकी समीप्रदात के घट जाने का भय है। एयर ट्रान्सपेट काउन्सिल की अस्पर्यस्थक रिपोर्ट ने भी यह संकेत किया है कि, "भारत में हवाई यात्रा की ऊँची रर्ध के कारता हवाई यात्रा के प्रति आकर्षण के नष्ट होने का भय है और इस बात की आराह्मा है कि कोग बहुत हवडी मात्रा में हवाई वहाजी द्वारा यात्रा के स्थान पर रेल द्वारा यात्रा करना असिक पुरुष्ठ करने लारेंगे।"

योजना के अन्तर्गत—पयम गोजना के अन्तर्गत बाबुरान कारपोरेशन के निमंत हम्म कराइ कावा का ज्यव नियत किया गया था। पर वास्तव में प्रथम गोजना में रूम्म करोड़ क्या ज्यव किया गया था जिसमें ह करोड़ कर्यों की रक्त एवर काक्ट खरीदने के लिये सम्मिलित थी। कुछ धन की मात्रा भूमि पर सातमात के साधन खरीदने, बर्तमान दम्बरी के सुधार तथा नये दस्तरों के खोलने पर मी क्या की गई थी। द्वितीय योजना में ३०% करोड़ रुपये ज्यय किसे जाने की ज्यवस्था की गई है जिसमें से १६ करोड़ रुपया तो इन्डियन एखर लाइन्ट कारपोरेशन पर श्रीर १४% करोड़ एसर इन्डिया इन्टरनेशनल पर ज्यय किया जायगा। ज्यय के मुख्य शीर्यक निम्न हैं:---

करोड रुपये में 4.58 मुक्रावजे का चुकाना 84.3X प्रश्नार क्राफ्टो का क्रय इन्डियन एग्रर लाइन्स के कार्य में डानि 10.00 इन्डियन एश्चर लाइन्स के दफ्तर और कर्मचारियों के ज्ञावास 640 प्रश्नर इन्डिया इन्टरनेशनल के कारखाने का विस्तार 9 - 2 4 0.49 इन्डियन एश्चर लाहन्स के श्चावश्यक सामान एश्चर इन्डिया इन्टरनेशनल के ऋग्यपनी का चकाना 90.0 30°43

हिल्लयन एक्टर लाइन्स के बेहे को आधुनिक बनाने के निमित्त ब्यय का प्रकार किया जा रहा है। कारवोरेशन ने ५ वाई काउन्टों के क्रय करने के लिए प्रथम योजना में ही आर्क्टर दे रक्का था और आशा की वाली है कि रहप् ७ के मध्य तक वे आ जावेंगे शीर अन्य जहांनों के क्रय करने के लिये धार्डर दिने जाने के सम्यव्य में खानशीन की जा रही है। इन्डिया इन्टरनेशनल के लिए यह व्यवस्था की गई है कि कुछ ट्यों-पान या वेट एक्टर काएन बढ़ी हुई माँग को पूर्ण करने के लिया आतिनेक सेवा के लिये क्रय किए जावें। इसाई सेवाओं के विस्तार के कार्यक्रम की निश्चित करते समय अतिनेकों बालों का ध्यान में रखना आवश्यक होगा वैके कि क्रय किए जाने वो सुर्था कुछ एक्टर की कुछ एक्टर के सिक्ट कि सेवाओं के प्रकार कार्यक्रम की किए यह में रखना आवश्यक होगा वैके कि क्रय किए कोने या होने सेवाओं की सुर्या को स्वार की कुछ एकटा, किराने-मोंड की दर, धातन की कुछ एकटा, हिराने-मोंड की दर, धातन की कुछ एकटा, होने रोकने की समावना, तेयाओं की सुरखा, और देश के सभी भागों को कुशल ध्याई सेवा स्थार एक दर्य से सम्बन्धित कर देने की आवश्यक्ता इस्पादि।

#### छाध्याय ३८

#### यातायात का परस्पर सम्बन्ध और नियोजन

भारतीय बाढायाव व्यवस्था में सुसम्बन्ध स्थापित करने झीर उसका नियोजन करने की दृष्टि से बाढायात की सभी प्रकार की सुविधाओं का प्रसार होना लाहिए, गातायात के विभिन्न साधनों में होने वाली अनुसित प्रतियोगिता को रोकना लाहिए और उपभोक्ता के लिए यातायात के क्यय को कम किया नाना जाविए।

किसी भी देश के यातायात की सुविधा में बृद्धि का उनके और्योगिक और झार्थिक विकास से निकट समस्य होता है। देश के झार्थिक विकास के लिए यह झानस्यक है कि उनमें यातायात की सुविधा वयांत हो, स्तरी हों मितायाता की सुविधा वयांत हो, स्तरी हो और यातायात की गति तीम हो। उद्योगों के लिए यातायात कर कर उत्पादन का महत्वपूर्ण झंग है इस्लिए उद्योगों का क्रम्य घटाने के लिए यातायात का क्रम्य पदाने की अत्यस्य हो हो। उत्योगों की प्रतियोगिता शक्ति कहेंगी और माल का उत्यागों में बहेगा। किसों भी देश की प्रतियोगिता शक्ति कहेंगी और माल का उत्यागों में बहेगा। किसों भी देश की प्रतियोगिता शक्ति से उत्यागों की स्वयस्था, रेलले, उदकी और इत्यर्द व्यर्द वहांगी तथा कलायान कम्मनिमी की किराया एवं भाशा नीति और उन्येगी पिक प्रकार के सामानों के यातायात की धुविधा का विरोध योग होता हैं। यदि यातायात नीति दोषपूर्ण है तो उत्योगों का स्वानीकस्था भी रोपपुर्ण होगा। यातायात पर पेनल उत्योगों का विकास निर्मेर नहीं करता है किन्तु और्योगिक विकास के प्रकार पर मी यातायात का प्रकार और उनका विकास निर्मेर करता है।

पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि आगामी कुछ वर्षों में देश में

खायात्र का उत्पादन बहुन से श्रीर चिन्ही में रखायनिक खाद का श्रीक उत्पादन होने से इन वस्तुओं का श्रायात कम करना पड़ेगा, जिवके कारख मन्दरगाहों से इन वस्तुओं को देश के खिमश्र मार्गों में पहुँचाने के लिए यावायात की कम श्रायहरकता होगी श्रीर ऐसी स्थिति में देश के श्रन्दर हुए उत्पादन की नियत स्थानों सक पहुँचाने के लिए यावायात को श्रम्यक प्रदूर हुए उत्पादन को नियत स्थानों सक पहुँचाने के लिए यावायात को श्रम्यक में वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि श्रीर राजमंगपुर के श्रिमेट के कारखाने से विचन श्रम्य मिन्नेट करनी के प्रवाद के उत्पादन कानमा कर दिवा है की संववचाडा में स्थित जानम मिने करना के प्रवाद से उपमोग के के स्थान के प्रवाद से अपना को श्रायाहन करने का मुराय की मौग कम हो जायां ने श्रमा श्रीर होने के कलस्वकर्य यावायात की मुराया की मौग कम हो जायां ने श्रमा श्रीर होने के कारखान के स्थान करने का मामा यह होगा कि यातायात की मुरायाओं को बढ़ाने की मौग कम हो जायां होता। इखालप यह श्रावस्था का स्थान की स्थान श्रीर हिम्म करने का प्रवाद की सुविधाओं को बढ़ाने के कारखीं का पता स्थाया आप श्रीर (व) यावायात की सुवधाओं को बढ़ाने के कारखीं का पता स्थाया आप श्रीर (व) यावायात की सुवधाओं को बढ़ाने के कारखीं का पता स्थाया आप श्रीर (व) यावायात की सुवधाओं को बढ़ाने के कारखीं का पता स्थाया आप श्रीर (व) यावायात की सुवधाओं का बढ़ाने के कारखीं का पता स्थाया आप श्रीर (व) यावायात की सुवधाओं को बढ़ाने के कारखीं का पता स्थाया आप श्रीर (व) यावायात की सुवधाओं को बढ़ाने के कारखीं का पता स्थाया आप श्रीर (व) यावायात की सुवधाओं का सुवसा वाय (व) सुवसा का सुवसा का सुवसा का सुवसा का सुवसा का सुवसा का सुवसा सुवसा का सुवसा का सुवसा स

भारत में वास्तविक कठिनाई यह है कि पंचवर्षीय योजना के होते हुए भी विकास की गति बहुत चीमी है। पंचवर्षीय योजना के समास हो जाने के पक्षात् भी शतायात की मुविषाएँ देश की व्यावश्यकता को देखते हुए कम ही रहेंगी। बाताबात की मुविषा में तीन गति से प्रवित न होने के क्षानेक कारण है;

(१) विच का अभाव है, इस कारण अधिक वहकों का निर्माण करने में, अधिक रेलने लाहन मिछाने में और रेलने के लिए अधिक रोलिंग स्टाक कर करने में, इक्ष्मों के लिए ओरत तथा वस करन करने में और विमान तथा जलवानों को कर्म करने में अपेर विमान तथा जलवानों को क्षम करने के लिए औरत तथा वस करन करने पहना है। केनल प्रधार वोजना की माँग पूर्ण करने के लिए ही नहीं किन्दु वर्तमान में चालू गाड़ियों, बयों और जलवानों को बदलने के लिए, जो कि प्रायः वेकार हो चुके हैं, अधिक गाड़ियों, बयों और जलवानों की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने सभी उपलब्ध विस्त स्थानों की नावायात की वर्तमान सिर्मित के सुधार में और उसके अधार में सुसम्बद उपाय वे व्यव करना चाहिए। वृत्यों करिनाई यह है ति यातायात के सावायों के लिए आवश्यक सामधी के मूल्य बहुत बड़े हुए हैं। यदि विक्त आवश्यकता पूर्ण मो हो जाय तब भी उससे इतनी अधिक मूल्यों पर सभी आवश्यक सामधी नहीं क्य की जा सकती। वित्त स्थान और सामानों का अधिक मूल्य होने के कारण भारत में यातायात की स्रोवण के अधार में बाया उत्तम हो जाती है।

(२) सहक धनाने और रेलवे लाइन विद्याने के लिए आवश्यक सामान का अमान है। इसके साथ ही मोटरों, रेलों के डिब्बों, इलानों, जलयानों, विमानों और इनके अलग कहा दुवों तथा स्टीर का भी बहुत अभाव है। इनमें से अधि-कोश के लिए मारत के विदेशों से आयात पर निर्मार करना पढ़ता है। इधर कुछ वरों से मारत में इलानों, जलयानों इत्यादि के उत्यादन में नृद्धि हुई है परन्तु अभी बहुत लम्मा मार्ग तय करना है। भारतीय यातायत के विकास की समस्या का (अ) सहक अधवा रेल के निर्माण के निष् आवश्यक सामग्री का उत्यादन करनेवाले उद्योगों के विकास से और (व) ओटर तथा जलयानों का निर्माण करनेवाले उद्योगों के विकास से सुद्दा सदस्य है। उद्यागों के वोरे-पोर विकास होने से यातायान की सुध्या की अगति भी सीमित हो गई है।

(३) इराक कारीगरों, इजीनियरों, विमान चालको इत्यादि का बहुत ग्राभाव है, यातायात की व्यवस्था का विकास करने के लिए इनका छभाद नहीं होना चाहिए। इसिकाए इनकी सक्सा की बहुत अधिक बहाने की आवस्यकता है। उपकार ने कारीगरी की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की है और यातायात की स्थिपकों का प्रशाद उसी गति से कोग जिस गति ने कारीगरों और अन्य

कुशल कर्मचारियों के अभाव की पृति होगी।

यातायात में ससम्बन्ध स्थापित करने की नीति का उद्देश्य है कि उपभोक्ता को यातायात में कम से कम ब्यय करना पड़े। इसका तर्कशंगत परिणाम यह निकला कि इमें बालाबात के अने सभी शाधनों को समाप्त कर नवे सामनों की उपयोग करना पढ़ेगा जो उपयुक्त नहीं हैं, समय की साँग पूर्ण नहीं कर सकते हैं और पुराने हैं। उपभोक्ता के लिए सहक बातायात रेतवे की अपेजा अभिक सला और सविधायनक है क्योंकि शहकों से ब्रासपास के सभी चेत्र लाभ उठा सकते हैं और रेलवे स्टेशन तक माल से जाने और वहाँ से लाने में जो अनावश्यक ब्यय होता है उसकी बचत हो जाती है। इसका तासर्य यह है कि सहक यातायात के प्रसार ग्रीर विकास से या तो। रेल यातायात बन्द हो जायगा या उसका न्देत्र संक्रांचत हो जायगा। यदि मोटर, द्रव और वर्से बैलगाडियों ने अधिक बचत बाले और तीक्ष्मति चल सकने वाले साधन हैं तो इसका ताल्पर्य है कि नगरों ग्रीर कस्त्रों में वैलगाड़ियों का श्रास्तत्व ही रह बायगा। यदि भाप से चलनेवाले जलयान हवा से चलाने वासे जलयानो से ऋषिक बचत वाले हैं तो हवा में चलने वाले जलयानों की ग्रावश्यकता ही नहीं रह बाती। परन्त व्यवहारिक चेत्र में इस प्रकार का तीव परिवर्तन न तो संभव है और न इसकी सलाइ दो जा सकती है क्योंकि (१) पूँची इस समय ऐसे सामनों में लगी हुई है जो आधुनिक इस रियति को व्यान में रखते हुए इस दिशा में अवेलिस नीति यह होगी कि यसेमान के यातायात के छापनो को प्रचलित रखा जाय और (ब्र) कार्य को ध्रीनियोजित करके, कुछ जामनों के अव्यविक कार्य भार को इक्ल करके और स्थाने सामनों के उपयुक्त कार्यक कार्यक कार्यक विकास कार्यका कर कर कार्यक का दुस्त्योग बचाया जाय, (व) यातायात से विभिन्न सामनों की परस्पर अर्जाचन प्रतियोगिता को रोका नाय, साथ ही एक ही प्रकार के साचन की विभिन्न इकाइयों की अनुचित प्रतियोगिता को समाप्त किया नाय, और (व) रेखने, सक्क, जस पातायात तथा इसाई कंपनियों को उचित साम के साथ ही साथ उपभोक्ताओं के किये यातायात सस्ता किया नाय।

वर्तमान में रोडवेन और रेलवे, रेलवे और जल यातायात और रेलवे समा वायु यातायात में तीन प्रतियोगिया नहीं है। यातायात के समी साधमों का अभाव है और सभी साधमों के कार्यवेज पर्याप्त हैं दर्शालय कुछ अपवादों के छिए रूप में कोई प्रतियोगिया नहीं है। इसके साध छोएकर स्पापार हिपयाने के लिए इममें कोई प्रतियोगिया नहीं है। इसके साध की विकास साधमों का किराया इस मकार निष्मित कियागाया है कि पतियोगिया नहीं हो सकती है। सरकारी वसें पर्याप्ताम में ममई तथा उत्तर प्रदेश में भिय-भिन्न किराया समुख्या हो मम्बई का किराया द स्वाद मील दें और उत्तर प्रदेश की पहुंच में मिल मिल किराया साधाया या का माझी से रूप मील तक कमसा प्रदेश की रहें पाई मिलिसीन है। वायुवान का किराया प्राप्त भाना प्रति भील है और रात की अपक स्वीवार है जिसाया पर्य अपना प्रति भील है और रात की अपक स्वीवार है किराया प्राप्त भाना प्रति भील है और रात की अपक स्वीवार है किराया प्राप्त भाना कि सील है जैरियन के भी अपक

अंगो का किराया २६ से २६ आना मित भील है। बर्गे और रेलों में कुछ दोत्रों में अवश्य प्रतियोगिता चलती है पर बड़े पैमाने पर कोई अनुचित प्रतियोगिता नहीं है। वायुपान से यात्रा अभी अवश्य कुछ महंगी है और रेलवे यात्रा ते कुछ अधिक भयपद भी है। कुछ उच्च अंशों के यात्रियों के अतिरिक्त वायु यात्रापास से रेलवे को कुछ हानि नहीं है परनु मित्रव्य में वैदे-वैदे सक्क और अप भयपद होसा जायगा वैदे-वैदे रेलवे के प्रतियोगिता भी बहती जायगी।

भारत के कुछ भागों में जलवानों द्वारा तदीव पातायात में और रेल वे पातायात में अतियोगिया चलती है और देश के विमानों की तटीय ज्यायार में अतियोगिया चलती है वरन्सु तटीय जलयान स्थापार को नियमित कर देने से यह प्रतियोगिया चलती है वरन्सु तटीय जलयान स्थापार को नियमित कर देने से यह प्रतियोगिया चलते हैं। सविष्य में युत्त प्रतियोगिया चढ़ने की समायना है, परन्तु हमाने अनुचित प्रतियोगिया बढ़ने का कोई कारण नहीं है। भिष्य में रेल वे छाइन से समायना इत्तर कि उनन्ते (भिष्मत बन्दरागाई में जल यातायात की आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके यातायात की विमान स्थानों के बीच अपवश्यक साथनों के नीच अपवश्यक प्रशास कर के की पूर्व सम्भावना है। रेलने तथा जल यातायात के वीच अचित समायन की स्थान मार्गि गई है जिस में अपवश्यक प्रतियोगिया करने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसमें अपवश्यक की गई है कि मैं मालीर बन्दर से रेस सम्बन्ध विकाममासुर होते हुए महाय से सम्भन्य किया लाय।

यदि यातायात के सभी वाचनी का राष्ट्रीकर का निया जाय तो हममे

पाद पातापात क सभी शांचनी का राष्ट्रकरण क्यां ता दा ता हमम परसर दलित सम्बन्ध स्थापित कर सकता सुराम हो जानगा। यदि सभी साममं की स्थामी स्टब्सर हो श्रीर वही इनका चलाये तो सकको को जोकने झरेर एक स्थान पर कई प्रकार के गांवागात उपलब्ध होने इत्यादि में व्यर्थ इपया नहीं लगाना पड़ेगा। निश्री उद्योग होने पर ऐका खालकृष्ण हो जाता है। उरकार ने सक्क मातापात का एफ सीमित तेल में राष्ट्रीमकरण किया है जिसके कारण इन्हें होगों में रोडनेल झोर रेलने के मध्य कोई अनुनिव प्रतियोगिता नहीं है। राष्ट्रीय-करण किये हुने सफ शांगागात से रेलने को सहायता मिलती है। यह एक कें विभिन्न चेली को रेलने मार्ग से सम्बन्धित करते और रोडनेश वर्तिय को निश्चित दोन में एक विशेष दूरी तक सीमत करत और रोडनेश वर्तिय कें उन सक्को पर चालू करके जहीं रोलने यातायात की हानिया नहीं है यह परियाम निकला है। रेलों से यात्रियों की सुविधा का प्रमन्य बढ़ा है और किराये में भी वृद्धि हुदें है श्रीर इससे टोनों में अनुचिव प्रतियोगिता की हानियों को समय्य कर दिया गया है। यदार राष्ट्रीकरण कर देने से अनुभित प्रतियोगिता तो समात की जा सकती है परन्तु यह ज्यनस्था सभी स्थितियों में मुनिकानक सिद्ध नहीं हो सकती। मारतीय रेलों और वायुवान कम्पनियों का कुछ बोड़े छोटे मार्गों को छोड़ कर पूरी तरह राष्ट्रीकरण किया जा सुका है और सड़क यातायात का बहुत सा मारा पी राज्य सरकारों के चुकी हैं, परन्तु कुछ नेत्रों में सड़क यातायात और पूरा नकें यातायात अमी मुत्रा ने हें पर यह सा मारा प्रतियोगित की स्था में हैं। यातायात के सभी सामर्गों का राष्ट्रीकरण करना सम्मय नहीं है क्योंकि (१) आवश्यक कर्मवारियों का अभाव है और (२) हानि होने का कर है। यह हानि विशेषकर अस यातायात में अधिक है। सकता है स्था के मिन्स्य के समी सा प्रतियोगित की स्था का स्था कि स्था है। सह कहा है स्था है। सह कहा है स्था के स्था है। इस कहा अस्तियोगिता की समस्य मुक्त काई सा सकता है। यह कहा अस्तियोगिता की समस्य मुक्त काई की स्था का सकती है। इसके साथ ही इससे एकाधिकार के दोय भी उत्यन्त्र सकते हैं जैसे उपयोगित के हिलों की उपेता, कार्य व्यय में दृक्ति और अकुशल कार्य। यदि हानिकारक प्रतियोगिता को समस्य हो आर्थ तो इस समस्यार जन्म हो अप तो है। इसके साथ ही इससे एकाधिकार के दोय भी उत्यन्त्र सकता है। यदि स्थानिकारक प्रतियोगिता को समस्य करने से गई समस्यार उत्यन हो जार तो हस समस्य स्थान का ती समस्य सा स्थानिकारक प्रतियोगिता को समस्य कार सकता हो साथ स्थान समस्य सा स्थानिकारक मारियोगिता को समा सकता है। स्थान करने से गई समस्यार उत्यन हो जार तो हस समस्य स्थान समस्य सा सा सकता।

यानायात का पूर्ण राष्ट्रीकरण व हो सकने पर भी यानायात के विभिन्न स्थापों में निम्मिलिलत उपायों से परस्कर प्राचार व स्वास्त्र के कार्यचेत्र को निर्मार कर कार्यचेत्र को निर्मार कर कार्यचेत्र को निर्मार कर कार्यचेत्र को निर्मार कर कर के ब्रीर क्लिम्म साधनों के अधिकतम और स्पृतना किराये की दर निर्मेशत करके और विभिन्न साधनों के स्वास्त्र कार के और स्पृतना किराये को दर निर्मेशत करके और विभिन्न साधनां के मानायात की सुविधाओं को निर्मेशत करके; (२) यानायात के किम्म साधनों के कार्य के लिय और उनमें उचित्र सम्बन्ध स्थापित कर के विभे केन्द्रीय यानायात की विभिन्न साधनों के क्षायं स्थापात कर विभिन्न साधनों के कार्य के विभन्न साधनों के कार्य स्थापित कर के। यानायात के विभिन्न साधनों के क्षाय उपभोक्ताओं के हिंतों की केन्द्र कार्य द्वारा ही रखा की जा सकती है। इस्ते किराये की दरों में यटने-बहुने की सम्मायना समान हो सकती है और जनता को अध्विधार हो सकती है परन्तु यह किटाइयाँ प्रयोग अधिकार दिये जाने पर क्षार समान सीत से की हरों के कार्य कर सकने के लिए न्यापक क्षेत्र देने पर राज्य यानायात परिषद इर कर सकती है।

 प्रयम पंचवर्षीय योजना में ५५७ करोड़ रुपया वातायात श्रीर उंचार विभाग के लिये नियत किया गया था। यह घन योजना के कुल न्यम का २३.६%
 या। दितीय योजना के अन्तर्गत १३८५ करोड़ रुपया, जो कि कुल योजना के स्वयं का रहाह % है, यातायात श्रीर संचार विभाग पर स्वयं करने के लिये नियत किया गया है। इस १३८% करोड़ स्वयं में से रेलवे, सहक, सहक गातायात, मन्दरगाही, जल यातायात और इसाई गातायात पर सम्बर्ध १०० करोड़ (कुल स्वयं का १८८%), १५६ करोड़ (१९%), १७ करोड़ (०४%), १५ करोड़ (०९%), १५ करोड़ (०९%), भू करोड़ (०९%) और १५ करोड़ (०९%) मा किया गाया। प्रथम योजना के अन्तर्गत भू५७ करोड़ स्वयं के कुल स्वयं में से इन्हों शर्पिकों पर समग्र १५८% है। १९० करोड़ (४५%), १२ करोड़ (०५%), १५० करोड़ (४५%), १२ करोड़ (०५%), ११० करोड़ (४५%), ११० करोड़ स्वयं है। अपना है अपना (१०%) स्वयं स्वयं परा परा परा परा परा है। इस अपना है और अपना साच है कि कुल स्वयं दिया गया है।

	१९५०-५१ की स्थिति	१९५५-५६ मे श्रनुमानित रिथति	१९६०-६१ तक ध्येय
रेलबे—		(	
(१) पैसेन्जर गाहियाँ (मील दस साख में)	દેપ	१०८	१२४
(२) माल को लादा गया(दस लाख दनी मे)	13	१२०	<b>१</b> ६२
सङ्क⊸-			
(१) राष्ट्रीय राजपय (हजार मीलों में)	१२.३	3.22	₹₹"==
(२) सरफेरड रोड्स (इनार मीलो मे)	8.9	१०७	\$ 54
जद्दाज	1	1	1
(१) तटीय श्रीर पडोसी से सम्बन्धित		1	
देग्करी को सम्मिलित करते हुये	]	1	Ì
(लाख जी, श्रार, टी.)	5.5	₹•₹	A. 3
(२) समुद्र पार ट्रैम्प टनेल की सम्मिलिस			1
करते हुये (लाख जी. श्रार. टी.)	8-0	₹,€	8.0
<b>बन्दरगाह</b> —		1	
सेवा वरने की शक्ति (दस लाख टनों में)	₹0	र्भ:०१	३२५

क्तर स्थि यथे ब्रॉक्ट्रों से यह बात होता है कि दिलीय योजना के ब्रन्त-यह सर्वतेम्प्रकी विकास का प्रयत्न किया जायगा। १९५५.यह की तुलना में सब से श्रीयन प्रतिसत वृद्धि १९६०-६१ में समझ पार की ब्रन्त यातायात के समस्य में की जायरी! जल वानायात के सम्बन्ध में ६८%, रेलवे में ६५%, तटीय जल यातायात में ३५% और सन्दरमाही पर माल उतारने चढ़ाने की शक्ति में ३०% की ब्रोब की जायबी!

प्रथम पंचवर्षीय योजना का मध्य ध्येय यातायात सम्बन्ध में यह था कि यथासम्मय गृत १० वर्षों से शात्यक्षिक कार्य में श्राने वाले प्रसाधनों को बदल कर नया कर दिया आया। रेलचे के सम्बन्ध में यह कार्य बहुत कठिन था। जल यातायात, बन्दरगाहों, प्रकाशस्तम्यों, नाय यातायात आदि के सम्बन्ध में भी इस कार्य के लिए बहुत बड़ी धनराशि नियत करना बाबश्यक थी। प्रथम योजना काल में क्योंकि कांव और उद्योगों की उत्पत्ति में बढ़ि हो गई भी इसलिये याता-यात की सविधा के स्वयाव का समझव विशेषकर बोजना के तीसरे वर्ष से होने समा था। इस स्थित का सम्मालने के लिये व्यतिरिक्त धन का अनुमान रेल्वे. एउकी, जन याताथात, नदियों और वाय बातायात के लिये किया गया और इनके विकास के कार्य-कम म भी बढ़ि की गई । देलवे के गत्रमानादि के कम का कार्य-कम बढाया गया श्रीर उन सेश्री में लाइने बढाने के लिये विशेष प्रयस्न किया गया जहाँ रेल बालावात की माँग ऋधिक थी। एक अन्तर्विभागीय अन्वेषणा वर्ग द्वारा पातायात के सभी साधनों के पारस्परिक विकास सम्बन्धी प्रश्न पर श्लीर मुख्यतः सडक यातायातः के विकास सम्बन्धी प्रकृतः पर जो बहती हुई माँग के हिसाब से बहत दिनों से विस्टहा हुआ था विचार किया गया । सहक यातायात के व्यक्तिगत भाग में विकास सम्बन्धी करिलाइयों को तर करने के लिये उपाय किये गए और साहसेन्स देने की जीति को आधिक जटार बनावा गया । मारतीय जल यातायास की सहायता के उपाय भी किये गये।

यातायात सापनों श्रीर उनके पारस्पारिक खामंत्रस्य के श्राविकतम विकास की श्रीर विशेष प्यान दिया गया है ताकि प्रत्येक अपने-अपने द्विन के कार्य को श्रूच्छे से अच्छे दक्क से पूर्ण कर उने । इस स्थिति का निष्कर्ष यह है कि आगामी पाँच वर्षों में कभी प्रकार के यातायात सापनों की माँग बहुत श्रविक बढ़ेगी, इसलिये यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रतिवर्ष यातायात श्रीर संचार के विकास के कार्य-क्रम पर विचार किया जाये ताकि कहाँ कहीं आवश्यक हो ऐसे उपायों को अपना मांचा नाव विवर्ष यातायात की कार्य-क्षाया नाव विवर्ष यातायात को कार्य-कार्य से श्रवायों के कार्य श्रीर कार्य से श्रवायों की श्राव्य से श्रवायों की श्राव्य की कार्य-कार्य से श्रव्य की स्थान से श्रव्य की स्थान से श्रव्य की स्थान से श्रव्य की स्थान स

### श्रम्याय ३६ प्रथम पंचवर्षीय योजना

नियोजन का तालायें यह है कि देश के उपलब्ध साधनों का नियमश्रह रूप में जपयोग किया जाय और इस दिशा में प्रगतिशील हिंदिकींग अपनाया जाय जिससे उत्पादन बढ़े. राष्ट्रीय लामाश बढ़े. रोजगार श्रीर सामाजिक कल्यास में कहि हो। इसके लिये यह अवस्थान है कि अपलब्ध साधनों की सारकाची थे काँच परल की जाय और राष्ट्रीय उत्पादन और आय में निर्धारित बृद्धि करने के लिये एक साधनों के उपयोग की गति को भी नियोजित किया जाय। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना १९५१-५२ में लागु हुई और १९५५-५६ तक पूरी हो गई। इस योजना पर ५ वर्ष में २,०६९ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। ब्यय की मात्र। निर्धारित करने में योजना द्यायोग ने इन बातों पर विचार किया कि (१) विकास की एक ऐसी प्रक्रिया का संमारंग किया जाय जिसके द्याधार पर भविष्य में ग्रीर बड़ी योजनाओं को कर्यान्वित (कया जा सके: (३) विकास कार्यक्रम को कार्योग्वित करने के लिए देश को कल कितने पायन उप-सन्ध हो एकते हैं; (३) विकास की गति और निजी तथा सरकारी चेत्र के धन्तर्गत साधनी की आवश्यकता के भीच निकट सम्बन्ध स्थापित हो, (४) योजना लाग होने के पर्ध वेस्टीय नथा राज्य सरकारों द्वारा श्चारम्भ की गई विकास योजनाओं को पराकिया जाय श्रीर (५) यह तथा देश विभाजन से देश की श्रव्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था की सुनियोजित आधार प्रदान किया जाए।

भारत की श्रामिक दियति में सबसे महत्वपूर्य थात यह है कि जनसंख्या में
प्रतिवर्ध १ है प्रतिशत की वृद्धि होती है | हर तस्य पर श्रीर देश के सभी उपलब्ध
साधनों पर दिवार करने के पश्चात् योजना श्रामोग ने यह व्यवस्था की है कि
१६७७ तक नर्षों में प्रति व्यक्ति की आय दूनी करने में कम समय लगेगा
परन्त भारत बीसे पिछड़े देश में हसमें श्रीदावर्षित अधिक समय लगेगा
परन्त भारत बीसे पिछड़े देश में हसमें श्रीदावर्षित अधिक समय लगेगा
परन्त भारत बीसे पिछड़े देश में हसमें श्रीदावर्षित अधिक समय लगेगा
परन्त भारत बीसे पिछड़े देश में हसमें श्रीदावर्षित अधिक समय लगेगा भ्योकि
देश में साधनों की कमी है, देकनिकल कुराखता का श्रमाय है और संगठन की
दियति कमनोर है । मारत में प्रति व्यक्ति श्राय दूनी करने के लिए श्रनेक पंचवर्षीय
योजनाश्रों की श्रावन्यकता पड़ेगी । सबसे महरायूर्ण बात यह है कि भारत सरकार
ने हस दिशा में कार्य आरम्म कर दिया है । समय के साथ कार्य की गति भी
नौर पकरती जायगी ।

पूंची निर्माण की गति—योजना आयोग ने यह माना है कि आधारमूत वर्ष १६६०-१६ में भारत की राष्ट्रीय आय ६,००० करोड़ रुपया थी और कुल राष्ट्रीय आप का और तत १ प्रतिशत वचत की जाती थी। इचका तात्रमं यह है कि १६५०-१६ में थारी जनता की कुल बचत ४५० करोड़ रुपया थी। यदि १६६५-५२ और १६५५-५६ के बीच मांत वर्ष २० मतिशत अतिरिक्त आय पूँजी निर्माण में लगा दी जाय, अर्थात मशीन रुप्यादि और काफी समय तक जलने वाले सामानी पर रुपया लगाया जाय नो पंचवर्षीय योजना के ग्रंत तक भारत की राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये एक बहु जायगा और बचत को दर भी ६ई मतिशत वार्षिक हो जायगी। १६५६-५६ में इस महार कुल ६०५ करोड़ चपया राष्ट्रीय वचत होगी। योजना आयोग ने बताया है कि इसके बाद १६६७-६६ में समात होने वाले १२ वर्षों में केवल २० मतिशत नहीं बल्कि ५० मतिशत अतिरिक्त राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष पूँजी निर्माण में लगाई जानी चारिये। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो १६७० तक प्रति व्यक्ति को आय (Per capita income) दो ग्रुनी हो जायगी।

त्राथमिकता का क्रम-राष्ट्रीय श्राय में उक्त-लिखित रृद्धि करने के लिए र्मातच्यक्ति की खाय दोग्नी करने के लिए संशोधित योजना में २,३५६ करोड़ रुपया विकास योजनाओं में ब्यय करने का निश्चय किया गया। योजना में भारतीय श्राधिक व्यवस्था को सरकारी तथा निजी उद्योग चेत्र में विभाजित किया गया है। सरकारी चेत्र में वह उद्योग सम्मिलत हैं जिनका मालिक स्वयं सरकार जिन पर केन्द्रीय या राज्य सरकार श्रथवा इन सरकारों के आधीन श्रधिकारियों का नियंत्रस है। निसी उद्योग स्तेत्र में वह उद्योग, वास्तिस स्रीर ब्यापार शामिस हैं जिनके मालिक उद्योगपति हैं, जिन पर उनका नियंत्रण है ग्रीर जिनका संचा-लन स्वयं इन्हीं उद्योगप्रतियों द्वारा द्वीता है। इन दोनों उद्योग देशों की समस्याएँ प्रायः समान है और दोनों को भेणियों में स्वच्ट विशेषताओं के आधार पर विभक्त नहीं किया जा सकता है। परन्तु शुविधाकी हिष्टि से पंचावर्षीय योजना में इन दोनों उद्योग चेत्रों पर प्रयक्त रूप से विचार किया गया है। सरकारी उद्योग चेत्र के लिए कल लागत की मात्रा नि । । रत कर ली गई है और इस चेत्र की वित्तीय द्यावश्यकता सरकार पूरी करती है स्नुत निजी उद्योग स्नेत्र के निर्धास्ति लक्ष्य के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ, न कह कर केवल सामान्य लक्ष्य सता दिया गया श्रीर इस लह्य की पूर्ति तथा खावश्यक वित्त लुटाने के लिए भी उद्योग लेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। सरकारी उद्योग चेत्र में खद्य की पूर्ति सरकार का प्रत्यत्त उत्तरदायित्व है परन्तु यही नात निजी उद्योग चेत्र में लागू नहीं होती

\$ 2E

है क्योंकि निजी उद्योग चेत्र में सरकार अप्रत्यक्त रूप से सहायता प्रदान करती और कारोबार के परिणामों का निरीक्षण करती रहती है। इसके मूल में यह विचार निश्चित है कि यदि निजी उद्योग चेत्र निर्धारित लक्ष्यों की पूर्त नहीं कर पाता है श्रीर उसकी प्रगति श्रपेत्तित गिन नहीं हो पाती है तो सरकारी उद्योग का कार्य चेत्र बह जायमा श्रीर सरकार इन निजी उद्याग चेत्र की विभिन्न इकाइयाँ का कार्य भार धीरे-धीरे स्वयं ग्रहण कर लेगी। कछ समय तक सरकारी श्रीर निजी चीत्र दोनों ही रहेगे।

पंचवर्षीय योजना के प्राइप में जो जलाई १९५१ में प्रकाशित किया गया या ग्रीर स्वयं पंचवर्षीय योजना में जो दिसम्बर १६५३ में संसद के सामने प्रस्तत की गुई थी क्रिपि विकास की प्राथमिकता दी गुई है खीर इसके शद यानायात तथा संचार. समाज सेवा कार्य और उद्योग को रखा गया है। पंचवर्षीय योजना की यदि योजना के प्रारूप से तलना की जाय तो पता चलेगा कि योजना के श्रंतिम रूप में उद्योग के महत्व को कुछ ऋषिक बढ़ा दिया गया है पर इससे योजनाका प्राथमिकताक्रम नहीं बदलता है। योजना के द्वांतिम रूप में किए. रिंचाई और दिजली की लागत कल लागत का ४३'२ प्रतिशत रखी गई. याता-यात तथा संचार की लागत २३ ६ प्रतिशत, समाज सेवा कार्यों पर ब्यय की भागत २२% प्रतिशत खीर उद्योग की लागत केरल ७% प्रतिशत रखी गई थी। योजना श्रायोग ने कृषि को श्राधिक सहत्व प्रदान करने के कारणों पर प्रकाश हाला है। आयोग का मत है कि खादाब और कच्चे माल के उत्पादन में पर्याप्त विक्र न होने से उद्योगों के तीन विकास की संमायना नहीं है। सबसे पहले यह ब्रावश्यक है कि श्राधिक स्थिति के मूल को इट किया जाय. कृषि चेत्र में पर्याप्त अतिरिक्त खाद्यान तथा कच्चा माल पैदा किया जाय श्रीर श्रन्य द्वेत्रों का कार्य आगो बहाने में उसका उपयोग किया जाय। इसी उद्देश्य के कारण कवि की प्राथमिकता प्रदान की गई है। छंशोधित योजना में यद्यपि कुल व्यय बहाकर २३५६ करोड रुपया कर दिया गया फिर भी प्राथमिकता के कम में कोई विशेष परिवर्तित नहीं किया गया है।

जहाँ तक श्रीद्योगिक चेत्र का सम्बन्ध है प्राथमिकता निर्घारित करते समय इन वातों पर विचार किया गया है कि (१) जूट श्रीर प्लाईवुड जैसे उद्योगों (Producer goods industries) की वर्तमान उत्पादन ग्रक्ति का प्ररा उपयोग किया जाय श्रीर उपभोग की वस्तुश्रों का उत्पादन करनेवाले उद्योगों, जैसे सुती कपड़ा, चीनी, साबुन और वनस्पति उद्योगों की भी वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय, (२) लोहा और इस्पात, एल्युमोनियम, िमंट रसायनिक खाद, मारी रसायनिक, मशीनों के ख्रीजारों इत्यादि उद्योगों की जरपादन शक्ति बढाई जाय, (३) उन श्रीबोगिक इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा किया जाय जिन पर काफी पुँजी लगाई जा चुकी है और (v) जिप्सम से गत्धक विशेष प्रकार के रेशम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक सामग्री, श्रीर श्रलीह धातश्रों के दुकड़ों का उत्पादन करने के लिये नये कारखाने स्थापित किये जायँ जिससे बढ़े और अत्यन्त महत्व के उद्योगों के लिए आवश्यक कदचे माल की परि की जा सके। प्राथमिकता का यह क्रम यह प्रकट करता है। कि उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया जायगा और किसी भी उद्योग के प्रति जनामीतना नहीं प्रयुक्ताची कावगी। शब्य प्रजीक काव्याने स्थापित कर सकते हैं परन्त कृषि के विपरीत उद्योगों का विकास पूर्णतया निजी उद्योग सेत्र के हाथों में स्रोह हिया गया है। कृषि तो सरकारी उद्योग सेश्र के श्रन्तगंस ह्याता है। पंच-वर्षीय योजना में ४२ उद्योगों के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और यह अनमान लगाया गया था कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पॉच वर्ष में कल २३३ करोड़ रुपया व्यय करना पढेगा। इसके साथ ही कारलानों के ज्ञाधनिकीकरण में और मशीनों को बदल में में १५० करोड़ क्या छीर व्यय होता । यदि इसमें चाल पॅली की रकम भी जोड़ दी जाय तो पता चलेगा कि पाँच वर्ष में नेवल उद्योग ही की विसीय ग्रावरणकता ७०७ करोड रुपये के बराबर होती। इस विसीय ग्रावरयकता की पूर्ति सरकार नहीं करेगी। इसके लिए निकी उद्योगों को स्वयं प्रयत्न करना पश्चेशा १

चित्त---योजना को उपल बनाने के लिए खबसे अहस्पपूर्ण बात यह है कि वित्तीय आवश्यकता पूरी करने में किसी प्रकार की बाधा न पहें। कृषि तथा श्रीयो- तिक सापनों का विकास करने के लिए बहुत बड़ी सात्रा में पूँची लगाने की आवश्यकता है। यदि वह पूँजी केये के अबदर ही प्राप्त नहीं होती तो हरके लिए से विदेशी लोतों की खहायता लेनी पड़ेगी। भारत की पंचवर्षीय योजना केन्द्रीय तथा लेनी की उपायता लेनी पड़ेगी। भारत की पंचवर्षीय योजना केन्द्रीय तथा राज्य वरकारों की वर्तमान आय में से चचत, आरतीय रेलवे की आप में से चचत, अरतीय का तथा के ने में बचत, अर्थ तथा जनता की बचत और विदेशी पूँची पर निर्मय करती है। योजना के क्या की पूर्व के लिए मारत के गैयह पावने, विदेशी महायता और अ्च्य पर भी पूरा विचार कर लिया गया है। इन चारे लाघनों का उपायेम कर लेने के बाद भी कुछ कभी द्वारा का विदेशी का अविदेश कर लगाकर या स्वदेशी बाबार ये अधिक मात्रा में अर्थ लेकर हम कभी की पूरा किया वागा परच्च यह देशा क्षत्र न हो सकता तो पंचवर्षीय योजना की लगात में इतनी रकम भी वसी कर दी आवश्यो।

योजना की कुल लागत २,०६६ करोड़ रुपया थी; बरकारी तथा निजी वचत से पीच वप में १,२५८ करोड़ रुपया प्राप्त होगा जबकि इन्हीं खोतों से योजना के मूल वप ११६५०-५१ में २२२ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। १,२५८ करोड़ रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सकारों और रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सकारों और तिये जजर की श्रतिरिक्त आय से प्राप्त होंगे और ५१८ करोड़ रुपया निजी बचत है । संशोधित योजना में बजद से प्राप्त होंगे और प्रतिकार वचत में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि आशा की जाती है कि ७४३ और ५१८ करोड़ रुपये कम्पार होगी। बढ़ी हुई लागत अधिकांश थादे के अर्थ प्रयन्थन द्वारा पूरी की जायां है लागत अधिकांश कार्य क्षार कर राव हुकर हो जाने से प्रतित होता है। यह आशा की जाती है कि पीयड़ पायने से प्राप्ति को विचाराधीन रखते हुवै यह कभी ७०१ करोड़ रुपये की रह जावगी।

योजना को फ्रांतिम रूप देने के पहले मारत को बिदेशों से महायता श्रीर श्रुण के १५६ करोक कपया मिला या। योजना खायोग ने इसे भी सम्मिलत कर लिया। योजना में यह व्यवस्था भी की गई थी कि घाटे का बजट बहुतकर २६० करोड़ करवा की श्रीर पूर्ति की जाय। इसके बाद भी ३६५, करोड़ उपयों की पूर्ति ग्रेप रह जाती है। यह बहुत संभा है कि यह कभी श्रोर अधिक हो यदि राज्य तपा निजी बनत की स्थिति श्राचा के श्रुप्तकल न रही।

यदि सारी स्थिति पर दृष्टि डाली लाय तो पता चलेगा कि सरकारी होन में लो कुल २,०६६ करोड़ रुपये की लागत रखी गई है उसमें से दीवंकालिक स्वय (Capital expenditure) के जल २,६०० ते १,५०० करोड़ रुपये के बीच में होगा। यदि इसमें निश्ची उसोग चुन में लगायी गयी पूंची को भी मिला लिया बाय (जिसमें उरोग, वाखिन्य और ब्यागर में लगी पूँची भी धीमालित है) तो पाँच वर्ष में सदेशी सोनों से ही दीवंकालिक स्वय की २,७०० से २,६०० परोड़ रुपये की राशि पूरी करनी पड़ेगी। यदि इसमें इसी अपि में पांचन की मद स्वय सी सित पूरी करनी पड़ेगी। यदि इसमें इसी अपि में में सित स्वय स्वयस्था का आधार है) और अन्तर्राष्ट्रीय कैस, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्युनोलैंड हत्याहि से मात स्थ्र करोड़ करोड़ कराये हो। जाते हैं। संस्वाधित स्वयं में यह ध्याप ३,१५० से ३,२५ करोड़ करायों के बीच हो। जाते हैं। संस्वाधित स्वयं में यह ध्याराधि ३,१५० से ३,२५ करोड़ करायों हो बीच हो। जाते हैं। संस्वाधित स्वयं में यह ध्याराधि ३,१५० से ३,२५ करोड़ करायों हो। जाते हैं। संस्वाधित स्वयं में यह ध्याराधि ३,१५० से ३,२५ करोड़ करायों हो बीच हो। जाते हैं। संस्वाधित स्वयं में यह ध्याराधि ३,१५० से ३,२५ करोड़ करायों हो बीच हो। जाते हैं। संस्वाधित स्वयं में यह धाराधी ३,१५० से ३,२५ करोड़ करायों हो बीच हो। जाते हैं। संस्वाधित स्वयं में यह धाराधी ३,१५० से ३,२५ करोड़ करायों हो बीच हो। जाते हैं। संस्वाधित स्वयं में यह धाराधी ३,१५० से २,१५० से ३,३५ करोड़ करायों हो बीच हो। जाते हैं। संस्वाधित स्वयं में यह धाराधी १,१५० से १,१० से १,१०

श्वातीचना—पंचवर्षीय योजना में भारत के कृषि तथा श्रीवेशिक विकास के सम्बन्ध में बड़ा श्वाचावाटी इच्छिकेख श्रमनाया गया। श्राम्कड़ों के श्रभाव श्रीर साधनों की कमी के कारख इससे श्रच्छी योजना तैयार करना संयव नहीं था। योजना पूर्ण होने पर राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगी, आय बढ़ेमा और जनता अधिक धनवान और प्रसन्त हो सकेगी, मारत के आर्थिक विकास में जो कमियाँ है उन्हें दूर किया आ सकेगा, खाद्याज में देश निरन्तर स्वावलम्बी बनता जायगा और कुछ कच्चे मालों का जिनके लिये देश आयादा पर निर्मर है, उत्पादन बढ़ेगा। योजना में वैशनिक प्रपाद और टेक्निकल शिख्ण की आवश्यकता को भी महत्व दिया या है। इन पर उत्याग और उक्कि के धन्स्तता निर्मर करती है। वैशनिक जाँचनरल, टेक्निकल शिक्षण इत्याद के लिये भी योजना में विशेष व्यवस्था की शांध है। कहा सक्त वह इक्का प्रमाय मक्ट होगा।

बह ब्रालोचना की गई है कि पाँच वर्षों में योजना की कार्यान्तित करने के किए ब्रावश्यक वित्त के सम्बन्ध में पंचवर्णीय योजना ने बहुत ब्राशावादी हथ्टि-कोशा अपनाया है और जनता से बहुत आशा की है। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि (क) योजना आयोग ने अनुमान खगाया है कि पू वर्षों में केरटीय सरकार के बजट, राज्य सरकारों के बजट और रेलवे से कारश: १६० करोड क्या. vo= करोब कपया श्रीर १७० करोड कपया श्रातिरिक्त प्राप्त होगा परस्त इस मात्रा में जानिक्ति गांग होता संभव नहीं है। खनसा में श्रव श्रीर श्रधिक का देने की समता नहीं है और रेलवे तथा सरकारी की श्राय भी उतनी श्रायक होना संभव नहीं है जितनी की योजना में अपेका की गई है। इसका तालर्यय यह है कि पंचवर्षीय योजना अपने मलरूप में कार्यान्वित नहीं हो पायेगी छीर उसमे काट छाँट करनी पढ़ेगी। (ख) योजना में यह माना है कि १६५१ और १६५६ के बीच प्रति वर्ष श्रविश्क्त आय का २० प्रतिशत प्रवा निर्माण में लगाया जायगा और १९५६ से १९६८ तक अतिरिक्त आय का ६० मतिशत इसमें लगाया जायगा। भारत जैसे निर्धन देश में जहाँ की अधिकतर जनता की आय अपने जीवन निर्वाह के लिए ही प्रयोग्त नहीं है आर्तिरिक्त आय का इतना अधिक अंश पूजी निर्माण में लगा सकते की आशा करना बास्तविक स्थिति के अनुकल नहीं है। यदि जनता की ब्राय बढती है तो वह उसकी विनियोग में खगाने की अपेना उपयोग में न्यय करना ग्राधिक पसन्द करेगी। यदि ऐसा होता है तो योजना श्रायोग की यह आशा कि १६५६ तक कुल राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये तक बद आयमी और १९७७ तक प्रति व्यक्ति की आय दुनी हो बायमी, पूरी नहीं हो सरती है।

इन द्वालोचनाश्रों में कुछ क्ल श्रवश्य है परन्तु यह योजना का श्राधार भूत दोष नहीं हैं। किसी भी योजना की श्रालोचना में यह तर्क दिये जा सक्ते हैं। नियोजन के लिए यह श्राश्यकीय है कि जनता त्याग करे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में संवसतः अन्य योजनाओं की अपेचा कुछ अधिक त्याय करने की माँग की गई है। परन्तु इस विषय में विभिन्न सत हो सकते हैं कि नार करने का जान का नव था उठक वर्षा स्वरंत की अपेद्धा की जाम और वह भारतीय जनता से किस सीमा तक त्यांग करने की अपेद्धा की जाम और वह त्राचान जनात चानच चान वार पान कर पान कर जा जा जा आर पर कितना त्याग कर सकने में समय है | योजना में यह व्यवस्था की गई है कि १९५१-५६ के बीच प्रति वर्ष अतिरिक्त आय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाया २८२१-२५ गणाच अत्याचन आवारवा अन्य गणाच्या नामाना मा स्थापना लाम सर्वाक १९५०-५१ में, जो योजना का प्रयम वर्ष था, केवल ५ प्रतिशत के नार नाम १६६४-६६ नु सा नाम को नाम नाम नाम नाम है। नाम ६ सावराव भ विनियोग की व्यवस्था की गई यी । इसके बाद की योजनाव्यों से प्रतिवर्ष व्यक्ति रिक्त स्नाय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाने की स्नाशा की जायगी। जहाँ तक इस पत्त का सम्बन्ध है योजना अभी पहला प्रयोग मात्र है। यदि जनता योजना में निर्धारित अनुपात में रुपया नहीं लगा सकी तो कम माश्रा में लगायेगी नानमा न मनमध्य अञ्चलक व प्रति में चीमी हो जायगी। यही बात ऋतिरिक्त क्राय के सम्बन्ध में मी लागू होती है। बिना सही स्वना के इस देत्र में उपयुक्त न उन्तर गुना थानू राजा राजा परा ४,७११ सुर ४ वर्ग पाउथ अनुसति निर्वासित करना संमय नहीं है । जैसे जैसे योजना लागू की जायगी श्रीर अञ्चल वास्ता होने उसी के साथ साथ योजना में आवश्यक परिवर्तन पंचवर्षीय योजना के श्रालोचकों ने कुछ गशीर तर्क भी दिये हैं। उनका किए जायंगे।

कहना है कि: (१) योजना में उद्योग की ग्रापेका कृषि को ग्राधिक महत्व दिया गया रि। इसका कारण यह बताया शया है कि जो योजनाएँ यसँमान में कार्यान्यत की जा रही हैं उन्हें पूरा किया जाय और अविष्य में देश के श्रीषोशिक विकास के लिए सुदृढ़ आधार स्थापित किया जाय। इस तर्के का मूल विचार यह है कि भारत का वर्तमान श्रीयोगिक विकास कृषि विकास के अनुसर हुआ है। परनु बास्तव में स्थित ऐसी नहीं है। भारतीय स्थित का शन रखने वाला कोई भी नार्थन न राज्य प्रत्य निर्मार में कृष्णे माल श्रीर विजली इत्यादि का वर्तमान इयक्ति यह जानता है कि भारत में कृष्णे माल श्रीर विजली इत्यादि का वर्तमान में जितना उत्पादन होता है उससे देश का बहुत अधिक श्रीयोगिक विकास किया जा सकता है। योजना आयोग ने एक और बात की ओर प्यान दिया। यह बहुत संभव है कि जब तक इस मारत के मावी ख्रीवीगिक विकास के लिए सुद्ध ग्राभार स्थापित करेंगे तज तक विश्व स्थिति में ऐसा परिवर्तन हो सकता है अप्य अभारत का श्रीद्योगिक विकास स्त्राज की श्रपेत् श्रीविक कठिन हो जायगा । ऐसी स्पिति में कृषि के विकास का क्या उपयोग किया जा सकेगा ? श्रंत में इस सम्बन्ध में रुक्से महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना का उद्देश्य मारत की श्रार्थिक ब्ययस्था की त्रुटियों को दूर करके देश का श्रविक सन्तुलित विकास करना है। इस दिशा में सबसे बड़ी कमी यह है कि भारत में मशीनों के निर्माण करने वाले उद्योग नहीं हैं, वियुत्त, इंजीनियरिंग, केमिकल इत्यादि के उद्योग का अच्छी तरह विकास नहीं हो सका है इसलिए अधिक सन्तुलित व्यवस्था बनाने के लिए योजना को इस दिशा की ओर अधिक व्यान देना चाहिए या और इन उद्योगों का विकास करने की अध्यक्षण बरनी चाहिए थी।

(२) योजना के अनुसार देश का श्रीशोशिक विकास निजी उद्योगप्रतियों के हाथों में सीपा गया है। इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है क्योंकि श्रनीत में निजी उद्योगपतियों ने भारतीय उद्योगों का कशलना पर्वक विकास किया । परन्त योजना के ब्रालोचकों का सत है कि बीबोगिक विकास ब्रधिकांश रूप से निजी जहाँ सप्तियों के हाथों से सीवने कीर जन्माहत के जरून निर्धारित करने के साथ निकी उद्योग के पर्या उपयोग के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय उद्योगपनियों का सब है कि योजना में २३३ करोड़ रुपये की एँजी का विनियोग करने की खोर १५० करोड़ हत्ये की यूँजी ट्रूफ्ट इत्यादि के लिए रखने की व्यवस्था की गई है। परन्त शह पंजी उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की पति के लिए बिरुक्क अपर्याप्त है। इसके साथ ही यह बात ध्यान देने योग्य है कि उद्योग केवल बिक्त की ही आवश्यकता नहीं होती है बल्कि इसके अतिरिक्त श्रमेक सुविधायों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कर सम्बन्धी, छूट हुट-फूट इत्यादि के लिए अधिक पंजी और अछ परिस्थितियों में नकद आर्थिक सहायता। यह खेद की बात है कि पेंचवर्षीय योजना में इसके लिए कछ व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अभाव में निजी उसीग देश के औसोगक विकास के प्रति खपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्योद्य नहीं कर सकता है।

(३) प्रथम योजना का एक छीर गंमीर दोप यह है कि इसमें धीर्षकालीन योजना छो पर विशेष ओर दिया गया है। इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि मुनिये- कित झापिक स्थवस्था में रीर्षकालिक योजनाओं पर विशेष और तेना चारिये । इस विदेशी राष्ट्री में, जिसका सबसे उल्लम उदाहरण सोतियत रूस है, रीर्पकालिक योजनात्रों की ही नियोजन का आधार स्वाग गया। परन्तु भारत ही स्थिति उससे मिल है। भारत में रीर्थकालिक योजनाएँ अधिक होनी चाहिये परन्तु साथ ही अस्थकालिक योजनाएँ अधिक होनी चाहिये परन्तु साथ ही अस्थकालिक योजनाओं पर विशेष और त्याचाल के सम्भन्य में देश शीम रावलां में मार्थ की स्थान स्था

दीर्घकालिक योजनाओं पर अधिक जोर देने में एक और हानि यह है कि यस्तुओं के उत्पादन में दीर्घकाल के बाद वृद्धि होगी जबकि जनता की रूप शक्ति श्रीप्र हो बदेनो। इससे मुद्रास्फीति का जोर छौर बहु जायगा। मुनियोजित च्य-यस्था में कुछ झेरा तक मुद्रास्कीति छौर परियाम स्वरूप अधिक कीमतें होना असि-बार्य है परन्तु यहि नियोजन के द्वारा क्सुखों को घूर्त बहुती है वो उत्यस्प्रद्वासीति का प्रमाव कम हो जाता है यदि पंचवर्षीय थोजना में अल्पकालिक मोजनाथों पर खाँवक जोर दिया जाता तो धेवा होना यमव या। इसके अपाव में योजना के सागृ होने से मुद्रास्कीति का जोर बढ़ा है जिससे उपमोकाओं को हानि हुई है।

(४) योजना की सफलता विशेष कर उस संगठन की कार्यसमता पर निर्मर करती है जिस पर उसके कार्यान्वित करने का उत्तरदायित है। भारतीय प्रथम वंचवर्षीय योजना की यह सबसे बड़ी कभी थी कि इसमें योजना की लाग करने के किए किसी विशेष संगठत की स्वयस्था नहीं की गई। कार शौद्योगिक क्रीर जही चारी क्रोजनाओं को कार्यान्तित करने का कार्य स्वतन्त्र कार्योरेशनों को मींवा गया है । इस कार्पेरेशनों पर सरकार खपना नियंत्रका रख सकते में विशेष समर्थ सिंह नहीं हुई है जिसके परिशाम स्वरूप जनता का बहुत सा रूपया नह हो गया है, योजनाओं में प्रायः संशोधन किया गया है और आशानकल उत्पादन भी मही बढ़ा है। श्रम्य बहत सी योजनाएँ राज्य सरकारों के श्रविकार क्षेत्रों में रखी गई हैं छीर राज्य सरकारें इनकी लाग करने का कार्य जिला श्रविकारियों की सींप देती हैं। यह प्रवन्ध सन्तोपजनक सिद्ध नहीं हो सका है। जिला आधिकारी श्चान्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विकास योजनाओं के प्रति पर्याम स्थान नहीं दे पात है। कुछ राज्य सरकारों हारा नियोजन अधिकारियों का कार्य विशेष सन्ती-वजनक नहीं रहा है। इसका परिवास यह हुआ है कि योजना को उचित रीति से लाग नहीं किया गया है और उससे जितनी खाशा की जाती थी उत्तरा लाम नहीं हो सका। इसके विपरीत जो कुछ प्रगति हुई है वह केवल कागजों तक ही सीमत है। यदि भारत सरकार आई। ए० एस० की तरह 'भारतीय आर्थिक प्रशासन' (Indian Economic Service) के अन्तर्गत उपयक्त कर्मचारी नियक करती और इस प्रकार योजना की कार्यान्वित करने के लिये विशेष संगठन को जन्म दिया जाता तो इस दिशा में अधिक प्रगति की जासकती थी। इससे कार्योलयो इत्यादि पर सरकारी व्यय में अवश्य वृद्धि होती परन्तु वह व्यय व्यर्थ नहीं जाता उससे पंचवर्षीय योजना की उपयोगिता बढ़ सकती थी।

हन दोषों के होने हुये भी इवमें सन्देह नहीं कि भारत की प्रथम पंचवधीय योजना देश के आर्थिक क्लिस्ट के सन्तन्य में एक प्रदेशनीय प्रयत्न या । ख्रारस्म में तो ख्रवस्य ही योजना की सक्तता कम होती। परन्तु यह देश में कृषि उद्योग, उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति क्षाय की वृद्धि करने के प्रयत्न का ख्रारस्म ही या।

#### मफलना की गामि

योजना आयोग द्वारा मई १६५७ में प्रकाशित प्रथम पश्चवधीय योजना के पुनर्वात्तर के अनुसार सम्पूर्ण पाँच वर्षों में किया नया ज्यय २०१२४ करोड़ रु हुआ (जबिक स्थोपित लक्ष्य २१७०,७ करोड़ रु था)। इसमें से १९००,३ करोड़ रु वज्य से प्राप्त आय भी तथा २०३५ करोड़ रु तिरेशी सहायता से प्राप्त हुये। इस प्रकार लागमा १६६ करोड़ रु कम स्थय हुये। पहले पाँच वर्षों में राज्य सरकारों ने ८६७% करोड़ रु तथा केम्हीय सरकार ने १११४%

कराज वर कारण्या । पूर्णि १६५५-६६ की बारतायिक संख्यायें पता नहीं है अतएव यह गम्भव है कि योजना का छुल स्थय २०१३ करोड़ वर्ण के बजाय १६६० करोड़ वर्ण है जाय। प्रारम्भ में २६० करोड़ वर्ण कोटे के खर्य प्रयम्बन की स्थयस्या थी। बारताय से यह ४२० करोड़ वर्ण हुला। इसके कलस्वरूप भारतीय अर्थ स्थयस्या पर काली आर पड़ा।

योजना में राष्ट्रीय झाय के ५% के विनियोग को बहा कर ७% तक करने का उद्देश्य या तथा पाँच वधों में २५,००-२६०० करोड़ द० के विनियोग क जदम था। उरकारी चीन में लगभग १५०१ करोड़ द० का विनियोग हुआ जब कि निजी चेन में १६०० करोड़ क० का विनियोग हुआ। १६४ कारा पाँच वर की अवधि में २,०० करोड़ क० विनियोग हुआ। १६५०-६१ की द्वलना में योजना के झन्त तक विनियोग का त्वर लगभग दूना हो चुका था।

कुछ कार्यों में प्रथम योजना की प्रगति और संस्कृता निस्तन्देह आइच्यं जनक रही है। खाद्याज हंजन और सुती कपड़ों के सम्बन्ध में १६५५-५६ वं स्त्रान्त सोचे हुए १६५५-५६ वं स्त्रान्त सोचे हुए १६५५-५६ वं स्त्रान्त सोचे सुत्राम निज्ञ गथा। अमोनिया सहन्तर, तटीम कलावात्रा और सीचेरट के सम्बन्ध में यदि उत्तराद्त १६५५-६६ वं स्त्रामानित स्वेय से कथ ही रहा कि भी काकी चूंच हुई है। कुछ ही कार्य देरे रहे हैं किनमें आधा के विपर्देश से बहुत कम मूझ हुई है और उनमें १६५५-५६ का भी सोचे हुई भीम तक बूंच न ही। इस्रांत्रिय हुं हि सार्य पर स्वाना्त की है सिक्त सार्व होगा। वंतायाद पर स्वाना्त की है सिक्त सार्व होगा।

दितीय पंचवर्षीय योजना में यह मान लिया गया है कि राष्ट्रीय बचत तथा विनियोग में बृद्धि के कारण १९५५-५६ की राष्ट्रीय आय के ७२% से १९६०-६१ विनियोग में बृद्धि के कारण १९५५-५६ की राष्ट्रीय आय में लगमम २५% की वृद्धि हो जायगी में १०'७% बढ़ जाने से, राष्ट्रीय आय में लगमम २५% की वृद्धि हो जायगी अपने अपने १९५५-५१ में बढ़कर ११,४८० अपने भार बढ़न कर सकता है कि आया योजना का अनुभव बतलाता है के अपने धार्मिक अपने भार बढ़न कर सकता है जैसा कि प्रथम योजना का अनुभव बतलाता है ।

"प्रथम योजना रिपोर्ट में १९५६-५७ से ५०% बचत करने की सीमान्त दर मान ली गई यी और इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि नार सा गर ना आर इंप्यून आसार राज्य अध्यान समान ना ना ना १६६८-६६ तक देश की ख्रार्थिक ब्यवस्था में राष्ट्रीय ख्राय का २०% दिनियोग किया जायगा और आग्रे चलकर इसी स्तर पर स्थायी हो जावगा। अब ऐसा प्राप्तास होता है कि यह अनुमान अत्यधिक है। जिन प्रस्यों (projections) काराज्य का प्रशास का स्थाप का स्थाप का स्थाप (Coefficient) ७% से जो कि १६५५५६ में या बढ़कर १६६०-६१ में १९% हो जायगा; १६६५-६६ तक गुणक के १४% और १६७०-७१ तक १६% तक बढ़ जाने का स्रमुमान है । उसके पश्चात् गुणक स्थिर रहेगा श्रीर १९७५ ७६ तक १७% तक वढ जायगा ( तालिका ने० १ के अनुसार ) । १६% या १७% राष्ट्रीय आप का विनि-नाना र्जास्त्र के प्रकृति है। पश्चार के नाहर नहीं है। पश्चार देशों में जिन्होंने अपना ग्रीबोगिक विकास पहिले आरम्म किया या पॅडी निर्माण की दर १० श्रीर अनुना आयानक विचार नारू आर्था के विनियोग की दर का १९१३-१९३६ के भीच क्रीवत १६ क्रीर २० के बीच था। रूस में १५ ख्रीर २० प्रतिशत की दर निरस्तर स्पिर रही है। उन देशों के श्लांक कों से बोई० सी० ए० एफ० ई० (ecale) चित्र के अन्तर्गत आते हैं यह पता लगता है कि १६५० से कुल पूँजी का निर्माण अयु र अवस्था अर्थ द रहे । बर्मा में १० मे २० प्रतिशत के बीच, जापान में २४ से ३० प्रतिशत के बीच, लंकी में १० से १३ प्रतिशत के बीच श्रीर फिलीपाइन्स में ७ से द्राप् प्रतिशत के बीच रहा है। भारत के सम्बन्ध में तुलनात्मक ऋँकडे १० से ११ प्रतिशत हैं। कुछ लैटिन रू. र । नारक में इस सकन्य के आँकड़े १५ और २६ प्रतिरात के भीच प्रायः रहे अगराण कार व रूप कर के हुछ केंचा भी हुआ है। पूर्वी योख के कुछ देशों में जैसे जैकोस्लोबेकिया स्रीर पोर्लेंग्ड में पूँजी निर्माण की दर २० स्रीर २५ प्रतिशत के बीच रही है। नये विकासोन्मुख देशों में विनियोग की दर वर्तमान स्तर से निश्चय ही बढ़ाई आ सकती है-यदि उपयुक्त विनियोग नीति का अनुसरण किया जाय द्भीर यहि राज्य द्वारा विकास कार्यक्रम द्वारम्भ किये जार्ये। इसलिये भारत के सम्बन्ध में यह भारत्या बचाना कि प्रयत्न करने से लिनियोग की दर उत्तरर बताये गये स्तर तक भटाई जा सकती है असंगत नहीं हो सकता"।

वक्रम एंच्यापीय योजना का उत्तेष्य था कि तेश में जीवन की गाधारभत बस्तकों के उपभोग को पुन: उस स्तर पर ले श्राया जाय जिस पर वह महापुद्ध के पर्व था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस सम्बन्ध में एक परा आगे है और उसका सहय यह है कि योजना काल के शस्त्रांत कल उपमोग की माना में लगभग ३०% और व्यक्ति उपभोगकी सात्रा से १२ से १३ प्रतिशत की बृद्धि हो। ऋछ विज्ञेष वस्तकों के प्रति स्वक्ति उपयोग के बाह्रकों से उस बात का ब्राभास मिलता है कि किन्ही अधिक प्राप्ति का बाजम न लगाया गया है। पौछिक सलाहकार समिति (Nutrition Advisory Committee) ने यह ग्रनमान जगाया था कि एक वयस्क के प्रतिदिन के सन्तलित ब्राहार में कम से कम १४ छों स अब होना चाहिये। १९५०-५१ में प्रत्येक वयरक प्रतिदिन १३ ग्रांस श्रास श्रीसत उपभोग करता था। किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिसाम स्वरूप १६५३ ५४ में मित्तव्यस्क मितिदिन अन्न के उपभोग की माना बढकर १५ औं हो गई। परन्त पने और दालों का उपभोग आभी भी निम्नतम आवश्यकताओं से कम है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति व्यस्क को प्रतिदिम २३ से ३ और तक चने और दालों का उपमोग करना चाहिये। किना बढती हुई जनसंख्या और प्रति व्यक्ति की श्चाय में बृद्धि हो जाने के प्रकश्यरूप खन्न के उपमोग मे वृद्धि होगी। अतएव हितीय पंचवर्षीय योजना में देश के भीतर खाद्याज का उत्पादन बहाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिये। "दय, धी, मास, मछली, बाबे, चर्ची, फल, तरकारियाँ और चीनी के उपमोग का यर्तमान स्तर निम्नतम ब्रावश्यकतात्रों से बहुत कम है। दिसीय योजना में रहन-सहन के अधिक ऊँचे स्तर की व्यवस्था करने के लिये पश-पालन. मछली-उद्योग, मुर्गी पालन. तरकारियों की खेती श्रीर श्रम्य प्रकार की खादा शामग्री के उत्पादन पर विशेष व्यान देना चाहिए"। दिलीय महायुद्ध के पूर्व भारत में प्रति व्यस्क प्रति वर्ष के हिसाब से १५ बज स्ती कपड़े का उपभोग करता था और प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर कपड़े के श्रीसत उपमोग का वही स्तर पुनः प्राप्त कर लिया गया है। सुती कपड़े की जाँच समिति की सिफारिश को मानकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १९६० तक प्रति व्यक्ति सती वपडे के श्रीसत अपभोग को श⊏ गत करने का लक्ष्य निर्धाति किया गया है।

प्राथमिकता का कम-प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि, विचाई

श्रीर विज्ञलों की शक्ति के विकास को प्रमुख महत्व दिया गया था श्रीर हन मही पर योजना की कुल लागत की ४२-४% रकम ज्यय करने का श्रमुमान था। इसके प्रयोजना की कुल लागत की ४२-४% रकम ज्यय करने का श्रमुमान था। इसके विपरित दितीय पंचवर्षीय गोजना ने उत्योगों को प्राथमिकता दी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्थान उद्योगों को प्राथमिकता दें दिखाया गया है। प्रित थी जवकि इस दूसरी योजना में (जैसा कि तालिका २ में दिखाया गया है। प्राथमिकता के कुल लागत का १८-५% व्यय होने का श्रन्थान लागाया गया है। प्राथमिकता के कुल लागत का १८-५% व्यय होने का श्रन्थान लागा गया है। प्राथमिकता के कुल लागत का १८-५% व्यय होने का श्रन्थान लागा गया है। प्राथमिकता के कुल लागत का १८-५% व्यय होने का कारण है। श्री प्रायम प्रायम प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले ही ते पर्याप्त च्यान दिया गया है, के विकास पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले ही ते पर्याप्त च्यान दिया गया है, क्रीर प्रथम की श्रन्था जन वर कोई निशेष प्रयाम देने की आयश्यकता नहीं है, श्रीर संपन है, श्रतप्त जन पर कोई निशेष प्रयाम देने की आयश्यकता नहीं है, श्रीर संपन है, श्रतप्त कर कुल लोग का लाग है कि देश के आया प्रथम प्रथम पर करने विकास ता ही कोई इल लोजा सर तक दृद्धि की जा सके आया बोजनारी की समस्या का ही कोई इल लोजा जा सके।

हितीय पंचयपीय योजना का यह जहेश्य है कि देश की राष्ट्रीय आय में प्रति तालिका २ मतकारी क्षेत्र में प्रथम और दितीय पंचयपीय योजना पर कुल

सरकारी क्षत्र में प्रथ	H all circ			
PACIFIC PROPERTY.	त के तुलनार	मक आकर्ड		
411.4	4 4 3	777	द्वितीय यो	सा
	प्रथम यो	অধা [		
Ī	कुल लागत (करोड़ इपयों में)	कुल का प्रतिशत		कुल का प्रतिशत
१. कृषि स्त्रीर चामुदायिक विकास	इग्रज	રપ્ર*ર	4.६८	११'=
२ सिंचाई और शक्ति (विजली)	६६१	१८:१	्ट१३ १३ <b>≈</b> ५	१६'० २८'६
३ परिवहन ग्रीर संचार	पूपुष	१२३ ६		\$ 15 'EL
🗸 उद्योग श्रीर खनिब	305	0.8	□ SE®	
्र निर्माश कार्य श्रीर शमाजिक सेवार्य	श्रद्	₹₹*¶	EXIL	\$5.0
	1	3.0	3.38	! ૨ <u>'</u> ૧_
६ विविष	२३५६	300%	¥5.00	१००%
কুল				

वर्ष लगभग ५% की वृद्धि हो और इस लक्ष्य की पूर्वि करने के लिये पाँच वर्ष की

ਬਾਰਹਿ ਜੋ ਲੜਾ 8200 ਕਰੀਟ ਸ਼ਬੂਰੇ ਕਾ ਗੁਲਾਰਿਕ ਰਿਜਿਥੀਗ (Net Investment) करने की ब्यावश्यकता होगी, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के ब्रन्तर्गत मुल रूप

में वास्तविक विभियोग की रकम ३१०० करीड करये थी। अनमान है कि इसमें से ३८०० करोड रुपये की रकम का विनियोग संस्कारी क्षेत्र पर होगा, जिसकी कावार्था महसार जापने विसीय साधारों में करेगी जीर शेष २.५०० करीड रूपये निजी सेच पर व्यथ होंगे. को निजी विनियोग द्वारा उपलब्ध होंगे। विकास सम्बन्धी

कार में प्रदेश करोड़ कारों की कमी जो कि प्रस्तावित वास्त्रविक विनियोग के कारण सरकारी सेत्र में खावज्यक होगा तालिका नं २ में दिया शखा है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 'आधारभत नीति' यह है कि (छ) इस्पात. यन्त्र निर्माणः जनिक पटार्थ आदि के प्रमुख और आधारभत उत्तोगों पर यथासंग्रह

श्रविक में श्रविक धन विनियोग किया जाय और इसके विपरीत सामान्य उपभोग में प्रयक्त होने वाली वस्तव्यों के उद्योगों पर वधार्सभव कम से कम घन व्यय किया

जाय: ग्रीर (व) छोटे पैमाने के व घरेलू उद्योग-धंघो के विकास की प्रोत्साइन दिया जाय. चाहे इस प्रधास में बड़े पैमाने के उत्तीगी की शान ही क्यों न ही। उद्योगों खार लानज पर प्रस्तावित दा । करोड ६पयों के व्यय में से

620 करोब रागों के लगामा बने श्रीर प्रथ्य वर्ष के अशोगों पर. 103 करोड़ दुपये खानल के विकास पर और २०० करोड़ दुपये ग्राम्य तथा छोटे उद्योगों पर व्यय किया जायगा । उद्योगों में से लोडे और इस्पात उद्योग की सबसे आधिक

माग मिलेगा। प्रमुख विशेषता द्वितीय योजना की छोटे और कटीर उद्योगों को भागमिकता देने की है, जिस पर २०० करोड क्यमा व्यय करने के लिए नियस किया गया है। यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों और खनिज पदार्थों को प्रमुख

रूप से प्राथमिकता दी गई है, किन्तु कृषि, परिवहन और सामाजिक सेवाओं की उपेक्षा नहीं की गई है। अनुमान है कि शह्यप्रभृद से शहद - दश तक दितीय थोजना के श्रन्तर्गत खाद्यान्न का उत्पादन ६५० लाख से ७५० लाख टन, एई का ४२ लाख से ५५ लाख गाँठ, गन्ते का ५० द लाख टन से ७० १ लाख टन. तिलहन का ५५ लाख से ७० लाख टन, चाय का ६४४ करोड़ से ७० करोड़

भींड हो जायगा। विचाई की जाने वाली भूमि का चेत्रफल ६% वरोड एकड़ हो जावगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार सेवल्यों और सामुदायिक योजनात्री के मरहलों की संख्या ५०० से ३८०० और ६२२ से ११२० कमश: हो जायगी। हितीय योजना की विशेषता यह है कि इसमें अनेकों ऋषि उत्पत्ति की वस्तर्ये जैसे नारियल, युपारी, लाख, कालीभिर्च और वृक्कफल आदि, जिनकी और प्रथम रोजना में प्यान नहीं दिया गया या, इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं और उनके विकास का प्येय निश्चित कर दिया गया है। द्वितीय योजना में कृपि का विकास अधिक विस्तत देंगपर होगा।

जहाँ तक परिवहन से सम्भन्य है भारतीय रेलो की याजियों तथा माल ले जाने को यादित बहा दी जायगी। रेलयथ १० करोड़ ८० लाख मील में बहाकर १२ परोड़ ४० लाख मील श्रीर माल की जुलाई १२ करोड़ में १६ करोड़ २० खाख हो जायगी। हची काल में राष्ट्रीय अबर्ज १२,६०० मील से ११,८०० मील श्रीर कदी तड़के १००,००० मील से १२५,००० मील बढ़कर हो जायगी। तटीय कपापार में जलयानों हारा टनेज ३२ लाख जी० श्रार० टी० से बढ़कर ४७ लाख जी० श्रार० टी० हो जायगा। मारतीय वन्दरगाहों की माल चढ़ान श्रीर उतारने की शांकर करोड़ ५० लाख टन से बढ़कर ३ करोड़ २५ लाख टन हो जायगी।

तालिका २ से मकट शेता है कि हितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (अ) हाथ के करये और शक्तिवालित करवे से नैपार किये गए कपड़े, राहायनिक खाटो, लोडे व हसात, प्रमुमीनियम और कोचले के उत्पादन में एक से अधिक दृद्धि होगी; (व) भारी राजवनी, आद्य के सामान, अप्रक, मैंगनील, साहकिशी, की को कोनी और विजाली के उत्पादन में अपेचाइत कम बृद्धि की जारगी; और (उ) मिल में तैयार होने याले एती कपड़ों, जनी सामान, चीती, साहन, जृती और मनस्पति तेलों के उत्पादन में और भी कम बृद्धि होगी। इस प्रयास में पर स्थान राणा गया है कि आधारमूत और प्रमुख उत्योगों का यस्परामम्य अधिक से अधिक हिकास किया जाय और जहाँ तक अत्य उत्योगों का स्थासम्ब इंग्लेड उत्योद के हारा आसिनीर्यंता के अधिक ते अधिक तिकट सर्वेचा वाय ।

रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता (Employment potential)
—िद्धतीर पंचवर्षीय भोधवा का एक मूलमृत उदेश्य वह भी है कि रोजगारी के
पर्यात अववार उत्तक किए जायें। मारलील असे क्वास्था की इसी आवश्रकता के
महार क्षम की की अपेक्षाकृत उद्योगों पर अधिक क्षम दिया गया है। इस योजना
की इतना अधिक कितृत जनाने का आधिक कारण यह है कि केवारी की समस्य को इत करने का प्रथम किया नाम की शांखिक कारण यह है कि केवारी की समस्य को इस करने का प्रथम किया नाम हित्योग योजना काल में नये काम करने वालों की धंवमा को वर्तमान संस्था में जुड़ जायथी सम्मग १ करोड़ के सद्मान की गई है। यदि उसमें से ३८ लाख की की त्यां में बहुत होती के बीज में बहुत उद्मान संख्या ६३ लाख के लगमा जाती है। यदि एक करोड तये अधिकों की संख्या में u 3 लाख पहले के बेकारों की संख्या (२५ लाख नगरों की जार २८ लाख ग्राम्य त्तेत्र में) जोड दी जाय ती कल बेकारी की संख्या १९५६-६१ में लगभग १५३ करोड़ हो लाग्नरी । रुनने नये व्यक्तियों को काम करने का अवसर पाप करवाना सम्मव जरी है। बदाचित द्राव नाम व्यक्तियों के लिये दितीय योजना में काम के तथे अवसर दिये जा सकते हैं। कित रोजधारी के श्रातिरिक्त ज्ञाबसरों की केवल योजना-मात्र तह लेने से सी समस्या इल नहीं की जा सकती। व्यापार ज़्यौर उद्योगों का प्रसार मात्र करके यह ग्राशा करना कि उनके द्वारा ग्राव श्राधिक व्यक्तियों की खपत बावने बाद होने लगेगी द्यार्थ है । इस समय होने अलेक द्यवसाय है जिनमें ब्राव-प्रवस्ता से अधिक लोगों को स्थवा लिया गया है। इसका परिवास यह होगा कि जैसे जैसे जन स्ववसायों में काम की वृद्धि होती. वैसे वैसे पहले से ही ऋषिक संख्या में काम करने वाले व्यक्तिया पर काम का बोक्त अधिक होता जामगा और इस प्रकार उन क्यवसायों में रोजगार के अवसरों में विद नहीं हो सकेगी। कछ उद्योगों और व्यापारिक संस्थाओं में श्रामनवीकरण की योजनाएँ साम किये जाने की भी सम्भावना है, जिसका पल यह होगा कि प्रसार किये गये उन उद्योगों में रोजगार के लिये और भी अधिक कम संख्या में लोगों की खपत की जा सकेगी। योजना आयोग इन कठिनाइयो से मुली भाँति परिचित है। "रोजगारी में धन-मानित वृद्धि लाने के लिए वित्त और उपयुक्त नोति का अनुसरस करने की आव-श्यकता तो होगी ही, उसके साथ-साथ सुगठित सङ्गठन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वेकारी दर करने के लिये छोटे-छोटे उद्योग-धन्यों को विकसित अरने पर श्राधिक बल दिया गया है, किन्त यह स्पष्ट है कि सब्यवस्थित प्रयत्नों के अभाव में इनका उस सीमा तक विकास और प्रसार नहीं हो सकता। काम करने के अवसर प्रदान करने का श्रर्थ केवल नौकरियों की जगहें बढा देना मात्र नहीं है। यह जगहीं के बढ़ा देने के प्रति जनता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। रोजगारी की क्यवस्था करने का यह भी अर्थ है कि भिन्न-भिन्न कर्मचारियों के लिए जितने प्रशिक्तरा की आवश्यकता है उसे प्रदान करने की सविधाओं का प्रवन्ध किया जाय। यह अनुमान लगाया गया है कि अनेक चेत्रों में उत्पादन दृद्धि होने के फलस्वरूप उसी ऋनपात में योड़ी या बहत मात्रा में रोजगारी में भी वृद्धि होगी। ऋतएव इस बात की अवस्थकता है कि अत्यधिक अभिनवीकरण पर नियलण किया साथ । साथ ही यह भी देखने की आवश्यकता है कि कहीं पहले से रोजगार प्राप्त लोगों की मजदरी बढ जाने से उस वस्तु की माँग में कभी न आ जाय और इस प्रकार वेकार लोगों को स्थिति और भी न विगड जाय।"

वित्त टयवस्था — गोजना की सफलता वित्त की प्राप्ति पर निर्मर है। मारत में सबसे बड़ी किटनाई यह है कि राष्ट्रीय सदायता पर निर्मर रहना अहत्तत कम है। इसिलये विदेशी वित्तीय सदायता पर निर्मर रहना आपर्यक्त हो जाता है। दिलीय योजना के अतुसार विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ पर्यों के क्या का प्रधन्य तालिका मं० दे में जैसा दिखास समयी ४८०० करोड़ पर्यों के क्या का प्रधन्य तालिका मं० दे में जैसा दिखास सपा है वित्ता लाया किस कर्यों को अतिरिक्त आप से, १२०० करोड़ क्या अपर केजट में व्यक्त स्वत्य अपर अंतर में व्यक्त स्वत्य अत्या अपर केजट में व्यक्त स्वत्य की अतिरिक्त आप से, १२०० करोड़ क्या अपर केजट में व्यक्त आप को स्वत्य की स्वत्य की

सरकारी चेत्र में विकास योजनाओं का अर्थ प्रबन्ध एक दूसरे हिंहकोण से भी देखा जा सकता है। पाँच वहाँ की खयदि में ४८०० करोड रुपयों के रुपय में से संगमग १००० करोड रुपयों का व्यथ तो शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अन्वेपण और राष्ट्रीय विकास आदि पर चाल ध्यम के रूप में होगा। इस प्रकार के व्यय से पॅजी का प्रत्यक्त रूप से निर्माण नहीं होता और इसलिये विनियोजित व्यय नहीं माना जाता। ऐसे चेत्रो पर व्यय चाल आय सोनों से पूरा किया जाता है। इसलिये चास्त्विक विनियोग ३८०० करोड रुपयों का है और इसका प्रवस्थ प्राण द्वारा क्या जा सकता है। विकासोन्मुल अर्थ व्यवस्था में जहाँ पर पंजी निर्माण सम्बन्धी व्यय उत्तरीचर बहुता जाता है, वहाँ यह बांछुनीय होगा कि उसके एक श्रंश का प्रबन्ध कर से प्राप्त श्राविरिक्त श्राय में से किया जाय। इस सिद्धान्त पर प्रथम योजना की रिपोर्ट में जोर दिया गया था और इस पर किर जोर देना चाहिये। योजना के अर्थ प्रवत्व की व्यवस्था में चालु आप में से केवल ८०० करोड़ उपयो फे प्रवस्थ की व्यवस्था की गई है जब कि चालू व्यय के अनुसार १००० करोड़ी रुपयों की शासम्यकता है। रेलवे से प्राप्त १५० करोड़ रुपयों की श्राय की चाला आय का भाग सममना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि कुल चालू आय से योजना के लिये प्राप्त विच हुए। करीड़ इपयों का हुआ जब कि चालू व्यय की मात्रा १००० फरोड़ ब्यथा अनुमान की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकारी आय में कुछ भी बचत नहीं है जिसका प्रयोग ३८०० करोड़ रुपये के विनियोग के लिए किया जाय, बास्तव में ५० करोड़ कपयों का घाटा है। दूसरे शन्दों में कुल ३८०० व रोड़ पका जी निर्माण का अर्थ-प्रवन्य व्यक्तिगत बचत द्वारा

ही करना सम्भव होगा । र्याद ८०० करोड़ रूपयों की विदेशी विसीय सहायता की बालग कर दिया जाय क्योंकि यह विदेशों की बचत पर निर्मर है और २०० करोड़ माली है। महामना वीमाल वावजे की बची हुई कवा में वाम की लाग तो देश की कार्शिक त्यवस्था के ब्रस्तर्रात चाल बचत की सात्रा जो कि सरकारी योजनाओं में विक्रिकोजिन की आयुक्ती, श्रेटपुर करीब उपयों के बरावर अवसी है। यदि यह मान क्षिया जाय कि ४०० वरोड इपयों की कमी सरकारी बचत द्वारा परी करली जायगी हो स्यक्तिशत स्वत की सात्रा को सरकारी चेत्र में स्थानास्तरित की जायगी वह ा तिर्ध कि किया क्रिक क्रमण

## व्यक्तिका संद ३

	सरकारी है	वेच के व	क्षिके वि	रका ने	स्रोत		
	सरकार। व	11 4P 1	idid i	नरा प	- GIIG	(करोड़	इपयों मे)
٤.	चालू श्राय के श्रतिरिक्त से		***		***	,,,	500
	(i) १६५५-५६ में प्रचलित	कर की	दर से	***	***		₹4.0
	(II) अर्विरिक्त कर से	,	***	***	***	2.9"	४५०
₹.	जनता से मात ऋगु से	***		***	414		१२००
	(i) বাজাব স্থা (Marke	t loar	12)	***			900
	(11) छोटी बचत	***		***		***	400
₹,	बजट के अन्य आय स्रोती से	7		***			¥00
	(i) रेल का विकास कार्यैक	म में यं	ोगदान				१५०
	(11) मोबिडेन्ट फरह तथा ह					धन से	240
٧.	बिदेशों के सोतो से		***			***	Eep
ч.	बादे के श्रथ महत्व से	***			444	***	१२००
٤,	कमी-देशीय श्रांतरिक सो		री की	वायगी	***		¥00
•			900			•	8600
•	''वया यह मान लेना युर्ग	क्संगत	न हो	या कि	52.50	करोड़ दप	यों तक की

व्यक्तिगत बचत की रकट सरकार को विनियोग के लिये प्राप्त हो जायगी। हम संबंध में क्षाजार में अपूर्ण लैने, छोटी सात्रा की बचत और घाटे के अर्थ प्रबन्ध में अन्तर बहत शाधारण महत्व की बात है। ये सब व्यक्तिमत बचन को ग्रापनी श्रोर से श्रायवा मत्य की वृद्धि द्वारा बरवश राजकीय कोप में पहुँचाने के दृद्ध है। ब्यांक्त-गत बचत की माजा राजकीय कीय में कितनी और किस दक्ष से पहुँचती है जनता की श्रवनी सम्पास की रोकड़, सरकारी अपूरा पत्री, तथा छोटी मात्रा वाले सेविग ''केंद्र और राज्यों के कजट कोती में जो आप करो, श्रूण, तथा अन्य उपायों से प्राप्त की जा वकती है पह लगमग २४०० करोक करये की है। धाटे के अर्थ प्रवस्प द्वारण हो। बाटे के अर्थ प्रवस्प द्वारण हो। इस के बाद के वीट का करों के राज्य प्रवस्प द्वारण और को की है। हम नामा में यदि द्वा० करों के करवी निवीश यहायना और को विश्वास के कुत आप को स्कारी चेंच में बीजना के कार्यक्रम की सार्योगित करने के लिये प्राप्त होगी पह ४४०० करोक क्याय होती है। इससे ४०० वरोक क्यायों को कार्य के कार्यो हो कार्य हो के कार्य हो कार्य के किया क्या है कि यह कमी देश के कोतों में वृक्षि द्वारण हो जी वाद में दुँदा जायगा। पह तो मान लिया स्वार्थ है कि यह कमी देश के कोतों में वृक्षि द्वारण हो जी लिया कार्य है कि यह कमी देश के कोतों में वृक्षि द्वारण हो की अर्थ प्रवस्थ कार्य हो जायगा। पह तो मान लिया कार्य है कि यह कमी देश के कोतों में वृक्षि द्वारण हो कि अर्थ प्रवस्थ प्रवस्थ प्रवस्थ प्रवस्थ कार्य प्रवस्थ कार्य वाच इंच वाद की भी विचारायोग रखते हुए कि जिय हम्में प्रवस्थ की बीजना की कररेखा यहाँ चताई गई है उसे प्रवस्थ पर आरय्य कार्य की बीजना की कररेखा यहाँ चताई गई है उसमें कार एक ही उत्पार विस्त पर निर्मेर रहा वा क्याया है, इय कसी की प्ररा करने का एक सी जा तक्य कर कारी उपक्र कार्य का कार्योग है। अर्थ प्रवस्थ विस्त कर कारी उपक्र करने का आरोग का लामांग है। अर्थ

हितीय योजना को इस बात का पूरा जात है कि १२०० करोड़ नपयों के बादे के अर्थ प्रक्य किये जाते हैं मुहास्क्रीति की दशा उसका हो जायगी। योजना बनाने वालों ने ऐसी स्थिति से बचाय के जिये अर्जेक प्रतिकरमों का निर्देश दिवा है। उनके पिकासाज्ञार:—

"सबसे ममुख सँरक्षण का उपाय बहुत बड़ी मात्रा में खादाख एकतित करके

रख लेना होगा जिस्से जब जब महास्फीति का प्रमाव जोर पकड़े तो उसका निरा-करण किया जा सके। जहाँ की द्यार्थिक व्यवस्था में तीवगति से विकास का प्रयत्न किया जारहा है यहाँ चाहे किसनी ही समस्रदारी से ऋर्ष प्रबन्ध क्यों न किया जाय मदास्क्रीति का भय पर्यातया मिटाया नहीं जा सकता ! मद्रास्क्रीति से सबसे उत्तम बचाव का दंग मुद्रास्कीति न होने देना है परना ऐसी नीति जिसमें मदास्प्रीत तो हो पर उसके दश्ममायों से बच निकलें कभी सफल नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में कछ जोलिय तो उठानी ही पडेगी। इस जौलिम से वसने का सबसे अधिक स्फल उपाय खाद्यानों के और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भएडार पर अधिकार रखना है ताकि जब इनकी कमी पडे तो बाजार में इनकी र्णात बढ़ादी जाय। भारतीय द्यार्थिक व्यवस्था में द्यन्त श्रीर यस्त्र के सम्यों का विशेष महत्व है स्त्रीर इनमें अधिक बृद्धि हर प्रकार से रोकना अस्यस्त स्नावश्यक है। अब तक इन वस्तुष्टी के मुल्य को युक्ति-संगत स्तर पर रक्खा जा सकेगा तब तक देश की अधिकांश जनसंख्या के जीवनस्तर की लागत नियत्र में रहेगी। अन्य वस्तक्षों के मुख्यों में वृक्षि अपेजाकृत कम महत्ता की बात होगी यद्मिन व्यवस्था में किसी भी वस्त के मुल्य में खत्यधिक वृद्धि होने से द्रव्य के खपैचाकत कम छावश्यक उपयोग की वस्त्रक्षों पर व्यव किये जाने का सम है। यदि ऐसा हो जाय तब उसे ने के करने का प्रथम करना आवश्यक होगा। सदारफीति के प्रभावों से बचने का टसरा उपाय विवेचनात्मक (discriminating) परन्त द्वरन्त ही करारोप के उपाय का अनुसरण कुछ बस्तुत्री का आवश्यकता से अधिक उपयोग होने से बचाने के लिये और अध्यधिक लामांश तथा अपनायास प्राप्त हुये लामांश की रोक देने क लिये (जिनका कि घाटे के अर्थ प्रवन्ध में उत्पन्न हो जाना स्तामा-विक ही है) अत्यन्त श्रायश्यक होगा। अन्त में, कन्द्रोल के उपाय का जिसमें राशनिंग तथा मात्रा नियत करना आदि चम्मिलत होंगे उपयोग के उचित सीमा से ऋगों जाने से रोकन के लिये तथा दुर्लम वस्तुआर्थ और कच्चे माल आदि के प्रयोग में मितव्यता लाने के लिये प्रयोग करना आवश्यक होगा। परन्तु अवीत का श्रानुमय बताता है कि श्रावश्यक प्रयोग की बस्तुत्रों पर कन्ट्रोल लागी समया-विध के लिये विश्वस्त उपाय सिद्ध नहीं होंगे। इस कारण यह स्त्रिनिवार्य हो जाता है कि इसके श्रातिरिक्त अन्य बचाय के उपायों का प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाय क्योंकि योजना के कार्य-कम में कमी करने की सम्भावना तो अत्यन्त कठिनाई में पक्ष्मे पर ही करना उचित होगा ।"

आलोचना—िर्द्वतीय पंचवर्षीय योजना की धारणा प्रथम योजना की अपेन्हा अधिक न्यायक और सुदृह है। अब यह योजना समास्र होयो तो प्रति रुपीक की वास्तविक आय में अपेकारूत आंचक दृद्धि शेगी और खोगों की आर्पिक स्थित में निश्चित रूप से सुपार शेगा। द्वितीय योजना की किम्मलिखित प्रमुख विशेषनाएँ हैं :

(१) इसके अन्तर्गत भौतिक (nhvsical) नियोजन पर बल दिया गया . है, न कि पितीय (financial) नियोजन पर। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य भीतिक ज्याहन के क्य में निर्माशित किये गये हैं जैसे इतने लाख टन हस्पात. कीयता. सीमेन्ट खादि और फिर इस मिल-मिल बस्तश्री के लक्ष्मों के लिखे विस को निर्धारण किया गया है। प्रथम पंचवर्णीय योजना के श्रन्तगत पर्याम हर ने साम जहीं किया जा सका और बास्तविक रूप में विकास का अब भी जहीं आगी रह सका. क्योंकि वह विश्वीय नियोजन पर आधारित या । मौतिक नियोजन में हम अपन कर बला सही दिया जाता है कि द्यमक योजना पर कितनी मात्रा में धन क्या किया गया है. बरन उसमें महत्यपूर्ण बात यह रहती है कि उस बस्त के जत्यादन में कितनी सक्ताना प्राप्त हुई है। इसका परिसाम यह होता है कि नियोजन में मांबक बास्तविकता का जाती है। किन्त मीतिक और विसीय सध्यों में साम्बर्ध स्थापित करने के लिये वह आवश्यक है कि निम्म विषयों पर विस्तृत और यथार्थ सदाना प्राप्त को आव : (श) भिन्न भिन्न वस्तुश्रों की प्रत्येक इकाई का उत्पादन करते में कितनी मात्रा में कच्चे माल, शक्ति, अम आदि की आवश्यकता होती है. क्षीर (व) प्रविध्य में इन विभिन्न करूने मालों व अम ग्राटि का क्या-रूप प्रकृत होता । श्राचारावश मारत में इनसे सम्बन्धित सही-सही शौर विश्वसनीय सन्ननाएँ ज्यालका सही है और इसीलए यह आरांका अधन्त होती है कि भौतिक वियोजन से समस्या इल होने के स्थान पर कहीं और नदिल न हो जाय। ''लोकसान्त्रिक तियोजन के शन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये एक ऐसे देश में बढ़ाँ का ज्ञानन यत्र आर्थिक नियोजन की आपश्यकताओं को वृति नहीं कर सकता जीर जहाँ का प्रत्येक विभाग और प्रत्येक सन्त्रालय ऋपनी चलाई हुई सोजनाको पर यथासंसव अधिकतम धन व्यय करने का स्थल करता है. विसीव नियोजन के स्थान पर मीतिक नियोजन पर वल देने का खनियार्थ परिणाम यह होगा कि (क) ग्रत्यांचक धन का अपन्यय होगा और (ख) आंधक गाला से सरकारी व्यय के कारण मदारकोति की प्रवर्तियों के उत्तब होने की संगावना है। प्रथम एस वर्णिय योजना के अन्तर्गत विक मन्त्रालय ने यह सिद्धांत सामने बच्चा कि विशेष परित्यिन तियों को छोड़ कर जान्य स्थितियों में किसी को भी निर्धारित रकम से अधिक ब्यय करने भी स्वीकृति नहीं दो. जानी. जाहिये और इस प्रकार सरकारी व्यय पर कड़ा नियंत्रस स्थापित किया गया । विन्तु बढ़ाँ तक मौतिक नियोजन का सम्बन्ध है, यह तक निरुक्कल निरम्भ है । बूँकि दिवीय पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश है कि निर्पारित किये गये भीतिक लक्ष्मी (physical targets) की पूर्ति की जाय, अत्यस्य भिजनिम्न विभागों और मन्त्रालयों को अपने निर्पारित वित्त से कुछ अधिक क्या कर रकते की जूट मात होगी। सरकारी न्यम में कभी करना अपना योजना-काल के अन्तर्गत अनुसानित रक्ष्म का विनियोग न कर काश्रम योजना का एक दोप है। किन्तु उत्तसे भी बड़ा दोष यह है कि घन का अवश्य किया जाय और उत्तर्भ फलस्वकष सरकारी घन की हानि तो हो ही लाथ ही लाथ अनियां जाय और उत्तर्भ फलस्वकष सरकारी घन की हानि तो हो ही लाथ ही लाथ अनियां जाय और उत्तर्भ फलस्वकष सरकारी घन की हानि तो हो ही लाथ ही लाथ अनियां कि के विषय विशेषन से सम्बद्ध खतरों और भूलों से यचने के लिये अत्यांक सावधान भी आवश्यक्ता है। किन्तु इंदर्भ कोई सन्देश नहीं कि विचीय मियोजन के स्थान पर भीतिक जियोजन पर बल दिये जाने से दितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक बास्तविकता आ गई है।

- (२) दिलीय योजना ने प्रमुख रूप से श्रीयोगिक विकास पर बल दिया है।
  प्रथम पंचयपीय योजना के अन्तर्गत कृषि और शक्ति (बिजली) के विकास को
  प्राथमिकता दो गई थी। इस प्रकार हितीय योजना से देश का श्राधिन विकास को
  प्राथमिकता दो गई थी। इस प्रकार हितीय योजना से देश का श्राधिन विकास
  श्रीपक सम्जुलित हो जावगा। श्रीयोगीकरण पर इस्तिए जोर दिया गया है कि
  (अ) प्रथम योजना के अन्तर्गत कुष्ठ और विचाई में पहले हो से काची मगित हो
  सुकी है और इसीलिए उर्जागी पर श्रीकि क्यान देना श्रावश्यक है। गया है, क्योंकि
  प्रथम योजना के अन्तर्गत ज्योगों की उपेखा की गई थी, (४) यदि इस प्रमुख क्य
  से केवल कृषि पर ही अपना व्यान विक्रित करते हैं तो यह समय नहीं है कि तेले
  से सहती हुई जनसंख्या के साथ-राथ येरोजगारी और श्रीयिक रोजगारी की समस्या
  को हल किया जा सके। श्रीयोगिक विकास को प्राथमिकता देने का यह उद्देश्य
  है कि नेरोजगारी और श्राशिक रोजगारी की समस्या को हल करने ने सहायता
  किसं, और (४) पहले की अपेखाक़त यह श्रीकक स्पर्य कर से स्नुम्य किया नाने
  लगा है कि देश की श्राधिक सम्बन्नता श्रान्ततः श्रीयोगीकरण से सम्बन
  - (३) प्रयम पंचवर्षीय योजना को श्रुपेदास्त्रच हिलीप योजना के श्रन्तर्गत 'श्रामातिक त्यार' पर श्रष्टिक स्थान दिया गया है। प्रथम योजना का उद्देश पर या कि देश में महाशुरू के पूर्व दैनिक उपयोग की वस्तुओं की जिस मात्रा में स्वयत

Vids the Author's article on "Some Basic Considerations about the Second Five-year Plan" in the Commerce, dated July 2, 1955, page 15.

होती थी, उटी स्तर को फिर से ले आया जाय। बितीय योजना एक पम और आने बढ़ गई और उनका लस्य यह है कि उनके समाप्त होने पर देश के कुल उपमोप में लगभग २०% और प्रति व्यक्ति के उपमोग में १२-११ प्रतिवात की दृष्टि हो। यह संमय होगा या नहों, किन्तु बितीय पंचवर्षीय योजना के समार होने तक प्रश्लीय आग की १०% राशि करों के रूप में ली जावगी, अविक अमी तक करों के रूप में लो जाने वाली राशि इसकी ७% है और यह निर्माण, सामानक कल्याण आदि पर अधिक रक्का व्यव करने की व्यवस्था की गई है क्योंकि इनसे झारा धनिकों की अपेवा निभंगी को अधिक लाम होता है। इसी कारण विताय स्वतारि गोजना को प्राणिवारीक कहा जा महा हो है। इसी कारण विताय

ति:संदेश दितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे अनेक दोव हैं जो इसे एकाड़ी श्रीर श्रात-श्राकांसी (over-ambitious) बना देते हैं । सबसे पहले तो यही तक अला जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में दिताय योजना के लिए यह समय जहीं है कि वह पाँच वर्ष की श्रमीय में कल ६,२०० करोड स्पूर के वास्तविक विति-योग (net investment) का धवन्य कर सके, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि १६५५-५६ में राष्ट्रीय खाय की जो ७ ३% राष्ट्रीय बचत होगी. उसे १६६०-६१ तक राष्टीय आय की १० ७% कर देना संमय नहीं होगा। इस घारणा का समर्थन कछ ऐसे विदेशी राष्ट्रों के अनुभवों के दृष्टान्त देकर किया गया है जहाँ पर लोकतान्त्रिक श्राधार पर नियोजन हला है या हो रहा है। प्रो॰ बी॰ श्रार॰ शिनीय की यह चारण है कि "अपने पिछले वर्षी के और दसरे जनतान्त्रिक देशो के ब्राधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी कुछ समय तक यह ब्राधा करना ब्यर्थ है कि विकास कार्य-क्रम के लिए इतने अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे. जिनसे राष्ट्रीय आय में होने वाली विद की दर दरानी हो जायगो। इस समय हमारे देश में राष्ट्रीय बचत की दर राष्ट्रीय आय की ७% या इससे भी कुछ कम है। पिछले पाँच वर्षों के अन्तर्गत इसमें लगभग १% वृक्षि हुई है। यह अनुमान करना कि भायी पाँच वर्षों में वृद्धि की दर बहुत अधिक तेज हो जायगी, केवल दराशा-मात्र है। सरकार ने यह नीति घोषित की है कि आय वितरण को अस-मानतात्रों की यथासमन कम किया जायगा, जिसका परिशाम यह होगा कि सम्पूर्ण बचत की रकम में घटती हो जायगी। चुँकि हमारे देश के अधिकांश लोग जिस मात्रा में लाचात्र का उपयोग करते हैं, वह राष्ट्रीय श्रीवत श्रीर पौष्टिक भोजन के निम्नतर स्तर से कम है, इसलिए यह अनुमान है कि दैनिक उपयोग के व्यय में जो वृद्धि होगी उसका ५.0% तो खाद्यान्न पर ही व्यय कर दिया खायगा । परम्परा के ऋाधार पर यह कहा जा सकता है कि यदापि इधर कई स्पों मे पैदाबार

YIY

ब्रन्ही ब्रवश्य हुई है, किन्तु फिर भी संमायना है कि ब्रागामी वर्षों में फरलें क्लिकल ही खराब होंगी था उनसे कम पैदाबार होगी। इन परिस्थितियों में यह मानापत्र करता कि मानी पाँच वर्णों में बचन की दर द प्रतिशत से श्राधिक होगी जिल्ल जरी है। जिल्ला दमके साथ ही बचत की दर में अनुमान से अधिक वृद्धि होता भी बिल्कल बासंभव नहीं है । खतएव इस बात की श्रावण्यकता है कि बचत की उक्त दर से जिस मात्रा में नित्तीय साधन वास्तव में उपलब्ध होंगे. उन्हीं के श्रमस्य बोजना के बानार को बनाजे के लिए उसमें सशोधन किए नार्य श्रीर राष्ट्रीय आय की अनुमासित बृद्धि के अससार हो विनियोग की रक्षम निर्मारित की जाय' ।

यह तर्फ दिया जा सकता है कि किसी भी योजना के खन्तर्गत खनमानित ब्यय की रक्तम स्त्रभावत: ही प्रयोगिक (Tentative) रूप में निर्धारित की आती है और यदि अनुमानित साधन जपलब्ध न हों से गोजना की लागत को उसी के श्चनसार घटाया जा सकता है। किन्त इस तर्क के विरोध में यह कहा जा सकता है कि (श्र) "इस प्रकार संशोधन करने से नियोजन में गहनड़ी था जाती है। सबसे बड़ा दीय ती यह है कि अनुमानित विनियोग और जतरादन के स्तर में बहुत श्राधिक कसी कर देने से सामान्य लतता में योजना के प्रति निराशा उत्पन्न ही जाने की संभावना रहती है। यदि सरकार कविम रूप से विनियोग की दर की लादने का प्रपास करती है, तो उसके कलस्वरूप निश्चित कप से भीषण महास्तीति का उदय होगा । श्राधिक नियम श्रत्यन्त कठोर होते हैं और अनके लागू होने में सौंच्यिको (Statisticlans), अर्थ-शास्त्रियो या राजनीतिको की सविधा-ग्रस्तिया पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । यदि कोई भूल की जाती है, तो उनके दुष्परि-याम हमें निश्चित रूप से भुगतने पहेंगे। इससे यह निष्कर्ण निकलता है कि श्रमिक से अधिक गयार्थगदी होकर अधिकतम सावधानी बरतने की आवश्यकता है". श्रीर (व) "वास्तव में जितने खायन उपलम्य हैं, उनकी चुमता से श्रविक विकास कार्य-कम को बलपूर्वक गतिशाल बनाने का अनिवार्य कर से यह परियास होगा कि श्रानियंत्रित महास्पीति उत्पन्न होगी । एक ऐसे जनतान्त्रिक देश में, जहाँ की अधिकांश जनता के पास जीविका-निर्वाह के बेवल निम्नतम साधन हैं, वहाँ मदारपीति के परिणाम श्रात्यन्त मयंकर होंगे श्रीर संभव है कि जनसे समाज का वर्तमान दाँचा भी जर्जर हो जाये। यदि मुदास्फीति को रोकने के लिए शास्त्रवादी

<sup>1.</sup> Prof. B. R. Shenoy, "A Note of Dissent on the Memorandum of the Economists' Panel", p.4. Also see for a summary of this note Commerce, dated, May 28, 1955, p. 15.

क्षयं ज्यवस्था के समान मीतिक सापनों का सद्दारा लिया गया तो योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासन-सम्बन्धी या अन्य नैपानिक उपानें के द्वारा क्यक्तितर स्थलकदा और जनतांत्रिक सस्याओं का (बीटे धीटे या तेजों से) लोध हो नावगा। अवस्य अविकाकांत्री योजना के मयकर हुष्यारिया। के प्रति हमें सेचेश रहने की आवश्यकता हैं? 1

दितीय पंचवर्षीय योजना की श्रालोचना का दसरा स्राधार यह है कि जसके कारतार्त जायभोका की क्रय-शक्ति पर उचित श्यान नहीं दिया गया है। जब किसी विकास कार्य-क्रम पर घन ज्यव किया जाता है तो यह अमिकी. कच्चे माल की पास करने वालों और अन्य व्यक्तियों को प्राप्त होता है. जो स्वयं उस धन को उत्तादित चरतथा पर स्थय करते हैं । बस्ततः आधिक विकास की यही प्रक्रिया है। यदि सभी इंदिरकोगों से विचार करें तो जात होगा कि धन-उपार्जन करने बालों के द्वारा उसका व्यय किया जाना श्रास्त्रन्त ग्रहकावर्थ है. श्रयोकि इसी के फलस्यरूप उत्पादित वस्तुओं को वेचन का अवसर प्राप्त होता है जिसका परिणाम यह होता है कि उन विकी हुई बस्तुओं के फलस्वरूप फिर नई बस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया की बराउर जारी रखने के लिए खावश्यक है कि उपभोक्ताओं की कय-शक्ति (purchasing power) में वृक्षि हो। जब तक कि सभी साधनों का पूर्ण उपमोग नहीं हो जाता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। यदि किन्हीं कारणी से लोग उत्पादित वस्तुक्रों का उपभोग नहीं कर पाने तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया का चेत्र संक्रचित हो जाता है। द्वितीय योजना में यह निर्देश किया गया है कि योजना की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में राष्ट्रीय आप पर कर की ७ प्रविशव दर को बढ़ाकर १९६०-६१ तक ६ या १० प्रतिशत किया जायगा। यही नहीं, कर की दर मे १२ प्रतिशत तक बुद्धि करने की आवश्यकता पड़ सकती है। भारत में कर की दर बहले ही से ऊँची है और इसीलिए योजना आयोग की यह धारणा है कि "करों के वर्तमान स्तर-राष्ट्रीय ग्राय का ७%-को भी बनाए रखने के लिये उसमें कुछ न कुछ संशोधन अवश्य करने होंगे"। यदि करों में अब तनिक मी वृद्धि हुई, तो उससे लोगों को श्चरपधिक कच्टों का सामना करना पडेशा और व्यापार च उद्योगों के सामने भी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो नायेंगी। यदि करी की किसी भी विधि से लोगों की क्यशक्ति चीया होगी अथवा वस्तुओं में वृद्धि होगी, तो यह निश्चित है कि द्वितीय योजना के कार्य-कम में नामा पहुँचायेगी। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि

Wide the Author's article, loc at , p.15.

होगी और जीवोगिक व व्यवधायिक कायों का देज विस्तृत होता जायगा, वैरेन्येषे करों से प्राप्त होने वाद्ये सरकारी राजस्य में निश्चित रूप से वृद्धि होती जायगी। किन्तु परि उपमोक्ताओं की क्षम-आकि को श्रीण बनाते हुए करों में वृद्धि करने का प्रवास किया जायगा तो यह निरचय है कि वोजना के कार्यान्यित होने में बावा पदेशी और राष्ट्रीय आय में अनुसारित वृद्धि मो नहीं आ योक्सी। इतका परिवास यह होगा कि बाजार में उधा कारप्तानों के पोदामों में बतीर विकी हुई वस्तुओं का वेर लग जायगा और इस प्रकार उसका उत्पादन या तो घट जायगा या विस्कृत ही बन्द हो जायगा या दिन्कुत ही बन्द हो जायगा । इस अन्यवस्था के फलान्वरूप योजना की प्रगति को गहरा प्रकार

. यहि लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे खपना उपमोग कम और बन्ध अधिक करें, से ठीक वैसे ही दृष्परिणाम उत्पन्न होंगे। इ.स. समय पूर्व यह धारणा पचलित थी कि झधिक बचतों से उसी द्यानपात में श्चार्थिक विकास भी श्रविक होता है। किन्त श्चर्यशास्त्र के श्राधनिक सिद्धान्त इस धारणा के बिलकल विरोधी निष्कर्पों पर पहुँचे हैं। उनके श्वनसार जितना ही श्रविक उपमोग किया जायता उतना ही श्रविक खाधिक विकास होता । यहि क्रतिम राजि का विभियोग करने के फलस्वरूप उत्पादन में यदि हो और उसकी खपत हो जाने पर पहले की अपेकाकृत अधिक उत्पादन हो और यह सम्पूर्ण आर्थिक प्रक्तिया निर्धिष्ठ रूप से चलती रहे. तो बचतों के सम्बन्ध में कठिताई उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्ट्रीय आय में बृद्धि होने के फलस्वरूप बचत की कुल रकम में भी वृद्धि होती है ब्रीर ब्रन्त में बचतों के द्वारा विनियोग सन्द्रालित हो जाता है। किन्तु यदि बहुत शीमता से बचत की रकम में शक्ति करने का प्रयास किया जाय तो ग्राधिक विकास का चेत्र सक्कित हो जायगा। यदि सरकार की कर नीति श्रथवा श्रन्य नीतियों से वस्तुश्लों के मुख्य में बिंद हो और उपभोकाओं की कय-शक्ति घट जाय, तो इसका परिणाम यह होगा कि कपड़े. चीनी, खाद्याच और अन्य वस्तुओं की प्रति-व्यक्ति खपत (Per ca pita consumption) में अनुमानित वृद्धि नहीं होगी और न रहन-छहन का स्तर ही ऊँचा उठेमा, चाहे किसी प्रकार उन वस्तुक्षों का उत्यादन बढ़ा ही क्यों न लिया जाय ।

तांसरी वात यह है कि योजना के अन्तर्गत अनुमानित बाटे के वजट की 1,700 करोड़ रुपये की रुज्य (चा देश की धर्तमान द्रव्य-पूर्ति का ५०-६०% है) से अत्यधिक मुद्रास्कीति उत्पन्न हो जाने की संमावना है। किसी भी ऐसे देश में, जहाँ व्यवस्थित रूप से आर्थिक विकास किया जा रहा है, भुद्रास्तीति का उदय होना श्रवश्यमायी है। किन्तु श्रावश्यकता इस बात की है कि मुद्राक्कीत पर कड़ा नियंत्रण रखा जाय जिससे कि श्रिष्ठक हानि न होने पाये। प्रोफेसर प्रिनीय की यह पारणा डीक ही है कि "यदि यह मान भी लिया जाय कि राष्ट्रीय श्राय में इदि को दर हुगुनी हो जायगी, तो मी श्राविर्त्तक रोकड़ बाकी (cash balances) के लिए इतनी श्रिष्ठक मौंग नहीं हो सकती कि कुत इत्य-पूर्ति (money supply) की ५०-६०% रक्तम की व्यवस्या चाटे के स्वत्र के रूप मं करने की श्रावश्यकता पढ़े। यदि केन्द्रीय बैंक (Central bank) का एक-विहाई श्रवुमानित द्रव्य चाटे के बजट के द्वारा चलन में श्राकर व्यवसायिक बैंको (Commercial banks) के खर्रावत कोगों में इदि करता है श्रोर उनके श्राचार पर वे व्यवसायक केंक ६-७ गुनी साव का निर्माण कर खेते हैं, तो योजना-काल के उपरान्त कुल हत्य की पूर्ति योजना मारंभ करने के समय की प्रम्य-पूर्ति से हुगुनी या उनके भी श्राविक हो सकती है। इनके कक्षरवरूर मुद्राक्तीति को निश्चित कर से कम्म सिकेगा?"।"

९ पर्याम सचनायें न होने के कारण यह बताना कि किस सीमा तक घारे का बार्थ प्रबन्ध भारतीय आर्थ व्यवस्था विना हानि पहुँचावे सहन कर सकती है श्रम्यान है। धीक शिनीय ने अनुमान लगाने का साहस किया है। "हम शीपेंड के फानर्गत चारे के प्रथं प्रबन्ध की मात्रा में पीयड पावने की मात्रा जो सरकारी केन्न की चाधिक चावश्यकता के लिये काम में काई गई है और देने पर जो मात्रा खावे जमें ही हारे के पार्थ प्रवस्थ करने की वह सीमा समस्रा जा सकता है जिस तक किसी हानि की बारांका नहीं की जा सकती। पाँच वर्षों के भीतर पीड पावते की मात्रा ९०० से संशाबत १५० करोड रुपये तक योजना के अन्तर्गत मानी गई है। इसके प्रक बंश की कालियात चेत्र के लिये नियत करना पहेगा और उसकी आया के बरावर वैकी हारा साख उत्पत्त करनी पढेगी । यदि हम रोकड बचत तथा पीछ पावने की रकर्मों को सरकारी और व्यक्तिगत चेत्रों में २:१ के अनुपात में क्रमश: चाँटें सो कत धारे का पार्थ प्रवन्त १८० से खगाका २२० करोड रुपये तक पाँच वपाँ की खबि में ठहरेगा, अर्थात ३५ से ३३ करोड़ रुपये अति वर्ष की दूर के हिसाब से होगा।" इस मात्रा को घाटे के अर्थ प्रवन्य की उचित सीमा चाहे हम मार्ने या न मार्ने पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि २०० करोढ़ रूपयों का घाटे का मित वर्ष श्रोसत अर्थ प्रबन्ध जो कि द्वितीय योजना में किया जाने वाला है बहुत अधिक है। इससे ऐसी मुदारकाति शक्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं कि योजना ही नष्ट-अष्ट हो जाय।

श्रंतिम दात यह है कि बरूपि दितीय बोजना दारा प्रथम बोजना की एक भूल का संघार किया गया है और खीरोजिक विकास पर पर्याप्त स्थान दिया गया है. किन्त किर भी संभव है कि एक दोषपर्ग औद्योगिक ढाँचे का ही निर्माण हो. श्योंकि उसमें दैनिक उपयोग में प्रयक्त होनेवाली वस्तुत्रों का उत्पादन करने वाले कारखानों के उद्योगों की उपेजा की गई है। "यदि योजना ग्रायोग की बड़े पैमाने बाले उद्योगों के स्थान पर छोटे पैमाने के श्लोर घरेलू उद्योग-धंघों की विकित्त करने की योजना सफल हो जाती है. सो इसका परिखाम यह होगा कि वहे-बढ़े उद्योगों का हास होने लगेगा और उनके द्वारा प्रत्यस्त या अप्रत्यस्त रूप में प्रयुक्त होने वाली मशीने, इस्पात और अन्य आचारशत सामग्री की माँग बढ़ने के स्थान पर और भी घट जायगी"। वसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि "यदि संरक्षण, संगठन श्रीर आधिक सहायता के द्वारा जितना ही अधिक घरेल उद्योग-धंघों का विकास होगा और कारलानों के जैन में ग्राधनिकीकरण वमसार करने का कार्य जिसने ही क्ष्रधिक अभव के लिए स्थिगत किया जायगा, तो उक्त समस्याओं की इल करने की कठिनाई भी बढती ही जायगी। यदि ऐसा विकास कार्य कम श्रपनाथा गया, जिसमें छोटे छोटे उद्योगों का प्रसार करके ग्रीद्योगिक नीनि दिल्कुल परिवर्तन कर ही जायगी और मधीनो व विजली की शक्ति की पूर्ति मी इन्हीं घरेलू उद्योग-धंगों के लिए की जायगी. तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कार्य आर्थिक **ए**ष्टि से नितान्त अतिचित होगाम । १

१ इस सम्बन्ध में इस बात पर और देना उचित होता कि ''होटे और प्रास्त उद्योगों को सगदित करने के तिव शहुत कपिक प्रवापन करना आवरणक होगा। ऐति- इसिन हिट से तो प्रश्नीत पुलंगित पेतृन्यों की स्थापना के साथ प्रास्त उद्योगों के दिल्ला हर होने के दहीं सुवा है। यह तो अधिक इन्हम्म की प्रवास की प्

इस सम्बन्ध में एक दसरा इध्टिकीण यह है कि भावी श्रीद्योगीकरण सरकार श्रीर निजी जहांची के समिक्षल प्रयास पर श्राघारित होगा। यद्यपि दितीय पंचवर्षीय योजना में निजी चेत्र के श्रन्तर्गंग २४०० करोड़ रुपए के ध्यय की रकम निर्धारित की गई है किन्त उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इतनी अधिक राणि किन माधनों से उपलब्ध होगी। योजना के ग्रनसार, "निजी उद्योगों के निर्माता-कार्य के लिए बचत की रक्या प्राप्त करने के क्या साधन होंगे. यह निर्देश करना कठिन है। इसके अतिरिक्त यह भी टावे के साथ नहीं सहा जा सकता है कि निर्माण कार्य में बानमाजित बढ़ि की पति होती हो । कल बचन के शपर्याप्त होते पर कमी कर में मे परी की जायगी इसका पता नहीं? । चेंकि सरकारी खेत्र को सभी साधन उपलब्ध होने की कटाचित अधिक सभावना है. इसीलिये बहत कुछ संभव है कि निजी जेब को श्रमभानित साधन न प्राप्त हो सकें। इस परिस्थिति का फल यह होता कि इधर भरकारी लेज के अंतर्शत औरोधिक विकास होता और उधर निजी केल में श्रीदोगिक प्रगति न होने के कारण सम्पूर्ण श्रीदोगिक विकास की स्थिति बहत कक सीया तक वैसी ही रह जायगी। प्रातपन दितीय योजना के अन्तर्गत जितना श्रीद्योगिक विकास होने का अनुमान विधा गया है बह नहीं हो सकेगा ।

द्विदीय पंचवर्षीय योजना ने बेरोजगारी की समस्या को इल करमें पर महुत जीर दिया है। वात्तव में कोटे पैमाने के और चरेलू उचीम प्रच्यों के विकास को मोस्साहित करने का मुक्त कारचा भी यही है। किन्तु यक्त दीवार करने वाले उचीमों का नियोजन इंगलैंक, अमरीका और रुख के झाबार पर किया जा रहा है। योजना आयोग को चाहिये था कि इमारी विशिष्ट आवश्यकताओं को व्यान में स्थकर इस प्रकार के नये यक्त वीवार करने की व्यवस्य करता, जो इतने कार्यक्षम होते कि उनके द्वारा प्रति इकाई के उत्पादन की उतनी ही लागत पच्ची जितनी कि विश्व के ग्रन्य श्रीचोनिक इष्टि से विकित्त देखों में तैयार की गई अम की संचत करने वाली (Labour-saving) और अपने आप चलने वाली मधीनों के द्वारा पच्ची है, किन्तु उनके (भारत की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनने वाली मशीनों) द्वारा पूँची-विनियोग की प्रति इकाई के

आवश्यक होगा । ऐसा करने पर सकताता तो सीमित साथा है ही प्राप्त होगी पर पेंदि असफल हुवे तो परिण्या भयावह होगा। <sup>19</sup> (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry's "Second Five-Year Plan, A Comparative Study of the Objectives and Techniques of the Trainty Plan-jrams", 39, 78)

के बन्त्रों का निर्माण होना पूर्णल्प से सम्मव है। फेवल पूँजी की बचत करने वाले (Capital-saving) ऐसे यन्त्रों का निर्माण करने का महत्व इसलिए मी बहुत क्रियक है कि केवल इन्हीं के द्वारा भारत की बेरोजगारी श्रीर स्नांशिक रोजगारी की समस्या स्थायी रूप से इल की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था की कमी दिनीय पंचवर्षीय योजना का एक बहुत ग्रामीर दोय है।

### योजना का पुनर्मूल्यन

दितीय पंचवर्षीय यो<u>जना</u> को प्रारम्म से ही ऋषाचारण कठिनाह्यों का सामना करना पड़ा। (अ) आयात की हुई मशीनों, कब्चे माल तथा अन्य माल का मल्य स्वेज-संकट के कारण बढ गया। विदेशों में भी मुख्य बढ़ गये। देश में विनियोग की श्रत्यधिक देर के कारण सदास्क्रीति की दशा उत्पन्न हो गई जिसके परिसाम स्वरूप मुख्यों में बृद्धि हुई। परिस्ताम यह हुआ। कि योजना के श्रंतर्गत विभिन्न योजन। खों की लागत बढ गयी तथा प्रारम्भ में निर्धारित वित्त से भौतिक लक्ष्यों (physical targets) की प्राप्ति अवस्मव हो गई। (व) योजना के लिये ग्रत्यधिक कर लगाने तथा अन्य उपाय करने पर भी साधनी की कमी पद्र गयी और विदेशी विनिमय का सकट उपस्थित हो गया। (स) दितीय योजनाका भार जनताकी वहन शक्ति के लिये ऋथिक सामित हुआ। योजना में खरैब ही कुछ त्याग करना होता है किन्तु दितीय योजना में अपेचित स्याग बहत श्रधिक हो गया। श्रतएव योजना आयोग तथा भारत सरकार की यह सुक्ताव दिया गया कि योजना में कटोती की जाय तथा विनियोग की दर कम की जाय । योजना श्रायोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा भारत सरकार ने विचार-विमर्श के बाद योजना में कटौती करने के बजाय उसे दो भागों में वाँट दिया। (१) माग श्र जिसके अन्तर्गत कृषि उत्पत्ति की बृद्धि से पत्यस रूप से सम्मन्धित योजनार्चे, मुख्य (core) योजनार्चे (रेलवे, बड़े बन्दरग्राह, स्टील, कोयला तथा ख़ान्य शक्ति योजनायें) जो काफी आगे वह गयी हैं तथा अन्य योजनायें जिन पर कल ४५.०० करोड़ रु के ब्यव का अनुमान है, तथा (२) भाग व जिसमें ३०० करोड़ स्पये की शेष योजनायें सम्मिलत है।

वैद्या ि 'दिवीय पंचवर्षीय योजनाः पुनर्महण्यन य सम्भावनाये' (मई १९५८) ते प्रकट है योजना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा क्रियोजना पर प्रात्मिक अनुमान को तुलाना में भू४० करोड़ ६० कम आयोत् ४९६० करोड़ ६० स्थय होगा। मई १९५८ में योजना आयोग ने धोषणा की कि यथार्थ उपलब्ध साधन

नर ८८.२८ न पालना आयाण न धारका का कि यथाथ उपलब्ध क्षापन ४२६० करोड रुक्टी है, किर भी माग ऋ के ऋग्रं प्रनम्बन का पूरा प्रयक्त किया

#### योजना के लिये प्रसाधन (१९४६-१९६१)

(करोड ६० में)

ं साधन	योजना के लक्ष्य	उपलब्धि की सम्भावना
१. बजर के साधन	2500	२२६२
(ग्र) चालू ब्राय से बचत	<b>१२००</b> †	<b>≒</b> €€
(व) रेलवे का अंशदान		१५०
(त) ऋष तथा श्ररूप दचन	2200	4088
(६) ऋण तथा विविध पूँजी प्राप्ति	२५०	38
२. विदेशी सहायता	<.	१०३⊏
इ. घाटेका ऋर्यप्रवन्धन	१२००	१२००
<b>कु</b> ल	8500	४२६०

जायगा। वितम्बर १६५८ मे यह धोयखा की गई कि माग क्र की वाजनाओं को ४५० करोड़ द० तक नहीं सीवित किया जो वका जातएव १५० करोड़ द० का बय और करना होगा और इस प्रकार कुल व्यव ४६५० करोड़ द० का काय और करना होगा और इस प्रकार कुल व्यव ४६५० करोड़ द० होगा। वोक्षना आयोग ने यह सुकाव दिया कि राज्य वस्कारें योजना की देश अवश्वि में १५० करोड़ द० का आतिरिक्त साधन प्राप्त करें—६० करोड़ द० कर झारा, ५० करोड़ द० का आतिरिक्त साधन प्राप्त करें—६० करोड़ द० कर झारा, ५० करोड़ द० का अवश्वि में कारी कर कर झारा, ५० करोड़ द० कर हारा एकत्रित नहीं कर पक्ती। जेंचे मुख्यों के कारचा जाता की वच्छा कम हो गई है तथा अध्यात वच्च निजी साधनी प्रयोग में से अपने इस साधनी हैं अत्याद इस साधना करना सम्भव नहीं प्रयोग होता। कुछ लोगों की राय में कही अच्छा होता यदि योजना अपनोग स्थिति का यधार्यता स्वचन तथा तथा व्यव को देश की शांकि के अन्दर ही स्वता।

श्रामात के मृत्यों में वृक्षि होने तथा ग्रन्य लागतों के बहुने के कारण छनसे ग्रापिक सुद्धि 'उचोम तथा खनिज' में हुई है तथा सबसे बड़ी कटौती 'सामाजिक

<sup>†</sup> इसके अन्तर्गत मूल योजना में दिखाया गया ८०० करोड़ ६० का चालू श्राय का करिरेक तथा कर से पूरा होने वाला ४०० करोड़ ६० का घाटा भी सम्मिलित है।

# ्द्रितीय योजना के सरकारी क्षेत्र में विभिन्न मर्दों के

(करोड र॰ में) श्रधिक लागत के श्रद्ध प्रस्ताविन कारण पननिश्चित व्यय (योजना सद्य (४८०० करोड भाग श्र हर् के भीतर) कवि और सामदाविक 48E 내용C 420 विकास । मिचाई और शक्ति \$53 **⊏€** • **⊏₹** • सामीगा तथा छोटे ज्योग 200 200 250 जदोश तथाल जि≔ 880 550 **650** परिवडन और सचार 8.3⊏4. M76.5 8.380 सामाजिक मेनार्ने P V4 **⊏**8 3 **⊏**₹• তি ভিদ . EE EY 19.0 YEOR ¥500 YYOO

रेप्पण के ब्रस्तरीत हुई है ताकि कुल व्यय ४५०० करोड क० हो वर्कें। विभिन्न पोजनाख्ये के लिये निर्वापत वित्त में परिवर्तन युक्तिपूर्वक नहीं किये गये हैं ब्रतप्त ये गलत भी हो सकते हैं।

य गलत भी हो सकते हैं।

"योजना में ७६ लाख व्यक्ति क्रांप के बाहर तथा १६ लाख कांप में काम
पार्वेंगे, ऐसी आसा की जाती है। विभिन्न योजनाओं को लागत बढ़ जाने के
कारण ऐसा अनुमान किया गया है कि कृषि के बाहर ७० लाख व्यक्तियों को काम
मिलेगा। यह अनुमान ४००० करोड़ क० कै व्यव तथा निजी चेत्र के व्यय में कोई
परिवर्तन न मानने पर आधासित है। ४५०० करोड़ क० के व्यय के अनुमान पर
६५ लाख व्यक्तियों को काम मिलने की आधा है?)

## <sub>श्रध्याय</sub> ४९ तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा

भारत की तृतीय योजना की तैय्यारी की बा रही है श्रीर सबसे श्रधिक गंभीर परन जो योजना आयोग तथा सरकार के समत्तृ है वह योजना के रूप श्रीर ग्राकार के सम्मन्त्र में है। तृतीय योजना के आरम्भ न करने का तो कोई आर आर्था । युवा प्रति होता योजना के कुछ ध्येयां की पूर्ति होना सम्मय नहीं प्रश्न ही नहीं है। यद्यपि द्वितीय योजना के कुछ नरपुरापश्याप्रकारिक विकास हमारी आशा से कहीं कम हुआ है, किर मी र अर्थ की प्रकार के साम की दिल्ला की स्थापन की साम की स्थापन की साम िला चलता रहना चाहिये और इसने लिये अधिक विस्तृत और महत्वाकांची तुतीय योजना की आवश्यकता है। इसके मी घ्येयों को लगमग प्रथम और द्वितीय हुआ । अपनि का श्री होना चाहिये, श्रयांत् देश में प्राप्त बस्तुओं के साथनों याजना के समान ही होना चाहिये, श्रयांत् देश में प्राप्त बस्तुओं के साथनों नावना च वनान पार्वा नावन अनार पुरा नावन नावना ना जायना का सर्वोक्तस्ट हंग से उपयोग, श्रीयोभिक तथा कृषि सम्बन्धो उत्पत्ति की श्रीवक से अपनित निर्देश करने के अवस्त्रों की दृष्टि तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को वास्तिवक रूप से ऊँचा उठावा जा सके, होना चाहिये। सारांश यह न त्या जा जावाज रहे । जाज जाज जाज का जाज । जावाज वह कि मारत में वास्तव रूप से कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो सके। यह तो प्रत्यज्ञ है कि इन आदर्शों को पूरा कर लोने के लिये लोगों को कुछ वराओं के अपने वर्तमान उपमोग को अधिक कर (tax) देकर त्याराना पड़ेगा और अपनी बचत की मात्रा को पूँजी की बृद्धि करने के लिये बढ़ाना पड़ेगा।

का भागा का पूजा का बाज कर सम्बन्ध से सतीयद उसके आकार पर ही केंद्रित अभी तक तृतीय योजना के सम्बन्ध से सतीयद उसके आकार पर ही केंद्रित असी के रहा है। सफारी सतानुसार तृतीय योजना का येय १०,००० करोड़ दूपयों के रहा है। सफारी में प्रतानियोग का ५ वर्ष को आविष्य से होना चाहिये जबकि हि तीय योजना में प्रतानियोग का ५ वर्ष के अप्ता ही थी। इस नीति के विरोधकों का कहना वित मात्रा केवल १२०० करोड़ रुपया ही थी। इस नीति के विरोधने का कहना वित मात्रा केवल १२०० करोड़ रुपया ही थी। इस नीति के विरोधने का कुमार उपने हैं कि इतनी मात्रा का वितियोग आरंपिक होगा और उन्होंने यह मुक्ताय उपने हैं कि इतनी मात्रा का वितियोग योजना में विभिन्योग का तर तथा पर वहीं होना चाहिये स्थित किया है कि तृतीय योजना से या। परन्त तृतीय योजना के आकार के सम्बन्ध में स्वनीय किया उसके तथा के स्थान के स्थान के स्थान से की स्थान से की सात्रा के सम्बन्ध में स्थान से हम तियोग सिक्त के स्थान के स्थान के स्थान से किया उसके स्थान और निर्धिक है।

नगर जिया अपन के सबसे अधिक गम्मीर बात विनिमय की मात्रा में सरकारी इस सम्बन्ध में सबसे अधिक गम्मीर बात विनिमय की मात्रा में सरकारी श्रीर व्यक्तिगत चेत्रों के माग की है। प्रथम गोवना में श्रीधोगिक विकास के सम्बन्ध में व्यक्तिगत चेत्र का माग कुल विनियोग में श्राधा या परन्तु दितीय योजना में वह घटाकर एक-निहाई कर दिया गया था। ऐसा स्पष्ट रूप से लंबित हो रहा है कि ततीय योजना में व्यक्तिगत द्वीत का भाग और भी अधिक पटा दिया जायगा। इसका अर्थ यह है कि दितीय योजना में केन्द्रीय और राज्य धर-कारो तारा विकास सम्बन्धी विजियोग जो कि ४८०० करोत रूपया था (ब्रीर जो बाट में बटाकर ४५०० करोड़ रुपया कर दिया गया था) उसे ७५०० करोड़ रुपया करना पहेगा यदि योजना का कुल न्यय १०००० करोड़ रुपया स्वला गया। यदि ऐसा हम्रा तो १०००० करोड़ सपयों के ब्राकार की योजना देश की शक्ति के बाहर होगी और यदि लाटी गई तो देश से बड़ी कठिताई तथा शब्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ५५०० करोड कायों की विकास योजना की विकास स्ववस्था करने से केम्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने बहत से नये करों का खारोप किया है छीर पहिले से आरोपित करों से बढ़ि की है जिसमें ५ वचों से १०० करोड कार्यों की कल अतिरिक्त आय की आशा की जाती है। इन करों के अतिरिक्त सरकार में बहुत बड़ी मात्रा में बाटे की व्यर्थ-व्यवस्था भी की है जा कि दितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों मे हथा। कानेब दुपये की साजा के लगभग होगो यशपि संघ के बित्त संत्री में १६५६-६० तक उसका २२२ करोड़ काये ही अनुमान लगाया है। चेंकि यह सर्वे विदित है कि दिलीय योजना की ५ वर्ष की परी श्रवधि में १५०० करोड़ रुपयों से अधिक का बाटे का अर्थ प्रबन्धन होगा इसलिये हम यह परिसाम निकाल सकते हैं कि वित्तमंत्री द्वारा अनुमानित मात्रा कम है। यदि सरकार अपनी विकास योजनाओं पर कर-आय अथवा जनता से लिये गये आरुण का व्यय करती है तो सद्रास्पीति उचका परिखाम नहीं होना चाहिये और उनके प्रसस्बद्ध मुख्य स्तर में वृद्धि भी न होनी चाहिये। देखा इसलिये होगा कि जनता की दाव्यिक श्चाय. जिसमें से बह कर देती है श्रयवा सरकारी श्रूकों में जिसका विनियोग करती है समान मात्रा की सेवाओं तथा वस्तुओं द्वारा सतुनित हो जाती है। यदि जनता अपनी आय का व्यय करती है तो यह इन मेदाओं और दस्तुओं का उपमोग स्वयं कर लेती है और यदि वह कर (tax) देता है अथवा सरकारी ऋण में विनियोग करती है तो दूसरे शब्दों में वह इस प्रकार सरकार को उसी माना की सैवाश्रो और वस्तुश्रों के उपमीम का अधिकार अदान कर देती है। यदि सरकारी विकास योजनाश्री की वित्त स्थवस्था कर-श्राय तथा ऋसा द्वारा प्राप्त धन से की जाती है तो देश में ऐसी वस्तुयें और सेवायें प्राप्त होगी जिन पर यह द्रव्य व्यय किया जा सकता है और कछ ही समय से ऐसी समायोजना स्थय हो जायगी कि ऐसे ब्यय के कार्या मुक्य स्तर में बुद्धिना हो। लगभग ऐसी ही स्थिति उस समय भी होती है जब कि दिवास मोजनाओं की दिस त्यवस्था विदेशी अनुदानी अथवा देश के विदेशी विजित्तम निषियों से की जाती है नयीकि यह घन मारत के बखुओं के आवात से ही प्राप्त होता है और इस प्रकार जो कुछ भी न्यय सरकार योजना पर करती है उससे संतुक्तित हो जाता है। यथामें में ये आवात की हुई वस्तुमें यदी नहीं कि मुल्य स्तर की वृद्धि में ही रोक्याम करें वस्तु ये वास्तव में मूल्य स्तर को नीचे गिराने में सहायक होती है और इस्तियों रूपें हम मुझा संकुचन उत्तरक करने का कारण कह सकते हैं। परना सेसा पार्ट का अप्री प्रकारन जिसका अप्री स्मित्त है जिसमें सरकार अपनी चालू कर-आय, ऋषा से मान्त भन, जमा पन और निविधों इस्त्यादि से जो कि उसके पार्ट है आधिक स्पर करती है, मुझास्त्रीति उत्तरन करने का कारण है और यहि इसकी कुल मांश अधिक हुई तो यह मुझास्त्रीति उत्तरन करने का कारण है और यहि इसकी कुल मांश अधिक हुई हो यह मुझास्त्रीति जा चहुत अधिक प्रमावशाली कारण बच चकते है, ब्योंकि हस्य के स्वय का यन्त की भूति हारा हम स्थित में सेतुलन नहीं होता।

तालयें यह है कि अपने देश में करारीय आपना आधिकतम सीमा पर पहुँच जुका है और जनता बिना अरुख कर उठाये अब और अधिक कर देने में अध-मंधे हैं, और पाटे का अधे मानण मयायह सीमा तक पहुँच जुका है और उठाका परिणाम मुझास्त्रीति कम्य मूल्य स्तर में युद्धि हो जुकी है। इस्तिये सरकार के लिये अब और अधिक पाटे के अधे मानण्य का विचार करना अद्यांचत होगा। परन्तु यह हमारी मुलीय योजना अधिक विस्तृत और महत्वाकांची है और सरकारी चेन अधिक विस्तृत है तो करी तथा भाटे के अधे महत्वाकांची है और सरकारी चेन अधिक विस्तृत है तो करी तथा भाटे के अधे महत्वाकांची थोजना को पूरा करने का कोई अस्य उपाय नहीं है। यदि कुल क्या से सरकारी चेत्र का माग और अधिक बहागा है और सरकार को उसकी व्यवस्था करने के लिये यन कही से देंद्व निकालना है तो हमें समकता चाहिये कि अधिक विस्तृत योजना को पूरा करना हमारी सामध्ये के बाहर है चाहे हमारी कितनी ही अधिक अध्वश्यकता वयो नहीं।

परन्तु यदि तृतीय योजना के श्रान्तर्यात कुल ज्यय मे स्वक्तिमत चेत्र का भाग बढ़ा दिया जाता है और यदि सरकार की शायिक, श्रीचांगिक तथा श्रान्य नीतियों को श्रावश्यकतामुखार परिवर्गित करके जीवन वातावरण का खनन किया जा ककता है तो यह सम्मव हो सकता है कि हम अपनी तृतीय योजना को विज्ञा किनिवर्गित यो यहा प्रमानकोति की द्वारा तथा किये हुई हो श्राप्यक विस्तृत तथा सदराकांची बनाएँ। यह हस्तियों सम्मव है कि व्यक्तिगत चेत्र में विभिन्नोंग का प्रमुख्य मादा क्वत की आशा और कुछ चोषा चीवरेशी पूँजी से किया जाता है और यह व्यवस्था में संतुत्तित हो स्त्रीर यह व्यव वस्तुओं की पूर्णि हारा देश की आर्थिक व्यवस्था में संतुत्तित हो और यह व्यव वस्तुओं की पूर्णि हारा देश की आर्थिक व्यवस्था में संतुत्तित हो

जाता है। जहाँ तक बैंक द्वारा लिये हुये ऋष्य से हणकी व्यवश्या होती है उस सीमा तक वस्तु की पूर्ति द्वारा संज्ञुलन नहीं होता और प्रदास्कृति उत्पन्न करने का कार्य्य वन सकता है। परन्तु मारत में व्यक्तिगत सेत्र के कुल विनियंका के बहुत धोढ़े से अंध्य की व्यवस्था हम दंग से होती है इसलिये व्यक्तिगत सेंत्र द्वारा विकास-वीजना में विनियोग से धुदास्कृति के प्रोत्साहित होने की सम्मायना नहीं है। यही कार्य है कि तृतीय योजना की क्ष्यरेला उसके आकार को प्रमावित करनी है।

इसमें संदेह नहीं कि द्वितीय योजना में आरम्भ किये हुये विकास कार्यों को उनकी याला-प्रशास्त्राओं सहित मुतीय योजना में पूर्ण करना है इसलिये विनिधेश का मात्रा दितीय योजना में आधिक अवस्य होगी। यह भी सत्य ही है कि यह जनस्वत के अधिक अंश को काम देना है तो यह आयस्त आयस्यक है कि मारतवर्ष में जनता को काम करने के अधिक अवसर प्रदान किये जाने चारिये। मारत की जनसंख्या में २% को मितवर्ष दृद्धि को विचाराधीन रखते हुये लोगों को बुबिसना रहन-कहन का हतर प्रदान करने के लिये आधिक विवाराधीन रखते विवाराधीन हिंदी लोगों को बुबिसना रहन-कहन का हतर प्रदान करने के लिये अधिक तीव गति से आर्थिक विवारा की आयर्थकता है।

परम्त यांट सरकारी चेत्र के विस्तार को बढ़ा दिया जाय तो यह सब सम्मव न हो सक्का। द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में राष्ट्रीय झाप लगभग २% प्रतिवर्ष की क्रीसन दर से बढ़ी है और लगमग २७ लाल ५० हजार व्यक्तियों की काम करने के अतिरिक्त अवसर भदान किये तमे हैं जब कि द्वितीय योजना का ह्येय 4% प्रतिवर्ष की वृद्धि राष्ट्रीय आव में और Co लाख व्यक्तियों की अविरिक्त काम देना निश्चित किया गया था। वृद्धि की इस दर ने जनता पर ऊँचे करों, जीवन-यापन के ऊँचे मूल्यों, श्रीर नीचे गिरे हुये रहन-सहन के दर्जे के रूप में बहत कटिनाइयाँ लादी हैं। ताकि इन कटिनाइयों को विना अधिक मात्रा में बढ़ाये तर्ताय योजना का विस्तार बढ़ाया जा सके इसलिये योजना आयोग और सरकार है. को यह निश्चय करना पड़ेगा कि किसी विचारादर्श के प्रति अपनीश्चास्था प्रदर्शित करने के लिये उसी पर ऋड़े रहना, ऋषवा ऋषिक तीव गति से देश का ऋार्थिक विकास करना देश के लिये कहाँ तक हितकर होगा। चॅकि प्ॅबीयादी व्यवस्था का स्यान समाजवादी व्यवस्था द्वारा घीरे-घीरे लिये जाने का काये छ।रम्म हो चुका है इसलिये वह तो अपना पूरा समय लेगा, परन्तु यदि तसके स्वामाविक विकास को जल्दी लाने का प्रयक्ष किया गया तो इसका अर्थ आर्थिक उन्नति श्रीर देश की सम्पन्नता की प्रगति में बाधा डालना होगा।

तृतीय योजना की रूपरेखा का जानना उसके आकार को निश्चित

करने के लिये ही आवश्यक नहीं है वरन देश को विकास योजनाओं से अधिकतम लाभ पान्त करने के लिये भी श्रावश्यक है। व्यक्तिशत सेत्र को उसका उचित ग्रंश देने के बाद दूसरा आवश्यक प्रश्न योजना के अन्तर्गत आये हुये विकास कार्यो का कम है। क्या तृतीय योजना के विकास कायक्रम में कृषि को वही स्थान दिया जाना चाहिये जो कि उद्योग को दिया जाय ! दिताय योजना के अनभव के जाचार पर जिसमें कवि को श्रीकोगिक विकास की तलना में कम महत्व का स्थान दिया गया था हम कह सकते है कि कृषि का स्थान ग्राधिक महत्व का रोजा साहिते । दिलीय गोजना में सर्वप्रथम १०० लाख रन खावाल के जरगदन का लक्ष्य ब्रह्माया गया था जो कि बाद में बदाकर शंब्ध लाख उन कर दिया गता । दितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में इस लक्ष्य का आधे से अधिक परा न किया जा सकेशा। कवि के प्रति उदासीनता के परिणाम स्वरूप खाद्याझ में कमी तथा उनके निरन्तर बहते जाने वाले मुल्य देश के समझ आये। ऐसी आर्थ व्यवस्था में जहाँ खायाल के मूल्य का सबसे ऋषिक महत्वशाली स्थान है वहाँ अस के मूल्य के बढ़ने के साथ ही साथ अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगते हैं। और इस प्रकार महास्कीति की स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इस सह वातां की उत्पन्न न होने दैने के लिये तृतीय योजना में कृषि उत्पत्ति के अधिक बदाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसमें सैंदेह नहीं कि देश की खल खाब तथा उत्पत्ति श्रीद्योगिक विकास के फलस्वरूप कृषि के विकास की दुलना में श्रीधक तीन गति से वह जायमी । यही बात काम के अवसरी, नियात तथा जनता के रहत-सहत के दर्जों के बढ़ाने के सम्बन्ध में भी कत्य है। परन्त प्रश्न तो यह है कि ऐसी श्राधिक उन्नांत का क्या प्रयोजन जब जनता को भर पेट भोजन मिलना ही दृष्कर हो जाय। कृषि क विकास के प्रति विशेष भ्यान देने का अर्थ चाहे स्मार्थिक विकास में कमी करना ही क्यों न हो यह जो खिम उठाने योग्य है क्योंकि इससे अब की उपन तथा अन्य कृषि उत्पत्ति के बढ बाने के कारण औद्योगिक विकास के लिये हुढ आधार मान्त ही जाता है।

श्रीचोमिक विकास से वास्तविक कठिनाई विभिन्न हितो क समायोजित करने की हैं जैसे : (१) छोटे स्तर के घरेलू उद्योग-अन्ते और ज्वाहट स्टाक कम्पनी व्यवस्था वाले वहें स्तर के उद्योग, श्रोर (२) बड़ी मधीनों के निर्माण करने वाले उद्योग तथा उपमोक्ता की बस्तुझी तथा श्रन्य छोटी-छोटी बस्तुझों का उत्यादन करने याले उद्योग मानतीय श्रार्थिक तथा उद्योग स्वयस्था में छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले परेलू, उद्योग-पन्यों का एक विशेष स्थान है और इस्तिये उन्हें पूर्ण रूप से प्रोत्साहत दिया जाना चाहिये परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि बड़े स्तर ~2~

पर उत्पादन करने वाले उद्योगों का ऋदित करके ऐसा किया जाय। दिर्त य योजना में एक महान भूल बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की चिन्ता न करके छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा धरेल उद्योग धन्मों को बहाने की नी गई थी। देसके मूल में योजना के अन्तर्गत काम करने के अवसरों को बढ़ाने की भावना थी। इसका उदाहरण सुती कपड़ा उत्पादन करने वाले उद्योग थे। यह नौति काम के अवसरों के बढ़ाने में सकल नहीं हुई वरन् उसने बड़ी मात्रा में उत्पा-दन करने वाले उद्योगों को घाटा पहुँचाया। यह भूल गुतीय योजना में बचाई जानी चाहिये श्रीर केवल उन्हीं घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिनका विकास बिना बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों को हानि पहुँ-चार्वे किया जा तकता है और केवल ऐसे ही ढंगों का प्रयोग किया जाना चाहिये जिनसे घरेलू उद्योगों की तो वहायता प्रभावशाली ढंग से हो पर वड़े उद्योगों को किसी प्रकार की द्वानि न पहुँचे। जैसे जैसे बड़ी सात्रा में उत्पादन करने वाले उचीगों का विकास होता चलेगा श्रविकाधिक काम करने के श्रवसर जनसंख्या को मिलते जायगे स्त्रीर इस भीच में इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि अमन्यचाय के दंगका प्रयोगन हो बरजूनचे कारखानों से तथा उन पुराने कारखानों में जहाँ मरीने बदली जाने वाली हैं अधिक कुरालता से काम खेने वाली मरीनों का हुतीय योजना में अधिक ब्यय होने के कारण वर्षो-स्यों लोगों की ब्राय बढ़ेगी स्वो-स्वो उन्हें अधिक उपभोग की वस्तुश्रो की आवर्यकता होगी। भूत

काल में ऐसी वस्तुयें श्रंशतः विदेशों में अपने विदेशी विनिमय निधियों के और अग्रतः सुमतान संतुलन के अतिरेक के आधार पर आयात की जा सकती थीं। अब उपमोक्ता की वस्तुका की पूर्ति देश में ही बढ़ानी है। परन्त सदि इन्हों उद्योगों पर अधिक विनिमय कर दिशा गया तो मशीनों के निर्माण, भारी राज्ञायनिक मय, इन्जीनियरिंग तथा श्रम्य इस प्रकार के उद्योगों पर जो कि स्रभी भारत में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुये हैं, और जिनके विकास की श्रीवोध्यक श्राधार प्रदान करने के लिये झावस्यकता है, ब्यय करने के लिये पर्याप्त मात्रा से घन न बचेगा। इन उद्योगों के सम्बन्ध में योजना के हिण्डकीय से कठिनाई यही है कि निकटस्य मविष्य में ये उद्योग लोगों को इतने काम के अवसर न मदान कर सकेंगे जितने कि उपमोग की वस्तुओं के उत्पादन वाले उद्योगों ने विकसित करने से मिलते। इसके अविरिक्त उनका उत्पादन बाजार में बिनी के लिये अधिक दिनों के पश्चात् श्रायेगा श्रीर बढ़ी हुई क्रय-शक्ति अधिक विनियोग होने के कारण बाजार में माल पहुँचने के पहिले पहुँच जायगी निष्ठसे सुद्रास्क्रीति की स्थिति उत्पक्ष हो जायगी।

परन्तु इन सब कठिनाइयों के होते हुये भी मारत की तृतीय योजना के अन्तर्गत भत काल की खपेक्षा काविक साजा में ज्यय बढ़ी मशीनों के निर्माण करने वाले

कारवाना के लिये नियत करना ग्रावण्यक होगा । · चूँकि अपने देश में शाधन का श्रमाव है इसलिये महत्व में रिशम बन्त

को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिये । इसका अर्थ यह हम्रा कि तृतीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये विकास से श्रासम्बन्धित समस्त व्यय तथा तृतीय योजना के बाहर विकास सम्बन्धी व्यय को न्युनतम स्तर पर रखना चाहिये श्रीर मारत के सरकारी ब्यय में जितनी भी बितब्यवता सम्मव हो, की जानी चाहिये। इस बात पर बारम्बार योजना त्राचोग ने सथा सरकार ने जोर दिया है परस्त स्त्रमी तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इसे कोई प्रयोगात्मक रूप नहीं दिया गया है। प्राप्त साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिये भी यह आवश्यक है कि तृतीय श्रीजना के बाहर के व्यय को न्यूनतम करने के लिये कोई प्रशोगात्मक उपाय दें विकास जार ।